



राजस्थान—



लेखक

श्रीकृष्ण दत्त शर्मा

एम० ए०, एल एल० बी०

[एडवोकेट तथा सेवाविधि सलाहकार]

छिपनलाल जन



बन्दहोरा बिल्डिंग (सहमी पेट्रोल पम्प के पास),

एम० आई० रोड जयपुर-302001

॥ ॐ श्री गार्गीताराय नमः ॥

गुणीता, योगेश, भवपेश  
एव सर्वा बाधोप  
को  
**सहनेह-समर्पित**

—इत

© S K DUTT

भारत सरकार, बायोराइट कार्यालय  
द्वारा प्रजोक्त

[इस पुस्तक में प्रकाशित अनुवांशिक विद्वान-  
मलियों तथा विवेचना की तकम करने का  
कष्ट न करें, भवपेश बाधोप बाधोप की  
जायगी। —लेखक

**1979**

प्रकाशक

**ए-वन एजेन्सज**

चंद्रहीरा बिल्डिंग,  
(लक्ष्मी पेड्रोत पम्प के पास)  
एम० आई० रोड, जयपुर-302001

मुद्रक

- सोलकी माट प्रिंटर्स,  
डिग्री हाउस, जयपुर
- विनीता प्रिंटर्स, जयपुर

[मादिकार सरोधित]



मूल्य 35/-

× लेखक की अन्य विधि रचनाएँ—

- Land Revenue Law in Rajasthan
- Tenancy Law in Rajasthan
- Law and Procedure of  
Disciplinary Proceedings  
(CCA) Rules
- Rajasthan Agricultural  
Produce Market Act
- Rajasthan Municipal Act and  
Election Orders
- अनुशासनिक बाधोप  
(भारत सरकार से पुरस्कृत)
- सेवा सम्बन्धी मामले एवं दिव्यूनल कानून
- उपदान (मेच्युटी) संदाय, अधिनियम  
(व्याख्या)
- राजस्थान यात्रा भत्ता नियम



## प्रावकथन

राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रशासनिक कार्य करने के लिए हमारा राज्य कृत-सकल है और इस दिशा में प्रस्तुत पुस्तक एक महत्वपूर्ण योगदान है। सिविल सेवाओं विशेषकर लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी, के लिए सेवा की शर्तों सम्बन्धी नियमों की पुस्तक का हिन्दी में सर्वथा अभाव था। इस अभाव की पूर्ति में यह पुस्तक सराहनीय कदम है, जिसमें लिपिक वर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कमचारियों को अपनी सेवा की शर्तों व नियमों को समझने में मायदशन मिल सकेगा। परिशिष्ट में दिये गये विविध नियम तो अन्य सेवाओं के लिये भी उपयोगी होंगे।

इस पुस्तक में 'विवेचना खण्ड' में इन नियमों के विभिन्न विषयों पर आठ अध्यायों में व्याख्यात्मक अध्ययन दिया गया है, जो अद्यतन न्यायालय नियमों, अधिकरण के नियमों तथा सरकारी आदेशों पर आधारित होने से प्रामाणिक एवं उपयोगी बन गया है। स्थान स्थान पर दिये गये उदाहरण विषय को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। हिन्दी में इस विषय पर पहली बार इस प्रकार की उपयोगी पुस्तक के लेखन के लिये लेखकों का प्रयास प्रशंसनीय है।

मुझे विश्वास है कि—यह पुस्तक प्रशासन, सरकारी कार्यालयों, कमचारियों एवं अभिभाषक वगैरह सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ऐसे महत्वपूर्ण प्रकाशन के लिये मैं लेखक तथा प्रकाशक दोनों को हार्दिक बधाई देता हूँ।

५३१४



अनेक वर्षों से मित्रों तथा सहयोगियों का आग्रह था कि—मन्त्रालयिक (लिपिक वर्गीय) सेवाओं सम्बन्धी नियमों पर हिन्दी में एक पुस्तक तैयार की जावे। इसके परिणाम स्वरूप हमने इस दुर्लभ काय को आरम्भ किया तथा ईश्वर की कृपा से आज यह पुस्तक पाठकों की सेवा में समर्पित है। लिपिक वर्गीय कमचारियों की नियमों की दिन प्रतिदिन बदलती परिस्थितियों ने अनिश्चितता में डाल दिया और फिर इन नियमों का हिन्दी अनुवाद उपलब्ध न होने से इनको समझने में भी कठिनाई उठानी पड़ी। इस समस्या का समाधान कर सही मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से इस पुस्तक की रचना की गई है। चतुर्थ श्रेणी कमचारियों के नियम भी हिन्दी में कहीं उपलब्ध नहीं थे। अब हमने इस पुस्तक में उनकी नियमावली भी प्रकाशित की है। इस प्रकार हिन्दी में अपने विषय की यह पहली पुस्तक है।

इस पुस्तक में सबसे अधिक विभिन्न लिपिक वर्गीय सेवाओं की चार नियमावलियाँ दी गई हैं—(1) अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम 1957, जो सचिवालय, राज्य विधान सभा, उच्च न्यायालय तथा उसके अधीनस्थ सिविल न्यायालयों और लोक सेवा आयोग के कार्यालयों को छोड़कर, अन्य समस्त कार्यालयों के लिपिक वर्ग पर लागू होते हैं। (2) सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1970, जो सचिवालय के लिपिक वर्ग पर लागू होते हैं। “राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 1952” के नियम 9 के अधीन जिन मामलों में नियम शांत हैं, सचिवालय की नियमावली विधानसभा सचिवालय के लिपिक वर्ग पर भी लागू होती है। (3) अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम 1958, जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल न्यायालयों के लिपिक वर्ग पर लागू होते हैं। (4) राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा नियम 1959, जो पंचायत समिति/जिला परिषद् के विभिन्न पदों पर लागू होते हैं। इस प्रकार समस्त लिपिक वर्गीय सेवाओं के नियम आपको इस पुस्तक में मिलेंगे। इनके बाद “चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 1963” दिये गये हैं, जो सभी सरकारी कार्यालयों में प्रभावशील हैं।

खण्ड 2 (मे) विवेचनात्मक अध्ययन में इन सभी के “नियमावली प्रसंग” देकर सभी विषयों को झाँठ अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सरकारी निर्देशों और न्यायालयों तथा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के निर्णयों सहित व्याख्या दी गई है। नियमों को समझने के लिये अध्याय (1) में मार्गदर्शन दिया गया

है। आप जिस विषय को देखना चाहें, उसकी अध्याय में "नियमावली प्रसंग" देखिये, फिर उस नियम को पढ़िये और फिर उस अध्याय को। इस प्रकार आप इस पुस्तक का आसानी से लाभ उठा सकेंगे। पुस्तक में जहाँ 'अपील स०' या 1978 RLT" का उल्लेख फुटनोट में किया गया है, वे "राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण" (ट्रिब्यूनल) के नियम हैं, जो पात्रका "Rajasthan Law Times" में प्रकाशित होते हैं। इनके सारांश 'लेखा विन' में भी समय-समय पर प्रकाशित होते रहते हैं।

'परिशिष्ट' में—इन नियमों से सम्बंधित कुछ नियमावतियों का हिंदी पाठ प्रस्तुत किया गया है, जो अप्राप्य थीं। कृपया इनके नाम 'नियमावली-तालिका' में देखिये।

आशा है, यह पुस्तक सरकारी सेवाओं के लिये एक अनुपम तथा लाभदायक ग्रंथ के रूप में सहायक सिद्ध होगी।

इस पुस्तक का प्राक्कथन लिखकर माननीय गायमूर्ति श्री पुरुषोत्तमदास कुदाल ने हमें आशीर्वाद देकर प्रोत्साहन दिया है, हम उनके हृदय से आभारी हैं। इस पुस्तक के लेखन एवं संकलन में हमारे अनुयमित्र श्री रणवीर सिंह गहलोत, सहायक सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय का सहयोग सदा की भाति-प्रशंसादायक रहा। हमें चतुर्थ श्रेणी सेवा नियमों को सम्मिलित करने की प्रेरणा श्री रामजी लाल शर्मा, (प्रान्तीय सचिव, राजस्थान सहायक कमचारी सघ, जयपुर) से मिली और उन्होंने संकलन में हमारी पूरी मदद की। कागज एवं मुद्रण की भयंकर महंगाई के बावजूद हमारे अनुयमित्र एवं प्रकाशक श्री कैलाश चंद्र शर्मा तथा श्री गणपत लाल शर्मा, (ए-वन एंजेसीज) ने जिस लगन, परिश्रम और साहस से इसके मुद्रण व प्रकाशन की व्यवस्था की, उसी के परिणाम स्वरूप यह पुस्तक हम पाठकों की सेवा में प्रस्तुत कर सके हैं। हम इन सब के आभारी हैं।

दिन प्रतिदिन बदलते नियमों की वृद्धि में हम जो कुछ प्राप्त कर सके, उसे हमने पाठकों को भेंट कर दिया है। इस पुस्तक में कोई भूल, त्रुटि या अंतराल विद्वान् पाठकों के ध्यान में आवे, तो हमें अवगत कराने की कृपा करें, ताकि भविष्य में उसका निराकरण किया जा सके।

अन्त में प्रमुखस्वरूप पाठकों को हम यह नूतन पुस्तक समर्पित करते हैं।

जय गोविंद!

वधीचि कुटीर

B-24, गोविन्दपुरी (पूर्व)

नयारामगढ़ रोड,

जयपुर-302002

एच. एच. जैन

## अनुक्रमणिका

खण्ड (1) लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थश्रेणी सेवा नियम	[1- 209]
खण्ड (2) विवेचना खण्ड	[210-284]
परिशिष्ट नियमावली-खण्ड	[1- 56]
कुल पृष्ठ 284+56 = 340	

## नियमावली तालिका

[\*परिशिष्ट सहित]

खण्ड (1) में—

- 1 राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1957  
(Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Staff Rules 1957) 9-98
- 2 राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1970  
(Rajasthan Secretariat Ministerial Service Rules 1970) 99-149
- 3 राजस्थान अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम  
(Subordinate Civil Courts Ministerial Establishment Rules 1958) 150-163
- 4 राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा नियम 1959  
(Raj- Panchayat Samitis & Zila Parishad Service Rules 1959) 164-192
- 5 राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम  
(Rajasthan Class IV Service (Recruitment & Other Service Conditions) Rules 1963) 193-209



\*परिशिष्ट मे—

[पृष्ठ संख्या 1 से पुन आरम्भ होती है]

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (अधिसेप कर्मियों का आभेसन) नियम  
Rajasthan Civil Services (Absorption of Surplus  
Employees) Rules, 1969 1-26
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (अस्थायी कमचारियों की अधिष्ठायी नियुक्ति  
तथा वरिष्ठता निर्धारण) नियम 1972  
(Rajasthan Civil Services (Substantive Appointment  
of Temporary Employees) Rules 1972) 26-31
- 3 राजस्थान सेवायें (पूर्ववर्ती वर्षों की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति  
द्वारा भर्ती) नियम 1972  
(Rajasthan Services (Recruitment by Promotion  
against vacancies of Earlier years) Rules, 1972 32-34
- 4 राजस्थान सिविल सेवा (सरकार द्वारा अधिग्रहित निजी संस्थानों  
तथा अन्य स्थापनाओं के कमचारियों की नियुक्ति तथा सेवा  
की शर्तें) नियम 1977  
(Rajasthan Civil Services (Appointment and Other  
Service Conditions of Employees of Private Institu-  
tion and Other Establishment taken Over by the  
Government) Rules 1977 (34-37
- 5 राजस्थान शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों (विकलांगों) का  
नियोजन नियम 1976  
(Rajasthan Employment of the Physically Handi-  
capped Rules 1976) 37-44
- 6 राजस्थान (सेवा में रहने हुए मृत्यु होने पर सरकारी कमचारियों  
के आश्रितों की भर्ती) नियम 1975,  
(Rajasthan Recruitment of Dependants of Govt  
Servants dying while in Service Rules 1975 44-48
- 7 राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा के सदस्यों  
पर आश्रितों की भर्ती नियम 1978 49-53
- 7 राजस्थान सिविल सेवा (CCA) नियमों की अनुसूचिया—  
अनुसूची (3) लिपिक वर्गीय सेवायें 53  
अनुसूची (4) चतुर्थ श्रेणी सेवायें 55

खण्ड (2)---

## 1.1 विवेचना खण्ड

मन्त्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी नियमावली

का

## व्याख्यात्मक-अध्ययन

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1	सेवा नियमों का स्वरूप एवं परिचय [Introduction to & Nature of Service Rules]	211
2	सेवा में प्रवेश—सर्ती एवं नियुक्ति [Recruitment & Appointment]	223
3	आरक्षण (Reservation) (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये)	23
4	अत्यावश्यक अस्थायी नियुक्तियाँ [Urgent Temporary Appointments]	241
5	परिबीक्षा एवं स्थायीकरण (पुष्टीकरण) [Probation & Confirmation]	248
6	वरिष्ठता सूची एवं वरिष्ठता के मापदण्ड [Seniority List & the Basis of Seniority]	257
7	संवर्धन, मापदण्ड, पात्रता एवं तरीका [Promotion—Its Criteria, Eligibility & Procedure]	266
8	विविध-मामले— [Miscellaneous]	279

छपते-छपते



नवीनतम सशोधन

[ कृपया निम्नांकित सशोधन को पहले पुस्तक में उचित स्थान पर चिह्न लगाकर पृष्ठ सं. लिख लीजिये, ताकि सशोधन ध्यान में रह सकें। कष्ट के लिये क्षमा करें ]

अधोनस्थ कार्यालय नियमावली में—

पृष्ठ संख्या 88 तथा 8 पर देखिये।

सचिवालय नियमावली में—

पृष्ठ संख्या 99, 149 तथा viii पर देखिये।

### 1 \*कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा

कृपया पृष्ठ 91 से 95 तक प्रकाशित पाठ्यक्रम में निम्न संशोधन कर लें—

(1) पृष्ठ 92 पर—खण्ड 'क' के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित करें—

खण्ड 'क'—समस्त अभ्यर्थियों के लिए

1 सामान्य अध्ययन, दैनिक-विज्ञान तथा

ताजा मामले (Current-affairs)

100

2 सामान्य हिंदी

100

(2) पृष्ठ 93-94 पर “खण्ड 'क' अनिवार्य प्रश्नपत्र” के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित करें—

खण्ड 'क'—अनिवार्य प्रश्न पत्र—इन विषयों का स्तर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा भण्डल की सेवे-डरी-परीक्षा का होगा।

1 सामान्य अध्ययन—यह प्रश्नपत्र ज्ञान के निम्नांकित क्षेत्रों को प्राकृत करेगा—(क) सामान्य विज्ञान, (ख) राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ताजा घटनाएँ, (ग) भारत का इतिहास तथा भूगोल, (घ) भारतीय नीति तथा भाषिक व्यवस्था, (ङ) भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, तथा (च) एक गणित-6 अंक की (दैनिक गणना करने में गति व छुटता की परख करने के लिये)।

2 सामान्य हिंदी—यह प्रश्नपत्र अभ्यर्थी की भाषा में प्रवीणता की परख करने के लिये होगा और इसमें बहुत से दिये गये विषयों में से एक पर निबंध लिखना, सारांश लेखन, पत्रलेखन, मुहावरों का प्रयोग, वाक्यों को शुद्ध करना, शब्द युग्मों (जोड़ों) में अन्तर आदि सम्मिलित होंगे।

(3) पृष्ठ 94 पर—“खण्ड 'ख' ऐच्छिक विषय” के नीचे विषयों की “क्रम सख्या 5, 6 व 7” की बजाय “क्रम सं 3, 4 व 5” प्रतिस्थापित की जाए।

### 2 अधीनस्थ कार्यालय नियमावली में

पृष्ठ 60 पर नियम 26 व (2) के नीचे निम्न नया परतुक जोड़े—

XX “परतु यह और है कि—उन विभागों के मामले में जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी भकेला है या नियुक्ति प्राधिकारी का केवल एक अधीनस्थ अधिकारी ही उपलब्ध है, तो सम्बंधित विभाग का प्रभारी उप शासन-सचिव समिति का एक सदस्य होगा।”

\* उपरोक्त संशोधन वि सं 5 (8) DOP/ A-II/77 Pt V दिनांक 15 जून 1979—जी एस आर 21 द्वारा “सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली” की अनुसूची II के भाग (5) में तथा जी एस आर 22 द्वारा “अधीनस्थ कार्यालय नियमावली की अनुसूची I भाग (2) में प्रति स्थापित किया गया। राजस्थान-राजपत्र, विशेषांक, भाग 3 (ग) I दिनांक 16 जून 1979 में पृष्ठ 45-149 पर प्रकाशित।

XX वि सं एक 7 (6) DOP/A-II/ 75 Pt II दिनांक 21 जून 1979 द्वारा जोड़ा गया।

# राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम 1957<sup>1</sup>

[Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Staff  
Rules 1957]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्गीय स्थापन में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा सम्बन्धी शर्तों को विनियमित करने हेतु राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं —

## भाग (1) साधारण

1 संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होना—इन नियमों का नाम 'राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1957' ह, और ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2 वर्तमान नियमों एवं आदेशों का अतिष्ठान—इन नियमों के अन्तर्गत आनेवाले मामलों से सम्बन्धित समस्त वर्तमान नियम और आदेश [अतिष्ठित हो जायेंगे]<sup>2</sup>, किन्तु ऐसे वर्तमान नियमों और आदेशों के अनुसरण में की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के अधीन की गयी कार्यवाही समझी जाएगी।

परन्तु यह है कि—

(1) ये नियम राजस्थान राज्य के पुनर्गठन पूर्व की सेवाओं के एकीकरण की प्रक्रिया में अधीनस्थ कार्यालयों में मन्त्रालयिक पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति पर, जो कि सेवाओं के ऐसे एकीकरण को विनियमित करने वाले नियमों और सरकार के आदेशों के अनुसार हो लागू नहीं होंगे,

(11) ये नियम राज्यपुनर्गठन अधिनियम के अधीन नये राजस्थान राज्य की भावित पुनर्गठन-पूर्व के बम्बई तथा मध्यभारत राज्यों तथा तत्कालीन अजमेर राज्य के कमचारियों के एकीकरण की प्रक्रिया में अधीनस्थ कार्यालयों में मन्त्रालयिक पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

1 नियुक्ति (ग) विभाग विनियम स F 10(1) App'ts (A)/55 दिनांक 10 मई 1957 द्वारा राजस्थान राजपत्र, साधारण, भाग 4 (ग), दिनांक 20 जून 1957 को प्रथमबार प्रकाशित। अप्राधिकृत हिंदी अनुवाद।

2 शब्दावली "एतद्द्वारा अतिष्ठित किये जाते हैं" के स्थान पर प्रतिस्थापित।  
विनियम स F 7(18) नियुक्ति (डी)/59 दिनांक 28-7-1961

3 स्थापन की प्रास्थिति (Status of the Staff)—इस स्थापन की प्रास्थिति लिपिक वर्गीय (मन्त्रालयिक) सेवा है।

4 परिभाषाएँ—जब तक कि किसी विषय या सदस्य में कोई बात अथवा अपेक्षित न हो इन नियमों में—

(क) “नियुक्ति प्राधिकारी से अभिप्रेत है—विभागाध्यक्ष या सरकार की अनुमति से विभागाध्यक्ष द्वारा स्थापन में नियुक्ति करने के अधिकार प्रदत्त ऐसा अधिकारी, उसे प्रदत्त प्राधिकार की सीमा तक।

औरतु यह है कि—जिसाधीन कार्यालयों के कार्यालय अधीनस्थ प्रथम श्रेणी तथा आशुलिपिक प्रथम श्रेणी के सम्बन्ध में नियुक्तिप्राधिकारी राजस्वमण्डल होगा।

- (ख) “आयोग” से राजस्थान लोकसेवा आयोग अभिप्रेत है,
- (ग) ‘सीधीभर्ती (direct recruitment) स पदोन्नति या स्थानान्तर द्वारा के अतिरिक्त नियम 7 में वर्णित भर्ती अभिप्रेत है
- (घ) ‘सरकार’ और ‘राज्य’ से क्रमशः राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य अभिप्रेत है
- (ङ) “विभागाध्यक्ष” से अधीनस्थ कार्यालय के सम्बन्ध में सरकार के अतिरिक्त सर्वोच्च प्रशासनिक प्राधिकारी से अभिप्रेत है,
- (च) ‘अनुसूची’ से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है,
- (छ) ‘स्थापन (स्टॉफ) से विभागाध्यक्ष के अधीन अधीनस्थ कार्यालय या कार्यालयों में यथास्थिति, लिपिक वर्गीय स्थापन से अभिप्रेत है,
- (ज) अधीनस्थ कार्यालय से सचिवालय, या राज्य विधानसभा या उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों या लोक सेवायांग के कार्यालय के अतिरिक्त सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी कार्यालय से अभिप्रेत है,

4(स) “कनिष्ठ डिप्लोमा कोस” से राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा कनिष्ठ डिप्लोमा दिये जाने के लिये आयोजित सचिवालय तथा व्यापार प्रशिक्षण विषय के कनिष्ठ डिप्लोमा पाठ्यक्रम (कोस) से, या ऐसे ही किसी समान डिप्लोमा से अभिप्रेत है, जो भारत में किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता हो और जो सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से इसके तत्समान मान लिया गया हो,

वि स एफ ५ (1) DOP/A-II/78 G SR 13 दिनांक-18.4.1978 द्वारा जोड़ा गया।

3 वि स एफ 7(10) कर्मिक (क-II)/74 दि 10.2.1975 द्वारा प्रतिस्थापित।

4 वि स एफ 10(1) नियुक्ति (क)/55 दि 14-7-1962 द्वारा जोड़ा गया।

5(अ)अधिष्ठायी नियुक्ति (Substantive Appointment)—मे इन नियमों के अधीन विहित भर्ती के तरीका में से किसी द्वारा ममुचिन चयन के बाद किसी अधिष्ठायी रिक्तस्थान पर इन नियमों के प्रावधानों के अधीन की गई नियुक्ति अभिप्रेत है और इसमें परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन (प्रोवेशनर) के रूप में नियुक्ति सम्मिलित है जो परिवीक्षा काल की समाप्ति पर पुष्टीकरण द्वारा अनुसरित हो।

टिप्पणी—“इन नियमों के अधीन विहित भर्ती के तरीका में से किसी” शब्दावली में आवश्यक अस्थाई नियुक्तियाँ (urgent temporary appointments) के अतिरिक्त, सेवा के प्रारम्भिक गठन पर या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक के अधीन बनाये गये विही नियमों के उपबन्धा के अनुसार की गई भर्ती सम्मिलित होगी।

6(ट) “सेवा” (Service) या “अनुभव” (Experience), जहाँ कहीं इन नियमों में एक सेवा से दूसरी में या उसी सेवा में एक श्रेणी (बैंडगरी) से दूसरी में या वरिष्ठ पदों पर अधिष्ठायी रूप से ऐसे पदा को धारण करने वाले व्यक्ति के मामले में, पदान्ति के लिये एक शत के रूप में विहित है, उसमें वह अवधि भी सम्मिलित होगी, जिसमें उस व्यक्ति ने अनुच्छेद 309 के परतुक के अधीन बने नियमों के अनुसार नियमित भर्ती के बाद ऐसे पदों पर लगातार कार्य किया है और इसमें वह अनुभव भी सम्मिलित होगा, जो उसने स्थानापन्न, अस्थाई या तदथ (एडहॉक) नियुक्ति द्वारा अर्जित किया है, यदि ऐसे नियुक्ति पदान्ति की नियमित पक्ति में की गई हो और वह स्थान पूर्ति के लिये या आकस्मिक (अवसर) प्रकार की या किसी विधि के अधीन अवैध नहीं हो तथा उसमें किसी वरिष्ठ कमचारी का अतिष्ठन (Supersession) अन्तर्लित न हो, सिवाय जब कि—या तो विहित शैक्षणिक और अन्य योग्यताओं की कमी, अयोग्यता (unfitness) या योग्यता (मेरिट) द्वारा अचयन या सम्बंधित वरिष्ठ कमचारी के दोष (default), 7[या जब ऐसी तदथ या आवश्यक अस्थाई नियुक्ति वरिष्ठता सह-योग्यता के अनुसार थी], के कारण से ऐसा अतिष्ठन हुआ हो।

टिप्पणी—सेवा के दौरान अनुपस्थिति, जैसे—प्रशिक्षण और प्रतिनियुक्ति आदि, जो राजस्थान सेवा नियम के अधीन कर्तव्य (duty) माने जाते हैं, भी पदोन्नति के

5 वि स एफ 7(3) DOP (A II) 73 दि 5-7 1974 तथा दि 11-2-1975 के शुद्धिपत्र द्वारा निविष्ट।

6 वि स एफ 6(2) नियुक्ति (क II) 71-1 दिनांक 9 10 1975 द्वारा निविष्ट तथा दि 27-3-1973 से प्रभावशील।

7 वि स एफ 6(2) नियुक्ति (क-II) 71 दि 13-7-1976 द्वारा निविष्ट तथा दि 1-10 1975 से निविष्ट समझा जावेगा।

लिये आवश्यक न्यूनतम अनुभव या सेवा की संगणना के लिये सेवा के रूप में संगणित की जावेगी।

5 निवचन (व्याख्या)—जब तक सदभ से अथवा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम स 8) इन नियमों के निवचन के लिये उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निवचन के लिये लागू होता है।

### भाग-(2) सर्ग (कंडर)

5 स्थापन की सत्था (Strength of the Staff)---(1) स्थापन की सरया उतनी होगी जितनी सरकार समय समय पर तय करे,

परंतु यह है कि—किसी रिक्त स्थान को नियुक्ति प्राधिकारी खाली रख सकेंगे या सरकार (उसे) प्रास्थगित रख सकेगी, जिसके लिये किसी व्यक्ति को कोई प्रतिकर (मुभावजा) पाने का अधिकार नहीं होगा।

(2) स्थापन में <sup>10</sup>[निजी सहायक और] आशुलिपिका का एक नवग तथा निम्न लिखित श्रेणियों के पदों में स एक या अधिक का एक साधारण सवग होगा, जो सरकार समय समय पर तय करे—

सहायक पजीयक राजस्व मण्डल <sup>1</sup>

प्रशासनिक अधिकारी या स्थापन अधिकारी, <sup>2</sup>

अधीक्षक श्रेणी प्रथम,

<sup>10</sup>[निजी सहायक, <sup>3</sup>। विलोपित]

अधीक्षक श्रेणी द्वितीय,

परिवेक्षक (सुपरवाइजस), <sup>4</sup>

[X X X] <sup>5</sup>

सहायक (एसिस्टेंटस) <sup>6</sup>

1 वि स एफ 3(3) Apptts (A-II)/73, दिनांक 11-5-1974 द्वारा निविष्ट।

2 वि स एफ 3(7) DOP (A II) 75, दिनांक 20-9-1975 द्वारा निविष्ट तथा दिनांक 1-5-1975 से प्रभावशील।

3 वि स एफ 3(2) DOP (A-II)/77, दिनांक 26-10-77 द्वारा निविष्ट।

4 वि स एफ 10 (1) Apptts (A)/55 2-2-1973 के खण्ड 22 द्वारा निविष्ट।

5 वि स एफ 10 (1) Apptts (A)/53, दि 16-6-1959 द्वारा शब्द "लेखाकार" विलोपित किया गया।

6 वि स एफ 10(1) Apptts (A)/55 दि 28-10-1967 के खण्ड 24 द्वारा जोड़ा गया।

मुख्य लिपिक (हैडक्लर्क), विभागाध्यक्ष कार्यालयों में  
मुख्य लिपिक (अथ कांयलियों में, कार्यालयों के संकलनों के प्रभारी लिपिक)  
लेखा लिपिक

अवेक्षक, स्थानीय निधि अवेक्षण विभाग,

कनिष्ठ अवेक्षक, स्थानीय निधि अवेक्षण विभाग<sup>9</sup>

<sup>10</sup> [आधुनिक (स्टेनोग्राफर क्लर्क)<sup>8</sup>] विलोपित

वरिष्ठ लिपिक (U D C)

कनिष्ठ लिपिक (L D C)

टिप्पणी—उपनियम (2) में वर्णित श्रेणियों में से किसी पर प्रभावशील वेतनमान में अधीनस्थ कार्यालय के किसी मन्त्रालयिक पद को इन नियमों के प्रयोजनार्थ उसी श्रेणी का पद माना जावेगा।

### भाग (3) भर्ती (Recruitment)

7 भर्ती के तरीके—(1) इन नियमों के लागू होने के बाद स्थापन के लिए भर्ती (निम्न प्रकार से) की जायेगी—

<sup>1</sup>[(क) आधुनिकों के सबग में आधुनिक द्वितीय श्रेणी के रूप में इन नियमों के भाग (5) के अनुसार तथा इन नियमों से सलग्न अनुसूची I के भाग II में विहित अहता-परीक्षा के द्वारा,]

<sup>2</sup>[(ख) कनिष्ठ लिपिक (L D C) के साधारण सबग में, उनमें से जो जूनियर डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करते हैं या कर चुके हैं। दोष रित्तिया यदि कोई हो, आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरी जावेगी।]

7 वि स एफ 1(13) App'ts (A II)/62, दि 19-6-1968 द्वारा जोड़ा गया।

8 वि स एफ 10(1) App'ts (A)/55, दि 14-7-1962 द्वारा निविष्ट।

9 वि स एफ 1(13) App'ts (A-II)/62, दि 19-6-1968 द्वारा निविष्ट।

10 वि स एफ 3(4) DOP (A 2)77 दिनांक 15-3-78 द्वारा निविष्ट तथा विलोपित।

1 वि स एफ 3 (4) DOP/A-2/77 दिनांक 15-3-1978 द्वारा निम्न के लिए प्रति स्थापित ' (क) आधुनिकों के सबग में आधुनिक श्रेणी तृतीय के रूप में चयन द्वारा"

2 वि स F 10 (1) App'ts (A)/55 दिनांक 14-7-1962 द्वारा ' (ख) साधारण सबग में कनिष्ठ लिपिक के रूप में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा और' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।



॥[ परंतु यह है कि—“राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व पथ) मय वागान, सिंचाई, जलप्रदाय तथा आयुर्वेदिक विभागकाय-प्रभारित कमचारी सेवा नियम 1964” से आवृत्त किसी विभाग में या कामिक विभाग में सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसे विभाग में दैनिक मजूरी या आयस्मिक काय प्रभारित आधार पर पहले नियोजित व्यक्तियों को जो ऐसे पदों पर जो आरम्भ में स्वीकृत किये गये थे और नियमित स्थापन पर लाये गये थे आमेलित (adsorbed) किया जा सकेगा और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छानबीन (स्क्रीनिंग) के बाद केवल एक बार उन पदों पर नियुक्त किये जा सकेंगे, जिनको प्रशासनिक विभाग में सरकार द्वारा समान घोषित किया जाय, यदि उन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को, जिस में काय प्रभारित पदा को आरम्भिक रूप से नियमित पदा में परिवर्तित किया गया था कम से कम दो वर्ष की सेवा पूरी करली हो और उनकी उपयुक्तता की सरकार द्वारा आदेश में दिये गये साधारणतया या विशेषतया निर्देशों के अनुसार परख (जाच) कर ली गई हो।

स्पष्टीकरण—“काय प्रभारित कमचारियों” का वही अर्थ है, जैसा कि राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) मय वागान, सिंचाई जलप्रदाय तथा आयुर्वेदिक विभाग काय भारित कमचारी सेवा नियम 1964 में परिभाषित किया गया है।

४[ परंतु यह है कि खान एवं भूगर्भ विभाग में नाकेदार (नियमित या कायप्रभारित) के रूप में पहले से नियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कनिष्ठ लिपिका के पद पर जो पद मूलतः इस प्रकार स्वीकृत थे और कनिष्ठ लिपिक के पदा में परिवर्तित किय गये या ऐसे पदा को नियमित स्थापन पर ले लिया गया, यदि वे संकण्ठरी परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ह, तो इन नियमों के अधीन विहित उच्च आयु सीमा दृक्कणति व राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा का शिथिलीकरण करत हुए आमेलित (adsorbed) तथा नियुक्त किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—“काय प्रभारित कमचारी” से किसी निर्माण काय मूल तथा सभाल दोनों के निष्पादन और/या देखभाल, विभागीय श्रमिक भण्डार, मशीनरी

3 वि स एफ 3 (4) DOP A-II/75 दि 26 6 1976 द्वारा निविष्ट

4 वि स एफ 3 (1) कामिक (क-2) 76 GSR 84 दिनांक 30 8 1978 द्वारा निविष्ट जो दि 1 10 1973 से 31 12 1975 तक प्रवृत्त रहेगा।

तथा निमाणकार्य आदि की देखभाल के लिये दैनिक या मासिक आधार पर भुगतान पाने वाले वास्तव में नियोजित किसी कमचारी अभिप्रेत ह ।

5 [ (ग) वरिष्ठ लिपिकों के पद पर 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा । ]

5 वि स एफ 3 (3) DOP/क-2/75 दिनांक 16 जनवरी 1978 द्वारा निम्न के लिए प्रति स्थापित—

§ [ (ग) वरिष्ठ लिपिका के पदा पर 100% पदोन्नति द्वारा (67% वरिष्ठता सह योग्यता से और 33% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से, सम्बन्धित विभाग के उन कनिष्ठ लिपिका में से

जिन्होंने कनिष्ठ लिपिक के रूप में सात वर्ष की सेवाये पूरी करली हो । )

इन नियमों में किसी बात के होते हुए, ऐसे व्यक्ति भी जो सीधी भर्ती द्वारा वरिष्ठ लिपिक के पद पर इस सशोधन की दिनांक तक नियुक्त किये जा चुके हैं, उपरोक्त खण्ड के अधीन सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरे जाने वाले 33 प्रतिशत के कोटा के विरुद्ध भर्ती के लिये पात्र (eligible) होंगे । यदि वे दा प्रयासों (attempt) में सफल नहीं होते हैं, तो उनकी सेवाय तुरन्त समाप्त (terminated) कर दी जावेगी, या यदि उन्होंने तीन वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करली हो और उनका आचरण सन्तोषजनक पाया गया हो, तो उनको वरिष्ठता के आधार पर कनिष्ठ लिपिक का पद दिया जा सकेगा, यदि यह उनको स्वीकार्य हो । ऐसे व्यक्तियों को अधिनेय (surplus) कमचारी माना जावेगा और राजस्थान सिविल सेवाय (अधिशेष कमचारियों का आमेलन) नियम 1969 के अधीन उनका आमेलित किया जायेगा । ]

वि स एफ 3 (11) कामिक (क-2)/74 दिनांक 3 2 1975 द्वारा निम्न के स्थान पर उपरोक्त § प्रतिस्थापित—

(ग) वरिष्ठ लिपिकों के पद पर, आंशिक रूप से उन में से जिन्होंने जूनियर डिप्लोमा कोर्स में 65% या अधिक अंक प्राप्त किये हो या 29 मार्च 1965 तक स्वयंकारों में से और आंशिक रूप से कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति द्वारा, 1 2 के अनुपात में ।

स्पष्टीकरण—दिनांक 3 3 1962 से निर्वाचन पर्यवेक्षकों (इलेक्शन सुपरवाइजर्स) के पदों को वरिष्ठ लिपिक के रूप में पुनर्पदनामांकित करने पर उनमें से भी इन पदों का भरा जायेगा ।

टिप्पणी—वरिष्ठ लिपिकों के सुवर्ग में पदोन्नति के अज्ञाता अथवा प्रकार से भरी जाने वाले पदों की सरया में यदि कोई रिक्त स्थान रहते हैं, तो उनको आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरा जावेगा ।

वि स एफ 10 (1) नियुक्ति (क)/55 दिनांक 16 5 1959 द्वारा नया खण्ड (ग) प्रथम बार जोड़ा गया था, जो इस प्रकार है—

(ग) वरिष्ठ लिपिका के पदों पर, आंशिक रूप से आयोग द्वारा आयोजित प्रति योगिता परीक्षा द्वारा तथा आंशिक रूप से कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति द्वारा ।”

(घ) प्रत्येक सवर्ग के अग्र पदों पर उसी में पदोन्नति द्वारा  
नियम 7(1) के परन्तुक

परन्तु यह है कि—

(1) किसी सवर्ग का कोई पद विभागाध्यक्ष की महमति में, दूसरे विभाग में उस पद के तत्समान पद धारण करने वाले व्यक्ति के स्थानान्तरण द्वारा भी भरा जा सकेगा।

<sup>6</sup>(2) (i) अस्थाई रूप से 1 9 1968 को या इससे पहले कनिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को स्पष्ट रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर तथा उनका कार्य सतोपप्रद पाया जाने पर<sup>7</sup> [1 9 1968 से] स्थायी बना दिया जावेगा।

कनिष्ठ लिपिक के रूप में कार्यरत एक व्यक्ति जिसका कार्य सतोपप्रद नहीं पाया जाता है, उसे सेवा से हटा दिया जावेगा—

(i) यदि उसने अस्थायी रूप से राज्य के कार्यवाहियों के सम्बन्ध में तीन वर्ष से कम के लिये सेवा की है, तो एक माह का नोटिस देते हुये,

(ii) यदि उसने तीन वर्ष से अधिक के लिये सेवा की है, तो राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अधीन) नियम 1958 में दिये गये तरीके का पालन करते हुये,

<sup>8</sup>(ii) कनिष्ठ लिपिक के पद पर 1 1 1962 का या इसके बाद परन्तु 31 10 1975 के पहले सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त व्यक्ति जो ऐसा पद या उच्चतर पद लगातार धारित कर रहे हों, इन नियमों के अधीन नियमित रूप से नियुक्त किये गए समझ जावेंगे,

6 वि स एफ 1 (18) Appis (A-II) 69 दिनांक 19 8 1969 द्वारा निम्न लिखित के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया—

(2) कोई व्यक्ति, जो एक जनवरी 1962 में पहले अस्थायी आधार पर सेवा में सम्मिलित हो गया था, सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों पर आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण कर लने पर एक कनिष्ठ लिपिक या एक कनिष्ठ लिपिक के रूप में, जैसा भी हो, स्थायी बना दिया जावेगा।<sup>9</sup>

7 वि स एफ 18 (2) नियुक्ति (क-2) 69 दि 16 2 1976 द्वारा निविष्ट।

8 वि स एफ 3 (3) DOP/A-II/75 दिनांक 16 1 1978 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—

\*“(ii) एक व्यक्ति जो सीधी भर्ती से भरे जाने वाले किसी पद के विरुद्ध एक जनवरी 1962 के पहले कनिष्ठ लिपिक के रूप में अस्थायी रूप में नियुक्त किया गया था, और—

[ क्रमशः

# नियम 7 ] राजस्थान अधीनस्थ न्यायलय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम [ 17

परन्तु यह है कि वह इन नियमों की अनुसूची I के भाग I में विहित पाठ्यक्रम के अनुसार हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन राज्य संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करता है/करती है, जो इन नियमों के प्रवृत्त होने के बाद केवल दो बार के लिए आयोजित की जावेगी। यदि वह दो प्रयासों में सफल नहीं होता/होती है, उसकी संवायें आगे के लिए समाप्त (टर्मिनेट) कर दी जायगी या उसने तीन वर्षों में अधिका की सेवा कर ली हो और उसका आचरण सन्तोषप्रद पाया जाय, तो उसे करणता के आधारों पर कनिष्ठ लिपिक का पद प्रस्तावित किया जा सकता है, यदि वह (पद) उसको स्वीकार्य हो। ऐसे व्यक्ति अधिशेष कनिष्ठ लिपिक के रूप में माने जावेंगे तथा राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कर्मचारियों) अधिनियम 1969 के अधीन अन्तर्लित किये जावेंगे।]

पिछले पेज से—

- (क) जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका, या
- (ख) (उस) कथित दिनांक के बाद (उस) कथित परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ

—(उसे) कनिष्ठ लिपिक के रूप में पुष्ट (कनफर्म) कर दिया जावेगा, परन्तु (शर्त) यह है कि—वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों के अधीन जो सरकार तय कर, तत्पश्चात् एकबार आयोजित अगली परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है।

विज्ञप्ति सं एफ 10 (1) नियुक्ति (क) /55 भाग XXV दिनांक 10 5 1972 द्वारा निम्न के स्थान पर उपरान्त "प्रति स्थापित—

- (ii) 1 1 1962 से पहले कनिष्ठ लिपिका के रूप में अस्थायी रूप से भर्ती किये गये व्यक्तियों को, जो—
- (क) उपरोक्त दिनांक के बाद नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका हो, या
- (ख) कथित परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ हो,—केवल (1) जूनियर डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण कर लेने पर जिसमें कम से कम 65 प्रतिशत में क प्राप्त किये हो, या
- (2) आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर—

पुष्ट (कनफर्म) कर दिया जावेगा।”

<sup>9</sup>[(3) सम्बन्धित नियुक्ति-प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के नियम 9 के अधीन विनिश्चित किये गये कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त स्थानों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत, उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से [पदोन्नति द्वारा] भरे जाने के लिए आरक्षित रखा जायेगा, जो सम्बन्धित विभाग में पांच वर्ष तक सेवा कर चुके हों और इन नियमों द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद के लिये विहित शैक्षणिक अर्हताएँ रखते हों।]  
[× × विसोपित<sup>10</sup>]

<sup>11</sup>(4) राज्य बीमा विभाग के साधारण सवर्ग में पयवधकों (सुपरवाइजर्स) के पदों को 100 प्रतिशत उसी सवर्ग में से तीन वर्ष के लिये 'सहायक' के रूप में कार्यरत सहायकों में से पदोन्नति द्वारा भरा जावेगा।

<sup>11</sup>(5) [विलापित × × ×]

9 वि स एफ 11 (6) DOP/ १-2/76/GSR 2 दिनांक 30 मार्च 1978 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित राजपत्र में दि 6 4 1978 का प्रकाशन तथा × शुद्धि पत्र दिनांक 12 7 1978 द्वारा संशोधित—

(3) प्रत्येक विभाग में कनिष्ठ लिपिकों के पदों के कुल रिक्त स्थानों का 10 प्रतिशत उन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्तियों के लिये सुरक्षित होगा, जिन्होंने मेट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और जो अभ्यष्टाधी हैं तथा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण (Qualified) हो जाते हैं परंतु शत यह है कि— ऐसे उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न होने पर इस प्रकार सुरक्षित रिक्त स्थान भ्रामों से जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु प्रायिक (सामान्य usual) रूप से भरे जावेंगे।

[उपरोक्त (3) वि स एफ 1 (18) नियुक्ति (क-2) 63 दिनांक 17 3 1964 द्वारा जोड़ा गया था]

10 वि स एफ 11 (6) DOP/ A 11 /76 GSR 29 दिनांक 19 सितम्बर 1978 द्वारा विलोपित, जो इस प्रकार था—

“और हिंदी में 20 शब्द या अंग्रेजी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुका हो। जिला स्तर पर एक संयुक्त टंकण परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसकी देखभाल एक समिति द्वारा की जावेगी जिसमें जिलाधीश द्वारा मनोनीत दो जिला स्तरीय अधिकारी होंगे तथा जिला नियोजन अधिकारी उसके मयोजक होंगे। जयपुर में यह टंकण परीक्षा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्वयं के कार्यालय तथा भुर्यावास पर स्थित अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के लिये जहाँ आवश्यक समझा जाव निदेशक नियोजन से परामर्श करके, आयोजित की जावेगी।”

11 - वि स एफ 2 (1) DOP/AII/ 76 GSR 46 दिनांक 29 सितम्बर 1978 द्वारा परंतु (4) प्रतिस्थापित किया गया तथा

- 12(6) राजस्व मण्डल के सहायक पंजीयक का पद राजस्व मण्डल कार्यालय, जिलाधीन कार्यालयों, उपनिवेश तथा भू प्रबंध विभागा के अधिष्ठायी प्रथम श्रेणी के अधीक्षका में से चयन द्वारा भरा जावेगा।
- 13(7) इन नियमों में से कुछ भी नियुक्ति प्राधिकारी को आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के पदों पर अधिष्ठायी नियुक्ति करने से प्रवारित नहीं करेगा,

परंतु 5 विलोपित किया गया, जो निम्न प्रकार से थे—वि स एफ 10 (1) नियु (क) 55 भाग 32 दिनांक 2 3 1973 द्वारा जोड़े गये थे—

- [(4) राज्य बीमा विभाग के साधारण सबग म पयवक्षको (सुपरवाइजर्स) के पदा को उसी सबग में से भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व-विद्यालय या सरकार द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय की उपाधि (डिग्री) के समकक्ष घोषित किये गये किसी विदेशी विश्व विद्यालय के स्नातक में से जिन्होंने बरिष्ठ लिपिकों के रूप में तीन वर्ष की सेवा की हो, पदोन्नति द्वारा भरा जावेगा।

- (5) राज्य बीमा विभाग में उस विभाग में पयवक्षको के पदा के प्रारम्भिक सृजन से तुरंत पहले अनुभाग प्रभारी और निरीक्षक के पदा का धारण करने वाले व्यक्ति, येन केन (जैसे जैसे) पयवक्षका के रूप में नियुक्त किये जान के लिये पान (eligible) हाने यदि वे मेट्रिक उत्तीर्ण तथा बरिष्ठ लिपिकों के रूप में तीन वर्ष की सेवा सहित हो और कम से कम 7 वर्ष की कुल सेवा सहित हा (चतुर्थ श्रेणी सेवा के अतिरिक्त) या खण्ड (4) में वर्णित योग्यताएं और अनुभव रखत हो।]

- 12 वि स एफ 3 (3) DOP (A—II) /73 दिनांक 11 5 1974 द्वारा जोड़ा गया।

- 13 वि स एफ 3 (4) DOP/ A-2/ 77 दिनांक 15 3 78 द्वारा निम्न के लिए प्रतिस्थापित—

- (7) इन नियमों में से कुछ भी नियुक्ति प्राधिकारी को आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के पदा पर रिक्त स्थानों के उपलब्ध होने की सीमा में रहते हुए उन व्यक्तियों में से जो आशुलिपिकद्वितीय श्रेणी या आशु टकक (स्टेनोग्राफिस्ट) के पदों को अस्थायी रूप में या तदर्थ (एडहाक) रूप में सम्बंधित विभाग में 15 9 1972 को धारण कर रहे थे और जिनका कार्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सतोषजनक पाया गया है और उस दिनांक को (निम्नांकित) अनुभव रखते हो, अधिष्ठायी नियुक्ति करने से प्रवारित (Preclude) नहीं करेगा—
- (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्व विद्यालय से आशुलिपि विषय के साथ या आशुलिपि (शोटहण्ड) में डिप्लोमा धारण करने वाला स्नातक,

जयति रितस्थान उपसध्य हा तथा दितां 1 1 1976 को या द्यते  
पहले सम्बन्धित विभाग म या दूमरे विभाग म स्थानांतरित कर न्ये

या-(ग) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बाड से उत्त्तर माध्यमिक (हायर  
मके-डरी) परीक्षा या तत्समा परीक्षा, जिमम शोट हैण्ड तक विषय  
हो उत्तीर्ण की हो और प्रागुनिपिक द्वितीय श्रेणी या प्रागुटंकक के  
रूप म दा यप की सेवा बिना बिनी सेवाभग (breaks) के, यनि कोई  
हा, कर चुका हो,<sup>1</sup>

स्पष्टीकरण—एक प्रश्न उठा है कि—क्या एक तम व्यक्ति को इस उपबन्ध के  
अधीन पात्र माना जावगा या नहीं जिसन बिनी मायता प्राप्त शिक्षा बाड या भाट  
म विधि द्वारा स्थापित किसी विषय विद्यालय से इटरमीजिएट परीक्षा पास की हो  
और असल मे शाट हैण्ड व टक्कन परीक्षा ऐसे बोर्ड या विश्वविद्यालय म उस गति से  
उत्तीर्ण की हो, जा राजस्थान माध्यमिक बाड की हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिए  
वैकल्पिक विषय के रूप मे विहित (गति) से कम नहीं है ।

इस प्रकरण की परीक्षा की गई और यह स्पष्ट किया जाता है कि—एक व्यक्ति  
जा ऐसी ग्रहता (योग्यता) या हायर सेकेंडरी परीक्षा से उत्त्तर (योग्यता) मय  
आवश्यक शोट हैण्ड तथा टाइट परीक्षा के रखते हैं उनको भी परन्तु 7 के बधित  
खण्ड (ख) म यणित योग्यता पूरी करने वाले समझा जावगा ।

या-(ग) के प्रागुलिपिक द्वितीय श्रेणी या प्रागुलिपिटंकक जा 15 9 1972 का<sup>2</sup>  
एसी दो यप की सेवा कर चुक हा, बिना किसी सेवाभग (breaks) के  
यदि कोई हो और जा निमुक्ति प्राधिकारी द्वारा सन्तोपप्रद कार्य करने के  
लिए प्रमाणित किये गये हा और<sup>3</sup> इन नियमों मे विहित ग्रहता  
परीक्षा (Qualifying Examination) 10 5 1972 के पहले  
उत्तीर्ण कर चुके हो या राजस्थान सचिवालय मन्त्रालयिक सेवा नियम  
1970 की अनुसूची II के भाग II मे विहित प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण  
करती हो या अनुसूची I के भाग III मे बखित प्रतियोगिता परीक्षा  
अथवा शोट हैण्ड मे या हिन्दी शोट हैण्ड में अथवा और हिन्दी की  
टक्कन परीक्षाओं के अतिरिक्त<sup>4</sup> [प्रथम उपसध्य अवसर पर एक प्रयास में  
उत्तीर्ण कर सके ।]

1 उपरोक्त परन्तु 3 वि स 3 (3) DOP ( A-II )/73 दिनांक  
13 12 1974 द्वारा जोडा गया था ।

2 उपरोक्त स्पष्टीकरण वि स 3 (3) DOP/A-II/73 दिनांक  
3 4 1975 द्वारा निविष्ट किया गया था ।

3 शुद्धि पत्र वि स एक 3 (3) DOP/A II/ 73 दिनांक 28 2 1975  
द्वारा शब्दावली "सम्बन्धित विभाग में" विलोपित की गई ।

गये व्यक्तियों में से जो आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के पत्र धारित कर रहे थे और जिनका कार्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सतोषप्रद पाया गया था और जो ऐसी दिनांक को निम्नांकित अहताओं में से एक पूरी करते हैं, (ऐसी नियुक्ति की जाए।) —

- (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उपाधि (स्नातक) परीक्षा या इसके समान अधिसूचित अहताओं में आशुलिपि के एक प्रश्न पत्र के उत्तीर्ण की हो, —या—
- (ख) किसी मायता प्राप्त माध्यमिक परीक्षा बोर्ड से हायर सेकेंडरी की परीक्षा में आशुलिपि के एक प्रश्नपत्र के उत्तीर्ण की हो या—हूँ व मा लोका प्रशासन संस्थान या भाषा विभाग द्वारा आयोजित आशुलिपि परीक्षा या व्यवस्था एक पद्धति आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण की हो या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित आशुलिपि की डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

टिप्पणी—(1) वर्ष 1958 से पूर्व प्राप्त किया गया मायता प्राप्त स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र/डिप्लोमा हायर सेकेंडरी बोर्ड प्रमाण पत्र के समकक्ष माना जावेगा और इस परतुक के खण्ड (ख) के अधीन वर्णित अहता पूरी करना माना जावेगा,

(2) वे व्यक्ति जो हायर सेकेंडरी परीक्षा से उच्चतर अहताओं, में आवश्यक आशुलिपि तथा टंकण परीक्षा के, धारण करने हैं उनको इस परतुक के खण्ड (ख) के, अधीन वर्णित अहता पूरी किये हुए माना जावेगा।]

<sup>14</sup> [(8) 1-1-1976 के पूर्व आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के रूप में अस्थाई तौर से नियुक्त व्यक्ति, जो परतुक (7) से आवृत नहीं होते हैं, उनको रिक्तस्थान उपलब्ध होने पर और उनके द्वारा सरकार द्वारा मायता प्राप्त संस्थान द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिये विहित स्तर की हिन्दी तथा अंग्रेजी में आशुलिपि व टंकण की गति परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नियमित रूप से नियुक्त आशु

- 4 वि स एफ 3 (3) DOP/AII/73 दि 20 9 1975 द्वारा निविष्ट एवं दिनांक 19 12 1974 से प्रभावशील (लागू)।
- 5 वि स 3 (3) DOP/AII/73 दिनांक 28 2 1975 द्वारा 'गुद्धि पत्र' के अनुसार शब्दावली 'भी उत्तीर्ण कर चुका हो' (have also passed) के स्थान पर प्रति स्थापित
- 14 वि स एफ 3 (4) DOP/A-2/77 दिनांक 15-3 78 द्वारा नया (8) जोड़ा गया तथा (8) व (9) को क्रमशः (9) व (10) पुनर्व्यवस्थित किया गया।



लिपिक द्वितीय श्रेणी सम्मानित जावेगा । उपरोक्त गति परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये दो अवसर से अधिक नहीं दिये जावेंगे । इन नियमों के प्रवृत्त होने के बाद ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्त दोनों परीक्षाओं में नहीं बैठते हैं या अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, वे यथास्थिति, प्रतिवर्तित होने या सेवा समाप्ति के दायी (भागी) होंगे ।]

15[(8 क) आधुनिकीकरण के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों तथा जो 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हों और परतुक (7) के अधीन आवृत्त नहीं होते हैं, तथा आधुनिकीकरण के रूप में रिक्तस्थान उपलब्ध होने पर तथा हायर सेवे द्वारा परीक्षा के लिये विहित स्तर की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित हिंदी आधुनिकीकरण तथा टंकण या अंग्रेजी आधुनिकीकरण तथा टंकण की गति परीक्षा, यथास्थिति, उत्तीर्ण करने पर उनको नियमित रूप से नियुक्त किया जावेगा । इन नियमों के प्रवृत्त होने के बाद ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्त दोनों परीक्षाओं में प्रवेश नहीं लेते हैं या उत्तीर्ण होने में असफल रहते हैं, तो उनको आधुनिकीकरण के रूप में उनकी अस्थायी नियुक्ति के पहले धारित पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जावेगा या अन्य मामलों में उनकी सेवार्य, यथास्थिति समाप्त कर दी जावेगी ।]

[(1) 16[परतुक यह है कि—(1) किसी विशिष्ट वर्ष में आधुनिकीकरण प्रथम श्रेणी के रिक्त स्थानों का 50 प्रतिशत द्वितीय श्रेणी आधुनिकीकरणों में से 17[जो 10-5-1972 के पहले या 15-3-1978 के बाद अहता परीक्षा या 15-3-1978 के पहले प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों, या नियम 7 के परतुक 7 के अधीन उपरोक्त परीक्षाओं में बैठने से मुक्त कर दिये गये हों और] कम से कम जो आधुनिकीकरण द्वितीय श्रेणी के रूप में सात वर्ष सेवा कर चुके हों वरिष्ठता-सह-मायता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जावेंगे, और

(ii) लघुतर (छांट) कार्यालयों में जहाँ रिक्तस्थान थोड़े हैं, निम्नांकित चक्रीय क्रम का अनुसरण किया जाएगा —

- 1 पथम रिक्तस्थान, उसके लिये जिसने इन नियमों के नियम 15 के उपनियम (7) के अधीन वर्णित राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की हो,

15 वि स एफ 3 (13) DOP/क 2/73 दिनांक—27 दिसम्बर 1978 जोड़ा गया ।

16 वि स एफ 3 (4) DOA/A-11/77 दिनांक 15-3-78 द्वारा जोड़ा गया । (इस परतुक की कोई संस्था अस्तित्व में नहीं है ।)

17 वि स एफ 3 (4) DoP/A 11/77 G R 25 दिनांक 13-9-1978 द्वारा निविष्ट । (इसमें परतुक की संख्या (1) अस्तित्व में है, यह सही नहीं है)

2 अगला रिक्तस्थान, उसके लिये जिसे पदोन्नत करना है। यही चक्रीय कम दोहराया जायेगा।]

18(9) प्रशासनिक अधिकारी या स्थापन अधिकारी का पद विशेष चयन द्वारा उन व्यक्तियों में से भरा जावेगा, जो निम्नांकित विभागीय समूहों में और विभागों के ऐसे दूसरे समूहों में, जो सरकार समय समय पर परि वर्तित करे या गठित करे, कार्यालय अधीक्षक प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के पद धारण करते हों—

(क) विशेष समूह (Special Groups)—

- (i) चिकित्सा, परिवार नियोजन संगठन को छोड़कर—निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ तथा मेडिकल कालेजों,
- (ii) कृषि—कृषि विभाग, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन, भेड़ और ऊँट डेयरी/दुग्ध प्रदाय, सहकारिता तथा वन विभाग,
- (iii) अभियान्तरी (इंजीनियरिंग)—सावजनिक निमाण विभाग जन स्वास्थ्य अभियान्तरी विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्थान नहर परियोजना और नगर आयोजना विभाग,
- (iv) राजस्व—राजस्वमण्डल, भूप्रवच, जिलाधीश कार्यालय तथा उनि वर्शन ।

(ख) साधारण समूह—(General Groups)—

- (i) चिकित्सा विभाग का परिवार नियोजन संगठन—
- (ii) साधारण—राज्य के समस्त विभाग एवं विभाग के मामले में जा उपरोक्त समूहों में सम्मिलित नहीं है और जिसमें अधीक्षकों के पांच पद विद्यमान हैं, ऐसे विभाग में प्रशासनिक अधिकारी या स्थापन अधिकारी के पदों पर ऐसे विभाग के कार्यालय अधीक्षक प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी में से नियम 26 के उपनियम (1) के द्वितीय-परतुक में प्रसंगित समिति (कमटी) की मस्तुनियों पर चयन किया जावेगा। यदि ऐसे किसी विभाग में कार्यालय-अधीक्षकों के पांच पद उपलब्ध न हों तो जिन विभागों को प्रशासनिक विभाग के द्वारा कार्मिक विभाग की सहमति से विशिष्टकृत (Solicited) किये जावेंगे, उनके कार्यालय अधीक्षक प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी ऐसे पदों पर पदोन्नति के लिये पात्र होंगे।

19(10) व्यक्ति, जो प्रशासनिक अधिकारी या स्थापना अधिकारी का पद

18 वि स 3 (7) DOP/A II/75 दिनांक 20-9-1975 द्वारा जोड़ा गया और दिनांक 1-5-1975 में प्रभावशील तथा दि० 1-3-78 से पुनर्संस्थापित कर 8 का, 9 किया गया।

19 वि स एफ 3 (7) DOP/A II/75 दि० 20-9-1975 द्वारा जोड़ा गया तथा दि० 1-5-1975 से प्रभावशील।

इन नियमों के प्रभावशील होने पर अस्थायी या स्थानापन्न रूप में सहायक धारण कर चुके हैं और ऐसे पदों को सहायक धारण कर रहे हैं और उनके ध्यान के समय के नियमों या आदेशों में ऐसे पदों के लिये विहित प्रवृत्तियों और अनुभव रखते हैं, नियम 26 के उपनियम (1) के द्वितीय-परन्तुक में वर्णित ध्यान समिति (बोर्ड) द्वारा (उनकी) उपयुक्तता की परामर्श द्वारा नियुक्ति के लिये विचार करने का पाव होगा।

21 [10 × × विलोपित]

1[7-क इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी किसी (ऐसे) व्यक्ति की, जो आपातकाल के दौरान सेना/ वायुसेना/ जलसेना में सम्मिलित होता है, नियुक्ति, पदोन्नति, बर्हिष्ठा और पुनर्स्थापना आदि सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित किये गये आदेशों और निर्देशों के द्वारा विनियमित होंगे, परन्तु यह है कि— ये भारत सरकार द्वारा इस विषय में प्रसारित निर्देशों के अनुसार, पर्याप्त रूप से परिचित रहित, ही विनियमित होंगे।]

20 वि स एफ 3 (7) DOP/A II/ 75 दि 19-6-1976 द्वारा शब्दावली “दो वर्ष की अवधि के लिये” विलोपित।

21 वि स एफ 3 (4) DOP/A-2/77 दिनांक 15-3-78 द्वारा 9 के स्थान पर 10 पुनर्स्थापित तथा 10 विलोपित किया गया जो वि स एफ 3 (7) DOP/A II/76 दि० 30 3-1977 द्वारा जोड़ा गया था तथा निम्नलिखित था—

“(10) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी व व्यक्ति जो अस्थायी रूप से प्राशुलिपिक के रूप में सम्बन्धित विभाग में नियुक्त किये गये थे और 1-10-1976 को प्राशुलिपिक या प्राशु-टकर के रूप में कम से कम दस वर्षों की सेवा, बिना सेवा भगा के यदि कोई हो पूरी कर चुके हों, और खण्ड (ग) के परन्तुक 7 के अधीन विहित परीक्षा (टेस्ट) उत्तीर्ण नहीं की हो और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सतुष्ट रूप से कार्य करने के लिए प्रमाणित हों, (तो उनकी) इसके बाद खण्ड (ग) के परन्तुक 7 में विहित परीक्षा (टेस्ट) उत्तीर्ण करने का एक और अवसर दिया जावेगा। (ऐसे) व्यक्ति को जो कथित परीक्षा को उत्तीर्ण करने में असफल रहते हैं, कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया जावेगा, यदि वे ऐसी नियुक्ति के लिये इच्छुक हैं। यदि वे इस प्रकार नियुक्त किये जाने के इच्छुक नहीं हैं, तो उनकी सेवाएँ समाप्त किये जाने योग्य होंगी।”

1 वि स एफ 21 (12) नियुक्ति (ग)/55 भाग II दि० 29-8 1973 द्वारा निरिच्छ तथा दि 29-10 1963 या सम्बन्धित सेवा नियमों के प्रभावशील होने के दिनांक से प्रभावशील।

28 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये रिक्तियों का आरक्षण—(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार के ऐसे आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के अनुसार होगा, जो भर्ती के समय प्रवृत्त हो, भर्ती चाहे सीधी भर्ती से हो या पदोन्नति द्वारा।

(2) पदोन्नति के लिए ऐसी आरक्षित रिक्तियां केवल योग्यता<sup>2</sup> (मेरिट) द्वारा भरी जाएंगी।

(3) ऐसी आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन पात्र अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के सदस्य हैं, नियुक्ति के लिए उस क्रम से जिसमें उनके नाम उस सूची में हैं जो सीधी भर्ती के लिए आयोग द्वारा, उन पदों के लिए जो उसके अधिकार में हैं, और अन्य मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा और पदोन्नति के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, बनाई गई हो, इस पर ध्यान न देते हुए कि दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में उनका कौनसा स्थान (रैंक) है, विचार किया जाएगा।

4(4) सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए अलग से विहित रीन्टर तालिकाओं के अनुसार उनका कठोरतापूर्वक पालन करते हुए नियुक्तियां की जाएंगी। किसी विशिष्ट वष में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों, यथास्थिति, में से पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य क्रियाविधि के अनुसार भरी जाएंगी और पश्चात्तर्फी

2 वि स एफ 7 (4) DOP (A II) 73 दि 3-10-1973 द्वारा निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित—

8 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये रिक्तियों का आरक्षण—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये रिक्तियों का आरक्षण सरकार के ऐसे आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के अनुसार होगा जो भर्ती के समय प्रवृत्त हो।”

3 वि स एफ 7 (6) DOP (A II) 75 III दिनांक 31-10-1975 द्वारा शब्दावली “मेरिट क्रम मिनियोरिटी” के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।

4 विनप्ति न 7 (4) कार्मिक (न II) 73 दि 10-2-1975 द्वारा निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित—

“(4) यदि किसी वष विशेष में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में से पर्याप्त संख्या में पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो रिक्तियों को आगे नहीं ले जाया जायगा और प्रसामान्य क्रियाविधि के अनुसार भरी जाएगी।”

(अगले) वष मे तत्समान सख्या म अतिरिक्त रिक्तियाँ आरक्षित की जावेंगी। ऐसी रिक्तियों को इस प्रकार बिना भरी रहती हैं अगले भर्ती व तीन वर्षों तक कुल योग मे आगे लेजाई जावेंगी और तत्पश्चात् ऐसे आरक्षण वा अवसर हो जायेगा।

परन्तु यह है कि किसी सेवा के किसी अवग के पदों वा पदा के वा/अथवा/समूह मे, जिनमे पदोन्नति इन नियमों के अधीन वेक्स याप्यता(मेरिट) व आधार पर की जाती है रिक्तियाँ को आगे नहीं ले जाया जायेगा।

टिप्पणी—[X X विलोपित]

9 रिक्तियों का अधधारण (तय किया जाना) —(1) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष म अगले बारह महीना के दौरान प्रत्याशित रिक्त पदों की सख्या और प्रत्येक तरीके से भर्ती किए जा सकने वाले व्यक्तियों की सख्या तय करेगा। ऐसी रिक्तियों की पिछड़ी समाप्ति के बारह मास की समाप्ति के पहले ऐसी रिक्तियों को पुन तय किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित सेवा नियमों स सलभ अनुसूचीत व कोष्ठक 3 मे विहित प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक तरीके से भरी जाने वाली वास्तविक मर्या की सगणना करने मे, प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी एक यथोचित चर्रीय क्रम वा अनुसरण करेगा जो प्रत्येक सेवा नियमों मे विहित अनुपात के अनुसार प्नाप्ति के कोटा वा सीधी भर्ती के कोटा पर प्राथमिकता देते हुए होगा, जैसे—जहाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का प्रतिशत क्रमश 75 और 25 है, ता चर्रीय क्रम इस प्रकार होगा—

1 पदोन्नति से	2 सीधी भर्ती से	3 सीधी भर्ती से
4 सीधी भर्ती से	5 पदोन्नति से	6 " "
7 सीधी भर्ती से	8 सीधी भर्ती से	9 पदोन्नति से—

5 वि स एफ 7 (6) DOP (A II) 75 III दिनांक 31-10-1975 द्वारा शब्दावली—“मेरिट तथा सिनियोरिटी सह मेरिट दोनों और सिनियोरिटी सह मेरिट नहीं” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

6 वि स F 7 (18) नियुक्ति (क) 59 दि 28-7-1961 द्वारा विलोपित—“टिप्पणी—इन नियमों व प्रवृत्त होने के समय प्रभावशील ऐसे आदेशों की प्रतिलिपि अनुसूची I म दी गई है।”

1 विज्ञप्ति स एफ 7 (1) DOP (A II) 73 दि 16-10-1973 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—

“9 रिक्तियों का तय किया जाना—इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी वाषिक रूप से नवम्बर माह मे अगले कलेण्डर वष मे प्रत्याशित प्रत्येक अवग म रिक्तियों की सख्या और प्रत्येक तरीके से भर्ती किये जा सकने वाले व्यक्तियों की सख्या को तय करेगा।”

और इसी प्रकार आगे क्रमानुसार ।

210 राष्ट्रीयता (Nationality)—सेवा में नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वह —

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) नेपाल की प्रजा हो, या
- (ग) भूटान की प्रजा हो या
- (घ) तिब्बती शरणार्थी हो, जो एक जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो, या

3(ड) भारतीय उद्भव का व्यक्ति हो, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लङ्का और केनया, यूगाण्डा के पूर्वी अफ्रीका देशों और तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (पहले

2 विज्ञप्ति स एफ 7 (4) DOP (A II) 76 दि 79 1976 द्वारा निम्नांकित के स्थान पर प्रतिस्थापित—

10 राष्ट्रीयता—सेवा में नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वह —

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) सिक्किम की प्रजा हो, या
- (ग) पाडोचेरी राज्य की प्रजा हो, या
- (घ) भारतीय उद्भव का व्यक्ति हो और पाकिस्तान से भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो —

(1) परन्तु (1) उसे पानता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के अग्र्यधीन, नेपाल की प्रजा या किसी तिब्बती को जो, 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो, सेवा के किसी पद पर नियुक्त किया जा सकेगा ।

11(1) उपयुक्त (ग), या (घ) प्रवग से सम्बन्धित कोई अभ्यर्थी हो तो वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको भारत सरकार ने पानता प्रमाण पत्र दे दिया हो, और यदि वह (घ) प्रवग का है तो वह पानता प्रमाण पत्र उसकी नियुक्ति की तारीख से केवल एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमार्ग होगा। तत्पश्चात् वह सेवा में केवल भारत का नागरिक हो जान पर ही रखा जा सकता है ।

(2) ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके लिए पानता प्रमाण-पत्र आवश्यक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने या साक्षात्कार में बुलाये जाने की अनुमति दी जा सकेगी तथा उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने के अग्र्यधीन अनन्तिम तौर पर नियुक्त भी किया जा सकेगा ।

3 वि स एफ 7 (5) LOP A II 76 दिनांक 23 10 1978 द्वारा प्रतिस्थापित—पहले इस खण्ड में 'विद्यतनाम' नहीं था ।

टायानिका और ज-जीवार) जाम्बिया, मालवी, जैरा और यूवापिया तथा वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया है ] परंतु यह है कि—प्रवण (ख), (ग), (घ) और (ङ) का अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसकी भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण पत्र दे दिया हो । एक अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है, आयाग या अय भत्ता प्राधिकारी द्वारा आयोजित परीक्षा या सामाज्यार में प्रवेश दिया जा सकेगा और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जान के अधधीन अनतिम तौर पर नियुक्ति दी जा सकेगी ।

410-क इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, मेवा में मर्ती के लिए पात्रता मन्त्री प्रावधान जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आगय से आय हुए हमरे देश के एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता, आयु सीमा और गुल्क या अय छूट से सम्बन्धित है, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निवाले गये ऐसे आदेशों या निर्देशों से विनियमित हाने, जा कि भारत सरकार द्वारा उस विषय में निवाले गय निर्देशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित हाने ।

11 आयु (Age)—किसी सवम में सीधी भर्ती के लिए एक अभ्यर्थी को 1[आवेदन प्राप्त करन के लिए नियत अतिम दिनाक के ठीक पश्चात् आने वाले वष की जनवरी के प्रथम दिन का] 18 वष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिये, किन्तु [28 वष] की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिये

परंतु यह है कि—

3[विलोपित]

(1) 31 दिसम्बर, 1958 तक, अस्थायी रूप से लगानार की गई सरकारी सेवा की अवधि पात्रता के प्रयोजनाय आयु में से कम करदी जावेगी ।

4 वि स एफ 7 (5) DOP (A II) 76 दि 20 1977 द्वारा निविष्ट ।

1 वि स एफ 7 (18) नियु (घ) 59 दि 28-7-1961 द्वारा "आवेदन के दिनाक के पश्चात् के वष की एक जनवरी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2 वि स एफ 1 (23) नियुक्ति/क II 69 दि 3 6 1971 द्वारा "25 वष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3 वि स एफ 10 (1) नियु (क) 55 दि 14 10-1962 द्वारा मन्दावली—“(1) कि—विशेष मामला में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिकतम आयु सीमा को शिथिल किया जा सकेगा” को विलापित कर विद्यमान प्रविष्टियों का पुनः स्थापित किया गया ।

(ii) जागीरदार मय जागीरदार के पुत्रों, जिनके निर्वाह के लिए कोई उप-जागीर नहीं थी, के लिए आयु की उच्च सीमा चालीस वष होगी।

टिप्पणी—यह शिथिलीकरण <sup>4</sup>[1 जनवरी 1964] को समाप्त हान वाली अवधि तक के लिए लागू रहेगा।

<sup>5</sup>[(iii) एक महिला अभ्यर्थी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु सीमा आगे पांच वष के लिए बढ़ाई हुई मानी जावेगी।

(iv) इन नियमों के प्रवृत्त होने के बाद यदि एक अभ्यर्थी अपनी आयु के अनुसार किसी परीक्षा में, यदि कोई हा सम्मिलित होने के लिए हक्कार होता, जिसमें कोई ऐसी परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी, तो वह उसके बाद की अगली परीक्षा में आयु के अनुसार हकदार माना जावेगा, और

(v) 25 वष की आयु प्राप्त करने से पहले नियुक्त और राज्य के काय कलापा के सम्बन्ध में अधिष्ठायी रूप से या अस्थायी रूप से खयातार काय करते आ रहे अभ्यर्थी के लिए आयु सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा,]

<sup>6</sup>(vi) [भूतपूर्व सैनिक]<sup>7</sup> और सुरक्षित सैनिकों, अर्थात्—सुरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनको सुरक्षित (रिजर्व) में स्थानांतरित कर दिया हा, के लिए उच्च आयु सीमा 50 वष होगी।

<sup>8</sup>(vii) राजनैतिक पीडितों के लिये उच्च आयु सीमा 31 दिसम्बर 1964 तक 40 वष होगी।

स्पष्टीकरण—शब्द 'राजनैतिक पीडित' का इस नियम के प्रयोजनार्थ वही अभिप्राय होगा जो इसे राजस्थान राजनैतिक पीडित सहायता नियम 1959 के नियम 2 के खण्ड (ii) में दिया गया है, जो राजस्थान राजपत्र के भाग 4 (ग) में दिनांक 11 जून 1959 को प्रकाशित हुआ।

4 वि स एफ 3 (9) नियु (घ) 59 दि 12 10-1962 द्वारा "31 दिसम्बर 1961" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5 वि स एफ 10 (1) नियु (A) 55 दिनांक 14 10 1962 द्वारा खण्ड (iii) (iv) व (v) जोड़े गये।

6 वि स एफ 3 (9) नियु (ग) 51 दि 27 8 1962 द्वारा जोड़ा गया।

7 वि स एफ 10 (1) नियुक्ति (ग) 66 भाग XXII दिनांक 12 4 1967 द्वारा जोड़ा गया।

8 वि स एफ 1 (16) नियुक्ति (क-II) 62 दि 31 5 1963 द्वारा जोड़ा गया।



9(vi) नियम 7 के तृतीय परतुक में वर्णित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व सम्बंध में जो किसी सरकारी कार्यालय में सेवारत हैं, आयु की उच्च सीमा 40 वर्ष होगी।

10(ix) [सेवा में किसी पद पर]<sup>11</sup> अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों का आयुसीमा के भीतर माना जावेगा, यदि वह उस समय आयु सीमा के भीतर थे जब कि उनको आरम्भ में नियुक्त किया गया था, यद्यपि वह आयोग के समक्ष अंतिमरूप में उपस्थित होने के समय उस आयु सीमा का लाभ चुके हैं और यदि वे अपनी आरम्भिक नियुक्ति के समय ऐसे पात्र थे तो उनको दो अवसर दिये जावेंगे।

11(x) जैश्ट प्रशिक्षकों के मामले में उपयुक्त उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा में एक सी सी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर घूट दी जावेगी और यदि इसके परिणामस्वरूप होने वाली आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो वह विहित आयु सीमा में ही समझा जायगा।

12(x1) स्वराज्य के मामले में 29 3 65 तक अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की रहेगी।

13(xii) 1 3 1963 का या इसके बाद बर्मा लका और के-या, टागानिका, युगांडा व जजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से लौटाए गये व्यक्तियों के लिए उपयुक्त उल्लिखित उच्च आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिल की जावेगी और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के मामले में 5 वर्ष की घूट और दी जावेगी।

- 9 वि स एफ 1 (15) नियु /क-II/63 दि 17 3 1964 द्वारा जोड़ा गया।
- 10 वि स एफ 1 (26) नियुक्ति (क-II)/62 दि 18 9 1965—द्वारा जोड़ा गया।
- 11 वि स एफ 1 (39) LOF/AII/73 दि 29 12 1974 द्वारा निर्दिष्ट।
- 12 वि स एफ 1 (10) नियु /क-II/66 दि 11 4 1967 द्वारा जोड़ा गया।
- 13 वि स एफ 1 (6) नियु (ग)/54/ भाग VI दि 17 3 72 द्वारा जोड़ा गया और सम संशोधन सुद्धि पत्र दि 30 6 1972 द्वारा संशोधित।
- 14 वि स एफ 1 (20) नियु (क-2) 62 दि 20 9 1975 द्वारा प्रतिस्थापित तथा 29 2 1977 तक प्रभावशील।

15(xiii) पूर्वी अफ्रीकी देशों—केन्या, टांझानिका, यूगाण्डा और जजीवार से वापस लौटाये गये व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

16(xiv) ऐसे भूतपूर्व कर्मी की मामले में उपयुक्त उल्लिखित उच्च आयु सीमा लागू नहीं होगी, जो दोषसिद्धि से पहले सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी आधार पर सेवा कर चुका हो और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

(xv) उस भूतपूर्व कर्मी के मामले में जो दोष सिद्धि से पूर्व अधिक आयु का नहीं था एवं नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था, उपयुक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में इतनी कानाबानि तक की छूट दी जायगी जो मुक्त कारावास की अवधि के बराबर हो,]

17(xvi) निम्न उक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से नियुक्त होने के बाद आयु सीमा के भीतर माना जायेगा, चाहे वे आयोग के समक्ष उपस्थित होने पर उस आयु सीमा को पार कर चुके हों, यदि वे सेना के कमीशन में प्रवेश के समय इसने लिय पात्र होते।

18 11-क—नियम 11 में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 7 (ख) के परतुक के अधीन सरकार द्वारा जारी किये गये साधारण या विशिष्ट निर्देशों की सीमा में रहते हुये नियमों में विहित आयु-सीमा की शर्तों में छूट दे सकेगा।

## 12 शैक्षणिक अर्हतायें (योग्यतायें)

(1) आशुलिपिक सवर्ग में सीधी भर्ती के लिए एक अभ्यर्थी—

19[(क) राजस्थान शिक्षा बोर्ड की हायर सेन्ट्ररी परीक्षा क्लास, विज्ञान

15 वि स एफ 1 (20) नियु (क-2) 67 दि 13 12 1974 द्वारा जोड़ा गया।

16 वि स एफ 5 (6) DOP/क-2/74 दि 18 3 1975 द्वारा जोड़ा गया तथा दि 28 8 1961 से प्रभावशील।

17 वि स एफ 7 (2) DOP (क-2) 75 दि 20 9 1976 द्वारा निविष्ट।

18 वि स एफ 3 (4) DOP (क-2) 75 दि 26 8 1976 द्वारा निविष्ट।

19 विज्ञानि स एफ 10 (1) नियुक्ति (क) / 55 भाग XXXV दि 10 5 1972 द्वारा नियम 12 के खण्ड (क) तथा (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित तथा विद्यमान खण्ड (ग) को खण्ड (ख) पुनराश्रित किया गया, जो अगले पृष्ठ पर दिया गया है—

या वाणिज्य में या सरकार द्वारा इसके समकक्ष माय कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो  $\times \times \times^{20}$ ।]

21[पत्र-तु 10 5 1972 के पहले प्राथमिक के पद पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त और 13 1975 को जो लगातार काम कर रहे व्यक्तियों के मामले में 'न्यूनतम अर्हता हाईस्कूल या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित (परीक्षा) होगी।]

[ (ख) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का तथा राजस्थानी बोलीषो का कार्यकारी प्रस्था पान हो। ]

(घ) प्राथमिक तृतीय श्रेणी के लिये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा कक्षा, विज्ञान या वाणिज्य में या सरकार द्वारा इसके समकक्ष माय कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो और आयोग द्वारा आयोजित निम्न लिखित अर्हता-परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो—

विषय	समय	पूर्णाङ्क
(1) अंग्रेजी	3 घण्टे	100
(11) सामान्य ज्ञान	3 घण्टे	100

परीक्षा का स्तर तथा पाठ्यक्रम—प्रश्न पत्रों का स्तर किसी भारतीय विश्व-विद्यालय की मैट्रिक्युलेशन के लगभग होगा।

### क्षेत्र

अंग्रेजी—प्रश्नपत्र अभ्यर्थी के अंग्रेजी व्याकरण व रचना के गान और साधारणतया समझने की शक्ति व सही अंग्रेजी लिखने की क्षमता की जाच के लिए रचित होगा।

भाषा की व्यवस्था, साधारण भाव प्रकट करने तथा उस कामकारी उपयोग का ध्यान रखा जावेगा। प्रश्न पत्र में निबंध लेखन, सारांश लेखन, प्राहण, शब्दांश साधारण उक्तियों व कहावतों के सही प्रयोग, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कथन आदि पर प्रश्न प्रश्नपत्र में सम्मिलित हो सकते हैं।

20 वि स एफ 3 (4) DOP/A 2/77 दिनाङ्क 15 3 78 द्वारा विलोपित, जो इस प्रकार थी—' और अनुसूची I के भाग III में उल्लिखित विषयों में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो।'

21 वि स एफ 3 (3) Dop (A II) 73 दि 20 9 1975 द्वारा निविष्ट तथा दि 19 12 1973 से प्रभावशील।

सामान्य ज्ञान (जनरल नोलेज)—भारत के संविधान, पंचवर्षीय योजनाएँ, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत का साधारण व आर्थिक भूगोल, नवीन घटनाएँ, प्रतिदिन का विज्ञान का कुछ ज्ञान और ऐसे दैनिक अवलोकन की बातें, जो एक

[ क्रमश

2 (2) मनिष्ट लिपिक (L D C) की श्रेणी में सीधी भर्ती के लिये एक

शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित हैं। अभ्यर्थी के उत्तरा में उसके द्वारा प्रश्नों की समझने की बुद्धि के प्रदर्शन की भाषा की जाती है, न कि किसी पाठ्य पुस्तक के ज्ञान की।

टिप्पणी—अर्हताएं (Qualifying marks) का प्रतिशत 40% होगा। सामान्य ज्ञान, द्वितीय प्रश्न पत्र, का उत्तर अभ्यर्थी हिन्दी या अंग्रेजी में दे सकते हैं।

×[परंतु यह है कि—सरकार के कार्यकलाप में अधिष्ठायी रूप से सेवा कर रहे व्यक्ति या वह व्यक्ति जिसने राजस्थान की सविदाकारी रियासत में अधिष्ठायी रूप से किसी स्थायी पद को धारण किया हो, चाहे उसे सेवामुक्त, अधिगोप या सेवारत रखा गया हो, आधुनिक के सबब में भर्ती के लिये पात्र होगा, यदि वह मेट्रिक्युलेट हो या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उसने उत्तीर्ण की हो।]

[उपरोक्त परंतु को विज्ञप्ति सं एफ 10 (1) नियुक्ति (क-2) 55 भाग III दिनांक 23 8 1963 द्वारा विलोपित कर दिया गया, जॉन 20 8 1957 से प्रभावशील हुआ।]

अंग्रेजी में 100 शब्द प्रति मिनट आधुनिक और 40 शब्द प्रति मिनट टाइप करने या हिन्दी में 40 शब्द प्रति मिनट आधुनिक और 30 शब्द प्रति मिनट टाइप की गति—परीक्षा (स्पीडटेस्ट) उत्तीर्ण कर लेता हो और परीक्षा की अवधि में आयोजित आधुनिक तृतीय श्रेणी की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता हो।

परंतु यह है कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा वर्ष 1956 या इससे पहले, आयोजित किसी जांच (टैस्ट) में भाग लिया हो और जिसे आधुनिक या टाइप में उत्तीर्ण हो जाने से छूट दे दी गई थी, उसे उस विषय में प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं है।

परंतु यह और है कि—एक अभ्यर्थी जो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में बाद में प्रविष्ट हुआ हो और उस विषय में उत्तीर्ण हो गया हो, जिसमें वह पहले असफल रहा था, तो उसे नियम 12 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में विहित परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ समझा जावेगा।

22 विज्ञप्ति सं एफ 18 (क) नियुक्ति (क) 59 दि 1 6 1959 तथा दि सं एफ 7 (18) नियुक्ति (घ)/59 दि 28 7 1961 द्वारा निम्नांकित के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया—

“साधारण सबब में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को—

(क) राजपूताना विश्वविद्यालय या/सरकार द्वारा इस नियम के प्रयोजनार्थ माध्य विश्वविद्यालय या बोर्ड की हाइस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो या आयोग द्वारा मेट्रिक्युलेशन के समकक्ष माध्य हिन्दी या संस्कृत की योग्यताएँ रखता हो और (ख) यदि वह उपरोक्त खण्ड (क) में वर्णित हिन्दी योग्यता नहीं रखता हो, तो देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का अच्छा कार्य करने योग्य ज्ञान रखता हो।

अभ्यर्थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल या <sup>23</sup>[ ] सेवेण्डरी परीक्षा या इस नियम के प्रयोजनाथ सरकार द्वारा माय किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण हो या मेट्रिक्युलेशन वे समकक्ष सरकार द्वारा माय हिन्दी या संस्कृत की योग्यतायें प्राप्त की हो ।

<sup>24</sup>(3) धरिष्ठ लिपिक (U D C) के लिए सीधी भर्ती के लिये एक अभ्यर्थी भारत मे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की कला, विज्ञान, कृषि या वाणिज्य मे उपाधि (Degree) प्राप्त हो ।

<sup>25</sup>परन्तु यह है कि—राज्य के कायकलापा के सम्बन्ध में अधिष्ठायी रूप से सेवा कर रहे व्यक्ति या राजस्थान की किसी रियासत मे स्थायी पद की अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाला व्यक्ति, चाहे उसे अधिदोष कमचारी के रूप मे सेवामुक्त (डिस्चार्ज) कर दिया गया हो या वह राज्य के कार्यों में सेवा कर रहा हो बिना किसी शैक्षणिक योग्यता के विचार के किसी समय मे भर्ती के लिए पात्र होगी ।

<sup>26</sup>कि—प्रायोग के क्षेत्र मे नही आनेवाले पदो पर भर्ती के लिए उच्च आयु सीमा उन लोगो के लिए 35 वर्ष होगी, जिनको किसी रिक्त स्थान की कमी या पद की समाप्ति (Abolition) के कारण राज्य सरकार की सेवा से छटनी कर दिया गया था, यदि वे इन नियमो मे विहित आयु सीमा के भीतर थे जबकि उनको आरम्भ मे उस पद पर नियुक्ति किया गया था जिस पर से उनको पहले छटनी कर दिया गया था, परन्तु भर्ती की अहतायें, चरित्र, शारीरिक स्वस्थता आदि की साधारण विहित धारायें (चैनल) पूरी करली गई हैं और वे किसी शिकायत या दोष के कारण छटनी नही किये गये थे तथा वे पिछले नियुक्ति प्राधिकारी से अच्छी सेवायें समर्पित करने का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

**13 चरित्र—**सेवा मे सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सेवा मे नियोजन के लिए अर्हित माना जाए । उसको उस विश्वविद्यालय

23 वि स एफ 3 (1) DOP (क-2) 76 दि 30 6 1976 द्वारा शब्द "हायर" विलोपित किया गया और राजपत्र मे प्रकाशन के दिनाङ्क से प्रभावशील ।

24 वि स एफ 10 (1) नियुक्ति (क) 55 दि 16 6 1959 द्वारा जोड़ा गया ।

25 वि स एफ 10 (1) नियुक्ति (क-2) 55 भाग XIII दिनाङ्क 23 8 1966 द्वारा जोड़ा गया ।

26 वि स 5 (2) DOP (A III) 73 दि 21 12 73 को निविष्ट ।

या महाविद्यालय के प्रधान शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें उसने अन्तिम बार शिक्षा पाई थी तथा साथ ही उसे दो और सच्चरित्रता प्रमाण-पत्र ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के देने चाहिए जो उसके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित न हों और न ही उसके रिश्तेदार हों। ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की तारीख से छ मास पूर्व के लिये दिये नहीं होने चाहियें।

**टिप्पणी —(1)** न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को स्वयं में सच्चरित्रता प्रमाण-पत्र नहीं दिये जाने का आधार नहीं माना जाना चाहिए। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उसके नैतिक अथमता सम्बन्धी कोई बात अतन्त्र स्त नहीं है या उनका सम्बन्ध हिसात्मक अपराध या ऐसे आन्दोलनों से नहीं है जिनका उद्देश्य विधि द्वारा सरकार को हिसात्मक तरीके से उसटना हो तो केवल दोषसिद्धि की निरहता नहीं समझा जाना चाहिये।

(2) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ जिन्होंने कारावास में अपने अनुशासित जीवन से और बाद के सदाचरण से अपने आपको पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजनाय इस आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिये कि वे पहले दोषसिद्ध हो चुके हैं। उन व्यक्तियों को जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्ध दोष किया गया है जिनमें नैतिक अथमता की कोई बात अतन्त्र स्त नहीं है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायगा, यदि वे पश्चात्पूर्ति देखरेख गृह के अधीक्षक या यदि किसी विशिष्ट जिले में ऐसे पश्चात्पूर्ति देखरेख गृह नहीं है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक से इस आशय की एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

(3) उन व्यक्तियों से जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्ध दोष किया गया है जो नैतिक अथमता से सम्बन्धित हैं, पश्चात्पूर्ति देखरेख गृह के अधीक्षक का इस आशय का एक प्रमाण पत्र जो कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित होगा, प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी कि वे नियोजन के लिये उपयुक्त हैं क्योंकि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चात्पूर्ति देखरेख गृह में अपने बाद के सदाचरण से यह साबित कर दिया है कि वे अब पूर्णतः सुधर गये हैं।

**14 शारीरिक योग्यता—**सेवा में सीधी भर्ती का अभ्यर्थी मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये और उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा मानसिक एवं शारीरिक दोष नहीं होना चाहिये जो उसके सेवा के रूप में अपने कर्तव्य का

1 वि स एफ 7 (2) DOP (क-2) 74 दिनांक 57 1974 द्वारा प्रतिस्थापित। उपरोक्त नियम 14 में से केवल तारांकित (क) तक इससे पहले लागू था।

दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधक हो और यदि वह चुन लिया जाय, तो उसे सरकार द्वारा तत्प्रयोजनाय अधिसूचित चिन्त्रिणा प्राधिकारी या इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । (३) नियुक्ति प्राधिकारी नियमित पक्ति में पदोन्नत हुए या राज्य के कायकलापा में पहले से सेवारत अभ्यर्थी के मामले में प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने से मुक्त कर सकता है, यदि उस (अभ्यर्थी) की पूर्ण नियुक्ति के लिये स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही की जा चुकी हो और दोनों पदों की मेडिकल परीक्षा के आवश्यक स्तर नये पद का कर्तव्या का दक्षतापूर्वक पालन करने में तुलनीय हो तथा उसकी आयु के कारण इस प्रयोजनाय उसकी दक्षता में कमी नहीं आयी है ।

#### 214-क अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग—

ऐसा अभ्यर्थी जिसे आयोग द्वारा प्रतिरूपण करने का अथवा गठे हुए दस्तावेज जिनको बिगाड़ दिया गया है, प्रस्तुत करने का या ऐसे व्योरे प्रस्तुत करने का जो गलत या मिथ्या है अथवा महत्वपूर्ण सूचना देने का अथवा परीक्षा या साक्षात्कार में नावाजिब साधनों का प्रयोग करने का या उनके प्रयोग का प्रयास करने का अथवा परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश पाने के निमित्त किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन काम में लाया जा दोषी घोषित किया जाता है या कर दिया गया है तो उस पर फौजदारी मुकदमा तो चलाया ही जा सकेगा इसके साथ साथ उसे —(क) अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से, आयोग । नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, और (ख) सरकार के अधीन नियोजन के लिए सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा ।

#### 314 ख नियुक्ति के लिए निरग्रहतायें—

(1) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, जब तक कि सरकार, अपना समाधान कर लेने के पश्चात् कि—ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के लागू होने से छूट न दे दे ।

(2) कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसका विवाह उस व्यक्ति से हुआ हो जिससे पहले से ही कोई जीवित पत्नी है सेवा में नियुक्ति के लिए पात्रा नहीं होगी, जब तक कि सरकार, अपना समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिये

2 वि स एफ 1 (33) नियुक्ति (क-2) 63 दि 26 8 1965 द्वारा जोड़ा गया ।

3 वि स एफ 7 (3) DOP (क-2) 76 दि 21 5 1976 द्वारा निविष्ट ।

विशेष आचार है किसी महिना अभ्यर्थी को इस नियम के उस पर लागू होने से छूट न दे दे।

4(3) [विलोपित × ×]

5(4) कोई विवाहित अभ्यर्थी, जिसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजन में 'दहेज' शब्द का वही समान अर्थ होगा, जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 (केन्द्रीय अधिनियम 28, 1961) में दिया गया है।

15 वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति की शर्तें—(Conditions for appointment to senior posts) —

(1) कोई व्यक्ति वरिष्ठ लिपिक (U D C) के पद पर <sup>1</sup>[पदोन्नति द्वारा] अधिष्ठायी रूप से नियुक्त नहीं किया जावेगा, जब तक कि राज्य के कायकलापो के सम्बन्ध में वह कम से कम <sup>2</sup>[5 वर्ष तक] एक कनिष्ठ लिपिक (L D C) के रूप में सेवा नहीं कर चुका हो, सिवाय इसके कि—तीन वर्ष की सेवा सहित स्नातक (ग्रैजुएट्स) वरिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

<sup>3</sup>(1-क) कोई व्यक्ति स्थानीय निधि अकेला विभाग में अकेला या सहायक अकेला के रूप में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त नहीं किया जावेगा, जब तक कि वह ऐसी परीक्षाएँ (टेस्ट) उत्तीर्ण न करले और ऐसी अन्य शर्तों को पूरा न करले जो समय समय पर सरकार द्वारा विहित की जावेगी।

(2) कोई व्यक्ति लेखा लिपिक के रूप में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त नहीं किया जावेगा, जब तक कि—वह ऐसी परीक्षा (टेस्ट) उत्तीर्ण न करले और ऐसी अन्य शर्तों को पूरा न करले जो सरकार द्वारा विहित की जावे।

4 वि स एफ 7 (3) DOP (क-2) 76 दि 15.11.1977 द्वारा विलोपित। (यह परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रतिबंध था)

5 वि स एफ 15 (9) DOP (क-2) 74 दि 5.11.1977 द्वारा निविष्ट।

1 वि स 10 (1) नियुक्ति (क) 55 दि 16.6.1959 द्वारा जोड़ा गया।

2 शब्द "सात वर्ष" के लिए प्रतिस्थापित—वि स एफ 3 (4) DOP/A-II/78 GSR दिनांक 10.1.1979 (राजपत्र दिनांक 18.1.79 पृष्ठ 428)

3 वि स एफ 1 (13) नियुक्ति (क-2) 62 दि 10.6.1968 द्वारा जाड़ा गया।



4[परंतु यह है कि—राजस्थान नहर मण्डल तथा मण्डल के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों में लेखा लिपिकों के पद पर उन अभ्यर्थियों में से विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की कम से कम वाणिज्य में उपाधि (डिग्री) प्राप्त हो और प्राथमिकता के लिये लेखा का कुछ अनुभव हो। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लेखा लिपिक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो (निम्न) द्वारा गठित एक चयन समिति द्वारा चयन के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी—

1 मण्डल के सचिव अध्यक्ष

2 सहायक वित्तीय परामर्शदाता सदस्य

3 निदेशक, उपनिवेश/मुख्य अभियंता के  
तकनीकी सलाहकार (यथा स्थिति) सदस्य

मण्डल का सहायक-सचिव चयन समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

5(3) कोई व्यक्ति मुख्यलिपिक या अनुभाग प्रभारी (हेडक्लर्क या सेक्शन इंचार्ज) के रूप में नियुक्त नहीं किया जावेगा, जब तक कि वह राज्य के कायकलाप के सम्बन्ध में कम से कम 10 वर्ष सेवा न कर चुका हो, मगर तीन वर्ष वरिष्ठ लिपिक के रूप में, सिवाय उन स्नातकों के, जो 7 वर्ष की सेवा कर चुके हों, मगर दो वर्ष वरिष्ठ लिपिक के रूप में सेवा के, मुख्य लिपिक या अनुभाग प्रभारी के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

6[(4) X— $\lambda$  विलोपित  $\times$ ]

7(4-क) कोई व्यक्ति सहायक (एसिस्टेंट) के रूप में अधिष्ठायी रूप से

4 वि स 3 (37) नियुक्ति (क) 59 दिनांक 7 6 1960 द्वारा जोड़ा गया।

5 वि स 7 (18) नियुक्ति (क) 59 दि 28 7 1961 द्वारा निर्रिक्त।

6 वि स एफ 3(4) DOP/A-2/77 दिनांक 15 3 78 द्वारा विलोपित,  
ओ वि स एफ 10 (1) नियु (क) 55 दि 14 7 1962 द्वारा जोड़ा  
गया था—

‘(4) कोई व्यक्ति आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर-क्लर्क) के पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा, जब तक कि उसने आशुलिपि (स्टेनोग्राफी) विषय में या अतिरिक्त विषय के रूप में हायर सेकेंडरी परीक्षा या उससे समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो, या उसने आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी आशुलिपिकों की परीक्षा (टेस्ट) में योग्यता प्राप्त कर ली हो।

7 वि स एफ 10 (1) नियु (क) 55 भाग XXIV दिनांक 28 10 1967  
द्वारा जोड़ा गया।

नियम 15 ] राजस्थान ग्रामीण कार्यलय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम [ 39

नियुक्त नहीं किया जावेगा, जब तक कि उसने राजकाज में कम से कम 10 वर्ष तक के लिये मग 5 वर्ष लिपिक के रूप में, सेवा नहीं की हो।

8(5) कोई व्यक्ति ग्रामीणक श्रेणी द्वितीय के रूप में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त नहीं किया जावेगा, जब तक कि—

(क) उसने राजकाज में कम से कम 10 वर्ष तक सेवा नहीं की हो, जिसमें (निम्न) सम्मिलित हैं—

(i) 1 जनवरी 1973 से पहले की किसी अवधि के सम्बन्ध में, सहायक और लिपिक के रूप में सान वर्ष की अवधि के लिये, और

(ii) 1 जनवरी 1973 को या इसके बाद की अवधि के सम्बन्ध में, सहायक के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिये, या

(ख) राजकाज में प्रागुलिपिक द्वितीय श्रेणी के रूप में कम से कम 10 वर्ष के लिये सेवा कर चुका हो।

स्पष्टीकरण—खण्ड (ख) के ग्रामीण 'दस वर्ष' की सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये, 1 सितम्बर 1968 से पहले प्रागुलिपिक तृतीय श्रेणी के रूप में की गई सेवा को प्रागुलिपिक द्वितीय श्रेणी के रूप में की गई सेवा माना जावेगा।

9(5-क) जहाँ ही यह विनिश्चित किया जावे कि—ग्रामीणक द्वितीय श्रेणी के पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाना है, तो सहायक तथा प्रागुलिपिक द्वितीय श्रेणी, जो पदोन्नति के लिये पात्र हैं, की सम्मिलित वरिष्ठता ऐसे रूप में लगातार स्थानापन्न कार्य करने के बाद में नियमित चयन होने की अवधि के आधार पर तय की जावेगी। (यदि) किसी मामले में कोई सहायक तथा प्रागुलिपिक द्वितीय श्रेणी ने बराबर अवधि के लिये लगातार स्थापन कार्य किया हो, तो सहायक (उक्त) प्रागुलिपिक श्रेणी द्वितीय से वरिष्ठ श्रेणी में होगा।

8 कि स एफ 10 (1) नियु (क) 55 of XXV दिनांक 10 5 1972 द्वारा निम्नांकित के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया—

"(5) कोई व्यक्ति ग्रामीणक द्वितीय श्रेणी के रूप में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त नहीं किया जावेगा, जब तक कि—वह राजकाज में कम से कम दस वर्ष के लिये, मग कम से कम दो वर्ष सहायक के रूप में तथा 5 वर्ष लिपिक के रूप में सेवा नहीं कर चुका हो या राजकाज में कम से कम 10 वर्ष के लिये प्रागुलिपिक तृतीय श्रेणी के रूप में सेवा नहीं कर चुका हो।"

9 कि स एफ 3 (2) DOP (क-2) 77 दि 26 10 1977 द्वारा निविष्ट।

10 (6) (क) कोई व्यक्ति अधीक्षक प्रथम श्रेणी के रूप में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त नहीं किया जावेगा, जब तक कि—उसने राजकाज में कम से कम दस वर्ष के लिये, मग एक वर्ष अधीक्षक द्वितीय श्रेणी के रूप में, सेवा नहीं कर ली हो।

(ख) ऐसे विभाग में जहाँ अधीक्षक द्वितीय श्रेणी का पद नहीं है, कोई व्यक्ति अधीक्षक प्रथम श्रेणी के रूप में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त नहीं किया जावेगा, जब तक कि उसने राजकाज में कम से कम दस वर्ष के लिये सेवा नहीं की हो, जिसमें (निम्न) सम्मिलित है—

(i) चार वर्ष सहायक के रूप में या सातवर्ष की सेवा सहायक तथा वरिष्ठ लिपिक के रूप में, या

(ii) आशुलिपिक के रूप में दस वर्ष, जिसमें पाच वर्ष आशुलिपिक प्रथम श्रेणी के रूप में या ऐसे विभाग में जहाँ आशुलिपिक प्रथम श्रेणी का पद विद्यमान नहीं है तो 15 वर्ष की अवधि के लिये आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के रूप में।

स्पष्टीकरण—खण्ड (ii) के अधीन सेवा की गणना के प्रयोजनाय, आशुलिपिक द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के रूप में 1 सितम्बर 1968 के पूर्व

10 वि स एफ 3 (2) DOP (क-2) 77 दि 26.10.1970 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—

पुराना नियम (6) (क) तथा (ख), उपरोक्त नियम (6) (क) व (ख) के समान भाषा में ही था, पहले (ख) में वर्तमान दो शर्तों की बजाय निम्न लिखित तीन शर्तें थी—

“(i) दो वर्ष अनुभाग प्रभारी/मुख्य लिपिक के रूप में या चार वर्ष सहायक के रूप में, या

(ii) 1 जनवरी 1973 के पहले की किसी अवधि के सम्बन्ध में सातवर्ष के लिये सहायक तथा वरिष्ठ लिपिक के रूप में और इसके बाद की अवधि के सम्बन्ध में चार वर्ष सहायक के रूप में, या

(iii) वह राजकाज में आशुलिपिक के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक मग पाच वर्ष आशुलिपिक प्रथम श्रेणी के रूप में या ऐसे विभाग में जहाँ आशुलिपिक प्रथम श्रेणी का पद विद्यमान नहीं है, 15 वर्ष की अवधि के लिये आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के रूप में सेवा कर चुका हा।

स्पष्टीकरण—खण्ड (iii) के अधीन सेवा की गणना के प्रयोजन से, 1 सितम्बर, 1968 के पहले आशुलिपिक श्रेणी द्वितीय तथा तृतीय के रूप में या की क्रमशः आशुलिपिक प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के रूप में सेवा माना जावेगा।

नियम 15 ] राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम [ 41

की सेवा को क्रमशः आशुलिपिक प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के रूप में संचालित माना जावेगा।

11(6-क) ज्यों ही यह विनिश्चित किया जाता है, कि अधीक्षक प्रथम श्रेणी के पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाना है, तो सहायकों तथा प्रथम श्रेणी के आशुलिपिका, जो पदोन्नति के लिये पात्र हैं, की सम्मति वरिष्ठता ऐसे रूप में लगातार स्थानापन्न कार्य करने के बाद में नियमित चयन है। की अवधि के आधार पर तय की जावेगी, परन्तु यह है कि—आशुलिपिका में स वह व्यक्ति जो आशुलिपिक प्रथम श्रेणी नियुक्त है या आशुलिपिक प्रथम श्रेणी के रूप में जिसकी लगातार सेवा सम्बन्धी है कि वह उक्त समान श्रेणी में जिसकी सेवा कम है, वह आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी से वरिष्ठ श्रेणी (रैंक) में होगा। (यदि किसी मामले में कोई सहायक तथा आशुलिपिक प्रथम श्रेणी लगातार स्थानापन्न कार्य करने की समान अवधि रखते हों, तो सहायक आशुलिपिक प्रथम श्रेणी से वरिष्ठ श्रेणी में होगा।

12(7) कोई द्वितीय श्रेणी का आशुलिपिक प्रथम श्रेणी के आशुलिपिक के पद 13[के 50% से अधिक रिक्त स्थानों] पर पदोन्नत नहीं किया जावेगा, जब तक कि—वह आयोज द्वारा आयोजित प्रथम श्रेणी आशुलिपिक की परीक्षा अंग्रेजी श्रुतिलेख में 120 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी श्रुतिलेख में 100 शब्द प्रति मिनट उत्तीर्ण न कर ले, 14[जो कि 100 अंकों की होगी] और चार वर्ष की सेवा न कर ली हो तथा आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के पद पर अधिष्ठायी होना चाहिए। परन्तु,

11 वि.स.ए. 3 (2) DOP (क-2) 77 दि. 28.10.1977 द्वारा निविष्ट।  
12 वि.स.ए. 3 (13) DOP (क-2) दिनांक 5-3-1976 द्वारा निम्न-लिखित उपनियम (7) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया—

“(7) कोई आशुलिपिक उच्च श्रेणी (राजस्थान नवीन बतनमान नियम 1969 के अधीन श्रेणी द्वितीय को श्रेणी प्रथम पुनर्पदानित करने पर) जब तक कि—वह आयोज द्वारा आयोजित अहता परीक्षा अंग्रेजी श्रुतिलेख में 120 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी श्रुतिलेख में 100 शब्द प्रति मिनट उत्तीर्ण न कर ले। जो व्यक्ति 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं और अथवा पदोन्नति के लिये योग्य (due) हैं उनको यह परीक्षा (टेस्ट) उत्तीर्ण नहीं करनी होगी।”

वि.स.ए. 3 (4) DOP/A-2/77 दिनांक 15-3-78 द्वारा प्रतिस्थापित।  
वि.स.ए. 3 (3) DOP (क-2) 75 दिनांक 17-5-1977 द्वारा शब्दावली “जो 100 शब्दों की होगी” के बजाय निविष्ट।

वे व्यक्ति जो 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं और आयुष्य पदोन्नति के लिये योग्य (due) हैं, उनको ग्रहता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

10(8) आशुलिपिक प्रथम श्रेणी परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता—<sup>13</sup>[प्रथम श्रेणी के पदों की 50% रिक्तियाँ बेविराद [कोई व्यक्ति जब तक कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है, आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक प्रथम श्रेणी की परीक्षा में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होगा—

- (i) आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के सवर्ग में अधिष्ठायी हो,
- (ii) इन नियमों के नियम 7 के परतुक (7) के अधीन अधिष्ठायी नियुक्ति के लिय पात्र हो,
- (iii) अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के लिये आयोग द्वारा आयोजित <sup>16</sup>[प्रतियोगिता परीक्षा या ग्रहता परीक्षा] उत्तीर्ण की हो तथा नियम 26 के उपनियम (3) के अधीन तदर्थ/आवश्यक अस्थायी रूप से अन्यथा कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिये आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के रूप में कार्य किया हो।

टिप्पणी—जो व्यक्ति इस सशोधन के प्रभावशील होने के तुरन्त बाद आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक प्रथम श्रेणी की ग्रहता-परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, उनको माह अक्टूबर 1975 में आयोजित ग्रहता परीक्षा उत्तीर्ण समझा जावेगा।

17(9) कोई व्यक्ति सहायक पंजीयक, राजस्व मण्डल के रूप में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसने अपने सम्पूर्ण सवर्ग में कार्यालय अधीक्षक प्रथम श्रेणी के रूप में कम से कम पांच वर्षों के लिये सेवा नहीं की हो और

15 वि स एफ 3 (13) DOP (क-2) 73 दिनांक 5-3-1976 द्वारा निम्न लिखित के स्थान पर प्रतिस्थापित—

“(8) आशुलिपिक प्रथम श्रेणी परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता—स्थायी (वनफमड) आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी आशुलिपिक प्रथम श्रेणी परीक्षा में प्रवेश के लिये पात्र होंगे, परन्तु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम दिनांक को उनके द्वारा आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के रूप में कम से कम चार वर्ष कार्य किया गया हो।”

16 उपरोक्त विनिर्दिष्ट दिनांक 15-3-78 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—  
“या तो 10-5-1972 तक ग्रहता परीक्षा या 10-5-1972 के बाद प्रतियोगिता परीक्षा”

17 वि स एफ 3 (3) (क 2) 73 दिनांक 17-5-1974 तथा सुद्धि पत्र समसंख्यक दि० 17-6-1974 द्वारा निविष्ट।

जिस वष में चयन किया जाता है उसकी पहली जनवरी का उस पद को अधिष्ठायी रूप से धारण न करता हो।

18(10) कोई व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी या स्थापन अधिकारी के रूप में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त नहीं किया जावेगा, जब तक कि उसने कार्यालय अधीक्षक प्रथम श्रेणी या कार्यालय अधीक्षक द्वितीय श्रेणी के रूप में प्रथम पांच वर्षों या दस वर्षों की अवधि के लिये सेवा नहीं की हो और वह ऐसा कोई पद चयन करने के वष के अप्रैल के प्रथम दिन को अधिष्ठायी रूप से धारण नहीं करता हो।

19(11) कोई व्यक्ति निजी-सहायक के रूप में अधिष्ठायी तौर पर नियुक्त नहीं किया जावेगा, जब तक कि उसने प्राधुलिपिक प्रथम श्रेणी के रूप में 10 वष या अधीक्षक श्रेणी द्वितीय के रूप में एक वष की अवधि के लिये सेवा न की हो और जिसने आयोग द्वारा आयोजित प्राधुलिपिक श्रेणी द्वितीय की परीक्षा उत्तीर्ण करली हो या नियम 7 के परन्तुक (7) के अधीन उसे छूट दे दी गई हो।

परन्तु यह है कि—यदि किसी विभाग में अधीक्षक प्रथम श्रेणी के पदा की सख्या प्राधुलिपिक प्रथम श्रेणी की कुल सख्या के बराबर हो, तो केवल साधारण सवग के सदस्य ही अधीक्षक श्रेणी प्रथम के पद पर पदोन्नति के पात्र होंगे,

परन्तु आगे यह भी है कि—यदि किसी विभाग में अधीक्षक प्रथम श्रेणी के कुल पदा की सख्या निजी सहायकों के पदों की सख्या से अधिक हो, तो साधारण सवग और प्राधुलिपिक सवग के सदस्य अधीक्षक प्रथम श्रेणी की अधिक सख्या के पदों पर पदोन्नति के लिये पात्र होंगे, जो कि उपनियम (6-क) व अनुसार भरे जावेंगे।

### 2015-क—[विलोपित]

18 वि स एफ 3 (2) DOP (क-2) 75 दिनांक 20-9-1975 द्वारा निविष्ट तथा दिनांक 1-5-1975 से प्रभावी।

19 वि स 3 (2) DOP (क-2) 77 दिनांक 26-10-1977 द्वारा निविष्ट।

20 निम्नांकित नियम 15-क वि स एफ 7 (1) DOP (क-2) 74 दिनांक 5-9-1974 द्वारा निविष्ट किया गया था तथा वि स एफ 3 (11) वार्षिक (क-2) 74 दिनांक 8-2-1975 द्वारा विलोपित किया गया—

“15-क—कोई अधिकारी पदोन्नति के लिय विचार में नहीं लिया जावेगा तब तक कि उसे पिछले निम्न पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त व पुष्ट (कनफर्म) नहीं कर दिया गया हो। यदि कोई अधिकारी पिछले निम्न पद पर अधिष्ठायी हाते हुए भी पदोन्नति के लिय पात्र नहीं हो तो वे अधिकारी जो भर्ती के तरीका में से या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये सेवा नियमों के अधीन चयन के बाद स्थानापन्न आधार पर ऐसे पद पर नियुक्त किये गये हैं, उन पर स्थानापन्न आधार पर केवल उसी बरिष्ठता के क्रम में पदोन्नति के लिये विचार में लाया जा सकता है, यदि वे उक्त निम्न पद पर अधिष्ठायी होते।”

16 पक्ष समथन—नियमों के अधीन अपेक्षित बातों के अलावा, भर्ती के लिये किसी भी प्रकार की सिफारिश पर, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समथन प्राप्त करने हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से किया गया प्रयत्न उसे भर्ती के लिये निरहित कर देगा।

### भाग (4) × × विलोपित × ×

[वि स एफ 3 (4) DOP/A-2/77 दिनांक 15 3 78 द्वारा भाग (4) को विलोपित किया गया जो इस प्रकार था —

### भाग 4 आशुलिपिकों के सवर्ग के लिये

17 आवेदन पत्र आमंत्रित करना—आशुलिपिकों [तथा स्टेनोग्राफर क्लर्क के] सवर्गों में सीधी भर्ती के लिये आवेदन नियुक्ति अधिकारी द्वारा रिक्त स्थानों का विज्ञापन द्वारा जिस प्रकार वह उचित समझे आमंत्रित किये जावेंगे और ऐसे प्रपत्र में दिये जावेंगे, जो [उसके द्वारा अनुमोदित किये जावें]

18 चयन—(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करने के बाद और समस्त या ऐसे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करने के बाद, जिनको वह वांछनीय समझे, चयन किया जावेगा। चयनित अभ्यर्थियों के नाम एवं सूची में उनकी योग्यता (मेरिट) के क्रम में रखे जावेंगे।

(2) उप नियम (1) में बनाई गई सूची में से उन अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए जो उस सूची में सर्वोच्च हैं और नियम (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति अधिकारी ऐसी जाच द्वारा जो वह आवश्यक समझे, अपना समाधान करने के बाद कि ऐसे अभ्यर्थी सब प्रकार से इन सवर्गों में नियुक्ति के लिये उपयुक्त हैं, इन सवर्गों में नियुक्तियाँ की जावेंगी।]

<sup>1</sup>भाग (5) आशुलिपिकों के पदों तथा साधारण सवर्ग के लिये प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने का तरीका। अहतायें—

<sup>2</sup>19 परीक्षाओं का समय—(Frequency of examination)—नियम 7

❧ वि स 10(1) नियुक्ति (क) 56 दिनांक 14 7-1962 तथा स एफ 7 (8) नियुक्ति (घ) 59 दि 28 7 1961 द्वारा जोड़ा गया तथा प्रति स्थापित किया गया।

1 “भाग (5) साधारण सवर्ग में सीधी भर्ती की प्रक्रिया” के अन्तर्गत प्रति स्थापित—दि 15 3 78 की विज्ञप्ति द्वारा

2 वि स प 3 (5) DOP/A-II/78 दिनांक 21 5 1979 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित, जा वि स एफ 3 (4) DOP/A-II/77 दि 15 3 78 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था—

में विहित प्रतियोगिता-परीक्षाएँ प्रत्येक वर्ष ऐसे स्थानों पर आयोजित की जावेंगी, जैसा कि आयोग तय करे

परन्तु यह है कि—आयोग राजस्थान सचिवालय मन्त्रालयिक सेवा नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त स्थानों के लिये संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर सकेगा। एक अभ्यर्थी अधीनस्थ कार्यालय तथा सचिवालय के रिक्तस्थानों के लिये आवेदन करने का हकदार होगा जिसके लिये केवल एक आवेदन पत्र कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिये होगा और अभ्यर्थी आवेदन पत्र में कनिष्ठ लिपिक (सचिवालय) या कनिष्ठ लिपिक (अधीनस्थ कार्यालय) के चयन (चोइस) का उल्लेख करेगा। ऐसी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को केवल एक परीक्षा शुल्क देनी होगी। आयोग सकल अभ्यर्थियों की जिन्होंने राजस्थान अधीनस्थ कार्यालयों के लिये आवेदन किया नियम 24 के अनुसार तथा राजस्थान सचिवालय मन्त्रालयिक सेवा नियम 1970, के नियम 22 (1) (ख) के अनुसार, उन अभ्यर्थियों के मामले में जिन्होंने यशोक्त सेवा के लिये आवेदन किया, एक सूची बनायेगा।

परन्तु यह और है कि—अधीनस्थ कार्यालयों के कनिष्ठ लिपिकों के पदों के लिये प्रतियोगिता-परीक्षा आयोग द्वारा क्षेत्रानुसार (Zonalwise) आयोजित की जावेगी। इस प्रयोजनार्थ क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे—

- (1) जयपुर क्षेत्र I—जिसमें जयपुर, अजमेर, टोंक, सीकर तथा भुवनेश्वर जिले सम्मिलित होंगे।
- (2) जयपुर क्षेत्र II—जिसमें अलवर, भरतपुर तथा सवाई माधोपुर जिले सम्मिलित होंगे।

[19 परीक्षा की पुनरावृत्ति—नियम 7 के अधीन विहित प्रतियोगिता परीक्षा प्रत्येक वर्ष में ऐसे स्थानों पर आयोजित की जायेगी, जो आयोग तय करे,

परन्तु यह है कि—नियम 7 के अधीन विहित ग्रहता-परीक्षाएँ प्रत्येक छ मास के बाद आयोग द्वारा निर्धारित स्थानों पर आयोजित की जायेगी।]

नोट—दि 15 3 78 से पूर्व इस नियम 19 में उपरोक्त नये नियम दि 21 5 1979 के प्रथम परतुक तक का नियम एकसमान था जो विलुप्त सं एफ 10 (1) नियुक्ति (क) 55 दिनांक 16 6 1959 तथा वि स एफ 7 (18) नियुक्ति (घ) 59 दिनांक 28 7 1961 के द्वारा यह निम्न के लिए प्रति स्थापित किया गया था—

“समस्त विभागों के साधारण सवर्ग की सीधी भर्ती के लिए एक प्रतियोगिता-परीक्षा प्रतिवर्ष प्रत्येक द्वितीय जनसंख्या के आधार पर आयोजित की जावेगी।



- (3) कोटा क्षेत्र—जिसमें कोटा, बूंदी व भातावाड जिले सम्मिलित होंगे।
- (4) उदयपुर क्षेत्र—जिसमें उदयपुर, डगरपुर, बासवाडा, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाडा जिले सम्मिलित होंगे।
- (5) बीकानेर क्षेत्र—जिसमें बीकानेर, चुरू और गयानगर जिले सम्मिलित होंगे।
- (6) जोधपुर क्षेत्र—जिसमें जोधपुर, बाडमेर, जासोर, सिरोही, पाली, नागौर और जैसलमेर जिले सम्मिलित होंगे।

3[20 परीक्षाओं के संचालन तथा पाठ्यक्रम के लिये प्राधिकार—

इन नियमों की नियम 19 के अनुसार परीक्षाएँ आयोग द्वारा संचालित की जाएँगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम इन नियमों से सलग अनुसूची I में वर्णित होगा।]

21 आवेदन पत्र आमन्त्रित करना—परीक्षा में बैठने हेतु आवेदन पत्र आयोग द्वारा पदा के विज्ञापन द्वारा पदों के विज्ञापन द्वारा, जिस प्रकार वह उचित समझे, आमन्त्रित किये जावेंगे और ऐसे प्रपत्र में होंगे जैसा कि वह (आयोग) अनुमोदित करे तथा 4[प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में तीन जिलों या विभागों के नाम बतान होंगे, जिनमें वह सेवा करना चाहता है।]

3 वि स एफ 3 (4) DOP/A-2/77 दिनांक 15 3 1978 द्वारा निम्ना-  
मिन् के लिये प्रतिस्थापित—

“20 परीक्षाएँ आयोजित करने के लिए प्राधिकारी तथा पाठ्यक्रम—  
परीक्षा प्रतिवर्ष आयोग द्वारा आयोजित की जावेगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम अनुसूची I में दिया गया है।”@

[@ वि स एफ 7 (18) नियुक्ति (घ) 59 दिनांक 28 7 1961 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—

परीक्षा आयोजित करने के लिए प्राधिकारी एवं पाठ्यक्रम—वर्ष भर में अपेक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिये दी गई मांग के आधार पर, जो 1 दिसम्बर तक नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा आयोग को मूचित की जावेगी, “परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जावेगी। मांग पत्र 1 दिसम्बर तक मन्षा को बतायगा। मांगपत्र में प्रत्येक द्विवीजन में रिक्त कार्यालयों में रिक्त स्थानों की संख्या बताई जावेगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम जैसा अनुसूची I में दिया है, होगा।”]

4 वि स एफ 10 (1) नियुक्ति (ग) 55 दिनांक 16 6 1959 तथा वि स एफ 7 (18) नियुक्ति (घ) 59 दिनांक 28 7 1961 द्वारा जाह  
गया व प्रतिस्थापित किया गया, जो इस प्रकार था—

‘अभ्यर्थी आयोग को ऐसी पुस्तक देंगे जो आयोग कबित करेगा।’

×<sup>5</sup> [विलोपित]

6[परंतु यह है कि—जनिष्ठ लिपिका के पद के लिये प्रतियोगी-परीक्षा के मामले में अभ्यर्थियों की नियम 19 में वर्णित क्षेत्रानुसार आवेदन करना होगा और प्रत्येक अभ्यर्थी करने आवेदन पत्र में दो जिलों के नाम प्राथमिकता के क्रम में उल्लिखित करेगा, जिनमें वह अपनी नियुक्ति चाहता है।]

7[ 21 क-परीक्षा शुल्क—

(1) सेवा के पद पर सीरी भर्ती के लिये अभ्यर्थी आयोग को ऐसी शुल्क देने प्रचार में देगा, जैसा आयोग द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जावे।

(2) न तो परीक्षा शुल्क के प्रत्यर्पण (वापसी) के लिये किसी दावे (मांग) पर विचार किया जायगा, न वह शुल्क किसी अभ्यर्थी परीक्षा के लिये आरम्भित की जा सकेगी, सिवाय इसके जब किसी अभ्यर्थी को आयोग द्वारा परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो ऐसे मामले में प्रत्यर्पण (वापसी) से पहले उस राशि में 5/- रुपये की कटौती करली जावेगी।]

5 वि स एक 3 (3) DOP (क 2) 76 दिनांक 30 6 1976 द्वारा विलोपित, जो इस प्रकार था—

“परंतु यह है कि—आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा जाने वाले पदों के अतिरिक्त विशिष्ट रिक्त पदों के 50 प्रतिशत तक में उल्लिखित अभ्यर्थियों के नामों को सुरक्षित सूची में रख सकेगा। आयोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी गई मूलसूची के दिनांक से छ माह के भीतर मांग करने पर ऐसे अभ्यर्थियों के नाम योग्यता के क्रम में नियुक्ति प्राधिकारी को अभिलेखित किय जा सकेंगे।”

6 वि स 3 (5) DOP/ A- II/78 दिनांक 21 5 1979 द्वारा जोड़ा गया।

7 वि स एक 9 (23) नियुक्ति (क 2) 72 दिनांक 17 6 1978 द्वारा निम्न के लिये प्रविस्थापित—

“21 क-परीक्षा शुल्क—प्रतियोगिता/ग्रहणा परीक्षा में बैठने वाला अभ्यर्थी आयोग को उसके द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान उपरोक्त वि स 3 (4) DOP/A-2-/77 दिनांक 15 3 78 द्वारा निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था—

\*“21 क-परीक्षा शुल्क-सेवा में किसी पद की सीबी भर्ती के लिये एक अभ्यर्थी आयोग द्वारा निश्चित शुल्क उसे देगा, [ क्रमश

8 22 परीक्षा में प्रवेश—कोई अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायगा, जब तक कि वह उस परीक्षा के लिये आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है। ऐसा प्रमाण पत्र देने के पहले आयोग स्वयं का समाधान कर लेगा कि—आवेदन पत्र सवया आयोग द्वारा स्वीकृत तरीके से प्रपत्र (फार्म) में दिया गया था।

परन्तु यह है कि—आयोग अपने विवेकाधिकार से विहित प्रपत्र (फार्म) भरने में हुई सद्भावपूर्ण त्रुटियों या आवेदन प्रस्तुत करने को परिशोधित करने या कोई

\* परन्तु शत यह है कि—बर्मा और चीनका से 1 3 1963 को या बाद में तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों के—या, टांगानिका, युगांडा तथा जजीबार से वापस आये व्यक्ति आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा विहित आवेदन शुल्क या परीक्षा शुल्क, जो भी हो, के भुगतान से मुक्त हों, पर शत यह है कि—आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी, यथा स्थिति, का यह समाधान हो जाय कि ऐसे व्यक्ति ऐसी शुल्क देने की स्थिति में नहीं हैं।

\* उपरोक्त परन्तु कि स एफ 1 (20) नियुक्ति (क) 2/67 दि 20 2 78 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो दि 29 2 1977 तक प्रभावी रहा। उपरोक्त नियम वि स एफ 1 (2) नियुक्ति/60 दिनांक 15 7 1966 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित किया गया था—

“21 क परीक्षा शुरु—(1) एक अभ्यर्थी को अनुसूची (2) के कालम 2 दिखाये गये पद पर सीधी भर्ती के लिये आयोग को ऐसे प्रकार से जैसा आयोग अनुमोदित करे कालम 3 में तथा यदि वह अनुमूचित जातियां या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, तो कालम 4 में उस पद के लिये विनिर्दिष्ट परीक्षा शुल्क देनी होगी। (2) परीक्षा शुल्क की वापसी का कोई दावा नहीं माना जावेगा, न शुल्क किसी अन्य परीक्षा के लिये सुरक्षित की जा सकेगी, जब तक कि—अभ्यर्थी को उस परीक्षा में प्रविष्ट नहीं कर लिया गया हो जिसके लिये वह शुल्क दी गई थी। इस प्रकार के मामले में अनुसूची (3) के कालम 5 में वर्णित कटौती वापसी के पहले की जावेगी।”

8 वि स एफ 10(1) नियुक्ति (क) 55 दि 16 5 1959 तथा स एफ 7 (18) नियुक्ति (घ)/59 दिनांक 28 7 1961 द्वारा निम्न के लिये प्रति स्थापित—

22 परीक्षा में प्रवेश—परीक्षा के लिये प्रवेश उन अभ्यर्थियों की संख्या तक सीमित होगा, जो हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्त कुल अंका के प्रतिशत के आधार पर योग्यता के क्रम में भरे जाने के अपक्षित रित्त स्थानों की संख्या से पाँच गुने से अधिक नहीं होंगे। प्रत्येक अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में उस द्विजीन का नाम देना होगा, जिसमें वह सेवा करना चाहता है।

प्रमाण पत्र आवेदन के साथ नहीं दिया जाने पर परीक्षा के आरम्भ से पूर्व ठीक समय में द देने पर अनुमति दे सकेगा ।

9 23 ध्यक्तित्व तथा साक्षात्कार (मौखिक) परीक्षा [विलोपित]

24 चयन (सलेक्शन) —

10 (1) आयोग नियम 19 में विहित क्षेत्रा (जोस) के आधार पर, योग्यता सूचियाँ तथा सार राज्य के लिये भी उन अभ्यर्थियों की, जो कनिष्ठ लिपिक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त 'यूनतम अहता' के अनुसार सफल घोषित हुए हैं, एक सम्मिलित योग्यता सूची तैयार करेगा ।

परन्तु यह है कि—आयोग, अतिरिक्त रूप से सूचित की गई रक्तिया के 50% तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम आरम्भित सूची में रख सकेगा । ऐसे अभ्यर्थियों के नाम, मूल सूची आयोग द्वारा सरकार का कार्मिक विभाग में संप्रेषित करने के दिनांक से छ मास के भीतर माँग पत्र प्राप्त होने पर जैसा आयोग तय करे उसी तरीके से, योग्यता के अंश में सरकार की कार्मिक विभाग में अतिरिक्त रक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिये अभिशसित कर सकेगा ।

9 वि स 10(1) नियुक्ति (क) 55 दि 16 6 1959 द्वारा विलापित जो इस प्रकार था—

23 ध्यक्तित्व तथा साक्षात्कार परीक्षा—ध्यक्तित्व तथा साक्षात्कार परीक्षा के लिय आयोग द्वारा केवल ऐसे अभ्यर्थियों को बुलाया जावेगा, जिहाने आयोग के अभिमत में पर्याप्त उच्च अंक प्राप्त किये हा, परन्तु यह है कि—कोई व्यक्ति जो कुल अंक का 45% तथा प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 40% अंक प्राप्त करने में असफल रहा है, साक्षात्कार के लिये नहीं बुलाया जावेगा । अभ्यर्थी का आयोग के किसी एक सदस्य द्वारा साक्षात्कार लिया जा सकेगा । प्रत्येक प्रशासनिक डिवीजन का डिवीजनल कमिशनर या उसके द्वारा मनोनीत एक जिलाधीन साक्षात्कार में उपस्थित रहगा, यदि ऐसा साक्षात्कार राज्य की राजधानी से बाहर आयोजित किया जावे ।

10 वि स एफ 3(5) DOP/A-II/78 दिनांक 21 5 1979 द्वारा उपनियम (1) व (2) के स्थान पर उपरोक्त नया उपनियम (1) प्रतिस्थापित तथा उपनियम (3), (4), (5) को क्रमश (2), (3) व (4) पुनर्संख्याकित कर उपनियम (6) को विलोपित किया गया, जो निम्न प्रकार से थे—

24 चयन (सलेक्शन)—(1) कनिष्ठ-लिपिक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त 'यूनतम अहता-अंक' के अनुसार आयोग सफल घोषित अभ्यर्थियों की एक योग्यता-सूची (मेरिट लिस्ट) निम्न प्रकार से तैयार करेगा—

(क) अभ्यर्थियों की साधारण सूची 'क', जो कुल योग के 60% या अधिक अंक प्राप्त करते हैं ।

परंतु यह और है कि—समय समय पर सरकार द्वारा विहित प्रारक्षण के अनुसार आयोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के एक अलग सूची भी तैयार करेगा और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के लिये इन नियमों में विहित टक्का परीक्षा में अर्हताको का प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होगा, परंतु टक्का परीक्षा में प्राप्त अंक उनके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़े जावेंगे।

(2) अभ्यर्थियों के नाम सम्बंधित सूचियों में उनके द्वारा परीक्षा में प्राप्त किये कुल अंकों के क्रम में व्यवस्थित किये जावेंगे।

(3) आयोग प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक तथा कुल अंकों में तीन तक कृपाक किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिये प्रदान कर सकेगा, जो अथवा उस परीक्षा में अर्हता प्राप्त (Qualified) नहीं कर सकता था।

परंतु यह है कि—आयोग किसी अभ्यर्थी की अभिशप्ता नहीं करेगा, जो कनिष्ठ लिपिक परीक्षा में प्रत्येक अनिवार्य तथा ऐच्छिक प्रश्न पत्र में कम से कम 35% अंक प्राप्त करने में असफल रहा हो।

(ख) अभ्यर्थियों की साधारण सूची 'ख', जो कुल के 60% से कम अंक प्राप्त करते हैं।

(ग) प्रारक्षित सूची अलग से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की,

परंतु यह है कि—इन नियमों में विहित टक्का परीक्षा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के लिये अर्हता-अंकों का प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होगा किंतु टक्का-परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंक कुल प्राप्तांकों में जोड़े दिये जावेंगे।

(2) साधारण सूचियों में उन अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित किया जायगा, जो इन नियमों के नियम 7 के परंतु 3 के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये प्रारक्षित रिक्त स्थानों के लिये या भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु 3 के अधीन बन किन्हीं नियमों के अधीन रिक्त स्थानों के अथवा प्रारक्षण (के लिये) भर्ती चाहते हैं।

(6) साधारण सूची 'ब' तथा साधारण सूची 'ख' परीक्षा पत्र की वापस की दिनांक के बाद के चौबीस महीनों के लिए और मरुक्षित सूची अगले छत्तीस

11 [X×विलोपित]

(4) आयोग इन सूचियों को सचिवालय के व्यवस्था एवं पद्धति विभाग को भेजेगा, जो इसको समस्त सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारियों को सूचना के लिए अधिसूचित करेगा। इन सूचियों में से व्यवस्था एवं पद्धति विभाग अभ्यर्थियों को विभिन्न निम्न प्राधिकारियों को उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई योग्यता (श्रेणियाँ) सूचियाँ में उनके द्वारा प्राप्त स्थान (पोजीशन) के आधार पर और विभाग में रही गयी रोस्टर सूची के अनुसार आवंटित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं जैसी आवश्यक समझे, वैसे जाच-पड़ताल करने के बाद समाधान करेगा कि ऐसे अभ्यर्थी किस प्रकार से (उन) पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं।

10 [(6) विलोपित]

1224क—आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के चयन तथा नियुक्ति का तरीका—

(1) आशुलिपिकों की ग्रहता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की आयोग सूचियाँ तैयार करेगा। ऐसी सूचियाँ आयोग द्वारा कार्यालय एवं प्रशासनिक सुधार (प्रशासनिक सुधार) विभाग को सचिवालय में भेजी जावेगी, जो उन्हें सूचनाय समस्त नियुक्ति-प्राधिकारियों को अधिसूचित करेगा। ऐसी सूचियों में से प्रशासनिक सुधार विभाग विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियों को सम्बन्धित विभाग द्वारा धारित किये गये रोस्टर (सूची) के अनुसार अभ्यर्थियों का आवंटन करेगा। आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के मामले में सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी जाच (पूछताछ) करने के बाद जो वह आवश्यक समझे, स्वयं का समाधान करेगा कि—ऐसे अभ्यर्थी सब प्रकार से आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के अन्याय उपयुक्त हैं।

परन्तु यह है कि—आयोग किसी (ऐसे) अभ्यर्थी की अनुमति (सिफारिश) नहीं करेगा, जो आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी की परीक्षा में आशुलिपिक के प्रश्नपत्र

महीनों के लिये प्रभावशील रहेगी। पिछले पूर्व वर्ष की साधारण सूची 'क' इस चालू वर्ष की साधारण सूची 'क' तथा साधारण सूची 'ख' पर प्राथमिकता प्राप्त करेगी। पूर्व (पिछले) वर्ष की साधारण सूची 'ख' वर्तमान (चालू) वर्ष की साधारण सूची 'क' तथा साधारण सूची 'ख' के समाप्त होने पर विचारणीय होगी।

11 वि स एफ 3(4) DOP/क-II/77 दि 15 3 78 द्वारा विलोपित जो निम्न प्रकार से था, इसमें तारांकित भाग वि स एफ 3(3) DOP/क-II/75 दि 17 5 77 द्वारा जोड़ा गया था—

“परन्तु यह भी है कि—आयोग किसी अभ्यर्थियों की अनुमति नहीं करेगा जो आशुलिपि तथा टंकण परीक्षा के प्रश्न पत्रों में कम से कम 35% अंक तथा कुल अंकों का कम से कम 40% \* [तथा आशुलिपिक प्रथम श्रेणी के लिये ग्रहता—परीक्षा में 40% अंक] प्राप्त करने में असफल रहा हो।

12 वि स एफ 3 (4) DOP/क-2/77 दिनांक 15 3-78 द्वारा जोड़ा गया।

तथा टक्का परीक्षा के प्रश्नपत्र में प्रत्येक में न्यूनतम 35 प्रतिशत तथा कुल में से 40% तथा आशुलिपिक प्रथम श्रेणी की अहता परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करने में असफल रहा हो।

परंतु आगे यह है कि—आयोग प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक तक तथा कुल में म तीन तक कृपाक किसी अभ्यर्थी की आशुलिपिका की परीक्षा में अहता प्राप्त करने के लिये दे सकेगा, जो अभ्यर्थी उस परीक्षा में अहता प्राप्त नहीं करता।

(2) आयोग द्वारा उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई दो वष की अवधि के लिये प्रभावी रहेंगी।

#### भाग (4) नियुक्तियाँ, परिवीक्षा तथा पुष्टीकरण (स्थायीकरण)

##### 25 निम्नलिखित श्रेणियों में नियुक्तियाँ—

<sup>1</sup>[(1) आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी तथा कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर नियुक्ति सम्बन्धित नियुक्ति-प्राधिकारियों द्वारा क्रमशः नियम 24 तथा 24क के अधीन तैयार किये गये सम्बन्धित सवग में या दूसरे विभाग से व्यक्तियों के स्थानान्तर द्वारा नियम 7 के परतुक (1) के अधीन ऐसे स्थानान्तर के लिये पात्र हो, की जावेंगी।

<sup>1</sup>[(2)  $\times$  विलोपित]

<sup>2</sup>(2) नियम 7 में किसी बात के हात हुए भी, कनिष्ठ लिपिक के रूप में

1 वि स एफ 3 (4) DOP (क-2) 77 दिनांक 15-3-1978 द्वारा नियम 25 (1) प्रतिस्थापित तथा उपनियम (2) विलोपित एवं परतुक (2) को उपनियम (3) पुनर्स्थापित किया गया, जो इस प्रकार है—

“(1) आशुलिपिक तृतीय श्रेणी कनिष्ठ लिपिक के पदों पर अधिष्ठायी नियुक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा क्रमशः नियम 18 (2) तथा नियम 24 (2) में विहितप्रकार से सम्बन्धित सवग में अधिष्ठायी रिक्त स्थान होने पर या दूसरे विभाग से व्यक्तियों के स्थानान्तर द्वारा नियम 7 के परतुक के अधीन ऐसे स्थानान्तर के लिय पात्र होने पर की जावेगी।”

(2) आशुलिपिक तृतीय श्रेणी या कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद की अस्थायी रूप से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, अस्थायी रूप से, उस पर नियमित व्यक्तियों की योग्यता के क्रम में नियुक्ति के द्वारा भरे जा सकेंगे, जो प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हुये थे परंतु या तो अहताक प्राप्त न कर सके या अहताक प्राप्त करने पर भी अधिष्ठायी नियुक्तियाँ प्राप्त न कर सके।

(1) परंतु यह है कि— जब तक प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है, कोई उपयुक्त व्यक्ति, जो नियम 11 से 15 के अधीन बाध्यकारी अहताक रखता हो, अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा।

दिनांक 31-3-1973 तक अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, जो ऐसे पदों या उच्चतर पदों को लगातार धारण करते आ रहे हैं, अस्थायी आधार पर नियमित रूप से नियुक्त माना जावेगा, परन्तु वे इन नियमों में विहित अग्र शर्तें पूरी करते हों। उनकी अस्थायी नियुक्ति की दिनांक के अनुसार और स्थायी रिक्त स्थान प्राप्त होने पर और उनका कार्य सतोषजनक पाया जाने पर कनिष्ठ लिपिक के रूप में अविष्ठायी नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

परन्तु यह है कि—यह व्यक्ति जो कनिष्ठ लिपिक के रूप में अस्थायी रूप से कार्य कर रहा है और जिसका कार्य सतोष जनक नहीं पाया गया हो वह सेवा से हटाया जाने योग्य होगा।

(1) उसे एक माह का नोटिस देते हुए, यदि उसने राजकाज में तीन वर्ष से कम के लिये सेवा की हो, और

(ii) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 में दिये गये 'तरीके' का पालन करते हुए, यदि उसने तीन वर्ष से अधिक के लिये सेवा की हो। 31-3-1973 के बाद अस्थायी रूप से कनिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्त समस्त व्यक्तियों को इन नियमों में विहित प्रतियोगिता-परीक्षा के द्वारा नियमित भर्ती प्राप्त करनी होगी।

3(3) नियम 7 में किसी बात के होते हुए भी, समस्त व्यक्ति जो 1-4-1973 को या इसके बाद कि तु 1-8-1977 से पहले तदर्थ (एडहॉक) आधार पर कनिष्ठ लिपिक के रूप में कार्य कर रहे थे और जा 1976 में इन पदों के लिये आयोग द्वारा नियमित भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगिता-परीक्षा में न बैठ सके या उत्तीर्ण न हो सके, इन पदों पर नियुक्ति के लिये सफल अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पदों के उपलब्ध होने पर कनिष्ठ लिपिकों के पदों के विरुद्ध समायोजित किय जावेंगे, उनको 4[अनुसूची I के भाग IV में विहित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रवृत्ता-परीक्षा] उत्तीर्ण करने के लिये तीन अवसर दिये जावेंगे, चाहे वे इन नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को पार कर चुके हों।

25 क—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए विशेष उपबन्ध—नियम 8, 9, 11 तथा 19 से 25 में किसी बात

3 वि स 5 (8) DOP (क-2) 77 GSR 69 दिनांक 28-1-1978 द्वारा परन्तु के रूप में जोड़ा गया।

4 वि स एफ 5 (8) DOP/A-II/77 भाग 2 दिनांक 5-10-1978 द्वारा शब्द "उपरोक्त परीक्षा" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।

5 वि स 10 (1) नियुक्ति (क) 55 दिनांक 27-11-1958 द्वारा जोड़ा गया।



के होने हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी के लिये, विशेष षटम (measure) के रूप में 28 फरवरी 1960 तक कनिष्ठ लिपिकों के पद पर अनुसूचित जातियां तथा जन-जातियों के सदस्यों में से, सरकार द्वारा विहित प्रकार से, नियुक्तियां करना सक्षम होगा।

#### 6 16 वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियाँ—

6 वि स एफ 3(11) कामिक (क-2) 74 दिनांक 8 2 1975 से निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित—

#### “26 वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियाँ—

(1) किसी सवर्ग में वरिष्ठ पद पर नियुक्ति पदोन्नति द्वारा की जावेगी, सिवाय वरिष्ठलिपिक के पद के, जो कि आंशिक रूप से पदोन्नति द्वारा और आंशिक रूप से सीधी भर्ती द्वारा भरा जावेगा। वरिष्ठ लिपिकों की नियुक्तियां करने में, पहली तीन नियुक्तियां पदोन्नति द्वारा की जावेगी और शेष सीधी भर्ती द्वारा और आगे इसी क्रम से। वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर की जावेगी

परंतु यह है कि, किसी विशिष्ट वष में, नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि—पदोन्नति के लिये पात्र कनिष्ठ लिपिकों की संख्या उस वष में वरिष्ठ लिपिकों के पदों के रिक्त स्थानों की संख्या से दस गुना बढ़ जाती है, तो वह उस वष में सीधी भर्तियों को छोड़ सकता है

परंतु आगे यह भी है कि—राजस्थान नहर मण्डल तथा मण्डल के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों में वरिष्ठ लिपिकों के पद पर नियुक्ति या तो उपयुक्त कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा की जा सकेगी। सीधी भर्तियों के मामले में मण्डल द्वारा नियुक्ति (निम्न) चयन समिति द्वारा किए गए चयन के आधार पर की जावेगी—

- |  |         |
|--|---------|
| 1 बोर्ड के सचिव  | अध्यक्ष |
| 2 सहायक वित्तीय सलाहकार                                    | सदस्य   |
| 3 उपनिवेश आयुक्त/मुख्य अभियन्ता के तकनीकी सहायक, यथास्थिति | सदस्य   |

बोर्ड के सहायक सचिव इस चयन समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा—

परंतु यह भी है कि—राजस्व मण्डल के सहायक पजीयक के पद पर नियुक्ति (निम्न) चयन समिति द्वारा पदोन्नति से की जावेगी—

- (1) अध्यक्ष राजस्व मंडल या उनके द्वारा मनोनीत राजस्वमंडल का एक सदस्य अध्यक्ष

(1) बरिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति, क्रमशः नियम 7 के उपनियम (ग) तथा नियम 26 ड (E) में दिये गये तरीके के अनुसार, तथा अर्ध समकक्ष तथा उच्चतर पदों पर नियम 26 घ (D) के उपनियम (4) के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित सम्बन्धित सूचियों में से व्यक्तियों का लेकर उस क्रम में जिसमें ऐसी सूचियों में उनको रखा गया है, की जावेगी, जब तक कि वे (सूचियाँ) पूरी नहीं हो जाती हैं।

परन्तु यह है कि—राजस्वमण्डल के सहायक पञ्जीयक के पद पर नियुक्तियाँ (निम्न) चयन समिति द्वारा पदोन्नति से की जावेगी—

(i) राजस्वमण्डल के अध्यक्ष या उनके मनोनीत राजस्व मण्डल का सदस्य अध्यक्ष

(ii) भू प्रबंध आयुक्त सदस्य

(iii) उपनिवेश आयुक्त सदस्य

परन्तु भागे यह भी है कि—प्रशासनिक अधिकारी या स्थापना अधिकारी के पद पर नियुक्ति (निम्न) चयन समिति की अभिसंधाओं के आधार पर की जावेगी—

(i) निदेशक, ह. व. मा. लोकप्रशासन संस्थान अध्यक्ष

(ii) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष सदस्य

(iii) कामिक विभाग का एक प्रतिनिधि, जो उपशासन सचिव से निम्न योएली का न हो सदस्य

चयन करने के लिये नियम 26-B, 26-C तथा 26-D में दिया गया तरीका अपनाया जावेगा। समिति योग्यता (मेरिट) के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की सूची (पैनल) तैयार करेगी।

(2) किसी व्यक्ति की दूसरे विभाग से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति नहीं की जावेगी, यदि इसमें उच्चतर पद पर पदोन्नति अन्तर्बलित होती हो, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का स्वयं का यह समाधान न हो जाय कि पदोन्नति के लिये उपयुक्त कोई व्यक्ति विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(ii) भू प्रबंध आयुक्त सदस्य

(iii) उपनिवेश आयुक्त सदस्य।

7 वि. स. एफ. 3 (7) DOP (क-2) 75 दि. 20.9.1975 द्वारा निविष्ट तथा दिनांक 1.9.1975 से प्रभावशील।

8(3) आवश्यक (अर्जेंट) अस्थाई नियुक्तियाँ—(Urgent Temporary Appointments)—(1) सेवा में एक रिक्त स्थान जो कि नियमों में अधीन या तो सीधी भर्ती से या पदोन्नति द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता है, सरकार या 'नियुक्तियाँ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी', यथास्थिति, द्वारा उस पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र अधिकारी को स्थानापन्न रूप से नियुक्त करके, या सेवा में सीधी भर्ती के लिए पात्र व्यक्ति को, जहाँ ऐसी सीधी भर्ती इन नियमों के उपबन्धों के अधीन दी गई है, अस्थाई रूप से नियुक्त करके भरा जा सकेगा।

परन्तु यह है कि—ऐसी कोई नियुक्ति आयोग की उस मामले में सहमति प्राप्त बिन्दु बिना, जहाँ ऐसी सहमति आवश्यक हो, एक वर्ष की अवधि से आगे जारी नहीं रखी जावेगी और उस (आयोग) के द्वारा सहमति देने से इंकार कर दान पर वह (नियुक्ति) तुरन्त समाप्त कर दी जावेगी।

<sup>10</sup>परन्तु आगे यह भी है कि—किसी सेवा या सेवा में किसी पद के लिए जिसके लिए भर्ती के उपरोक्त दोनों तरीके विहित किये गये हैं, सरकार या नियुक्ति

8 वि स एफ 1 (10) नियुक्ति (क-2) 72 दिनांक 16-2-1973 द्वारा निम्न के लिए प्रतिस्थापित—

(3) अस्थायी नियुक्तियाँ—(1) नियम 15 में किसी बात के होते हुए भी, अधीक्षक या मुख्यलिपिक (विभागाध्यक्ष कार्यालय तथा अन्य कार्यालयों में), वरिष्ठ लिपिक, (सहायक), या आधुनिक लिपिक श्रेणी प्रथम और द्वितीय के रिक्त स्थान अस्थाई रूप से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों के वरिष्ठतम उपयुक्त कर्मचारी की स्थानापन्न नियुक्ति द्वारा भरे जा सकेंगे।

(2) वरिष्ठ लिपिक का रिक्तस्थान जो साधारणतया सीधी भर्ती से भरा जाता है, अस्थाई तौर पर नियुक्ति-प्राधिकारी द्वारा कार्यालयाध्यक्ष तथा विभागाध्यक्ष द्वारा मनोनीत उस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी के साथ बर्तन गत समिति की अभिप्राय पर उस पर इस प्रकार अभिमतित अर्थों को अस्थाई रूप से नियुक्त करके भरा जा सकेगा यदि आयोग का कोई मनोनीत (अर्थों) उपलब्ध न हो।

(3) कनिष्ठ लिपिक या आधुनिक लिपिक का रिक्त स्थान अस्थाई तौर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सबसे अधिक उपयुक्त उपलब्ध अर्थों को अस्थाई रूप में नियुक्त कर भरा जा सकेगा, यदि आयोग का कोई मनोनीत (अर्थों) उपलब्ध न हो।

9 वि स एफ 1 (10) DOP (क-2) 72 दिनांक 12-9-1973 के अधीन शुद्धिपत्र द्वारा शब्द 'नियुक्ति प्राधिकारी' के स्थान पर प्रतिस्थापित

10 वि स एफ 1 (10) DOP (क-2) 72 दिनांक 28-11-1973 द्वारा निम्न के लिए प्रतिस्थापित—

करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, जैसी स्थिति हो, राज्य सेवा के मामले में कार्मिक विभाग में सरकार की तथा अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग में सरकार की विशिष्ट अनुमति के अलावा, सीधी भर्ती के कटे में अस्थाई रिक्त स्थान को तीन माह से अधिक की अवधि के लिए पूरवर्तक नियुक्ति द्वारा सीधी भर्ती के लिए पान व्यक्तियों में से तथा अल्पकालिक विज्ञापन दिये बिना के अथवा, नहीं भरेगा।

<sup>11</sup>(11) पदोन्नति के लिए पानता की शता का पूरी करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता की दशा में, सरकार, उपरोक्त खण्ड ( ) में बाधित पदां प्रति के लिए पानता की चाहे, कोई भी शत क्यों न हो, आवश्यक अस्थायी आधार पर रिक्त स्थानों को भरने की अनुमति देने के लिए, वेतन तथा अन्य भत्ता सम्बन्धी ऐसे प्रतिबंध तथा शर्तें जसी वह दे उनके अधीन रहते हुए सामान्य निर्देश जारी कर सकेगी। ऐसी नियुक्तियां, येनकेन, आयोग की सहमति के अधीन रहेगी जसा कि उपरोक्त खण्ड के अधीन वांछित है।

<sup>12</sup>[(11)] आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के पदों पर आवश्यक अस्थायी नियुक्ति करने पर प्रतिबंध—अधीनस्थ कार्यालयों में आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के सब्ग में आगे से कोई आवश्यक अस्थाई नियुक्ति नहीं की जावेगी।]

<sup>13</sup>(4) कनिष्ठ लिपिकों के लिए आवश्यक अस्थायी नियुक्ति हेतु विशेष शर्तें—कनिष्ठ लिपिकों के पद पर कोई आवश्यक अस्थायी नियुक्ति सिवाय (उन) व्यक्तियों के जो कि नियम 30 के खण्ड (कक) के अधीन टक्का परीक्षा से मुक्त कर दिये गये हैं, नहीं की जायगी, जब तक कि एक व्यक्ति नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित टक्का परीक्षा में अंग्रेजी में 25 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण नहीं हो जाता है। इस प्रकार का प्रमाणपत्र नियुक्ति आदेश में ही अभिलिखित किया जावेगा।

“परंतु आगे यह भी है कि—किसी सेवा या सेवा में किसी पद के लिए जहां भर्ती के लिए दोनों तरीके विहित हैं सरकार या नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, जसी भी स्थिति हो, सीधी भर्ती के लिए पान किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके अस्थाई रिक्त स्थान को नहीं भरगा, जब तक कि पदोन्नति के लिए उपयुक्त कोई पान व्यक्ति उपलब्ध हो।”

11 वि स एफ 7 (7) कार्मिक (क-2) 75 दिनांक 31 10 1975 द्वारा निविष्ट तथा दि 10-5-1951 से प्रभावशील।

12 वि स एफ 3 (4) LOP (क-2) 77 दिनांक 15-3 1978 द्वारा जोड़ा गया।

13 वि स एफ 3 (1) LOP (क-2) 77 दिनांक 23 3-1977 द्वारा जोड़ा गया।

14 26-अ—नियम 26 में किसी बात में हाते हुए भी, पचायत समिति एवं जिला परिषद सेवाओं का एक सन्तुष्ट सेवा में वरिष्ठ लिपिक का पद धारण करते हुए साधारण सबंध की अगली उच्चतर श्रेणी के पदों पर वेचस जिलाधीन कार्यालय में पदोन्नति के लिए पात्र होगा, परन्तु शत यह है कि वह इन नियमों में उन पदों के लिए वर्णित शर्तें पूरी करता हो। इस प्रकार पदोन्नति स्थितियों की राजस्थान पचायत समिति जिला परिषद सेवा में अधिष्ठायी रूप से पदों को धारण करने की शक्ति की सेवा को वरिष्ठता के प्रयोजनाय तथा राजस्थान सेवा नियम के उद्देश्यों के अनुसार पेशान के प्रयोजनाय संगठित किया जाएगा।

15 26-अ—पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए तरीका तथा मापदण्ड (Criteria)—(1) वरिष्ठ लिपिकों के पदों तथा अन्य समकक्ष पदों तक पदोन्नति

14 वि स एक 10 (1) नियुक्ति (ग) 57 भाग III दिनांक 22-11-1963 द्वारा जोड़ा गया।

15 विज्ञप्ति स एफ 3 (11) वार्षिक (क-2) 74 दिनांक 8 2 1975 द्वारा निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया—

§ 26 ए (1) वरिष्ठ लिपिक के पदों में अथवा उच्चतर पदों पर नियुक्ति सबंध योग्यता के आधार पर तथा वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर 1 2 के अनुपात में चयन द्वारा की जावेगी। वरिष्ठ लिपिक के पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति आगे से वरिष्ठता-सह-योग्यता के एकमात्र आधार पर की जावेगी।

× परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि—किसी व्यक्ति विशेष में सबंध योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये उपर्युक्त शक्ति उपलब्ध नहीं है तो नियुक्ति इन नियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जा सकेगी। ×

§ वि स एक 1 (22) नियुक्ति (क-2) 70 दिनांक 25 9 1972 द्वारा उपरोक्त नियम 26 ए निम्नलिखित के लिये प्रतिस्थापित किया गया था—

“26 ए योग्यता के आधार पर चयन द्वारा पदोन्नति—

(1) वरिष्ठ लिपिकों तथा अन्य वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति सबंध योग्यता के आधार पर तथा वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर चयन द्वारा 1 2 के अनुपात में की जावेगी

× परन्तु की जा सकेगी। (उपरोक्त) ×

(2) सबंध योग्यता के आधार पर चयन उही व्यक्तियों में से किया जायेगा जो इन नियमों के अधीन पदोन्नति के लिये अथवा पात्र हो, ऐसे अभ्यर्थियों की सराया जिनके सबंध में तत्प्रयोजनाय विचार किया जाना है, योग्यता तथा वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भर जान वाले रिक्त पदों की कुल संख्या से दस गुनी

नियम 26 ब्र ] राजस्थान ग्रामीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम [ 59

हेतु चयन वरिष्ठता-सह योग्यता के आधार पर ही किया जावेगा। वरिष्ठ लिपिकों के पद से उच्चतर पदों पर पदोन्नति हेतु चयन सवधा योग्यता के आधार पर तथा वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर 1 2 के अनुपात में किया जावेगा।

परंतु यदि विभागीय-पदोन्नति समिति का समाधान हो जाय कि किसी वय कोप से सवधा योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त कि उपलब्ध नहीं है तो नियुक्ति इन नियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से वरिष्ठता-सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जा सकेगी।

(2) इन नियमों के नियम 15 के ग्रामीन वांछित न्यूनतम ग्रहतायें तथा अनुभव चयन के वय के अग्रतः माह की पहली दिनांक को रखने की सीमा के ग्रामीन नियम 6 के ग्रामीन वर्णित पदों के चारक व्यक्ति पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

होगी परंतु यह तब जब कि अभ्यर्थी इतनी सख्या में उपलब्ध हो। जहां पात्र अभ्यर्थियों की सख्या रिक्त पदों की सख्या के वरिष्ठतम व्यक्तियों के सम्बन्ध में तत्प्रयोजनाय विचार किया जायगा।

परंतु जब तक कि इन नियमों में अथवा उच्चतर कालावधि विहित न की गई हो, समान (उसी) सवग में (निम्न श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में) केवल योग्यता के कोटा में पदोन्नति के लिये केवल वे ही व्यक्ति पात्र होंगे जिन्होंने निम्नतर पद पर 6 वय से ग्रहण सेवा पूरी करली हो।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अपने द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की, सवधा योग्यता के आधार पर, एक अलग सूची तयार करेगा और प्राथमिकता (preference) के क्रम में नामों को व्यवस्थित करेगा तथा अधिष्ठायी रिक्त स्थानों के होने पर योग्यता से भरे जाने वाले पदोन्नति के कोटे में उस सूची में से उसी क्रम में जिसमें उनको सूची में रक्खा गया है, नियुक्ति की जावेगा।

(4) एक ही वय के दौरान पदा की किसी श्रेणी में नियुक्त व्यक्तियों में से वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर नियुक्त व्यक्ति, योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ रहेंगे। पदोन्नति द्वारा पद की किसी श्रेणी में नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, प्राथमिकता क्रम का ध्यान रखे बिना, तय की जावेगी, मानो एस व्यक्ति वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये हों।

(5) इन नियमों में कि ही शाय उपबन्धों में किसी प्रतिकूल बात के हात हुए भी, इस नियम के उपबन्ध प्रभावशील होंगे।

स्पष्टीकरण—उपनियम (1) के ग्रामीन दोनों ही आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की सख्या तय करने के प्रयोजनाय निम्नलिखित चक्रीय क्रम का अनुसरण किया जावेगा—

प्रथम योग्यता के आधार पर, अगले दो वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर, अगला एक योग्यता के आधार पर, अगले दो वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर, यही चक्रीय क्रम दोहराया जायेगा।”

स्पष्टीकरण—जब किसी पद पर किसी विशेष धप में पदोन्नति के लिए नियमित चयन से पहले ही सीधी भर्ती कर ली गई हो, तो ऐसे व्यक्ति जा भर्ती के नौनो तरीका से उस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं या थे और पहले सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर लिए गए हैं, तो उन पर भी पदोन्नति के लिए विचार किया जावेगा ।

(3) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह भगले निम्न पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त तथा पुनः (कनफम) नहीं हो गया है । यदि भगले निम्न पद में कोई अधिष्ठायी व्यक्ति पदोन्नति के लिए पात्र नहीं हो, तो वह व्यक्ति जो ऐसे भर्ती के किसी एक तरीके के अनुसार या पद पर भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक के अधीन वन किसी सेवा नियम के अधीन चयन के बा' स्थानापन रूप से नियुक्त किया गया है, स्थानापन रूप से (उसकी) पदोन्नति के लिए केवल वरिष्ठता के उस क्रम में, जिस पर यदि वह उस निम्न पद पर अधिष्ठायी होने पर होता विचार किया जा सकेगा ।

1626 ग— 'वरिष्ठता-सह योग्यता' के आधार पर चयन का तरीका—

(1) जैसे ही सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी नियम 6 के अधीन रिक्तस्थानों की सरया तय करता है और विनिश्चय करता है कि—कुछ सख्या में पदों की पदोन्नति द्वारा भरना वांछित है, तो वह इन नियमों के अधीन सम्बन्धित पदों के श्रेणी में पदोन्नति के लिए पात्र तथा अहित वरिष्ठतम व्यक्तियों में से रिक्तस्थानों की सरया से पांच गुन से अनाधिक नामा की एक सही तथा परिपूर्ण सूची तयार करेगा ।

(2) एक समिति, जिसमें सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष तथा सम्बन्धित विभाग के दो वरिष्ठ उपविभागाध्यक्ष या जिन विभागों में उपविभागाध्यक्ष नहीं हो वे विभाग के भगले दो वरिष्ठतम अधिकारी और कार्यालय अधीक्षक प्रथम श्रेणी तथा अन्य समकक्ष या उच्चतर पदा के मामले में सरकार के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग का एक प्रतिनिधि भी, सदस्य के रूप में होंगे, उस सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी तथा उनमें से ऐसे व्यक्तियों से साक्षात्कार करेगी जिन्हें वह साक्षात्कार करना आवश्यक समझे और एक सूची तयार करेगी जिसमें उपनियम (1) में उपदर्शित पदों की सरया की दुगुनी सख्या तक उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम अतिरिक्त होंगे ।

(3) समिति एक पृथक सूची तैयार करेगी, जिसमें ऐसे व्यक्तियों के नाम होंगे जिनका चयन पहले से विद्यमान स्थानापन्न रिक्तियों को या ऐसे पदों को जिनमें समिति की आगामी बैठक होने तक रिक्त होने की संभावना हो, भरने के लिए किया जा सके —

(क) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रविष्टि पुनरीक्षित एवं पुनर्विलासित की जायेगी,

(ख) यह सूची सामान्यतः उस समय तक प्रवृत्त (लागू) रहेगी जब तक कि उपनियम (1) के खण्ड (क) के अनुसार पुनर्विलोकिन या पुनरीक्षित न की जाय।

(4) समिति द्वारा चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम पदों के प्रत्येक प्रवर्ग (कैटेगरी) के लिये अलग से उनकी वरिष्ठता के क्रम में व्यवस्थित किए जावेंगे।

(5) समिति द्वारा पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अलग से तैयार की गई सूची सम्बंधित नियुक्ति प्राधिकारी को अभ्यर्थियों की तथा अतिष्ठित व्यक्तियों की भी यदि कोई हो, गोपनीय पत्रों तथा वैयक्तिक पत्रिकाओं के साथ भेजी जावेगी।

1726 घ सेवा में सर्वांगत कनिष्ठ, वरिष्ठ तथा अन्य पदों पर पदोन्नति के लिए संशोधित मापण्ड, पात्रता तथा तरीका—

(1) ज्योंही नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के रिक्रिया के विनिश्चय सम्बन्धी नियम के अधीन रिक्तियों की संख्या विनिश्चित करता है और तय करता है कि—कतिपय (कुछ) संख्या में पद पदोन्नति से भरते हैं, तो उपनियम (9) के उपबंधों की सीमा में रहते हुए वह वरिष्ठतम व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगा जो इन नियमों के अधीन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर या योग्यता के आधार पर सम्बंधित पदों की श्रेणी में पदोन्नति के लिए पात्र तथा अर्हित (eligible & qualified) हैं।

(2) सम्बंधित अनुसूची के कालम (5) या 'पद जिनमें पदोन्नति करनी है' के वार में सम्बद्ध कालम, जसी स्थिति हो में वर्णित व्यक्ति उस (अनुसूची) के कालम 2 में वर्णित पदों पर कालम 3 में विनिर्दिष्ट सीमा तक, कालम 6 या 'पदोन्नति के लिए' यूननम अहता तथा अनुभव सम्बन्धी कालम यथा स्थिति, में वर्णित यूननम अहताये तथा अनुभव चयन के वष के अग्रेत मास के प्रथम दिन का धारण करने पर पदोन्नति के लिये पात्र होंगे।

17 वि.स.एफ. 7 (10) DOP (क-2) दिनांक 7.3.1978 द्वारा प्रतिस्थापित। पुराना नियम 26 घ आगे अलग से दिया जा रहा है।



(3) कोई व्यक्ति जब तक वह अधिष्ठायी रूप से नियुक्त व स्थायी (वनफमड) नहीं है, उसकी पदोन्नति के लिये विचार नहीं किया जावेगा। यदि पिछले निम्नतर पद पर पदोन्नति के लिये पात्र कोई व्यक्ति अधिष्ठायी नहीं है, तो वे व्यक्ति जो ऐसे पदों पर भर्ती के किसी एक तरीके के अनुसार या भारत के मविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक के अधीन बने किसी सेवा नियम के अधीन चयन के बाद स्थापनापन्न आधार पर नियुक्त किये गये हैं, (उन पर) केवल स्थापनापन्न आधार पर पदोन्नति के लिये वरिष्ठता के उस क्रम में विचार किया जा सकता है, जिसमें यदि वे उक्त निम्नतर पद पर अधिष्ठायी होने पर होते।

टिप्पणी—ऐसे मामले में जब किसी विनिष्ट वय में किसी पद पर सीधी भर्ती पदोन्नति द्वारा नियमित चयन के पहले करली गई है, तो ऐसे व्यक्ति जो उस पद पर भर्ती के दोना तरीका से नियुक्ति के लिय पात्र हैं या पात्र थे और उनको सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर दिया गया है, तो उन पर भी पदोन्नति के लिय विचार किया जावेगा।

(4) ऐसे पद/पदों से या सेवा में सम्मिलित नहीं हैं सेवा के निम्नतम पद या पद श्रेणी में पदोन्नति की नियमित पक्ति में पदोन्नति के लिये चयन सवधायोग्यता के आधार पर तथा वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर 50/50 के अनुपात में किया जायेगा,

परंतु यह है कि—यदि समिति का यह समाधान हो जाय कि—किसी विनिष्ट वय में सवधा योग्यता के आधार पर पदोन्नति के द्वारा चयन के लिये उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, तो वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा चयन उसी समान प्रकार से किया जा सकेगा जैसा इन नियमों में वर्णित हैं।

(5) उपनियम (7) के उपबन्धों की सीमा में रहते हुए, राज्य-सेवा के किसी निम्नतम पद या पद की श्रेणी से राज्य सेवा के किसी अगले उच्चतर पद या पद की श्रेणी में और अधीनस्थ सेवाओं तथा लिपिक वर्गीय सेवाओं के समस्त पदों के लिए पदोन्नति द्वारा चयन सवधा वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर उन व्यक्तियों में से किया जायेगा, जो महता परीक्षा, यदि कोई नियमों में विहित हो, उत्तीर्ण कर चुका है और चयन के वय के अग्रले माह के प्रथम दिवस को उस पद या पद श्रेणी पर, जिससे चयन किया जाना है, कम से कम पांच वय की सेवा पूरी कर चुका है, जब तक कि नियमों में अन्यत्र भिन्न अवधि विहित नहीं की गई हो।

परंतु यह है कि—पांच वय की सेवा की आवश्यक अवधि सहित व्यक्तियों की अनुपलब्धता की दशा में, समिति विहित सेवावधि में कम वाले व्यक्तियों पर विचार कर सकेगी, यदि वे इन नियमों में अन्यत्र विहित पदोन्नति के लिय अग्र शर्तों तथा महताओं को पूरा करते हैं और वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिये अग्रवर्ती उपयुक्त पाये गये हैं।

(6) राज्य सेवा में समस्त अन्य उच्चतर पदों या उच्चतर श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिये चयन सर्वथा योग्यता के आधार पर और वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर 50:50 के अनुपात में किया जायेगा।

परंतु यह है कि—यदि समिति का यह समाधान हो जाये कि—किसी विशिष्ट वर्ग में सर्वथा योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा चयन के लिये उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, तो वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा चयन उन्नीसमान प्रकार से किया जा सकेगा, जसा इन नियमों में वर्णित है।

### सरकारी निर्देश

❧ विषय—वर्गियों के पदों की 'योग्यता' और 'वरिष्ठता सह योग्यता' के आधार पर पदोन्नति से भरे जाना।

पदोन्नति के लिये संशोधित तरीके के बारे में सम्बंधित नियम का वर्तमान उपनियम (6) कुछ श्रेणियों के पदों पर 50:50 के अनुपात में 'वरिष्ठता सह योग्यता' तथा 'योग्यता' के आधार पर पदोन्नति करने के लिये उपबन्ध करता है। ये नियम स्पष्ट रूप से यह नहीं बताते कि—ऐसी श्रेणी के पदों पर चयन 'वरिष्ठता सह योग्यता' के आधार पर किया जायगा या 'योग्यता' के आधार पर।

सर्वकार द्वारा इस पर विचार किया गया और निम्नांकित तरीके का अनुसरण किया जाना चाहिये—

“पात्रता, पदोन्नति आदि के संशोधित मापदण्ड निर्धारित करने वाले नियम के उपनियम (6) के नीचे दिये गये 'स्पष्टीकरण' के अनुसार वरिष्ठता सह-योग्यता और योग्यता के आधार पर अलग अलग भरे जाने वाले पदों की सत्यापन की जानी चाहिये। पहले वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले रिक्त स्थानों को भरने के लिये चयन किया जाना चाहिए। तत्पश्चात् योग्यता के कोटा के रिक्तस्थानों का भरने के लिये योग्यता के आधार पर व्यक्तियों का चयन करना चाहिये।”

जहां दिनांक 7 मार्च 1978 की अधिधोषणा के जारी होने के बाद उपयुक्त श्रेणी के पदों के लिये विभागीय-पदोन्नति समिति की बैठकें पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं और उनके द्वारा की गई अभिलेखापन यदि उपरोक्त सिद्धान्त के विपरीत हैं, तो उनको उपरोक्त स्पष्टीकरण के प्रकाश में पुनर्विलोकित किया जा सकेगा।

❧ परिपत्र सं. एफ 7 (10) DOP (A-II) 77-1 GSR 24 दिनांक 11 सितम्बर 1978, राजस्थान राजपत्र-असाधारण-भाग 4 (ग) (I) दिनांक 16.9.1978 पृष्ठ 211 पर प्रकाशित।

(7) राज्यसेवा में उच्चतम पद या पद की उच्चतम श्रेणी पर पदोन्नति के लिये चयन सदा केवल योग्यता के आधार पर किया जावेगा।

(8) वे व्यक्ति जो योग्यता के आधार पर किसी पद या पद की श्रेणी पर पदोन्नति द्वारा चयनित तथा नियुक्त किये गये हैं वे अगले उच्चतर पद या पद की श्रेणी पर जो कि योग्यता से भरा जाना है, पदोन्नति के लिये केवल तभी पात्र होंगे जब कि वे नियमित चयन के बाद, जो उस पद या पद की श्रेणी, जिसके लिये चयन करना हो, के लिए चयन के वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिवस का कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों, जबकि इन नियमों में अप्रत्यक्ष कोई उच्चतर सेवा की अवधि विहित न हो।

परन्तु पांच वर्ष की सेवा की शर्त उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी यदि उसमें कनिष्ठ कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिये विचारार्थ पात्र है।

परन्तु आगे यह है कि—भरे जाने वाले रिक्तस्थानों की संख्या के बराबर (समाप्त) पिछले निम्नतर पद की श्रेणी में जिससे पदोन्नति की जाती है, पदोन्नति के लिये पात्र व्यक्तियों की अनुपलब्धता की दृष्टि से समिति पांच वर्ष की सेवा से कम सेवा वाले व्यक्तियों पर विचार कर सकेगी यदि वे केवल योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिये अर्हता पात्र एवं उपयुक्त पाये जाते हैं।

स्पष्टीकरण—यदि सेवा में निम्नतर अगली उच्चतर या उच्चतम पद के वर्गीकरण के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो वह मामला सरकार के वार्मिंक विभाग को भेजा जावेगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(9) पदोन्नति के लिये पात्र व्यक्तियों पर विचार का विस्तार क्षेत्र (Zone) निम्नांकित होगा—

(1) रिक्त स्थानों की संख्या	विचार करने के लिये पात्र व्यक्तियों की संख्या
(क) 1 से 5 रिक्त स्थान	— रिक्तस्थानों की संख्या से 4 गुनी
(ख) 6 से 10 रिक्तस्थान	— 3 गुनी, किन्तु कम से कम 20 पात्र व्यक्तियों पर विचार किया जावेगा।
(ग) 10 से अधिक रिक्तस्थान	— 2 गुनी, किन्तु कम से कम 30 पात्र व्यक्तियों पर विचार किया जावेगा।

(1) राज्य सेवा में उच्चतम पद के लिए—

(क) यदि पदोन्नति किसी पद की एक श्रेणी से हो, तो पांच की संख्या तक पात्र व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिये विचार किया जावेगा,

(ख) यदि पदान्ति समान वेतनमान के पदा की विभिन्न श्रेणियों से है, तो उसी वेतनमान की प्रत्येक श्रेणी से दो तक की सख्या में पात्र व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिये विचार किया जावेगा,

(ग) यदि पदोन्नति विभिन्न वेतनमान के पदा की विभिन्न श्रेणियों से है, तो पदोन्नति के लिये पहले उच्चतर वेतनमान में पात्र व्यक्तियों पर और यदि उच्चतर वेतनमान में योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो निम्नतर वेतनमान में पदों की श्रेणियों के पात्र व्यक्तियों पर और इसी क्रम से आगे विचार किया जावेगा। इस मामले में विचार करने का क्षेत्र सब में पांच वरिष्ठतम पात्र व्यक्तियों तक सीमित रहगा।

(10) इस नियम में स्पष्ट रूप से अथवा उपरिचित के अतिरिक्त, पदान्ति के लिये पात्रता की शर्तें, समिति का गठन तथा चयन का तरीका समान रूप से वही होगा, जो इन नियमों में अन्यत्र विहित किया गया है।

(11) समिति समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जो इन नियमों के अधीन सम्बन्धित पदों की श्रेणी में पदोन्नति के लिये पात्र तथा अर्हित हैं उनमें से जिनको आवश्यक समझे साक्षात्कार करेगी, और एक सूची बनायेगी, जिसमें वर्तमान रिक्तियां तथा रिक्तियों को तय करने के बाद अगले बारह महीनों में होने वाली रिक्तियों की सख्या के बराबर उपयुक्त व्यक्तियों के नाम होंगे। समिति एक भ्रलग सूची भी बनायेगी, जिसमें उपरोक्त सूची में चयनित व्यक्तियों के 50% के बराबर व्यक्तियों के नाम होंगे या यदि रिक्तियों की सख्या केवल एक हो, तो एक और व्यक्ति का चयन करेगी, जो कि समिति की अगली बैठक तक होने वाली स्थाई या अस्थायी रिक्तियों को अस्थाई या स्थानापन्न आधार पर भरने के लिये उपयुक्त समझे जावें और इस प्रकार बनाई हुई सूची को प्रतिवर्ष पुनरीक्षित तथा पुनर्विलाकित किया जावेगा और इस प्रकार पुनरीक्षित और पुनर्विलाकित होने तक व० (सूची) प्रभावी रहेगी।

इस प्रकार योग्यता के आधार पर और वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर तैयार की गई सूचिया उस पद की श्रेणी पर वरिष्ठता के क्रम में व्यवस्थित की जावेगी, जिस (पद) पर स चयन किया जाना है। ऐसी सूचिया सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी का समस्त अभ्यर्थियों में उनमें से जिनका कि चयन नहीं हुआ यदि कोई हो, के वार्षिक गुप्त प्रतिवेदन तथा व्यक्तिगत पत्रिकाओं सहित भेजी जावेंगी।

स्पष्टीकरण—योग्यता के आधार पर चयन के प्रयोजनाथ, सूची में वे अधिकारी जिनको 'असाधारण' (आउटस्टैंडिंग) और "बहुत अच्छा" श्रेणित किया गया है, वरिष्ठता के क्रम में प्रथम श्रेणी में वर्गीकृत होंगे, वे

अधिकारी जो 'अच्छा' श्रेणित किये गये हैं, वे वरिष्ठता के क्रम में द्वितीय श्रेणी वर्गीकृत होंगे और वे अधिकारी जो "औसत" और "अव्ययित" श्रेणित किये गये, वे तृतीय श्रेणी में वर्गीकृत होंगे। वे अधिकारी जो द्वितीय श्रेणी सूची में श्रेणित तथा वर्गीकृत किये गये हैं, प्रथम श्रेणी सूची में श्रेणित व वर्गीकृत अधिकारियों के नीचे रहे जावेंगे और ऐसे अधिकारियों को इस श्रेणी से केवल (तभी) नियुक्त किया जावेगा, यदि प्रथम श्रेणी सूची में श्रेणित व वर्गीकृत अधिकारी समाप्त (exhausted) हो जाते हैं, अथवा व सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त नहीं किये जायेंगे। तृतीय श्रेणी सूची में श्रेणित तथा वर्गीकृत अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जावेगा।

(12) जहाँ आयोग से परामर्श आवश्यक हो, समिति द्वारा तैयार की गई सूचियाँ उन समस्त व्यक्तियों की व्यक्तित्व पंजीकामा तथा वापिक गोपनीय पत्रियाँ सहित जिनके नामों पर समिति ने विचार किया है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग को अग्रप्रेषित की जावेंगी।

(13) आयोग समिति द्वारा तैयार की गई सूचियों पर नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अथवा संबंधित प्रलेखों के साथ विचार करेगा और जब कोई परिवर्तन आवश्यक न समझा जावे, तो उस सूची को अनुमोदित (अप्रूव) करेगा। यदि नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त सूची में आयोग कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो वह अपने द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों से नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा। आयोग की टिप्पणी को, यदि कोई हो, ध्यान में रखने के बाद, नियुक्ति प्राधिकारी (उन) सूचियों को, ऐसे परिवर्तनों सहित जो उसके अभिमत में 'यायोजित व ठीक' हों, अन्तिम रूप से अनुमोदित करेगा और जब नियुक्ति प्राधिकारी सरकार के अधीनस्थ एक प्राधिकारी है तो आयोग द्वारा अनुमोदित सूचियों को केवल सरकार की स्वीकृति के बाद ही परिवर्तित करना चाहिये।

(14) नियुक्ति प्राधिकारी पूर्ववर्ती उपनियम (13) के अधीन अन्तिम रूप से अनुमोदित सूचियों में से उसी क्रम में जिसमें उनको सूची में रखा गया है, व्यक्तियों को लेते हुए नियुक्तियाँ करेगा जब तक कि ऐसी सूचियाँ समाप्त या पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित, जैसा भी हो न करली जायें।

(15) उन व्यक्तियों की पदोन्नति, नियुक्तियाँ या अथवा आनुपातिक मामलों पर जो निलम्बनाधीन हों या जिनके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही हो, उस पद पर पदोन्नति के समय विचार किया जाना के लिये जिस पर वे पात्र हैं या यदि निलम्बन जांच या कायबाही विचाराधीन नहीं होती तो पात्र होत समयोचित और निष्पक्ष तरीके से प्रावधिक कायबाही के लिए सरकार निर्देश जारी कर सकेगी।

(16) इस नियम के उपबंध इन नियमों के किसी उपबंध में कोई विपरीत बात के होत हुए भी प्रभावी होंगे।

### पुराना नियम 26 घ इस प्रकार है —

उपरोक्त वर्तमान नियम 26-घ विज्ञप्ति नं. F 7 (10) (A-II) 77 G S R 93 दिनांक 7 मार्च 1978 द्वारा निम्नांकित के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया जो 31 10 1975 से 7 3 1978 तक प्रभावशील रहा —

26-घ-सेवा में सम्मिलित कनिष्ठ, वरिष्ठ तथा अन्य पदों पर पदोन्नति के लिये सशोधित मापदण्ड, पात्रता तथा तरीका—

(1) जो पद (इस) सेवा में सम्मिलित नहीं है उनमें से (इस) सेवा के निम्नतम पद या श्रेणी (कटेगरी) पर पदोन्नति की नियमित पक्ति में पदोन्नति के लिये चयन अवधि योग्यता (मेरिट) के आधार पर किया जावेगा।

(2) उपनियम (4) के उपबन्धों की सीमा में रहते हुए, सेवा में निम्नतम पद या श्रेणी के पद से सेवा में अगले उच्चतर पद या श्रेणी के लिये और वेतनमान स 11 तक के समस्त पदों के लिए जो राजस्थान सिविल सेवा (नवीन वेतनमान) नियम 1959 या सरकार द्वारा समय समय पर घोषित समकक्ष वेतनमानों के समस्त पदों के लिये पदोन्नति हेतु चयन उन लोगों में से केवल वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर किया जावेगा जो इन नियमों के अधीन विहित अहता-परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर चुके हों तथा जो उस पद या पद की श्रेणी जिसके लिये चयन करना हो, के लिये चयन के वष के अप्रैल माह के प्रथम दिवस को कम से कम पांच वर्ष तक सेवा कर चुके हों, जब तक कि इन नियमों में कोई भिन्न अवधि विहित न हो।

परन्तु यह है कि—पांच वर्ष की वाञ्छित सेवावधि वाले व्यक्तियों के अनुपलब्ध होने की दशा में, समिति विहित अवधि से कम सेवा वाले व्यक्तियों पर विचार कर सकेगी, यदि वे इन नियमों में अन्यत्र विहित पदोन्नति के लिये अहता-परीक्षा, अनुभव या अन्य शर्तों को पूरा करते हों तथा वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिये अन्यथा उपयुक्त पाये गये हों।

परन्तु आगे यह है कि—राज्य सेवा (State Service) में सम्मिलित पदों के सम्बन्ध में जिनमें निम्नतम पद पर नियुक्ति का तरीका पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का उपबन्ध करता है और जहाँ ऐसे पदों को इस उपनियम के अधीन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरा जाना वाञ्छित है, तो समिति उस विचार क्षेत्र में उपलब्ध उच्च योग्यता (Outstanding merit) वाले ऐसे व्यक्तियों का जो कि वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर चयनित नहीं किये जा सकते, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों के एक—चौथाई की सीमा तक, और यदि रिक्त स्थानों की संख्या एक से अधिक, परन्तु चार से कम है, तो पदोन्नति के लिये चयन कर सकेगी। समिति एक

व्यक्ति को केवल योग्यता पर चयनित कर सकेगी और यदि रिक्त स्थान चार स अधिक हैं, और केवल योग्यता से भरे जाने वाले रिक्तस्थानों की सख्या की उपरोक्त आधार पर सगणना में अग्र आता है, तो समिति आधे आ अधिक के (ऐसे) अग्र क लिये एक और व्यक्ति का चयन कर सकेगी। वरिष्ठता के निर्धारण के प्रयोजनाय, ऐसे व्यक्ति वरिष्ठता-सह योग्यता के आधार पर चयनित किये हुये समझ जावगे।

(3) सेवा में अथ समस्त उच्चतर पदा या पद की उच्चतर श्रेणी पर पदोन्नति के लिये चयन केवल योग्यता के आधार पर किया जावेगा।

(4) सेवा में उच्चतम पद या पद की उच्चतम श्रेणी पर पदोन्नति के लिये चयन सदा केवल योग्यता के आधार पर किया जावेगा।

(5) वे व्यक्ति जो योग्यता के आधार पर किसी पद या पद की श्रेणी पर पदोन्नति द्वारा चयनित तथा नियुक्त किय गये हैं, वे अगले उच्चतर पद या पद की श्रेणी पर पदोन्नति के लिये केवल तभी पात्र हाने जबकि वे नियमित चयन के बाद जो उस पद या पद की श्रेणी जिसके लिये चयन के वष के अगले माह के प्रथम दिवस को कम से कम पाँच वष की सेवा कर चुके हों, जबकि इन नियमों में अथन कोई उच्चतर सेवा की अवधि विहित न हा।

परंतु पाच वष की सेवा की शत उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, यदि उससे अनिष्ट कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिये विचारार्थ पात्र हो।

परंतु आगे यह है कि—भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की सख्या के बराबर (सख्या में) निम्नतर पद की श्रेणी में जिससे पदोन्नति की जानी है, पदोन्नति के लिये पात्र व्यक्तियों की अनुपलब्धता की दशा में, समिति पाच वष की सेवा स कम सेवा वाले व्यक्तियों पर विचार कर सकेगी, यदि वे केवल योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिये अथवा पात्र एवं उपयुक्त पाये जाते हैं।

स्पष्टीकरण—यदि सेवा में निम्नतर, अगली उच्चतर या उच्चतम पद के वर्गीकरण के बारे में कोई सदेह उत्पन्न होता है, तो वह मामला सरकार के कार्मिक विभाग को भेजा जावेगा, जिस पर उसका निणय अंतिम होगा।

(6) पदोन्नति के लिए पात्रता का क्षेत्र वरिष्ठता-सह-योग्यता या योग्यता, जैसा भी हो के आधार पर भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की सख्या से पाँच गुना होगा।

परन्तु यह है कि—योग्यता के आधार पर चयन के लिये उपयुक्त व्यक्तियों की पर्याप्त सख्या में अनुपलब्धता के मामले में समिति अपने विवेकाधिकार के अधीन पात्रता के क्षेत्र से बाहर के असाधारण योग्यता वाले व्यक्तियों पर विचार कर सकेगी परंतु वे योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की सख्या के छ गुनी के भीतर होंगे।

(7) इस नियम में स्पष्ट रूप से अथवा उपरि वर्त के अतिरिक्त, पदावधि के लिये पात्रता की शर्तें, समिति का गठन तथा चयन का तरीका समान रूप से वही होगा, जो इन नियमों में अथवा विहित किया गया है।

(8) समिति समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगी जो जो इन नियमों के अधीन सम्बन्धित पदों की श्रेणी में पदावधि के लिये पात्र तथा अर्हित हैं, उनमें से जिनको आवश्यक समझे साक्षात्कार करेगी और एक सूची तैयार करेगी जिसमें वर्तमान रिक्तियों तथा रिक्तियों को तय करने के बाद अगले बारह महीनों में होने वाली रिक्तियों की संख्या के बराबर उपयुक्त व्यक्तियों के नाम होंगे। समिति एक अलग सूची भी बनायेगी जिसमें उपरोक्त सूची में चयनित व्यक्तियों की संख्या के 50 प्रतिशत के बराबर व्यक्तियों के नाम होंगे या यदि रिक्तियों की संख्या केवल एक हो, तो एक और व्यक्ति का चयन करेगी, जो कि समिति की अगली बैठक तक होने वाली स्थाई या अस्थायी रिक्तियों को अस्थायी या स्थापना आधार पर भरने के लिये उपयुक्त समझे जावें और इस प्रकार बनाई हुई सूची को प्रतिवर्ष पुनरीक्षित तथा पुनर्विलोकित किया जावेगा और इस प्रकार पुनरीक्षित और पुनर्विलोकित होने तक वह (सूची) प्रभावी रहेगी।

इस प्रकार योग्यता के आधार पर तैयार की गई सूचियाँ प्राथमिकता के क्रम में व्यवस्थित की जावेगी तथा वरिष्ठता सह याव्यता के आधार पर तैयार की गई सूची उस पद की श्रेणी पर, जिसमें से चयन किया गया है, वरिष्ठता के क्रम में व्यवस्थित की जावेगी। ऐसी सूचियाँ सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी समस्त अभ्यर्थियों, मध्य उनके जिनका कि चयन नहीं हुआ, यदि कोई हो, के वार्षिक गुप्त प्रतिवेदन तथा वैयक्तिक पत्रिकाओं सहित भेजी जावेगी।

स्पष्टीकरण - प्राथमिकता की सूची में अधिकारियों को योग्यता के आधार पर "असाधारण" (आउटस्टैंडिंग), बहुत अच्छा" तथा 'अच्छा- के क्रम में वर्गीकृत किया जावेगा। प्रत्येक श्रेणी में अधिकारी गण पिछली निचली श्रेणी (Next below grade) में अपनी वास्तविक वरिष्ठता धारण करेंगे।

(9) जहाँ आयोग से परामर्श आवश्यक हो, समिति द्वारा तैयार की गई सूचियाँ उन समस्त व्यक्तियों की वैयक्तिक पत्रिकाओं तथा वार्षिक गोपनीय पत्रियों सहित, जिनके नामों पर समिति ने विचार किया है नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग की अग्रपंक्ति की जावेगी।

(10) आयोग समिति द्वारा तैयार की गई सूचियों पर नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अथवा सम्बन्धित प्रलेखों के साथ विचार करेगा और जब कोई परिवर्तन आवश्यक न समझा जावे, तो उस सूची को अनुमोदित (अप्रूव) करेगा। यदि नियुक्ति-प्राधिकारी से प्राप्त सूची में आयोग कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो वह अपने द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों से नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा।



आयोग की टिप्पणी को, यदि कोई हो, ध्यान में रखने के बाद, नियुक्ति प्राधिकारी सूचिया को, ऐसे परिवर्तनों सहित जो उसके अभिमत में न्यायोचित व ठीक हों, अंतिम रूप से अनुमोदित करेगा और जब नियुक्ति प्राधिकारी सरकार के अधीनस्थ एक प्राधिकारी है, तो उसे आयोग द्वारा अनुमोदित सूचियों को केवल सरकार की स्वीकृति के बाद ही परिवर्तित करना चाहिये।

(11) नियुक्ति प्राधिकारी उक्त उपनियम (10) के अधीन अंतिम रूप से अनुमोदित सूचियों में से उसी क्रम में, जिसमें उनको सूची में रखा गया है, व्यक्तियों को लेते हुए नियुक्तियाँ करेगा, जब तक कि ऐसी सूचिया समाप्त या पुनर्विलोकिता और पुनरीक्षित, जैसा भी हो, न करली जायें।

8(11-क) उन व्यक्तियों की पदोन्नति, नियुक्तियाँ या अन्य आनुपेक्षिक मामला पर जो निलम्बनाधीन हो या जिनके विरुद्ध विभागीय जाच चल रही हो, उस पद पर पदोन्नति के समय विचार किया जाने के लिए, जिस पर वे पान हैं या यदि यह निलम्बन या जाच या कायवाही विचाराधीन नहीं होती तो पात्र होते समानोचित और निष्पक्ष तरीके से प्रावधिक कायवाही के लिये सरकार निर्देश जारी कर सकेगी।

(12) इस नियम के उपबन्ध इन नियमों के किसी उपबन्ध में कोई विपरीत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।]॥

8 वि स एफ 10 (1) कार्मिक (क-2) 75 I दिनांक 5-3-76 द्वारा निविष्ट तथा दिनांक 4-11- 975 से प्रभावी।

॥[ उपरोक्त नियम 26-घ विज्ञप्ति स एफ 7(6) DOP (A-II) 75-I दिनांक 31-10-1975 द्वारा निम्नांकित नियम 26 घ के स्थान पर प्रतिस्थापित-किया गया था—अर्थात् दि० 31-10-75 तक निम्नांकित नियम प्रभावशील रहा—

26 घ—योग्यता के आधार पर चयन का तरीका—

(1) सवधा योग्यता के आधार पर चयन उन व्यक्तियों में से किया जायगा जो इन नियमों के अधीन पदोन्नति के लिए अर्हता पात्र हैं। योग्यता तथा वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की कुल संख्या की पाँच गुनी संख्या में पात्र अभ्यर्थियों पर इस प्रयोजनाय विचार किया जावेगा। जहाँ पात्र अभ्यर्थियों की संख्या रिक्त स्थानों की पाँच गुनी संख्या से अधिक हो जाती है, तो इस प्रयोजनाय आवश्यक संख्या में वरिष्ठतम व्यक्तियों पर विचार किया जावेगा।

परन्तु यह है कि—योग्यता के कोटा में उसी सवग में प्रथम पदोन्नति के लिये वे व्यक्ति पात्र होंगे जिन्होंने उस पद पर, जिस पर पदोन्नति की जानी है, नियमित चयन

के वष के अप्रैल मास के प्रथम दिवस को कम से कम छ' वष की सेवा पूरी करनी हो, जबकि इन नियमों के अन्तर्गत कोई उच्चतर अवधि विहित नहीं की गई हो।

(2) इस नियम में प्रकट रूप से अप्रत्या विहित को छोड़कर, सबका योग्यता के आधार पर चयन करने के लिये उस पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर चयन करने का तरीका, यथा सम्भव, अपनाया जावेगा,

परन्तु यह है कि—व्यक्ति जो योग्यता के आधार पर किसी पद की श्रेणी पर विभागीय-पदोन्नति समिति द्वारा नियमित चयन के बाद पदोन्नत किये गये थे, व उच्चतर पद की अगली श्रेणी पर अगली पदोन्नति के लिये केवल तभी पात्र होंगे जब कि उस पद पर सेवा ? जिस पर वे पिछली बार योग्यता के आधार पर पदोन्नत किये गये थे।

(3) समिति अपने द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की एक अलग सूची योग्यता के आधार पर बनायेगी और उनके नामों को प्राथमिकता के क्रम में व्यवस्थित करेगी।

(4) व्यक्तियों के नामों को, जो पदों की प्रत्येक श्रेणी के लिये दो सूचियों में, उपरोक्त उपनियम (3) में तथा नियम 26-ग के उपनियम (5) में वर्णित, सम्मिलित हैं तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृत हैं, (उन्हें) पदों की प्रत्येक श्रेणी के लिये अलग एक सूची में वरिष्ठता के क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जावेगा।

(5) एक ही और समान चयन के परिणाम स्वरूप एक समान श्रेणी या पदश्रेणी (Class, Category or grade) के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों में वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर नियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा योग्यता के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे। समान श्रेणी या पदश्रेणी पर सर्वथा योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, प्राथमिकता के क्रम पर ध्यान दिये बिना, विनिश्चित की जावेगी, मानो ऐसे व्यक्ति वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये थे।

(6) इस नियम के उपबन्ध, इन नियमों के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी प्रभावशाली होंगे।

(7) दोनों में से किसी आधार पर भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की मर्यादा निर्धारित करने के प्रयोजन से निम्नांकित चक्रीय क्रम का अनुसरण किया जावेगा—

“प्रथम योग्यता से—अगले दो वरिष्ठता सह-योग्यता—अगला एक योग्यता से—फिर दो वरिष्ठता सह-योग्यता से यही क्रम दोहराया जावेगा।”

1826-इ (E) वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिये तरीका—  
(1) वरिष्ठ लिपिक के पदा के रिक्त स्थानों के 67% (षट्) नियम 26-ग के अधीन दिये गये तरीके के अनुसार वरिष्ठता सह-योग्यता व आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जावेंगे।

(2) इन नियमों के नियम 7 के उपनियम (ग) के परंतु के अधीन रहत हुए वरिष्ठ लिपिकों के पदा के रिक्त स्थानों का 33%, वरिष्ठ लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति से भरा जावेगा जो सात वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों। आयोग द्वारा एक प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतराल पर जो सरकार व्यवस्था एक पद्धति विभाग में आयोग के परामर्श से तय कर सरकार द्वारा उस परीक्षा के लिए अधिसूचित पाठ्यक्रम के अनुसार, आयोजित की जावेगी।

(3) उपरोक्त उपनियम (2) में उल्लिखित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करने में आयोग जहां तक संभव हो सके, उस समान तरीके का अनुसरण करेगा जो इन नियमों के भाग (5) में दिया गया है।

127 वरिष्ठता (सीनियोरिटी)—सेवा में वरिष्ठता सेवा की प्रत्येक श्रेणी में अधिष्ठायी नियुक्ति के वर्ष के अनुसार विनिश्चित की जावेगी

परंतु यह है कि—

(1) इन नियमों व प्रभावी होने से पहले या नियम 2 के परंतु के अनुसार पदा की किसी विशेष श्रेणी (कैटेगरी) पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक (inter se) वरिष्ठता सरकार के निर्देशों के अधीन यदि कोई हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तदर्थ (एडहॉक) आधार पर विनिश्चित, संशोधित या परिवर्तित की जावेगी।

(ii) आधुनिक लिपिकों के सबग में एक तथा समान चयन के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा और साधारण सबग में एक तथा समान परीक्षा के परिणाम स्वरूप, नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता क्रमशः नियम 18 (2) तथा नियम 24 (2) के अधीन तयार की गई सूची के क्रम के अनुसार होगी, सिवाय उनके

18 वि स एफ 3 (11) वार्मिग (क-2) 74 दिनांक 8-2-1975 द्वारा निविष्ट।

1 वि स एफ 7 (6) LOP (क-2) 73 दिनांक 15.11.1976 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—

27 वरिष्ठता—पदों की प्रत्येक श्रेणी की वरिष्ठता सम्बंधित पद की श्रेणी पर अधिष्ठायी नियुक्ति की आका के दिनांक से विनिश्चित की जावेगी।'

जिनको रिक्त पद प्रस्तावित किया गया तब उन्होंने सेवा में प्रवेश (Join) नहीं किया हो।

2[(11-क) नियम 7 के परतुक (7) के अधीन अधिष्ठायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता आधुनिक श्रेणी द्वितीय या आधुनिक पद पर 3[ X X X ] उनकी सेवा की पुन लगातार सम्बन्धी अवधि से तय की जावेगी।

4[(11-ख) नियम 7 के परतुक (8 फ) के अधीन अधिष्ठायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता अधीनस्थ कार्यालय में आधुनिक के पद पर उनकी लगातार सेवामें की कुल अवधि से तय की जावेगी।]

5[(XIII) वे व्यक्ति जो किसी ऐसे चयन के परिणाम स्वरूप, जो पुन-रीक्षण व पुनर्विलोकन की सीमा में नहीं हो, चयनित व नियुक्त किये गये हैं वे बाद के चयन के परिणामस्वरूप चयनित व नियुक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे।

एक ही (समान) चयन में वरिष्ठता सह-योग्यता तथा योग्यता (मेरिट) के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी, जो पिछली निम्न श्रेणी (next below grade) में थी।"

- 2 वि स एक 3 (3) DOP (क-2) 73 दि 13 12 1974 द्वारा निविष्ट।
- 3 वि स एक 3 (4) DOP (क-2) 77 दि 15 3 78 द्वारा शब्दावली "सम्बन्धित विभाग में" विलोपित की गई।
- 4 वि स एक 3 (13) DOP/ क-2/73 दिनांक-27 12 1978 द्वारा जोड़ा गया।
- 5 वि स एक 7 (10) DOP A-II/77 GSR 10 दिनांक 17 जून 1978 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—

6[(111) वे व्यक्ति जो किसी चयन के परिणामस्वरूप चयनित एवं नियुक्त हुए हैं जो कि पुनर्विलोकन और पुनर्विलोकन के अधीन नहीं है, उन व्यक्तियों से वरिष्ठ माने जावेंगे जो किसी पश्चातवर्ती चयन के परिणाम स्वरूप चयनित व नियुक्त किये गये हैं। वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो पिछली निम्न श्रेणी में है, सिवाय उच्चपदों पर लगातार स्थानापन्नता के मामले के, जिसमें यह लगातार स्थानापन्नता की अवधि (सम्बाई) के आधार पर होगी, परंतु यह है कि—ऐसी स्थानापन्नता तदर्थ या आकस्मिक नहीं थी।

<sup>6</sup>(iv) यदि दो या अधिक व्यक्ति बरिष्ठ लिपिक के पदा पर एक ही (समान) वय में नियुक्त किये गये हों तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती से नियुक्त से बरिष्ठ होगा।

<sup>6</sup>(v) इन नियमों के अधीन भर्ती किये गये या पदोन्नत किये गये व्यक्ति सेवाओं के एकीकरण की प्रक्रिया में उसी समान सबब के पदा पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों से प्रत्येक सबब में बरिष्ठ होंगे।

<sup>7</sup>(vi) जूनियर डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वालों में से किसी विशिष्ट वय में भर्ती किये गये बरिष्ठ लिपिकों और बरिष्ठ लिपिकों की पारस्परिक बरिष्ठता उनके द्वारा ऐसी परीक्षा में प्राप्त योग्यता के क्रम (माडर आफ मेरिट) के अनुसार होगी।

<sup>7</sup>(vi) जूनियर डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वालों में से भर्ती किये गये बरिष्ठ तथा बरिष्ठ लिपिक उनसे बरिष्ठ होंगे, जो किसी विशिष्ट वय में आयोग के द्वारा भर्ती किये गये हों।

<sup>8</sup>(vii) सेवाओं के एकीकरण की प्रक्रिया में बरिष्ठ लिपिकों के रूप में नियुक्त तथा किसी अन्य विभाग को स्थायी रूप से स्थानान्तरित व्यक्तियों की पारस्परिक बरिष्ठता (उनकी) सेवा की कुल अवधि के आधार पर तय की जायेगी।

<sup>8</sup>(ix) सेवा के एकीकरण के बाद बरिष्ठ लिपिकों के रूप में नियुक्त तथा किसी अन्य विभाग को स्थायी रूप से स्थानान्तरित व्यक्तियों की पारस्परिक बरिष्ठता

वि स 7 (o) DOP (A-2) 75-11 दिनांक 31 10 1975 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित तथा राजपत्र में प्रकाशन से प्रभावशील—

“(iii) पदों की विशिष्ट श्रेणी पर पदोन्नति द्वारा एक ही दिनांक को नियुक्त व्यक्तियों की आपसी बरिष्ठता वही होगी, जो उनकी पिछली निम्न श्रेणी (next below grade) में थी। जबकि उच्च पदों पर लगातार स्थानापन्नता के मामला में यह (बरिष्ठता) ऐसी लगातार स्थानापन्नता की अवधि (लम्बाई) के अनुसार होगी, परंतु यह है कि—ऐसी स्थानापन्नता तदर्थ (एडहॉक) या आकस्मिक (fortuitous) नहीं थी।”

6 वि स एफ 10 (1) नियुक्ति (क) 55 दिनांक 16 6 1959 द्वारा जोड़ा गया।

7 वि स 10 (1) नियुक्ति (क) 55 दिनांक 14 7 1962 द्वारा जोड़ा गया।

8 वि स एफ 10 (1) नियुक्ति (क) 55 दिनांक 14 10 1962 द्वारा जोड़ा गया।

उनके वरिष्ठ लिपिक के रूप में पुष्टीकरण के दिनांक के अनुसार या, यदि वह दिनांक एक ही है तो वरिष्ठ लिपिक के रूप में स्थानापन्न नियुक्ति के दिनांक से, तय की जावेगी।

टिप्पणी—स्थानापन्न व्यक्तियों के मामले में वरिष्ठता उपरोक्त परतुक (vi), (vii) के उपबन्धों के अनुसार केवल अधिष्ठायी सवंग में तय की जावेगी।

9[(x) विनियम स एफ 10 (1) नियुक्ति (क) 55 भाग xxxi दिनांक 30 दिसम्बर 1971 द्वारा संशोधित नियम 7 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन निर्वाचन विभाग के निर्वाचन-पर्यवेक्षकों में से वरिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता निर्वाचन-पर्यवेक्षक के रूप में राजस्थान लोक सेवायोग के अनुमोदन के पश्चात् उनकी अधिष्ठायी नियुक्ति के दिनांक से विनिश्चित की जावेगी। उसी दिनांक को वरिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता लगातार स्थानापन्नता के आधार पर तय की जावेगी, परन्तु यह है कि ऐसी स्थानापन्नता तदर्थ या आकस्मिक न हो।]

10(xi) विभिन्न सेवाओं या राजस्थान पञ्चमत्त समिति एवं जिला परिषद् सेवाओं के अधिष्ठायी कमचारियों के मामले में जिनकी नियुक्ति ऐसे पदा पर विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा की गई है और जिनका स्थानांतरण इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार इस सेवा में किसी सवंग या समूह में विशेष रूप से अनुमेष (permissible) है और उसका इस प्रकार स्थानांतरण हुआ है और ऐसे दो या अधिक कमचारियों की एकीकृत वरिष्ठता निर्धारण करना आवश्यक हो गया है,

■ वि स एफ 10 (1) नियु (क) 55 भाग xxxi दिनांक 23 मार्च 1979 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित दि 13 2 से प्रभावी—

(x) नियम 7 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन निर्वाचन-पर्यवेक्षकों में से वरिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता उनकी वरिष्ठ लिपिक के रूप में अधिष्ठायी नियुक्ति के दिनांक—अर्थात्—13 62 से तय की जावेगी। एक ही (समान) दिनांक को इस प्रकार वरिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता निर्वाचन-पर्यवेक्षक के रूप में उनकी सम्बन्धित अधिष्ठायी नियुक्ति के दिनांक से तय की जावेगी।”

[उपरोक्त वि स एफ 10 (1) नियु (क) 55 भाग X X I दि 30 12 1971 द्वारा जोड़ा गया तथा दि 13 62 से प्रभावी था]

10 वि स 1 (19) नि (क-2) 72 दिनांक 4 9 1974 द्वारा निविष्ट तथा सुद्धि पत्र दि 8 11 1974 द्वारा संशोधित।

जो किसी नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन समान सेवा/मवग/ वृत्त या इकाई से सम्बद्ध नहीं हैं, तो विभिन्न सवग में उनकी अधिष्ठायी नियुक्ति का वष चाहे कुछ भी क्यों न हो, आरम्भिक नियुक्ति पर उनकी एकीकृत वरिष्ठता इन नियमों के अधीन किसी मवग या समूह में पदोन्नति या पुष्टीकरण के लिये, उस सम्बन्धित पद की श्रेणी या प्रवग (केटगरी) या समान या उच्चतर पद पर लगातार स्थानापन्नता की दिनांक से तय की जावेगी, परन्तु यह है कि—ऐसी स्थानापन्नता आकस्मिक प्रकार की या तदर्थ (एडहाक) या आवश्यक अस्थायी नियुक्ति नहीं थी और जब आज्ञा दी गई तब प्रवेश (जोइन) करने में उस कर्मचारी की ओर से कोई व्यक्तिगत (Jocaul) नहीं था।

उपरोक्त सिद्धांत ऐसे पदों के लिये प्रयुक्त होगा, जो कार्मिक (नियम) विभाग की पूर्व स्वीकृति से वर्णित किये जाय और इस शत के अधीन होगा कि दो या अधिक व्यक्तियों की पूर्व निर्धारित पारस्परिक वरिष्ठता को ध्येयक्रम या प्रतिष्ठान के मामलों को छोड़कर, नहीं छोड़ा जायेगा।

### 11[(xii) X X विलापित X X ]

12(xiii) नियम 7 के परतुक के अधीन जारी किये गये किसी साधारण या विशिष्ट निर्देशों के अधीन रहते हुये, उस परतुक के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वह होगी जो नियुक्ति प्राधिकारी, तदर्थ आचार पर सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अनुमोदित ऐसे सिद्धांतों के अनुसार, निर्धारित करे। उस कथित परतुक के अधीन आमेसित दैनिक वेतन वाले, आकस्मिक या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की वरिष्ठता इस सेवा में उनकी अधिष्ठायी नियुक्ति की आज्ञा की दिनांक से गणित की जावेगी।

- 11 वि स एफ 9 (23) नियुक्ति (क-2) 72 दिनांक 17 6 1978 द्वारा विलोपित, जो वि स एफ 7 (6) DOP (A-2) 75 II दिनांक 31 10 1975 द्वारा निविष्ट किया गया, निम्नांकित रूप में था—

“(xii) किसी एक तथा समान चयन के परिणाम स्वरूप और केवल योग्यता के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता लगातार स्थानापन्नता की अवधि पर कोई ध्यान दिया बिना, उसी समान क्रम में होगी, जिसमें उनका नाम चयन सूची में आया है।”

- 12 वि स एफ 3 (4) DOP (A-2) 75 दिनांक 26 6 1976 द्वारा निविष्ट।

13[(xiv) और (v) —X X विलोपित X X]

14[(xv) नियम 7 के परतुक 3 के अधीन आरक्षित रिक्तस्थानों के विरुद्ध कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर पदोन्नति से नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता लगातार सेवा की अवधि (लम्बाई) के आधार पर तय की जावेगी।]

15 (xvi) नियम 7 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के द्वितीय परतुक के अधीन जारी किये गये किसी साधारण या विशेष निर्देशों की सीमा में रहते हुए, इस परतुक के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वह होगी जो नियुक्ति प्राधिकारी तत्पश्चात् आधार पर ऐसे सिद्धांतों के अनुसार तय करे, जो सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा स्वीकार किये जावेंगे। उक्त परतुक के अधीन आमेसित किये दैनिक वेतन प्राप्त कार्य प्रभारित कर्मचारियों की वरिष्ठता सेवा में उनकी अधिष्ठायी नियुक्ति की आज्ञा के दिनांक से सगणित की जावेगी।

16 (xvii) वे व्यक्ति जो नियमों के नियम 25 के उपनियम (2) के परतुक (3) के अधीन आवृत्त हैं और इन नियमों की अनुसूची 1 के भाग iv में विहित पाठ्यक्रम के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित ग्रहता परीक्षा के परिणाम स्वरूप कनिष्ठ लिपिका के पदों पर नियुक्त किये गये हैं, उन व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे जो वर्ष 1976

18 वि स एफ 3(4) DOP/A-2/77 दिनांक 15 3 2978 द्वारा परतुक (xiv) तथा (xv) विलोपित जो वि स एफ 3 (7) DOP/(A-2) 76 दि 30 3 1977 द्वारा निम्न प्रकार से जोड़े गये थे—

“(xiv) नियम 7 के परतुक (10) के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता केवल परीक्षा (टेस्ट) उत्तीर्ण करने के बाद तय की जावेगी और आधुनिक या आधुनिक के रूप में उनकी तदर्थ/आवश्यक अस्थायी/स्थानापन्न पिछली सेवार्थ इस प्रयोजनाय विचारणीय नहीं होगी।

(xv) नियम 7 परतुक (10) के अधीन कनिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता लिपिक वर्गीय पद पर उनकी लगातार सेवा की अवधि (लम्बाई) के आधार पर तय की जावेगी।”

14 वि स एफ 11 (6) DOP/क-2/76 दिनांक 30 3 1 1978 द्वारा जाड़ा गया तथा शुद्धिपत्र दिनांक 12 7 78 द्वारा सशोधित।

15 वि स एफ 3(3) (1) कार्मिक (क-2) 76 दिनांक 30 8 1978 द्वारा जाड़ा गया तथा दिनांक 1 10 1973 से 31 12 1975 तक प्रभावी।

16 वि स एफ 5 (8) DOP/A-II/77 भाग 2 दिनांक 5 10 1978 द्वारा जोड़े गये। (यहाँ परतुक (xvii) दो बार सत्याकित भूल से किया गया प्रतीत होता है।)



तक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के परिणामस्वरूप पहले हो नियमित रूप से नियुक्त हैं या नियम 25 के उपनियम (2) के परंतुक (2) के अधीन कनिष्ठ लिपिका के रूप में नियमित रूप से नियुक्त किये जा चुके हैं, किंतु उन कनिष्ठ लिपिकों से वरिष्ठ होंगे जो इन नियमों की अनुसूची I के भाग IV में विहित पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ष 1978 में आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये हैं,

16(xviii) कनिष्ठ लिपिकों के पदा पर नियुक्त, (तथा) इन नियमों के नियम 25 के उपनियम (2) के परंतुक (3) के अधीन आवृत्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता उस क्रम का अनुसरण करेगी जिसमें उनको नियम 24 के अधीन बनाई गई सूची में स्थान दिया गया है।

1727-क—नियम 27 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राजस्वमण्डल तथा अनेक जिलाधीन कार्यालयों के लिपिक वर्गीय स्थापन के प्रत्येक सवर्ग की वरिष्ठता अलग से धारित की जावेगी, किंतु अध्यक्ष, राजस्व मण्डल निमंत्रण प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और सेवा की विशिष्ट आवश्यकताओं में एक कर्मचारी को एक सवर्ग से दूसरे में उसी (समान) पद पर अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने के लिये समक्ष होंगे। किंतु इस प्रकार से स्थानांतरित कर्मचारी अपने पदक सवर्ग में अपना पदाधिकार (लियन), वरिष्ठता तथा पदोन्नति का अधिकार धारित करते रहेंगे और ऐसे मामले में जब ऐसा व्यक्ति दूसरे कार्यालय में कार्य करते हुए अधिवापिकी प्राप्त कर लेता है, तो उसकी सेवा निवृत्ति से होने वाला रिक्तस्थान, नियुक्ति तथा पदोन्नति के प्रयोजनाथ उसके पदक कार्यालय में रिक्त हुआ माना जावेगा।

1827 ख—वे व्यक्ति जो कार्यालय-अधीक्षक प्रथम श्रेणी और आधुनिक प्रथम श्रेणी के पद पर पर पहले ही स्थायी कर दिये गये हैं या विज्ञप्ति सं F 3 (2) DOP/1-II/76 दिनांक 5 अक्टूबर 1976 द्वारा नियम-27-क के निविष्ट होने से पहले नियमित आधार पर ऐसे (पदा) पर पहले ही नियमित कर लिये गये हैं, उन जिला/मण्डल (बोर्ड) कार्यालय में अपने पदाधिकार धारण करेंगे, जिन्होंने नियुक्ति (क-11) विभाग में सरकार द्वारा अनुमोदित सिद्धांतों के आधार पर राजस्व-मण्डल विनिश्चित कर। नियम 27-क के प्रभावशील होने के दिनांक को तदर्थ आधार पर कार्यालय-अधीक्षक प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी और आधुनिक प्रथम

17 वि. सं 3 (2) DOP (A-II) 76 G S R 98 दि 5 10 1976 द्वारा निविष्ट।

18 वि सं एफ 5 (1) DOP/A-II/78 G S R 78 दि 6 फरवरी 1979, द्वारा निविष्ट। राजस्थान-राजपत्र असाधारण, भाग 4 (ग) (1) दि 6 ■ 79 में पृष्ठ 363 पर प्रकाशित।

श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के पदों को धारण करने वाले व्यक्ति निम्न पद पर अपनी अधिष्ठायी स्थिति के आधार पर अपना पदाधिकार विनिश्चिन (Delineated) करवायेंगे। ऐसे व्यक्ति नियम 27-क के उपबन्धा के अनुसार नियमित पदोन्नति के लिये पात्र होंगे।

### 128 परीक्षा की अवधि—

2[(1) सीधी भर्ती से सेवा में किसी अधिष्ठायी रिक्त स्थान पर नियुक्त समस्त व्यक्तियों का दो वर्ष की अवधि के लिये तथा पदोन्नति विशेष चयन द्वारा किसी पद पर ऐसे रिक्त स्थान पर नियुक्त व्यक्तियों को एक वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर रखा जावेगा,]

परन्तु यह है कि—

( ) पदोन्नति/विशेष चयन या सीधी भर्ती द्वारा अधिष्ठायी रिक्त स्थान पर उनकी नियुक्ति से पूर्व, उनमें से ऐसे (व्यक्ति) जिन्होंने उस पद पर त्रित पर बाद में नियमित चयन हो गया है, अर्थात् रूप से स्थानापन्न कार्य किया है उनको नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी स्थानापन्न या अस्थायी सेवा को परीक्षा की अवधि में गणित करने की अनुमति दी जा सकती है। मनेकेन, ऐसा करना किसी वरिष्ठ व्यक्ति को प्रतिष्ठित करना या नियुक्ति के सम्बन्धित कोटा या धारक्षण में उनकी प्राथमिकता के क्रम को बाधित (disturb) करना नहीं माना जावेगा।

(ii) ऐसी नियुक्ति के बाद की कोई अवधि, जिसमें कोई व्यक्ति तत्समान या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रहता है, परीक्षा की अवधि में गणित की जावेगी।

- 1 वि स एफ 1 (35) कार्मिक (क-2) 74 दिनांक 4.5.1977 द्वारा निम्नांकित क स्थान पर प्रतिस्थापित तथा राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी—

‘29 परीक्षा—किसी अवधि में सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों को एक वर्ष के लिये परीक्षा पर रखा जावेगा।

स्पष्टीकरण—उस व्यक्ति के मामले में जो मर जाता है या अविवाहिकी आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होने वाला है परीक्षाकाल को इस प्रकार कम कर दिया जावेगा कि—वह उसकी मृत्यु या सेवा निवृत्ति के दिनांक से तुरंत पहले के एक दिन पूर्व समाप्त हो जावे। मृत्यु या सेवा निवृत्ति के ऐसे मामले में पुष्टिकरण सम्बन्धी विभागीय परीक्षा उस की करने की शक्त भी छोड़ दी गई समझी जावेगी।

- 2 वि स एफ DOP/ A-11/74 दि 9.4.1979 द्वारा प्रतिस्थापित ‘प्रत्येक व्यक्ति’ के स्थान पर ‘समस्त व्यक्तियों’ परिवर्तित कि

इसके विपरीत किसी विकल्प की अनुपस्थिति में, यह मान लिया जावेगा कि उन्होंने इस नियम के अधीन स्थायीकरण (पुष्टीकरण) के पक्ष में विकल्प लिया है और पूर्व पद पर उनका पदाधिकार समाप्त (Cease) हो जावेगा ।”

429 परिवीक्षा के दौरान असंतोष प्रद प्रगति—

(1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर ऐसा प्रतीत हो कि—सेवा के किसी सदस्य ने अपने अवसरा का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या वह सन्तोषप्रद कार्य करने में असफल रहा है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उस उसकी नियुक्ति से ठीक पूर्व उसके द्वारा अधिष्ठायी रूप से धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगी, परन्तु यह तब जब कि उस पद पर उसका धारणाधिकार (लियन) हो, और अन्य मामलों में उसकी सेवान्ता की समाप्ति या सेवोन्मुक्ति कर सकेगी ,

परन्तु यह है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी मामले में या मामलों की श्रेणी में यदि वह ऐसा उचित समझे, तो सेवा के किसी सदस्य की परिवीक्षा की कालावधि को विनिर्दिष्ट अवधि तक बढ़ा सकेगा, जो सीधीभर्ती द्वारा सेवा में किसी पद पर नियुक्ति व्यक्ति के मामले में दो वर्ष से तथा ऐसे पद पर पदोन्नति । विशेष ध्यान द्वारा नियुक्ति व्यक्ति के मामले में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी

परन्तु आगे यह भी है कि—नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों के मामले में यथास्थिति, यदि वह ऐसा उचित

4 वि स एफ । (35) कार्मिक (क 2) 74 दिनांक 4 5 1977 द्वारा निम्न के लिए प्रतिस्थापित—

“29 परिवीक्षा के दौरान असंतोषप्रद प्रगति—(1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर ऐसा प्रतीत हो कि एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति सन्तोष प्रद कार्य करने में असफल रहा है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे उसकी नियुक्ति से ठीक पूर्व उसके द्वारा अधिष्ठायी रूप से धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा, परन्तु यह तब जबकि उस पद पर उसका धारणाधिकार (लियन) हो, और अन्य मामलों में उसे सेवा से मुक्त कर सकेगा ।

परन्तु यह है कि—नियुक्ति प्राधिकारी किसी परिवीक्षाधीन या परिवीक्षाकाल विनिर्दिष्ट अवधि तक बढ़ा सकेगा, जो छ मास से अधिक नहीं होगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर प्रतिवर्तित या सेवामुक्त परिवीक्षाधीन व्यक्ति किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा । ,

5 वि स 7 (6) DOP (A-2) 77 दिनांक 25 10 1977 द्वारा जोड़ा गया तथा दिनांक 1-1-1973 से प्रभावी ।

समझा, तो परिवीक्षा की कालावधि को एक बार में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये तथा कुल मिलाकर तीन वर्ष से अधिक वृद्धि के लिये, बढ़ा सकेगा।

(2) उपरोक्त परतुक में किसी बात के होते हुए भी, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, यदि एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति को निलम्बनाधीन रखा गया हो, या उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित हो या आरम्भ कर दी गई हो, तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को उस अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा, जो नियुक्ति प्राधिकारी उन परिस्थितियों में उचित समझे।

(3) उपनियम (1) के अधीन परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर प्रतिवर्तित या सेवानिवृत्त परिवीक्षाधीन व्यक्ति किसी भी प्रकार की क्षति पूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा।

30 पुष्टीकरण (कनफर्मेशन) या स्थायीकरण—एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति अपने पद पर परिवीक्षा की कालावधि की समाप्ति पर स्थायी (कनफर्म) कर दिया जायगा यदि —

(क) वह हिन्दी में प्रवीणता सम्बन्धी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है,

(क) उन निविष्ट लिपिकों के मामले में जो टकणपरीक्षा को विकल्प में नहीं चुनते हैं, उनको नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित एक टकणपरीक्षा हिन्दी या अंग्रेजी में जो आयोजन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में विहित स्तर से निम्न नहीं होगी या हरिश्चन्द्र मायूर लोक प्रशासन राज्य संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा (टेस्ट) दो वर्ष की अवधि के भीतर उत्तीर्ण करनी होगी, इसमें अग्रफल रहने पर वे स्थायी नहीं किये जावेंगे और उनकी सेवाये समाप्त की जा सकेंगी। वे अभ्यर्थी जिन्होंने या तो किसी विश्वविद्यालय से या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से टकण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उनको यह परीक्षा (टेस्ट) उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उन अभ्यर्थियों के मामले में जो स्नातक

6 वि स 10 (1) नियुक्ति (क) 55 दिनांक 16 6 1959 द्वारा निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित

“एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति अपने पद पर परिवीक्षा की कालावधि की समाप्ति पर स्थायी कर दिया जाएगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उसकी सत्यनिष्ठा सन्देह से परे है और वह अथवा स्थायीकरण के लिए योग्य है।”

7 वि स एफ 3 (3) DOP (A-2) 76 दिनांक 30 6, 1976 द्वारा निविष्ट तथा राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी।

8 वि स 3 (8) DOP (क 2) 76 दिनांक 13 4 1977 द्वारा जोड़ा गया।

(ग्रेजुएट) नहीं है और जिन्होंने टक्कण-परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उनको आयोग द्वारा आयोजित बनिठ लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिये इन नियमों में विहित स्तर से निम्न स्तर की नहीं हो, ऐसी अंग्रेजी या हिन्दी में टक्कण परीक्षा 11 मास की अवधि के भीतर उत्तीर्ण करनी होगी, किन्तु यह अवधि ऐसे अभ्यर्थी के मामले में आगे तीन मास तक बढ़ाई जा सकेगी जो टक्कण परीक्षा में छ मास के भीतर बैठता है परन्तु उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने में असफल रहता है या उसके नियंत्रण के बाहर के कारणों से उस परीक्षा में नहीं बैठ सका हो और उसका काय मन्तोष प्रद पाया गया हो। ऐसी परीक्षायें जयपुर में निदेशक, हरिश्चन्द्र माधुर लोक प्रशासन राज्य सस्थान द्वारा आयोजित की जायेगी तथा अयत्र जिला नियोजन अधिकारी द्वारा जिला मुख्यावास पर आयोजित की जावेगी, जो एक समिति के पर्यवेक्षण में होगी। जिसमें जिलाधीश द्वारा मनोनीत दो जिला स्तरीय अधिकारी होंगे तथा जिना नियोजन अधिकारी उसका समोजक होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के ऐसे अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा ऐसे निर्देशों के अनुसार आयोजित होगी जो निदेशक, हरिश्चन्द्र माधुर लोक प्रशासन राज्य सस्थान और जिला नियोजन अधिकारी, यथास्थिति, द्वारा जारी किये जा सकेंगे।

परन्तु यह है कि—शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को अनुसूची I के भाग II में प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम में विहित टक्कण परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण —(1) इस परन्तुक के प्रयोजनाय “शारीरिक रूप से विकलांग” के अर्थ में वह व्यक्ति सम्मिलित है, जिसके किसी एक या दोनों हाथों में ऐसा शारीरिक दोष है या हाथों में ऐसी विकलांगता है जो टक्कण काय में बाधा उत्पन्न करती है।

(2) इस प्रकार शारीरिक रूप से विकलांग होने के प्रमाण में अभ्यर्थी को एक चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की श्रेणी से निम्न का नहीं हो परीक्षा में बैठने के लिए आयोग को प्रस्तुत किये जा रहे उसके आवेदन पत्र के समय प्रस्तुत करना होगा।

10(ककक) आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के मामले में इन नियमों के नियम 7 के परन्तुक (7) के अन्तर्गत नियुक्ति तथा जो इन नियमों के नियम 7 के परन्तुक (7) के खण्ड (ख) में वर्णित किसी सस्थान या सरकार द्वारा समय समय पर मान्यता प्राप्त सस्थानों से द्वितीय भाषा की परख (टेस्ट) कम गति पर उत्तीर्ण कर चुके हो।]

- 9 वि स 3(9) DOP (क-2) 76 दिनांक 21 1 1977 द्वारा जोड़ा गया।
- 10 वि स 3(4) DOP (क-2) 77 दिनांक 15 3 1978 द्वारा जोड़ा गया।
- 11 वि स 21 (6) नियुक्ति (ग) 54 भाग VI दिनांक 17 3 1972 द्वारा जोड़ा गया।

(ख) उसने विहित विभागीय परीक्षाएँ, यदि कोई हो पूर्ण रूप से उत्तीर्ण करली हो, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया हो कि उसकी सत्य निष्ठा सदेह से परे है और वह अथवा स्थायीकरण के योग्य है।

11(घ) उपरोक्त उपखण्ड (क) तथा (ख) में वर्णित परीक्षाएँ स्वयंकारो के मामले में 29 3 1965 तक प्रभावी नहीं होगी।

टिप्पणी—उपरोक्त सशोधन दिनांक 30 3 1963 से प्रभावी हुआ समझा जायगा तथा दिनांक 29 3 1965 तक प्रभावी रहेगा।

1230-क—पूववर्ती नियमों में किसी बात के होते हुये, राजस्थान राज्य के पुनगठन से पूर्व के ऐसे कर्मचारी को जो दिनांक 1 4 56 को तीन वर्ष से अनधिक की लगातार सेवा नियुक्ति प्राधिकारी के समाधान हेतु पूरी कर चुका हो, उनकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जावेगा।

130-ख—नियम 30 में किसी बात के होते हुए भी किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति का उसकी परिवीक्षा की कालावधि की समाप्ति पर अपने पद पर स्थायीकरण कर दिया जायगा चाहे परिवीक्षा की अवधि के दौरान, नियमों में निर्धारित विहित विभागीय परीक्षा/प्रशिक्षण/हिंदी में प्रवीणता सम्बन्धी परीक्षा का, यदि कोई हो, आयोजन नहीं किया गया हो, परंतु यह जब तक कि—

(1) वह अथवा स्थायीकरण के योग्य हो, और

(ii) परिवीक्षा की कालावधि इस सशोधन के राजस्थान-राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक को अथवा उससे पूर्व समाप्त हो जाती है।

231 वेतन मान—विभिन्न वर्गों के पदों पर नियुक्त किसी व्यक्ति के मासिक वेतन की शृङ्खला (वेतनमान) वह होगी, जो सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत की जाय।

12 वि स एफ 10 (1) नियुक्ति (क) 55 दिनांक 16 6 1959 द्वारा जोड़ा गया।

1 वि स एफ 1 (12) नियुक्ति (क-2) 68 भाग V दिनांक-17 10 1970 द्वारा निविष्ट।

2 वि स 10 (1) नियुक्ति (क) 55 दिनांक 16 6 1959 के द्वारा निम्न शब्दावली के सिधे प्रतिस्थापित—

“अनुसूची III के कालम 2 में वर्णित किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति को उस अनुसूची के कालम 3 में वर्णित वेतनमान में मासिक वेतनमान अनुज्ञेय होगा।”

**32 परीक्षा के दौरान वेतन वृद्धि**—एक परीक्षाधीन व्यक्ति राजस्थान सेवा नियम 1951 के उपबन्धों के अनुसार उसे अनुज्ञेय वेतनमान में वेतन वृद्धि प्राप्त करेगा।

**32 क**—इन नियमों के प्रसारित होने के दिनांक को आशुलिपिक तृतीय श्रेणी के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति को या इन नियमों के नियम 25 के उपनियम (2) के परंतुक या नियम 26 (3) के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति को, जो आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक तृतीय श्रेणी के लिये परीक्षा (टस्ट) उत्तीर्ण करने में असमर्थ रहा, उसकी नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन न करने के मामले में उस पद के लिये विहित वेतनमान में वेतन वृद्धि या अतिरिक्त करने की अनुमति दी जावेगी।

परन्तु यह है कि नियुक्ति प्राधिकारी वह पर धारित धरन के लिये दफ्ती उपयुक्तता के बारे में अथवा (अथवा) समाधान कर लेता है।

**स्पष्टीकरण**—वि स एफ (21) नियुक्ति (घ) 59 दिनांक 16 मार्च, 1964 के अधीन यह स्पष्ट कर दिया गया था कि—उपरोक्त सशोधन पूर्ववर्ती प्रभाव से इन नियमों के प्रभावी होने के दिनांक से प्रभावी होंगे।

अब यह पुनः स्पष्टीकरण किया जाता है कि—किसी व्यक्ति की आशुलिपिक के रूप में प्रारम्भिक नियुक्ति के समय यह आवश्यक था कि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रसंगित नियमों में वर्णित गति से, या नियमों प्रसारित होने के दिनांक से पहले की अवधि के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान एकीकरण) नियम 1950 (U P S) वर्णित गति की धर से आशुलिपि तथा टंकण की परीक्षा लेनी चाहिये और उनका यह समाधान हो जाने के बाद उसे इस बारे में लिखित में अभिलिखित करना चाहिये कि—अभ्यर्थी वांछित गतियाँ प्राप्त हैं तथा केवल तभी सम्बन्धित व्यक्तियों को

3 वि स एफ 3 (11) नियुक्ति (क-2) 58 भाग IV दिनांक-16 10 1973 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—

**32 परीक्षा के दौरान वेतन**—सेवा, सेवा के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों का प्रारम्भिक वेतन उस पद के वेतनमान का दूरतम होगा, यदि यह है कि—राजकाय में पहले से कार्यरत व्यक्तियों का वेतन राजस्थान सेवा नियम 1951 के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित किया जायगा।

4 वि स एफ 10 (21) नियुक्ति (घ), 59 दिनांक-17 8 1963 तथा 25 9 1963 द्वारा जोड़ा गया।

5 वि स एफ 10 (1) नियुक्ति (क) 57 दिनांक 27 8 1964 द्वारा जोड़ा गया।

आशुनिर्दिष्ट के रूप में प्रस्थापित तौर पर नियुक्त करना चाहिये। यदि ऐसा कर लिया गया है, तो उन पदों के धारक उस समय तक वेतन वृद्धि प्राप्त करने में होंगे जब तक कि वे आयोग की परीक्षा में नहीं बैठते हैं। जैसे कैंपे, यदि वह इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उनकी आगे की वेतन वृद्धि रोक दी जावेगी किन्तु पूर्ववर्ती प्रभाव से नहीं। दूसरे शब्दों में—जब तक वे आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण न कर लेते हैं, भविष्य की वेतन वृद्धि अर्जित करने के हक्दार नहीं होंगे। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है किन्तु उसे उस पद पर रखना पड़ रहा है क्योंकि नियुक्ति के लिये कोई पान व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो उसे वेतन वृद्धि अर्जित करने की स्वीकृति दी जा सकती है, परन्तु (शत) यह है कि विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी लिखित में यह प्रमाणित करे कि—पदस्थापन के लिये कोई पान व्यक्ति परीक्षा में नहीं बैठता है, ता उसकी भविष्य की वेतनवृद्धि रोक दी जावेगी। यदि दूसरी ओर वह बीमारी के कारण परीक्षा में भाग लेने से वंचित रहा हो, जिस तथ्य को सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तो वह अगली परीक्षा में बैठने तथा सफल होने तक के लिये वेतन वृद्धि प्राप्त करता रहेगा।

33 दस्तावेज (इसका बरी B11 130 y B1r) पार करने की कसौटी—किसी समय में नियुक्त कोई व्यक्ति को तब तक दस्तावेज पार करने की स्वीकृति नहीं दी जावेगी, जब तक नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाय कि—उमने सतोपप्रद रूप से कार्य किया है और उसकी सत्यनिष्ठा सदेह से परे है।

### भाग (8) अन्य उपबन्ध

34 अशकाश, भत्ते, पेंशन, आदि का विनियमन—इन नियमों में उपर्युक्त के सिवाय स्थापन (स्टाफ) के वेतन भत्ते पेंशन अवकाश और सेवा की अन्य शर्तें (निम्नलिखित) द्वारा विनियमित होगी—

- (1) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1949, यथा आदिनांक सशोधित
- \*(2) राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान एकीकरण) नियम 1950—यथा आदिनांक सशोधित,
- (3) राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान युक्तियुक्तकरण Rationalisation) नियम 1956, यथा आदिनांक सशोधित।
- (4) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और प्रतील नियम 1958, यथा आदिनांक सशोधित।

\* वि स एफ 10 (1) नियुक्ति (क) 55 दि 10 6 1959 द्वारा जोड़ा गया तथा क्रमांक 2,3,4 को 3,4,5 पुनः स्थापित किया गया।



❧(5) राजस्थान सेवा नियम 1951 (यथा आदिनाक सशोधित) और

(6) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये कोई अन्य नियम जिनमें सेवा की सामान्य शर्तें विहित की गयी हों और जो तत्समय प्रवृत्त हो। □□

## छपते-छपते

समीक्षित सशोधन 1979

(1) नियम 7 के परतुको में निम्नांकित सशोधन करके पढ़िये—

(i) पृष्ठ 19 पर—परतुक (7) की पक्ति 2 में 'श्रेणी के आगे "या आधु टकक, यथास्थिति और जोड़ लें तथा पृष्ठ 20 पर पहली पक्ति में "1-1-76" की बजाय '31-7-1977' पढ़िये।

(ii) पृष्ठ 21 पर—परतुक (8) की पहली पक्ति इस प्रकार पढ़िये— '31-7-1977 के पूर्व आधुलिपिक द्वितीय श्रेणी या आधु टकक, यथास्थिति के रूप में अस्थायी।' आगे तीसरी पक्ति में 'सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा आयोजित' के बजाय 'हरिश्चंद्र भायूर लोक प्रशासन राज्य संस्थान द्वारा आयोजित अथवा आधुलिपि और अथवा टीकण (टाइप) तथा भाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी आधुलिपि तथा हिंदी टकक की' पढ़िये।

(iii) पृष्ठ 22 पर—पहली-दूसरी पक्ति में 'दो अवसर' की बजाय "तीन अवसर" पढ़िये।

[वि स एफ 3(4) DOP/A-II/77 GSR 30 दि 23-5 1979 द्वारा, जो राजस्थान राजपत्र दि 31-5 1979 में पृष्ठ 80-82 पर प्रकाशित]

(2) पृष्ठ 39 पर नियम 15 के उपनियम (5) के अंत में निम्न परतुक जोड़ा गया—

×[परतु यह है कि—यदि एक विभाग में अधीक्षक श्रेणी द्वितीय के पदों की कुल संख्या और आधुलिपिक द्वितीय श्रेणी के पदों की कुल संख्या बराबर हो तो साधारण सदन के सदस्य अधीक्षक श्रेणी द्वितीय के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।]

❧ वि स एफ (7) (18) नियुक्ति (घ) 59 दिनांक 28-7-1961 द्वारा निम्न शब्दावली के स्थान पर प्रतिस्थापित—

"राजस्थान सेवा नियम 1951 (यथा आदिनाक सशोधित) तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये कोई अन्य नियम जो तत्समय प्रवृत्त हो।"

× वि स प 3(2) DOP/A-II/77 GSX/2 दिनांक 1 जून 1979 द्वारा जोड़ा गया।

# अनुसूची - I

(नियम 20 देखिये)

प्रतियोगिता परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम तथा नियम

<sup>1</sup>भाग (1)—वरिष्ठ लिपिकों के लिये

प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे और प्रत्येक विषय के अंको की संख्या उनके समक्ष दिखाये अनुसार होगी —

खण्ड-क—सब अभ्यर्थियों के लिये (विषय एवं अंक)

( ) अंग्रेजी 75 (2) सामान्य ज्ञान 75 (3) गणित 75

1 वि स एफ 10 (1) नियु (क) 55 दिनांक 15 6 1959 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—

“प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे और प्रत्येक विषय के अंको की संख्या उनके समक्ष दिखाये अनुसार होगी—

खण्ड 'ब'—लिखित

1 हिंदी 100 2 गणित 50

टिप्पणी—जो व्यक्ति हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, उनको मेट्रिक्युलेशन स्तर की अंग्रेजी की अर्हता-परीक्षा में बैठना होगा और उसमें 50% अंक प्राप्त करने होंगे।

खण्ड 'ख'—मौखिक

3 व्यक्तित्व तथा साक्षात्कार परीक्षा 50

मौखिक परीक्षा के लिये कुल अंक निम्न प्रकार विभाजित होंगे—

व्यक्तित्व 20, सामान्य ज्ञान 20, विशिष्ट पद के लिये उपयुक्तता 10

एक अभ्यर्थी जिसके पास आयोग द्वारा आयोजित अंग्रेजी या हिंदी टक्का-परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र है उसे 10 अंक तक के कृपाक दिये जा सकेंगे, परंतु उसके द्वारा मौखिक परीक्षा में प्राप्त किये गये अंक इन कृपाकों सहित 50 से अधिक न हों।

लिखित प्रश्न पत्रों का स्तर व क्षेत्र निम्नलिखित होगा—

1 हिंदी—यह प्रश्न पत्र अभ्यर्थी की भाषा में दक्षता की परख करने के लिये बनाया जायेगा। अनेक वरिष्ठ विषयों में से एक पर निबंध लिखने के साथ इसमें सारांश लेखन, पत्र लेखन, मुहावरों का प्रयोग आदि सम्मिलित किये जा सकेंगे। समय दो घण्टे होगा। बहुत ही सुन्दर हस्तलेख के लिये अधिकतम 5 तक कृपाक दिये जा सकेंगे।

क्रमशः

खण्ड-ख—प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न विषयों में से एक ले—

- (4) सामान्य भारतीय इतिहास 100, (5) सामान्य भूगोल 100  
 (6) प्रारम्भिक भौतिकी एवं नागरिक शास्त्र 100, (7)<sup>2</sup> भारतीय अर्थशास्त्र एवं  
 रासायनिकी 100 (8) हिन्दी 100, [(9) बुक कीपिंग व लेखा 100,  
 (10) व्यापार प्रणाली 100]

टिप्पणी—खण्ड क तथा ख में वर्णित प्रत्येक विषय के प्रश्नपत्र का समय तीन घण्टा  
 का होगा।

प्रत्येक विषय में परीक्षा का स्तर व क्षेत्र निम्नांकित होगा—

खण्ड-क (अनिवार्य)

1 अंग्रेजी—प्रश्नपत्र भाषा में अभ्यर्थी की प्रवीणता की जाच करने के लिये  
 तैयार किया जायेगा। दिये हुए विषयों में वे एक पर घ अंग्रेजी में निबध (Essay)  
 लिखने के साथ इसमें हिन्दी से इंगलिश अनुवाद, सारांश (प्र सी) रेखन तथा मुहा  
 वरा (idioms) के प्रयोग आदि सम्मिलित हो सकेंगे।

2 सामान्य ज्ञान (जनरल नोलेज)—यह प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धि, अवलोकन  
 (निरीक्षण) की शक्ति और (ऐसे) ज्ञान की जाच के लिये तैयार किया जावेगा,  
 जिसकी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है जो स्कूला और कॉलेजों में पढ़ाये जान  
 वाले विषयों में साधारण आधारभूत बातें सीखे हुये हैं और उनके संग्रह को विश्व  
 विद्यालय में या पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ पढ़ने से, व्याख्यान सुनने से और  
 अपने आसपास की वस्तुओं जैसे रेडियो, वायुयान आदि में बुद्धिमत्तापूर्ण रुचि लेकर  
 सीखे हों। प्रश्न साधारणतया ऐसे होंगे, जिनके सक्षिप्त उत्तर स्वीकार हो सकें और  
 साथ ही लोक प्रिय विज्ञान को भी सम्मिलित करेंगे तथा उस समय की सामाजिक,  
 राजनैतिक तथा आर्थिक घटनाओं को भी।

3 अंक गणित—सम्पूर्ण अथ गणित (बीज गणित के बि हो व तरीका का  
 का प्रयोग किया जा सकेगा)

2 गणित—यह प्रश्न पत्र नेमी गणना करने में अभ्यर्थी की गति तथा  
 शुद्धता की परख करने के लिये होगा।

टिप्पणी—अभ्यर्थी को अपनी स्वयं की लेखन सामग्री काम में लेने को कहा  
 जा सकता है, परन्तु इस के लिये पर्याप्त सूचना देनी चाहिए।

2 यहाँ मूल नियमावली में मुद्रण की भूल है—, '6 प्रारम्भिकी भौतिकी एवं  
 रासायनिकी तथा 7 भारतीय अर्थशास्त्र व नागरिक शास्त्र' होना  
 चाहिये—दत्त।

3 वि स 10(1) नियुक्ति (क) 55 दिनांक 31-3-1962 द्वारा जोड़ा गया।

### खण्ड—ख (ऐच्छिक)

4 सामान्य भारतीय इतिहास—ज्ञान का न्यूनतम क्षेत्र वह होगा जो इटर मीडिएट कालेज के विद्यार्थी को प्राप्त करना चाहिये, जो भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों (Periods) के मुख्य पहलुओं और प्रमुख घटनाओं का परिचय प्राप्त कर चुका है और विशेष रूप से अरुबर के शासन से लेकर वर्तमान तक के युग से सम्बन्धित है।

5 सामान्य भूगोल—न्यूनतम क्षेत्र वही होगा जैसा सामान्य भारतीय इतिहास के लिये है। प्रश्न पत्र में विश्व के भूगोल पर प्रश्न तथा भूरचना (फिजियो-ग्राफी) पर प्रश्न सम्मिलित होंगे। इनमें एक प्रश्न मानचित्र खेचने का होगा।

6 प्रारम्भिक भौतिकी एवं रासायनिकी—प्रश्न पत्र प्रारम्भिक भौतिकी एवं रासायनिकी पर होगा जिसमें ज्ञान का न्यूनतम क्षेत्र वह होगा जो इटर कालेज के एक छात्र से प्राप्त करने की अपेक्षा (भाषा) की जाती है।

7 भारतीय अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र—इसमें ज्ञान का न्यूनतम क्षेत्र वह होगा जो इटरकालेज के एक छात्र से प्राप्त करने की भाषा की जाती है। अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र के मूल सिद्धांतों (Salient principles) तथा उनको भारतीय परिस्थितियों में लागू करने पर प्रश्न पूछे जा सकेंगे।

8 हिंदी—प्रश्न पत्र अर्थव्यर्थ की भाषा में प्रवीणता की जांच करने के लिये होगा। बहुत से श्रिये गये विषयों में से एक पर निश्चय लिखने के साथ साथ इसमें सारांश लेखन, पत्र लेखन तथा मुहावरों का प्रयोग आदि सम्मिलित हो सकेंगे। प्रश्न पत्र का सामान्य स्तर राजस्थान विश्वविद्यालय की हाई स्कूल परीक्षा का होगा।

49 बुककीपिंग व लेखा तथा व्यापार पद्धति के—प्रश्न पत्रों में ज्ञान का न्यूनतम स्तर वही होगा जो इटरमीडिएट/प्रोविन्शियली कोम के छात्र के लिये है।

टिप्पणी—(1) एक ऐच्छिक प्रश्नपत्र का उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में लिखा जा सकेगा।

(2) प्रायोगिकी की निर्देश दे सकेगा कि किन अभ्यर्थियों का छिछला मान या गरी लेखनी है उनके अंको में कटौती कर ली जाये।

### भाग (2) कनिष्ठ लिपिकों के लिये

प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे और प्रत्येक विषय के अंको की सराया उनके समान दिखाये अनुसार होगी—

4 वि स एफ 10 (1) नियु० (क) 55 दि 31 3 1962 तथा 14 10 62 द्वारा जोड़ा गया।

5 वि स 3 (3) DOP/A II/76 दिनांक 30 6 1976 द्वारा प्रतिस्थापित

खण्ड—क—समस्त अभ्यर्थियों के लिये  
(1) सामान्य हिन्दी 100, (2) सामान्य ज्ञान 100, (3) भ्रमणणित 100

तथा राज पत्र में प्रकाशन के निम्न से प्रभावशील, पुराना पाठ्यक्रम  
(30 6 76 से पूरा वा) यहाँ दिया जा रहा है।—

भाग II—कनिष्ठ लिपिकों के लिये  
प्रतियोगिता परीक्षा में निम्न विषय सम्मिलित होंगे तथा प्रत्येक विषय क  
उनके समक्ष प्रकृत भव होंगे।

खण्ड (क) समस्त अभ्यर्थियों के लिये  
(1) अंग्रेजी 75 (2) सामान्यज्ञान 75 (3) गणित 75

खण्ड (ख)—निम्न में से कोई दो विषय लेने होंगे  
(4) टक्कण अंग्रेजी 100 (5) टक्कण हिन्दी 100 (6) हिन्दी 100

द्वितीय—(1) खण्ड 'क' तथा खण्ड 'ख' में हिन्दी के प्रश्न पत्र तीन बटे  
के होंगे।

(2) जो विभाग टक्कण लिपिक चाहते हैं, नियुक्ति के मामले में  
उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देंगे, जो अंग्रेजी या हिन्दी  
या दोनों में टक्कण-परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं।

प्रत्येक विषय का स्तर व क्षेत्र निम्न प्रकार से होगा—

खण्ड (क) अनिवार्य

1 अंग्रेजी—यह प्रश्नपत्र अभ्यर्थी की भाषा में दक्षता की परख के लिये बनाया  
जायेगा। अंग्रेजी में एक निबन्ध लिखने के साथ इसमें हिन्दी से अंग्रेजी  
अनुवाद, सारांश लेखन तथा मुहावरों का प्रयोग आदि सम्मिलित होंगे।

2 सामान्यज्ञान—यह प्रश्नपत्र सामान्य बुद्धि, अवलोकन शक्ति तथा ज्ञान जिसकी  
अभ्यर्थी से माशा की जाती है, जो स्कूल में पढाये जाने वाले विषयों की  
सामान्य पृष्ठभूमि रखते हुए आस पास की वस्तुओं के प्रति बुद्धिपूर्ण रुचि लेता  
रहता है।

3 गणित—अभ्यर्थी की नेमी गणना करने में गति व शुद्धता की परख करने  
के लिये यह प्रश्न पत्र बनाया जावेगा।

4 खण्ड (ख) (ऐच्छिक)  
अंग्रेजी में टक्कण—इस परीक्षा में गति-परीक्षा और दक्षता परीक्षा प्रत्येक  
50 अंक की होगी। न्यूनतम गति 30 शब्द प्रति मिनट अपेक्षित है। प्रमाण

### 8[ टिप्पणी—विनोदित ]

एण्ड—ख—अभ्यर्थी इनमें से कोई एक विषय लेगा

शारीरिक रूप से विरूपागो के लिये जो नियम 30 की शर्तों को पूरी करते हैं और उन अभ्यर्थियों के लिये जो कला/विज्ञान/वाणिज्य में डिग्री धारण करते हैं—

(1) सामान्य अंग्रेजी 100, (2) अंग्रेजी में टंकण 100,

(3) हिंदी में टंकण (टाइप) 100—

उन अभ्यर्थियों के लिये जो स्नातक (ग्रेजुएट) नहीं हैं—

(1) अंग्रेजी में (टाइप) टंकण 100, (2) हिन्दी में टंकण 100

टिप्पणियाँ—(1) एण्ड व तथा ख में वर्णित विषयों तथा सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न-पत्रों का समय तीन घंटे का होगा। (2) समस्त प्रश्न-पत्रों का जहाँ विशेष रूप से वांछित न हो, हिंदी या अंग्रेजी में उत्तर दिया जावेगा, किंतु कोई अभ्यर्थी को आंशिक रूप से हिंदी में या आंशिक रूप से अंग्रेजी में किसी प्रश्न-पत्र का उत्तर देने के लिये अनुमति नहीं दी जावेगी जब तक कि ऐसा करने के लिये विशेष रूप से अनुमति नहीं हो।

### एण्ड 'क' अनिवार्य प्रश्न-पत्र

1 प्रश्नपत्रों का स्तर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैंकेडरी परीक्षा का होगा।

(पीछे में)

5 हिंदी में टंकण—इस परीक्षा में एक गति परीक्षा और एक दक्षता परीक्षा प्रत्येक 50 अंकों की होगी। न्यूनतम गति 30 शब्द प्रति मिनट अपेक्षित है।

6, हिंदी—यह प्रश्न पत्र भाषा में अभ्यर्थी की दक्षता की परख करने के लिये होगा। अनेक दिये गये विषयों में से एक पर निबंध लिखने के साथ इसमें सारांश लेखन, पत्र लेखन, मुहावरों का प्रयोग आदि सम्मिलित होंगे।

टिप्पणी—(1) अभ्यर्थी अपना स्वयं का पेन और पसिल लायेगा।

(2) बुरे हस्तलेख के कारण अभ्यर्थी को दिय गये अंकों में से कटौती करने लिये आयोग परीक्षकों को निर्देश दे सकेगा।

6 वि स एफ 5 (8) DOP/A-2/77/GSR 9 दि० 28 जनवरी 1978 द्वारा जोटी गई निम्नांकित टिप्पणी वि स एफ (8) DOP/A-II/77 भाग II दिनांक 5 10 1978 द्वारा विलोपित की गई—

टिप्पणी—नियम 25 के उपनियम (2) के परंतुक (3) में वर्णित अभ्यर्थी "सामान्यतः" के प्रश्न-पत्र की बजाय कार्यालय पद्धति, सारांश लेखन, हस्तलेखन तथा सरकारी तंत्र की व्यवस्था" ऐच्छिकरूप से ले सकते हैं।

राजस्थान प्रचीनस्य कार्यालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम [ अनुसूची

2 सामान्य हिंदी—प्रश्न-पत्र अभ्यर्थियों की भाषा मध्यमता की जांच क लिये होगा। बहुत से दिय गये विषयों में से एक पर निबन्ध लिखने के साथ ही सारांश लेखन, पत्र लेखन, मुहावरों का प्रयोग आदि सम्मिलित हो सकेंगे।

3 सामान्यज्ञान—प्रश्न-पत्र साधारण, बुद्धि, निरीक्षणशक्ति और गान परख के लिये बनाया जावेगा, जिस (ज्ञान) की उन अभ्यर्थियों से प्राप्ति की जात है जो स्कूल में पढ़ाये जाने वाले विषयों की साधारण आधारभूत बातें सीखकर अपने घरों और की वस्तुओं पर, राजस्थान के विशेष सदर्भ सहित, बुद्धिमत्तापूर्वक रवि को बनावे रखता है।

4 अक्षरगणित—यह प्रश्न-पत्र अभ्यर्थी की नैमी सगणना करने के गति व सूक्ष्मता की परख करने के लिये होगा।

\*5 [ विलोपित  $\times \times \times$  ]

छाण्ड 'छा' ऐच्छिक विषय

5 सामान्य अंग्रेजी—यह प्रश्न-पत्र अभ्यर्थी की भाषा में दक्षता की परख करने के लिये होगा। अंग्रेजी में लिखे गये एक निबन्ध के साथ इसमें हिन्दी से से अंग्रेजी में अनुवाद, सारांश-लेखन तथा मुहावरों का प्रयोग आदि सम्मिलित हो सकेंगे।

6 अंग्रेजी में टंकण (टाइपिंग)—इस परीक्षा में एक गति की परख (टेस्ट) तथा एक दक्षता की परख सम्मिलित होगी, जिसमें प्रत्येक के लिये 50 अक्षर होंगे। 'यूनितम (टाइप करने को) गति 25 शब्द प्रतिमिनट की भाषा की जाती है। प्रत्येक परख में 'यूनितम उत्तीर्णांक 18 अक्षर होंगे।

7 हिंदी में टंकण—इस परीक्षा में एक गति की परख तथा एक दक्षता की परख सम्मिलित होगी, जिसमें प्रत्येक के लिए 50 अक्षर होंगे। 'यूनितम गति 20 शब्द प्रति मिनट की भाषा की जाती है। प्रत्येक परख में 'यूनितम उत्तीर्णांक 18 अक्षर होंगे।

टिप्पणी—(1) अभ्यर्थी अपनी स्वयं की लेखनी (पेन) व पेंसिल साथ लायेंगे।

7 वि स एफ 5 (8) DOP (A II) 77 GSR 69 दिनांक 28.1.1978 द्वारा जोड़ा गया तथा विनियम 5 (8) DOP/A-II/77 भाग 2 दिनांक 5.10.78 द्वारा विलोपित किया गया जो इस प्रकार था—

5 कार्यालयपद्धति सारांशलेखन हस्तलेखन (सुंदरलेख) तथा सरकारी तब की व्यवस्था—यह प्रश्न पत्र अभ्यर्थी के कार्यालय पद्धति जिसे अनुमति पर आधारित, सारांश (प्रैसी) लेखन, सुंदरलेख तथा सरकारी तब की व्यवस्था (Set up ढांचा) ज्ञान की परख करने के लिये बनाया जावेगा”

(2) आयोग ऐसे निर्देश परीक्षकों को दे सकेगा कि—बुरी लेखनी (हैंड राइटिंग) के लिये वे अभ्यर्थियों के अंकों में कटौती करें।

### भाग (3) आशुलिपिकों के लिये

एक अभ्यर्थी को या तो अंग्रेजी आशुलिपि और अंग्रेजी टंकण या हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टंकण (परीक्षा) उत्तीर्ण करनी होगी और आशुलिपिक श्रेणी द्वितीय के पद के लिये भर्ना-परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे—

- 1 अंग्रेजी आशुलिपि परख 100 अंक  
(इस परख में 100 शब्द प्रतिमिनट से श्रुतिलेख होगा)
- 2 अंग्रेजी टंकण परख 100 अंक  
(इस परख में गतिपरीक्षा तथा दक्षता परीक्षा प्रत्येक 50 अंक की होगी। गति 40 शब्द प्रतिमिनट होगी)
- 3 हिन्दी आशुलिपि परख 100 अंक  
(इस परख में 80 शब्द प्रतिमिनट से श्रुतिलेख होगा)
- 4 हिन्दी टंकण परख 100 अंक  
(इस परख में गति परीक्षा तथा दक्षता परीक्षा प्रत्येक 50 अंक की होगी। गति 30 शब्द प्रति मिनट होगी)  
टिप्पणी—यह परख प्रत्येक छ मास बाद आयोजित की जायेगी।

- 8 उपरोक्त पाठ्यक्रम वि स F 3 (4) DOP/A-II/77 दि 23 5 1979 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित किया गया—

### भाग (3) आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के लिये

["आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के पद के लिए (भर्ना) परीक्षा में निम्नांकित दो वैकल्पिक समूहों में दिये गये विषय सम्मिलित हैं। एक अभ्यर्थी को इन दो समूहों में से किसी एक में वर्णित विषयों में उत्तीर्ण होना होगा।

#### समूह "क"

- 1 अंग्रेजी आशुलिपि परख 100 अंक  
इस परख में 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से श्रुतिलेख होगा।
- 2 अंग्रेजी टंकण परख 100 अंक  
इस परख में गति की परख तथा दक्षता की परख प्रत्येक 50 अंकों की होगी। गति 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिये।
- 3 हिन्दी आशुलिपि परख 100 अंक  
इस परख में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति से श्रुतिलेख होगा।



पीछे से

4 हिन्दी टक्कण परख

100 अक्षर

इस परख में गति की परख तथा दक्षता की परख प्रत्येक 50 अक्षरों की होगी।  
गति 20 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।

समूह "ख"

1 अंग्रेजी प्राशुलिपि परख

100 अक्षर, इस परख में 80 शब्द प्रतिमिनट

की गति से श्रुतिलेख होगा।

2 अंग्रेजी टक्कण परख

100 अक्षर, इस परख में गति की परख तथा

दक्षता की परख प्रत्येक 50 अक्षरों की होगी। गति 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिये।

3 हिन्दी प्राशुलिपि परख

100 अक्षर, इस परख में 80 शब्द प्रतिमिनट की

गति से श्रुतिलेख होगा।

4 हिन्दी टक्कण परख

100 अक्षर, इस परख में गति की परख तथा

दक्षता की परख प्रत्येक 50 अक्षरों की होगी। गति 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिये।

टिप्पणी—(1) यदि किसी अभ्यर्थी ने प्रायोग द्वारा 3 जनवरी 1972 से पहले आयोजित परीक्षा समूह 'क' में आनेवाले विषयों में से किसी में पहले ही उत्तीर्ण करली है, तो उसे उस समूह के बचक शेष विषयों में उत्तीर्ण होना होगा।

(2) यह परीक्षा बच में कम से कम एक बार होगी। [15 3 78 के बाद  
—“प्रत्येक छ मास बाद होगी प्रतिस्थापित किया गया।]  
उपरोक्त पाठ्यक्रम कि स 10 (1) नियुक्ति (क) 59 भाग XXV दिनांक10 5 1975 द्वारा निर्माकित के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था—  
भाग (3) प्राशुलिपिकों के लिये

प्रहता परीक्षा निर्माकित विषयों में होगी—

1 अंग्रेजी प्राशुलिपि परख

100 अक्षर, इसमें 130 शब्द प्रति मिनट पर

2 अंग्रेजी टक्कण परख

100 अक्षर की होगी। गति 40 शब्द प्रति मिनट होगी।

प्रत्येक 50 अक्षरों की होगी। गति 40 शब्द प्रति मिनट होगी।

3 हिन्दी प्राशुलिपि परख

100 अक्षर, इसमें 80 शब्द प्रतिमिनट पर

श्रुतिलेख होगा।

4 हिन्दी टक्कण परख

100 अक्षर, इसमें गति-परीक्षा तथा प्रवीणता परीक्षा

प्रत्येक 50 अक्षरों की होगी। गति 30 शब्द प्रति मिनट होगी।

क्रमशः

### भाग (4)

नियम 25 के उप नियम (2) के परंतु (3) के अधीन आवृत्त व्यक्तियों के लिये कनिष्ठ लिपिका के पद के लिये—

### अर्हता परीक्षा (Qualifying Examination)

इस अर्हता-परीक्षा में निम्न विषय सम्मिलित होंगे तथा प्रत्येक विषय उनके भागे अ कित सस्या या अ का का होगा ।

#### विषय

#### अंक

प्रश्नपत्र-I	भाग I सामान्य हिन्दी भाग II सारांश लेखन एवं हिन्दी या अंग्रेजी में निबंध	100
--------------	---	-----

प्रश्नपत्र-II	कार्यालय पद्धति एवं सरकारी तन्त्र की व्यवस्था (ढाँचा)	100
---------------	--	-----

प्रश्नपत्र III	हिन्दी या अंग्रेजी में टक्कण परीक्षा	100
----------------	--------------------------------------	-----

टिप्पणी—प्रश्न पत्र I में सारांश लेखन तथा निबंध तथा प्रश्नपत्र II में कार्यालय पद्धति तथा सरकारी तन्त्र की व्यवस्था के हिन्दी या अंग्रेजी में उत्तर दिये जा सकते हैं, किन्तु किसी अभ्यर्थी की आशिक रूप से हिन्दी में और आशिक रूप से अंग्रेजी में उत्तर देने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

इन विषयों में परीक्षा का स्तर तथा क्षेत्र निम्न प्रकार से होगा —

1 सामान्य हिन्दी—यह प्रश्नपत्र अभ्यर्थी की भाषा में प्रवीणता की परख करने के लिये होगा । बहुत से दिये गये विषयों में से एक पर निबंध लिखने के साथ ही इसमें सारांश लेखन, पत्र लेखन, मुद्रावरो का प्रयोग आदि सम्मिलित हो सकेंगे ।

(पीछे से)

टिप्पणी—(1) हिन्दी आधुनिकी के पदों के लिये अभ्यर्थियों के मामले में अंग्रेजी आधुनिकी तथा अंग्रेजी टक्कण परीक्षा अनिवार्य होगी ।

(2) जो अभ्यर्थी पहले से ही आयोग द्वारा आयोजित हिन्दी आधुनिकी तथा टक्कण परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे उपरोक्त बिंदु 3 व 4 में वर्णित विषयों में परीक्षा देने से मुक्त रहेंगे ।

9 वि स एफ 5 (8) DOP /A-II/ pt II दिनांक 5 10 1978 द्वारा जोड़ा गया, जो राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग) दि 12 10 78 में पृ, 298-300 पर प्रकाशित किया गया ।

राजस्थान ग्रामीनस्य कार्यालय लिपि वर्गीय स्थापन नियम [ अनुसूची

2 कार्यालय पद्धति तथा सरकारी तंत्र की व्यवस्था—यह प्रश्नपत्र अभ्यर्थी के जिला-मैनुअल पर आधारित कार्यालय पद्धति व ज्ञान की परख करने तथा सरकारी तंत्र की व्यवस्था के बारे में अभ्यर्थी के ज्ञान की परख के लिये होगा।

3 हिंदी या अंग्रेजी में टक्का-लेखन (टाइप राइटिंग)—इस परीक्षा में गति की परख तथा दक्षता की परख प्रत्येक 50 शब्द की होगी। अंग्रेजी टक्का में 25 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टक्का में 20 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति की माता की जाती है।

टिप्पणी—(1) प्रश्न पत्र I तथा II में उत्तीर्णांक 35% तथा प्रश्नपत्र III में प्रत्येक परख में 18 अंक होंगे।

2 अभ्यर्थी अपने निजी कलम (पेन), पसिंस आदि लायेंगे।

3 गंदी हस्तलेखनी के लिये अभ्यर्थी को दिये गये अंकों में से बढ़ाती करने के लिये प्रायोग निर्देश दे सवेगा।

अनुसूची II [विलोपित]

[ विज्ञप्ति स एक 1 (2) नियुक्ति (ब) 60 दि 15 7 1966 द्वारा विलोपित ]

परीक्षा शुल्क

(नियम 21-क देखिये)

स	पद	परीक्षा शुल्क	अनुसूचित जाति/ जनजाति के निये परीक्षा शुल्क	प्रत्येक (वापसी) पर कटौती
1	वरिष्ठ लिपिक (U D C)	रु 0/-	रु 10/-	रु 3/-
2	कनिष्ठ लिपिक (L D C)	रु 10/-	रु 5/-	रु 2/-

# राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1970

[Rajasthan Secretariat Ministerial Service Rules 1970]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

## छपते छपते-सशोधन 1979

[देलिये पृष्ठ 149 पर]

### □ भूल सुधार—

(1) नियम 29 बरिष्ठता—पृष्ठ 134 पर—इसमें दूसरी पक्ति में “अधिष्ठायी नियुक्ति के आदेश की तारीख” के बजाय<sup>1</sup> “अधिष्ठायी नियुक्ति के वर्ष” पढ़िय।

(2) नियम-26 क (पृष्ठ 133) पर इस प्रकार जोड़िये—

26 क —बरिष्ठ लिपिक के पदों पर पदोन्नति का तरीका—

(1) बरिष्ठ लिपिकों के पदों के 67% रिक्त स्थानों को बरिष्ठता-सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जावेगा और ऐसे रिक्त स्थानों को भरने के लिए नियम 25 में वर्णित उपबन्ध लागू होंगे।

(2) बरिष्ठ लिपिकों के पदों के 33% रिक्त स्थानों पर राजस्थान सचिवालय के कनिष्ठ लिपिक<sup>2</sup> [और टेलिफोन ऑपरेटरो] में से जैसा कि अनुसूची I के ग्रुप 'क' के अधीन<sup>3</sup> [क्रम सं० 3] के सामने कालम 6 में वर्णित है, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग की सहमति से

1 वि स एफ 7 (6) DOP (क-2) 73 दिनांक 15 नवम्बर, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित

2 वि एफ 2 (4<sup>क</sup>) DOP/B-1/67 दिनांक 29-5-1974 द्वारा निविष्ट

3 'क्रम सं 2' के स्थान पर वि स एफ 2 (18) DOP (B-1) 73 दिनांक 14-10-1974 द्वारा प्रतिस्थापित तथा दिनांक 15-9-1972 से प्रभावी।

अनुसूची III में उक्त परीक्षा के लिये वर्णित पाठ्यक्रम के अनुसार समय-समय पर तय किये गये अन्तराल (Intervals) पर एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जावेगी।

परन्तु यह है कि इस नियम के अधीन प्रथम प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के प्रयोजनाय उपरोक्त अनुपात में रिक्त स्थानों को 1 जनवरी 1972 संशोधित किया जावेगा। उक्त दिनांक से पहले के विद्यमान रिक्त स्थान वरिष्ठ सह-योग्यता के आधार पर भरे जावेंगे।

परन्तु आगे यह है कि—वरिष्ठ लिपिकों का वेतन एक पद प्रतिवर्ष टेलिफोन आपरेटर से से, जा सचिवालय में टेलिफोन आपरेटर के रूप में सात वर्ष की सेवा धारण करते हो, भ्रन के लिये आरक्षित होगा। यदि किसी वर्ष में कोई टेलिफोन आपरेटर सफल/पान नहीं हो, तो आरक्षित-पद विलुप्त (lapse) हो जायेगा और आरक्षण आगे नहीं ले जाया जावेगा। यह आरक्षण पाच वर्ष के लिये 1974-75 से 1978-79 तक की परीक्षाओं के लिये होगा और 31 मार्च, 1969 के बाद समाप्त हो जायेगा।

(3) उप नियम (2) में वर्णित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के लिये आयोग, यथासम्भव, इन नियमों के भाग IV में वर्णित समान तरीके का अनुसरण करेगा।

## \* राजस्थान सचिवालय

# लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1970

[The Rajasthan Secretariate Ministerial Service Rules 1970]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा में भर्ती की तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा संबंधी शर्तों को विनियमित करने हेतु राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

### भाग—I साधारण

1 सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ —(1) इन नियमों का नाम राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1970 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाएँ —जब तक कि कोई बात विषय अथवा सदभ में विरुद्ध न हो, इन नियमों में —

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से सचिवालय लिपिकवर्गीय स्थापन से संबंधित करने वाला शासन उप सचिव अभिप्रेत है,

(ख) 'आयोग' से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है

(ग) 'ममिति' से नियम 25 व 26 में निर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति अभिप्रेत है,

(घ) 'सीधी भर्ती' से पदोन्नति से अथवा, इन नियमों के भाग IV में यथा विहित भर्ती अभिप्रेत है,

(ङ) 'सरकार' और 'राज्य' से क्रमशः राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य अभिप्रेत है,

§ G S R 8 दि० 29 अप्रैल 1970 द्वारा राजस्थान राजपत्र असाधारण, भाग 4 (ग) दि० 5 मई 1970 को प्रथम बार प्रकाशित। जी एस आर 19 (65) वि स प 2 (2)/वि र/प्रशा/72 दि० 24 मई 1976 द्वारा राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग) I दि० 8 7-76 पृ० 162 (137 165) में प्राधिकृत हिन्दी पाठ (1 जुलाई 1974 तक संशोधित) प्रकाशित हुआ। बाद के संशोधनों का हिन्दी पाठ अप्राधिकृत अनुवाद है।

(ब) "जूनियर डिप्लोमा कोर्स" से सचिवालय का जूनियर डिप्लोमा कान और बाय प्रशिक्षण (विजनेस ट्रेनिंग) अभिप्रेत है जिसे पूरा कर लेने पर राजस्थान के विश्वविद्यालयों द्वारा जूनियर डिप्लोमा दिया जाता है।

(छ) 'सभा का सदस्य' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो इन नियमों के या नियम 38 द्वारा अतिष्ठित नियमों या आदेशों के, उपयोगों के अधीन सेवा में किसी पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किया गया हो इसमें किसी स्थायी पद के पति परिवीक्षा पर रखा गया व्यक्ति भी सम्मिलित है,

(ज) 'अनुसूची' से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है,

(झ) 'सभा' से राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा अभिप्रेत है, 1(ब) 'अधिष्ठायी नियुक्ति' से इन नियमों के अधीन विहित भर्तियों के तरीकों में से किसी द्वारा समुचित ध्यान के बाद किसी अधिष्ठायी अभिप्रेत है और इसमें परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति सम्मिलित है, जो परिवीक्षा काल की समाप्ति पर पुष्टीकरण द्वारा अनुसरित हो।

टिप्पणी — 'इन नियमों के अधीन विहित भर्तियों के तरीकों में से किसी' शब्दावली में आवश्यक (मजेंट) अस्थाई नियुक्तियों के अतिरिक्त, सभा के प्रारम्भिक गठन पर या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के पर लुक के अधीन बनाए गये किन्हीं नियमों के उपयोगों के अनुसार भी गई भर्तियों सम्मिलित होगी।

(ट) "वय" से प्रत्येक वय प्रथम अप्रैल को प्रारम्भ होने वाला वित्तीय वय अभिप्रेत है।

2(ठ) "सेवा या अनुभव" जहाँ कहीं इन नियमों में एक सेवा से दूसरी में या उसी सेवा में एक प्रवर्ग (कटेगरी) से दूसरे में या वरिष्ठ पदों पर अधिष्ठायी रूप से ऐसे पदों की धारण करने वाले व्यक्ति के

1 वि स एफ 7 (3) DOP (A II) 73 दि 5-7-1974 तथा शुद्धिपत्र दि 11-2-75 द्वारा निविष्ट।  
2 वि स एफ 6 (2) नियुक्ति (क II) 71 I दि 9-10-1975 द्वारा निविष्ट तथा दि 27-3-1973 से प्रभावशील।

मामले में, पदोन्नति के लिये एक शन के रूप में विहित है उसमें वह अवधि भी सम्मिलित होगी, जिसमें उस व्यक्ति ने अनुच्छेद 309 के परतुल्य के अधीन वन नियमों के अनुसार नियमित भर्ती के बाद ऐसे पदों पर लगातार कार्य किया है और इसमें वह अनुभव भी सम्मिलित होगा, जो उसने स्थानांतरण, अस्थायी या तदर्थ नियुक्ति द्वारा अर्जित किया है, यदि ऐसी नियुक्ति पदोन्नति की नियमित पक्ति में की गई हो और वह स्थानपूर्ति के लिये या आन्तरिक (अवसर) प्रकार की या किसी विधि के अधीन अवधि नहीं हो तथा उसमें किसी वरिष्ठ कर्मचारी का अतिष्ठान (Supersession) अंतर्वलित न हो सिवाय जबकि—या तो विहित शैक्षणिक और अन्य योग्यताओं की कमी, अयोग्यता या योग्यता (मेरिट) द्वारा अचयन या सम्बंधित वरिष्ठ कर्मचारी के दाप<sup>3</sup>, [या जब ऐसी तदर्थ या अर्जेंट गत्याई नियुक्ति विनिष्ठता सह योग्यता के अनुसार की, जिसके कारण से ऐसा अतिष्ठान हुआ हो।]

टिप्पणी (1) सेवा के दौरान अनुपस्थिति, जैसे—प्रशिक्षण और प्रतिनियुक्ति आदि जो राजस्थान सेवा नियम के अधिन कृत य' (ड्यूटी) मानी जाती है, भी पदोन्नति के लिये आवश्यक 'यूनतम अनुभव या सेवा की संगणना के लिये सेवा के रूप में संगणित की जावेगी।

टिप्पणी (2) जब सेवा का एक सदस्य, जो निजी सचिव या निजी महायक, तथा स्थिति, के पद को धारण किये हुए है, पैतृक समय में उच्चतर पद पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया या अर्जेंट अस्थायी आधार पर उच्चतर पद पर पदोन्नत हो जाता, परंतु उसे जनहित में कायमुक्त नहीं किया गया, तो जब वह पदोन्नति के लिये इस प्रकार हकदार होता है या उससे वनिष्ठ (व्यक्ति) ऐसे पद का कार्यभार संभालता है, जो भी बाद में हा उस दिनांक से अवधि उक्त पद पर जिस पर वह पदोन्नत कर दिया जाता सेवा या अनुभव के रूप में संगणित की जावेगी।

3 वि. न. एफ. न. (2) नियुक्ति (क II) 71 दि. 13-7-1976 द्वारा निविष्ट तथा दि. 1-11-1975 से निविष्ट समझा जावेगा।

4 वि. स. 5 (9) DOP/A II/76 दिनांक 4-6-1977 द्वारा निविष्ट तथा दि. 1-11-1975 से प्रभावशील।



3 निवचन —जब तब सदस्य से भयथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम स 8) इ नियमो के निवचन के लिये उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निवचन के लिय लागू होता है।

#### भाग II सवग

4 सेवा का गठन एव पदों की सख्या —

- (1) सेवा के चार ग्रुप हंगे
- (2) सेवा के प्रत्येक ग्रुप म सम्मिलित पदो का स्वरूप वह होगा जसा नि अनुसूची I के स्तम्भ 2 म विनिर्दिष्ट किया गया है,
- (3) प्रत्येक ग्रुप मे पदो की सख्या उतनी हांगी जितनी सरकार समय स पर प्रवधारित करे, परतु सरकार —
- (क) प्रावश्यक प्रतीत होने पर कोई भी स्थायी या अस्थायी पद समय समय पर सृजन कर सकेगी।
- (ख) किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का प्रतिकर पाने का हकदार बनाये बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद को समय समय पर खाली रख सकेगी, उसको प्रास्थगित रख सकेगी या उसको तोड़ सकेगी या उसका प्रवसान होने दे सकेगी।

#### भाग III भर्ती

5 भर्ती के तरीक —इन नियमो के प्रारम्भ होने के पश्चात सवा मे भर्ती निम्नलिखित तरीको से होगी —

- (क) इन नियमो के भाग IV के अनुसार अनुसूची I के स्तम्भ सख्या 3 मे अधिकृत सीधी भर्ती द्वारा,
- (ख) इन नियमो के भाग V के अनुसार अनुसूची I के स्तम्भ स 3 म अधिकृत पदोन्नति द्वारा

परतु—

- (1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि किसी वष विशेष म भर्ती के किसी एक तरीके से नियुक्ति की जाने के लिये उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो नियुक्ति दूसरे तरीके से उसी रीति से की जा सकेगी जैसा कि इन नियमो म विहित है
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी किसी अथे या विचलाय व्यक्ति को सेवा के किसी पद पर नियुक्त कर सकेगा परतु यह तब जब कि वह उस पद के लिये इन नियमो मे अधिकृतित नूनतम शैक्षिक अहताय रखता हो, ऐसे किसी पद के लिये किसी मा यवा प्राप्त सत्यान मे प्रशिक्षण

प्राप्त किया हुआ हो तथा उक्त पद के लिए अभ्यर्था उपयुक्त पाया जाय

5/3) 1-9-1968 को उसके पूर्व कनिष्ठ लिपिक के रूप में अस्थायी तौर पर भर्ती किया गया व्यक्तियों को, स्पष्ट रिक्रिया उपलब्ध होना पर उनका काम निम्नांकित सिद्धान्तों पर सतोपप्रद पाये जाने पर स्थायी कर दिया जायगा —

- (i) कनिष्ठ लिपिकों को उनकी भर्ती के वर्ष के अनुसार स्थायी किया जावेगा ।
- (ii) एक समान भर्ती के वर्ष के भीतर जूनियर डिप्टीमा कोस उत्तीर्ण और लोक सेवायोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी स्थायीकरण के लिये उसी क्रम में तदर्थ आधार पर भर्ती किये गए कनिष्ठ लिपिकों पर प्राथमिकता प्राप्त करेंगे ।
- (iii) किसी विशिष्ट वर्ष के जू डि को उत्तीर्ण अभ्यर्थी उसी वर्ष के आयोग से चयनित अभ्यर्थियों पर प्राथमिकता प्राप्त करेंगे ।
- (iv) यदि किसी विशिष्ट वर्ष में तदर्थ तरीके से भर्ती किये गये कनिष्ठ लिपिकों में कुछ ऐसे हों जो जू डि को आयोग परीक्षा अगले वर्षों में उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उनको उस वर्ष के अभ्यर्त तदर्थ कनिष्ठ लिपिकों पर स्थायीकरण में प्राथमिकता दी जावेगी, परन्तु यह है कि- कोई व्यक्ति जिसने लोक सेवा आयोग की परीक्षा पिछले वर्ष में उत्तीर्ण कर ली हो तो वह उस व्यक्ति से वरिष्ठ होगा जिसने जू डि को परीक्षा बाद के (अगले) वर्ष में उत्तीर्ण की है ।

कनिष्ठ लिपिक के रूप में कार्य कर रहे किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका काम सतोपप्रद नहीं पाया जाय सेवा से (1) यदि उसने राज्य के काम कलाप के सबंध में अस्थायी तौर पर तीन वर्ष से कम सेवा की हो तो एक मास का नोटिस देकर (2) यदि उसने तीन वर्ष से अधिक सेवा की हो तो राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण कर हटा दिया जायगा,

- (4) वह व्यक्ति जिसे सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद में प्रति 1-1-1962 में पूर्व वरिष्ठ लिपिक के रूप में अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था और जो —

(क) उक्त तारीख के पश्चात् पाल नहीं कर सचा, या (ख) उक्त तारीख के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्राधानित पराग सिद्ध निम्न के [ निश्चय 5 ]

(स) उवा परीक्षा म नहीं बठा,  
परिष्ठ लिखि के

परिष्कृत लिपि के रूप में स्थायी कर दिया गया। परन्तु यह तब जबकि वह त्रिभुज प्रापिकारी द्वारा इसके पश्चात् बनल एव वाच मापोजित एसी परीक्षा जा लगी गीति स और ऐसी भर्त्ता के सम्बन्धित रहते हुए भर्त्ता मन्वार द्वारा प्रविष्टित की जाय पास कर स । भर्त्ता की विधि बालावधि विशेष मन्वार के भर्त्ता के विधि के समान है ।

(5) भर्तों की किसी कालावधि विशेष म प्राणुलिपि - 50 प्रतिशत रिक्तियों की भरने के लिये सचिवालय के ऐसे कनिष्ठ/वरिष्ठ लिपिकों में से चयन द्वारा भर्तों की जायेगी जिन्होंने प्राणुलिपि के लिये दत्त निदेशों में सचयन, दत्त नियमों के भाग (5) में किसी बान के होते हुए उनके चयन के दिनांक से पदोन्नति समझा जावेगा। यदि किसी यप के अक्षयित मन्त्रा के एम अक्षयियों उपलब्ध न हों, तो वेपे रक्तिषा भाग (4) के अन्वय तथे के अनुसार प्रतियागी परीक्षा द्वारा सीधीभर्तों से भी भरी जावेगी।

(5 क)-वि-इन नियमों में कुछ भी नियुक्ति प्राधिकार का प्रावृत्तिविषय पर रक्तिको की उपलब्धता की सीमा में रहते हुए उन व्यक्तियों में स प्रविष्टायी नियुक्ति करने स प्रवारित नहीं करेगा, जो अत्यायी या तदय रूप म राजस्यान सचिवालय म 1-1976 की या हसत पहल प्राधुविषय का प पारित पर रह ये और जिनका काय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सनोपप्रद पाया गया हो और जो निम्नलिखित अहताओं में स कोइ ऐसी निांक की पूरी करते ये—

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित निांक की पूरी या उससे कम

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा या उससे समकक्ष घोषित महत्वायें उत्तीर्ण हा मय प्राशुनिधि एक प्रश्न पत्र के रूप में —या— (प्रागे पृष्ठ 113 पर )

एक 2 (9) DOP/B-1/75 5  
5-5-1975

6 वि स एक 2 (9) DOP/B-I/75 दि 18-8-1975 द्वारा प्रतिस्थापित  
एच दि 5-5-1970 से प्रभावी।  
7 वि स एक 3 (4) DOP/A-II/77 दि 18-8-1975 द्वारा प्रतिस्थापित  
वि स एक 3 (4) DOP/A-II/77 दि 18-8-1975 द्वारा प्रतिस्थापित

7 वि स एक 3 (4) DOP/A-II/77 दि 15-3-78 द्वारा प्रतिस्थापित  
बजाय प्रतिस्थापित एव 15-3-78 से प्रभावी ।  
8 वि स एक 3 (4) DOP/A II/77 दि 15-3-78 द्वारा 'प्रतियापी क  
प्रतिस्थापित, जो प्राये 15-3-78 से प्रभावी ।

8 वि स एक 3 (4) DOP/A II/77 दि 15-3-78 से प्रमावी ।  
प्रतिस्थापित, जो भागे पृष्ठ 111 112 पर दिया गया है

पुरान परतुस इस प्रकार थे—

(ब) 15-9-72 से 15-3-78 तक प्रभावशील—

कै[ 5 ब—कि इन नियमों में कुछ भी नियुक्ति प्राधिकारी की आशुलिपिक पद पर रक्तियों की उपलब्धता की सीमा में रहते हुए उन व्यक्तियों में से अधिष्ठायी नियुक्ति करने से प्रवारित नहीं करेगा, जो अस्थायी या तदर्थ रूप में राजस्थान सचिवालय में 5 5 1970 या 15-9 1972 को आशुलिपि या आशुटकन के पद धारित कर रहे थे और जिनका काय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सतोष प्रद पाया गया हो और जो निम्नलिखित अहतामो और अनुभवों में से कोई ऐसी दिनांक को धारण करते थे —

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय का स्नातक मय आशुलिपिक एक विषय के हो या आशुलिपि में डिप्लोमावारी हो या —

(ख) राजस्थान सेकेणरी शिक्षा बोर्ड से हायर सेकेण्डरी परीक्षा या उससे समतुल्य परीक्षा मय आशुलिपि एक विषय के रूप में उत्तीर्ण हो और आशुलिपिक या आशुटकन के रूप में, प्रतरालो ब्रूक्स को छोड़ते हुए यदि कोई हा दो वर्ष की सेवा कर चुका हो य

कै[ 5 ब—एक प्रश्न उठाया गया है कि एग व्यक्ति जो किसी मा यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण है और ऐसे बोर्ड या विश्व विद्यालय से आशुलिपि एग टकण परीक्षा अलग से राजस्थान सेकेण्डरी शिक्षा बोर्ड की हायर सेकेण्डरी में ऐच्छिक विषय के लिये विहित गति से अनधिक से उत्तीर्ण है उसे इस उपबंध के अधिन पाय समझा जावगा या नहीं ?

इस मामले की समीक्षा की गई और यह स्पष्ट किया जाता है कि—ऐसी योग्यता वाले या हायर सेकेण्डरी से उच्चतर (परीक्षा) मय आवश्यक आशुलिपि तथा टकण परीक्षा के, उत्तीर्ण व्यक्तियों को परतुक 5 क के उक्त खण्ड (ग) में वर्णित अहतामो (योग्यतामो) को पूरी करने वाले समझा जावेगा ।

(ग) प्रतरालो को छोड़कर, यदि कोई हो राजस्थान सचिवालय में 15-9-1972 को जिन आशुलिपिकों या आशुटकनों ने दो वर्षों की सेवा पूरी करली है और नियुक्ति प्राधिकारी ने उनके स्थापप्रद काय को प्रमाणित कर दिया है और जो अनुसूची II के भाग II में वर्णित प्रतियोगी परीक्षा भी अंग्रेजी आशुलिपि में या हिन्दी आशुलिपि में हिन्दी व अंग्रेजी की टकण-परीक्षा के अलावा उत्तीर्ण कर ली है ।]

उपरोक्त परतुक 5-क तथा 5-ख को विलोपित कर नया परतुक 5 क निविष्ट किया गया—वि स एक 2 (44) DOP/B-I/70 दि 13-12-1974, दि 15-9-1972 से प्रभावो। स्पष्टीकरण (क) वि स एक 12 (137) DOP/B-I/59 दि 7-3-1975 द्वारा निविष्ट।

(ख) 15-9-72 से पूछ के परतुक 5-क तथा 5-ख इस प्रकार थे—  
(1-क) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात्, प्राशुलिपिक या प्राशुटकर के पदों पर प्रथम भर्ती, रिक्तियाँ उपलब्ध होने के अग्र्यधीन रहते हुए उन व्यक्ति में से अधिष्ठायी रूप में की जायेगी जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को राजस्थान सचिवालय में स्थायी या तदनु रूप में प्राशुलिपिक या प्राशुटकर के पद धारण कर रहे हों एवं जिनका कार्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सतोपप्रद पाया जाय और उक्त तारीख को जिनके पास निम्नलिखित में से कोई भी ग्रहताएँ और अनुभव हों —

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का प्राशुलिपिक विषय सहित स्नातक हो या प्राशुलिपि में डिप्लोमाधारी हो या  
(ख) राजस्थान के उच्चतर माध्यमिक बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या इससे समतुल्य परीक्षा प्राशुलिपि विषय सहित पास किया हुआ हो और व्यवधानों को यदि कोई हो, शामिल न करते हुए प्राशुलिपिक या प्राशुटकर के रूप में 2 वर्ष की सेवा किया हुआ हो।

स्पष्टीकरण—इस परतुक के प्रयोजनाय ऐसा कोई व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व आयोजित स्नातक द्वितीय की या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में बैठे या किन्तु उक्त परीक्षा में उते उत्तीर्ण घोषित करने वाला उसका परिणाम उक्त प्रारम्भण के पश्चात् निकला है तो उसे इन नियमों के प्रारम्भ के पूर्व स्नातक द्वितीय की परीक्षा या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा यथास्थिति पास किया हुआ समझा जायगा।

[ 5-ग) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् प्राशुलिपिक के पदों पर द्वितीय भर्ती उन प्राशुलिपिकों और प्राशुटकरों में से की जाएगी जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को राजस्थान सचिवालय में अस्थायी या तदनु रूप में कार्य कर रहे हों और जिनकी ऐसे प्रारम्भ की तारीख को राजस्थान सचिवालय में उक्त रूप में दो वर्ष की सेवा व्यवधान को यदि कोई हो, शामिल करना

(ख) किसी मायता प्राप्त सेकेडरी शिप्मा बोर्ड से प्राशुलिपि एक विषय सहित हायर सेके डरी परीक्षा या हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन राज्य सस्थान या मापा विभाग या व्यवस्था व पद्धति द्वारा आयोजित प्राशुलिपि की परीक्षा या औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान द्वारा आयोजित डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो

टिप्पणी (क) 1968 के वर्ष से पूर्व प्राप्त किया गया मायता प्राप्त स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट/डिप्लोमा को हायर सेकेडरी बोर्ड सर्टिफिकेट के समतुल्य माना जावेगा और इस परन्तुक के खण्ड (ख) के अधीन वर्णित अहतायें पूरी करना माना जावेगा ।

(ख) हायर सेकेडरी परीक्षा से उच्चतर अहता, मय आवश्यक प्राशुलिपि एवं टकण परीक्षा के धारण करने वाले व्यक्ति भी इस परन्तुक के खण्ड (ख) के अधीन वर्णित अहतायें पूरी करने वाले माने जावेंगे ।

15 (ख)—किसी ऐसे व्यक्ति की, जो आपातकाल के दौरान सेना/वायुसेना/जलसेना में सम्मिलित होता है, भर्ती नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता और पुष्टीकरण आदि सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित किये गये आदेशों और निर्देशों के द्वारा विनियमित होंगे, परन्तु शत यह है कि—ये भारत सरकार द्वारा इस विषय में प्रसारित निर्देशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तन सहित, ही विनियमित हानी ।

10(6) 1-1-1976 से पूर्व प्राशुलिपिकों के रूप में अस्थायी तौर से नियुक्त व्यक्ति जो परन्तुक 5-क के अधीन आवृत नहीं हैं, नियमित रूप से नियुक्त

न करते हुए हो गयी हो तथा उक्त भर्ती निम्नलिखित शर्तों के अधधीन और निम्नलिखित रीति से की जायेगी —

(क) केवल वे ही प्राशुलिपिक या प्राशुटक पात्र होंगे जिनके लिए नियुक्ति प्राधिकारी ने यह प्रमाणित कर दिया है कि इन्होंने सतोषप्रद काम किया है और

(ख) उन्हें अंग्रेजी और हिन्दी टकण परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने के प्रस्तावा अनुसूची II के भाग II में उल्लिखित प्रतियोगी परीक्षा या तो अंग्रेजी प्राशुलिपि में अथवा हिन्दी प्राशुलिपि में उत्तीर्ण करनी होगी, न कि दोनों में ।]

9 वि स एफ 21 (12) नियुक्ति (ग)/55 भाग II दि 29 8 1973 द्वारा निविष्ट तथा दि 29-10-1963 से प्रभावी माने जावेंगे ।

10 वि स एफ 3 (4) DOP/A-II/77 दि 15 3-1978 द्वारा जोड़ा गया

अपरोक्त परतुक 5-ब तथा 5-ख को विलोपित कर नया परतुक 5 ब निविष्ट किया गया—वि स एफ 2 (44) DOP/B-1/70 दि 13-12-1974, दि 15-9-1972 से प्रभावी । स्पष्टीकरण (ख) वि स एफ 12 (137) DOP/B-1/59 दि 7-3-1975 द्वारा निविष्ट ।

(ख) 15-9-72 से पूर्व के परतुक 5-क तथा 5-ख इस प्रकार थे—  
(ग) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात्, प्राशुलिपिक या प्राशुटकक के पदों पर प्रथम भर्ती रिक्रितियाँ उपलब्ध होने के अन्तर्धान रहते हुए उन व्यक्तियों में से अधिष्ठायी रूप में की जायेगी जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को राजस्थान सचिवालय में स्थायी या तदर्थ रूप में प्राशुलिपिक या प्राशुटकक के पद धारण कर रहे हों एवं जिनका कार्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सतोषप्रद पाया जाय और उक्त तारीख को जिनके पास निम्नलिखित में से कोई भी प्रहताए और अनुभव हों —

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का प्राशुलिपिक विषय सहित स्नातक हो या प्राशुलिपि में डिप्लोमाधारी हो या  
(ख) राजस्थान के उच्चतर माध्यमिक बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या इसके समतुल्य परीक्षा प्राशुलिपि विषय सहित पास किया हुआ हो और व्यवधानों को यदि कोई हो शामिल न करते हुए प्राशुलिपिक या प्राशुटकक के रूप में 2 वर्ष की सेवा किया हुआ हो ।

स्पष्टीकरण—इस परतुक के प्रयोजनाय ऐसा कोई व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व आयोजित स्नातक डिग्री की या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में बैठा था किन्तु उक्त परीक्षा में उसे उत्तीर्ण घोषित करने वाला उसका परिणाम उक्त प्रारम्भण के पश्चात् निकला है तो उसे इन नियमों के प्रारम्भ के पूर्व स्नातक डिग्री की परीक्षा या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा यथास्थिति पास किया हुआ समझा जायगा ।

(5-ग) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् प्राशुलिपिकों के पदों पर द्वितीय भर्ती उन प्राशुलिपिकों और प्राशुटककों में से की जाएगी जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को राजस्थान सचिवालय में अस्थायी या तदर्थ रूप से कार्य कर रहे हों और जिनकी ऐसे प्रारम्भ की तारीख को राजस्थान सचिवालय में उक्त रूप में दो वर्ष की सेवा व्यवधान को यदि कोई हो शामिल नमश

(ख) किसी मायता प्राप्त सेवेन्दरी शिफा बोड स आगुलिफि एव विपय सहित हायर सेवेन्दरी उगीक्षा या हरिश्चन्द्र मायुर लोफ प्रशासन राज्य सस्थान या मापा विभाग या व्यवस्था व पद्धति द्वारा आयोजित आगुलिपि की परीक्षा या प्रोद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान द्वारा आयोजित डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो

टिप्पणी (क) 1968 के धप से पूव प्राप्त किया गया मायता प्राप्त स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट/डिप्लोमा की हायर सेकेन्दरी बोड सर्टिफिकेट के समतुल्य माना जावेगा और इस परन्तुफ के खण्ड (ख) के अधीन वलित ग्रहतायें पूरी करना माना जावेगा ।

(ख) हायर सेवेन्दरी परीक्षा से उच्चतर ग्रहता मय आवश्यक आगुलिपि एव टक्का परीक्षा के, धारण करने वाले व्यक्ति भी इस परन्तुफ के खण्ड (ख) के अधीन वलित ग्रहतायें पूरी करने वाले माने जावेगे ।

15 (क)—किसी ऐसे ध्याक्त की, जो आपातकाल के दौरान सेना/वायुसेना/जलसेना मे सम्मिलित होता है, भर्ती नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता और पुष्टीकरण प्राप्ति सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित किये गये आदेशों और निर्देशों के द्वारा विनियमित होगी, परन्तु शत यह है कि—ये भारत सरकार द्वारा इस विषय मे प्रसारित निर्देशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तन सहित, ही विनियमित होगी ।

10(6) 1-1-1976 से पूव आगुलिपिको के रूप मे अस्थायी तौर से नियुक्त व्यक्ति जो परन्तुफ 5-ब के अधीन आवृत नहीं हैं, नियमित रूप से नियुक्त

न करते हुए हो गयी हो तथा उक्त भर्ती निम्नलिखित शर्तों के अधीन और निम्नलिखित रीति से की जावेगी —

(क) केवल वे ही आगुलिपिक या आशुटकक पात्र होंगे जिनके लिए नियुक्ति प्राधिकारी ने यह प्रमाणित कर दिया हो कि इन्होंने सतोपप्रद काय किया है, और

(ख) उह अग्रजी और हिंदी टक्का परीक्षाए उत्तीर्ण करने के अलावा अनुसूची II के भाग II मे उल्लिखित प्रतियोगी परीक्षा या तो अग्रजी आगुलिपि मे अथवा हिंदी आगुलिपि मे उत्तीर्ण करनी होगी, न कि दोनों मे ।]

9 वि स एफ 21 (12) नियुक्ति (ग)/55 भाग II दि 29 8 1973 द्वारा निविष्ट तथा दि 29-10-1963 से प्रभावी माने जावेंगे ।

10 वि स एफ 3 (4) DOP/A II/77 दि 15 3-1978 द्वारा जोड़ा गया



प्राशुलिपिका के रूप में माने जावेंगे, (यह) रिक्तस्थानों के उपलब्ध होने पर तथा उनके द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी प्राशुलिपि में गति परीक्षा और टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, जो हायर सेकेण्डरी परीक्षा के लिये निर्धारित स्तर की होगी और सरकार द्वारा मायता प्राप्त सत्यान द्वारा आयोजित की जावेगी। गति परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये दो अवसर से अधिक नहीं दिये जावेंगे।

ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्त दोनों परीक्षाओं में इन नियमों के प्रवृत्त होने के बाद भाग नहीं लेते हैं या असफल हो जाते हैं, उनके प्रत्यावर्तन या सेवा समाप्ति, यथास्थिति, के दायी होंगे।

(7) विधि रचनाकारों/अनुवादकों के पद पर भर्ती अस्याई रूप से ऐसे व्यक्ति के पुनर्नियोजन द्वारा भी की जा सकती है जो विधिरचनाकार/अनुवादक सहायक मुख्य अनुवादक या वरिष्ठ विधिरचनाकार/मुख्य अनुवादक के रूप में सेवा निवृत्त हुआ हो,

(8) जहाँ सरकार कर्मचारियों के किसी समय में कोई पद किसी ऐसे व्यक्ति के स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने का विनिश्चय करती है जो सचिवालय में मित्र किसी विभाग में लिपिकवर्गीय पद धारण कर रहा है तो वह ऐसी बातों को आवश्यक समझी जाय, निहित कर सकेंगे जिनके अभ्यधीन रहते हुए ऐसा स्थानांतरण किया जा सके।

तथा 15-3-1978 से प्रभावशील। विद्यमान परतुक (6) से (9) को क्रमशः (7) से (10) पुनर्संख्याकित किया गया तथा विद्यमान परतुक (10) को विलोपित किया गया, जो कि स एफ 3 (7) DOP/A II/76 दि 30-2-1977 से जोड़ा गया था तथा इस प्रकार था—

[10 इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी वे व्यक्ति जो सचिवालय में प्राशुलिपिकों के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये थे और जिन्होंने अपना 1-10-76 को, अंतराला, यदि कोई हो, को छोड़कर, प्राशुलिपिक या प्राशुटंक के रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी करली है और परतुक 5-क के खण्ड (ग) के अधीन विहित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सतोषप्रद कार्य के लिये प्रमाणित कर दिये गये हैं, उनको परतुक 5-क के खण्ड (ग) के अधीन विहित परीक्षा उत्तीर्ण करने या इसके बाद एक और अवसर दिया जायेगा।

उन व्यक्तियों को जो उपरोक्त परीक्षा पास करने में असफल रहते हैं, निष्ट लिपिकों के रिक्त स्थानों के निरुद्ध नियुक्ति का प्रस्ताव किया जाय, यदि वे प्रकार नियुक्त होने के इच्छुक हों। यदि वे इस प्रकार नियुक्ति के लिये इच्छुक हों तो उनकी सेवायें समाप्त की जाने की दायी होगी।

(9) राजस्थान के महालेखाकार के कार्यालय के ऐसे अधिपक्ष व्यक्ति को जिसे 31-5-56 से पूर्व राजस्थान सचिवालय में अस्थायी रूप से सीधा वरिष्ठ लिपिक के पद पर भर्ती किया गया था, सचिवालय में ऐसे व्यक्ति की भर्ती से पहिले की तारीख से, सचिवालय में वरिष्ठ लिपिक के रूप में स्थानापन्न तौर से कार्य कर रहे व्यक्तियों की स्थायी पदों पर अधिष्ठायी नियुक्ति के पश्चात् होने, अधिस्थायी रूप से नियुक्त किया जायेगा।

(10) राजस्थान सचिवालय में वाणिज्यिक लेखा लिपिकों के रूप में सीधे भर्ती किये गये तथा उन पदों पर ऐसे पदों के लिए विहित लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत दिनांक 5-7-1958 को या उसके पश्चात् किंतु 10-10-1960 तक स्थायी किये गये व्यक्ति व 15) प्रति मास के विशेष वेतन के साथ, वाणिज्यिक लेखा लिपिक के पद नाम से, सचिवालय के वरिष्ठ लिपिक/लेखालिपिक के नियमित सबग में उनकी वरिष्ठता भी वाणिज्यिक लेखा लिपिक के रूप में उनकी अधिष्ठायी नियुक्ति के दिनांक के आधार पर नियत की जायेगी।

11(11) कि—जो व्यक्ति राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1956 के उपबन्धों के अनुसार टेलिफोन प्रचालक (ऑपरटर) के रूप में सीधे भर्ती किये गये थे और ऐसे पदों पर स्थायी (कनफर्म्ड) कर दिये गये थे, व टेलिफोन प्रचालक के रूप में उनकी नियुक्ति की दिनांक से कनिष्ठ लिपिकों के पद पर पर नियुक्त समझे जावेंगे और उनकी उचित वरिष्ठता उनको कनिष्ठ लिपिकों के सबग में [टेलिफोन प्रचालक के पद पर उनके स्थायीकरण के दिनांक के आधार पर समनुदेशित की जायेगी। ऐसे व्यक्तियों के वरिष्ठ लिपिक के पदों पर पदोन्नति के लिये विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन किये जाने पर पदोन्नति द्वारा वरिष्ठ लिपिक के पदों पर उस दिनांक से नियुक्त किया जावेगा जिसे दिनांक से वे अपनी कनिष्ठ लिपिक के सबग में वरिष्ठता के आधार पर उस रूप में नियुक्त किये जाते। इन नियमों में विहित अन्य शर्तों को पूरी करने के अन्वये ऐसे व्यक्ति वरिष्ठ लिपिकों के पदों पर उस दिनांक से स्थायी किये जाने के पात्र होंगे जिसको उनके दुरन्त कनिष्ठों के वरिष्ठ लिपिकों के रूप में स्थायी किया गया था। उनकी वरिष्ठ लिपिकों के सबग में उस दिनांक से वरिष्ठता दी जायेगी जिस दिनांक को उनके दुरन्त कनिष्ठ पदोन्नति से वरिष्ठ लिपिक नियुक्त किये गये और स्थायी किये गये थे।]

11 वि स एफ 3 (1) DOP/A II/78 दिनांक 28-1-1978 द्वारा जोड़ा गया।

12 वि स एफ 3 (1) DOP/A II/78 दि 17-5-1979 द्वारा संशोधित।

6 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये रिक्तियों का आरक्षण —

(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये रिक्तियों का आरक्षण सरकार के ऐसे आरक्षण सबधी आदेशों के अनुसार होगा जो भर्ती के समय प्रवृत्त हो भर्ती चाहे सीधी हो तथा पदोन्नति द्वारा हो,

(2) पदोन्नति के लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ <sup>12</sup>[केवल योग्यता] द्वारा भरी जायेंगी।

(3) "य प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने में उन पात्र अभ्यर्थियों के सबध में जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्य हैं नियुक्ति के लिये दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सूची में कौनसा रैंक है इस पर ध्यान न देते हुए आयोग के अधिनार क्षेत्र में आने वाले पदों के लिये आयोग द्वारा अग्र मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिये बनायी गयी सूची में जिस क्रम में उनके नाम हैं उसी क्रमानुसार तथा पदोन्नति के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, विचार किया जायेगा।

13(4) सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिये अलग से विहित रोस्टर तालि काओं के अनुसार उनका कठोरता से पालन करते हुए नियुक्तियाँ की जावेगी। किसी विशिष्ट वष में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों यथास्थिति म से पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उनके लिये इन प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ सामान्य क्रियाविधि के अनुसार भरती जायेंगी और परचाट् भर्ती (अगले) वष में अनिश्चित रिक्तियों आरक्षित की जायेंगी। ऐसी रिक्तियाँ जो इस प्रकार बिना भरी रहती हैं अगली भर्ती के वर्षों तक कुल योग में भाग से जायी जायेंगी और तत्पश्चात् ऐसे आरक्षण का अवसान (समाप्ति) हो जायेगा।

परंतु यह है कि—किसी सभा के किसी सचय के पदों या पदों के वग/धेशी/समूह में जिन में पदोन्नति इन नियमों के अधीन<sup>12</sup> [केवल योग्यता] के आधार पर की जाती है, रिक्तियों की भाग नहीं ले जाया जायेगा।

12 वि स प 7 (6) DOP/A II/75 III दिनांक 31 10 75 द्वारा शब्दावली "मेरिट कम सीनियारिटी" के स्थान पर प्रतिस्थापित

13 वि स प 7 (4) कार्मिक (क II) 73 दिनांक 10 2-1975 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—

(4) किसी वष विशेष में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों से पर्याप्त संख्या में पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो रिक्तियाँ भरी जायेंगी तथा प्रसामान्य क्रियाविधि के अनुसार भर ली जायेंगी।'

राजस्थान सरकार का आदेश सख्या एफ 7 (4) डी ओ पी/ए II/73  
दिनांक 3 9 1973

भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 के उपबन्धों के अनुसार राजस्थान सरकार यह निर्देश देती है कि निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में प्रत्येक प्रवर्ग के पदों पर योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के मामले में क्रमशः 10 और 5 प्रतिशत का आरक्षण किया जावेगा —

(1)(क) यदि किसी वर्ष में पदोन्नति से भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या 10 से कम हो तो उस वर्ष अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पदोन्नति के लिये कोई आरक्षण नहीं होगा।

(ख) यदि किसी वर्ष में पदोन्नति से भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या 20 से कम हो तो उस वर्ष में अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की पदोन्नति के लिये कोई आरक्षण नहीं होगा।

(2) इस प्रकार आरक्षित पदों पर पदोन्नति हेतु पात्र कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी —

(क) उसे संबंधित पद पर पदोन्नति के लिये विहित न्यूनतम महत्ता और अनुभव अवश्य प्राप्त हो।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया गया हो कि उसकी सत्यनिष्ठा सदेह से परे है तथा वह अथवा रुत से पदोन्नति के लिये उपयुक्त है।

(ग) उसके सेवा अभिलेख के सभी प्रकार से किये गये मूल्यांकन के आधार पर उसका सेवा अभिलेख अच्छा हो।

147 राष्ट्रीयता—सेवा में नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी के लिये आवश्यक है कि वह —

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या

(घ) तिब्बती शरणार्थी हो जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो, या

14 वि स प 7 (4) DOP/A II/76 दि 7 9 76 द्वारा प्रतिस्थापित —  
जो भगले पृष्ठ पर देखिये।

15[(ड) भारतीय उदभव का व्यक्ति हो, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और केनया, यूगाण्डा के पूर्वी अफ्रीकी देशों और तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (पहले टांगानिका और जंजीवार), जाम्बिया, मालवी जंग और यूथोपिया तथा विमतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो।]

परंतु यह है कि—प्रवर्ग (ख) (ग) (घ) और (ड) का अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसको भारत सरकार ने पत्रता प्रमाण पत्र दे दिया हो। एक अभ्यर्थी को जिसके मामले में पत्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा आयोजित परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकेगा और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र न्युनित ज्ञान के अध्वशीन अंतिम तौर पर नियुक्ति दी जा सकेगी।

‘7 राष्ट्रीयता —(1) सेवा में नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी के विदे आवश्यक है कि वह—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) लिक्किम का प्रजाजन हो या

(ग) भारतीय उदभव का व्यक्ति हो और पाकिस्तान से भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो

परंतु—

(1) उसे पत्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के अध्वशीन रहते हुए नेपाल के प्रजाजन या 14 मी ऐसा तिब्बती को भी जो 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो सेवा के किसी पद पर नियुक्त किया जा सकेगा,

(11) उपयुक्त (ग) प्रवर्ग से संबंधित कोई अभ्यर्थी हो तो वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसको भारत सरकार ने पत्रता प्रमाण पत्र दे दिया हो और यह पत्रता प्रमाण-पत्र उसकी नियुक्ति की तारीख से केवल एक वर्ष की कालावधि के लिये विधि माय होगा तत्पश्चात वह सेवा में भारत का नागरिक हो जाने पर ही रखा जायेगा।

(2) ऐसे अभ्यर्थी को जिसके लिये पत्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सवालित किसी परीक्षा में बैठने या साक्षात्कार में बुलाये जान कि अनुमति दी जा सकेगी और उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने के अध्वशीन रहते हुए अंतिम तौर पर नियुक्त किया जा सकेगा।

15 वि स एक 7 (5) DOP/A II/78 दिनांक 23-10-1978 द्वारा प्रतिस्थापित।

167-क इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, सेवा में भर्ती के लिये पात्रता संबंधी उपबंध जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आये हुए दूसरे देशों के एक व्यक्ति की राष्ट्रियता आगु सीमा, शुल्क या अन्य छूट से संबंधित हैं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित ऐसे आदेशों या निर्देशों से विनियमित होंगे, जो कि भारत सरकार द्वारा उस विषय में प्रसारित निर्देशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित होंगे ।

#### 178 रिक्तियों का अवधारण —

18[(1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए कनिष्ठ लिपिकों के प्रतिशत नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष में अगले बारह महीना के दौरान प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या और प्रत्येक तरीके से भर्ती किये जा सकने वाले व्यक्तियों की संख्या तय करेगा । ऐसी रिक्तियों की पिछली समाप्ति के बारह मास की समाप्ति के पहले ऐसी रिक्तियों को पुन तय किया जावेगा । कनिष्ठ लिपिकों के मामले में इन नियमों के नियम 22 के उप नियम (1) (ख) के उपबंधों के अनुसार आयोग सूचिया तैयार करेगा ।]

(2) सम्बंधित सेवा नियमों से सलग्न अनुसूची के कोष्ठक (3) में विहित प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक तरीके से भरी जा ने वाली वास्तविक संख्या की संख्या करने में, प्रत्येक नियुक्त प्राधिकारी एक यथोचित चक्रीय क्रम का अनुसरण करेगा जो प्रत्येक सेवा नियमों में वर्णित अनुपात के अनुसार पदोन्नति के कौटा की सीधी भर्ती के कोटे पर प्राथमिकता देते हुए होगा । जैसे—जहां सीधी भर्ती से और पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का प्रतिशत क्रमश 75 और 25 है, तो चक्रीय क्रम इस प्रकार होगा—

16 वि सं प 7 (5) DOP/A-II/76, दिनांक 20 6 1977 द्वारा निविष्ट ।

17 वि सं प 7 (1) DOP/A-II/73 दि 16 10 1973 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—

“8 रिक्तियों का अवधारण—इन नियमों के उपबंधों और सरकार के निर्देशों यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में यह प्रवधारित करेगा कि वर्ष के दौरान प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक तरीके से भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी ।”

18 वि सं प 3 (3) DOP/A II/76 दि 30 नवम्बर 1976 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1 पदोन्नति से, 2 सीधी भर्ती से, 3 सीधी भर्ती से, 4 सीधी भर्ती से, 5 पदोन्नति से, 6 सीधी भर्ती से, 7 सीधी भर्ती से, 8 सीधी भर्ती से, 9 पदोन्नति से और इसी प्रकार नमानुसार भागे ।

9 आयु सेवा में सीधी भर्ती का अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिये नियत अंतिम तारीख के ठीक पश्चात् होने वाली प्रथम अप्रैल की 18 वष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिये किन्तु 28 वष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिये

परन्तु—

- (i) महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्षों तक की छूट दी जायगी,
- (ii) भूतपूर्व सैनिक वमचारियों और रिजर्विष्ट अर्थात् प्रतिरक्षा सेवा में उन कम चारियों के मामले में जिन्हें रिजर्व में अन्तर्लिखित कर दिया गया हो अधिकतम आयु सीमा पचास वष होगी,
- (iii) अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जिसने दायमिन्ड में पूव सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी आधार पर सेवा की थी और जो नियमा का अधीन अधिका नियुक्ति का पात्र था ।
- (iv) उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो दोषसिद्धि से पूव अधिकतम आयु का नहीं था एक नियमा के अधीन नियुक्ति का पात्र था अधिकतम आयु सीमा में इतनी कालावधि तक की छूट दी जायगी जो भुक्त कारावास की अवधि के बराबर हो,
- (v) अथे या विकलांग व्यक्ति के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वष होगी,
- (vi) सरकार के अधीन किसी पद को अभ्यायी रूप से धारण करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा में ही समझा जायगा यदि वह आरम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में था चाहे उसने आयाग/नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष अंतिम रूप से उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार करली हो और यदि वह अपनी आरम्भिक नियुक्ति के समय उपरोक्त रूप से आयु सीमा में पात्र था तो उसे आयाग/नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के दो अवसर तक प्रदान किया जायेंगे,
- (vii) यह अनुज्ञा दी जायगी कि राष्ट्रीय केडेट फोर में केडेट प्रशिक्षक द्वारा की गयी सेवा की कालावधि उसकी वास्तविक आयु में से कम कर दी जायगी,
- (viii) यदि कोई अभ्यर्थी इन नियमों के आरम्भ होने के पश्चात् किसी भी वष जिसमें ऐसी परीक्षा नहीं हुई हो अपनी आयु के आधार पर परीक्षा में

बैठने का हकदार होता तो जहाँ तक आयु का सम्बन्ध है वह उस वय के ठीक बाद होने वाली भागामी परीक्षा में बैठने का हकदार समझा जायगा,

(ix) 15 10-69 से पूर्व किसी भी कालावधि में 25 वय की आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व तथा उसके पश्चात् किसी भी कालावधि में 28 वय की आयु प्राप्त करने से पूर्व, नियुक्त उन अभ्यर्थियों के लिए आयु सम्बन्धी कोई प्रतिवन्ध नहीं होगा जो राज्य के काय कलापो के सम्बन्ध में पहले से ही अधिष्ठायी या अस्थायी हैसियत से लगातार सेवा कर रहे हैं।

<sup>19</sup>(x) कि-जो पद आयोग के परिक्षेत्र में नहीं हैं उन पदों पर ऐसे व्यक्तियों के लिये जो राज्य सरकार की सेवा से रिक्त स्थानों के न होने से या पदों का समाप्त कर देने के कारण छूटनी कर दिये गये थे, अधिकतम आयुसीमा 35 वय होगी, यदि वे उस समय इन नियमों के अधीन विहित आयुसीमा के भीतर थे, जब कि उनको आरम्भ में उन पदों पर नियुक्त किया था जिनसे वे छूटनी किये गये। परन्तु यह है कि-अहता चरिन, शारीरिक स्वस्थता आदि की सामान्य विहित धारणें पूरी करली गई हो और वे किसी शिकायत या दोष के कारण छूटनी नहीं किये गये थे तथा वे अपने भूतपूर्व नियुक्ति प्राधिकारी से अच्छी सेवा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

<sup>20</sup>(xi) 1-3 63 को या इसके बाद बर्मा, श्रीलंका और केनिया, टागानिका युगांडा व जजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से लौटाये गये व्यक्तियों के लिये उपयुक्त उल्लिखित आयुसीमा 45 वय तक शिथिल की जावेगी और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के मामले में पाँच वय की छूट और दी जायेगी।

<sup>21</sup>(xii) पूर्वी अफ्रीकी देशों-केनिया, टागानिका, युगाण्डा और जजीबार से वापस लौटाये गये व्यक्तियों के मामले में कोई आयुसीमा नहीं होगी।

(xiii) निम्न क्त आपात कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निम्न क्त होने के बाद आयुसीमा के

19 वि सख्या प 5 (2) DOP A II/73 दिनांक 22 12 1973 द्वारा निविष्ट।

20 वि स एफ 1 (20) DOP/AII/67 दिनांक 13-12-1973 द्वारा निविष्ट एव दि 28-2-75 तक प्रभावी। वि समसत्यक दि 20 9-75 द्वारा प्रतिस्थापित एव दि 29 2 1977 तक प्रभावी।

21 वि समसत्यक दि 13 12 1974 द्वारा निविष्ट।

22 वि समसत्यक दि 20 9 1975 द्वारा निविष्ट।



भीतर माना जावेगा, ताहू वे प्रायोग के समय उपस्थित होने पर उन प्रायुमीमा को पार कर चुने हो, यदि वे सेना के कमीशन में प्रवेश क समय इसके लिये पात्र हाते ।

10 "लिपि" एवं तकनीकी गृहताए — अनुसूची I में निर्दिष्ट पदो पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थी म निम्नलिखित गृहताए होना आवश्यक है —

- (i) अनुसूची I के स्तम्भ 4 म दी गई गृहताए और दक्कागरी लिपि मे लिपित हिन्दी वा तथा राजस्थानी शैलियो म स किसी एक का यावहारिक ज्ञान और
- (ii) जहा आवश्यक हो गृहता परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा पास करना जसा कि अनुसूची II मे विहित है ।

11 चरित्र — सया म सीधी भर्ती के अभ्यर्थी वा चरित्र एमा होना चाहिये जो उसे सवा म नियोजन के लिय गृहित करे । उसको उस विश्वविद्यालय वा महाविद्यालय वा विद्यालय के प्रधान शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रप्त सच्चरित्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिये जिसम उसने अन्तिम बार शिक्षा पायी थी तथा साथ ही उने दो और सच्चरित्रता प्रमाण पत्र ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तिया के देने चाहिये जो उनके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय वा विद्यालय से संबंधित न हो और न उनके रिश्तेदार हो । ऐसे व्यक्तियो द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का तारीख से छ मास से पूर के लिये हुये नहीं होने चाहिये ।

#### टिप्पण

(1) "यायालय द्वारा दोषसिद्धि मात्र को सच्चरित्रता प्रमाण-पत्र न दिये जाने का आघार नही माना जाना चाहिये । दोषसिद्धि की परिस्थितियो पर विचार किया जाना चाहिये और यदि उनमे नैतिक अधमता साथी कोई बात अन्तर्ग्रस्त नहीं है या उनका सबब हिंसात्मक अपराध या ऐसे आदोलो से नहीं है जिनका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार की हिंसात्मक तरीको से उलटना हो तो केवल दोषसिद्धि को निरहता नहीं समझा जाना चाहिये ।

(2) ऐसे भूतपूर्व कदियो के साथ जिन्होने कारावास म अपने अनुशासित जीवन से और बाद के सदाचरण से अपने आपको पूरतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो सेवा मे नियोजन के प्रयोजनार्थ इस आघार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिये कि वे पहले सिद्धदोष हो चुके हैं । उन व्यक्तियो को जिह ऐसे अपराधो के लिए सिद्ध दोष किया गया है जिनम नैतिक अधमता या हिंसा की कोई बात अन्तर्ग्रस्त नहीं है, पूरतया सुधरा हुआ मान लिया जायगा यदि वे पश्चातवर्ती देखरेख देखरेख के अधीन की या यदि किसी जिले विद्यो में ऐसे पश्चातवर्ती देखरेख

ह नहीं है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की इस आशय की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(3) उन भूतपूर्व कैदियों में जिन्हें ऐसे अपराधों के लिये सिद्धापा किया गया है जो नतिक अधमता या हिंसा से संबंधित हैं पश्चात्तवर्ती दखरेख उन्हें के अधीक्षक का इस आशय का एक प्रमाण पत्र जो कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चात्तवर्ती दखरेख शुरू में अपने बाद के सदाचार से यह साबित कर दिया है कि वे अब पूर्णतः सुधर गये हैं अतः वे नियोजन के लिये उपयुक्त हैं।

12 शारीरिक योग्यता — सेवा में सीधी भर्ती या अभ्यर्थी मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये और उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा मानसिक एवं शारीरिक नुबस नहीं होना चाहिये जो उसके सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधक हो और यदि वह चुन लिया जाय तो उसे सरकार द्वारा तत्प्रयोजनाय अभिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी पदानुक्ति के नियमिन क्रम में पेशेवर अभ्यर्थी के मामले में या यदि अभ्यर्थी राज्य के काय कलाप के अवयव में पहले से ही सेवारत है और पूर्व नियुक्ति के लिये उसकी चिकित्सा परीक्षा पहले ही की जा चुकी है, इस दशा में और उसके द्वारा धारित तथा धारित किया जान वाला (दोनों) पेशे की चिकित्सा परीक्षा का आवश्यक मानमान 75 परसेन्ट या उससे अधिक पूर्णतः पालन करने के लिये तुलनात्मक दृष्टि से एक समान हो और तत्प्रयोजनार्थ आशु के कारण भी उसकी काय दक्षता में कोई कमी न आती है तो उत्तम प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से उसे अभियुक्ति प्रदान कर सकेगा।

13 अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग — ऐसा अभ्यर्थी जिस नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतिरूपण करने का अवकाश गृह हुआ अथवा जिसको विगाह दिया गया है प्रस्तुत करने का या ऐसे व्योरे प्रस्तुत करने का जो गलत या मिथ्या है अथवा महत्वपूर्ण सूचना दबाने का अथवा परीक्षा या साक्षात्कार में गलती का साधन का प्रयोग करने का या उनके प्रयोग का प्रयास करने का अथवा परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश पान के निमित्त किसी अन्य अनियमित या अनुचित माध्यम का प्रयोग करने का दावा किया गया है तो जोरदार मुकदमा चलाया जाना आवश्यक होगा अतः अनियमित उस सरकार के अधीन है जो पर नियुक्ति के लिये स्थायी तौर पर या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये नियुक्ति का दावा करता है।

'124 ] राजस्थान सचिवालय लिखित वर्गीय सेवा नियम [ नियम 14-16

14 पक्ष समयन- इन नियमों के अधीन अपक्षित बातों को छोड़कर भर्ती के लिये अन्य किसी भी प्रकार की सिफारिश पर, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पत्र में समयन प्राप्त न हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से किये गये प्रयत्न का कार. उसे भर्ती के लिए निरहित किया जा सकेगा।

15 नियुक्ति के लिये निरहता —(1) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार, अपना समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं किसी अभ्यर्थी को इस नियम के उस पर लागू होने से छूट न दें।

(2) कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसका विवाह उस व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से ही कोई जीवित पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार अपना समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार हैं किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के उस पर लागू होने से छूट न दें।

23 3) विलोपित

24 (4) कोई विवाहित अभ्यर्थी जिसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। स्पष्टीकरण — इस नियम के प्रयोजनात् दहेज शब्द का वही समान अर्थ होगा, जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 (केन्द्रीय अधिनियम 28, 1961) में दिया गया है।

भाग IV-सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16 आयोग द्वारा परीक्षा — 20 [कनिष्ठ लिपिकों, आधुनिक लिपिकों और विधि रचनाकारों/अनुवादकों] के पदों पर भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा अनुसूची II में के पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिये विहित पाठ्य विवरण के अनुसार ऐसे अन्तरालों पर जो नियुक्ति प्राधिकारी आयोग के परामर्श से समय समय पर अवधारित करे, आयोजित की जायेगी जब तक कि सरकार आयोग के परामर्श के किसी रूप विशेष

23 वि स प 7 (3) कामिक (क 2) 76 दि 15-2 1977 द्वारा विलोपित (यह परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रतिबंध था।)

24 वि स एफ 15 (9) कामिक (क-2) 74 दि 5 1-1977 द्वारा निविष्ट।

25 वि स एफ 2 (45) DOP/B-1/74 दिनांक 7 11 1975 द्वारा आधुनिक लिपिकों विधि रचनाकार/अनुवादकों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

में परीक्षा में न लेने का विनिश्चय न कर ले । पाठ्य विवरण सरकार द्वारा जैसा कि वह उपयुक्त समझे आयोग के परामर्श से समय समय पर सन्शोधित किया जा सकेगा ।

<sup>26</sup>परन्तु यह है कि—आगुलिपिकों तथा वरिष्ठ आगुलिपिकों के पदों के लिये इन नियमों के अधीन विहित प्रहता-परीक्षा प्रत्येक छ मास से ऐसे स्थानों पर आयोजित होगी, जो आयोग तय करे ।

<sup>27</sup>परन्तु यह है कि राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1957 के उपबन्धों के अधीन कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त स्थानों के लिये आयोग समुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर मकेगा ।<sup>28</sup> [एक अभ्यर्थी सचिवालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों दोनों के लिये रिक्त स्थानों के लिये आवेदन करने का हक्दार हागा, जिसके लिये केवल एक आवेदन पत्र कनिष्ठलिपिक समुक्त प्रतियोगी परीक्षा हस्तु होगा और अभ्यर्थी को अपनी इच्छा की सेवा का आवेदन पत्र में कनिष्ठ लिपिक (सचिवालय) या कनिष्ठ लिपिक (अधीनस्थ कार्यालय) उल्लेख करना होगा । ऐसी समुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिये अभ्यर्थी द्वारा केवल एक परीक्षा शुल्क देय होगा] आयोग राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा के लिये आवेदन करने वालों के लिये नियम 22 (1) (ख) के अनुसार तथा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्थापना नियम 1957 के नियम 24 के अनुसार उक्त सेवा के लिये आवेदन करने वालों के मामले में सफल अभ्यर्थियों की सूची तयार करेगा ।

<sup>29</sup>[विलोपित]

<sup>30</sup>16-क-वरिष्ठ आगुलिपिकों की परीक्षा में प्रवेश हेतु धारता—

<sup>31</sup>[वरिष्ठ आगुलिपिकों के पदों के 50 प्रतिशत के विरुद्ध जो व्यक्ति]

- 26 वि स एफ 3 (4) DOP/A-II/77 दिनांक 15 3 78 द्वारा जोड़ा गया ।
- 27 वि स प 3 (3) DOP/A-II/76 दिनांक 30 11 1976 द्वारा निविष्ट ।
- 28 वि समसूचक दिनांक 29 10 1977 द्वारा प्रतिस्थापित ।
- 29 वि स एफ 11 (6) DOP/A-II/76 दिनांक 16 11 1978 द्वारा विलोपित ।
- 30 वि स प 3 (19) वामिक/क-2/73 दिनांक 5-3 1976 से निविष्ट एवं दिनांक 18 3 1976 से प्रभावी ।
- 31 वि सख्या प 3 (4) वामिक/क-2/73 दिनांक 15 3 78 द्वारा प्रतिस्थापित ।

राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम [ नियम 17 ]  
निम्नलिखित शर्तों को पूरी करत हैं, वे वरिष्ठ आशुलिपिक की भायोग द्वारा प्राप्ति  
जित परीक्षा में बैठने के लिये पात्र होंगे—

- (1) आशुलिपिक के सवग में अधिष्ठायी हो, या—
- (ii) इन नियमों के नियम 5 के परतुक (5-क) के अधीन अधिष्ठायी नियुक्ति के लिये पात्र हो, या—
- (iii) भायोग द्वारा आयोजित सचिवालय आशुलिपिकों की [अहता परीक्षा] में उत्तीर्ण हो और तदय/अर्जेंट अस्थायी रूप से नियम 28 के अधीन के अलावा कम से कम दा वष की अवधि के लिये आशुलिपिक के रूप में कार्य कर चुका हो।

टिप्पणी—इस सशोधन के प्रवृत्त होने के तुरत बाद भायोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ आशुलिपिकों की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकने वाले व्यक्ति अक्टूबर 1975 के माह में आयोजित वरिष्ठ-आशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण किये हुये माने जायेंगे।

32]7 आवदन पत्र आमंत्रित करना --सेवा के पदों पर सीधी भर्ती के लिये आयुक्त द्वारा उन रिक्त पदों को जिन पर भर्ती की जानी है, राजपत्र में प्रकाशित कर ऐसे तरीका से जैसा भायोग द्वारा उचित समझा जाय, निर्दिष्ट किया जायगा और उनक लिय आवदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।

33]रतु भायोग या नियुक्ति प्राधिकारी यथास्थिति विज्ञापित पत्रों की रित्तिया का 34]00 प्रतिशत तब कनिष्ठ लिपिकों के मामले में और 50 प्रतिशत तक अन्य मामलों में प्रतियोगी परीक्षा में भरी गयी (रित्तिया) के अतिरिक्त उपयुक्त अभ्यर्थियों के नामों की सूची सुरक्षित सूची पर रख सकेंगे। मागपत्र पर, ऐसे अभ्यर्थियों के नाम मरिट के क्रम में भायोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी का मूल सूची संप्रतिष्ठ करने की दिनांक से छ माह के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी का मर्म शक्ति किये जा सकेंगे।

(2) इन नियमों के उपबन्धों के अधधीन रहत हुए भायोग नाटित से सा या ऐसे अन्य तरीके से जो वह उचित समझे, अभ्यर्थियों के माग पत्रों के लिए ऐव

32 वि सख्या प 6 (1) DOP B-1/70 दिनांक 22.5.1973 द्वारा प्रतिस्थापित।

33 वि सख्या 1 (27) नियुक्ति (क-II) 69-1 दिनांक 13.12.1973 द्वारा प्रतिस्थापित।

34 वि सख्या प 2 (45) DOP/B-1/70 दिनांक 7.1.1975 द्वारा प्रतिस्थापित।

अनुदेश जारी कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे तथा जिनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित बातों के बारे में भी जानकारी हो —

- (i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या बताते हुए सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या
- (ii) परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख एवं उसे प्रस्तुत करने का तरीका,
- (iii) अपेक्षित अर्हताएँ और अभ्यर्थियों द्वारा इन अर्हताओं को सिद्ध करने का तरीका,
- (iv) परीक्षा की तारीख और स्थान,
- (v) परीक्षा का पाठ्य विवरण ।

18 परीक्षा में प्रवेश —जब तक की अभ्यर्थी के पास उस परीक्षा में प्रवेश हेतु आयोग द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र न हो तब तक उसकी परीक्षा में प्रवेश नहीं किया जायेगा । ऐसा प्रमाण पत्र प्रदान करने से पूर्व आयोग प्रत्येक मामले में अपना समाधान करेगा कि आवेदन संवधा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किया गया है ।

परंतु आयोग अपने स्वविवेक से ऐसी किसी सदभावित भूल को जो विहित प्रारूप को भरते समय या आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में हो गयी हो, सुधारने की अनुमति दे सकेगा अथवा ऐसा प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्रों को जो आवेदन पत्र के साथ नहीं भेजे गये हैं परीक्षा प्रारम्भ होने से पर्याप्त समय पूर्व भेजे जाने की अनुमति दे सकेगा ।

35/19 आवेदन का प्रारूप —आवेदन, आयोग द्वारा अनुमोदित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा । प्रारूप ऐसी फीस देकर जो समय समय पर आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाय यथा स्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी या आयोग के सचिव से प्राप्त किया जा सकेगा ।

20 परीक्षा फीस —सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी या आयोग द्वारा नियत फीस अदा करेगा ।

20-क फीस वापिस लौटाना —परीक्षा फीस वापिस लौटाने के लिये कोई दावा प्रहण नहीं किया जायेगा और न ही फीस किसी अन्य परीक्षा के लिये आरक्षण की जायेगी जब तक कि अभ्यर्थी को उस परीक्षा में यथास्थिति, यदि नियुक्ति प्राधि

कारी या भ्राम्योग द्वारा प्रवेश होन दिया गया हो। प्रवेश न दिये जान की सूत में फीस लोटाने से पूव ऐसी राशि की, जो नियुक्ति प्राधिकारी, या भ्राम्योग यथास्थिति, द्वारा नियत की जाय, बटौती कर ली जायेगी।

21 भ्राम्येदन पत्रों की समीक्षा —यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी या भ्राम्योग उसको प्राप्त भ्राम्येदन पत्रों की समीक्षा करगा और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिये इतने अहित अभ्यासियों से, जितने उस याछनीय प्रतीत हो, अपने समक्ष परीक्षा/साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा।

### 22 नियुक्त प्राधिकारी। भ्राम्योग की। सकारिण

(1) भ्राम्योग कनिष्ठ लिपिकों के पद के लिये कनिष्ठ लिपिक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम अहता अंक प्राप्त करन के अनुसार सफल घोषित अभ्यासियों की योग्यता सूची निम्न प्रकार से बनायेगा—

(क) साधारण सूची क' कुल का 60 प्रतिशत और अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यासियों की,

(ख) साधारण सूची 'ख'—कुल 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यासियों की,

(ग) आरक्षित सूची—अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यासियों की अलग से।

परंतु यह है कि—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यासियों के लिये इन नियमों में विहित टकण परीक्षा में अहतांक का प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होगा, परंतु टकण परीक्षा में प्राप्त अंकों को कुल प्राप्तांका में जोड़ा जावेगा।

(ii) साधारण सूचिया में उन अभ्यासियों को भी सम्मिलित किया जावेगा जिन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाय गये किन्हीं नियमों के अधीन उनके लिये आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती चाही है।

(iii) अभ्यासियों के नाम सम्बद्ध सूचियों में उनके द्वारा परीक्षा में प्राप्त किये गए कुल अंकों के क्रम में व्यवस्थित किये जावेगे

(iv) साधारण सूची क' तथा साधारण सूची ख 24 माहों के लिए और आरक्षित सूची परीक्षा के परिणाम की घोषणा की दिनांक के बाद के अगले 37 माहों के लिये लागू रहेगी। पूर्ववर्ती वष की साधारण सूची क' चालू वष की साधारण सूची ख' पर केवल तभी विचार किया जावेगा, जब चालू वष की साधारण सूची क' और साधारण सूची 'ख' समाप्त हो जायेगी।

परन्तु--

- (1) उन व्यक्तियों के नाम, जिन्होंने जूनियर डिप्लोमा कोर्स पास कर लिया है, उपर्युक्त नियम के अधीन तैयार की गयी सूची में सबसे ऊपर रखे जायेंगे, उनके नाम उक्त परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर क्रमांकित किये जायेंगे।
- (11) कनिष्ठ लिपिक के पदों पर की जाने वाली नियुक्ति के मामले में केवल ऐसे अभ्यर्थियों को ही निर्दिष्ट सूची में सर्वांगित किया जायेगा, जिन्होंने नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित परीक्षा हिंदी टंकण में 20 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से या अंग्रेजी टंकण में 26 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से पास करली हो।

<sup>37</sup>(2) अनुसूची I के ग्रुप 'ख' के अधीन विधि रचनाकार/अनुवादक के पदों के लिये आयोग अभ्यर्थियों की अपनी प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये कुल अंकों से प्रकट प्रवीणता के क्रम में एक सूची तैयार करेगा और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अर्पित करेगा। जहाँ दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्त अंक कुल मिलाकर बराबर हों तो आयोग उक्त पदों के विशेष खण्ड के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा

<sup>38</sup>परन्तु यह है कि आयोग--

- (1) कनिष्ठ लिपिकों की परीक्षा में जो अभ्यर्थी कम से कम 35% अंक प्रत्येक अनिवार्य तथा ऐच्छिक प्रश्नपत्र में प्राप्त करने में असफल रहता है, उसके नाम की सिफारिश नहीं करेगा,
- (11) [××विलोपित×× दि 15 3 1978 से]
- (111) विधि रचनाकार/अनुवादक परीक्षा में जो अभ्यर्थी कम से कम 35% अंक प्रत्येक प्रश्न पत्र में और कम से कम कुल अंकों में 50% अंक प्राप्त करने में असफलता रहता है, उसके नाम की सिफारिश नहीं करेगा,

परन्तु यह है कि--आयोग प्रत्येक अनिवार्य प्रश्न पत्र में एक तक और कुल योग में तीन तक कृपाक दे सकेगा, ताकि वह अभ्यर्थी परीक्षा में अहता प्राप्त कर सके, जो कि अगला उक्त परीक्षा में अहता प्राप्त नहीं करता।

37 वि स एफ 3 (4) DOP/A II/77 दि 15 3 78 द्वारा शब्दावली 'भोर ग्रुप 'ग' के अधीन आधुनिक लिपिक के पदों के लिये" विलोपित।

38 वि स प 3 (3) DOP/A II/75 दिनांक 30-11-1976 द्वारा प्रति-स्थापित।



33(2-क)(1) आधुनिक के चयन व नियुक्ति व निये तरीका—आयोग आधुनिक की अहता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की सूचियाँ आधुनिकों तथा वरिष्ठ आधुनिकों के पदों के लिये तैयार करेगा। ऐसी सूचियाँ आयोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेंगी।

परन्तु यह है कि—आधुनिक अहता परीक्षा में आधुनिक तथा टक्का व प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 35% तथा कुल में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहने वाले अभ्यर्थी को आयोग त्रिकारित नहीं करेगा और वरिष्ठ आधुनिक अहता परीक्षा में कम से कम 40% अंक प्राप्त करने में असफल रहने वाले अभ्यर्थी को आयोग त्रिकारित नहीं करेगा।

परन्तु आगे यह भी है कि—आयोग प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक तक अधिकतम से तीन तक प्रश्नों की आधुनिक परीक्षा में अहता प्राप्त के लिये दे सकेगा जो कि अभ्यर्थी को आधुनिक परीक्षा में अहता प्राप्त नहीं करता।

(2) उपनियम (1) के अधीन आयोग द्वारा तैयार की गई सूचियाँ को की अधिक के लिये प्रभावी रहेंगी।

(3) आधुनिक के पदों के लिए सूची, उपलब्ध रिक्तियों की याद रिक्तियों की जिनके उपलब्ध होने की सम्भावना है, सत्या के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त सूची II में विहित पाठ्य विवरण के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों से प्रकट योग्यता के क्रम में तैयार की जायेंगी और वरिष्ठ आधुनिकों के पदों के लिये उन समस्त व्यक्तियों की सूची तैयार की जायेंगी जिन्होंने अनुसूची II में विहित पाठ्य विवरण के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में अहता प्राप्त कर ली हो। दोनों सूचियाँ नियुक्ति प्राधिकारी को संप्रति की जायेंगी।

(4) [विलोपित दिनांक 15 3 78 से]

23 सेवा में नियुक्ति —(1) नियम 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 40 सिवाय आधुनिकों के पदों के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी नियम 22 के अधीन तैयार की गयी सूची में से योग्यता क्रम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त करेगा बशर्त कि ऐसी जाँच जो आवश्यक समझी जाय, करने के पश्चात् उसका समाधान हो जाय कि ऐसे अभ्यर्थी ऐसी नियुक्ति के लिये अथवा सब प्रकार से उपयुक्त है।

40 परन्तु यह है कि—नियम 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति

39 वि स प 3 (4) DOP/A II 77 दिनांक 15 3 1978 द्वारा जोड़ा गया तथा उपनियम (4) विलोपित किया गया।

40 वि स प 3 (4) DOP/A-II-77 दि 15 3 78 से जोड़ा गया

प्राधिकारी नियम 22 के उपनियम (2-A) के अधीन नौयार सूची में से ग्रासुलिपिको के पदो पर अभ्यर्थियो को नियुक्त करेगा बशर्ते कि जैसी उचित समझे वंसी जाच के बाद उसका यह समाधान हो जाय कि- ऐसे अभ्यर्थी ऐसी नियुक्ति के लिये अय समस्त प्रकार से उपयुक्त हैं।

(2) नियम 7 में किसी बात के होते हुये भी 31-3 1973 तक कनिष्ठ लिपिको के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्ति, जो ऐसे पदो या उच्चतर पदो को निरंतर धारण करते आ रहे हो नियमित रूप से अस्थाई आधार पर नियुक्त हुए समझे जायेंगे, परंतु यह तब जब कि वे नियमो में विहित अय शर्तें पूरी करते हो। ऐसे व्यक्ति, स्थायी रिक्तिया होने पर तथा उनका काय सतोपप्रद पाया जाने पर उनकी अस्थायी नियुक्ति की तारीख के अनुसार कनिष्ठ लिपिक के रूप में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किये जाने के पात्र होंगे

परंतु अस्थायी रूप से कनिष्ठ लिपिक के रूप में काय करने वाला कोई व्यक्ति जिसका कार्य सतोपप्रद न पाया जाय, सेवा से निम्न तरीके से हटाया जा सकेगा

- (i) यदि उसने राज्य के काय कलाप के सबब में, अस्थायी तौर पर 3 वष से कम सेवा की हो तो उसे एक मास का नोटिस देवर, और
- (ii) यदि उसने 3 वष से अधिक की सेवा की है तो राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 में अधि विहित प्रक्रिया का अनुसरण करके 31-3-1973 के पश्चात् कनिष्ठ लिपिक के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त समस्त व्यक्तियों से नियमो में यथा विहित प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा नियमित भर्ती प्राप्न करने की अपेक्षा की जायेगी।

41(3) नियम 5 में किसी बात के होते हुए समस्त व्यक्ति जो 1-4-1973 को या उसके बाद किन्तु 1-8-1977 के पहले तदर्थ आधार पर कनिष्ठ लिपिको के रूप में काय कर रहे और जो आयोग द्वारा 1976 में उक्त पदा पर नियमित भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठ सके या उत्तीर्ण नहीं हा सके, उनकी उक्त पदा पर नियुक्ति के लिये सफल अभ्यर्थियों के उपलब्ध हो जाने पर अधीनस्थ कार्यालयो में रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर कनिष्ठ लिपिको के पदो पर समायोजित किया जायेगा। 42[अनुसूची II के भाग (5) में विहित पाठ्यक्रम के अनुसार गृहता

41 वि स प 5 (8) DPP/A II/77 दि 28-1-1978 द्वारा जोड़ा गया।

42 वि समसूचक दि 5-10-78 द्वारा प्रतिस्थापित।

132 ] राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम (नियम 24-25)  
 परीक्षा] उत्तीर्ण करने के लिये उनको तीन अवसर दिये जायेंगे, यद्यपि उन्होंने इन  
 नियमों में विहित अधिकतम आयुसीमा पार कर ली हो।

### भाग V—पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

24 चयन की कसौटी — अनुसूची I के स्तम्भ 5 में प्रगणित पद  
 धारक यदि वे अनुसूची I के स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट यूनतम अहतायें एवं अनु-  
 43 [नियम 25 26 या 26-क के अधीन चयन की दिनांक के पहले की पहा  
 अग्रल को] रखते हो तो स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे  
 44 [X×विलोपित×]

45 स्पष्टीकरण—किसी विशिष्ट वष में पदोन्नति के लिये नियमित चयन के  
 पहले किसी मामले में एक पद पर सीधी भर्ती कर ली गई हो, तो ऐसे व्यक्ति जो  
 उस पद पर नियुक्ति के लिये भर्ती के दोनों तरीकों से पात्र हैं या थे और पहले सीधी  
 भर्ती से नियुक्त कर लिये गये पदोन्नति के लिये उन पर भी विचार किया जावेगा।

24-क किसी अधिकारी की पदोन्नति के लिये तब तक विचार नहीं किया  
 जायेगा जब तक कि वह ठीक नीचे के पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त तथा स्-  
 न हो। यदि कोई अधिकारी जो ठीक निचले पद पर अधिष्ठायी है, पदोन्नति  
 लिये पात्र नहीं है तो उन अधिकारियों के बारे में जो भर्ती के तरीकों में से किसी ए-  
 1 लिये पात्र नहीं है तो उन अधिकारियों के अनुसार या भारत के सचिवालय के अनुच्छेद 309 के परतुक्त के प्रथम  
 प्रख्यापित वि-ही सेवा नियमों के अधीन चयन के पश्चात् ऐसे पद पर स्थानापन्न आधार पर  
 में नियुक्त किये गये हो, केवल उसी वरिष्ठता के क्रम में स्थानापन्न आधार पर  
 पदोन्नति हेतु विचार किया जा सकता जिसमें वे तब होते जब कि वे उक्त नीचे के  
 पद पर अधिष्ठायी होते।

25 चयन की प्रक्रिया — (1) ज्योंही यह विनिश्चित हो जाय कि वष के  
 दौरान अमुक सरवा में पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, नियुक्ति प्राधिकारी एक सूची  
 तैयार करेगा जिसमें सेवा के ऐसे सदस्यों के नाम होंगे जो अनुसूची I के प्रत्येक  
 प्रवर्ग में सम्मिलित ठीक नीचे की श्रेष्ठ के स्वरूप वाले पद धारण करते हो। सूची  
 में रिक्तियों की संख्या के पांच गुने तक व्यक्तियों के नाम होंगे और उसके नाम

43 वि, स एफ 2 (45) DOP/B-I/70 दिनांक 7-11-75 द्वारा  
 जोड़ा गया।

44 वि स एफ 3 (19) DGP/A-II/73 दि 5-3-1976 द्वारा  
 दि 18-3-1976 से विलोपित

45, वि स एफ 7 (1) DOP/A-II/75 दिनांक 20-9-75 द्वारा  
 जोड़ा गया।

वरिष्ठता क्रम में रखे जायेंगे ।

(2) एक समिति, जिसमें नियुक्ति (ख) विभाग के शासन दिशिष्ट सचिव और शासन मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत अथवा दो शासन उप सचिव होंगे सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी तथा उनमें से ऐसे व्यक्तियों से साक्षात्कार करेगी जिनसे वह साक्षात्कार करना आवश्यक समझे और विहित प्रक्रिया के अनुसार एक सूची तैयार करेगी जिसमें उक्त पदों की सहाय के बराबर जैसा कि उप नियम (1) में उपदिष्ट है, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम होंगे ।

(3) उपयुक्त मानकर चयन किये गये अभ्यर्थियों के नाम वरिष्ठता क्रम में रखे जायेंगे ।

(4) [विलोपित दि 30 4 76 से]

(5) अनुभाग अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के लिये समिति द्वारा तैयार की गयी सूची शासन मुख्य सचिव को और अन्य पदों के सम्बन्ध में समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियां नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेंगी और उन सूचियों में सम्मिलित अभ्यर्थियों की तथा अधिकृत व्यक्तियों, यदि कोई हो, की गायनीय पत्रियां तथा वैयक्तिक फाइलें भेजी जायेंगी ।

(6) (7) विलोपित दि 1-1-75 से]

26 सेवा में सर्वोच्च कनिष्ठ, वरिष्ठ तथा अन्य पदों पर पदोन्नति के लिये लक्षोपित मापदण्ड, पात्रता तथा तरीका—

[क्षेत्रम्पादकीय टिप्पणी—यह नियम 26 'राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1957' के नियम 26-घ में मध्य पुराने नियमों के दिया जा चुका है, कृपया देखने का श्रम करें तथा क्षमा करें]

### भाग-VI नियुक्ति, परीक्षा और स्थाईकरण आदि

27 सेवा में नियुक्ति—इन नियमों से सलग्न अनुसूची में वर्णित सेवा के पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति नियम 8 के अधीन तय की गई रिक्तियों के होने पर नियम 25 तथा 26, यथास्थिति के अधीन चयनित व्यक्तियों में से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जावेगी ।

28 अर्जेंट अस्थाई नियुक्तियां—

[क्षेत्रम्पादकीय टिप्पणी—यह नियम 28 अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमों में नियम 26 (3) के रूप में अविबल दिया गया है, कृपया वही देखने का श्रम करें तथा क्षमा करें]

40 28-क आशुलिपिक के पद पर अर्जेंट अस्थाई नियुक्तियों पर प्रति  
बन्ध—राजस्थान सचिवालय में आशुलिपिकों के सर्वग में अर्जेंट अस्थाई नियुक्ति  
इसके बाद नहीं की जायेगी ।

29 बरिष्ठता --सब में पदों के प्रत्येक वर्ग में बरिष्ठता उस सेवा के पदों  
के किसी वर्ग में अधिष्ठायी नियुक्ति के आदेश की तारीख से अवधारित की  
जायेगी --

परन्तु --

- (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पहले ही पदों के किसी वर्ग विशेष में नियुक्त  
व्यक्तियों की पारस्परिक बरिष्ठता वह होगी जो इन नियमों के प्रारम्भ  
होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों के अधीन सम्म प्राधिकारी द्वारा नियत की जाय ।
- (2) यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वर्ग विशेष की रिक्तियों के प्रति  
सेवा में नियुक्त किये गये हों तो पदानुक्ति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधा भर्ती  
द्वारा नियुक्त व्यक्ति में बरिष्ठ होगा चाहे उसका नियुक्ति वर्ष कुछ भी हो,
- (3) किसी वर्ग विशेष के पदों पर सेवा में सीधी भर्ती द्वारा एक ही समय में  
आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक बरिष्ठता ऐसे व्यक्तियों का  
छोड़कर जिनकी रिक्ति पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया किन्तु जो छ  
सप्ताह की कालावधि के भीतर सेवा में उपस्थित नहीं हुए उसी क्रम में  
रहेगी जिसमें उनका नियम 22 के अधीन तयार की गयी सूची में रखा  
गया है ,

47 (3-क) कि-इन नियमों के नियम 23 के उपनियम (4) के अधीन आवृत्त व्यक्ति  
जो इन नियमों की अनुसूची (2) के भाग 5 में विहित पाठ्यक्रम के अनुसार  
आयोग द्वारा आयोजित अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के परिणाम स्वरूप  
बलिष्ठ लिपिकों के पद पर नियुक्त किये गये, वे उन व्यक्तियों से बलिष्ठ  
( जूनियर ) होंगे जो इन नियमों के उपबन्धों के अधीन वर्ष 1976 तक  
नियुक्ति प्राधिकारी या आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा पास करने के परि  
णाम स्वरूप नियमित रूप से पहले से ही नियुक्त हैं या नियम 23 के  
उप नियम (2) के अधीन नियमित रूप से नियुक्त हैं, किन्तु इन नियमों का  
अनुसूची (2) के भाग (4) में विहित पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ष 1978

46 वि सख्या एफ 3 (4) DOP/A II/77 दिनांक 15 3 1978 द्वारा  
निविष्ट ।

47 वि सख्या 5 (8) DOP/A-II Pt-II दिनांक 5 10 1978 द्वारा  
जोड़ा गया ।

मे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा पास करने के परिणाम स्वरूप नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों से व वरिष्ठ होंगे ।

47(3) बि-इन नियमों के नियम 23 के उप नियम (4) के अधीन आवृत्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता जो कनिष्ठ लिपिका के पदों पर नियुक्त हैं नियम 22 के अधीन बनाई गई सूची में उनको स्थापित किये गये क्रम का अनुसरण करेगी ।

48(4) कि-किसी चयन, जो कि पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के अधीन नहीं हैं, के परिणाम स्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे जो बाद के चयन के परिणाम स्वरूप चयनित तथा नियुक्त हुए हैं । वरिष्ठता-सह योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो उनकी पिछली निम्नश्रेणी में थी सिवाय उस मामले के जिसमें उच्चतर पद पर लगातार स्थानापन्न हो तो यह लगातार स्थानापन्न कार्य करने की लम्बी अवधि के अनुसार होगी परन्तु ऐसी स्थानापन्नता तदर्थ या आकस्मिक न हो ।

49(4-क) कि-एक और समान चयन के परिणाम स्वरूप चयनित और योग्यता (मेरिट) के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता उसी क्रम में होगी, जिसमें उनके नाम चयन-सूची में आये हैं, और लगातार स्थानापन्न की अवधि का कोई ध्यान दिये बिना होगी ।

(5) एक ही वय में कनिष्ठ लिपिकों और वरिष्ठ लिपिकों में से आशुलिपिकों के रूप में नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा आशुलिपिकों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे,

60(5) कि-नियम 5 के परन्तुक 5-क के अधीन अविष्ठायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता सचिवालय में आशुलिपिक या आशुटकक

48 वि संख्या 5 (6) कार्मिक/क-II/75 दिनांक 31 10 1975 द्वारा प्रतिस्थापित ।

49 वि संख्या प 7 (6) कार्मिक (क-II) 75 दिनांक 31 10-1975 द्वारा निविष्ट ।

50 वि सं एफ 2 (44) DOP/A-1/70 दिनांक 13 12 74 द्वारा निविष्ट तथा दिनांक 15-9-1972 से प्रभावशील । पुराने परन्तुक 5 क, 5ग, तथा 5ग विलोपित किये गये जो इस प्रकार थे—

(5-क) नियम 5 के परन्तुक क-क के अधीन अविष्ठायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों

के पद पर उनकी सेवा की लगातार कुल लम्बी अवधि द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

- (6) यदि एक ही वष में दो या दो से अधिक व्यक्ति सहायको और प्राशुलिपिकों में से अनुभाग अधिकारियों के रूप में नियुक्त किये जाय तो, सहायको में से नियुक्त व्यक्ति प्राशुलिपिकों में से नियुक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ होगा,  
 (7) यदि एक ही वष में दो या दो से अधिक व्यक्ति वरिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किये जाय तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होगा,  
 (8) विहित परीक्षा पास कर लेने के पश्चात् एक ही वष में वरिष्ठ प्राशुलिपिकों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की या 48 वष की आयु प्राप्त कर लेने के कारण परीक्षा से छूट दिये गये अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरिष्ठता नहीं रहेगी जैसी कि ठीक नीचे के मवग में है।

[(9) (9क) (10)—विस्तारित दिनांक 15-3-1978 से]

30 तथा 30—क परिवीक्षा की अवधि—

[सम्पादकीय टिप्पणी—उपरोक्त नियम 30, 30क तथा 31 “अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम” के नियम क्रमशः 28 28—क तथा 29 के अविरल समान भाषा में हैं जो पीछे दिये गये हैं। कृपया देखने का धन करें व क्षमा करें]

32 स्थायीकरण (पुष्टीकरण—कनफर्मेशन)

एक अभ्यर्थी जो परिवीक्षा पर है उसकी परिवीक्षा की अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जावेगा यदि—

(1) वह विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उस उत्तीर्ण कर लेता है।

की पारस्परिक वरिष्ठता सचिवालय में प्राशुलिपिकों या प्राशुटककों के पद पर उनकी कुल सेवावधि द्वारा अवधारित की जायेगी

(5-ख) नियम 5 के परन्तुक 5—स के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, सचिवालय में प्राशुलिपिकों या प्राशुटककों के पद पर उनकी कुल सेवावधि द्वारा अवधारित की जायेगी,

(5-ग) परन्तुक 5-क और परन्तुक 5ख में निर्दिष्ट व्यक्ति उक्त परन्तुक के अधीन उपयुक्त ऐसे व्यक्तियों की अधिष्ठायी नियुक्ति या भर्ती से पूर्व प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा प्राशुलिपिकों के रूप में नियुक्ति समस्त व्यक्तियों से वरिष्ठ होगा,

51(12) कनिष्ठ लिपिकों के मामले में जो टक्का परीक्षा का विवक्ष्य नहीं लेते हैं, (उनको) आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में विहित से निम्नतर स्तर की नहीं हो, ऐसी टक्का परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित दो वर्ष की अवधि के भीतर पास करनी होगी इसमें असफल रहने पर वे स्थायी नहीं किये जावेंगे और उनकी सेवाये समाप्त की जा सकेंगी। इस स्पष्ट से आवृत्त अभ्यर्थी जिन्होंने किसी विश्वविद्यालय या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से टक्का परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उनको इस (उक्त) परीक्षा को पास करना आवश्यक नहीं है। अस्नातक अनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्होंने टक्का परीक्षा पास नहीं की है, उनको नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित अंग्रेजी या हिंदी में टक्का परीक्षा छ, मास के भीतर पास करनी होगी, जो आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा के लिये इन नियमों में विहित स्तर से निम्नतर नहीं होगी, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में छ मास की अवधि को छ मास के लिये आगे बढ़ाया जा सकेगा, जो छ मास के भीतर टक्का परीक्षा में बैठे किन्तु असफल रहे और जिनका काय सतोषप्रद रहा।

“परंतु यह है कि—शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को अनुसूची (2) के भाग 5 में प्रतियोगी परीक्षा के पाठ्यक्रम में विहित टक्का परीक्षा पास करना आवश्यक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—(1) इस परंतुक के प्रयोजनार्थ “शारीरिक रूप से विकलांग” के अर्थ में वह व्यक्ति सम्मिलित है, जिसके किसी एक या दोनों हाथों में ऐसा शारीरिक दोष है या हाथों में ऐसी विकलांगता है जो टक्का काम में बाधा उत्पन्न करती है।

(2) इस प्रकार शारीरिक रूप से विकलांग होने के प्रमाण में अभ्यर्थी को एक चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र, जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की श्रेणी से निम्न का नहीं हो, परीक्षा में बैठने के लिए आयोग को प्रस्तुत किये जा रहे उससे आवेदन पत्र के समय प्रस्तुत करना होगा।

52(1-20) इन नियमों के नियम 5 के परंतुक 5-A के अधीन नियुक्त आधुनिक लिपिका के मामले में और जो इन नियमों के नियम 5 के परंतुक

51 वि ■ एफ 3 (3) DOP/A-II/76 दि 30-11-1975 द्वारा निविष्ट।

52 वि स एफ 3 (9) DOP/A-II-76 दि 21-1-1977 द्वारा जोड़ा गया।

53 वि स एफ 3 (4) DOP/A-II/77 दि 15-3-1978 द्वारा जोड़ा गया।



5-ब के खण्ड (ख) में वर्णित किसी सस्यान से या सरकार द्वारा समय समय पर मायता प्राप्त सस्यानो से निम्नतर गति में द्वितीय भाषा की परीक्षा पास कर चुके हैं।

- (ii) उसने विहित प्रशिक्षण, कोई हो, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो,
- (iii) जहाँ आवश्यक हो, हिंदी में प्रवीणता परीक्षा पास की हो, और
- (iv) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि उसकी सत्यनिष्ठा सदेह से परे है और वह समय-समय पर स्थायीकरण के योग्य है।

### भाग VII-वेतन छुट्टी और भत्ते आदि

33 वेतनमान-सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का मासिक वेतन वह होगा जो नियम 36 में निर्दिष्ट नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो या जो समय समय पर सरकार द्वारा मजूर किया जाय।

5433-क परीक्षा के दौरान वेतन वृद्धि—एक परीक्षाधीन व्यक्ति राजस्थान सेवा नियम 1951 के उपबन्धों के अनुसार उसे अनुज्ञेय वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा।

34 इन नियमों के जारी होने की तारीख को कोई व्यक्ति जो प्राशुलिक के रूप में कार्य कर रहा हो और जो नियम 33 के अन्तर्गत आता हो उस वेतनमान में वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि वह अनुसूची II के भाग II में विहित प्रतियोगी परीक्षा पास न कर ले।

5534 क [नियम 5 के परंतु (11) के अनुसार वरिष्ठलिपिकों के पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त तथा स्थायी किये गये व्यक्ति उनके वेतन स्वीकारण के लिये उनके द्वारा वरिष्ठ लिपिकी के पदों पर वास्तव में कार्यभार सम्भालने के दिनांक में प्रकल्पित रूप से उस स्टज पर जिस पर वे व्यक्ति देय दिनांक को पदोन्नति द्वारा वरिष्ठ लिपिक के रूप में पदोन्नति द्वारा नियुक्त कर दिए जाते, और जो वेतन प्राप्त करते, उसके लिये अधिकृत होंगे और उनको कोई वेतन व भत्ते का बकाया उस अवधि के लिये ग्राह्य नहीं होगा, जिसमें उन्होंने वास्तव में वरिष्ठ लिपिक के रूप में कार्य नहीं किया है।]

35 दक्षता अवरोध पार करने की कसौटी—जहाँ किसी वेतनमान में दक्षता अवरोध का उपबन्ध हो तो उसे दक्षता अवरोध पार करने की अनुज्ञा नहीं दी जायगी

54 वि म प 3 (11) नियुक्ति/क-2/58 दिनांक 16-10-1973 द्वारा निविष्ट।

55 वि स एफ 3 (1) DOP/A-II/78 दिनांक 17-5-1979 द्वारा जोड़ा गया।

यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उसने सतोषप्रद कार्य नहीं किया है तथा उसकी मत्पनिष्ठा में संदेह है।

36 वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन आदि का विनियमन—इन नियमों में उपर्युक्त के सिवाय सेवा के सदस्यों के वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य बातें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होगी—

- 1 राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1949
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान एकीकरण) नियम, 1950
- 3 राजस्थान सेवा नियम, 1951
- 4 राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान युक्तियुक्तकरण) नियम, 1956
- 5 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियमण और अपील) नियम, 1958
- 6 राजस्थान सिविल सेवा (पुनरोक्ति वेतन) नियम 1961
- 7 राजस्थान सिविल सेवा (नवीन) वेतनमान नियम, 1969
- 8 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये कोई अन्य नियम जो अन्तर्गत प्रवृत्त हो।

37 शकाग्रों का निराकरण—यदि इन नियमों के लागू होना और इनके विस्तार के बारे में कोई शका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के पास नियुक्ति (क) विभाग में आदेशाय भेजा जायगा जिस पर नियुक्ति विभाग का विनिश्चय प्रथम होगा।

38 निरस्तन तथा व्यावृत्ति—इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों में संबंधित समस्त नियम तथा आदेश जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, इसके द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

परंतु इस प्रकार निरस्तित नियमों और आदेशों के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गई कारवाई इन नियमों के तदनुसारी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश और की गई कारवाई समझी जायगी।

परंतु यह धोर है कि—इन नियमों में या राजस्थान सचिवालय लिपिक-वर्गीय स्थापन नियम 1956 के अधीन वर्णित कोई बात नियुक्ति प्राधिकारी को, उन व्यक्तियों को जो पहले पुनर्गठन से पूर्व के राजस्थान, अजमेर, बम्बई और मध्य

56 वि सख्या प 3 (12) DOP/B-1/56 दिनांक 22-2-1974 द्वारा जोड़ा गया तथा दिनांक 5-5-1970 से प्रभावी एवं वि सख्या 3 (712) DOP/B-1/56 दिनांक 20-10-1975 द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 5-5-1970 से प्रभावी।

भारत राज्यों के नियोजन में ये राज्य पुनगठन अधिनियम 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 37/1956) के अधीन उनकी सेवाओं के एकीकरण को शासित करने वाले भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अनुसूची में सम्मिलित पदों पर, इस बात का ध्यान दिये बिना कि—ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रवृत्त के 31 वें दिवस को उपरोक्त पुनगठन पूर्व के राज्यों में से किसी में धारित पद को अनुसूची में सम्मिलित किसी पद के समानोक्त किया या या कथित निर्देशों के अधीन भारत सरकार द्वारा एकाकी पद (प्राइसोलेटेड पोस्ट) वर्गीकृत किया गया था, नवम्बर 1956 के प्रथम दिवस के प्रभाव से अधिष्ठायी या स्थानापन्न रूप में नियुक्त करने से या इसके बाद अधिष्ठायी स्थानापन्न रूप में पदोन्नत करने से प्रवारित नहीं करेगी या प्रवारित किया हुआ न समझा जावेगा।

5739 नियमों को शिथिल करने की शक्ति—किसी असाधारण मामले में जहाँ सरकार के प्रशासनिक विभाग का समाधान हो जाता है कि—भर्ती के लिए आयु सम्बन्धी या अनुभव सम्बन्धी नियमों के प्रभाव से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई उत्पन्न हुई है या जहाँ सरकार का यह अभिमत हो कि—किन्हीं व्यक्तियों की आयु या अनुभव सम्बन्धी इन नियमों के किसी उपबन्ध को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है तो यह कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति से और आयोग के परामर्श से आज्ञा द्वारा इन नियमों के सम्बद्ध उपबन्धों को, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उस मामले को यायसगत तथा साफ तरीके से निपटाने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगा। परन्तु यह है कि ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पहले से वर्णित उपबन्धों से कम लाभप्रद नहीं होगा। शिथिलीकरण के ऐसे मामले कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवायोग को निर्देशित किये जावेंगे।

## अनुसूची-I

क्र.सं.	पद का नाम	भर्ती व सेवा प्रविष्टि	सीधी भर्ती के लिये 'यूनतम' सहित	जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिये 'यूनतम' अनुसूचिता
1	2	3	4	5	6
					7

## अ.प.क.

वरिष्ठ पद

आ. विनोदित

2 सहायक 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा वरिष्ठ लिपिक । स्तम्भ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष की सेवा ।

3 वरिष्ठ लिपिक 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा (67 प्रतिशत वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा 33 प्रतिशत प्रति योगी परीक्षा द्वारा) (क) स्तम्भ 3 में उल्लिखित (1) वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा दानो बोर्ड के कमिष्ठ स्तम्भ 5 में उल्लिखित पद पर लिपिक । स्नातक के मामले में 3 (2) टेल्फोन अपरेटर, प्रति वर्ष का अनुभव या अन्य योगी परीक्षा के आधार व्यक्तियों के मामले में 7 पर भरे जाने वाले केवल वर्ष का अनुभव । 33 प्रतिशत पदों के लिए पात्र होंगे ।

आ. वि. सं. प. 2 (3) बानिज्य/त. 1/75 दि. 30-5-1975 द्वारा दि. 1-1-1975 से विस्तारित, पृ. 142 की पाद टिप्पणी में देते ।

[illegible]

1. The first part of the  
 report is the introduction  
 which states the purpose of the study  
 and the scope of the work.

The second part of the report  
 is the literature review which  
 discusses the work of other  
 authors on the same subject.

The third part of the report is the  
 methodology which describes the  
 methods used in the study.

The fourth part of the report is the  
 results which present the findings  
 of the study.

The fifth part of the report is the  
 conclusion which summarizes the  
 main points of the study.

The sixth part of the report is the  
 bibliography which lists the  
 sources used in the study.

The seventh part of the report is the  
 appendix which contains the  
 data and other material used in the study.

The eighth part of the report is the  
 index which lists the pages on which  
 the topics are discussed.

The ninth part of the report is the  
 table of contents which shows the  
 structure of the report.

The tenth part of the report is the  
 title page which contains the title  
 of the study and the name of the author.

1	2	3	4	5	6	7
2	वरिष्ठ माधु लिपिक	ॐ [50 प्रतिशत पदो- प्रति द्वारा, 50 प्रति शत सचिवालय के माधुलिपिकों से से सीधी स्तरों द्वारा]	—	माधुलिपिक		

ॐ(1) अनुसूची II के भाग II में मया उल्लिखित माधुलिपिकों की अधिकारी परीक्षा 15-3 या 15-3-78 के पहले प्रतियोगी परीक्षा पास किया हुआ हो या नियम 5 के पर हुए 5 के अधीन उक्त परीक्षा में बैठने से मुक्त होना चाहिए परंतु उन व्यक्तियों से जिनकी आयु 48 वर्ष से अधिक है और जिनकी पदोन्नति मयया प्राप्तभ्य हो गयी है, उक्त परीक्षा पास करने की अपेक्षा नहीं की जायगी।

(2) राजस्थान सचिवालय में माधुलिपिकों के रूप में कम से कम 7 वर्ष की अवधि के लिये काम कर चुका हो

दि स एक 3 (4) DOP/A 11/77 दि 15-3-1978 द्वारा प्रतिस्थापित।

### 3 मातृलिपिक

50 प्रतिशत सीधी  
भर्ती द्वारा और 50  
प्रतिशत राजस्थान  
सचिवालय के कनिष्ठ  
लिपिकों एवं वरिष्ठ  
लिपिकों से से (नियम  
5 के परचुक 5 के  
अनुसार)

(1)(न) राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या सरकार द्वारा इस रूप से मायता प्राप्त समस्त परीक्षा पास किया हुआ होना चाहिये ।

(ख) मैट्रिक या माध्यमिक परीक्षा या सरकार द्वारा इस रूप से मायता प्राप्त समस्त परीक्षा पास किया हुआ, जो सचिवालय से कनिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्य कर रहा हो ।

(2) अनुसूची 11 के भाग 11 से उल्लिखित प्रहारी परीक्षा पास किया हुआ हो ।

### श्रृंखला 'घ'

[श्रृंखला 'घ' वि से 3 (1) DOP/A 11/78 दिनांक 28-1-1978 द्वारा विलोपित]



## अनुसूची II

(नियम 5 देखिये)

<sup>1</sup>[अर्हक] परीक्षा के लिये पाठ्य विवरण और नियम

भाग I बरिष्ठ आशुलिपिकों के पदों के लिये अर्हक परीक्षा

(1) अर्हक परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जायेगी। परीक्षा के लिये श्रुतिलेख को न्यूनतम गति अंग्रेजी में 120 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 100 शब्द प्रति मिनट होगी, जो 100 अंकों का होगा।

<sup>1</sup>भाग II आशुलिपिका के लिये

एक अभ्यर्थी को या तो अंग्रेजी आशुलिपि और अंग्रेजी टंकण या हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टंकण (परीक्षा) उत्तीर्ण करनी होगी और आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के पद के लिये अर्हता-परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे —

- |   |  |         |
|---|--|---------|
| 1 | अंग्रेजी आशुलिपि परख   | 100 अंक |
|   | (इस परीक्षा में 100 शब्द प्रति मिनट स श्रुतिलेख होगा)  |         |
| 2 | अंग्रेजी टंकण परख  | 100 अंक |
|   | (इस परख में गति परीक्षा तथा दक्षता परीक्षा प्रत्येक 50 अंक की होगी। गति 40 शब्द प्रति मिनट होगी) |         |
| 3 | हिन्दी आशुलिपि परख   | 100 अंक |
|   | (इस परख में 80 शब्द प्रति मिनट स श्रुतिलेख होगा)   |         |

- 1 उपरोक्त पाठ्यक्रम वि स एक 3 (4) DOP/AII/77 दि 23 5 1979 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित किया गया जो इस प्रकार था।

भाग II आशुलिपिका के लिये

आशुलिपिकों के पदों के लिये [अर्हक] परीक्षा में दो वैकल्पिक ग्रुप A और B में दिये गये विषय होंगे। अभ्यर्थी स दूा ग्रुपों में स किसी भी एक ग्रुप में उल्लिखित विषयों में पास होने की अपेक्षा की जायेगी। कमज

- ॐ वि सख्या एक 3 (4) DOP/A-II/77 दिनांक 15 3 1978 द्वारा प्रतिस्थापित।

- 4 हिन्दी टक्कण परीक्षा 100 अंक  
(इस परीक्षा में गति परीक्षा तथा दक्षता परीक्षा प्रत्येक 50 अंक की होगी।  
गति 30 शब्द प्रति मिनट होगी)

भाग III विधि रचनाकारों/अनुवादकों के लिये प्रतियोगी परीक्षा

1 प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे —

(1) अंग्रेजी से हिन्दी में या सविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक भाषा में अनुवाद । 100 अंक

अभ्यर्थियों को प्रेस विज्ञप्ति तथा, पत्र पत्रिकाओं के लेखों, शासकीय सफरनामा,

पीछे से

ग्रुप-क

- 1 अंग्रेजी प्राथुलिपि परीक्षा 100 अंक  
इस परीक्षा में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से श्रुतिलेख लिखना होगा।
- 2 अंग्रेजी टक्कण परीक्षा 100 अंक  
इस परीक्षा में गति परीक्षा और दक्षता परीक्षा सम्मिलित होगी और प्रत्येक के 50 अंक होंगे। गति 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिये।
- 3 हिन्दी प्राथुलिपि परीक्षा 100 अंक  
इस परीक्षा में 60 शब्द प्रति मिनट की गति से श्रुतिलेख लिखना होगा।
- 4 हिन्दी टक्कण परीक्षा 100 अंक  
इस परीक्षा में गति परीक्षा और दक्षता परीक्षा सम्मिलित होगी और प्रत्येक के 50 अंक होंगे। गति 20 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिये।

ग्रुप-ख

- 1 अंग्रेजी प्राथुलिपि परीक्षा 100 अंक  
इस परीक्षा में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से श्रुतिलेख लिखना होगा।
- 2 अंग्रेजी टक्कण परीक्षा 100 अंक  
इस परीक्षा में गति परीक्षा और दक्षता परीक्षा सम्मिलित होगी और प्रत्येक के 50 अंक होंगे। गति 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिये।
- 3 हिन्दी प्राथुलिपि परीक्षा 100 अंक  
इस परीक्षा में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से श्रुतिलेख लिखना होगा।
- 4 हिन्दी टक्कण परीक्षा 100 अंक  
इस परीक्षा में गति परीक्षा और दक्षता परीक्षा सम्मिलित होगी और प्रत्येक के 50 अंक होंगे। गति 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिये।

टिप्पणी—यदि किसी अभ्यर्थी ने 3 जनवरी, 1962 से पूर्व आयोग द्वारा संचालित ग्रुप क में सम्मिलित किसी विषय में परीक्षा पास करली हो तो उससे उक्त ग्रुप के केवल शेष विषयों में ही परीक्षा पास करने की अपेक्षा की जायगी।

विधाना, नियमों और अनुदेशों के अवतरणों का हिंदी में या किसी अन्य भाषा में अनुवाद करना होगा और उक्त रचनाओं में प्रयुक्त की जाने वाली सामान्य अभि व्यक्तियों और उक्तियों की व्याख्या करनी होगी।

(2) हिंदी या अन्य भाषा विशेष से अंग्रेजी में अनुवाद।

अभ्यर्थियों को पत्र पत्रिकाओं के लेखों, भाषणों आदि के हिन्दी या उपरोक्त अन्य भाषाओं के अवतरणों का अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा।

टिप्पण—दो लिखित प्रश्न पत्रों में से प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिये अनुत्तरेय समय 3 घंटे होगा। खराब हस्तलेख होने के कारण अभ्यर्थियों को दिये गये पत्रों में से कटौती की जायेगी।

❧भाग IV कनिष्ठ लिपिकों के पद के लिये प्रतियोगी परीक्षा

❧सम्पादकीय निवेदन—इस भाग के लिये कृपया “अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम” की अनुसूची I में भाग (2) देखिये—समान भाषा में उक्त पाठ्यक्रम इन भागों में है, अतः कृपया वहीं पर देखने का श्रम करें।]

### ❧❧ भाग V

नियम 23 के उपनियम (4) के अधीन आवृत्त व्यक्तियों के लिये कनिष्ठ

लिपिकों के पद के लिये अर्हता परीक्षा

[❧सम्पादकीय निवेदन—इस भाग के पाठ्यक्रम के लिये कृपया “अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्थापना नियम” की अनुसूची II में भाग (4) देखिये—समान भाषा में उक्त पाठ्यक्रम इन भागों में है। अतः कृपया वहीं पर देखने का श्रम करें।]

अनुसूची III खरिष्ट लिपिकों के पदों के लिये प्रतियोगी परीक्षा

(नियम 26—क के अधीन)

कुल 5 प्रश्न पत्र होंगे।

प्रश्न पत्र I	सचिवालय नियमावली और कार्यविधि नियम	50 अंक
प्रश्न पत्र II	राजस्थान सेवा नियम अध्याय III, IV, V, VI और VII	50 अंक

❧ वि स एफ 3 (3) DOP/A II/76 दि 30 11-1976 द्वारा प्रतिस्थापित तथा भादिनाक संशोधित।

❧❧ वि स एफ 5 (8) DOP/A II/Pr II दिनांक 5-10-1978 द्वारा जोड़ा गया।

प्रश्न पत्र III	राजस्थान सेवा नियम अध्याय X, XI, XII और XV	50 अंक
प्रश्न पत्र IV	राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 और राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958	50 अंक
प्रश्न पत्र V	हिन्दी में निबंध और सक्षिप्तीकरण लेख	50 अंक
		कुल— 250 अंक

### ❧ नवीनतम संशोधन 1979

1 'कृपया 'राजस्थान सचिवालय मन्त्रालयिक सेवा नियम 1970' में जहाँ कहीं शब्द 'वरिष्ठ आशुलिपिक' और "ज्यूनियर श्रेणी आशुलिपिक" (Senior Stenographer and Selection Grade Stenographer) प्रयोग में लिये गये हैं, उनके स्थान पर क्रमशः 'निजी सहायक' तथा 'वरिष्ठ निजी सहायक' पढ़ने का धम करें।

[वि स एफ 3 (6) DOP/A-II 78 GSR-28 दिनांक 21-5-1979 द्वारा संशोधित किया गया]

2 नियम 5 में निम्नांकित संशोधन करने का धम करें।

- (1) पृष्ठ 110 पर परतुक (5 क) में पहली पक्ति में आशुलिपिक के आगे "या आशुटकक, यथास्थिति" जोड़े तथा पक्ति स 4 में "1-76" की बजाय "31-7-1977" करें।
- (ii) पृष्ठ 113 पर परतुक (6) की पहली पक्ति में इस प्रकार पढ़ें—  
"31-7-1977 से पूर्व आशुलिपिकों या आशुटककों, यथास्थिति के रूप में।"
- (iii) पृष्ठ 114 पर पक्ति 3 4 पर 'सरकार द्वारा मायता प्राप्त संस्थान द्वारा' के स्थान पर—“हरिश्चन्द्र मामुर लोक प्रशासन राज्य संस्थान द्वारा अंग्रेजी आशुलिपि और अंग्रेजी टंकण में तथा भाषा विभाग द्वारा हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी टंकण में” पढ़ें। इसके आगे पक्ति 5 में 'दो अवसर' के बजाय 'तीन अवसर' पढ़ें।

[❧ वि स एफ 3 (4) DOP/A-II/77 G S R 29 दि 23-5-79 द्वारा]

### 3

## \* राजस्थान अधीनस्थ सिविल न्यायालय मन्त्रालयिक (लिपिकवर्गीय) स्थापन नियम 1958

[Rajasthan Subordinate Civil Courts Ministerial Establishment  
Rules 1958]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल न्यायालयों के लिपिक वर्गीय (मन्त्रालयिक) स्थापन में नियुक्ति और इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

### भाग-1 साधारण

1 संक्षिप्त नाम प्रारम्भ तथा विस्तार—(1) इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1958 है।

(2) ये तुरत प्रवृत्त होंगे,

(3) राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल न्यायालयों के लिपिक वर्गीय (मन्त्रालयिक) स्थापन के समस्त व्यक्तियों पर ये प्रभावी होंगे।

2 विद्यमान नियमों तथा आज्ञाओं का अतिष्ठान—समस्त विद्यमान नियम व आज्ञाएँ जो इन नियमों द्वारा आवृत्त मामला से सम्बन्धित हैं एतद् द्वारा अतिष्ठित किये जाने हैं, परंतु ऐसे विद्यमान नियमों तथा आज्ञाओं के अनुसरण में या द्वारा की गई कार्यवाही इन नियमों के अधीन की गई समझी जाएगी, परंतु यह है कि —

\* वि स एफ 3 (9) AC/Int/56 दिनांक 18 फरवरी 1958, जो राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग), दिनांक 27 मार्च 1958 को प्रथम बार प्रकाशित।

अप्रामादित हिंदी अनुवाद—दि 30 जून 1978 तक सशोधित पाठ।

(i) ये नियम राजस्थान उच्च यायालय के अधीनस्थ सिविल यायालयों के लिपिक वर्गीय पदों पर, पुनगठन पूर्व के राजस्थान राज्य की सेवाओं के एकीकरण की प्रक्रिया में, जो सेवाओं के ऐसे एकीकरण को विनियमित करने वाले नियमों और सरकारी आदेशों के अनुसार हैं, नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे,

(ii) ये नियम राजस्थान उच्च यायालय के अधीनस्थ सिविल यायालयों के लिपिक वर्गीय पदों पर, तत्कालीन अजमेर राज्य और पुनगठन पूर्व के बम्बई और मध्यभारत के कमचारियों जो राज्य पुनगठन अधिनियम के अधीन नए राजस्थान राज्य का भाग बने, के एकीकरण की प्रक्रिया में नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।

3 परिभाषाएँ—जब तक की कोई बात विषय अथवा मद में विरुद्ध न हो, इन नियमों में —

(क) 'उच्च यायालय' से राजस्थान उच्च यायालय अभिप्रेत है,

+ (ख) 'सरकार' और "राज्य" से क्रमशः राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य अभिप्रेत है,

(ग) 'आयोग' से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है,

(घ) "लिपिक वर्गीय स्थापन" से राजस्थान उच्च यायालय के अधीनस्थ सिविल यायालयों के लिपिक वर्गीय स्थापन अभिप्रेत है,

(ङ) 'विहित प्रपत्र' से उच्च यायालय द्वारा विहित प्रपत्र अभिप्रेत है।

(च) "अधीनस्थ सिविल यायालय" से राजस्थान उच्च यायालय के, अधीनस्थ जिला एवं सत्र यायाधीशों, अपर जिला एवं सत्र यायाधीशों, अपर सिविल यायाधीशों, मुंसिफों (मह. मुंसिफ दण्ड नायक) अपर मुंसिफों के यायालय और लघुवाद यायालय अभिप्रेत है।

(छ) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से अभिप्रेत है, जिला एवं सत्र यायाधीश या ऐसा अधिकारी उसे प्रत्यायोजित प्राधिकार के अधीन रहते हुये, जिसे उच्च यायालय की अनुमति में जिला एवं सत्र यायाधीश द्वारा स्थापन पर नियुक्त करने का प्राधिकार प्रत्यायोजित किया गया है।

(ज) "सीधी भर्ती" से पदोन्नति या स्थानान्तरण से अथवा भर्ती अभिप्रेत है।

(झ) "जज शिप" से एक जिला एवं सत्र यायाधीश की प्रशासनिक अधिकारता अभिप्रेत है, और

(ञ) 'अनुसूची' से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है।

4 निवचन—जब तक सदम से अथवा अपेक्षित न हो राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम स 8) इन नियमों के निवचन के लिये उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निवचन के लिये लागू होता है ।

### भाग (2) सवग (कडर)

5 स्थापन की सख्या—(1) एक जजशिप के स्थापन की सख्या वह होगी जो राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत कुल सख्या में स जजशिप के प्रस्थापन विवरण (Proposition statement) में समय समय पर उच्च न्यायालय द्वारा तय की जाय

परन्तु यह है कि—नियुक्ति प्राधिकारी उच्च न्यायालय की आज्ञाओं के अध्यधीन रहकर समय-समय पर किसी रिक्त पद को बिना किसी व्यक्ति को प्रतिकार पाने का अधिकार दिये बिना, भरा छोड़ सकता है ।

(2) स्थापन में आधुनिकीकरण का एक सवग तथा निम्नांकित प्रवर्ग के पदा में से, जैसा उच्च न्यायालय समय समय पर तय करे, एक या अधिक का एक साधारण सवग होगा --

- 1 मुत्सरिम
- 2 वरिष्ठ लिपिक (U D C)—(क) सीनियर लिपिक, (ख) रीडर, (ग) लेखालिपिक, (घ) विक्रम भूमी, (ङ) मुख्य प्रतिलिपिकार, (च) अभिलेख रक्षक ।
- 3 कनिष्ठ लिपिक (L D C)—(क) टक्क (टाइपिस्ट) (ख) भावक तथा जावक लिपिक, (ग) सिविल लिपिक (घ) अपराधिक लिपिक, (ङ) निष्पादन (इजराय) लिपिक, (च) सहायक नाजिर (छ) प्रतिलिपिकार, (ज) सहायक अभिलेख रक्षक, (झ) विमुक्ति लिपिक (रिलीविंग क्लर्क) ।

### भाग (3) भर्ती

6 भर्ती के तरीके —इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् स्थापन में भर्ती (इस प्रकार) होगी —

- (क) आधुनिकीकरण सवग में आधुनिकीकरण तृतीय श्रेणी के रूप में चयन द्वारा,
- (ख) कनिष्ठ लिपिक के रूप में साधारण सवग में एक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, और
- (ग) प्रत्येक सवर्ग में अथ पदों पर एक जजशिप के भीतर पदोन्नति द्वारा

परन्तु यह है कि—किसी सवर्ग के एक पद को दूसरी जजशिप में सम्बन्धित सवर्ग में तत्समान पद धारण करने वाले व्यक्ति के, सम्बन्धित जिला एवं सत्र

'यायाधीश की सहमति तथा राजस्थान उच्च 'यायालय की अनुमति से स्थानांतर द्वारा भी भरा जा सकेगा। उच्च 'यायालय भी विशेष कारणा से लिपिकवर्गीय स्थापन के किसी सदस्य को एक जजशिप से दूसरी में स्थानांतरित कर सकेगा।

× 6 A इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति की, जो आपातकाल के दौरान सेना/वायुसेना/नौ सेना में सम्मिलित होता है, भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता और पुष्टीकरण आदि सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित किये गये आदेशों और निर्देशों के द्वारा विनियमित होंगे, परंतु यह है कि—ये भारत सरकार द्वारा इस विषय में प्रसारित निर्देशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, ही विनियमित होंगे।

उपरोक्त सशोधन दिनांक 29-10-1963 से प्रभावी हुआ समझा जावेगा।

7 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये रिक्तस्थानों का आरक्षण - अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों का आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त आरक्षण सम्बन्धी सरकार की आज्ञाओं के अनुसार होगा।

× × [टिप्पणी—विलोपित]

8 राष्ट्रीयता - [सम्पादकोप निवेदन—कृपया यह नियम सब नियमों में एक समान है अतः पीछे पृष्ठ 27 पर नियम 10 या पृष्ठ 117 118 पर नियम 7 देखिये]

8 क - [कृपया पीछे पृष्ठ 28 पर नियम 10 क या पृष्ठ 119 पर नियम 7 क देखिये जो एक समान हैं]

9 आयु—किसी अवकाश में सीधी भर्ती का अर्ह्यार्थी आवेदन प्राप्त करने के दिनांक के <sup>1</sup>[ठीक पश्चात् आने वाली प्रथम जनवरी को] 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिये किंतु <sup>2</sup>[28 वर्ष की] आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिये।

× वि स एफ 21 (12) नियुक्ति (ग) 55 भाग II दिनांक 29 8 1973 द्वारा निविष्ट।

× × वि सरया एफ 3 (9) AC/Intg/56 दिनांक 11-2-1960 द्वारा निम्नांकित टिप्पणी विलोपित—

'टिप्पणी—इन नियमों के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त ऐसी आज्ञाओं की प्रति लिपि अनुसूची I में दी गई है, '

1 वि स एफ 3 (9) AC/Intg/56 दिनांक 12 2 1960 द्वारा निविष्ट।

2 वि सरया एफ 1 (25) A-II 69 दिनांक 3 6 70 द्वारा '25' के स्थान पर प्रतिस्थापित।



परन्तु यह है कि—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी उच्च न्यायालय की अनुमति से विशेष मामले में अधिकतम आयु सीमा को शिथिल कर सकेगा, और

(ii) 31 दिसम्बर 1958 तक अस्थायी रूप से सरकारी सेवा में लगातार स्थानापन्न कार्य करने की अवधि आयु में से पात्रता के प्रयोजनाय कम कर दी जायेगी।

3(iii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के सदस्य के मामले में उच्च आयु सीमा 5 वर्ष से शिथिल कर दी जायेगी,

4टिप्पणी—महिला अभ्यर्थियों के मामले में उच्च आयु सीमा को 5 वर्ष द्वारा बढ़ा दिया जायेगा।

5(iv) परन्तु यह है कि—सुरक्षित सैनिकों (रिजर्विस्ट) अर्थात् प्रतिरक्षा सेवा के सुरक्षित (रिजर्व) में स्थानांतरित कमचारियों के लिये उच्च आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

6(v) राजनैतिक-पीडितों के लिये 31 दिसम्बर 1964 तक उच्च आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

स्पष्टीकरण—शब्द “राजनैतिक पीडित” का इस नियम के प्रयोजनाय वही अर्थ होगा, जो राजस्थान राजनैतिक पीडितों की सहायता नियम 1959 के नियम 2 के खण्ड (iii) के अधीन वर्णित है, जो राजस्थान राजपत्र, भाग 4 (ग) में दिनांक 18-6-1959 को प्रकाशित हुआ।

7(vi) राष्ट्रीय कैंडेट कौर में कैंडेट प्रशिक्षकों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा के बराबर अवधि से उच्च आयु सीमा शिथिल की जाने योग्य होगी और

3 वि सख्या एक 3 (9) AC / Intg/56 दिनांक 11-2-1960 द्वारा जोड़ा गया।

4 वि सख्या एक 1 (12) नियुक्ति/घ/60 दिनांक 16-11-1960 द्वारा जोड़ा गया।

5 वि सख्या एक 3 (9) नियुक्ति/ग/58 दिनांक 27-8-1962 द्वारा जोड़ा गया।

6 वि सख्या एक 1 (16) नियुक्ति/क-2/62 दिनांक 31-5-1963 द्वारा जोड़ा गया।

7 वि सख्या एक 1 (10) नियुक्ति/क-2/66 दिनांक 11-4-1967 तथा 15-5-71 द्वारा जोड़ा गया।

यदि परिणामजन्म आयु विहित आयु से तीन वर्ष से अधिक से नहीं बढ़ती है, तो उसे विहित आयु में माना जावेगा।

<sup>8</sup>(vii) 1-3-1963 को या इसके बाद बर्मा श्रीलंका और केनिया, टागानिका, युगांडा व जजीवार के पूर्वी अफ्रीकी-देशों से लौटाये गये व्यक्तियों के लिये उपयुक्त उल्लिखित आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिल की जावेगी और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के मामले में पांच वर्ष की छूट और दी जावेगी।

<sup>9</sup>(viii) पूर्वी अफ्रीकी देशों—केनिया, टागानिका, युगाण्डा और जजीवार से वापस लौटाये गये व्यक्तियों के मामले में कोई आयुसीमा नहीं होगी।

#### 10 शैक्षिक अर्हताएँ - (Academic qualifications)

(1) आशुलिपिक सबग में सीधी भर्ती के लिये एक अभ्यर्थी को -

(क) राजस्थान विश्व विद्यालय की इंटरमीडिएट परीक्षा या भारत में विधि द्वारा स्थापित अन्य किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड की तत्समान परीक्षा या सरकार द्वारा तत्समान भाषा अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो

परंतु यह है कि—सरकारी विभाग में अस्थायी आधार पर 1 10-1957 को कम से कम एक वर्ष के लिये कार्य कर रहे व्यक्ति को इंटर परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी

(ख) अंग्रेजी में 100 शब्द प्रति मिनट से आशुलिपि और 40 शब्द प्रति मिनट से टंकण की या हिन्दी में 80 शब्द प्र मि आशुलिपि और 30 शब्द प्र मि टंकण की प्रावधिक गति परीक्षा और आयोग द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी आशुलिपिक की परीक्षा परीक्षा की अवधि में उत्तीर्ण की हो, और

(ग) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी तथा राजस्थानी बोलियों का व्यावहारिक ज्ञान हो।

(2) साधारण सबग में सीधी भर्ती के लिये एक अभ्यर्थी राजपूताना विश्वविद्यालय की या इस नियम के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा भाषा विश्वविद्यालय या बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो और इसके अतिरिक्त देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी तथा राजस्थानी बोलियों का व्यावहारिक ज्ञान हो।

8 वि सख्या एफ 1 (20) नियुक्ति/क-2/67 दिनांक 20 9 75 तथा मुद्रि पत्र समसंख्यक दिनांक 17-12 76 द्वारा दिनांक 29 2-77 तक प्रभावी।

9 वि सख्या एफ 1 (20) नियुक्ति/क-2/67 दिनांक 13 12 1974

11 चरित्र--[कृपया पृष्ठ 122 पर नियम 11 देखिये--उक्त नियम में टिप्पणी स (2) व (3) एक टिप्पणी स (2) में सम्मिलित है।]

12 शारीरिक योग्यता--किसी सवंग में सीधे भर्ती का अभ्यर्थी मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये और उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा मानसिक एवं शारीरिक दोष नहीं होना चाहिये जो उससे कतव्यपालन में बाधक हो और यदि वह चुन लिया जाय तो, उसे सरकार द्वारा तत्प्रयोजनाय विहित चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

§ 12ब-अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग -ऐसा अभ्यर्थी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी/प्रायोग द्वारा प्रतिरूपण करने का अथवा गढ़े हुए दस्तावेज या ऐसा दस्तावेज जो बिगाड़ दिया गया है, प्रस्तुत करने का या ऐसे व्योरे प्रस्तुत करने का जो गलत या मिथ्या है अथवा महत्वपूर्ण सूचना दवाने का अथवा परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश पाने के निमित्त किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन काम में लाने का दोषी घोषित किया जाता है या बर दिया गया है, तो फौजदारी मुकद्दमा चलाये जाने के दायि-बाधीन होने के अतिरिक्त उसे सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिए स्थायी तौर पर विनिर्दिष्ट कासावधि के लिये विवर्जित किया जायेगा —

(क) आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के लिये/किसी परीक्षा में प्रवेश से या आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी साक्षात्कार में प्रवेश से, और

(ख) सरकार द्वारा सरकार के अधीन नियोजन से।

13 पदोन्नति--(1) एक जजशिप के पद साधारणतया उस जजशिप के लिपिकी के लिये आरक्षित है और उच्चतर पदों पर पदोन्नति साधारणतया उनमें से ही की जावेगी। किसी विशिष्ट पद पर पदोन्नति के लिये यदि कोई उन्मुक्त लिपिक जजशिप में उपलब्ध न हो, तो उच्च यायालय की स्वीकृति से दूसरी जजशिप से पदोन्नति हो सकेगी।

(2) वरिष्ठ श्रेणी (upper division grade) के पदों पर पदोन्नति वरिष्ठता के अनुसार दलता के अधीन रहते हुए की जावेगी।

परन्तु यह है कि—कोई व्यक्ति अधिष्ठायी रूप से लेखालिपिक के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह ऐसी परीक्षा (टेस्ट) उत्तीर्ण न कर ले

और ऐसी अन्य शर्तें पूरी न कर ले जो इस प्रयोजनाय समय समय पर विहित की जा सकेंगी।

(3) कोई व्यक्ति अधिष्ठायी रूप से मुस्तरिम नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह कम से कम 10 वर्ष के लिए सेवा में कम से कम 5 वर्ष एक वरिष्ठ लिपिक या आधुलिपिक के रूप में न रहा हो,

(4) कनिष्ठ श्रेणी (Lower division grade) के पदों को धारण करने वाले व्यक्ति चयनित पदों पर पदोन्नति के लिये पात्र नहीं होंगे, परन्तु यह है कि—ऐसे व्यक्तियों को आधुलिपिक के रूप में नियुक्त किय जाने से प्रवारित नहीं किया जावेगा, यदि वे अथवा ऐसी नियुक्ति के लिये पात्र हैं।

टिप्पणी—किसी व्यक्ति को अक्षमता के लिये अतिष्ठित करने में उसकी सेवा के पूर्व अभिलेख को उचित वजन दिया जावेगा और वरिष्ठता को केवल तभी नहीं मानना चाहिये, जब अतिष्ठित कमचारी उस पद को धारण करने के लिये अयोग्य (unfit) हो जिस पर पदोन्नति की जानी है।

#### भाग (4) सीधी भर्ती की प्रक्रिया

14 परीक्षाओं की अवधि—प्रत्येक वर्ष में शीघ्र ही या जैसी परिस्थितियों की मांग हो प्रत्येक जिला-यायाधीश अपनी जगहों के लिये उतने अभ्यर्थियों को भर्ती करेगा जितने वर्ष भर में हो सकने वाले रिक्त पदों के लिये आवश्यक हो।

15 परीक्षा के संचालन के लिये प्राधिकारी तथा पाठ्यक्रम—परीक्षा का संचालन जिला-यायाधीश द्वारा या वरिष्ठ-यायाधीश या मुंसिफ द्वारा, यदि ऐसी शक्ति उनमें से किसी एक को जिला-यायाधीश द्वारा प्रत्यायोजित कर दी गई हो, वर्ष के दौरान सम्भावित रिक्त स्थानों के आधार पर किया जावेगा। परीक्षा पाठ्य क्रम अनुसूची 1[1] में दिये अनुसार होगा।

16 आवेदन प्रामात्रित करना—परीक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन जिला-यायाधीश द्वारा पदों को जैसा वह उचित समझे विनापन के द्वारा प्रामात्रित किये जायेंगे और अनुसूची 1[11] में दिये गये प्रार 'क' में होगी।

2[प्रार्थी को एक रुपये की राशि आवेदन शुल्क के रूप में जिला यायालय में जमा करानी होगी।]

3[परन्तु यह है कि बर्मा और श्री लंका में। 3-1963 को या बाद

1 वि स एफ 3 (9) AC/Intg/56 दि 11-2-1960 द्वारा प्रतिस्थापित।

2 वि स एफ 3 (9) AC/Intg/56 दि 12-9-1960 द्वारा जोड़ा गया।

3 वि स एफ 1 (20) नियुक्ति (क 2) 67 दिनांक 20-9-1975 द्वारा प्रतिस्थापित।

मे तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों केनिया, टांगानिका, युगाण्डा और जजीवार से वापस लौटाये गये व्यक्ति आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा विहित प्रावेदन शुल्क के भुगतान से मुक्त रहेंगे, इस शर्त के अध्वधीन कि आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि ऐसे व्यक्ति ऐसी शुल्क देने की स्थिति में नहीं हैं।]

17 <sup>1</sup>[ विलोपित ।]

18 पक्ष समयन— इन नियमों के अधीन अर्पेक्षित बातों को छोड़ कर, भर्ती के लिये अर्पेक्षित किसी भी प्रकार की सिफारिश पर, चाहे वह लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समयन प्राप्त करने हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से किये गये प्रयत्न के कारण उस भर्ती के लिये निरहित किया जा सकेगा।

19 चयनित अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन— कुल प्राप्ताका के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के नाम योग्यता के क्रम में एक सजित्व रजिस्टर में विहित प्ररूप (फॉर्म) में प्रविष्ट किये जावेंगे और प्रत्येक प्रविष्टि पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक व लघु हस्ताक्षर किये जावेंगे।

"परंतु यह है कि कोई अभ्यर्थी, जो कुल अंकों का कम से कम 40% तथा प्रत्येक प्रश्नपत्र में कम से कम 30% अंक प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त करने में असफल रहता है, चयनित नहीं किया जायगा। यदि दो या अधिक ऐसे प्रत्यर्थी कुल में से समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उनके नाम योग्यता के क्रम में साधारण उप-युक्तता के आधार पर व्यवस्थित किये जावेंगे। अभ्युक्ति (रिमाक्स) के स्तर में उस अभ्यर्थी के सामने एक प्रविष्टि की जावेगी, जिसने आशुलिपिक के रूप में ग्रहण प्राप्त की है।

टिप्पणी— एक कर्मचारी जो नियमित पक्ति में कार्य कर रहा है आशुलिपिक के रूप में ग्रहण प्राप्त समझा जावेगा, यदि लाकसेवायोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में यह प्रमाणित कर दिया जाये कि वह 100 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि में तथा 40 शब्द प्रति मिनट टंकण में गति धारण करता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रविष्टि किया गया किसी अभ्यर्थी का नाम अदक्षता या अवधार के लिये हटाया जा सकेगा।

1 वि स एफ 3 (9) AC/Intg/56 दि 12-9 1960 द्वारा

नियम 17 व्यक्तित्व एवं मौखिक परीक्षा" विलोपित किया गया।

2 वि स एफ 3 (9) AC/Intg/56 दि 18 11 1960 द्वारा निविष्ट।

(3) यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी को उन नियम (1) के अधीन विहित सजिल्द रजिस्टर की सूची के अनुसार वरिष्ठता के कठोर क्रम में उसकी भर्ती की दिनांक से एक वर्ष के भीतर नियुक्ति नहीं दी गयी हो, तो उसका नाम भर्ती किये गये अभ्यर्थियों के रजिस्टर से स्वतः ही हटा दिया जावेगा। इसके बाद उसे अगले वर्ष में भर्ती के लिये दूसरे के साथ दुबारा अपना अवसर लेना होगा।

### भाग (5) नियुक्ति, परीक्षा तथा पुष्टीकरण

20 नियुक्ति—(1) लिपिक वर्गीय स्थापन पर समस्त नियुक्तियाँ जिला-ग्रामाधीन द्वारा की जावेगी। आशुलिपिकों के मामले के अतिरिक्त, प्रथमनियुक्ति निम्नतम पदों पर की जावेगी।

(2) आशुलिपिकों के पदों को भरने में उन कर्मचारियों को, जो विहित अहतायें धारण करते हैं और पढ़ने से ही उस जनशिव में काम कर रहे हैं जिसमें रिक्रियान हुआ है, प्राथमिकता दी जायेगी।

परन्तु यह है कि—इन नियमों के अनुसार के अग्रगण्य दी गई नियुक्ति की किसी आशा से व्यक्ति कोई व्यक्ति उच्च ग्रामालय को अपील करने का अधिकार रखेगा।

21 वरिष्ठता—पदोन्नति के प्रयोजनाथ सेवा में वरिष्ठता साधारणतया उस श्रेणी में पुष्टीकरण की आशा के दिनांक से और यदि ऐसा दिनांक एक से अधिक व्यक्ति के मामले में समान (एक ही) है, तो पिछली निम्नतर श्रेणी में उनकी सम्बन्धित स्थिति के अनुसार तय की जावेगी।

परन्तु यह है कि—किसी विशिष्ट श्रेणी के पदों पर इन नियमों के प्रवृत्त होने से पहले नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तदय आधार पर विनिश्चित, सशोधित या परिवर्तित की जावेगी।

22 परीक्षा—किसी समय में सीधी भर्ती में नियुक्त समस्त व्यक्तियों को एक वर्ष के लिये परीक्षा पर रखा जावेगा।

23 परीक्षा के दौरान असन्तोषप्रद प्रगति—(1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परीक्षा काल के दौरान किसी समय या अन्त में यह प्रतीत हो कि—परीक्षाधीन सतोष दिलाने में असफल रहा है, तो नियुक्तिप्राधिकारी उसे उक्त पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा जो उसके द्वारा अधिष्ठायी रूप से उसके परीक्षा पर नियुक्ति से सुरन्त पूर्व धारित किया गया था, परन्तु यह है कि—यह उक्त पर पदाधिकार (सिजन) धारण करता है या अन्य मामला में उसे सेवा से हटा सकेगा।

परंतु यह है कि— नियुक्ति प्राधिकारी किसी परिवीक्षाधीन की परिवीक्षा की अवधि को एक विशिष्ट अवधि के लिये बढ़ा सकेगा जो मास से अधिक नहीं होगी ।

(2) उप नियम (1) के अधीन परिवीक्षा की अवधि के दौरान या अंत में परिवर्तित या हटाया गया परिवीक्षाधीन व्यक्ति किसी प्रतिकर के लिये अधिकृत नहीं होगा ।

24 पुष्टीकरण (स्यायोकरण-क्वॉरेंटेशन)--एक परिवीक्षाधीन को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा की अवधि के अंत में स्यायी कर दिया जायेगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि—उसकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है और वह अवधि पुष्टीकरण के लिये उपयुक्त है ।

### भाग (5) वेतन

25 वेतन की दरें--सबग के पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों का वेतनमान वही होगा, जो नियम 28 में वर्णित नियमों के अनुसार ग्राह्य होगा, या जो समय समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाय ।

126 परिवीक्षा के दौरान वेतन--सेवा/सबग के पदों पर सीधी भर्ती हैं नियुक्त व्यक्तियों का प्रारम्भिक वेतन उस पद के वेतनमान का न्यूनतम होगा ।

परंतु यह है कि—उस व्यक्ति का वेतन जो पहले से ही राज्य के कायकलापो के सम्बन्ध में सेवा कर रहा है राजस्थान सेवा नियम 1951 के उपबन्धों के अनुसार स्थिर किया जावेगा ।

226 क परिवीक्षा के दौरान वेतन वृद्धि--एक परिवीक्षाधीन राजस्थान सेवा नियम 1951 के उपबन्धों के अनुसार उसे ग्राह्य वेतनमान में वेतनवृद्धि ग्राह्यित करेगा ।

27 दक्षतावरी पार करने की कसौटी--किसी सबग में नियुक्त किसी व्यक्ति को दक्षतावरी पार करने की अनुमति नहीं दी जावेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाय कि—उसने सतोषप्रद रूप से कार्य किया है और उसकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है ।

### भाग (7) अन्य उपबन्ध

28 अवकाश, भत्ते पेंशन आदि का विनियमन--इन नियमों में विहित के अतिरिक्त स्थापन का वेतन, भत्ते, पेंशन अवकाश तथा सेवा की अन्य शर्तें (निम्न

- 1 वि स एफ/(15) नियुक्ति (क-2)67 दि 18 2-1969 द्वारा प्रतिस्थापित ।
- 2 वि स 3(11) नियु (क-2)58 भाग IV दिनांक 16 10 1973 तथा शुद्धिपत्र समसंख्यक दिनांक 15 3 1974 द्वारा निविष्ट ।

लिखित) द्वारा निनियमित होगी—

- (1) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1949, यथा अद्यतन सशोधित
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान एकीकरण) नियम 1950—यथा अद्यतन सशोधित
- (3) राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान युक्तियुक्तकरण) नियम 1956—यथा अद्यतन सशोधित
- (4) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958—यथा अद्यतन सशोधित
- (5) राजस्थान सेवा नियम 1951 (यथा अद्यतन सशोधित) और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परतु के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये तथा तत्समय प्रभावशील अन्य नियम ।

### अनुसूची I

प्रतियोगी-परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम तथा नियम

(देखिये-नियम 15)

प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे तथा प्रत्येक विषय के सामने प्रकित अंक होंगे—

खण्ड - क—लिखित

- |   |          |      |   |                              |     |
|---|----------|------|---|------------------------------|-----|
| 1 | अंग्रेजी | 100, | 2 | हिन्दी                       | 100 |
| 3 | अंक गणित | 100, | 4 | सामान्य ज्ञान व आलोच्य मामले | 100 |

×खण्ड—'ख' मौखिक—बिलोपित

खण्ड क—(अनिवार्य)

1 अंग्रेजी—यह प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों की भाषा में प्रवीणता की परख करने के लिये होगा । अंग्रेजी में एक निबंध लिखने के साथ साथ, इसमें हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सारांशलेखन तथा मुहावरों के प्रयोग आदि सम्मिलित होंगे । प्रश्नपत्र का स्तर राजपूताना विश्वविद्यालय की हाई स्कूल परीक्षा के समान होगा ।

2 हिन्दी—यह प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों की भाषा में प्रवीणता की परख करने के लिये होगा । कई दिये गये विषयों में से एक पर निबंध लिखने के साथ साथ, इसमें सारांश लेखन पत्र लेखन, मुहावरों का प्रयोग आदि सम्मिलित होंगे । दो घण्टे का समय दिया जावेगा । अत्यधिक सुंदर हस्तलेख के लिये अधिकतम पांच तक वृत्तांक दिये जायेंगे ।



3 सामान्य ज्ञान—यह प्रश्नपत्र साधारण बुद्धि, अवलोकन की शक्ति और ऐसा ज्ञान जो एक अभ्यर्थी से जो स्कूल में पढ़ाये गये विषयों के साधारण आधार पर उसके चारों ओर की वस्तुओं में बुद्धिमत्तापूर्ण रुचि को बनाये रखने के लिये अपेक्षित है, की परीक्षा के लिये होगा।

4 एक गणित—यह प्रश्नपत्र अभ्यर्थी की नेमी संगणना करने में गति और शुद्धता की परीक्षा के लिये होगा।

× [खण्ड 'ख'—भौतिक परीक्षा—विलोपित]

### अनुसूची—II

प्रारूप 'क' (देखिये नियम 16)

- (1) अभ्यर्थी का नाम (मोटे अक्षरों में)
- (2) जन्म दिनांक
- (3) धर्म
- (4) आयु, जन्म दिनांक (अग्रेजी कलेंडर वष में)
- (5) पिता का नाम मय व्यवसाय
- (6) निवास स्थान
- (7) शैक्षणिक ग्रहण—(उत्तीर्ण की गई परीक्षाएँ मय श्रेणी तथा वर्षों का विवरण देते हुए)
- (8) यदि आशुलिपिक हो, तो टंकण तथा आशुलिपि की गति
- (9) क्या वह आसानी से सही व शीघ्र हिन्दी लिख व पढ़ सकता है ?
- (10) क्या अभ्यर्थी पहले या आवेदन करने के समय राज्य सरकार की सेवा में रहा है या है ? यदि हाँ, तो विभाग का पूरा विवरण दें—  
धारित पद, प्राप्त वेतन। क्या उसके कार्यालय के अध्यक्ष से ऐसा आवेदन करने की उसने अनुमति ले ली है ? और उसने सरकारी नौकरी छोड़ दी हो तो उसकी क्या परिस्थिति (कारण) रही ?
- (11) क्या प्रार्थी ने अधीनस्थ सिविल न्यायालयों के लिपिक वर्गीय स्थापना में नियुक्ति के लिए पहले कोई आवेदन किया था ? यदि हाँ तो उसका क्या परिणाम रहा ?

× वि सख्या एफ 3 (9) AC/Intg/56 दिनांक 12-9-1960 द्वारा विलोपित।

- (12) क्या यह अनुसूचित जाति/जन जाति का है ? यदि हा, तो विवरण, मय अपनी माय की पुष्टि मे किसी दण्डनायक के प्रमाण पत्र के, दीजिये ।

ह प्रार्थी

(भय दिनाक व पता)

टिप्पणी—(1) जम दिनाक वही होगी जो हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा तत्समान माय मय परीक्षा के प्रमाण पत्र म अभिलिखित है ।

(2) आवेदन मे साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र सलग्न होमे—

(क) उपरोक्त पैरा 7 मे वर्णित परीक्षायें उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र

(ख) प्रार्थी जिसमे अन्तिम बार पढा उस विद्यालय या कालेज या विश्व-विद्यालय के मुख्य शैक्षणिक अधिकारी का तथा दो सम्माय व्यक्तियों का (सम्बन्धी न हो) जो प्रार्थी के निजी जीवन के जालकार हा तथा विश्वविद्यालय, कालेज या स्कूल से सम्बन्धित नही हो, अच्छे चरित्र के प्रमाण पत्र ।

(ग) मय कोई प्रशस्ता के प्रमाण पत्र, जो प्रार्थी प्रस्तुत करना चाहे ।

— — — — —

4

## राजस्थान पंचायत-समिति तथा जिला-परिषद् सेवा नियम, 1959

[Rajasthan Panchayat Samities & Zila Parishads Service Rules, 1959]

राजस्थान पंचायत समितीज एण्ड जिला परिषदस एक्ट, 1959 की धारा 79 की उप धारा (1) और इस विषय में समय बनाने वाले समस्त प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा में भर्ती करने तथा सेवा की शर्तों का नियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है।

### राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा नियम

1 सलिप्त नाम तथा प्रारम्भ ये नियम राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा नियम, 1959 कहलायेंगे और दिनांक 2 अक्टूबर, 1959 से लागू होंगे।

2 परिभाषायें—इन नियमों में, जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात विपरीत न हो—

- (क) "एक्ट" से अभिप्राय राजस्थान पंचायत समितीज एण्ड जिला परिषदस एक्ट 1959 से है।
- (ख) "कमीशन" से अभिप्राय एक्ट की धारा 86 (6) के अन्तर्गत गठित सिलेक्शन कमीशन से है।
- (ग) "समिति" से तात्पर्य एक्ट की धारा 88 के अन्तर्गत गठित जिला स्थापना (Establishment) समिति से है।
- (घ) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय नियम 7 द्वारा निर्धारित तरीके से भर्ती करने से है।
- (ङ) "डिविजन" से अभिप्राय रेवेन्यू डिविजन से है।

और वि स एफ 3 (38) नियुक्ति (घ)—59 दिनांक 30 9 1959, राजस्थान राज-पत्र भाग 4 ग सप्ताहवार दि 1 10 1959 में प्रथम बार प्रकाशित। प्राधिकृत हस्ताक्षर—

- (च) "पूर्व नियोजित प्राधिकारी" से अभिप्राय इन नियमों के प्रवर्तन के पहिले नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से है।
- (छ) "सरकार" से अभिप्राय राजस्थान सरकार से है।
- (ज) "पंचायत समिति" तथा "जिला परिषद्" से अभिप्राय एक्ट के अंतर्गत गठित पंचायत समिति तथा जिला परिषद् से है।
- (झ) "सेवा का सदस्य" से अभिप्राय इन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत "सेवा में किसी पद पर भूला (Substantively) नियुक्त किसी व्यक्ति से है।
- (ञ) "अनुसूची" से अभिप्राय इन नियमों के साथ लगी अनुसूची से है।
- (ट) "सेवा से अभिप्राय राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा से है।
- (ठ) "राज्य" से अभिप्राय राजस्थान राज्य से है।
- (ड) "विकास अधिकारी" से अभिप्राय एक्ट की धारा 26 के अंतर्गत विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी से है।
- (ढ) "नियोजक प्राधिकारी" से अभिप्राय, जैसी भी स्थिति हो, पंचायत समिति या जिला परिषद् से है।
- (ण) "राज्य की सचिव निधि" से अभिप्राय भारत के सचिवान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत राज्य के लिए गठित निधि से है।
- (त) "चिकित्सा अधिकारी" से अभिप्राय जिला चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी अथवा प्रधान चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा ऐसे चिकित्सा अधिकारी से है जो सी ए एस ग्रेड I के पद से नीचे का न हो।
- (थ) "निम्नतम ग्रेड" (Lowest grade) से अभिप्राय पदों की एक ही वर्ग (Category) में भिन्न भिन्न अर्हताओं (Qualifications) तथा अनुभव के लिये निम्नतम ग्रेड से है।

3 सत्या—सेवा में कमचारियों की तादाद उतनी होगी जो प्रत्येक पंचायत समिति के लिए एक्ट की धारा 31 के अंतर्गत और प्रत्येक जिला परिषद् के लिए एक्ट की धारा 60 के अंतर्गत समय समय पर नियत की जाय।

4 सेवा में पदों के वर्ग (1) सेवा में पदों के वर्ग निम्नलिखित होंगे —

- (1) ग्राम सेवक। (2) ग्राम सेविकाएँ।
- (3) प्राथमिक पाठशाला अध्यापक। (4) फील्ड मैन।
- (5) स्टॉक मैन। (6) स्टॉक सहायक।
- (7) पशु चिकित्सा वम्पाउट्टर।

- (8) कुक्कुट पालन प्रदर्शक (Poultry Demonstrator) ।
- (9) भेड तथा ऊन पयवेसक ।      (10) ड्रेस
- (11) टीका लगाने वाले ।
- (12) (1) उच्च लिपिक (जिनमे सेखा लिपिक भी शामिल है)  
(2) लिपिक (जिनमे टाईपिस्ट भी शामिल हैं) ।
- (13) ड्राईवर ।      (14) प्रोजेक्टर चालक ।
- (15) मेट (उद्योग)      1(16) ग्रुप पंचायत सचिव ।
- 2(17) कार्यालय सहायक ।

प्रत्येक वर्ग को विभिन्न ग्रेड्स में विभाजित किया जा सकेगा जसा कि अनुसूची में दिया गया है ।

3[टिप्पणी—ग्रुप पंचायत सचिवों तथा ग्राम सेवकों के पद पर और स्ट्राक मैन तथा पशु चिकित्सा कम्पाउण्डर के पद आपस में समान तथा पारस्परिक स्थानांतरणीय होंगे ।]

(2) सरकार, अर्थात् 4 के पदों को छोड़कर, किसी अन्य पद के वर्ग को सेवा में संलग्न (Encadre) कर सकेगी ।

5 सेवा का आरम्भिक गठन—(1) सेवा के गठन के तत्काल पूर्व सेवा में सम्मिलित भिन्न भिन्न वर्गों के पदों पर नियुक्त सारे व्यक्ति पंचायत समिति या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा, इन नियमों के प्रावधानों के अधीन उन पदों पर 4[XXX] नियुक्त किये गये समझे जावेंगे

किंतु शत यह है कि कोई स्थायी सरकारी कर्मचारी इन नियमों के लागू होने के 90 दिन के भीतर सेवा का सदस्य न बनने की अपनी इच्छा का प्रयोग कर सकेगा । उस दशा में पूर्व नियोजन प्राधिकारी, राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसी कामवाही कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे

1 वि स एफ 4/L/PS/AR/13/92/12863 दिनांक 30-10-67 द्वारा निविष्ट ।

2 वि स एफ 4/L/PS/AR/7/70/1840-49 दिनांक 29-4-1971 द्वारा निविष्ट ।

3 वि स एफ 41/L/PS/AR/9/70/1289-98 दिनांक 25-3-1971 द्वारा प्रतिस्थापित ।

4 शब्द "मूलतः" विलोपित—राज प स जि प सेवा (संशोधन) नियम 1969 द्वारा जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ग) दिनांक 8-1-1968 पृ 723 पर प्रकाशित ।

किंतु शत यह भी है कि कोई अस्थायी सरकारी कर्मचारी का, इन नियमों के लागू होने के 30 दिन के भीतर, सेवा का सदस्य न बनने की अपनी इच्छा का प्रयोग कर सकेगा और उस दशा में पूर्व नियोजन प्राधिकारी, राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत, उसकी नौकरी खत्म कर देगा।

टिप्पणी—वे व्यक्ति जो प्रारम्भ में ग्राम सेवक के रूप में नियुक्त किये गये थे, किंतु अक्टूबर 1959 के दूसरे दिन को उसके समतुल्य या उच्चतर पद की सेवा में वर्गीकृत नहीं किये गये थे, स्थापना सदन या अस्थायी रूप से धारण किये हुए थे वह 2.10.59 को भी ग्राम सेवक के रूप में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त समझा जावेगा और उनके ग्राम सेवक के रूप में प्रतिवर्तन होने तक सबके पदा पर प्रति नियुक्ति पर समझा जावेगा]

(2) कोई कर्मचारी, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, जो सेवा का सदस्य न बनने की अपनी इच्छा का उप नियम (1) के परन्तुको के अन्तर्गत प्रयोग करता है उस राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत, दिनांक 2 अक्टूबर, 1959 से सेवा मुक्त किये जाने का नोटिस दे दिया गया समझा जायेगा और 2 अक्टूबर, 1959 से, जब तक कि पूर्व नियोजन प्राधिकारी उसे अन्य पद पर न लगाने दे या राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत सेवा से मुक्त न कर दें, वह पंचायत समिति या जिला परिषद् जैसी भी स्थिति हो, की सेवाय प्रतिनियुक्त किया गया (On deputation) समझा जावेगा।

(3) किसी अन्य वर्ग के पदों के कर्मचारियों जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् नियम 4 (2) के अधीन वर्गीकृत किये जाय, के साथ भी इस नियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार ही व्यवहार किया जायेगा।

6 भर्ती का स्त्रोत — इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् रिक्त स्थान निम्न रीति से भरे जायेंगे —

(क) प्रत्येक वर्ग के निम्नतम ग्रेड में सीधी भर्ती करके।

(ख) उसी वर्ग में निचले ग्रेड से ऊँचे में पदोन्नति (तर्फ़ी) करके।

(ग) किसी पंचायत समिति, जिला परिषद् या सरकार के अधीन समानु रूप पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों का तबादला करके

किंतु शत यह है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का, उसकी पूर्व सहमति के बिना, सेवा में तबादला नहीं किया जायेगा।

7 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए रिक्त स्थानों का आरक्षण — (1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए रिक्त स्थानों का आरक्षण, सरकार द्वारा जारी की गई उस समय प्रवृत्त आज्ञाओं के अनुसार

किया जावेगा। भूतपूर्व संनिको के निते वष भर के कुल रिक्त स्थानो का 12½% आरक्षण होगा।

(2) इस प्रकार आरक्षित रिक्त स्थानो को भरने में, उन अर्ह्यधियों की नियुक्ति के लिये, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्य हैं उसी क्रम में दूसरे अर्ह्यधियों के साथ उनकी सङ्घित श्रेणी पर विचार किए बिना विचार किया जायेगा, जिसमें उनके नाम सूची में हैं।

(3) यदि इस प्रकार आरक्षित सभी रिक्त स्थानो को भरने के लिये पर्याप्त सदस्य में ऐसे अर्ह्यधियों उपलब्ध न हो जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं, तो शेष रिक्त स्थान सूची में से अन्य अर्ह्यधियों की नियुक्ति द्वारा भर लिये जायेंगे और उसके समान सस्या में अरिर्रिक्त रिक्त स्थान अगले वष में भरने के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के अर्ह्यधियों के लिये आरक्षित किये जायेंगे।

परंतु यह है कि—यदि पर्याप्त सस्या में उपयुक्त अर्ह्यधियों जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के हैं, कथित परीक्षा/चयन या साक्षात्कार के परिणाम स्वरूप दूसरे वष में (भी) सब रिक्त स्थानो को भरने के लिये उपलब्ध न हो, तो अतिरिक्त रिक्त स्थान या उनमें से ऐसे जो भरे नहीं गये समाप्त (लेप्त) हा जायेंगे।

टिप्पणी—आरक्षण कुल रिक्त स्थानो के आधार पर सङ्घित किया जायेगा। पांच वष की अवधि के ऊपर रुढाको (अशा) का समायोजन कर लिया जायेगा।

(4) पदोन्नति के लिये कोई आरक्षण नहीं होगा।

18 रिक्त स्थानों का निश्चित किया जाना—इन नियमों के प्रावधानों और सरकार के निदेशों यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए पंचायत समिति या जिला परिषद प्रत्येक वष में दो बार अवधि—पहली जनवरी और पहली जुलाई को आगामी छ मास की अवधि में प्रत्येक वष के भीतर प्रत्याशित रिक्त स्थानो की सस्या और भर्ती किये जा सकने वाले व्यक्तियों की सस्या निश्चित करेगी और आयोग को ससूचित करेगी।

9 राष्ट्रीयता—सेवा में नियुक्ति का कोई उम्मीदवार —

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए या

(ख) सिक्किम का प्रजाजन होना चाहिए, या

1 विनपति जी एस आर 392(2) दिनांक 27-1 1971 द्वारा प्रतिस्थापित, जो राजस्थान राज पत्र भाग 4 (ग) I दि 3 2-1972 पृष्ठ 499(48) पर प्रकाशित।

(ग) नेपाल या भारत के भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्ती (French Possession) का प्रजाजन होना चाहिए, या ।

(घ) भारत में मूल निवास करने वाला ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो स्थायी रूप से भारत में बसने के इरादे से पाकिस्तान से भारत की प्रव्रजन कर माया है

किन्तु शर्त यह है कि यदि वह वग (ग) तथा (घ) में बतनाया गया व्यक्ति है तो वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र दे दिया गया हो

परन्तु यह शर्त और भी है कि यदि वह वग (घ) के अधीन आता हो तो पात्रता प्रमाण-पत्र उसकी नियुक्ति की तारीख से केवल एक वर्ष की अवधि के लिए ही मान्य होगा जिसके उपरान्त कि उसे सेवा में उसी स्थिति में रखा जा सकेगा जब वह भारत का नागरिक हो जाय

जिस उम्मीदवार की दशा में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, उसको कमीशन द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा अथवा साक्षात्कार में प्रवेश मिल सकेगा और उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिये जाने की शर्त के अधीन अस्थायी रूप में भी नियुक्त किया जा सकेगा ।

10 आयु —सीधी भर्ती के लिए किसी भी उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक होगा कि उसके द्वारा आवेदन किये जाने की तारीख में आगे आने वाली जनवरी के पहिले दिन उसकी आयु 16 वय से कम और 25 वय से अधिक नहीं होनी चाहिए किन्तु शर्त यह है कि —

(1) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के किसी उम्मीदवार की दशा में उच्चतर आयु की सीमा 30 वय होगी ।

(2) भूतपूर्व सैनिकों की दशा में उच्चतर आयु की सीमा 50 वर्ष होगी ।

(3) जागीरदारों के पुत्रों को सम्मिलित करते हुए ऐसे जागीरदारों जिनके कि पास उनके निर्वाह के लिए कोई उप जागीर नहीं थी की दशा में उच्चतर आयु की सीमा 31 दिसम्बर, 1963 तक, 40 वय होगी ।

(4) उन व्यक्तियों के लिये उच्च आयुसीमा, जो ग्राम पंचायत/न्याय पंचायत के सचिवों के रूप में पहले से कार्य कर रहे थे, उनके द्वारा पंचायत सचिव के रूप में की गई सेवा की अवधि तक, अधिकतम तीन वर्षों तक, शिथिल की जाएगी ।

(5) महिलाओं के लिये उच्च आयु सीमा 35 वय होगी ।

(6) ऐसे व्यक्तियों के लिये उच्च आयु सीमा, जो पंचायत समिति/जिला परिषद के अधीन उनकी अस्थाई नियुक्ति पर विहित आयु सीमा में थे, उनके द्वारा



पचापन समिति जिसे परिपद के अधीन की गई सेवा की अवधि तक नियम की जा सकेगी,

परन्तु यह भी है कि—उच्च प्रायः सीमा सम्बन्धी प्रतिवर्षीय व्ययों का मामलो में लागू नहीं होगी, जो चर्चित के और सरकार द्वारा आयोजित प्रमाण में 31 दिसम्बर 1961 के पूर्व भेजे गये थे।

(7) तृतीय श्रेणी के प्राथमिक शान्ति निगरानों के लिये उच्च प्रायः सीमा 30 वर्ष होगी।

परन्तु यह भी है कि—यदि इन नियमों में विहित प्रायः सीमा में उन्मुख व्ययों किसी विशिष्ट वर्ष में या किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हैं, ऐसा माना जाने पर प्रायोगिक उच्च प्रायः सीमा में 5 वर्ष की छूट दे सकेंगे। ऐसी छूट यन्त्रण, सेवा के सम्पूर्ण प्रयोग के लिये दी जायेगी न कि व्यक्तिगत मामले या मामलों में।

[टिप्पण—विशेषित XX]

11. शैक्षणिक महत्ताएँ तथा सहकारी, वृत्तिकाइय, सेवा-सेवा के विभिन्न वर्गों में भर्ती होने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी सुनतम शैक्षणिक, टेक्निकल, योग्यताएँ एवं अनुभव आवश्यक है जो कि इन नियमों के साथ सभी अनुसूची में दिये गये हैं।

12. धरित्र—सेवा में सीधी भर्ती चाहने वाले उम्मीदवार को चाहिये कि वह कमीशन को ऐसे विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल अथवा संस्था जहाँ उसने सबसे अतः में शिक्षा प्राप्त की है, के प्रचार शिक्का अधिकारी का सचचरित्र होने का एक प्रमाण-पत्र तथा ऐम ही दो और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें जो उसे ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा दिये गये हों जिनका नाम उसके (उम्मीदवार के) विश्व विद्यालय, कॉलेज, या उसकी संस्था से संबंध हो और जो न उसके संबंधी हों तथा जो (प्रमाण-पत्र) आवेदन करने की तारीख से छह महीने की अवधि से पहले के लिये हुए न हों।

नोट—आयातन द्वारा दोषसिद्धि से ही यह आवश्यक नहीं हो जाता कि सचचरित्रता के प्रमाण पत्र को प्रस्वीकार कर दिया जाय। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और यदि उनमें कोई नैतिक पतन या हिंसा संबंधी अपराधों से सम्पर्क न पाया जाय या विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक साधनों द्वारा उत्पन्न जिसका उद्देश्य हो ऐसे आंदोलन से सम्पर्क न पाया जाय तो केवल मात्र दोषसिद्धि को ही निर्णायकता नहीं समझा जाना चाहिए।

13. शारीरिक योग्यता—सेवा में सीधी भर्ती चाहने वाले उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वह मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से अच्छी तरह स्वस्थ हो और ऐसे किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के

रूप में उसके द्वारा अपने कर्तव्य का कुशलता से निर्वहन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो और यदि वह नियुक्ति के लिए चुन लिया जाय तो उसे चिकित्सा अधिकारी से लेकर उसे आशय का एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिए।

14 पत्र समायन (Convincing) — भर्ती के लिए किसी भी सिफारिश पर चार वह लिखित हो या जबानी सिवाय उसके जो नियमों के अधीन अपेक्षित हो, ध्यान नहीं दिया जायगा। यदि कोई उम्मीदवार और तरीका से प्रत्यक्ष रूप में प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप में अपनी उम्मीदवारी को पक्ष में सहायता प्राप्त करने का कोई भी प्रयत्न करेगा तो उस अनिहित (Disqualify) किया जा सकेगा।

### भाग 3 — सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया

15 आवेदन पत्र आमंत्रित करना — (1) पंचायत समितियों प्रत्यक्ष जिला परिषदों द्वारा सेवा में सीधी भर्ती के लिये कमीशन संभाग की जाने पर कमीशन द्वारा ऐसे तरीके से, जो वह ठीक समझे आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।

× [परन्तु सेवा में सीधी भर्ती के लिये सरकार भी मति कर सकती है।]

16 आवेदन पत्र का काम — आवेदन कमीशन द्वारा निर्धारित काम में दिया जायगा जो कमीशन द्वारा सचयन किये गये अधिकारियों से तथा ऐसी फीस देन पर जो कमीशन द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाय, प्राप्त किया जा सकेगा।

17 आवेदन पत्रों की जांच — कमीशन उसके द्वारा प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की जांच करेगा और उन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए अर्हित उम्मीदवारों में से इतने उम्मीदवारों से, जितने उसे ठीक लगे, अपने सचयन साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा।

×× [परन्तु वर्ष 1973-74 के लिये पंचायत प्राथमिक शीलाग्रों के अध्ययन के पदों की सीधी भर्ती के लिये कमीशन अध्ययनों की उपयुक्तता को उनकी योग्यताओं और अनुभव आदि के आधार पर, उनको साक्षात्कार में बुलाये बिना, मूल्यांकन कर सकेगा]

18 आवेदन पत्रों की जांच — कमीशन उसके द्वारा प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की जांच करेगा और उन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए अर्हित उम्मीदवारों में से इतने उम्मीदवारों से, जितने उसे ठीक लगे, अपने सचयन साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा।

× वि.स.एफ. 4/L/PS/AR/13/67-68/7929 दिनांक 15.7.1968 द्वारा निविष्ट।

×× वि.स.एफ. 4/L/PS/AR/2/73/1282 दिनांक 14.6.1973 द्वारा जारी किया।

× [17-क—पंचायत-सचिवों का सेवा में आमेसन—

××[(1) आगे के नियमों में किसी बात के होते हुए भी, वे व्यक्ति जो पंचायत सचिवों का पद धारण कर रहे हैं, ग्राम सेवक या ग्रुप पंचायत सचिव के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होंगे, परंतु वह मिडिल पास हैं और इस नियम के उप नियम (2) में वर्णित सूची बनाने के समय 45 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं हैं।]

(2) राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत में 'ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव' तथा पंचायतों के समूह में 'ग्रुप पंचायत सचिव' नियुक्त करने की योजना के अनुसरण में, श्रेणीबद्ध कार्यक्रम (फ्रेड प्रोग्राम) के अनुसार, ऐसे सचिवों की एक सूची तैयार करेगी, जो ग्राम सेवक या ग्रुप पंचायत सचिवों के रूप में आमेसन के लिये उपयुक्त हो और उस सूची को कमीशन को भेजेगी।

(3) कमीशन ऐसी सूची प्राप्त होने पर उस सूची की जाच पड़ताल कर उनमें से ऐसी का ग्राम सेवक या ग्रुप-पंचायत सचिव के रूप में नियुक्ति के लिये चयन करेगा, जो इस नियम के उप नियम (1) में वर्णित योग्यताओं और शर्तों को पूरा करते हो। कमीशन ऐसे व्यक्तियों की जिले वार योग्यता सूची तैयार करेगा और उसे सम्बंधित जिले की 'जिला स्थापन समिति' को पंचायत समितियों को नियम 18 (2) के अधीन घावटन तथा नियम 19 के अधीन पंचायत समिति द्वारा नियुक्ति के लिये सप्रेषित करेगा।

18 कमीशन की सिफारिशें—(1) कमीशन, जिले में प्रत्येक श्रेणी या वर्ग के पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले उम्मीदवारों की योग्यता नुसार जिलावार सूची तैयार करेगा और उस सूची को संबंधित जिला स्थापना समिति के पास भेज देगा।

<sup>1</sup>[परन्तु यह है कि—(1) कमीशन द्वारा तैयार की गई योग्यतासूची में अभ्यर्थियों की संख्या ऐसी योग्यता सूची बनाने के समय रिक्त स्थानों की वास्तव में उपलब्ध संख्या के एवं तथा आधा वार (बेड गुणा) से अधिक नहीं होगी, (ii) इस प्रकार बनाई गयी अभ्यर्थियों की योग्यता सूची इसके बनाने के दिनांक से छ

× वि सख्या F 4/L/PS/AR/8/66/13022 दिनांक 24 6-66 द्वारा जोड़ा गया।

×× वि सख्या एफ 4/L/PS/AR/1/77/129 दिनांक 28 मार्च 1977 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>1</sup> GSR 392 दि 27-11-1972 जो राजपत्र में दि 3 2 72 को पृष्ठ 489(48) पर प्रकाशित, द्वारा जोड़ा गया।

मास की अवधि के लिये बंध रही। ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद यह समाप्त (लेप्त) हुई समझी जावेगी।]

(2) जिला स्थापना समिति, पंचायत समितियों अथवा जिला परिषद् से मांग की जाने पर सूची में से ऐसे क्रम से जिसमें कि सूची में उनके नाम दिये हुए हों, उम्मीदवार भ्रष्टा करेगी। पंचायत समितियाँ अथवा जिला परिषद् जिला स्थापना समिति के पास अपनी मांगें (Requisition) भेजते समय नियम 7 की प्रपेक्षाओं को ध्यान में रखेगी।

2[18 क—राज्य सरकार द्वारा आबटन—(1) राज्य सरकार किसी जिले की सूची में से जहाँ रिक्तस्थान नहीं हैं, किसी दूसरे जिले की अभ्याप्तियों को योग्यता के क्रम में आबटन कर सकेगी, जहाँ नियुक्ति के लिये रिक्त स्थान हों, परन्तु यह है कि—पिछले जिले की जिलेवार सूची में कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो।

(11) ऐसे अभ्याप्तियों के आबटन के लिये जिला स्थापन समिति नियम 18 के उप नियम (2) में विहित तरीके का अनुसरण करेगी।]

[18 ख—विलोपित दि 2 दिसम्बर 1977]

19 पंचायत समितियों अथवा जिला परिषद् द्वारा नियुक्ति—पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् जिला स्थापन समिति द्वारा भ्रष्टा किये उम्मीदवारों को ऐसे क्रम से नियुक्त करेगी जिसमें कि जिला स्थापना समिति द्वारा उनके नाम प्रेषित किये गये हैं।

परन्तु यह है कि—किसी समय रिक्तस्थान की पूर्ति के लिये पंचायत समिति में अभ्यापक के पद के लिये अयनित अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा तैयार की गई योग्यता-सूची में से तदर्थ नियुक्ति की जा सकेगी।]

419 -क(1) —नियम 15 से 19 के उपबन्धों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी उन कनिष्ठ लिपिकों पर आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा कनिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्ति के लिये उनकी उपयोगिता का निर्धारण करने हेतु विचार किया

2 G S R 21 दि 20 1-1970 द्वारा जोड़ा गया जो राजपत्र दि 14-5 70 को पृष्ठ 83 पर प्रकाशित।

3 वि स एफ 4/L/PS/AR/4/75/92 दि 31 जनवरी 1976 द्वारा जोड़ा गया। जी एस आर, 258 (16)।

4 वि स एफ 4/L/PS/AR/1/73/1708-16 दि 3 दिसम्बर 1973 द्वारा जोड़ा गया।

जायगा जिनकी अस्थायी आधार पर, नियुक्ति तारीख 1-4-1971 से पूर्व, इन नियमों के अनुसरण में सीधी भर्ती किये जाने तक, पंचायत समितियों या जिला परिषदों द्वारा की गयी थी, और जो उसके पश्चात् निरन्तर सेवामें हो परन्तु यह कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाय —

(1) जिन कनिष्ठ लिपिकों का चयन नहीं किया गया है वे संकड़ी/मैट्रिक्यूलेशन या हायर सेंकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिये,

(11) ऐसे चयन न किये गये कनिष्ठ लिपिक उम्मीदवारों की वापिक गोपनीय रिपोर्ट सत्यापन के हो

(11) पंचायत समिति का विकास अधिकारी या जिला परिषद का सचिव यह प्रमाण पत्र दे कि चयन न किये गये कनिष्ठ लिपिक ने कार्यालय प्रक्रिया का पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर लिया है और यह कि ऐसे कनिष्ठ लिपिक की सत्यनिष्ठा के बारे में सदेह उत्पन्न करने वाली कोई बात उसके ध्यान में नहीं आई है, और

(iv) इस नियम के अधीन अतिरिक्त चयन न किये गये व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए सीधी भर्ती द्वारा भरे गये कनिष्ठ लिपिकों के पदों की कुल संख्या के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के विहित अनुपात का सहायण किया जाय।

(2) आयोग इन कनिष्ठ लिपिकों पर उस जिले के आधार पर विचार करेगा जिनमें उनका पदस्थापन 1 अक्टूबर 1972 को किया गया था और आयोग निर्धारित उपयुक्त व्यक्ति का आइटन उस पंचायत समिति या जिला परिषद की जिला स्थापना समिति द्वारा किया जायगा जहाँ उनका पदस्थापन 1 अक्टूबर 1972 को था।

(3) सम्बन्धित पंचायत समिति या जिला परिषद व्यक्तियों को नियमित नियुक्ति उन पदों पर तब करेगी जब वे स्पष्ट रिक्त हो परन्तु यदि ऐसी रिक्त विद्यमान न हो तो उस कनिष्ठ लिपिक को सेवा तुरन्त समाप्त कर दी जायगी।

भाग 4 - पदोन्नति (तरक्की) तथा स्थानांतरण द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

20 चयन (सिलेक्शन) के लिये कसौटी — (1) तरक्की के प्रयोजनों के हेतु जिले के भीतर सेवा कर रहे सेवा के उन सदस्यों में से जो ऐसी तरक्की के पात्र हो, सीनियरिटी एवं योग्यता के आधार पर अनुसूची के स्लेम 5 व 6 के प्रावधानों के अनुसार चुनाव (सिलेक्शन) किया जायगा

परन्तु यह कि — (1) नियमों के अधीन सेवा के अतिरिक्त सदस्य और

विनोद एफ 4/L/PS/AR/11/69/6748 दिना 20 8 1969 द्वारा जोड़ा गया, सापत्र नं० 30 10 1969 में पृष्ठ 173 पर प्रकाशित।

पंचायत समिति व जिला परिषद धनुर्य श्रेणी सेवा नियम 1959 के अधीन सेवा के अधिष्ठायी सदस्य, जो इन नियमों के नियम 11 के अधीन विहित शर्तों के अनुसार मेधा म किसी अन्य उच्चतर पद के लिये अर्पण पात्र है, इस अर्थोप में दिये गये तरीके से पदोन्नति के द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्त किया जा सकेंगे। ऐसी नियुक्तियां, येन केन, इन नियमों के नियम 25 से 27 तक के उपबंधों के अधीन होना चाहिये।

(2) पदोन्नति (सरकारी) के लिए उम्मीदवारों का चुनाव (सिलेक्शन) करने में —

- (क) उनकी टैकनिकल अर्हताएं तथा ज्ञान,
  - (ख) उनके धनुर्य, काम करने की शक्ति तथा बुद्धि,
  - (ग) उनकी ईमानदारी, तथा
  - (घ) उनकी सेवा के पूर्व रिकार्ड।
- का ध्यान रखा जायेगा।

21 ध्यान (सिलेक्शन) की प्रक्रिया — जब सभी भी सेवा की विभिन्न श्रेणियों तथा वर्गों में रिक्त स्थानों के द्वारा भरे जाने हों तो जिला स्थापना समिति, पंचायत समिति, अथवा जिला परिषदों से सिकांरित आमंत्रित करेगी, जिन व्यक्तियों के सम्बन्ध में, सरकारी के लिए सिकांरित की गई है तथा जिनको अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव है, प्राप्त हुई सिकांरितों तथा उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (Annual Confidential reports) तथा उनके सेवा संबंधी अन्य रिकार्ड पर विचार करने के पश्चात् उन व्यक्तियों को जो उस श्रेणी एवं वर्ग में सीनियोरिटी के अनुसार सरकारी के लिए उपयुक्त हैं जिलावार सूची तैयार करेगी और यदि किंहीं व्यक्तियों का अधिकरण किया गया हो तो उनके कारण बतलायेगी।

22 (1) पंचायत समितियों अथवा जिला परिषदों में मार्ग मार्ग पर जिला स्थापना समिति जिलावार सूची में से व्यक्तियों को उसी क्रम से भर्त करेगी जिसमें कि उनके नाम ऐसी सूची में आये हों।

(2) जिला स्थापना समिति से व्यक्तियों के अलॉट (Allot) किये जाने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर पंचायत समिति अथवा जिला परिषद इस प्रकार अलॉट किये गये व्यक्तियों को उन पदों पर नियुक्त करेगी जिनके लिए कमेटो द्वारा उनका चुनाव (सिलेक्शन) किया गया है।

22 क—एक सरकारी कर्मचारी का सेवा के पदों पर स्थानांतरण—पंचायत समिति या जिला परिषद इस प्रकार की मांग प्राप्त होने पर कि—सेवा में किसी पद पर पदोन्नति से या अन्य पंचायत समिति या जिला परिषद में स्थानांतरण से नियुक्ति के लिये सेवा का कोई सदस्य उपलब्ध नहीं है और वह पद सेवा के पद के समान

राज्य की सेवा में पद धारण करने वाले व्यक्ति के स्थानान्तर द्वारा भरा जाना है, तो जिलाधिकारी (कसबटर) ऐसे सरकारी कर्मचारी की सहमति और सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की अनुमति के बाद जिसा स्थापन समिति को ऐसे व्यक्ति के स्थानान्तर के लिये सिफारिश भेजेगा। अब समिति ऐसे व्यक्ति को सम्बन्धित पंचायत समिति या जिला परिषद् को आवंटित करेगी। इसके बाद सम्बद्ध पंचायत समिति या जिला परिषद् इस प्रकार आवंटित व्यक्ति को राजस्थान पंचायत समिति (विकास अधिकारियों, प्रसार अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की शर्तें) नियम 1959 में वर्णित शर्तों पर उस पद पर नियुक्त करेगी।

22 ख—पदों की कटौती/समाप्ति पर अधिशेष हुए सरकारी कर्मचारियों की सेवा के स्थानान्तर द्वारा भर्ती—(1) जब सरकार के अधीन पदों की कटौती/समाप्ति के कारण एक कर्मचारी अधिशेष हो जाता है या होने वाला है, तो उसे उसकी सहमति से स्थानान्तर द्वारा सेवा में, इस नियम में दिये वर्णित तरीके से, उस पद पर नियुक्त किया जा सकेगा, जिसे सरकार ऐसे सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके स्थानान्तर के तुरन्त पहले धारित पद के समतुल्य धोषित करे।

(2) सरकार के अधीन अधिशेष किये गये ऐसे व्यक्तियों की सूची कमीशन को भेजी जावेगी, जो उसमें से सेवा के पदों के लिये प्रत्येक जिले के लिए व्यक्तियों का चयन करेगा और इस प्रकार चयनित व्यक्तियों को पंचायत समिति/जिला परिषद् को ऐसी प स/जि प में विद्यमान रिक्तस्थानों की संख्या की सीमा तक आवंटित करेगा। कमीशन को भेजी गई सूची की एक प्रति साथ साथ सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को भी भेजी जावेगी।

(3) पंचायत समिति या जिला परिषद्, यथास्थिति, इस प्रकार आवंटित व्यक्ति को समानीकृत पद पर ऐसी शर्तों पर जो लागू हो नियुक्त करेगी।

1[22 खख—सरकार की सेवा में प्रतिवर्ती प्रतिनियुक्ति—(1) पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध बाह्य सेवा में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा, परन्तु यह नियम राज्य सरकार की सेवा के ऐसे सदस्य के स्थानान्तरण पर लागू नहीं होगा।

(2) बाह्य सेवा में व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति उन निबन्धनों और शर्तों द्वारा शासित होगी, जो बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने वाले सरकारी कर्मचारियों

1 वि स एफ 4/एल जे/ए धार/पी टी/15/78/330 जी एस धार 87 दिनांक 19 अगस्त 1978 द्वारा जोड़ा गया। राजपत्र में दि 21-9-78 पृ 262 पर प्रकाशित। (1979 RLT-II 421)

पर लागू होती है, परन्तु राज्य सरकार की सेवा में प्रतिनियुक्ति [पर स्थानान्तरित व्यक्ति को कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा]

22ग—पदों की कटौती/समाप्ति पर अधिशेष हुए सेवा के सदस्यों का भ्रामेत्तन—(1) सेवा में कुछ पदों की कटौती/समाप्ति पर, पंचायत समिति/जिला परिषद द्वारा अधिशेष हुए व्यक्तियों की सूची सरकार को और एक प्रति जिलाधिकारी (क्लेक्टर) को संप्रेषित की जायेगी जिसके आधार पर सरकार इस प्रकार सेवा में अधिशेष हुए व्यक्तियों की जिलेवार सूची बनायेगी।

(2) ऐसे अधिशेष हुए कमचारी वग की सूची, जो तब सेवा में विद्यमान रिक्त पदों की सराया के अनुसार या समान पदों पर या सेवा के कटौती में लाये गये पदों के समतुल्य सरकार द्वारा घोषित पदों पर जिले के भीतर भ्रामेत्तित किये जा सकते हैं सरकार द्वारा जिला स्थापना समिति को भेजी जायेगी,

(3) ऐसे व्यक्तियों को सम्बन्धित पंचायत समिति या जिला परिषद को समिति तदनुसार आवंटित करेगी, जो ऐसे आवंटित व्यक्तियों को समान पदों पर या समतुल्य पदों पर सेवा में ऐसे समतुल्य पदों के लिये लागू निर्वाचनों और शर्तों के अनुसार नियुक्त करेंगी।

(4) ऐसे व्यक्तियों की एक सूची जिनको जिले के बाहर भ्रामेत्तित करना प्रस्तावित है, सरकार द्वारा कमिशन को भेजी जावेगी, जो नियम 22-ख के उप नियम (2) व (3) में विहित तरीके का पालन करते हुए सिवाय विभागाध्यक्ष को भ्रामेत्तित किये जाने वाले व्यक्तियों की सूची भेजने के, उनको सेवा में समान पदों या समतुल्य पदों पर भ्रामेत्तित करेगा।

#### सम्पादकीय टिप्पणी

(1) कृषि विभाग का कम्प्लेस्ट इन्स्पेक्टर (खाद निरीक्षक) का पद ग्राम सेवक (सलेक्शन ग्रेड) के समतुल्य घोषित किया गया है।

[वि स एफ 135 (7) (4) OCD/Insp/P D/63/18320 दि 30-9-1963 द्वारा, जो राजपत्र में दि 5-12-1963 को प्रकाशित हुई]

(2) ग्रुप पंचायत सचिव पद ग्राम सेवक के समतुल्य है।

[वि स एफ 4/L/PS/AR/13/67/12864 दि 30-11-1967 द्वारा।]

(3) फील्डमैन (जूनियर) ग्राम सेवक (जूनियर) के बराबर और फील्डमैन (सीनियर) ग्राम सेवक (सीनियर) के बराबर तथा ग्राम सेविका प्राथमिक शाला शिक्षिका के बराबर समतुल्य घोषित किये गये हैं।

[वि स एफ 135 (7) (4) OCD/Insp/P D/63/18371 दि 30-9-1963, जो राजपत्र में दि 5-12-1963 को प्रकाशित हुई]



### भाग 5-स्थायी नियुक्तियाँ

23 (1) उस प्रवस्था में जब कि कोई चुनाव (सिनेकतन) 7 किया गया हो या किसी रिक्त स्थान भरने के लिए कमिशन द्वारा चुना गया व्यक्ति किसी समय उपलब्ध न हो तो नियोजक प्राधिकारी द्वारा, ऐसी प्रवधि के लिए छ महीने स अधिक नहीं होगी, नियुक्ति की जा सकेगी बसतें कि ऐसी रिक्ति का भरा जाना अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित हो।

(2) यदि ऐसे रिक्त स्थान के सीधी मर्ती द्वारा प्रसाईं तीर पर भरे जाने का प्रस्ताव हो तो निवृत्ततम सेवा योजना कार्यालय (Employment Exchange) स अपेक्षित प्रहताए रखने वाले इतने व्यक्तिया के इतने इतने नामों की एर तालिका भेजने की कहा जाय जिसमें इस प्रकार भरी जान वाली रिक्तिया की सख्या स कम से कम पांच गुने नाम हो। तत्पश्चात नियोजक प्राधिकारी पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की तालिका में से नियुक्त करेगा।

(3) यदि रिक्त स्थान की तरबकी द्वारा प्रस्थापी एर स भरे जाने का प्रस्ताव हो तो नियोजक प्राधिकारी द्वारा भगली निम्न श्रेणी म स सबसे सीनियर कमचारी इस प्रकार नियुक्त किया जा सकेगा।

किन्तु शत यह है कि तब से सीनियर कमचारी का रिकार्ड सनीपजनक न हो तो वह व्यक्ति जिसका नाम उसके ठीक नीचे भाना हो इस प्रकार नियुक्त किया जा सकेगा।

(4) तथापि ऐसी प्रस्थापी नियुक्ति की प्रवधि केवल समिति की पूव सह मति से, छ महीने के बाद के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

(5) इस नियम के अन्तगत की गई प्रस्थापी नियुक्तियाँ कमिशन की पूव सहमति के बिना 12 महीने से अधिक की प्रवधि तक जारी नहीं रखी जा सकेगी।

(6) इस नियम के अन्तगत की गई प्रस्थापी नियुक्ति जते हो कमिशन प्रभव समिति द्वारा जैसी भी दशा हो, चुना गया उम्मीदवार उपलब्ध हो समाप्त हो जायगी।

24 वरिष्ठता (सीनियोरिटी) —प्रत्येक श्रेणी वग म सीनियोरिटी ऐसी श्रेणी प्रवधा वग में किसी पद पर की गई मूल नियुक्ति की आज्ञा की तारीख के आधार पर निश्चित की जायगी —

किन्तु शत यह है —

(1) कि इन नियमों के प्रारम्भ से पहिले किसी विशेष श्रेणी (ग्रेड) प्रवधा वग में पदों पर सेवा में नियुक्त किये गये सदस्या की आपस म सीनियोरिटी वह होगी जो सरकार द्वारा निश्चित की गई हो अथवा की जाय,

(ii) कि यदि दो या अधिक व्यक्ति उसी श्रेणी अथवा वग वाले पदों पर एक ही तारीख की उसी आज्ञा या उही आज्ञाओं के अंगीन नियुक्त किये जाय तो उनकी सीनियोरिटी उस ही क्रम में होगी जिसमें कि उनके नाम कमिशन अथवा समिति, जैसी भी दशा हो, द्वारा तैयार की गई जिलेवार सूची में आये हो।

(iii) कि इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् सरकारी सेवा से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सीनियोरिटी समिति द्वारा, समान पद पर उनकी मूल (Substantive) सेवा की निरन्तर अवधि के आधार पर तदर्थ निश्चित की जायगी।

1(iv) ग्राम सेवक तथा ग्रुप पंचायत सचिवों की पारस्परिक वरिष्ठता सूची और स्टॉकमैन तथा पशु चिकित्सा कम्पाउण्डर की वैसी ही पारस्परिक सूची उनकी अधिष्ठायी निमुक्ति के दिनांक के क्रम में तैयार की जावेगी।

25 परीक्षा — सेवा के समस्त सदस्य सिवाय उनके जिनकी कि सेवा में प्रारम्भिक नियुक्ति हो, तथा जो सरकारी सेवा से स्थानान्तरित किये जाय, नियुक्त किये जाने पर परीक्षा पर रखे जायेंगे। सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों के लिए परीक्षा काल दो वर्ष का होगा और जो तरक्की द्वारा नियुक्त किये गये हैं उनके लिए एक वर्ष होगा।

26 परीक्षा काल में असन्तोषजनक प्रगति — (1) यदि जिला परिषद् अथवा पंचायत समिति को जान पड़े कि सेवा में काम करने वाले किसी सदस्य ने उसकी मिले अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या वह सन्तोष प्रदान करने में विफल रहा है तो पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् उसको सेवा से हटा सकेगी या यदि उसका कोई मूल पद हो तो उस पद पर वापिस भेज सकेगी।

किन्तु शत है कि पंचायत समिति/जिला परिषद् सेवा के किसी भी सदस्य का परीक्षाकाल ऐसी अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक नहीं हो, बढ़ा सकेगी।

(2) ऐसा परीक्षाधीन कोई व्यक्ति, जो उप नियम (1) के अधीन परीक्षा काल में या उसकी समाप्ति पर सेवा से उसके मूल पद पर भेज दिया जाय (Reverted) या हटा दिया जाय (Removed) किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा।

---

1 जो एस आर 213 दिनांक 5-10-70 द्वारा प्रथमतः निविष्ट, जो क्र 11 एफ 41/L/PS/AR/9/70/1289-98 दिनांक 25-3-1971 द्वारा प्रतिस्थापित की गई।

27 स्थायीकरण (पुष्टीकरण) —बोर्ड परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा काल समाप्त होने पर उससे पद पर स्थायी कर दिया जायगा यदि पंचायत समिति ग्रथवा जिला परिषद् को यह सतोष हो जाय कि (परिवीक्षाधीन व्यक्ति की) ईमानदारी सदेह से परे है, उसका काम सतोषप्रद है तथा यह स्थायीकरण के लिए ग्रथया उपयुक्त (fit) है।

28 जिले के भीतर स्थानान्तरण —(1) ऐसे कर्मचारी का नाम जो स्वयं जिले के भीतर ग्रथना स्थानान्तरण चाहता हो या जिसका स्थानान्तरण करने की जरूरत समझी जाय पंचायत समिति द्वारा या जिला परिषद् द्वारा, जैसी भी दशा हो, समिति को भेज दिया जायगा। तदुपरांत समिति इन नामों को एक जिलावार सूची में प्रविष्ट कर लेगी।

(2) ऐसे कर्मचारी की स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति समिति की सिफारिश पर सम्बंधित पंचायत समिति ग्रथवा जिला परिषद् द्वारा की जा सकेगी जो उस पंचायत समिति या जिला परिषद् जैसी भी दशा हो सलाह करेगी जिसके प्रशासनिक नियन्त्रण में वह तत्प समय हो तथा जिसके प्रशासनिक नियन्त्रण में उसको स्थानान्तरित किये जाने का प्रस्ताव हो।

(3) कर्मचारी का स्थानान्तरण होने पर उसका कांफ़ीडेंशियल रोल तब सेवा का रिकार्ड, बिना परिहाय देरी के उस पंचायत समिति के पास भेज दिया जायगा जिसको कि उसकी सेवायें स्थानान्तरित की गई हैं।

29 जिले से बाहर स्थानान्तरण —(1) ऐसे कर्मचारी का नाम जं एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण चाहता है ग्रथवा जिसका इस प्रकार स्थानान्तरण चाहा जाय पंचायत समितियों या जिला परिषद् द्वारा, जैसी भी दशा हो कमीशन को भेज दिया जायगा। तत्पश्चात् कमीशन इन नामों को एक जिला वार सूची में प्रविष्ट करेगा।

(2) ऐसे कर्मचारी की स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति कमीशन की सिफारिश पर सम्बंधित पंचायत समिति ग्रथवा जिला परिषद् द्वारा की जा सकेगी जो उस पंचायत समिति या जिला परिषद्, जैसी भी दशा हो, स सलाह करेगा जिसके कि प्रशासनिक नियन्त्रण में वह तत्समय हो तथा जिसके प्रशासनिक नियन्त्रण में उसे स्थानान्तरित किये जाने का प्रस्ताव हो।

(3) इस प्रकार स्थानान्तरित किये गये कर्मचारी की सीनियोरिटी उसके द्वारा लगातार समान पद पर की गई मूल सेवा की निरंतर ग्रथधि पर उस जिले की समिति द्वारा जहां उसको स्थानान्तरित किया जाय तदय निश्चित की जायगी।

(4) किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण होने पर उसका कांफ़ीडेंशियल रोल

तथा सेवा का रिकार्ड, बिना परिहाय विलम्ब के, उस पचायत समिति/जिला परिषद के पास भेज दिया जायगा जिसको कि उसकी सेवायें स्थानांतरित की गई हो।

30 सेवा के सदस्य का सरकार के अधीन पदों पर पुनः स्थानांतरण — नियम 9 के अंतर्गत नियुक्त किये गये व्यक्ति पचायत समिति या जिला परिषद जैसी दशा हो द्वारा सरकार के अधीन किसी पद पर, संबंधित विभाग के अध्यक्ष के परामर्श से, पुनः स्थानांतरित किये जा सकेंगे बशर्ते कि ऐसा कमचारी कमीशन द्वारा आवश्यकता से अधिक (Surplus) घोषित कर दिया गया है।

1[31 वेतनमान एवं महंगाई भत्ता —सेवा के किसी सदस्य को अनुज्ञेय वेतनमान और महंगाई भत्ता वह होगा जो सरकारी कमचारियों के तत्समान वर्ग, प्रवर्ग या सेवा के किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पद के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर नियत किया जाय।]

31 क—राज्य सरकार की अनुमति के अध्वधीन रहते हुए पचायत-समिति और जिला परिषद् सेवा के किसी सदस्य को विशेष परिस्थितियों में जिला स्थापन समिति की सिफारिश पर ऐसी वेतनवृद्धियों की स्वीकृति को समुचित बताते हुए अपरिपक्व वेतन वृद्धियां भी, कुल मिलाकर दो से अधिक नहीं, स्वीकार कर सकेगी।

2[स्पष्टीकरण —सरकार द्वारा किसी स्तर पर आयोजित वार्षिक ग्रामसेवक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने को इस नियम के अंतर्गत निम्नलिखित सीमा तक अपरिपक्व वेतन वृद्धियां स्वीकार करने के लिये समुचित बनाते हुए विशेष परिस्थिति समझा जावेगा—

- |  |  |
|--|--|
| 1 पचायत समिति स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले ग्रामसेवक को | एक वेतन वृद्धि, बिना सचयी प्रभाव के    |
| 2 जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले ग्रामसेवक को        | दो वेतन वृद्धियां, बिना सचयी प्रभाव के |
| 3 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले ग्रामसेवक को       | एक वेतन वृद्धि, सचयी प्रभाव से         |
| 4 राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले ग्राम सेवक को  | दो वेतन वृद्धियां, सचयी प्रभाव से]     |

1 वि स एफ 4/एल/पी एस/ए आर/21/78/457/जी एस आर 154 दिनांक 28 नवम्बर 1978 द्वारा प्रतिस्थापित, जो राजस्थान राजपत्र, भाग 4 (ग) I दिनांक 4 1 1979 को पृष्ठ 419 पर प्रकाशित।

2 वि सरया F 4/PS/AR/1/59/6495 दिनांक 12 8-1969 द्वारा जोड़ा गया जो राजपत्र दिनांक 30 10 69 में पृष्ठ 161 पर प्रकाशित।

## भाग ६—वेतन

32 परिवीक्षा काल में वार्षिक वेतन वृद्धि (Increment) —परिवीक्षा पीन व्यक्ति को परिवीक्षा-काल में, उसकी स्वीकृत वेतन श्रेणी (Scale of pay) में वार्षिक वेतन वृद्धियाँ, जैसे ही वे देय होंगी किन्तु शत यह है कि यदि परिवीक्षा की अवधि में सतोपप्रद काम करने में विफल रहने के कारण वृद्धि कर दी गई है तो ऐसी वृद्धि वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिनी जायगी जब तक कि अवधि में वृद्धि करने वाला प्राधिकारी अथवा निर्देश न दे दे।

33 दक्षतायरोध (Efficiency bar) पार करने के लिए कमीटी —सेवा के किसी भी सदस्य को तब तक दक्षतायरोध पार नहीं करने दिया जायगा जब तक कि उसका काम सन्तोषजनक न रहा हो तथा उसकी ईमानदारी सन्देह से परे न रही हो।

## भाग ७—अन्य प्रावधान

34 वेतन, अवकाश भत्ते, पेन्शन, इत्यादि का नियमन —इन नियमों में जैसा प्रावहित है उसको छोड़कर तथा उतने समय तक कि इन मामलों में ऐसे समस्त अध्याय विही भी मामलों के बारे में पृथक् नियम नहीं बना दिये जाते, सेवा के सदस्यों के वेतन भत्ते, पेन्शन, अवकाश तथा सेवा की अन्य शर्तें राजस्थान सर्विस रूल्स 1951 तथा राजस्थान ट्रेवलिंग एलाउन्स रूल्स [समय समय पर यथा संशोधित] द्वारा आवश्यक परिवर्तनों के साथ नियमित होंगे।

टिप्पणी — राजस्थान सेवा नियम के अध्याय (11) के खण्ड (4) में वर्णित अध्ययन-अवकाश नियमों का लाभ ग्रामसेवकों (साधारण सेवा) के लिये विस्तृत करने का विनिश्चय किया गया है जो इस पद पर छ वर्ष की सेवा कर चुके हो, सिवाय इसके कि सरकार कारण अभिलिखित करते हुए इस अवधि को कम करके 4 वर्ष कर सकती है, ऐसे समुचित मामले में और कृषि या पशुपालन कालेजी या ग्रामीण स्थानों में शैक्षणिक सत्रों में प्रवेश लेने के लिये प्रार्थी की सेवा की पूरी अवधि में 4 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये। ऐसा अवकाश किसी विशिष्ट जिले में ग्रामसेवकों की संख्या के 10% से अधिक को एक साथ स्वीकार नहीं किया जावेगा। संशोधित पंचायत समिति की सिफारिश पर यह अवकाश जिला स्थापन समिति स्वीकृत करेगी। अध्ययन अवकाश का अवकाश वेतन उस पंचायत समिति द्वारा देय होगा जिससे वह ऐसे अवकाश पर जाता है।

34-क अध्ययन अवकाश की स्वीकृति—(1) ग्राम सेवकों, प्राथमिक शाला अध्यापकों और भैंसा के ऐसे अन्य सदस्यों को जिन्हें सरकार द्वारा समय समय पर अधिपोषित किया जाय जो किसी मायता प्राप्त विश्वविद्यालय, ग्रामीण स्थानों

के शैक्षिक सत्रो मे घोर अथ ऐसे सत्रो मे जो सरकार समय समय पर स्वीकृत करे, प्रवेश लेना चाहते हैं, निम्नलिखित शर्तों पर अध्ययन अवकाश ग्राह्य होगा —

(क) प्रार्थी की सम्पूर्ण सेवा की अवधि मे अध्ययन अवकाश चार वर्ष से अधिक नहीं होगा और ऐसा अवकाश एक बार मे किसी त्रिशिष्ट जिले मे ग्राम सेवको, अध्यापको या सेवा के अथ सदस्यो की वास्तविक सख्या के 10% से अधिक को स्वीकृत नहीं किया जावेगा ।

1[परन्तु यह है कि—पाच वष तक का अध्ययन अवकाश उन ग्राम सेवको को ग्राह्य होगा जो पशुचिकित्सा और पशुपालन मे डिग्री कोस मे उच्चतर शिक्षा के लिये भेजे गये हैं ।]

(ख) अवकाश सेवा के बेयल ऐसे सदस्यो को स्वीकृत किया जायगा, जिन्होने कम से कम छ वष की सेवा की हो मियाय इसके कि—सरकार लिखित मे कारण अभिलिखित करके समुचित मामलो मे इसे चार वष की अवधि के लिये कम कर सकती है ।

(ग) सेवा के ऐसे सदस्यो का जिन्होने 20 वष या अधिक की सेवा करली है, यह अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा । परन्तु सरकार 20 वष की सेवा पूरी करी वाले सेवा के सदस्य को अध्ययन-अवकाश स्वीकृत करने पर लगे इस प्रतिबन्ध को शिथिल कर सकेगी, यदि सेवा का ऐसा सदस्य अवकाश से उसकी वापसी के बाद पांच वष की अवधि के लिये सेवारत रहने का या पाच वष की अवधि के लिये सेवा नहीं कर सकन पर पंचायत समिति को अध्ययन अवकाश का खर्चा वापिस करने का बचन देता है ।

(घ) अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के लिये अथ निवन्धन एव शर्तें जो राजस्थान सेवा नियम के अध्याय (11) के खण्ड (4) मे वर्णित नियमो मे दी गई हैं, लागू होगी ।

(2) यह अवकाश सम्बन्धित पंचायत समिति की सिफारिश पर जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत किया जावेगा, परन्तु यदि जिलास्थापन समिति पंचायत समिति की सिफारिश के तीन महीने के भीतर स्वीकृति देने मे असफल रहती है या अवकाश स्वीकृत करने से मना करती है, तो सरकार ऐसा अवकाश स्वीकार कर सकेगी ।

1 वि सख्या एफ 4/L/PS/AR/5/70/904-14 दिनांक 19-12 1971 द्वारा जोड़ा गया और राज पत्र मे दि 11 11-1971 को पृष्ठ 416(12) पर प्रकाशित ।

(3) अध्ययन-अवकाश वा अवकाश वेतन उस पचायत समिति द्वारा देय होगा, जिससे पचायत समिति सेवा का एक सदस्य ऐसे अवकाश पर खाना होता है।

§ 34 क (क) 20 वष की अहक सेवा पूर्ण करने पर सेवा निवृत्ति — पचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा का सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी को 'न्यूनतम 3 माह का लिपित में पूव नोटिस देने के पश्चात् उस तारीख को, जिसकी वह 20 वष की अहक सेवा पूर्ण करता है या 45 वष की आयु प्राप्त करता है जो भी पूर्वतर हो या उससे पश्चात् किसी ऐसी तारीख को, सेवा से सेवानिवृत्त हो सकेगा जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाय

परंतु नियुक्ति प्राधिकारी पचायत समिति या जिला परिषद् सेवा क किसी सदस्य की सेवानिवृत्ति की अनुज्ञा रोक देने के लिए स्वतन्त्र होगा

(1) जो निलम्बनाधीन हो

(11) जिससे मामले में अनुशासनिक कार्रवाई सम्बन्धित है या बड़ी शास्ति आरोपित करने के लिए अनुपस्थित हो और अनुशासनिक प्राधिकारी का मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह विचार हो कि ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप सेवा से हटाये जाने या पदच्युति की शास्ति आरोपित की जा सकती है।

(111) जिसके मामले में अभियोजन अनुपस्थित है या चलाया जा चुका है,

(ख) पचायत समिति या जिला परिषद् सेवा का सदस्य जिसने इस उप नियम के खण्ड (क) के अधीन सेवानिवृत्ति के लिए नोटिस दिया है, सेवानिवृत्ति के नोटिस की स्वीकृति की उपधारणा कर सकेगा और सेवानिवृत्ति स्वतः ही नोटिस के निबन्धनों के अनुसार प्रभावी होगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके प्रतिरूप कोई आदेश लिखित में जारी न कर दिया गया हो और पचायत समिति या जिला परिषद् सेवा के सदस्य को इसकी तारीख नोटिस की कालावधि की समाप्ति से पूर्व न करदी गई हो।

1

(ग) यदि पचायत समिति या जिला परिषद् सेवा का कोई सदस्य इस उपनियम के अधीन सेवानिवृत्ति चाहता हो जबकि वह देयातिरिक्त अवकाश पर हो तथा ड्यूटी पर वापस न आय तो सेवानिवृत्ति, देयातिरिक्त अवकाश के प्रारम्भ की

§ वि स एफ 4/L/PS/AR/2/75/372 GSR 41 दि 21 सितम्बर 1978 द्वारा प्रतिस्थापित, जो वि स GSR 138 दिनांक 3 मार्च 1976 द्वारा जोड़ा गया था।

तारीख से प्रभावी होगी और ऐसे अवकाश की बाबत सदस्य अवकाश वेतन उससे वसूल किया जायगा।

(घ) पंचायत समिति या जिला परिषद् सेवा का कोई सदस्य जो इस उप-नियम के खण्ड (क) के अधीन स्वेच्छया सेवानिवृत्ति चाहता है, 5 वष की ग्रहक सेवा के अधिकार-भार (वैटेज) का हकदार होगा जो उसके द्वारा वस्तुतः की गई ग्रहक सेवा के अतिरिक्त होगा। तथापि, इस पांच वष के अधिकार-भार की मजूरी निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगी —

पंचायत समिति या जिला परिषद् के ऐसे सदस्य की बाबत जो पेंशन नियमों द्वारा शासित होता है—

- (1) ऐसे मामलों में सेवानिवृत्ति के फायदों के लिए ग्रहक सेवा की वृद्धि 5 वष और जोड़कर कर दी जाएगी। काल्पनिक सेवा को जोड़ने के पश्चात् सेवा की परिणामी अवधि किसी भी दशा में 33 वष की ग्रहक सेवा, या उस ग्रहक सेवा, जो पंचायत समिति या जिला परिषद् सेवा का सम्बन्धित सदस्य गणनाकर्त्ता यदि वह अधिवापिता की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त होता, उनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।
- (11) ऐसे मामलों में जहां उपयुक्त (1) के अधीन ग्रहक सेवा में वृद्धि की जाती है, वे उपलब्धियां, जो पंचायत समिति या जिला परिषद् सेवा का सदस्य सेवानिवृत्ति की तारीख से तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहा था पेंशन एवं उपदान के परिकलन के प्रयोजनाय हिसाब में ली जायेगी।

पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा के ऐसे सदस्य की बाबत जो अभिदायी भविष्य निधि स्कीम द्वारा शासित होता है—

- (111) राजस्थान पंचायत समिति या जिला परिषद् सेवा अभिदाय (बोनस एवं विशेष अभिदाय) यदि कोई हो, में उस रकम तक की वृद्धि की जाएगी जो 5 वष की काल्पनिक सेवा के जोड़े जाने पर प्रोद्भूत होता।
- (1V) काल्पनिक अभिदाय, अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख की या उसके पश्चात् निधि को अभिदाय किये बिना सेवानिवृत्ति की तारीख से तत्काल पूर्व दिये गए अभिदाय की रकम के आधार पर, जोड़ा जायेगा।
- (V) पूर्वोक्त रीति से की गई परिणामी वृद्धि उस अभिदाय (बोनस एवं विशेष अभिदाय) यदि कोई हो, से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी जो उससे भविष्य निधि खाते में जमा बरदी जाती यदि वह



33 वर्ष की ग्रहक सेवा पूर्ण कर या अधिवापिता की आयु प्राप्त कर जो भी कम हो, सेवानिवृत्त होता ।

(vi) इस खण्ड में वर्णित 5 वर्ष की काल्पनिक ग्रहक सेवा का फायदा पचायत समिति या जिला परिषद् सेवा के ऐसे सदस्य को अनुनय नहीं होगा जो इस नियम के उप नियम (2) के अधीन सेवानिवृत्त हुआ हो ।

(ड) पचायत समिति या जिला परिषद् सेवा का कोई सदस्य जो उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने का नोटिस देता है, नियुक्ति प्राप्ति वाली, जो उसे सेवानिवृत्त करने में सक्षम हो, को इस आशय का निर्देश देकर स्वयं का समाधान करेगा कि उसने तथ्यत पेशान के लिए 20 वर्ष की ग्रहक सेवा पूर्ण कर ली है ।

(च) पचायत समिति या जिला परिषद् सेवा का सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदा से, इस उपनियम के खण्ड (क) के अधीन दिया गया नोटिस वापस ले सकेगा परन्तु इस प्रकार वापस लेने की प्रारम्भ नोटिस की अवधि की समाप्ति से पूर्व की गई हो ।

(छ) पचायत समिति या जिला परिषद् सेवा के किसी सदस्य को सेवानिवृत्त करने में सक्षम प्राधिकारी, योग्य मामला में, इस उपनियम के खण्ड (क) के अधीन अनुध्यात 3 माह से कम कालावधि का नोटिस सामुदायिक विकास एवं पचायत विभाग में सरकार की सहमति से स्वीकार कर सकेगा ।

(ज) स्वेच्छया सेवानिवृत्ति का नोटिस देने वाला पचायत समिति का या जिला परिषद् सेवा का सदस्य नोटिस की समाप्ति से पूर्व उसके खाते में जमा भवकाश के लिए भी आवेदन कर सकेगा जो उसे मजूर की जा सकेगी जिससे कि वह नोटिस की कालावधि के साथ साथ चल सके । भवकाश की वह कालावधि, यदि कोई हो, जो नोटिस की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे बढ़ी हुई हो परन्तु उस तारीख से आगे बढ़ी हुई नहीं हो जिस पर पचायत समिति या जिला परिषद् सेवा का सदस्य अधिवापिता की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त होता, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, स्वविवेकानुसार, उसके खाते में जमा उपाजित भवकाश के परिमाण, 120 दिन से अधिक, तक तावधि भवकाश के रूप में मजूर की जा सकेगी ।

35 पेन्शन तथा प्रोविडेंट फंड —सेवा का सदस्य, सरकार द्वारा राज्य की सघनित निधि से पेन्शन पाने का हक्कदार होगा और प्रत्येक पचायत समिति तथा जिला परिषद् सरकार को पेन्शन के हेतु राजस्थान सर्विस रूल्स के परिशिष्ट 5 में

निर्धारित दरो के अनुसार पेशन सबधी अशदान देगी तथा भुगतान करेगी

किंतु शत यह है कि—

यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नियम 5 में निर्देश है राजस्थान सर्विस रूल्स के अन्तर्गत पेशन का लाभ पाने का हक्दार न हो कि तु जो उस पंचायत समिति जिसके अधीन वह किसी पद पर नियुक्त है के गठन की तारीख से पहिले से ही पेशन के लाभ के बदले में अशदायी प्रोवीडेंट फंड में, अभिदान करता रहा है तो वह पेशन का हक्दार नहीं होगा और उस अशदायी प्रोवीडेंट फंड में फंड पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार, उसमें अभिदान करता रहेगा और उस हेतु पंचायत समिति या जिला परिषद् का अशदान, उस फंड पर लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार निश्चित किया जायगा।

36 एकीकरण तथा फिक्सेशन सम्बन्धी मामले—नियम 5 के अधीन नियुक्ति किये गये कर्मचारियों के एकीकरण, वेतन निर्धारण (Fixation), सीनियो-रिटी आदि से सम्बन्धित मामले ऐसे होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर निश्चित किये जाएँ।

### [37 विलोपित]

38 राज्य सेवा (State service) में सरकारी के लिए पात्रता (Eligibility) —सेवा का सदस्य राज्य सेवाओं पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अगले ऊँचे पदों पर नियुक्ति किये जाने या सरकारी पाने का पात्र होगा। इस प्रकार नियुक्ति किये गये या सरकारी दिये गये व्यक्ति उनके द्वारा सेवा में मूलरूप से पद धारण किये जाने की अवधि को, सीनियोरिटी के प्रयोजनों हेतु गिनेंगे। वे ऐसी अवधि को, राजस्थान सर्विस रूल्स के प्रावधानों के अनुसार पेशन के प्रयोजनों के लिए भी गिनेंगे।

× [परन्तु यह है कि—पंचायत समितियों के प्राथमिक विद्यालयों के तृतीय श्रेणी के अध्यापक राज्य सरकार के अधीन शिक्षा विभाग में सर्वमान्य पदों पर स्थानांतर के लिये पात्र होंगे।]

× × [39 प्रशिक्षण के दौरान असन्तोषजनक प्रगति—यदि सेवा का एक सदस्य पंचायत समिति/जिला परिषद् या राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये

× वि स एफ 189/16/1/PD/Adm70/3915 दिनांक 13 3 1970 द्वारा जोड़ा गया, जो राजपत्र में दि 1 3 3 1970 को पृष्ठ 56 पर प्रकाशित हुआ।

× × वि स एफ 4 A/L/PS/AR/2/70/1285 दि 5-6-1960 द्वारा जोड़ा गया, जो राजपत्र दि 6-6-1970 में पृष्ठ 57 पर प्रकाशित हुआ।

जाने के बाद प्रशिक्षण में भाग लेने में असफल रहता है या उपरोक्त प्रशिक्षण में प्रवेश लेने के बाद अध्ययन को सतोषप्रद रूप से प्राप्त करने में या प्रशिक्षण को पूरा करने में या ऐसे प्रशिक्षण की विहित परीक्षा में बैठने में और उत्तीर्ण होने में बिना किसी समुचित और युक्तियुक्त कारण के असफल रहता है, तो वह ऐसे प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त की गयी छान्दवृत्ति, यदि कोई हो, की राशि वापस करने के लिये उत्तरदायी होगा तथा अनुशासनिक कार्यवाही के लिये भी दायी होगा ।]

### अस्थाई कर्मचारियों का स्थायीकरण

राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम

धारा 86, उप धारा (8-क)

“(8-क)—उप धारा (5), उपधारा (6), उपधारा (8) में किसी बात के होते हुए, समस्त व्यक्ति जो राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम 1976 के प्रवृत्त होने के पहले अस्थायी रूप से सेवा में सर्वांगित पदों पर नियुक्त किये गये थे, जो इस उपधारा के प्रवृत्त होने पर कम से कम दो वर्ष की अस्थाई सेवा पूरी कर चुके हैं, उनको ऐसे प्रवृत्त होने के दिनांक से उन पदों पर अधिष्ठायी नियुक्त किया जावेगा जिन पर वे अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये थे ।”

उपरोक्त संशोधन दि 14-12-76 से प्रवृत्त हुआ, जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (क) दि 14-12-76 में पृष्ठ 233 (1977 RLT-I-1) पर प्रकाशित हुआ । अतः 14-12-76 से पहले के समस्त अस्थाई कर्मचारी अपने पदों पर 14-12-76 से अधिष्ठायी (Substantive) अर्थात्-स्थायी (Confirmed) कर दिये जावेंगे । इसके लिये नियमानुसार स्थायी समिति नियम का प्रस्ताव पारित करेगी तथा भर्त्ता जारी की जावेगी । यह आज्ञापक (अनिवार्य) रूप से करना होगा ।

## अनुसूची

(देखिये नियम 4, 6, 11, 20 तथा 21)

क्र स	पद का वग तथा अंणी (पैड) (यदि नहीं हो)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित ग्रहणाए	वह पद जिस पर से सरकारी द्वारा नियुक्ति की जा सकती है	सरकारी के लिए अपेक्षित 'यूनतम मनुभव एवं ग्रहणाए	रिमाक्से
1	2	3	4	5	6

1. ग्राम सेवक तथा ग्राम  
सेविकाएँ
- मेट्रिक, वैसिक तथा प्रसार दोनों में  
प्रशिक्षित, ग्राम सेवक के लिये और  
शुह विज्ञान में ग्राम सेविका के लिये,  
सिवाय उनके जो 1-4-56 के  
पहले भर्ती हुए—
- (i) मेट्रिक अप्रशिक्षित, या
- (ii) नॉन मेट्रिक, वैसिक व प्रसार  
दोनों में प्रशिक्षित ग्राम
- ग्राम सेवक तथा  
ग्राम सेविकाएँ
- (1) 5 वर्ष की सेवा : उत्पादक  
प्रोग्राम में तथा जनता का  
योगदान प्राप्त करने में  
मिती सफलताओं के लिए  
प्राथमिकता दी जायगी।
- (2) वैसिक तथा एक्सटेंशन  
ट्रेनिंग दोनों में प्रशिक्षण,

6

5

4

3

2

1

सेवक के लिये, या गृह  
विज्ञान प्राग सेवा के  
लिये, या  
(iii) मिडिल पाठ या भारतीय  
सेना II श्रेणी, भूतपूर्व  
सैनिकों के लिये ।

सिवाय उक्त ग्राम सेवकों के  
जो 1-4-56 से पहले मर्ती  
हुए हो तथा जिन्होंने कम से  
कम एकसठ-घन की ट्रेनिंग  
की हो।

ग्राम सेविका—

(3) 3 वर्ष की सेवा गृह विज्ञान  
विंग में प्रशिक्षित ।

क स	पद का वर्ष	सीधी भर्ती के लिये 'ग्रहतायें'
1	2	3

2 प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक मैट्रिक प्रशिक्षित

<sup>1</sup>नोट—महिला उम्मीदवारों की सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम ग्रहता मैट्रिक तथा एस टी सी प्रशिक्षित या राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रशिक्षित मैट्रिक के समतुल्य घोषित कोई भी अन्य ग्रहता होगी ।

परन्तु इ गरपुर वासवाडा के जन जाति जिलों में और बाडमेर तथा जैसलमेर के रेगिस्तानी जिलों में महिला उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की दशा में न्यूनतम ग्रहता अप्रशिक्षित मैट्रिक या उसके समतुल्य हो सकेगी ।

<sup>2</sup>[3 फील्डमैन 4 पशुविक्रिया कम्पाउंडर 5 कुक्कुट पालन प्रदर्शक]

6 स्टाक मैन तथा स्टाक असिस्टेंट -

मैट्रिक साइस विषय सहित, भेड पालन तथा उत्पादन में 6 महीने की ट्रेनिंग सहित ।

<sup>2</sup>[7 भेड तथा ऊन पर्यवेक्षक 8 ट्रेसर 9 टीका लगाने वाले]

10 वरिष्ठ लिपिक (जिसमें लेखालिपिक, ग्राथुलिपिक सम्मिलित हैं—

कनिष्ठ लिपिक का 7 वर्ष का अनुभव तथा मैट्रिक होना चाहिये, यदि स्नातक हो तो तीन वर्ष का अनुभव । लेखालिपिक राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लेखालिपिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये ।

कनिष्ठ लिपिक (ढकण लिपिक सहित)—

मैट्रिक होने चाहिये या हिन्दी अथवा संस्कृत में ऐसी योग्यतायें प्राप्त हो, जो कमीशन के द्वारा मैट्रिक के बराबर मान ली गई हैं । ढकण (टाइप) की योग्यता वालों को प्राथमिकता मिलेगी ।

11 ड्राइवर—हिन्दी जानने वाले तथा ड्राइविंग लाइसेंस युक्त ।

<sup>2</sup>[12 प्रोजेक्टर चालक 13 भेट (उद्योग)]

1 वि स एफ 4/एल/पी एस/ए गार /20/78/459 जी एस गार 153 दि 22 नवम्बर 1978 द्वारा प्रतिस्थापित जो राजपत्र दि 4 1 1979 के पृष्ठ 419 पर प्रकाशित ।

2 ये पद अथ पंचायत समितियों में नहीं हैं ।

## 314 ग्रुप पंचायत सचिव

(i) मेट्रिक, तीन मास के पंचायत सचिव के प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जावेगी, या

(ii) मेट्रिक, ग्रामसेवक के लिये बेसिक एव प्रसार दोनों में प्रशिक्षित, या

(iii) मिडिल पास, ग्रामसेवक के लिये बेसिक एव प्रसार दोनों में प्रशिक्षित

315 कार्यालय सहायक—“राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम” में दिये गये तरीके के अनुसार ।

— — —

+

~ ~ ~

- - -

3 वि सख्या एक 4/L/PS/AR/13/67/12863 दिनांक 30 11 1967 द्वारा जोड़ा गया ।

4 वि सख्या एक 4/L/PS/AR/RS/1840-49 दिनांक 29 4 1971 द्वारा निविष्ट ।

## 5

## 1 राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्तों एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 1963

[Rajasthan Class IV Services (Recruitment and Other Service Conditions) Rules, 1963]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परचुके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा के पदों पर भर्तों तथा इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं —

### भाग (1) सामान्य नियम

1 संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—इन नियमों का नाम “राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्तों एवं सेवा की अन्य शर्तें)” नियम 1963<sup>१</sup> है, ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2 परिभाषाएँ—जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में—

(क) ‘नियुक्ति प्राधिकारी’ से अभिप्रेत है, कार्यालय का अध्यक्ष या यह अधिकारी जिसे कार्यालयीय द्वारा ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की गई है ।<sup>२</sup>

३ (ख) “राजपत्र” से राजस्थान-राजपत्र अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन तत्समय प्रभावी किसी विधि के अनुसारण में प्रकाशित किया जाता है ।

1 वि स एफ 1 (21) नियुक्ति (क-2) 62 दिनांक 8 जुलाई 1963, राजस्थान राजपत्र असाधारण, भाग 4 (ग) दिनांक 12-7-1963 में तथा प्राधिकृत हिंदी पाठ 30 अप्रैल 1975 तक सशोधित-राजपत्र दिनांक 20-5-1976 पृष्ठ 162 पर प्रकाशित ।

2 “1962” के लिये वि स एफ 1 (21) नियुक्ति (क-5) 62 दिनांक 12-8-1965 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3 खण्ड (ख) दिनांक 15-7-63 से प्रभावशील होना समझा गया ।



4(ग) "कार्यालयध्यक्ष" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिस सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 3 के अधीन कार्यालय के अध्यक्ष के रूप में अधिषोषित किया जाय।

(घ) 'सेवा का सदस्य' से यह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इन नियमों या इन नियमों द्वारा अतिष्ठित नियमों या आज्ञाओं के उपबन्धों के अधीन सेवा में किसी पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किया गया हो और इसके अन्तर्गत परिवीक्षा पर रखा गया व्यक्ति भी आता है।

(ङ) 'सेवा' से अभिप्रेत है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा,

(च) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है, इन नियमों की अनुसूची,

4(छ) 'अधिष्ठायी नियुक्ति' से अभिप्रेत है, इन नियमों में विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्पन्न किया जाकर किसी अधिष्ठायी रिक्त पद पर इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की गई कोई नियुक्ति और इसके अन्तर्गत है, परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन के रूप में की गई कोई नियुक्ति यदि उस पर परिवीक्षा की जाय। अधि की समाप्ति के पश्चात् स्थायी करण कर दिया जाय।

टिप्पणी—अधिव्यक्ति "इन नियमों में विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्पन्न किया जाकर" में, आवश्यक अस्थायी नियुक्ति को छोड़कर सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गई या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक के अधीन प्रस्थापित किसी नियम के उपबन्धों के अनुसार की गई भर्ती सम्मिलित है।

(ज) 'सेवा या अनुभव'—जहाँ वहाँ इन नियमों में एक सेवा से दूसरी में या उसी सेवा में एक प्रवर्ग (कैटेगरी) से दूसरे में या वरिष्ठ पदों पर अधिष्ठायी रूप से ऐसे पदों की धारण करने वाले व्यक्ति के मामले में, (सेवा या अनुभव) पदोन्नति के लिये एक शत के रूप में विहित है उसमें वह प्रवर्ग भी सम्मिलित होगी, जिसमें उस व्यक्ति ने अनुच्छेद 309 के परतुक के अधीन बने नियमों के अनुसार नियमित भर्ती के बाद उस पदों पर लगातार कार्य किया है और इसमें वह अनुभव भी सम्मिलित होगा, जो उसने स्थानापन्न, अस्थायी या तदर्थ नियुक्ति द्वारा अर्जित किया है, यदि ऐसी नियुक्ति पदोन्नति की नियमित पक्ति में की गई हो और वह स्थानप्राप्ति के लिये

4 वि स एफ 1 / 21) नियुक्ति (क-2) 62 गिर्ना 12 8 65 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—"कार्यालयाध्यक्ष" से वह अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे नियुक्ति के अधिकार प्रत्यापोजित कर दिये गये हों।

या प्राक्स्थितिक प्रकार की या किसी विधि के अधीन भर्तव्य नहीं है तथा तबसे किसी व्यक्ति का अतिष्ठन अतवर्तित न हो, सिवाय जब कि—या तो विहित शैक्षणिक और अन्य योग्यताओं की कमी अयोग्यता या योग्यता द्वारा अचयन या सम्बन्धित चरिष्ठ कमवर्गी के दोष [या जब ऐसी तथ्य या प्रजेक्ट अस्थायी नियुक्ति चरिष्ठता सह योग्यता के अनुसार हो], जिसके कारण से ऐसा अधिष्ठन हुआ हो।

टिप्पणी—सेवा के दौरान अनुपस्थिति जैसे प्रशिक्षण और प्रतिनियुक्ति प्राप्ति, जो राजस्थान सेवा नियम के अधीन 'कनव्य' मानी जाती है, भी पदोन्नति के लिये आवश्यक न्यूनतम अनुभव या सेवा की संगणना के लिये सेवा के रूप में मंगणित की जावेगी।

3 निवचन—जब तक सदन से अथवा अधिष्ठित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम संख्या 8) इन नियमों के निवचन के लिये उसी प्रकार लागू होगा जिन प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निवचन के लिये लागू होता है।

### भाग (2) सवग (फंडर)

4 सेवा का गठन एवं पदों की सख्या—(1) सेवा में सम्मिलित पदों का स्वरूप यह होगा, जैसा कि—अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(2) सेवा की प्रत्येक ग्रेड में पदों की सख्या उतनी होगी जितनी सरकार समय समय पर तय करे, परन्तु सरकार—

- (क) आवश्यक प्रतीत होने पर कोई भी स्थायी या अस्थायी पद समय समय पर सजित कर सकेगी, और
- (ख) किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का प्रतिकर पाने का हकदार बनाए बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद को समय समय पर खाली रख सकेंगी उसको प्रतिस्थापित रख सकेगी या उसको तोड़ सकेगी।

5 सेवा का गठन—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे—

- (क) अनुसूची I में विनिर्दिष्ट पदों को अधिष्ठापी रूप में धारण करने वाले व्यक्ति
- (ख) इन नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गए व्यक्ति, और
- (ग) इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये व्यक्ति

### भाग (3) भर्ती

6 भर्ती के तरीके—इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से होगी—

(क) इन नियमों के भाग (4) के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा, और

(ख) किसी कमचारी का, तत्कालीन पद पर, एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण द्वारा,

<sup>1</sup>(ग) कार्य प्रभारित वक्ताज कमचारियों के आमेलन द्वारा,

<sup>2</sup>(घ) अशकालिक (पाट टाइम) कमचारियों के आमेलन द्वारा

परंतु इन नियमों की कोई बात ऐसे कमचारियों को जो पुनर्गठन पूर्व के अजमेर, बम्बई और मध्य भारत राज्यों में पहले में ही नियोजित थे, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट उपयुक्त पदा पर उनकी सेवाओं के एकीकरण सम्बन्धी नियमों के अनुसार नियुक्ति करने से न्यायालय के अध्यक्ष को प्रचारित नहीं करेगी।

6-क इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी आपातकाल के दौरान सेना/वायुसेना/नौ सेना में कार्यग्रहण करने वाले व्यक्ति की भर्ती नियुक्ति, पदोन्नति वरिष्ठता और स्थायीकरण आदि ऐसे आदेशों और अनुदेशों से विनियमित हों जो सरकार द्वारा, समय समय पर, जारी किये जाएं परंतु यह तब जब कि भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, आवश्यक परिवर्तन सहित विनियमित किया जाय।

7 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये रिक्तियों का आरक्षण—

[क्षेत्रपथ पीछे पृष्ठ 25 पर नियम 8 या पृष्ठ 118 पर नियम 6 देखिये। जो समान भाषा में एकरूप हैं।]

7-क रिक्तियों का अवधारण—

[क्षेत्रपथ पीछे पृष्ठ 26 पर नियम 9 देखिये, जो समान भाषा में एकरूप हैं।]

8 राष्ट्रीयता—[क्षेत्रपथ पीछे पृष्ठ 27 पर नियम 10 या पृष्ठ 217 पर नियम 7 देखिये, जो समान भाषा में एकरूप हैं।]

8 क—[क्षेत्रपथ पीछे पृष्ठ 28 पर नियम 10-क या पृष्ठ 119 पर नियम 7 क देखिये, जो समान भाषा में एकरूप हैं।]

1 वि सख्या एफ 4 (1) DOP/A-2/73 दिनांक 20-9-75 द्वारा निविष्ट।

2 वि सख्या एफ 5 (1) DOP/A-2/78 GSR 28 दि 19-9-78 द्वारा जोड़ा गया।

9 आयु—अनुसूची में प्रणालित किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिये नियत अंतिम दिनांक के बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिन 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिये, लेकिन 2॥ वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिये,

परन्तु —

(i) असाधारण मामलों में कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा विभागाध्यक्ष से परामर्श कर ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकेगी,

(ii) महिला अभ्यर्थियों अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के मामले में ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी

(iii) भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों और रिजर्विस्ट अथवा प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारियों के लिये जिनको रिजर्व में अन्तर्लिखित कर दिया गया था, अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी,

(iv) अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों की आयु सीमा में ही समझा जायगा यदि वे आरम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष अंतिम रूप से उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी आरम्भिक नियुक्ति के समय उपरोक्त रूप में आयु सीमा में पात्र थे तो उन्हें दो तक अवसर प्रदान किये जायेंगे,

(v) कस्टि प्रशिक्षकों के मामले में ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा में एक से अधिक की गई सेवा की हालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिवारिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जाएगा,

(vi) उन व्यक्तियों के मामले में जो विहित अधिकतम आयुसीमा से अधिक आयु के होने पर 1-4-1973 से पूर्व नियुक्त किये गये हैं, अधिकतम आयु सीमा में सरकार 40 वर्ष की आयु तक की छूट दे सकेगी,

(vii) आयोग के क्षेत्र में नहीं आने वाले पदों पर भर्ती हेतु उन व्यक्तियों की जिनकी राज्य सरकार की सेवा से निवृत्ति न होने के कारण या पद की समाप्ति के कारण छूटनी कर दी गई थी, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी यदि वे उस पद पर जिस पर से उनकी प्रथमतः छूटनी की गई है, आरम्भिक नियुक्ति के समय, विहित आयु सीमा में ही थे परन्तु यह तब जब कि वे, अहता, चरित्र, स्वस्थता आदि के सम्बन्ध में भर्ती के लिये विहित सामान्य माध्यमों की पूर्ति करते हों तथा उनकी छूटनी

शिकायत या अपचार के आधार पर नहीं हुई हो, तथा वे अन्तिम नियुक्ति प्राधिकारी से, अच्छी सेवा का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दें।

(viii) 1-3-1963 को या इसके बाद और 1 11-64 को वर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देशों—केनिया, टांगानिका, युगाण्डा और जजीबार से वापस लौटाये गये (आम्रजित) व्यक्तियों के लिये उपरोक्त आयुसीमा 45 वर्ष तक शिथिल की जावेगी और अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के मामले में पाच वर्ष की छूट और दी जावेगी

(ix) पूर्वी अफ्रीकी देशों—केनिया, टांगानिका, युगाण्डा और जजी बार से वापस लौटाये गये व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

(x) उपरोक्त आयु सीमा एक भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो उसकी दोष सिद्धि के पूर्व किसी पद पर सेवा कर चुका हो और नियमों में अधीन नियुक्ति के लिये पात्र था।

(xi) अथ भूतपूर्व कैदियों के मामले में उपरोक्त वर्णित आयु सीमा को उसके द्वारा भोगे गये कारावास की अवधि के बराबर शिथिल कर दिया जायेगा, परन्तु यह है कि—वह उसकी दोष सिद्धि से पहले अधिकार्यु नहीं था तथा नियमों के लिये पात्र था।

(xii) निरुक्त आपात कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से नियुक्त होने के बाद आयु सीमा के भीतर माना जावेगा, चाहे वे आयुयोग के समक्ष उपस्थित हों पर उस आयु सीमा को पार कर चुके हों, यदि वे सेना के कमीशन में प्रवेश के समय इसके लिय पात्र होते।

10 शक्तिशालक योग्यताएँ—अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित ग्रहताएँ होगी—

(i) अनुसूची के स्तम्भ 4 में दी गई ग्रहताएँ, और

(ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान।

11 आवेदन का प्रारूप—आवेदन अनुसूची XI में दिये गये प्रारूप में किया जायेगा।

12 चरित्र—सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे सेवा में नियोजन के लिये ग्रहित बनाता हो। उसे एक उत्तरदायी व्यक्ति का, जो उसका रिश्तेदार नहीं हो, एक सच्चरित्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिये।

टिप्पण—[कृपया पीछे पृष्ठ 35 पर नियम 13 के नीचे या पृष्ठ 122 पर नियम 11 के नीचे की टिप्पणियाँ देखिये, जो समान भाषा में हैं]

13 शारीरिक योग्यता—सेवा में सीधी भर्ती का अभ्यर्थी मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये और उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा मानसिक एवं शारीरिक दोष नहीं होना चाहिये जो उसके सेवा के सदस्य के रूप में अपने उच्चतम दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधक हो और यदि वह चुन लिया जाए तो उसे राजस्थान सरकार के कार्यालयों के सम्बंध में नियोजित किसी भी चिकित्सा अधिकारी का इस बारे में एक प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करना चाहिये।

#### भाग (4) सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया

14 भर्ती के स्रोत—सेवा के पद पर सीधी भर्ती के लिये नियुक्ति प्राधिकारी स्थानीय नियोजन कार्यालय से अभ्यर्थियों की एक सूची मगायेगा। यदि नियोजन (रोजगार) कार्यालय से अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी ही रीति से जैसा कि कार्यालय का अध्यक्ष उचित समझे, पद भरे जा सकेंगे,

परंतु उक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय नियुक्ति प्राधिकारी वष के दौरान होने वाली अतिरिक्त आवश्यकता के लिये भी उपयुक्त व्यक्तियों का चयन कर सकेगा।

15 आवेदन पत्रों की समीक्षा—नियुक्ति प्राधिकारी उन आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा जो उसे प्राप्त हुए हों और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिये अर्हित उक्त अभ्यर्थियों से जितने उसे साक्षात्कार के लिये वाछनीय प्रतीत हो, अपन समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा,

परंतु किसी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अयोग्यता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

16 अभ्यर्थी का चयन—नियम 8 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की जिन्हें वह सम्बंधित पदा पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझता है एक सूची योग्यता क्रमानुसार तैयार करेगा और उक्त सूची क्रम में नियुक्त करेगा।

किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे समाधान न हो जाय कि—ऐसा अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये अन्य सब प्रकार से उपयुक्त है।

#### भाग (5)—पदावधि द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17 चयन की फसौटी—अनुसूची I के स्तम्भ 5 में प्रणालित पदों के धारक व्यक्ति अनुसूची I के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पदा के लिये वरिष्ठता एवं

योग्यता के आधार पर पदोन्नति के पात्र होंगे। पदोन्नति या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनके स्वास्थ्य, योग्यता, तत्परता और दक्षता को ध्यान में रखते हुए, विभाग के अध्यक्ष के अनुमोदन से की जाएगी।

17-क— किसी व्यक्ति के बारे में पदोन्नति के लिये तब तक विचार नहीं किया जायगा जब तक कि उसे ठीक नीचे के पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त कर स्थायी न कर दिया गया हो। यदि ठीक नीचे के पद का कोई भी अधिष्ठायी व्यक्ति पदोन्नति के लिये पात्र न हो, तो वे व्यक्ति जो भर्ती के तरीकों में से किसी एक के अनुसार या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु के अधीन प्रस्तापित कि-ही सेवा नियमों के अधीन चयन के पश्चात् ऐसे पद पर स्थापनापन रूप से नियुक्त किए गए हैं, उनके बारे में उसी वरिष्ठता क्रम में वेबल म्यानायन्स आधार पर पदोन्नति के लिये विचार किया जा सकेगा, जिसमें वे होते यदि वे उक्त नीचे के पद पर अधिष्ठायी होते।

स्पष्टीकरण—किसी विशिष्ट वय में जब पदोन्नति द्वारा नियमित वय से पहले ही किसी पद पर सीधी भर्ती कर ली गयी हो, तो ऐसे व्यक्ति जो उम्र पद पर भर्ती के दोनों तरीकों से नियुक्ति के लिये पात्र है या थे और पहले सीधी भर्ती से नियुक्त कर दिये गये हैं, पदोन्नति के लिये विचार में लाये जायेंगे।

217-ख काय प्रभारित कमचारियों के आमेसन की प्रक्रिया—इन नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जो व्यक्ति किसी विभाग में दैनिक उपतान या आकस्मिक काय प्रभार (वक चाजह) के आधार पर पहले ऐसे पदों पर नियोजित किये गये थे जो आरम्भ में ही स्वीकृत थे और नियमित स्थापन पर ले आये गये हैं, व नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सवीक्षा (स्कीनिंग) के बाद वेबल एक बार उन पदा पर जो प्रशासनिक विभाग में सरकार द्वारा समतुल्य घोषित किये जाय, आमेलित तथा नियुक्त किये जायेंगे, यदि उन्होंने उस वय की जनवरी के प्रथम दिन कम से कम दो वय की सेवा कर ली है, जिस वय में काय प्रभारित पदों को प्रारम्भिक रूप से नियमित पदों में परिवर्तित किया गया है और उनकी उपयुक्तता का विनिश्चय ऐसे तरीके से करली गई है, जो सरकार किसी आज्ञा से साधारणतया या विशेषतया निर्देशित करे।

स्पष्टीकरण—“काय प्रभारित कमचारियों” शब्दावली का वही समान अर्थ होगा, जो “राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग (मवन एव पय) मय बागान,

- 1 वि स प 7(1) कायिक (ब-2) 75 दिनांक 20-9 1975 द्वारा जोड़ा गया।
- 2 वि स प 4(1) DOP/A-2/73 दिनांक 20 9 75 द्वारा जोड़ा गया।

सिंचाई जल प्रदाय तथा आयुर्वेदिक विभाग काय प्रभारित कमचारी सेवा नियम 1964" में परिभाषित किया गया है।

<sup>1</sup>17-ग-अ शकालिक कमचारियों के आमेलन की प्रक्रिया—इन नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी वे व्यक्ति जो किसी विभाग में ऐसे पदों पर जो आरम्भ में स्वीकृत किये गये और (बाद में) नियमित स्थापन पर ले आये गये अथवा कालोन (पाट टाइम) आधार पर पहले नियुक्त किये गये थे और जो ऐसे पद पर कार्य कर रहे हैं, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समीक्षा के बाद ऐसे पदों पर जो प्रशासनिक विभाग में सरकार द्वारा समकल घोषित किये जाय, केवल एक बार आमेलित तथा नियुक्त किये जा सकेंगे, यदि 14-78 को उन्होंने कम से कम दो वर्ष की सेवा कर ली हो या जो 14-76 के पहले नियुक्त किये गये थे और उनकी उपयुक्तता का उस तरीके से विनिश्चय करने के बाद, जसा कि सरकार एक आज्ञा द्वारा साधारणतया या विशेषतया निर्देशित करे।

18 अर्जेंट अस्थायी नियुक्तिया—(1) सेवा में की गिती, जिसे इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा तत्काल नहीं भरा जा सके यथा-स्थिति सरकार या नियुक्ति करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे अधिकारी की स्थानापन्न रूप से नियुक्ति करके जो पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र हो या अस्थायी रूप से ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करके, जो सेवा में सीधी भर्ती का पात्र हो, जहां एनी सीधीभर्ती के लिये इन नियमों के उपबन्धों के अधीन उपबधित किया गया हो, भरी जा सकेगी

<sup>2</sup>[परंतु—×× विलोपित ××]

<sup>3</sup>(2) पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता की दशा में उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन वांछित पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, सरकार अर्जेंट अस्थायी आधार पर रिक्तियों को भरने के लिये, वेतन व अन्य भत्तों सम्बन्धी ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के साथ जो वह निर्देशित करे, अनुमति प्रदान करने के लिये सामान्य निर्देश दे सकेगी,

1 वि स प (1) DOP/A-II/78, G S R 28, दिनांक 19 सितम्बर 1978 द्वारा जोड़ा गया।

2 वि सख्या प 4 (1) DOP/A-2/74 II दिनांक 21 7 1976 द्वारा निविष्ट।



ऐसी नियुक्तियाँ, येनकेन, उक्त उपनियम में वांछित के अनुसार प्रायोग की सहमति के अध्वधीन होगी।<sup>3</sup>

19 वरिष्ठता—सेवा के प्रत्येक प्रवर्ग में वरिष्ठता उक्त विशिष्ट प्रवर्ग के किसी पद पर की गई अधिष्ठायी नियुक्ति के वप के अनुसार अवधारित की जायेगी

परंतु (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पहले ही तथा/अथवा राजस्थान राज्य के पुनगठन के पहले सेवामो के एकीकरण की प्रक्रिया में या राज्य के पुनगठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित नये राजस्थान राज्य की सेवामों में नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, विभाग में अध्यक्ष द्वारा तदय आधार पर अवधारित, उपा तरित या परिवर्तित की जायेगी,

(2) किसी विशिष्ट ग्रेड के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही समय के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता ऐसे व्यक्तियों के सिवाय जिनकी रिक्रि पर नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया किंतु जो सेवा में उपस्थित नहीं हुये, उसी क्रम में रहेगी जिसमें उनको नियम 16 के अधीन तैयार की गई सूची में रखा गया है।

1(3) नियम 17 के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस पद पर या समतुल्य पद पर जिस पर वे ऐसी नियुक्ति से पहले काय कर रहे थे, लगातार काय करने के दिनांक के अनुसार विनिश्चित की जायेगी

2(4) विभिन्न श्रेणी के पदों को, जिनसे उच्चतर पदों पर पदोन्नति इन नियमों में उपबोधित है, धारण करने वालों की एकीकृत वरिष्ठता पदों की निम्नतम श्रेणी (कटेगरी) पर अधिष्ठायी नियुक्ति के वप के अनुसार संपादित की जायेगी।

3(5) नियम 17 (ग) के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता नियुक्त प्राधिकारी द्वारा उस पद पर, जिस पर वे ऐसी नियुक्ति से पहले काय कर रहे थे, लगातार काय करने की दिनांक के अनुसार विनिश्चित की जायेगी।

3 वि सख्या प 7 (7) कांमिक/क-2/75 दिनांक 31 10 1975 द्वारा विलोपित।

1 वि स एफ 4 (1) DOP/A-2/73 दिनांक 20-9-75 द्वारा जोड़ा गया।

2 वि स एफ 4 (1) DOP/A-2/73 दि 21-7-76 द्वारा जोड़ा गया तथा दि 23-10-75 से प्रभावी।

3 वि स एफ 4 (1) DOP/A-2/78 दि 19 सित 1978 द्वारा जोड़ा गया।

## 20 परिवीक्षा की अवधि—

<sup>1</sup>[सेवा में किसी अधिष्ठायी रिक्ति के विरुद्ध सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त समस्त व्यक्तियों को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाएगा और उनको जो सेवा में पदोन्नति/विशेष चयन द्वारा अधिष्ठायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किये गये हैं, एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाएगा]

पर तु यह है कि—

(1) उनमें से ऐसे व्यक्तियों के लिये जिन्होंने पदोन्नति/विशेष चयन द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा अधिष्ठायी रिक्ति के विरुद्ध उनकी नियुक्ति से पहले उस पद पर अस्थायी रूप से स्थानापन्न काय किया, जो बाद में नियमित चयन द्वारा अनुसरित हुआ, उनको नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी स्थानापन्न या अस्थायी सेवा को परिवीक्षा की अवधि में संगणित करने की अनुमति दी जा सकेगी। येन केन, यह किसी वरिष्ठ व्यक्ति का अतिष्ठत अन्तर्वर्तित होना या भर्ती में सम्बन्धित कोटा या प्राक्षरण में उनकी प्राथमिकता को अस्त व्यस्त करना नहीं माना जावेगा।

(11) ऐसी नियुक्ति के बाद ऐसी अवधि जिसमें कोई व्यक्ति किसी समान पद या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रहा हो, तो वह अवधि परिवीक्षा की अवधि में संगणित की जावेगी,

(2) उप नियम (1) में वर्णित परिवीक्षा की अवधि के दौरान, प्रत्येक परिवीक्षाधीन को ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और ऐसे प्रशिक्षण में जाने के लिये कहा जा सकता है, जैसा सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण—ऐसे व्यक्ति के मामले में जो मर जाता है या अधिवार्षिकी प्राप्ति करने के कारण सेवा नियुक्त होने वाला है, उसकी परिवीक्षा की कालावधि घटाकर उसकी मृत्यु के या सरकारी सेवा से निवृत्त होने के ठीक पहले वाले दिन के एक दिन पहले समाप्त हुई समझी जायेगी। स्थायीकरण से सम्बन्धित नियम में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति के मामले में अधित्यक्त समझी जायेगी।

<sup>2</sup>20 क—नियम 21 में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी

1 वि स प 1 (35) कार्मिक/क-2/74 दि 9-4-79 द्वारा प्रतिस्थापित।

2 वि स एफ 1 (14) T70 दिनांक 16-9-71 द्वारा निविष्ट तथा समसम्यक दिनांक 22-1-74 तथा वि स एफ 7(7) DOP/A II/74 दि 28 12 74 द्वारा प्रतिस्थापित। राजपत्र दि 20 5 76 में हिंदी पाठ में इसे नियम '21 क' के रूप में दिया गया है, जो गलत है।

द्वारा 6 माह की कालावधि के भीतर यदि स्थायीकरण का कोई आदेश जारी नहीं किया जाता है, तो अस्थायी या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने भर्ती के किसी भी तरीके से हुई अपनी नियमित भर्ती की तारीख के पश्चात् दो वर्ष का या उन सौगो के मामले में कम का जो पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये हैं और जहाँ परिवीक्षा की कालावधि कम विहित की गई है, उसी प्राधिकारी के अधीन उसी पद पर या किसी उच्चतर पद पर सेवाकाल पूरा कर लिया हो यदि वह प्रतिनियुक्ति पर न जाता या प्रशिक्षणाधीन न होता तो इस प्रकार कार्य करता स्थायी रिक्रिया होने पर नियमों के अधीन विहित कोटा के तथा उसकी वरिष्ठता से अध्यधीन रहते हुए स्थायी माने जाने का हक्दार होगा यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति नियमों के अधीन स्थायीकरण की विहित शर्तें पूरी कर ले,

परंतु यदि कर्मचारी का कार्य सतोपप्रद नहीं रहा है या उसने स्थायीकरण के लिए विहित शर्तें, यथा-विभागीय परीक्षा, प्रशिक्षण या पदोन्नति सद्यः पाठ्यक्रम आदि उत्तीर्ण करना, पूरी न की हो तो उपर्युक्त कालावधि उस सीमा तक जो कि राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम 1959 और बिन्ही अध्याय नियमों के अधीन परिवीक्षा के लिये विहित है या एक वर्ष जो भी विहित शर्तों को पूरा करने में या सतोप कराने में असफल हो जाता है तो वह ऐसे पद से ठोक उस तरीके से जिस तरीके से एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति सेवोन्मुक्त किये जाने के या उसके अधिष्ठायी अथवा निचले पद पर, यदि कोई हो, जिसके लिये वह हक्दार हो, प्रतिवर्तित किये जाने के दायित्वाधीन होगा

परंतु यह और कि—उक्त कालावधि के दौरान उसके सतोपप्रद कार्य निष्पादन के विरुद्ध यदि उसे कोई कारण समुचित नहीं किया गया तो सेवा को उक्त कालावधि के पश्चात् स्थायीकरण से उसे विवर्जित नहीं किया जा सकता।

(ख) खण्ड (क) के द्वितीय परंतु में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी का स्थायी न किये जाने के कारणों को यदि कर्मचारी अराजपत्रित हैं, तो नियुक्ति प्राधिकारी उस कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में तथा गोपनीय प्रतिवेदन पत्रावली में तुरन्त अभिलिखित करेगा तथा राजपत्रित अधिकारी की दशा में, उन कारणों से, महालेखाकार राजस्थान को समुचित करेगा तथा उस अधिकारी की गोपनीय प्रतिवेदन पत्रावली में अभिलिखित करेगा। इन सभी मामलों में लिखित रसीद अभिलेख में रखी जायेगी।

स्पष्टीकरण—(1) इन नियमों के प्रयोजनार्थ 'नियमित भर्ती' से अभिप्रेत है भर्ती के किसी भी तरीके से की गई नियुक्ति या सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु के अधीन प्रस्थापित बिन्ही सेवा नियमों के अनुसार की गई नियुक्ति या उन पदों पर की गई नियुक्ति जिनके लिये

कोई सेवा नियम विद्यमान नहीं है, यदि पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में है तो भर्ती उनके परामर्श से की गई है लेकिन इसमें अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति, तदर्थ नियुक्ति या ऐसी अस्थायी या धारणाधिकार के अधीन रिक्तियों पर जो वर्पानु वष पुनरावलोकन एवं पुनरोक्षण के दायित्वाधीन है, स्थानापन्न पदोन्नति सम्मिलित नहीं है। ऐसी दशा में जहाँ सेवा नियम विनिर्दिष्ट स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति की अनुज्ञा देते हों, तो ऐसी नियुक्ति नियमित भर्ती ही मानी जायगी यदि उस पद पर नियुक्ति, जिस पर से उसका स्थानांतरण हुआ था, नियमित भर्ती के पश्चात् हुई थी। नियमों के अधीन पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति के पात्र व्यक्ति नियमित भर्ती किये हुये व्यक्तियों के रूप में माने जायेंगे।

(11) वे व्यक्ति जो किसी दूसरे सबग में धारणाधिकार रखते हैं, इस नियम के अधीन स्थायी किये जाने के पात्र होंगे तथा वे यह विकल्प देने के भी पात्र होंगे कि क्या वे इस नियम के अधीन उनकी अस्थायी नियुक्ति के दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् स्थायीकरण नहीं चाहते। इसके प्रतिकूल कोई भी विकल्प न दिये जाने की दशा में इस नियम के अधीन उनका विकल्प स्थायीकरण के लिये दिया हुआ समझा जाएगा और पूरे पद पर उनका धारणाधिकार समाप्त हो जायगा।

21 स्थायीकरण (पुष्टीकरण-कनफर्मेशन)—परिबीक्षाधीन व्यक्ति अपने पद पर परिबीक्षा कालावधि की समाप्ति पर स्थायी कर दिया जायगा, यदि—

(क) वह विभागाध्यक्ष परीक्षा में, यदि कोई हो, पूरा तथा पास हो गया है,

(ख) विभागाध्यक्ष का समाधान हो गया है कि—उसकी सरपनिष्ठा सदेह से परे है और वह अथवा स्थायीकरण के योग्य है।

×21-क—नियम 21 में किसी बात के होते हुए भी एवं परिबीक्षाधीन को उसकी नियुक्ति में उसकी परिबीक्षा की कालावधि के अंत में स्थाई कर दिया जायेगा, चाहे नियम में विहित विभागीय परीक्षा/प्रशिक्षण हिंदी में प्रवीणता परीक्षा, यदि कोई हो, परिबीक्षा की कालावधि के दौरान आयोजित नहीं किये गये हों, परन्तु (1) वह अथवा स्थायीकरण के लिए योग्य है, तथा (11) परिबीक्षा की कालावधि राजस्थान राजपत्र में इस सशोधन के प्रकाशित होने के दिनांक को या इससे पहले समाप्त हो जाती है।

22 परिबीक्षा के दौरान वेतन—सेवा सबग में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति का प्रारम्भिक वेतन उस पद के वेतनमान का न्यूनतम होगा।

23 परिवीक्षा के दौरान वेतन वृद्धि—परिवीक्षाधीन व्यक्ति राजस्थान सेवा नियम 1951 के उपबन्धों के अनुसार उसको अनुज्ञेय वेतनमान में वेतन वृद्धि लेगा।

24 छुट्टी, भत्ते, पेन्शन, आदि का विनियमन—सेवा के सदस्यों के वेतन भत्ते, पेन्शन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें इन नियमों में उपबन्धित के सिवाय, निम्नलिखित द्वारा विनियमित होगी —

(1) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1949, अद्यतन सशोधित।

(2) राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान एकीकरण) नियम 1956, अद्यतन सशोधित,

(3) राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान युक्तियुक्तकरण) नियम 1956, अद्यतन सशोधित,

(4) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958, अद्यतन सशोधित,

(5) राजस्थान सेवा नियम 1951, अद्यतन सशोधित,

(6) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1961 और

(7) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परतुब के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गए कोई अन्य नियम जिसमें सेवा की सामान्य शर्तें विहित की गई हो और जो तत्समय प्रवृत्त हो।

25 शर्तों का निराकरण—यदि इन नियमों के लागू किये जाने और इनके विस्तार के बारे में कोई शका उत्पन्न हो, तो मामला सरकार के पात न्यायिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

26 निरसन तथा व्यापृति—इन नियमों के अन्तर्गत आने [वाले विषयों] सम्बन्धित समस्त नियम तथा आदेश, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त हो इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं,

परतुब इस प्रकार अतिष्ठित नियमों तथा आदेशों के अधीन की गई बायबाही इन नियमों और आदेशों के तत्सम्बन्धी उपबन्धों के अधीन दिया गया आदेश या की गई बायबाही समझी जायगी।

× अनुसूची I

क्रम सं०	पद का नाम	भर्ती का सरीका प्रतिशत सहित	सीधी भर्ती के लिये ग्रहणार्थ	पद जिनसे पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जानी है	पदोन्नति के लिये अपेक्षित न्यूनतम अनुभव तथा ग्रहणार्थ	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	दफ्तरी	100% पदोन्नति द्वारा	—	रिवाइ या युव लिफ्टर	जिल्दसाजी का अनुभव/ कायक्षमता	—
2	जमादार	„	—	1 रिवाइ या युव लिफ्टर या बाइंडर 2 चपरासी 3 साइकल सवार 4 भदली 5 जलधारी 6 चौकीदार 7 फर्निचर 8 कार्यालय के कार्य के लिये निम्न- तम वेतनमान में स्वीकृत समतुल्य पद 9 भयी 1 चपरासी 2 साइकल सवार 3 भदली	चपरासी पर नियंत्रण आदि रखने की क्षमता	जिल्दसाजी में अनुभव जिल्द- साजी में कार्य
3	रिवाइ या युव लिफ्टर/ बाइंडर	„	—			

× वि सं एफ 4 (1) DOP/A-II/73 दि 20 9 1975 द्वारा प्रतिस्थापित  
एव दि 19 9 78 तक सशोधित ।

1	2	3	4	5	6	7
					क्षमता	
				4	जलघारी	बुक बाइंडर के लिये
				5	चौकीदार	बुक लिपटर के लिये
				6	फर्राश	लिये हिंदी तथा अको का कार्यकारी ज्ञान
				7	कार्यालय के	कार्य के लिये निम्नतम वेतनमान में स्वीकृत समतुल्य पद

अभ्युक्ति—क्षेत्रीयस्तर के लिये प्रायोगिक परीक्षा ली जा सकती है।

- 4 (1) अपरासी 100% किसी मायता — — क्षेत्रीय  
 (2) साइकल सीधी प्राप्त स्कूल से  
 सवार भर्ती से बसा पाव  
 (3) प्रवर्ती उत्तीर्ण हो  
 (4) जलघारी  
 (5) चौकीदार  
 (6) फर्राश  
 (7) कार्यालय के कार्य के लिये निम्नतम वेतनमान में स्वीकृत समतुल्य पद

अभ्युक्ति—क्षेत्रीयस्थिति प्राधिकारी द्वारा स्तम्भ 4 में विहित गृहताओं को शिथिल किया जा सकता है—(1) यदि अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हों,

(11) यदि महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों के लिये पर्याप्त संख्या में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न हों।

स्पष्टीकरण—(1) “कार्यालय के कार्य के लिये निम्नतम वेतनमान में स्वीकृत समतुल्य पद” अभ्युक्ति में अपरासी के पद के लिये स्वीकृत वेतनमान के समतुल्य वेतनमान में स्वीकृत पद सम्मिलित है और इसमें क्षेत्रीय कार्य या फेडरल

या वकशाप के लिये स्वीकृत पद या जिनके लिये अलग से पदोन्नति की पक्ति उपबधित है, जैसे—हेल्पर, मेट, कीट सप्राहक प्रयोगशाला बाँय आदि, सम्मिलित नहीं होंगे ।

(11) यदि किसी विभाग में स्तम्भ 5 में क्र स 1 के विरुद्ध वर्णित पद विद्यमान नहीं है, तो स्तम्भ 5 में क्र स 2 के विरुद्ध वर्णित पदों को धारण करने वाले व्यक्ति स्तम्भ 2 में क्र स 1 में वर्णित पदों पर पदोन्नति के लिये पात्र होंगे ।

## अनुसूची II

- 1 नाम
- 2 पद
- 3 शैक्षिक योग्यता
- 4 पद जिसके लिये आवेदन पत्र दिया गया है
- 5 वर्तमान नियुक्ति पर सेवा का काल
- 6 अग्रे पक्ष प्राधिकारी की अभ्युक्तियाँ

अग्रे पक्ष प्राधिकारी का नाम तथा पद

\_\_\_\_\_



राजस्थान लिपिकवर्गीय एवं  
चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम

विवेचना—खण्ड [2]

अध्याय

विषय

- 1 सेवा नियमों का स्वरूप एवं परिचय  
[Introduction to & Nature of Service Rules]
  - 2 सेवा में प्रवेश—भर्ती एवं नियुक्ति  
[Recruitment & Appointment]
  - 3 आरक्षण—(अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये)  
[Reservation for S C / S T]
  - 4 अत्यावश्यक अस्थायी नियुक्तियाँ  
[Urgent Temporary Appointments]
  - 5 परीक्षा एवं स्थायीकरण  
[Probation & Confirmation]
  - 6 वारिष्ठता सूची एवं वरिष्ठता के मापदण्ड  
[Seniority List & the Basis of Seniority]
  - 7 पदोन्नति मापदण्ड, पात्रता एवं तरीका  
[Promotion—its Criteria, Eligibility & Procedure]
  - 8 विविध—मासले  
[Miscellaneous]
-

अध्याय  
1

## सेवा-नियमों का स्वरूप एवं परिचय

### [Introduction to & Nature of Service Rules]

#### अनुक्रम

- |                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1 सरकारी सेवा में प्रवेश  | 7 विद्यमान नियमों का प्रतिष्ठान/निरसन |
| 2 सरकारी सेवा की कहानी    | 8 निवचन के सिद्धान्त                  |
| 3 सेवा नियमों का स्वरूप   | 9 कुछ महत्वपूर्ण परिभाषायें --        |
| 4 सेवाओं का वर्गीकरण एवं  | (क) नियुक्ति प्राधिकारी               |
| सेवा-नियमों की रूपरेखा    | (ख) अधिष्ठाता नियुक्ति                |
| 5 नियमावली-प्रसंग         | (ग) सेवा या अनुभव                     |
| 6 संक्षिप्त नाम तथा आरम्भ | 10 नियमों का अर्थ करना                |

1 सरकारी सेवा में प्रवेश—हर व्यक्ति सरकारी-सेवा में प्रवेश करने की कोशिश करता है कि तु सरकारी सेवा एक प्रकार से “नियमों के जाल” में फँसी हुई जिन्दगी है, जिसकी अपनी अनेक समस्याएँ हैं। इसलिए एक सरकारी मेवक को सम्बन्धित नियमावलियों का माचारण ही नहीं बरन सम्पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। नियमों का ज्ञान न होने से उसे सेवा के मामलों में पीछे रहना होगा और उसे हानि उठानी होगी। इसी दृष्टिकोण से इस पुस्तक की रचना की गई है। सेवा में प्रवेश के साथ सम्बन्धित नियमों का ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का कर्तव्य है।

2 सरकारी सेवा की कहानी एक रूप रेखा—एक व्यक्ति सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए पहले भर्ती (recruitment) की कोशिश करता है, जो आजकल अधिकतर प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होती है। भर्ती होने पर उसे नियुक्ति (appointment) प्राप्त होती है और उसका सेवाकाल अनेक नियमों से शासित होने लगता है। यह नियुक्ति अस्थायी या स्थायी होती है तथा उसे नियमानुसार ‘परिवर्धन’ (प्रोमोशन) पर रखा जाता है और उसके कार्य, व्यवहार तथा कुशलता की परख कुछ निश्चित अवधि के लिए की जाती है। इसके बाद स्थायी पद रिक्त होने पर

उसे स्थायी या पुष्ट (क्वॉन्फ़र्मेशन) कर दिया जाता है या अस्थायी पद पर वह कई वर्षों तक अस्थायी ही चलता रहता है।

स्थायीकरण (क्वॉन्फ़र्मेशन) के बाद उसे सबग (कॉर्डर) में सम्मिलित किया जाता है और वह अपने पद पर बने रहने का पदाधिकार (लिमन) प्राप्त करता है। इस पर उसका नाम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किया जाता है जो नियमांनुसार बनाई जाती है। इस वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति (प्रोमोशन या टर्नफी) अगला उच्चतर पद रिक्त होने पर की जाती है। इस बीच उसे निश्चित नियमों के अनुसार वेतनमान में वेतन तथा वार्षिक वेतन वृद्धियाँ (इंक्रीमेंट) व ग्रॉस भत्ता मिलते हैं। उसे 'दक्षतावरोध' (E B) पार करने पर ग्रॉस की वेतन वृद्धियाँ मिलती हैं। आजकल नवीन वेतनमान में 'दक्षतावरोध' समाप्त कर दिया गया है, पर कई शर्तें वेतनमान के साथ जोड़ दी गई हैं, जिनकी पूरा करने पर ग्रॉस की वेतन वृद्धियाँ मिल पाती हैं।

उसकी कार्यकुशलता तथा व्यवहार की सदा परीक्षा चलती रहती है और उसका वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (या मूल्यांकन रिपोर्ट) तैयार किया जाता है, जिसमें दी गई "प्रतिकूल प्रविष्टियाँ" उसकी पदोन्नति के लिये बाधक होती हैं। पदोन्नति भी स्थानापन्न या अस्थायी होती है और कई बार वापस पिछले निम्न पद पर प्रत्यावर्तन भी हो जाता है। पदोन्नति के बाद 'परिचोखापर' कार्य करने के बाद उस उच्चतर पद पर 'स्थायीकरण' (पुष्टिकरण) किया जाता है।

इस बीच किसी अनियमितता या नियम भङ्ग का दोषी होने पर विभागीय जाच के बाद राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अधीन कोई दण्ड भी दिया जा सकता है। 20 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद 'अनिवार्य सेवा नियुक्ति' की समस्या भी आ सकती है। अन्त में 55 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर सेवा निवृत्ति (रिटायरमेंट) के साथ सरकारी सेवा समाप्त हो जाती है और नियमानुसार 'पेंशन' आजीवन मिलती है।<sup>1</sup>

इस प्रकार एक सरकारी कर्मचारी का पूरा सेवाकाल नियमों के जाल में डलका रहता है।

3 सेवा-नियमों का स्वरूप--एक सरकारी कर्मचारी की सेवायें नियमों से शासित होती हैं जो भारतीय-संविधान के अनुच्छेद 309 अथवा उसके पर-बुद्ध के अधीन बनाये जाते हैं। नियमों के अधीन सरकारी नौकरी एक प्रकार स्तर या प्राप्ति का मामला है, न कि सत्रिदा वर<sup>1</sup> ये नियम सरकारी कर्मचारी तथा सरकार

1 दिनेश चन्द्र सायमा बनाम असम राज्य 1977 Lab IC 1852(SC),  
रोशनसालन टण्डन बनाम भारत सघ AIR 1967 SC 1889,

दोनों पर बाधक हैं।<sup>2</sup> ये नियम 'संवैधानिक नियम' हैं तथा इनको विधि (कानून) माना जाता है। इन नियमों का भंग होने पर 'यायालय या ट्राइब्यूनल में शरण ली जा सकती है।' जब यह एक सुस्थापित मत है कि ये नियम विधायी स्वरूप के हैं और इनकी व्याख्या के लिये इनको कानून के समान माना जाता है।<sup>3</sup> जहाँ ऐसे संवैधानिक नियम नहीं हों वहाँ सरकार प्रशासनिक निर्देशों से भी सेवा की शर्तें लागू कर सकती है।<sup>4</sup> नियमों के नीचे दो हुई टिप्पणियाँ इनका अ करने में सहायक मानी गई हैं।<sup>5</sup> जहाँ नियम किसी बारे में शान्त हो वहाँ कालकारी आज्ञायें उन अन्तरालों (gaps) को पूरा कर सकती हैं।<sup>6</sup>

इस प्रकार सरकार संवैधानिक नियमों तथा प्रशासनिक या कालकारी आज्ञाओं से सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करती है।

4 सेवाओं का वर्गीकरण एवं सेवा नियमों को रूप देना - राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को वर्गीकृत करने के लिये 'राजस्थान सिविल सेवाओं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अधीन) नियम 1958' के नियम 6 से 11 में विवरण दिया गया है तथा अनुसूची I से IV में तालिकाएँ दी गई हैं। इसी प्रकार "राजस्थान सेवा नियम 1951" के भाग (2) में परिशिष्ट XII में भी इनकी सूची दी गई है। इनके अनुसार राजस्थान की सिविल सेवाओं को चार श्रेणियों में बाँटा गया है -

- I राज्य सेवाएँ (State Services),
- II अधीनस्थ सेवाएँ (Subordinate Services)
- III लिपिक वर्गीय (या अत्रालयिक) सेवाएँ (Ministerial Services)
- IV चतुर्थ श्रेणी सेवाएँ (Class IV Services)

- 
- 2 एन के चौहान बनाम गुजरात राज्य 1977 SCC (L & S) 127
  - 3 AIR 1961 SC 868, 1969 Lab 1 C 100 (SC), AIR 1961 SC 751, AIR 1967 SC 1910, 1972 SC 1546, 1972 SC 1429
  - 4 डॉ अमर जीत सिंह अहलूवालिया बनाम पंजाब राज्य AIR 1975 SC 984, सन्तराम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य AIR 1967 SC 1910, जे पी माथुर बनाम भारत सघ 1974 RLW 396  
भारत सघ बनाम माजी जगामाया 1977 SCC (L & S) 191
  - 5 तारासिंह बनाम राजस्थान राज्य AIR 1975 SC 1487

इन सभी सेवाओं में अलग-अलग कई सबग च सबार्गे हैं, जिनके लिये प्रत्येक प्रत्येक "भर्ती एवं भ्रम्य सेवा की शर्तों" सम्बन्धी नियमावलिया बनाई गई हैं, जो विभिन्न विषयों पर नियमों द्वारा उपबन्ध करती हैं —

- (1) सबग (काठर) — स्टाफ की प्रारिपति, पदों के नाम, सख्या,
- (2) भर्ती के तरीके — पात्रता की शर्तें (राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षणिक योग्यता, चरित्र, शारीरिक स्वस्थता आदि, तथा ग्रहता (योग्यता) की भ्रम्य शर्तें ।
- (3) सीधी भर्ती का तरीका,
- (4) पदोन्नति द्वारा भर्ती का तरीका,
- (5) नियुक्ति, परिवर्तन, पुष्टीकरण, वेतनमान, वरिष्ठता के सिद्धांत आदि ।

इनके अतिरिक्त प्रत्येक नियमावली के अन्त में उन सामान्य नियमों की एक सारिणी भी दी गई है, जिनसे ये सेवाएँ शासित होंगी हैं ।

इस पुस्तक में हम इन चार श्रेणियों में से केवल अन्तिम दो श्रेणियों अर्थात् लिपिक वर्गीय सेवा तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा की नियमावलियों के हिन्दी पाठ संहिता विवेचना प्रस्तुत कर रहे हैं । इनमें पदोन्नति, वरिष्ठता तथा स्थायीकरण सम्बन्धी अध्यायों श्रेणी I तथा II के सरकारी सेवकों के लिये भी उपयोगी हैं । सेवा सम्बन्धी मामलों के लिये हम पाठकों से पुस्तक "सेवा सम्बन्धी मामलों एवं अपील ट्रिब्यूनल कानून" तथा विभागीय जांच, अनुशासन एवं दण्ड सम्बन्धी मामलों के लिये पुस्तक "अनुशासनिक कार्यवाही" पढ़ने का अनुरोध करते हैं, जो अपने विषय की भाषा भूल पुस्तकें हैं ।

### 5 नियमावली प्रसार

विषय	अधीनस्थ कार्यालय	सचिवालय	अधीनस्थ कार्यालय	पञ्च दल समिति	चतुर्थ श्रेणी
1 सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ (प्रवृत्त) होने की दिनांक	1 20 6-57	1 5 5-70	1 27 3-58	1 2 10 59	1 12 7 63
2 विद्यमान नियमों का					
1. अतिष्ठन/निरसन	2	38	2	×	26
3 परिभाषाएँ	4	2	3	2	2
4 निवचन	5	3	4	×	3

6 सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ— इन सब नियमावलियों का नियम 1 उस नाम का उल्लेख करता है जिससे इन नियमों को पुकारा जाता है या प्रसंग दिया जाता है। ऊपर तालिका में हमने उन दिनाकों का प्रसंग दिया है जिनको ये नियम प्रारम्भ या प्रवृत्त हुये—अर्थात्—लागू किये गये। इस लागू होने की दिनांक के बाद ही इन नियमों के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती है।

7 विद्यमान नियमों का प्रतिष्ठान/निरसन—अधीनस्थ कार्यालय नियमावली तथा अधीनस्थ 'यायालय नियमावली' के नियम (2) इससे पहले के समस्त नियमों और आज्ञाओं को समाप्त (प्रतिष्ठित) करते हैं—अर्थात् वे इन नियमों के लागू होने के दिनांक के बाद लागू नहीं होंगे। परन्तु इसके लिये शर्तें भी दी गई हैं—(1) कार्यवाही जो पुराने नियमों या आज्ञाओं के अनुसार की गई वह वैध होगी और इन नियमों के अधीन की गई कार्यवाही मानी जावेगी।

(2) ये नियम राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से जो सेवाओं का एकीकरण किया गया और नियुक्तियाँ की गईं उन पर लागू नहीं होंगे।

इसी प्रकार सचिवालय-नियमावली के नियम 38 द्वारा विद्यमान नियमों व आज्ञाओं को निरसित या समाप्त कर उनके अधीन की गयी पुरानी कार्यवाही को इन नियमों के अधीन मानकर नियमित किया गया है।

8 निबन्धन (अर्थ करने) के सिद्धान्त—इन नियमावलियों का निबन्धन या अर्थ करने के लिये 'साधारण खण्ड अधिनियम' के सिद्धान्त लागू किये गये हैं और विधानसभा के अधिनियमों की तरह इनका भी अर्थ किया जाता है।

निबन्धन के लिए किसी नियम या अधिनियम में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की पहले परिभाषायें दी जाती हैं, इससे उन शब्दों का सही अर्थ समझा जा सकता है जिसमें उनका प्रयोग किया गया है। परिभाषाओं के पहले एक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है—“जब तक कोई बात विषय अथवा सन्दर्भ में विद्वद् न हो”। इसका अर्थ है कि—जब तक विषय या प्रसंग से कोई दूसरा अर्थ न निकलता हो, तो इस परिभाषा में दिया गया अर्थ ही माना जावेगा। इस प्रकार अर्थ करते समय विषय का तथा उसके प्रसंग का ध्यान रखना आवश्यक है। यह एक स्थापित मत है। इन सर्वपानिक नियमों में जो परिभाषायें दी हुई हैं उनमें मुलाकर उनका सही, सत्य व स्वतंत्र अर्थ लगाना या उसमें सुधार या संशोधन करना 'यायालय' का कार्य नहीं है।<sup>1</sup> परन्तु इन नियमों का जो अर्थ व व्याख्या सरकार या विभाग द्वारा की जाती है उसे मानने के लिए 'यायालय' बाध्य नहीं है, परन्तु ये नियमों

की भाषा तथा अर्थ सिद्धान्तों के अनुसार उनकी सही व्याख्या करते हैं।<sup>1</sup> निवचन यानी अर्थ करने के मामलों में साधारणज्ञान के नियमों की बजाय व्याकरण के नियमों को प्रमुखता दी जाती है।<sup>2</sup> जो कुछ विधि यानी नियमों में प्रकट या अप्रकट रूप से अधिष्ठित नहीं किया गया है, नहीं बताया गया है, उसे अर्थ करते समय लागू नहीं किया जा सकता।<sup>3</sup> जहाँ कोई दुविधा या दो अर्थ नहीं निक्कलते हैं, वहाँ उन शब्दों का क्या अर्थ है, यही देखना होता है।<sup>4</sup> परन्तु परिभाषाओं की भाषा 'या' या 'तयों' की भाँति होती है, इनमें दिया गया अर्थ साधारण, लोकप्रिय तथा प्राकृतिक अर्थों से भिन्न भी हो सकता है और किसी प्रकार के संदेह या शका को दूर रखने के लिए ही नियमों में निवचन सण्ड या परिभाषायें दी जाती हैं। इस प्रकार इन नियमों के लिये वही परिभाषायें भाँति होगी, जो इन नियमों में दी गई हैं। दूसरे अधिनियम या नियमों की परिभाषायें यहाँ लागू नहीं होंगी।<sup>5</sup> कृपया इसे सदा ध्यान में रखिये

9 कुछ महत्वपूर्ण परिभाषायें—आपको इन नियमों के किसी भाग (उपबन्ध) को पढ़ते समय पहले यह देख लेना चाहिये कि—इन नियमों में आये मुख्य शब्दों की क्या परिभाषायें दी गई हैं? फिर उसी के अनुसार उस नियम का अर्थ कीजिये। यह मुख्य बात है।

इन नियमावलियों में जो परिभाषायें दी गई हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का हम यहाँ विवेचन करेंगे—

(क) नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) 'नियुक्ति प्राधिकारी' वह प्राधिकारी होता है जिसे नियमों के अधीन किसी सेवा या सवर्ग में किसी पद पर नियुक्ति करने का अधिकार होता है। नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार "राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958" के भाग (3) नियम 12 में दिये गए हैं। नियम 12 का सम्बद्ध उपनियम (3) इस प्रकार है—

"(3) किसी लिपिक वर्गीय सेवाओं तथा अतुल्य श्रेणी सेवाओं में समस्त नियुक्तियाँ विभागाध्यक्ष द्वारा इस विषय में जारी किए गए नियमों एवं अनुदेशों के अधीन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की जायेगी।"

2 AIR 1954 SC 584

3 AIR 1961 Raj 59

4 ILR (1961) 11 Raj 56

5 AIR 1964 Raj 243

6 AIR 1965 Raj 5

इस प्रकार लिपिकवर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवानियो का नियुक्ति प्राधिकारी 'कार्यालयाध्यक्ष' है, परन्तु उसे इसके लिए विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किए गए नियमों और निर्देशों के अधीन ही नियुक्ति करनी होगी। परन्तु जब ऐसा नियम या निर्देशों का अभाव हो, तो उसे नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। यह एक समझने योग्य बात है।

इन नियमावलियों में भी 'नियुक्ति प्राधिकारी' की अलग से परिभाषा दी गई है अतः इन नियमों एवं सेवानियों के प्रसंग में ये परिभाषाएँ लागू होंगी जो इस प्रकार हैं--

(1) अधीनस्थ कार्यालयों में नियम 4 (क) —

(i) विभागाध्यक्ष

या (ii) विभागाध्यक्ष द्वारा सरकार की अनुमति से नियुक्ति करने के अधिकार प्रदत्त अधिकारी, जो दिये गए अधिकार की सीमा में रहेगा।

(2) सचिवालय में—नियम 4 (क)—शासन उप सचिव, जो लिपिक वर्गीय स्थापना का कार्य करता है।

(3) अधीनस्थ सिविल न्यायालयों में—नियम 3 (ख)—

(i) जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

या (ii) जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय की अनुमति से, नियुक्ति करने के अधिकार प्रदत्त अन्य अधिकारी, जो दिए गए अधिकारों की सीमा में रहेगा।

(4) पंचायत समिति में—पंचायत समिति/स्थानीय समिति प्रशासन

जिला परिषद् में—जिला परिषद्/उपसमिति प्रशासन

(नियम 2 ड नियोजक प्राधिकारी)

(5) चतुर्थ श्रेणी के लिये—(नियम 2 (क) तथा (ग)

(i) कार्यालयाध्यक्ष (सामान्य वित्तीय सेवा नियम के नियम 3 के अधीन घोषित)

या (ii) वह अधिकारी, जिसे कार्यालयाध्यक्ष ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित करे।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि—नियुक्ति प्राधिकारी हो स्थायीकरण (पुष्टीकरण), पदोन्नति, वरिष्ठता निर्धारण, प्रत्यावर्तन तथा सेवानुक्ति एवं पदच्युति के दण्ड की कार्यवाही करने के लिये अधिकृत है। केवल नियुक्ति करने का अधिकार जिसे प्रत्यायोजित किया गया है, वह अधिकारी उपरोक्त कार्यवाही सभी वर सकेगा जब उसे स्पष्ट रूप से ऐसा करने का अधिकार भी दिया गया हो। इस प्रकार अधिकार या शक्ति का प्रत्यायोजन एवं लिखित विशेष प्राप्ता द्वारा ही किया जा सकेगा, जो अधिसूचित की जायेगी।



## (स) अधिष्ठायी-नियुक्ति (Substantive-Appointment)

अधीनस्थ कार्यनिय, सचिवालय तथा चतुर्थ श्रेणी की नियमावतियों में यह परिभाषा एक समान रूप से दिनांक 5-7-74 को जोड़ी गई है। यह परिभाषा वरिष्ठता निर्धारण करने के लिये महत्वपूर्ण है। इसका विशेषण इस प्रकार है -

(1) इन नियमों में विहित (दिये गये) शर्तों के किसी भी तरीके से समुचित (due) चयन" किया जाना इसकी पहली शर्त है। इस प्रकार शर्तों के जो तरीके इन नियमों में दिये गये हैं उनके द्वारा चयन होना आवश्यक है। हिन्दु "ग्रजेंट अध्यायी नियुक्ति" को इसके लिये स्वीकार नहीं किया जावेगा। किसी सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गई शर्तों को समुचित चयन माना है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के पश्चात् के अधीन बनाये गये किसी नियम के अनुसार की गई शर्तों भी समुचित है। इस प्रकार दूसरे शब्दों में, यह नियुक्ति नियमित होनी चाहिये, मनमानी नहीं।

(2) इन नियमों के प्रावधानों के अधीन की गई नियुक्ति होना दूसरी शर्त है, - अर्थात्—नियमों में दी गई शर्तें पूरी होनी चाहिये।

(3) यह नियुक्ति किसी अधिष्ठायी रिक्त स्थान यानी स्थायी रिक्त स्थान पर होगी, न कि अध्यायी स्थान पर।

दूसरे शब्दों में—“कोई नियुक्ति स्थायीकरण (कनफर्मेशन) के बाद ही अधिष्ठायी नियुक्ति होगी।”

(4) “परिबीक्षा पर” या परिबीक्षाधीन के रूप में की गई नियुक्ति जब परिबीक्षा की अवधि पूरी हो जाय और पुष्टीकरण कर दिया जावे, तो अधिष्ठायी नियुक्ति होगी।

अधिष्ठायी नियुक्ति, अध्यायी नियुक्ति नियमित नियुक्ति तथा तदर्थ नियुक्ति में अन्तर —

[Substantive, Temporary, Regular and Ad hoc appointment—distinction therein]

“(1) कोई पद या तो स्थायी पद (Permanent Post) होता है या अध्यायी पद हो सकता है

एक स्थायी पद पर नियुक्ति अधिष्ठायी (Substantive) रूप में, जिसे स्थायी रूप (Permanent capacity) में भी कहा जाता है, या अध्यायी/स्थानापन्न या तदर्थ रूप में हो सकती है। किसी स्थायी पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति परिबीक्षा

पर भी हो सकती है। जब नियुक्ति अधिष्ठायी रूप से या परिचीना पर किसी स्थायी पद पर की जाती है, तो यह नियमित नियुक्ति (regular appointment) होगी।

(2) यदि सेवा के नियमों की अनुमति हो तो एक स्थायी पद पर अस्थायी नियुक्ति (temporary) भी नियमित आधार पर दी जा सकती है, परन्तु साधारणतया स्थानापन्न (Officiating) नियुक्ति या तदर्थ (Ad hoc) नियुक्ति कभी भी नियमित नियुक्ति नहीं हो सकती। नियुक्ति करने की शक्तता (competence) को नियुक्ति के स्वरूप (Nature of appointment) से भिन्न करना आवश्यक है।

(3) एक अस्थायी पद पर नियुक्ति स्थायी रूप से (permanently) या अधिष्ठायी रूप से (Substantively) कभी भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उस पद का स्वरूप ही उम नियुक्ति को अस्थायी बना देता है। यदि यह एक पद अल्पकालीन (Short tenure) के लिये सज्जित किया जाता है तो उस पर की गई नियुक्ति भी अस्थायी नियुक्ति होगी यद्यपि भर्ती या नियुक्ति के नियमों के अनुसार यह नियमित नियुक्ति हो सकती है।

(4) किसी स्थायी या अस्थायी पद पर स्थानापन्न या तदर्थ नियुक्ति जब तक नियमित नियुक्ति नहीं की जावे, तब तक के लिये "स्थानपूर्ति की व्यवस्था मात्र" (Only a stop gap arrangement) हैं। परन्तु यह स्थानापन्न नियुक्ति कई बार थोड़ी सी भिन्न अंशों में भी आती है (i) कई बार स्थानापन्न नियुक्ति उस समय की जाती है, जब उस पद का धारक अवकाश पर है और इस बीच के लिये कोई व्यवस्था करनी होती है, या (ii) कई बार स्थानापन्न नियुक्ति किसी की उच्चतर पद पर उपयुक्तता की परख करने के लिए की जाती है।

पहले मामले में इसे नियमित नियुक्ति नहीं कहा जा सकता, किन्तु दूसरे मामले में नियमों के अनुसार यह नियमित नियुक्ति हो सकती है और यह 'परिचीना पर (On Probation) की नियुक्ति होगी।'

(ग) सेवा या अनुभव (Service or Experience)

नियमों में किसी पद या सेवा से उच्चतर या वरिष्ठ पद पर पदोन्नति के लिए कुछ वर्षों की सेवा या अनुभव की एक शर्त होती है। ऐसी स्थिति में उस पद पर सेवा या अनुभव के काल में निम्न को सम्मिलित किया जावेगा—

(1) अनुच्छेद 309 के परतुक के अधीन बने नियमों के अनुसार नियमित भर्तों के बाद ऐसे पदों पर लगातार कार्य किया उसकी अवधि-अर्थात् नियमित नियुक्ति के बाद का कार्यकाल सेवाकाल गिना जावेगा,

(2) इसमें उस काल का अनुभव भी गिना जावेगा, जो उसने अधिष्ठायी या स्थायी (नियमित नियुक्ति) के पहले स्थानापन्न, अस्थायी या तदर्थ नियुक्ति के द्वारा

प्राप्त किया है। परन्तु इस अनुभव की अवधि को गिनने के लिये कुछ शर्तें हैं, जो इस प्रकार हैं —

- (i) ऐसी नियुक्ति (यानी स्थानापन्न अस्थायी या तदथ) पदोन्नति के लिए जो नियम है उनके अनुसार पात्रता का ध्यान रखकर, नियमित रूप से होनी आवश्यक है।
- (ii) ऐसी नियुक्ति केवल स्थान भरने के लिये या किसी को अवसर (मीके) का लाभ देने के लिये नहीं होनी चाहिये-यानी अनियमित या मनमानी नहीं होना चाहिये।
- (iii) ऐसी नियुक्ति किसी विधि (कानून) के अधीन अवधि नहीं होनी चाहिये।
- (iv) ऐसी नियुक्ति में कि-नी वरिष्ठ कर्मचारी को प्रतिष्ठित नहीं किया हो-यानी वरिष्ठ को बिना विचार किये छोड़कर कनिष्ठ को पदोन्नति नहीं दी गई हो। परन्तु इस शर्त के लिये कुछ अपवाद (छूट) भी हैं--
- (क) यदि ऐसा प्रतिष्ठन इस कारण से किया गया हो कि--उस वरिष्ठ व्यक्ति में निर्धारित शैक्षणिक योग्यतायें या अन्य योग्यतायें नहीं हो-या--
- (ख) वह उस पद के लिये अयोग्य या अनुपयुक्त (Unfit) पाया गया हो-या-
- (ग) योग्यता (मेरिट) के आधार पर उसका चयन नहीं हुआ हो, या
- (घ) उस वरिष्ठ कर्मचारी के किसी दोष (default) के कारण उसे पीछे छोड़ दिया गया हो, या
- (ङ) ऐसी तदन या आवश्यक अस्थाई नियुक्ति वरिष्ठता-सह-योग्यता के अनुसार की गई हो और ऐसी स्थिति में उसकी वरिष्ठता को अयोग्यता के कारण से पीछे रखना पड़ा हो।

उपरोक्त कारणों से किया गया वरिष्ठ कर्मचारी का प्रतिष्ठन कनिष्ठ कर्मचारी की स्थानापन्न, अस्थायी या तदथ नियुक्ति द्वारा की गई सेवा को दूषित नहीं करेगा और उस कनिष्ठ कर्मचारी का ऐसी नियुक्ति का अनुभव सेवा में गिना जावेगा।

(3) इस परिभाषा के नीचे दी गई टिप्पणी द्वारा सेवा के बीच की अनुपस्थिति-जैसे-प्रशिक्षण प्रतिनियुक्ति आदि, जिसको राजस्थान सेवा नियम के अधीन कर्तव्य (duty) की परिभाषा में [रा से नि नियम 7 (8)] सम्मिलित किया गया है, सेवा या अनुभव में गिना जायेगा।

(4) सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा के नियम में एक टिप्पणी और है, जिसके अनुसार निजी सचिव या निजी सहायक की उस सेवा को भी गिना जावेगा, जिसे लोकहित में अपने पद से पदोन्नति के लिये चयनित होने पर भी काय मुक्त नहीं किया गया।

इस प्रकार जहाँ कहीं इन नियमों में पदोन्नति के लिये सेवा या अनुभव की शर्त लगायी गयी है, उसके लिये उपरोक्त परिभाषा की शर्तें लागू होंगी। यह परिभाषा इन नियमों में दिनांक 9-10-75 को जोड़ी गई तथा इसे पूर्वकालिक प्रभाव से दिनांक 27-3-73 से प्रभावशील माना गया है। अतः जिन कर्मचारियों को इससे लाभ मिल सकता हो उनको अपने नियुक्ति प्राधिकारी से इसका लाभ देने के लिये आवेदन करना चाहिये।

10 नियमों का अर्थ करना—किसी नियमावली के किसी नियम का अर्थ करने के लिये निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं—

(1) जिस नियम का अर्थ समझना है, पहले उस नियम को पूरा पढ़िये। प्रत्येक नियम में कई उपनियम होते हैं। ये उपनियम आपस में एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं और स्वतन्त्र भी। इसी प्रकार एक उपनियम के भी कई खण्ड (clauses) होते हैं, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं।

(2) नियम के अन्त में जो “परंतु” (‘Proviso परंतु यह है कि—’) होता है, वह उस नियम की बातों में या तो कोई छूट देता है या उसमें कोई शर्त लगाता है। कई बार एक से अधिक परंतु भी होते हैं। यह परंतु मुख्य नियम से भिन्न होते हुए भी उसके मूल अर्थ को नष्ट नहीं करते। यह एक स्थापित मत है कि—“परंतु का अर्थ इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि—वह उस मूल नियम को ही खा जाये जिसका वह परंतु है।”<sup>1</sup> इस प्रकार परंतु मूल नियम की सीमा में ही रहेगा। किंतु कई बार ये परंतु अपने आप में स्वतन्त्र उपबन्ध भी बन जाते हैं, तो इनका स्वतन्त्र अर्थ भी करना होता है। इस प्रकार के परंतु के उदाहरण भर्ती के तरीके, वरिष्ठता के नियम तथा आयु में छूट के नियमों में देखने की मिलेंगे। परंतु कई बार पूरे नियम का होता है तो कभी कभी केवल किसी उपनियम का ही, इसका ध्यान रखने पर ही सही अर्थ किया जा सकेगा।

(3) नियमों के अन्त में ‘टिप्पणी’ (Note) या स्पष्टीकरण (Explanation or clarification) दिये होते हैं, जो उस नियम के प्रयोग में आये किसी शब्द या शब्दावली का प्रयोग से सही अर्थ बताते हैं। इससे अर्थ की दुविधा दूर होती है। अतः नियम का अर्थ करने के लिये इनको पहले सम्मिलित लेना चाहिये।

(4) नियम में प्रयोग में आये विशेष या तकनीकी शब्दों की परिभाषाएँ (जो नियमों के आरम्भ में दी गई हैं,) भी नियम के पहले सग्य द्वारा पढ़ लेनी चाहिये और उस परिभाषा के अनुसार ही अर्थ करना चाहिये, क्योंकि विभिन्न सेवा नियमों में कुछ शब्द समान होते हुए भी उनके अर्थों में कुछ भ्रन्तर है।

(5) कई नियमों के आरम्भ में शब्दावली—‘इन नियमों में किसी बात का होते हुए भी’ या ‘इन नियमों में किसी बात के विपरीत होते हुए भी’ का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि—इस नियम में आगे दी गई बातें इन नियमों में दूसरे स्थान (नियम) में दी गई बातों से प्रभावित नहीं होगी और उसका प्रभाव अक्षारोही होगा यानी वह उन सब पर हावी रहेगा और जहाँ किसी दूसरे नियम या खण्ड में कोई विपरीत बात है, तो वह इस नियम के मामले में लागू नहीं होगी।

(6) इन नियमों में बार बार सशोधन होते रहते हैं। अतः जिस समय के मामले की परीक्षा करनी है, उस समय उस नियम का क्या स्वरूप या भाषा थी, उसे देखना होगा और उसी के अनुसार उसका प्रयोग तथा अर्थ करना होगा।

(7) इन नियमों में किये गए सशोधनों के नीचे पाद टिप्पणियों में उस विनाश, अधिसूचना या आज्ञा का क्रमांक (स) तथा दिनांक दिया गया है, जिसके द्वारा वह सशोधन किया गया है। सशोधन उसी दिनांक से लागू होता है, जब वह ‘राजस्थान राजपत्र’ में प्रकाशित होता है या उस विज्ञापित दिनांक से। पर तु कई बार किसी सशोधन को पूर्व कालिक प्रभाव से किसी विशेष दिनांक से भी प्रभावी (लागू) किया जा सकता है। अतः सशोधन जिस दिनांक से लागू हुआ, उसके बाद के मामलों पर ही वह लागू होगा और पुराने मामले सशोधन से पहले के नियम से निरटारे जायेंगे।

(8) सशोधन की पाद टिप्पणी (फुट नोट) में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों का अर्थ भी जानना उचित होगा—

‘Added (जोड़ा गया) तथा निविष्ट (inserted)’ का अर्थ है—यह नया उद्भव (प्रवधान) जोड़ा गया है। ‘विलोपित’ (deleted or Omitted) का अर्थ है—किसी नियम, उपनियम या अंश को हटा दिया गया। प्रतिस्थापित (Substituted) शब्द का प्रयोग किसी पुराने नियम या उसके अंश को हटाकर उसके स्थान पर नया स्थापित करने से है।

(9) पाद टिप्पणियों के नीचे यथा समव पुराने नियमों को भी दिया गया है, जो पहले लागू थे। इससे पुराने सम्भवतः मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी।

भाषा है, उपरोक्त बातों का ध्यान रखने से आपको इन नियमों का सही अर्थ निकाल कर इनका प्रयोग करने में मदद मिलेगी।

अध्याय  
2सेवा में प्रवेश—भर्ती एवं नियुक्ति  
(Recruitment & Appointment)

## अनुक्रम

नियमावली प्रसंग	8 भर्ती सम्बन्धी विशेष नियमावलियाँ
1 स्थापन/सेवा/सर्वश्रेष्ठ	9 सामान्य शर्तें
2 पदों के भेद	10 शर्तों की संख्या
3 रिक्तियों का विनिश्चय	11 शर्तों में छूट
4 रिक्त स्थानों को भरना अनिवार्य नहीं	12 नियुक्ति का प्राधिकार
5 समान वेतन के पद	13 नियुक्ति आज्ञा के आवश्यक तत्व
6 भर्ती एवं नियुक्ति	14 नियुक्ति का स्वरूप व वधता
7 भर्ती एवं नियुक्ति के तरीके	15 नियुक्ति की विशेष शर्तें

## नियमावली प्रसंग

विषय	अधीनस्थ कार्यालय	सचिवालय	अधीनस्थ न्यायालय	पंचायत समिति	चतुर्थ श्रेणी
	A	B	C	D	E
1 सेवा/स्थापना की संख्या एवं पद	6	4	5	3,4,5	4,5
2 रिक्तियों का विनिश्चय	9	8	14	8	7क
3 भर्ती के तरीके	7	5	6	6	6
4 सेवा में वापसी पर	7क	5क	6क	X	6क
5 राष्ट्रीयता	10	7	8	9	8
6 परिभाषकों को छूट	10क	7क	X	X	8क
7 आयु सीमा में छूट	11,11क	9	9	10	9
8 शैक्षिक अहतायें	12	10	10	11	10
9 चरित्र	13	11	11	12	12

	A	B	C	D	E
10 शारीरिक स्वस्थता	14	12	12	13	13
11 अनियमित/अनुचित साधन	14ख	13	12ख	X	X
12 नियुक्ति के लिए निरहतायें	14ख	15	X	X	X
13 पदासमर्थन	16	14	18	14	X
14 भर्ती परीक्षाएँ	19-24	16 23	14 19	15-17	X

### 1 स्थापन/सेवा एवं सवग का अर्थ व स्वरूप

विभिन्न नियमों में स्थापन/सेवा/सवा के सदस्य आदि शब्दों की परिभाषायें दी गई हैं जो सभी 'लिविंग वर्गीय' की ओर सकेत करती हैं। "स.ग." की परिभाषा राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 7 (4) में इस प्रकार की गई है—

"सवग से किसी सेवा या सवा के एक भाग में अभिप्रेत है, जिसे एक प्रत्यक्ष कार्य के रूप में स्वीकृत किया गया हो।"

इस प्रकार एक सेवा या एक संवर्ग (काइर) भी हो सकता है या सेवा में कई सवग (काइर) भी हो सकते हैं। प्रत्येक सवग में कई पद (Post) हो सकते हैं या केवल एक पद। इन पदों या सवग की सत्या समय समय पर सरकार तय करती है।

अधीनस्थ कार्यालयों में, तथा अधीनस्थ 'मायालयों में दो सवग हैं—(1) प्राथमिक सवग तथा (2) साधारण सवग। सचिवालय में सवग की बजाय चार समूह (ग्रुप) बनाये गये हैं, जो अब तीन ही रह गये हैं। (देखिये अनुसूची I)। पचासत समिति/जिला परिषद में एक सेवा में 17 पदों के बराबर दिए गए हैं। चतुर्थ श्रेणी में अनेक पद हैं, जिनमें तीन पद वगिष्ठ हैं (भेलिए—अनुसूची I)। लिविंग वर्गीय सेवा तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा के विभिन्न पदों की सूचियाँ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अधीन) नियम 1958 की सलाह अनुसूची III तथा IV में देखनी चाहिए।

2 पदों के भेद व उनमें अन्तर—पदों के भेदों का वर्णन इन नियमावलीयों में नहीं है, परन्तु राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 7 में तीन प्रकार के पदों की परिभाषायें मिलती हैं—

(1) स्थायी पद (Permanent Post—Rule 7 (26) से अभिप्रेत है विना किसी समय की सीमा के निश्चित दर पर वेतन वाला पद। इसे 'प्रतिष्ठायी-पद (Substantive Post) भी कहते हैं।

(2) अस्थायी पद (Temporary Post—Rule 7 (34) से अभिप्रेत है, एक सीमित समय के लिये निश्चित दर पर वेतन वाला पद।

- (3) सायधिक पद (Tenure Post—Rule 7 (36) से अभिप्रेत है, एवं ऐसा स्थायी पद जिसे एक सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से एवं निश्चित अवधि में अस्थिक के लिए धारण नहीं कर सकता ।

3 रिक्तियाँ या रिक्त स्थानों (Vacancies) का विनिश्चय—किसी पद (स्थान) को रिक्त (खाली) रखना या उसे समाप्त कर, दानु या नया पद सृजित कर, देना या उसे नया पदनाम देना या उसका स्तर बदलना आदि ये सब सरकार के प्रशासनिक कार्य हैं ।

रिक्तियों की सरवा सय करने के लिए सम्बन्धित नियमों में स्पष्ट तरीका बताया गया है । उपनियम (1) के अनुसार अगले बारह महीनों में जो पद रिक्त हो या होंगे, उनका अनुमान लगाया जाता है और उनकी सरवा निर्धारित की जाती है । उपनियम (2) के अनुसार जो पद सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों से भरे जान हों, तो उनके निश्चित प्रनिशत (कोटा) के आधार पर चर्रीय क्रम (रोटेशनल साइकिल) अपनाया जावेगा और उसी के अनुसार भर्ती व नियुक्तियाँ की जावेगी ।

4 रिक्त स्थानों की भरना आज्ञापक (अनिवाय, नहीं) — रिक्त स्थानों की प्रति वष भरन के लिये सम्बन्धित नियमों में कोई आज्ञापक उावध नहीं है । सरकार कई वर्षों तक रिक्त स्थान को नहीं भी भरे, यह उसका विवेकाधिकार है । परंतु रिक्त स्थानों का विनिश्चय प्रति वष अवश्य करना होगा ।

[अपील स 120/76 श्रीमती लज्जा देवी दि 26 7-1978

अपील स 144/77 मदनलाल जैन दि 26 7 1978

अपील स 95/66 प्रेमसुख मादेश्वरी दि 24 7 1978]

5 समान वेतनमान के पदों में भी अतर — कार्यालय अधीक्षक भेरी द्वितीय तथा माधुनिक थैली प्रथम दोनों इन नियमों में अलग अलग पद ह, इसलिये एक पद के धारण करने वाले कर्मचारी की केवल इसलिये कि दोनों पदों के वेतनमान समान हैं, दूसरे पद पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता ।

[अपील स 68/1976 यू सी सौगानी 1978 RLT-5]

■ भर्ती एवं नियुक्ति (Recruitment V Appointment) — सरकारी सेवा में भर्ती प्रवेश की तैयारी है जबकि नियुक्ति प्रवेश है । भर्ती अधिकारी या चयनकर्ता तथा नियुक्ति प्राधिकारी दोनों अलग अलग भी होते हैं और एक भी हो सकते हैं । भर्ती अधिकारी का कार्य "आयोग" करता है, जहाँ रिक्त पद आयोग की सिफारिश से भरने होते हैं । अन्य मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी ही भर्ती अधिकारी भी होता है । भर्ती के लिये चयनसूची में नाम आ जाने मात्र से अभ्यर्थी को कोई अधि-



कार उत्सन्न नहीं हो जाता,<sup>1</sup> जिस 'यापालय या ट्रिब्यूनल द्वारा प्राप्त किया जा सके। नियुक्ति के बाद भी केवल सीमित अधिकार उत्सन्न होता है, जो पुष्टीकरण के बाद प्राप्ति (Status) तथा पदाधिकार (Lien) में बदल जाता है। एक कमचारी प्रपील अधिकरण में अपने इस अधिकार की मांग कर सकता है। शब्द 'भर्ती' और 'नियुक्ति' पर्यायवाची (समानार्थी) नहीं हैं और इनका अर्थ भिन्न भिन्न है। भर्ती से स्पष्ट अभिप्राय है—“सूची में लेना, स्वीकार करना, चयन करना, नियुक्ति हनु अनुमति देना।” यह वास्तविक नियुक्ति या सेवा में पदस्थापन नहीं है।<sup>2</sup>

7 भर्ती एवं नियुक्ति के तरीके — भर्ती के दो ही तरीके अपनाये जा सकते हैं जो नियमों में दिये गये हैं। इन नियमावलिओं में दिये गये दो प्रकार के तरीके मुख्य हैं —

- (1) सीधी भर्ती — जो नियमों में वर्णित प्रतियोगी परीक्षा या प्रवृत्त परीक्षा के द्वारा की जाती है। इसमें खुली प्रतियोगिता होती है या सीमित प्रतियोगिता। सीधी भर्ती सम्बन्धी नियमों के प्रसंग ऊपर “भर्ती परीक्षाएँ” शीर्षक में दिये गये हैं। इन नियमों में आवेदन पत्र आमंत्रित करना परीक्षा शुल्क, प्रवेश के लिए शर्तें, परीक्षा का समय संचालन पाठ्यक्रम तथा स्तर का वर्णन है। विस्तृत पाठ्यक्रम तथा उनका क्षेत्र व स्तर सलज्ज अनुसूची में दिया गया है।

कृपया यथा स्थान देखिये।

- (ii) चयन या पदोन्नति द्वारा — पदोन्नति के लिये चयन (selection) या विशेष चयन सक्षम प्राधिकारी द्वारा या विभागीय पदोन्नति समिति (D P C) द्वारा नियमों में निर्धारित तरीके से निश्चित शर्तों व पात्रता के आधार पर किया जाता है, जिसका विस्तृत विवेचन हम अध्याय (7) में करेंगे।

इन दो तरीकों के अलावा भर्ती या नियुक्ति के कुछ तरीकों के प्रावधान और मिलते हैं जो इस प्रकार हैं —

- (क) स्थानान्तर द्वारा — किसी एक विभाग से दूसरे विभाग में समान पद पर स्थानान्तर द्वारा भर्ती या नियुक्ति की जा सकती है।

(ख) आभेलन (absorption) द्वारा—जब कोई सेवा या पद को समाप्त (abolish) कर दिया जावे या एकीकरण (merger) किया जावे, या प्रशासनिक कारणों से या मितव्ययिता के लिए कुछ पदों में कमी या कटौती की जावे, तो अधिशेष (surplus) घोषित कमचारियों को दूसरे विभागों में अन्य पदों पर आभेलित किया जाता है जो नई नियुक्ति या भर्ती का एक तरीका है। इसके लिए अलग से नियमावली बनाई गई है—“राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कार्मिकों का आभेलन) नियम 1969” जो आगे परिशिष्ट (1) में दी जा रही है।

(ग) प्रतिनियुक्ति (deputation) द्वारा—जब किसी सरकारी कमचारी को किसी दूसरे विभाग में अस्थाई अवधि के लिए या किसी बाहरी सेवा (स्थानीय निकाय, निगम, कंपनी आदि में) में किसी निश्चित अवधि के लिए भेजा जाना है, तो इस प्रकार से भर्ती की जाती है।

8 भर्ती सम्बन्धी कुछ विशेष नियमावलियाँ—प्रत्येक सेवा के लिए भर्ती तथा सेवा की अन्य शर्तों 'सम्बन्धी अलग अलग नियमावनियाँ हैं। फिर भी विशेष परिस्थितियों के आधार पर निम्नलिखित विशेष नियमावलियाँ भर्ती सम्बन्धी शर्तों तथा प्रक्रिया के लिए बनाई गई हैं --

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कार्मिकों का आभेलन) नियम 1969 जिसका बख़्त हम ऊपर कर चुके हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (सरकार द्वारा अधिग्रहीत निजी संस्थानों तथा अन्य स्थापनों के कमचारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम 1977—इस नियमावली में उन कमचारियों की भर्ती, नियुक्ति आदि के नियम दिये गये हैं जो किसी निजी संस्थान या स्थापन को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने पर सरकारी सेवा में सम्मिलित किए जाते हैं।
- (3) राजस्थान (सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर सरकारी कमचारियों के आश्रितों की भर्ती) नियम 1975—सरकारी कमचारी की सेवा में अकाल मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार की मदद करने के लिए उसके आश्रितों को सरकारी सेवा में भर्ती किया जाने के लिए यह नियमावली बनाई गई है। ऐसी ही नियमावली पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवाओं के लिए 1978 में बनाई गई है। यह नियमावली नगरपालिकाओं के कमचारियों पर भी लागू की गई है तथा

सावजनिक निर्माण विभाग, बागान, सिचाई, जल प्रदाय तथा प्रायुर्विभाग के काम प्रभारित (वर्कचाज) कमचारियों को भी इसका लाभ दिया गया है।

—ये नियमावलियाँ सेवा में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण हैं। परंतु इनका हिंदी पाठ भागे 'परिशिष्ट' में दिया जा रहा है।

9 भर्ती एवं नियुक्ति के लिये सामान्य शर्तें—भर्ती के लिए अनेक शर्तें हैं जिनमें दो प्रकार की शर्तें होती हैं—(1) भर्ती के पहले पूरी की जाने वाली शर्तें (Pre conditions), जिनको पूरा किए बिना भर्ती ही नहीं हो सकती, (2) भर्ती के बाद पूरी की जाने वाली शर्तें—जो भर्ती के बाद नियुक्ति से पहले या बाद में पूरी करनी होती हैं। इन शर्तों को पूरा करने पर ही नियुक्ति नियमित तथा वैध मानी जाती है। इन शर्तों में छूट देने या इनको शिथिल करने का सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी को अधिकार है।

इन शर्तों में जो योग्यता से सम्बन्धित हैं उनको 'ग्रहतायें' (Qualifications) कहा जाता है और जो उपयुक्तता से सम्बन्धित हैं, 'पात्रतायें' (Eligibility) कहा जाता है।

इन नियमावलियों में जो सामान्य शर्तें दी गई हैं, उनकी सूची हम इस अध्याय के आरम्भ में 'नियमावली प्रकरण' में दे चुके हैं। इनमें राष्ट्रीयता प्रायु सीमा, शैक्षणिक ग्रहतायें, चरित्र, शारीरिक स्वस्थता, अनियमित व अनुचित साधनों का प्रयोग, पक्ष समर्थन सम्बन्धी शर्तें लगभग सभी नियमों में समान हैं। ये ऐसी शर्तें हैं, जिनको पूरा न करने पर या इनमें सरकार द्वारा छूट नहीं दी जाने पर 'नियुक्ति, अनियमित तथा अवैध हो जाती है। ऐसी अनियमित नियुक्ति के कारण भागे सेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण परिलाभ भवरुद्ध हो जाते हैं।

10 ग्रहताओं, एवं पात्रता की शर्तों की व्युत्पत्ति—नियुक्ति प्राधिकारी को यह छूट कि—वह सरकारी सेवा में भर्ती के लिये आवश्यक ग्रहतायें (योग्यतायें) निर्धारित करे और नियुक्ति के लिये ऐसी पूर्व वांछित शर्तें भी निर्धारित करे जो सरकारी सेवकों में उचित अनुशासन की स्थापना के लिये आवश्यक हो। सरकार नियुक्ति की भाति पदोन्नति के लिये भी शर्तें विहित कर सकती है। इससे अनुच्छेद 16 का हनन नहीं होता।<sup>1</sup> परंतु निर्धारित की गई योग्यतायें सरकारी सेवकों के द्वारा उस पद पर किये जाने वाले कार्य से सुसम्बद्ध होनी चाहिये। यह एक युक्तियुक्त मापदण्ड होना चाहिये। बौद्धिक कुशलता के साथ शारीरिक कुशलता अनुशासन की

भावना, नैतिक निष्ठा, राज्य के प्रति बफादारी— ये सब योग्यतायें हो सकती हैं। तकनीकी नियुक्तियों में तकनीकी स्तर व योग्यतायें मांगी जा सकती हैं, परन्तु राज-नैतिक पीडितों या शरणाग्रियों को भर्ती में प्राथमिकता देने की शत कोई पात्रता का युक्तियुक्त आधार नहीं माना गया।<sup>2</sup>

विभागीय परीक्षा में सफल होना भर्ती की एक आवश्यक शत थी किन्तु जब एक कमचारी तीन बार परीक्षा देकर भी सफल नहीं हुआ, तो उसे रा से नि 23 क (2) का सरक्षण नहीं मिल सकता।<sup>3</sup>

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय अनुसचिवीय स्थापन नियमों के नियम 7 के अधीन एक निम्न लिपिक (L D C) का जिसने तीन वष से अधिक की सेवा पूरी करली और जो नियम 23-A (2) के अनुसार अथवा योग्यता प्राप्त था, विभागीय परीक्षा में दो बार असफल रहने पर भी हटाया नहीं जा सकता। क्योंकि विभागीय परीक्षा में सफल होना नियमों में आवश्यक शत नहीं थी।<sup>4</sup>

11 भर्ती नियुक्ति आदि की शत में छूट—भर्ती के लिये कुछ विशेष परिस्थितियों का समाधान करने के लिये इन नियमों में कुछ विशेष उपबन्ध भी किये गये हैं, जो उस प्रकार हैं—

(1) सेना/जलसेना/वायुसेना में आपत्काल के समय भर्ती हुए सरकारी कमचारियों की वापसी पर सेवा में पुन लेने की शर्तें।

(2) भारतीय लोग जो विदेशों में जाकर बस गये थे, उन्हें वहाँ को सरकार ने वापस भारत लौटा दिया, ऐसे लोगों को 'परिव्राजक' कहते हैं। उनको सरकारी सेवा में भर्ती के लिये छूट दी गई है।

(3) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 के उपबन्धों की पालना में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये भर्ती में रिक्त पदों का आरक्षण (सुरक्षित पद) किया गया है, जिसका वर्णन आगे अध्याय (3) में किया जा रहा है।

(4) अधिकतम आयु के बारे में भी अनेक प्रकार की छूट दी गई हैं जो 'आयु' शीपक नियम के नीचे परतुक में दी गई हैं।

(5) शारीरिक स्वस्थता की शर्तें विकलांगों और अपंगों के मामले में शिथिल कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त विकलांगों के लिए 2 प्रतिशत रिक्त पदों को

2 सुखनन्दन ठाकुर बनाम बिहार राज्य AIR 1957 Patna 617

3 वेदनिधि शर्मा बनाम निदेशक तकनीकी शिक्षा 1971 WLN 302

4 फनेचंद बनाम राज्य 1967 RLW 196

प्रारक्षित किया गया है। इसने लिए "राजस्थान गाररीफ रूप से अक्षम व्यक्तियों का नियोजन नियम 1976" बनाये गए हैं, जिसे अध्यायाही प्रभाव से लागू किया गया है। ये नियम आगे परिशिष्ट (5) में दिए जा रहे हैं।

[इसका 'नियमावली प्रणम' में देखकर सम्बन्धित नियम देखने का धम करें।]

12 नियुक्ति के प्राधिकार का स्वरूप एवं वैधता - हम अध्याय (1) में "नियुक्ति प्राधिकारी" की परिभाषा का विवेचन कर चुके हैं। सविधान के अनुच्छेद 311(1) में यह अपेक्षा की गई है कि—नियुक्ति और निष्कासन (सेवा से मुक्ति या पदच्युति) दोनों करने वाला प्राधिकारी एक ही स्तर (Status) का होना चाहिये। नियुक्ति प्राधिकारी जिसने नियुक्ति की थी, वही उस कमचारी को हटा सकता है, यह आवश्यक नहीं है। उसी समान श्रेणी व पद का प्राधिकारी होना पर्याप्त है।<sup>1</sup> राजस्थान सिविल सेवा (घर्षाकरण, नियन्त्रण एवं अधीन) नियम 1958 के नियम 2 (क) में नियुक्ति-प्राधिकारी की परिभाषा दी गई है जिसके अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी के निम्नलिखित लक्षण बताये जा सकते हैं —

- 1 जिस प्राधिकारी की किसी सेवा/श्रेणी/पद पर उस कमचारी को नियुक्त करने के अधिकार दिय गये हो या
- 2 वह अधिकारी जिसने उसे वास्तव में नियुक्त किया हो, या
- 3 वह अधिकारी जिसने उसकी नियुक्ति को स्थायी (कनफर्म) किया हो—  
—इन तीनों में से जो सर्वोच्च हो वही "नियुक्ति प्राधिकारी" माना जावेगा।<sup>2</sup>

साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 15 के अनुसार—"नियुक्ति के अधिकार में पदेन (ex-officio) नियुक्ति करना भी सम्मिलित है तथा धारा 16 के अनुसार निरन्धन या निष्कासन करने की शक्ति भी उसमें सम्मिलित है। इस प्रकार नियुक्ति का प्राधिकार विस्तृत है। नियुक्ति केवल वही प्राधिकारी कर सकता है जिसे किही नियमों में ऐसा प्राधिकार प्राप्त है या ऐसा प्राधिकार प्रत्यायोजित किया गया हो। अतः नियुक्ति की आणा पर वही अधिकारी हस्ताक्षर करेगा, जिसे नियुक्ति का प्राधिकार है। इसे (For)" करके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जारी की गई 'नियुक्ति आज्ञा' की वैधता को चुनौती दी जा सकती है।

13 नियुक्ति-आज्ञा के आवश्यक तत्व—नियुक्ति की आज्ञा (जिसमें पदोन्नति की आज्ञा भी सम्मिलित है) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है उसमें निम्नादि आवश्यक बातें होनी चाहिये—

1 AIR 1954 Raj 207, AIR 1955 SC 70

2 देखिये पुस्तक 'अनुशासनिक कायदाही (1979, अध्याय (3) पृष्ठ 18-19 तथा अध्याय (6) पृष्ठ 28-33

- (1) नियुक्ति-प्राप्ति की क्रम सख्या व दिनांक
- (2) नियुक्ति जिस नियम के अधीन की गई उसका प्रसंग,
- (3) नियुक्ति करने के अधिकार की घोषणा
- (4) नियुक्ति का स्वरूप—स्थायी या अस्थायी, उसकी अवधि, आयोग से चयनित कर्मचारी के उपलब्ध होने पर हटाये जाने की शर्त नोटिस द्वारा हटाने की शर्त, पात्रता सम्बन्धी कोई शर्त (जैसे-स्वास्थ्य परीक्षा, टक्का परीक्षा) जो भी आवश्यक हो।
- (5) वेतनमान व पद का नाम—कार्यालय जहाँ पदस्थापन किया गया।
- (6) स्थानांतर द्वारा नियुक्ति के मामले में—वरिष्ठता, पदाधिकार, विकल्प आदि के बारे में शर्तें।

इस प्रकार नियुक्ति-प्राप्ति एक विस्तृत दस्तावेज होना चाहिये। इसमें भविष्य में होने वाली कई उलझनों से बचा जा सकता है। सब प्रकार की नियुक्तियों के लिये एकसा प्रारूप (फॉर्म) तैयार करना एक कठिन कार्य है, किन्तु उपरोक्त आवश्यक तत्व उसमें सम्मिलित किये गये हैं, इसका ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा नियुक्ति की प्राप्ति में अवघटता होने की आशंका है।

14 नियुक्ति का स्वरूप व वधता—नियुक्ति के स्वरूप का विवेचन करने व उसकी वधता की जांच करने के लिए इसे हम तीन स्थितियाँ (स्टेज) से विभाजित कर सकते हैं—

(1) शर्तों की स्थिति—जब एक अभ्यर्थी शर्तों की प्रारम्भिक शर्तों को पूरा कर नियमानुसार शर्तों के तरीके से चयनित किया जाता है।

(2) नियुक्ति की प्रारम्भिक स्थिति—शर्तों के तुरन्त बाद प्रारम्भिक नियुक्ति की स्थिति आती है। उन शर्तों को “परिबीक्षा” कहते हैं। इनके साथ साथ प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिये कुछ विशेष पात्रता की शर्तें नियमों में दी गई हैं, उनका पूरा करना भी आवश्यक है। इनको पूरा किये बिना नियुक्ति अपनी पूर्ण स्थिति में नहीं पहुँचती अर्थात्—पुष्टीकरण नहीं किया जा सकता।

(3) नियुक्ति की अधिष्ठायी स्थिति—जब नियुक्ति की प्रारम्भिक शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो उस कर्मचारी को अधिष्ठायी पद पर अधिष्ठायी (स्थायी) नियुक्ति प्रदान की जाती है और उसे स्थायी (कनफर्म) कर दिया जाता है जिससे उसे उस पद पर ‘पदाधिकार’ मिलता है। उपरोक्त तीनों स्थितियों में से किसी में भी यदि किसी नियम के विपरीत कार्यवाही करके नियुक्ति दी जाती है तो वह “अनियमित” नियुक्ति होगी और यदि वह नियुक्ति किसी भेदभाव पर आधारित है तो वह सविधान के अनुच्छेद 16 के विपरीत होने से अवैध हो जावेगी।

[कृपया "अस्थायी नियुक्ति" सम्बन्धी विवेचन के लिए भागे अध्याय (4) देखिये]

नियमित एवं अनियमित नियुक्ति का अन्तर हम अध्याय (1) में स्पष्ट कर चुके हैं। नियुक्ति की अनियमितता भागे जाकर बड़ी दुखदायी हो सकती है और एक कमचारी को अनेक परिलाभा से वंचित होना पड़ता है। "जब अयोग्यता की प्रारम्भिक नियुक्ति अनियमित थी, क्योंकि वह अधिवयस्क (over age) था। उसकी आयु में सशोधन की प्राप्ति भी ठुकरा दी गई तो जब तक उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति को नियमित नहीं किया जाता, उसका पुष्टीकरण (स्थायीकरण) नहीं किया जा सकता। अतः नियुक्ति को नियमित करना होगा।"

एक मामले में निर्णय दिया गया कि—"1967 में की गई नियुक्ति को 1977 में रिट्रिब्यूशन द्वारा अवैध घोषित करने के लिए अत्यधिक देरी हो गई है। न्यायालय के लिए 10 वर्ष पहले की नियुक्ति की वैधता देखना अनुपेय नहीं है—प्रति-न्यायालय उस पर विचार नहीं कर सकता।" अतः किसी की प्रारम्भिक नियुक्ति या पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की अनियमितता को तुरन्त चुनौती देनी चाहिये। मामला कई वर्षों तक पुराना पड़ जाने से उत्पन्न प्राधिकारी को बाद में न्यायालय की कामवाही से चुनौती नहीं दी जा सकती। यह एक ध्यान देने योग्य सिद्धान्त है।

15 नियुक्ति की विशेष शर्तें—इन नियमों में नियुक्ति की तीन स्थितियों—(सीधी भर्ती, पदोन्नति से, या स्थानांतरण से) के लिये कुछ विशेष शर्तें लगाई गई हैं, जो पूर्व शर्तें (Pre-conditions) होने से उनकी सही वास्तविकता नहीं करने पर नियुक्ति अनियमित एवं अवैध हो जाती है। विभिन्न नियमावतियों में जो ऐसी शर्तें दी गई हैं, उनकी एक प्रसंग तालिका हम नीचे दे रहे हैं, जो उपयोगी होगी। ये शर्तें पीछे बताई गई 'सामान्य शर्तों' के अतिरिक्त हैं और इनको नियमों में सशोधन किये बिना शिथिल नहीं किया जा सकता।

(क) सचिवालय लिपिकवर्गीय नियमावली में— नियम ९ के नीचे 1। पर तुल्य दिये हुये जिनमें विभिन्न पदों पर नियुक्ति की विशेष शर्तों का वर्णन किया गया है। भागे नियम 10 में शैक्षणिक तथा तकनीकी योग्यताओं का विवरण है। फिर नियम 23 व 27 में सेवा में नियुक्ति का वर्णन है। पदोन्नति के लिये भागे (5) में नियम 24 से 26 के प्रावधान हैं।

1 अपील संख्या 195/77 छोटासिंह 1978 RLT 30।

2 भार के गुप्ता बनाम दिल्ली प्रशासन 1979 SLJ 121 (Delhi Para 11)  
नरसिंह का बनाम बिहार राज्य 1974 (2) SLR 298

(ख) अधीनस्थ कार्यालय नियमावली में—इसी प्रकार नियम 7 के नीचे 18 परतुको में अलग अलग पदों के लिये विशेष शर्तें दी गई हैं। आगे नियम 12 में शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण है। फिर नियम 15 में वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियों के लिये विशेष शर्तें निषेधात्मक शब्दों में दी गई हैं और नियम 26 में वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति (पदोन्नति) के तरीके बताये गये हैं। कनिष्ठ पदों पर नियुक्ति की आवश्यक शर्तें नियम 25 में दी गई हैं। इन सब नियमों को साथ साथ पढ़ना चाहिये।

(ग) अधीनस्थ न्यायालय नियमावली में—नियम 20 में नियुक्तियों का तरीका दिया गया है तथा पदोन्नति का विवरण नियम 13 में है। नियुक्ति की किसी भांति से व्ययित कर्मचारी उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

(देखिये—नियम के नीचे परतुक)

### सिविल सेवाओं की दुखद-स्थिति

यदि हमारी सिविल सेवाओं में स्थायी तथा श्रेणीबद्ध (पदोन्नति की) प्रणाली से लोगों को उचित तरीके से दिशा निर्देशित कर सक्रिय बना दिया जाय, तो वे हमारे युग की प्रगतिशील चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। परन्तु दुखद स्थिति यह है कि—इन सिविल सेवाओं के बहुत से लोगों को उनकी सेवा सम्बन्धी मामलों के लिये सघन में धकेल दिया गया और उनकी अविभाजित प्रबल शक्तियों और तीव्र सूझबूझ को राष्ट्र के भाग्योदय की विकास योजनाओं की पूरा करने के पथ से विमुख कर दिया गया है और इस प्रकार 'सेवाविधि शास्त्र' का एक घमिल क्षेत्र बन गया है।"

—याय मूर्ति श्रीकृष्ण ऐय्यर  
[1977 SCC (L&S) 127]



प्रध्याय  
3

## आरक्षण—(Reservation)

अनुसूचित जातियों/अनजातियों के लिए

### अनुक्रम

- |   |                    |   |                        |
|---|--------------------|---|------------------------|
| 1 | नियमों का विस्तारण | 4 | "40 बिन्दुओं का रोस्टर |
| 2 | आरक्षण का प्रतिमान | 5 | रोस्टर का प्रपत्र      |
| 3 | पदोन्नति आरक्षण    | 6 | संशोधित सूची           |

### क्षेत्र नियमावली प्रसार

- |                  |   |              |   |
|------------------|---|--------------|---|
| अधीनस्थ न्यायालय | 8 | सचिवालय      | 6 |
| अधीनस्थ न्यायालय | 7 | पंचायत समिति | 7 |

### चतुर्थ धारा 7

#### 1 नियमों का विस्तारण—

उपरोक्त नियमों का विस्तारण करने पर निम्नांकित बातें स्पष्ट होती हैं—

(1) यह आरक्षण सरकार द्वारा जारी किये गये उन आदेशों के अनुसार होगा, जो भर्ती के समय लागू थे।

(2) आरक्षण सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों के लिये लागू होगा।

(3) पदोन्नति में आरक्षण के रिक्त स्थान पहले 'योग्यता सह वरिष्ठता' के आधार पर (2-9-1975 से 31-10-75 तक) भरने थे, अब 31-10-75 से 'केवल योग्यता (मेरिट) के आधार पर भरने हैं और इसके लिये वरिष्ठता पर कोई विचार नहीं करना होगा।

#### (4) रिक्तियाँ भरने का तरीका—

(क) सीधी भर्ती के लिये—आयोग या निष्पत्ति प्राधिकारी, जो भी चयन (भर्ती) कर रहा है, एक सूची तैयार करता है, उसमें सभी पात्र अभ्यर्थियों के नाम नियमानुसार उनके द्वारा प्राप्त योग्यता या अंकों के अनुसार क्रम में रखे जावेंगे। इनमें अनुसूचित जाति/अनजाति के लोगों के नाम भी उसी क्रम

में होंगे, उनको अलग से चिह्नित करके या अलग सूची बना करके छांट लिया जावेगा। अब “40-बिन्दुओं के रोस्टर रजिस्टर” के अनुसार पहले अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों से उनके आरक्षित स्थान भर लिये जावेंगे तथा यदि कोई आरक्षित स्थान रिक्त रह जावे, तो उसे अनारक्षित (unreserved) कर के अगले वष के लिये ले जाया जावेगा (carry forward) और इस वष उसको साधारण सूची से भर लिया जावेगा।

(ख) पदोन्नति के लिये—अलग से “40 बिन्दुओं का रोस्टर रजिस्टर” रखा जावेगा और विभागीय-पदोन्नति-समिति या नियुक्ति प्राधिकारी, जो भी पदोन्नति हेतु चयन करे, अपने द्वारा तैयार की गई पात्र अभ्यर्थियों की सूची में से अनुसूचित जाति/जन जाति के पात्र अभ्यर्थियों को उनकी तुलनात्मक श्रेणी (रेक) का ध्यान दिये बिना, पदोन्नति के रिक्त पदों को भरेगा।

#### (5) विशेष निवेदन—

निवेदन यह है कि—दिनांक 31-10-75 को पदोन्नति के लिये “केवल योग्यता” का जो सशोधित मापदण्ड लागू किया गया है, उसके अनुसार तर्कीक म सशोधन नहीं किया गया प्रतीत होता है। फिर भी ‘केवल योग्यता’ से चयन के लिये जितने भी अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति पात्र हैं, उन पर विचार करना होगा, चाहे उनके नाम समिति द्वारा वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर तैयार की गई सूची में आवें या नहीं। यह ध्यान देने योग्य है। रोस्टर-रजिस्टर में आरक्षित पदों को पात्र अभ्यर्थियों से भरने के बाद भी कोई पद रिक्त रह जाता है, तो उसे अनारक्षित कर साधारण अभ्यर्थियों से भर लिया जावेगा, परन्तु इस प्रकार के रिक्त पदों को अगले वष के लिये अग्रणीत (carry forward) नहीं किया जावेगा।

आगे “40 बिन्दु के रोस्टर रजिस्टर” का प्रपत्र दिया गया है और साथ ही विभिन्न सरकारी आदेशों के सारांश व अंश भी आगे दिये जा रहे हैं।

“राजस्थान अधीनस्थ लिपिक नियम के नियम 8 के अनुसार तथा सशोधित सरकारी आज्ञा दिनांक 10-2-75 के उपबन्धों के अनुसार अनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यर्थियों की आरक्षित रिक्तस्थानों पर पदोन्नति केवल मेरिट के आधार पर करनी होगी।<sup>1</sup>”

2 आरक्षण का प्रतिशत—(आज्ञाओं का सारांश)—सरकार द्वारा प्रसारित आज्ञाओं का सारांश मागदशनाथ आगे दिया जा रहा है —

1 अपील सं 595/77 जोहरसिंह दिनांक 21-8-77।

राजस्थान विधान सभा अनुसूचित जाति कल्याण समिति छठा प्रतिवेदन 1976-77 से साभार संप्रदित—दत्त।

- (1) आदेश स प 25 (42/सा प्र (क) 5) दि 19 सितम्बर 1951, को आदेश स डी 9692/प 4 (8) सा प्र (क) 56 दिनांक 27.7.56 द्वारा संशोधित—  
12½% सीधी भर्ती में आरक्षण, दो वर्षों तक "वेरी फारवा" अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट।
- (2) परिपत्र स प 6 (4) नियु (क) IV/62 दि 5 अप्रैल 1962—  
सीधी भर्ती में 12½% समस्त सेवानो में तथा 15% चतुर्थ श्रेणी तथा में—  
1 अप्रैल 1962 से आरक्षण स्थानीय निवासियों, राजकीय उपक्रमों में लागू किया गया।
- (3) आज्ञा स एफ 7 (15) नियुक्ति (क-5) 68 दि 4.7.1970 —  
सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के लिये 17% तथा अनु जन जाति के लिये 11% राजस्थान पुलिस सेवा में क्रमशः 14% तथा 9%।
- (4) वि स प 7 (11) नियुक्ति (क-5) 70 दि 15.10.71—  
कुल मिलाकर आरक्षण सीधी भर्ती के पदों के 50% से कम हो।  
"100-बिंदु रोस्टर" लागू किया गया।  
पूरातन अस्थाई 45 दिन या अधिक की नियुक्ति पर भी आरक्षण लागू किया गया।
- (5) आदेश स एफ 7 (4) DOP/A-II/73 दिनांक 3-9-1973/3-10-1973—  
(भूत आज्ञा पीछे पृष्ठ 117 पर देखिये)---पदोन्नति में भी आरक्षण लागू।
- (6) आदेश स एफ 9 (19) DOP/A-V/74 दिनांक 10 फरवरी 1975—  
सीधी भर्ती का बंटन क्रमशः 17%, 11% के बजाय 16% व 12% किया गया—  
"40 बिंदु रोस्टर" लागू किया गया।
- (7) स एफ 9 (19) कार्मिक (क-5) 74 दिनांक 10 फरवरी 1975—  
(1) पदोन्नति के लिये प्रत्येक श्रेणी/प्रवर्ग/समूह के पदों में 16% व 12% का आरक्षण, उन सेवा सवर्गों में जहाँ सीधी भर्ती का तत्त्व 50% से अधिक न हो। [अब 50% की बजाय 66⅔% कर दिया गया है—  
स प 7 (4) कार्मिक (क-2) 73 दि 18.10.76]  
(2) आरक्षण को लागू करने का तरीका (आगे देखिये)  
(3) आरक्षण तदर्थ या अर्जेंट अस्थायी नियुक्तियों पर भी लागू जो 'तदर्थ पदोन्नति' ही मानी जावेंगी। [स प 15 (24) कार्मिक (क-2) 75 दि 31 सितम्बर 75 द्वारा प्रतिस्थापित]

### 3 पदोन्नति में आरक्षण लागू करने का तरीका (सारांश)

[स एफ 9 (19) कामिक क-5) 74 दिनांक 10 फरवरी 1975 का पैरा (2)।]

(i) अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रतिशत के अनुसार आरक्षण की संगणना पदोन्नति के लिये पदों के प्रवर्ग के प्रतिवर्ष के कुल रिक्त स्थानों पर की जावेगी। यदि पदोन्नति से किसी पदों के प्रवर्ग में 40 रिक्त स्थान भरने हों, तो उनमें से केवल 11 पद (6 अनुसूचित जाति के लिये तथा 5 अनुसूचित जन जाति के लिये) आरक्षित किये जायेंगे। इसके अनुसार प्रत्येक प्रकार के पदों के लिये अलग अलग रोस्टर रजिस्टर रखे जावेंगे जिनमें बिन्दु 1, 7, 14, 21, 28, 35 अनुसूचित जाति के लिये तथा बिन्दु 4, 12, 22 30, 39 अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षित होंगे।

(ii) जब रोस्टर के अनुसार आरक्षण में रिक्त स्थान हों, तो अनु जाति व जन जाति के अभ्यर्थियों की अलग अलग सूचियाँ बनाई जायेंगी, जो सामान्य विचारण के क्षेत्र में आते हों। उनको मुख्य सूची की पारस्परिक वरिष्ठता में व्यवस्थित किया जावेगा।

(iii) अनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यर्थियों पर विभागीय पदोन्नति समिति या जहाँ ऐसी समिति अलग से न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 'केवल योग्यता' के आधार पर उनकी पदोन्नति का निणय करना चाहिये।

(iv) जब साधारण श्रेणी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के चयनित व्यक्तियों की अलग सूचियाँ बना ली जावें, तो इनको एक समुक्त सूची में मिला देना चाहिये। इस प्रकार की सूची में से उपरोक्त रोस्टर के अनुसार पदोन्नतियाँ दी जानी चाहिये।

❖(v) यदि पदोन्नति के लिये इन जातियों के मात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो रिक्त पद को समुक्त सूची के अन्य अभ्यर्थियों से भर लेना चाहिये। इसके लिये प्रशासनिक विभाग से उन पदों को अनारक्षित करने की स्वीकृति लेकर ही ऐसा करना चाहिये।

(vi) पदोन्नति का इस प्रकार न भरा गया आरक्षित पद अगले वर्ष के लिये आगे ले जाया जायेगा और तीन वर्ष बाद वह समाप्त हो जायेगा। परंतु केवल मेरिट (योग्यता) से ही जाने वाली पदोन्नति के मामले में ये रिक्त आरक्षित पद आगे नहीं ले जाये जायेंगे।

❖ वि स एफ 15 (24) कामिक (क-II) 75 दिनांक 3-12 1975 द्वारा प्रतिस्थापित।

(अब पदोन्नति केवल मेरिट से की जावेगी, अत रिक्त पद भाग नहीं ले जाया जावेगा।— लेखक)

ले जाया जावेगा।— लेखक)

4 40 बिंदुओं का रोस्टर—सीधी भर्ती और पदोन्नति में—

[U=अनारक्षित (unreserved) SC अनुसूचित जाति ST अनुसूचित जन जाति]

1 SC	11 U	21 SC	31 U
2 U	12 ST	22 ST	32 U
3 U	13 U	23 U	33 U
4 ST	14 SC	24 U	34 U
5 U	15 U	25 U	35 SC
6 U	16 U	26 U	36 U
7 SC	17 U	27 U	37 U
8 U	18 U	28 SC	38 U
9 U	19 U	29 U	39 S, T
10 U	20 U	30 ST	40 U

दिखायी—यदि किसी भर्ती-वर्ग में केवल एक ही व्यक्ति (unreserved) हो

टिप्पणी—यदि किसी भर्ती-वर्ग में केवल दो रिक्त स्थान हों, तो उनमें से एक भारक्षित होगा। यदि केवल एक रिक्त स्थान हो, तो वह अनारक्षित (Un reserved) होगा। यदि इस कारण से किसी भारक्षित-बिन्दु को अनारक्षित मानना पड़े, तो वह भारक्षित भ्रगले तीन भर्ती वर्गों तक भाग ले जाया जा सकेगा।

(4) सीधी भर्ती और पदोन्नति के पदों को भरने की रोस्टर प्रणाली 40 बिंदु का रोस्टर सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के भारक्षित कोटा दोनों के लिए ल होगा। रोस्टर इस प्रकार रखा जावेगा—

- (i) भागे दिए गए प्ररूप (प्रोफार्मा) में सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए भलग भलग 40 बिंदु का रोस्टर रखा जावेगा।
- (ii) यह रोस्टर एक चलते रहने वाले खाते की तरह वर्षावृष रखा जावेगा। उदाहरणार्थ—यदि किसी वर्ग में भर्ती बिंदु 6 पर रु जाती है तो भ्रगले वर्ग बिंदु 7 से चालू होगी।
- (iii) स्थाई नियुक्तियों तथा उन अस्थायी नियुक्तियों के लिए जो स्थाई होने वाली हैं या अनिश्चित काल के लिए रहने वाली हैं एक ई (Common) रोस्टर रखा जावेगा।

टिप्पणी— कोई अस्थायी पद जो रोस्टर में सम्मिलित है और बाद में स्थाई में बदल दिया गया हो, उसे रोस्टर में दुबारा नहीं दिखाया जावेगा।

(iv) 45 दिवस या अधिक के लिए या जो स्थायी होने वाली नहीं हैं ऐसी पूर्णतः अस्थायी नियुक्तियों के लिए भलग से रोस्टर रखा जावेगा।



6 अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां नवीनतम सशोधित सूची 1978

[अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां आदेश (सशोधन) अधिनियम 1978 के अधीन, जो भारत सरकार द्वारा स. बी. सी. /12016/34/76 एस. सी. टी.-V द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II दिनांक 20 सितम्बर 1976 में प्रकाशित एवं दि. 27-7-1977 से प्रभावी]

राजस्थान में अनुसूचित जातियां (Scheduled Castes)

- 1 आदि घरधी 2 अहेरी, 3 बाबी 4 बागरी, बागडी, 5 बैरवा बरवा, 6 बाजर 7 बलाई, 8 बासचर, बासफोड, 9 बावरी, 10 बारगी बारगी बिरगी, 11 बावरिया, 12 बंडिया, बेरिया, 13 भाड, 14 भगी, चूडा मेहतर, झोलगना हसी, मालकाड हलालखोर, लालबंगी, बालमीकि, बाल्मीकि, कोरर, जदमाली, 15 बिडाकिया 16 बोला 17 चमार, चाम्बी, चाम्बी भाबी, जारिया जाटव, मोची, रदास, रोहिदास रंगर, रंगर, रामदासिया, ससादर, असोडी, चमडिया, चम्भार, चामगर हरसाया हराल लालपा, मोचीगर, मदार मेडिया तेलंग मोची, कमाडी मोची, रानीगर रोहित, सामगार 18 चाण्डाल 19 देवगर, 20 धानक, धानुक् 21 धानकिया 22 घोषी 23 भोली 24 डोम, डूम 25 गाडिया, 26 गराछा गाछा 27 गुरू गुरूडा, गुरडा गरोडा, 28 गावरिया, 29 गोवधी, 30 जियाड, 31 कालबेलिया सपेरा 32 कामड, कामडिया, 33 काजर, कजर 34 कापडिया सांसी 35 लानगर, 36 खटीक 37 कोली, कोरी 38 कूचबद, कूसेबन्द, 39 कोरिया, 40 मदारी बाजीगर, 41 महर तारल, डेपूमेयू 42 महाय, वशी, डेड, डेदम वाकर, 43 मजहबी 44 भाग मातण, मिनिमडिग 45 भाग गरोडी, माग गरडी 46 मेघ, मेघवाई, मेघवाल, मेघवार, 47 मेहर 48 नड, 49 पाली, 50 रावल, 51 साल्वी 52 सांसी 53 साटिया सटिया, 54 सरभगी 55 सरगर, 56 सिगीवाला 57 थोरी 58 नायक, 58 तीरगर तीरबद 59 तुरी ।

राजस्थान में अनुसूचित जन जातियां (Scheduled Tribes)

- 1 भील, 1 ल व सिया, डोली भील, -1 डूगरी भील डूगरी घासिया मेवासी भील, रावल भील ताडवी भील भगालिया भिलाता, पावडा, बासवा, 2 भील मीणा, 3 डामर डामरिया, 4 धानका, ताडवी, टेटारिया, बाल्वी 5 घासिया (राजपूत घासिया के) घलावा, 6 कठोडी, कालकारी धूरकठोडी धूरकालकारी, सोन कठोडी सोन कालकारी, 7 कोकना कोनी, कुना 8 कोलीधार टोकरे कोली, कोलचा, कोनधा 9 मीणा 10 नायकडा नायका, चोलीवाला नायक बापडिया नायक, माता नायक, नाना नायक, 11 पटेलिया 12 सेहरिया सहरिया ।

# अत्यावश्यक अस्थाई नियुक्तियाँ

[Urgent Temporary Appointments]

## अनुक्रम

- 1 अस्थाई नियुक्ति की शर्तें व तरीका
- 2 सरकार के निर्देश
- 3 अस्थाई पदोन्नति तथा विभागीय जाच
- 4 तदर्थ नियुक्ति का अर्थ
- 5 अधिकरण के कुछ महत्वपूर्ण नियम

## □ नियमावली-प्रसंग

अधीनस्थ कार्यालय 26 (3) (4), सचिवालय 28, 28 क

चतुर्थ श्रेणी सेवा 18

पचायत समिति/जि प सेवा 23

(1) अस्थाई नियुक्ति के लिये आवश्यक शर्तें व तरीका—नियमित तथा अनियमित नियुक्ति का विवरण हम पीछे कर चुके हैं। यहाँ हम ऊपर प्रसंगित नियमों के आधार पर अर्जेंट अस्थाई नियुक्ति की शर्तों का विस्तार करेंगे। इस नियम का पालन किये बिना ही मनमाने तरीके से अनियमित नियुक्तियों की जाती रही है, जिनको नियमित करना एक भयानक समस्या बन गई है। इन नियमों के विपरीत की गई नियुक्तियाँ अनियमित होने में उन पर की गई सेवा या अनुभव का लाभ उस पदधारक को नहीं मिल सकता परन्तु इन नियमों के अनुसार की गई अस्थाई नियुक्ति भी नियमित मानी जावगी और उसका लाभ उसके पदधारक को दिया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है।

(1) “अर्जेंट अस्थाई नियुक्ति” के अधीन अधीनस्थ कार्यालय नियमावली का नियम 26 (3) तथा सचिवालय नियमावली का नियम 28 समान भाषा में है, परन्तु चतुर्थ श्रेणी नियमावली में उप नियम (1) के दोनों परन्तु नहीं हैं। पचायत समिति सेवा नियमों के नियम 23 के प्रावधान इनसे सघन है, कृपया संबंधित नियम देखिये।

(2) उपनियम/खण्ड (1) के अनुसार—

- (i) सेवा में कोई रिक्त पद है, जिसे सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नियमानुसार पूरित नहीं करा जा सकता,



- (ii) ऐसी अर्जेंट परिस्थिति में सरकार या नियुक्ति करने के लिये मजदूर प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, उस पद को तुरन्त निम्न प्रकार से भर सकता है —
- (क) पदोन्नति द्वारा—यदि वह रिक्त पद पदोन्नति से भरा जाने वाला है, तो उस पद पर ऐसे कर्मचारी को "स्थानापन्न रूप से" नियुक्त किया जावेगा, जो उस पद पर "पदोन्नति के लिये पात्र" (eligible for promotion) हो, या
- (ख) सीधी भर्ती द्वारा—यदि नियमों में सीधी भर्ती करने का प्रावधान है तो उस रिक्त पद पर एक व्यक्ति को "अस्थायी रूप में" लगाया जावेगा, जो सब से "सीधी भर्ती के लिये पात्र" हो।
- (3) उपनियम/खण्ड (1) के दो परतुक हैं, उनका अनुसार—

- (i) जहाँ प्रायोग की सहमति आवश्यक हो, वहाँ ऐसी अस्थाई नियुक्ति का मामला तुरन्त प्रायोग को संप्रेषित किया जावेगा और एक वर्ष तक प्रथम के लिये जारी नहीं रहेगा, परन्तु जहाँ प्रायोग सहमति नहीं दे, तो तुरन्त ही उस नियुक्ति को समाप्त कर दिया जावेगा,
- (ii) सीधी भर्ती के कोट के अस्थायी रिक्त स्थान को पूरे समय के लिये भरने के लिये निम्न शर्तों का पालन आवश्यक है —(क) जहाँ भर्ती के दोनों तरीकों—सीधी भर्ती और पदोन्नति से, कोई पद भरा जा सकता हो, तो सरकार के प्रशासनिक विभाग की विशेष अनुमति लनी होगी, (ख) वह रिक्त स्थान तीन माह से अधिक अवधि के लिये नहीं भरा जायेगा, (ग) सीधीभर्ती के लिये पात्र व्यक्तियों के अलावा अन्य से नहीं भरा जावेगा और (घ) इससे लिये अस्थावधि विज्ञापन के बाद भर्ती की जावेगी।

- (4) उपनियम/खण्ड (2) के अनुसार—

यदि पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले शोध व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो—

- (i) सरकार उपनियम (1) में बख्ति पदोन्नति की पात्रता की शर्त पर ध्यान दिये बिना अर्जेंट अस्थायी आधार पर रिक्त स्थानों को भरने की अनुमति देने के लिये सामान्य निर्देश दे सकती,
- (ii) उन निर्देशों में वेतन एवं अन्य भत्तों के बारे में शर्तें व प्रतिबंध होंगे, उनका पालन आवश्यक होगा, और
- (iii) उपरोक्त प्रकार से प्रायोग की सहमति, जहाँ आवश्यक हो, ली जावेगी।
- (5) अर्जेंट अस्थाई नियुक्तियों पर प्रतिबंध—
- (i) अधीनस्थ कार्यालय नियमावली के नियम 26 (3) के खण्ड (iii) के

अनुसार दि 15-3-78 के बाद 'आशुलिपिक थैली द्वितीय' के पद पर प्रजेंट अस्थायी नियुक्ति नहीं की जावेगी, इसी प्रकार—

- (ii) सचिवालय में नियम 28-क के अधीन, आशुलिपिकों के सवग में कोई प्रजेंट अस्थायी नियुक्ति नहीं की जावेगी ।

(6) अधीनस्थ कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिकों की प्रजेंट अस्थायी नियुक्तियों के लिये नियम 26 के उपनियम (4) में दि 23 5-77 से निम्न विशेष शर्तें और लगाई गयी हैं कि—

(1) "जिस व्यक्ति को प्रजेंट अस्थायी नियुक्ति द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त करना है, उसे नियुक्ति के लिये महान् प्राधिकारी द्वारा आयोजित टक्का-परीक्षा (अंग्रेजी में 25 शब्द प्रतिमिनट या हिन्दी में 20 शब्द प्रतिमिनट) पास करनी होगी, यदि उसे नियम 30 के खण्ड (क) के अधीन टक्का-परीक्षा संयुक्त नहीं किया गया हो ।

(2) इस टक्का परीक्षा को पास करने का प्रमाण-पत्र उसकी नियुक्ति आदेश में ही अभिलिखित किया जाना आवश्यक है ।

इस प्रकार उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार की गयी अस्थायी/स्थानापन्न नियुक्तियाँ "नियमित" होगी और इन नियमों का ध्यान रखे बिना की गई मनमानी नियुक्तियाँ "अनियमित" होगी, जैसा भागे न्यायालय-निर्णयों के आधार पर बताया जा रहा है ।

## 2 राजस्थान सरकार के निर्देश—

(1) जब विभागीय परीक्षाएँ आयोजित नहीं हुई हो और इसके कारण किसी कर्मचारी का स्थायीकरण नहीं हुआ हो, तो उसे उच्चतर पद पर अत्यावश्यक अस्थायी पदोन्नति दी जा सकेगी । किंतु उसकी पदोन्नति नहीं की जा सकेगी, जिसने विभागीय परीक्षा आयोजित होने पर उसमें भाग नहीं लिया हो या उसमें असफल हो गया हो ।

[ वि स F 7 (7) कामिक (कII) 75 दि 12-11-76 ]

(2) आवश्यक अस्थायी नियुक्तियों की समय वृद्धि के लिये समय पर स्वीकृति लेना सरकार ने आवश्यक माना है ।

[ वि स F6 (3) DOP (A-V) 79 दि 31 जनवरी 1979 ]

(3) विभिन्न सेवाओं के नियमों के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले खरिष्ठ पदों पर अस्थायी/स्थानापन्न नियुक्तियाँ

[ स एफ 1 (16) Appts (A-II) 67 दिनांक 12-6-1972 ]

के प्रमाण में विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा ऐसी प्रत्याई/स्वयनापन्न नियमों के अनुसरण में कोई समानता नहीं है। कई बार सेवा नियमों के सम्बन्ध में शक्तियाँ प्रदान करता है, का भी आज्ञा में उल्लेख नहीं किया जाता और कई बार शब्द 'तदर्थ' (एडहोक) का भी प्रयोग किया जाता है, जो नियमों में उपस्थित नहीं है। इससे अनेक उत्पन्न हुई हैं और ऐसे मामलों में विवाद होते हैं।

अतः सरकार ने निम्न लिया है कि— निगमित विभागों में नियुक्ति प्राधिकारियों को ध्यान में रखना होगा, जबकि साधारण/कनिष्ठ बतन पर जो सेवा का आधार बनाते हैं तथा वरिष्ठ पदों पर जो सेवा के भीतर प्रत्याई/स्वयनापन्न नियुक्तियों की जाती हैं, जो उपरोक्त सम्बद्ध नियमों के अधीन, नियमित करने के होते हैं, सम्बन्धित नियमों के अनुसार होगी—

- (1) ऐसी नियुक्तियों के लिये निम्नलिखित 'अधिकारियों तथा जिनके' सी० सी० ए० नियमों के अधीन पिछले पांच वर्षों के दौरान दण्डित किया गया है उन पर विचार नहीं किया जाना चाहिये।
- (2) पिछले पांच वर्षों के दौरान दिया गया दण्ड घटना के वर्ष के प्रति संगणित किया जाना चाहिये।

§3(1) ऐसे अधिकारियों पर भी, जिनके विरुद्ध सी सी ए इल्ल के नियम 16 के अधीन विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है तथा जिन पर, आरोपों के कारण स्वल्प को देखते हुए, प्राथमिक रूप से सी सी ए नियमों के नियम 14 में वर्णित प्रत्यापन्न दण्डों में से एक आरोपित किया जाने वाला (likely सम्भावित) है, उन पर भी समान रूप से विचार नहीं किया जाना चाहिये।

(11) उन मामलों में जहाँ सी सी ए इल्ल के नियम 17 के अधीन के एक जांच चल रही हो, तो उनकी स्थानापन्न/प्रत्यायी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है।

(12) ऐसे अधिकारी जिनके सत्यापित प्रमाणपत्र [Certificate of integrity] रोक लिये गये हैं उन पर विचार नहीं करना चाहिये।

(5) ऐसी नियुक्तियों को 'तदर्थ' (एडहोक) नाम नहीं देना चाहिये, क्योंकि विविध सेवा नियमों में ऐसा कोई नियम नहीं है जो तदर्थ नियुक्ति करने का उपबन्ध

§ वि स एफ 1(16) नियुक्ति (क-11) 67 दि 22-7-72 के बुद्धिपत्र द्वारा निम्नांकित के लिए प्रतिस्थापित—  
“ऐसे अधिकारियों पर भी, जिनके विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है और ऐसी स्थिति पर पट्टा चलाई गई है जहाँ सरकार ने निम्न लिया हो कि दण्ड अधिकारित किया जाना चाहिये, समान रूप से विचार नहीं किया जाना चाहिए।”

करता हो। जैसा कि सम्बन्धित नियम का शीर्षक बताता है, ऐसी नियुक्तियों को यदि स्थायी रिक्तस्थान हो, तो स्थानापन्न या अस्थायी (रिक्त स्थान) हो, तो अस्थाई कहा जाना चाहिये।

(6) ऐसी नियुक्तियाँ केवल वरिष्ठता-सह योग्यता के आधार पर उन में से जिनका पिछले पांच वर्षों का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (A C R) सतोष जनक हो, करनी चाहिये।”

3 अस्थायी पदोन्नति तथा विभागीय जाच—राज्य सरकार के परिपत्र दि 12-6-72 में विहित भागदशक निदेशों का ध्यान दिये बिना अपीलार्थी की पदोन्नति में बाहरी विचारों को स्थान दिया गया। जब पिछले 5 वर्षों के भीतरी कोई दण्ड नहीं दिया गया और न ऐसा निष्कर्ष दिया गया कि—नियम 14 (रा सि से CCA Rules) में वर्णित कोई असाधारण दण्ड नियम 16 के अधीन चालू जाच में अधिरो पित किये जाने की सम्भावना है। आरोप पत्र जो छुट्टी के बारे में है गंभीर नहीं हो सकता। तीन मामलों में जाच सम्बन्धित है, इनकी कोई सुमंगति यहाँ नहीं मानी गई। इस परिपत्र में कहीं भी ऐसा नहीं है कि—पिछली वि प समिति द्वारा पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त पाये गये व्यक्ति को इसके बाद में पदोन्नति नहीं दी जा सकती या उस पर विचार नहीं किया जा सकता। पिछली वि प समिति द्वारा उपयुक्तता का माप-दण्ड अप्रयुक्त माना गया। अपीलार्थी का मामला सही रूप से विचार में नहीं लाया गया। पदोन्नति के लिये चयन उचित मापदण्ड के सत्यनिष्ठ प्रयोग द्वारा किया जाना चाहिये।

काशी प्रसाद जैन बनाम राज्य (19/8 RLT 33)

एम एस राजवशी बनाम राज्य (1979 RLT 34)

श्रीमती तीजादेवी व समाज कल्याण विभाग 1979 RLT 41

जगदीश प्रसाद शर्मा व राजस्व विभाग 1979 RLT 56

4 तदर्थ (Adhoc) का अर्थ—‘शब्द “एड हॉक” का उसके सही अर्थ में अभिप्राय है, “स्थान पूर्ति (यानी—स्थान रोकना stop gap), अर्थात्—पदोन्नति के लिये पात्र सभी व्यक्तियों पर विचार किये बिना नियुक्ति करना। ऐसी नियुक्तियाँ उन व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करती हैं, जिन पर विचार नहीं किया गया यद्यपि वे उसके लिये पात्र थे। केवल वे ही व्यक्ति ऐसी नियुक्ति को चुनौती दे सकते हैं, न कि वे जिन पर विचार करने के बाद जिनको नहीं चुना गया।”

“जब नियमानुसार विचार करने के बाद ऐसी तत्थ नियुक्तियाँ की जाती हैं, तो इनमें तथा नियमित नियुक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाता। दोनों प्रकार की ये नियुक्तियाँ यदि चयन के क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों की पात्रता पर विचार करने के बाद की जाती हैं तो वे समान विचारों (consideration) से शासित होगी, अर्थात्—आरम्भ में नियुक्त व्यक्ति उन पदों पर जिन पर वे पदोन्नत किये गये हैं तब वत स्थानापन्न (Officialing) होंगे जब कि वे पद स्पष्ट रूप से रिक्त न हो जाय जिन पर उनकी स्थायी (वनफम) किया जा सके।”

[सी बी दुबे बनाम भारतसभ 1975 (1) SLR 580 (Delhi)]

(1) नियमों का पालन अनिवार्य—जहाँ नियमों में अस्पष्टता रक्त स्थानों पर एवहाक नियुक्तियाँ करने की विधि (प्रासाजर) दी हुई है, तो उन नियमों का भाग्य या उन नियमों की अवहेलना करके दी गई नियुक्तियाँ सर्वोच्च न्यायाधीश (1) के अधीन अवैध हैं।

[डा० स्वयंवर प्रसाद मुदानिया बनाम राजस्थान राज्य—1971 RLW 397]

(ii) तदर्थ पत्राचार 1969 से सगानार दी जा रही है। यह सरकार का कोई अधिकार नहीं है कि वह कई वर्षों तक (1969 से 1975 तक) नियमावली में विभागीय पदोन्नति समिति को बुलाये बिना तत्त्व नियुक्तियाँ जारी रखे। वय व अनुसार वरिष्ठता तय करनी होती है और पत्राचार विभागीय-पदोन्नति समिति की मिकारिण पर होनी जाती है।

[डा० धीकात राय बनाम राजस्थान राज्य 1975 (2) SLR 94 (Ra)]

(iii) नियुक्ति जो दो वय तक चलनी रही उसे तदर्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तदर्थ नियुक्ति इतनी लम्बी अवधि के लिये नहीं रह सकती।

[डा० धमनलाल बनाम हिमाचल प्रदेश 1975 (2) SLR 806 (HP)]

5 अधिकरण के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष—राजस्थान अधीनस्थ कार्यलय लिपिकवर्गीय सेवा नियम के नियम 26(3) (i) के अधीन एक रक्तस्थान की अस्थायी रूप से भरा जा सकता है, चाहे वह रक्तस्थान स्थायी ही हो।

नियम 26 (3) के अधीन की गई नियुक्ति प्रत्यक्ष एक कार्यकारी व्यवस्था है, जिसमें पदोन्नति के कोई तत्व नहीं होते।

[अपील नं 92/1976 धनस्यामलाल शर्मा 5-1-77]

नियम 15 (5) 26 (3) (i) 26 B 27 तथा 27 A—परिपत्र दि 12-6-72 का लागू होना—पाच वय में पहले का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन या सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र राखना अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के प्रयोजन से असम्भव है, भल उनको नहीं देखा जा सकता।

[अपील नं 737/77 कबरलाल (1978 RLT 79)]

अपीलार्थी की अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के द्वारा पदोन्नति के लिये उस निष्ठा से विचार करना हागा जिस दिन से उसके कनिष्ठों को ऐसी नियुक्ति दी गई, मार समुचित समय पर उसके हक पर विचार नहीं किया गया।

[अपील नं 105/78 पद्म नारायण दुवे, (1978 RLT 116)]

जब कभी एक वरिष्ठ व्यक्ति सका में प्रतिवर्तित किया जाता है और उसके कारण अर्जेंट अस्थायी नियुक्तियों के लिये नयी व्यवस्था करने की आवश्यकता होता है, तो ऐसी परिस्थिति में अर्जेंट अस्थायी नियुक्तियों के लिये नई व्यवस्थाओं विधि के

सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार करनी होगी। जब ऐसी नियुक्तिया की जायें, तो वरिष्ठता के आधार पर उपयुक्तता के अध्ययन विचार करना होगा और यदि वरिष्ठता-सूची उपलब्ध नहीं है, तो सब पात्र अभ्यर्थियों पर पदोन्नति के लिये विचार करना होगा।

[अपील स 143/78 श्री कृष्ण भाटया दि 31-7-1978]

पदोन्नति के कोटे के रिक्त स्थानों पर अर्जेंट अस्थाई नियुक्ति वरिष्ठता के क्रम में उपयुक्तता के अध्ययन रहकर करनी होगी। यदि आयोग ने कुछ अधिकारियों की अस्थायी सेवा जारी रखने के बारे में सहमति रोक ली हो, जो सीधी भर्तियों के कोटे में थे, तो उन अधिकारियों को पदोन्नति के कोटे में से प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता।

[अपील स 84/78 बिरोरीमल अग्रवाल (1978 RLT 111)]

तदर्थ पदोन्नति से प्रत्यावर्तन—तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्ति का पदोन्नति में निहित अधिकार नहीं होता और उसे किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। जब पदोन्नति नियमों के प्रतिबल की गई हो, तो गलत आज्ञा के अधीन प्राप्त किया गया अनुचित अस्थायी लाभ बिना सुनवाई का अवसर दिये व्यक्ति कमचारियों के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद वापस लिया जा सकता है।

— [अपील स 774/77 बाबूलाल (1978 RLT-IV 64)]

जब एक कमचारी को अस्थायी रूप से उच्च पद पर पदोन्नत किया गया और बाद में उसके अधिष्ठायी पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया। आज्ञा में स्पष्ट शब्दों में कोई कलक (Stigma) नहीं है, तो संविधान का अनुच्छेद 311 (2) प्रभावित नहीं होगा।

[अपील स 84/76 प्रभुदयाल बनाम राज्य दि 11 11 76]

सामान्य नियम यह है कि—अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति वाले व्यक्तियों के प्रतिवर्तन पर वरिष्ठतम व्यक्ति को प्रतिवर्तित किया जावेगा।

[अपील स 439/77 कल्याणदान दि 13 6 78]

सात वर्ष बाद प्रत्यावर्तन—अपीलार्थी को आशुलिपिक के पद पर तदर्थ आधार पर 27 8-71 को पदोन्नत किया गया। सात वर्ष की सम्म्वी शर्तों तक कार्य करने के बाद उसे वरिष्ठ लिपिक के पद पर प्रतिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि यह पाया गया कि उसकी पदोन्नति की आज्ञा उचित (proper) नहीं थी। दूषित आज्ञा देने से पहले उसे 'कारण बताओ नोटिस' भी नहीं दिया गया। अभिनिर्धारित कि—नैसर्गिक तथ्य के सिद्धांतों की भाँति है कि यह नहीं किया जाना चाहिये था। अतः दूषित आज्ञा अपास्त की गई।

[अपील स 415/78 सन्नीमुद्दीन सिद्दीकी (1978 RLT 171)]

# परिवीक्षा एवम् स्थायीकरण [Probation & Confirmation]

- |                                    |         |                                     |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 1 परिवीक्षा का अर्थ व स्वरूप       | अनुक्रम | 6 पुष्टीकरण अनिवार्य                |
| 2 परिवीक्षा की शर्तें              |         | 7 पुष्टीकरण व विशेष नियम व प्रावधान |
| 3 परिवीक्षा में असन्तोष-जनक प्रगति |         | 8 विभागीय जाच व निरीक्षण के दौरान   |
| 4 पुष्टीकरण का अर्थ व महत्व        |         | 9 कुछ प्रश्न व उत्तर                |
| 5 पुष्टीकरण की शर्तें              |         | 10 कुछ महत्वपूर्ण निष्पत्ति         |

## ● नियमावली प्रसार

विषय	अधीनस्थ सचिवालय कार्यालय		अधीनस्थ पचायत पंचायत समिति श्रृंखला		
	A	B	C	D	E
1 परिवीक्षा की अवधि	28,	30,			
2 स्थायीकरण आवश्यक	28 क	30 क	22	25	20
3 —म असन्तोषजनक प्रगति	29	31	X	X	20 क
4 स्थायीकरण (पुष्टीकरण)	30	32	23	26	X
5 वेतनमान	31	33	24	27	21
6 परिवीक्षा में वेतन वृद्धि	32	33 क	25	31	22
			26	32	23

### 1 परिवीक्षा का अर्थ एवं स्वरूप—

नियुक्ति की प्रारम्भिक अवस्था में एक नवभर्ता की उपयुक्तता तथा कार्य कुशलता का परीक्षण किया जाता है और उसे आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाती है। इस 'परिवीक्षा' (प्रोवेशन) कहते हैं। परिवीक्षा के दौरान उस नवभर्ता को नियमानुसार वेतन एवं भत्ते तथा वास्तविक वेतन वृद्धियाँ भी दी जाती हैं। परिवीक्षा के दो रूप हैं—(1) सीधी भर्ती के द्वारा जब कोई व्यक्ति किसी स्थायी रिक्त पद पर कुछ निश्चित अवधि व शर्तों पर नियुक्त किया जाता है तो उसे परिवीक्षाधीन (प्रोबेशनर) कहते हैं। [नियम—राज सेवा नियम 7 (30)] इस

प्रकार के व्यक्ति सेवा में नये नये भर्ती होते हैं। यह नियुक्ति परिवीक्षा के बाद अधिष्ठायी (स्थायी) हो जाती है, जब उसका पुष्टीकरण कर दिया जाता है। परन्तु उसके अनुपयुक्त पाये जाने की दशा में उस परिवीक्षाधीन की सेवा समाप्त की जा सकती है।

(11) "परिवीक्षा पर" (On Probation)—जब कोई व्यक्ति उच्चतर पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो उसकी उपयुक्तता की जांच की जाती है, वह "परिवीक्षा पर" बही जाती है। यह स्थिति 'स्थानापन्न नियुक्ति' की है, जिसे परिवीक्षा की शर्तें पूरी करने पर स्थायी या अधिष्ठायी कर दिया जाता है, परन्तु अनुपयुक्त पाये जाने की दशा में उक्त "परिवीक्षा पर" कार्यरत व्यक्ति की सेवा समाप्त नहीं की जाती, वरन् उसे मूलस्थान पर वापस प्रतिधत्तित (reverted) कर दिया जाता है।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि—परिवीक्षा के दौरान किसी भी कमचारी को उस पद पर जिस पर उसे कार्य पर लगाया गया है, कोई पदाधिकार पुष्टीकरण से पहले प्राप्त नहीं होता। अतः उन्हें सेवा से हटाने पर कोई प्रतिकर (मुआवजा) नहीं मिल सकता।

2 परिवीक्षा की शर्तें—नियमों में वर्णित उपबन्धों के आधार पर परिवीक्षा की दो शर्तें हैं—

(1) परिवीक्षा की अवधि—

(क) 'परिवीक्षाधीन' के लिये—दो वर्ष,

(ख) 'परिवीक्षा पर' नियुक्ति के लिये—एक वर्ष

परन्तु अधीनस्थ न्यायालय नियमावली के नियम 22 में सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्ति (= परिवीक्षाधीन) के लिये परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष है, जब कि पदोन्नति के बाद परिवीक्षा की कोई अवधि नहीं बताई गई है।

(11) सरकार द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करना या प्रशिक्षण प्राप्त करना।

परिवीक्षा की अवधि की गणना—अस्थायी रूप से उसी पद पर किये गये कार्य की अवधि को परिवीक्षा में गिना जा सकता है और प्रतिनियुक्ति पर जाकर किसी उच्चतर पद पर किये कार्य की अवधि को भी परिवीक्षा में गिन लिया जावेगा।

इन शर्तों को पूरी करने पर एक कमचारी का स्थायीकरण (पुष्टीकरण) किया जा सकता है।

3 परिवीक्षा के दौरान असंतोषजनक प्रगति—

उपरोक्त शर्तें पूरी न करने पर निम्न कार्यवाही की जाती है—

(1) परिवीक्षा की अवधि में वृद्धि—समुचित मामलों में इसे क्रमशः 2 वर्ष और 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के नियम 23 के



अनुसार यह वृद्धि "छ मास" की होती है। अनुसूचित जाति/जन जाति व सन्तों के लिये कुन मिलाकर 3 वष तक की वृद्धि की जा सकती है। निलम्बन और विभागीय जांच व मामले में भी इस अवधि को यथावित बढ़ाया जा सकता है।

- (ii) परिवीक्षाधीन की सेवा समाप्ति (Discharge)  
(iii) 'परिवीक्षा-पर' नियुक्त व्यक्ति का प्रतिवर्तन—(reversion) जसा कि पहले ऊपर बताया जा चुका है।

4 पुष्टीकरण (स्थापिकरण-जनफर्मेशन) का अर्थ एवं महत्व—

पुष्टीकरण सेवा की एक बात है और कुछ विहित (निर्धारित) घटनाओं व घटित होने पर इसे प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न होता है। इसको स्थगित रखने का कोई अधिकार नहीं है जब कि इसकी शर्तें पूरी हो गई हों। पुष्टीकरण सेवा का एक आवश्यक परिणाम है और सम्भवतः एक सरकारी कमचारी के सदाकाल (कैरियर) में एक महत्वपूर्ण घटनात्मक भूचिह्न (सैण्डमाक) है। यह उस उस पद पर अधिकार प्रदान कर उसके नियोजन में सुरक्षा प्रदान करता है। जब तक पुष्टीकरण नहीं होता सेवा के अनेक लाभ अर्जित नहीं होते।<sup>1</sup>

उच्चतम न्यायालय ने पुष्टीकरण का व्यवहारिक स्वरूप बताते हुए एक प्रमुख निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि—“(नियम जो) जेष्ठता (वरिष्ठता) व अवधारण को पुष्टीकरण की एकमात्र बसोटी पर निर्भर कर देता है, हमें असमर्थता प्रतीत होता है। पुष्टीकरण सरकारी सेवा की निम्न-अनिश्चितताओं में से एक है जो कि न तो पेश्वारी की दक्षता पर और न ही अधिष्ठायी रिक्तियों के उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक सुस्पष्ट दृष्टान्त जो कि हमारे देश के एक भाग में सुजात है न्यायपालिका के एक माननीय सदस्य का है जिनको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पुष्ट कर दिये जाने के कई वर्ष पश्चात् जिला न्यायाधीश के रूप में पुष्ट किया गया था। यह बात इन रिट पिटीशनो के अभिलेख पर है कि—स्वानापन उप-इजीनियर की पुष्टि नहीं की गई थी, भले ही अधिष्ठायी रिक्तियाँ उपलब्ध थी जिनमें कि वह पुष्ट किया जा सकता था। इससे यह दर्शित होता है कि—यह जरूरी नहीं है कि पुष्टीकरण कि हों निश्चित नियमों के अनुरूप हो और यह बात कि क्या किसी कमचारी को पुष्टि की जानी चाहिये या नहीं सरकार की इच्छा पर ही निर्भर करती है।”<sup>2</sup>

इस प्रकार पुष्टीकरण सरकार की मनमानी कायवाही के रूप में एक समस्या बन गया है। इससे निपटने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं और इसे नियमित बनाने के लिए नियमों में संशोधन किये गये हैं।

- 1 डॉ० विनय कुमार बनाम उड़ीसा राज्य 1974 (1) SLR 320 (Orissa)
- 2 एस बी पटवर्धन बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) 3 उम नि प 609 = AIR 1977 S C 2051 (पैरा 39)

## 5 पुष्टीकरण की शर्तें—

विभिन्न नियमों में शर्तों को अनेक रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिनको सार रूप में इस प्रकार बताया जा सकता है —

- (i) परिवीक्षा की अवधि पूरी करनी होगी,
- (ii) निर्धारित विभागीय परीक्षाएँ या प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरे करने होंगे,
- (iii) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि—(क) उसकी सत्यनिष्ठा सदेह से परे है और (ख) अथवा वह सब प्रकार से उस पद के लिये उपयुक्त (fit) है। यह उसकी वार्षिक गुप्त रिपोर्ट (A C R) या मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित होगा।

## 6 पुष्टीकरण अनिवार्य, जिसे रोका नहीं जायेगा—

पुष्टीकरण समस्या को हल करने के लिये अब पुष्टीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है, जो निम्नांकित शर्तों पर निभर करेगा —

- 1 नियमित नियुक्ति की गई हो,
- 2 परिवीक्षा की निर्धारित अवधि पूरी हो गई हो,
- 3 स्थायी रिक्त स्थान उपलब्ध हो,
- परिवीक्षाधीन के लिये निर्धारित शर्तें पूरी कर ली गई हो,
- 5 नियमानुसार कोटा के अनुसार और वरिष्ठता के अनुसार वह पान हो

—उपरोक्त शर्तों के पूरा होने पर भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि पूरी होने के दिनांक से छ माह के भीतर पुष्टीकरण की आज्ञा जारी नहीं करे, तो उस कमचारी का पुष्टीकृत मानन का अधिकार प्राप्त होगा—अर्थात्—वह स्वतः या अनिवार्य रूप से पुष्टीकृत या स्थायी हो जायेगा।

[इसका शब्द “नियमित नियुक्ति” के अर्थ के लिये अध्याय (1) में पृष्ठ 218 पर, अध्याय (2) में पृष्ठ 231 पर तथा अधीनस्थ कार्यालय नियमावली के नियम 28—क के स्पष्टीकरण पृष्ठ 81 पर देखिये]

## पुष्टीकरण रोका नहीं जायेगा—

असतोप जनक प्रगति के लिये ऊपर पैरा 3 में वर्णित कायवाही की जा सकेगी, परन्तु ऐसी कायवाही न की गई हो, तो उसका पुष्टीकरण नहीं रोका जा सकेगा। उसका पुष्टीकरण रोकने पर उसकी परिवीक्षा की अवधि में वृद्धि की जाती है, परन्तु इसके लिये उसके कार्य के असतोपजनक होने के कारण उस कमचारी को उस परिवीक्षा की अवधि के भीतर ही संप्रेषित किये जाना आवश्यक है और उसकी सेवा पुस्तिका तथा गोपनीय पत्रिका में तत्काल लिखे जाने आवश्यक हैं। परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने के बाद असतोपजनक कार्य बतलाना व परिवीक्षा की अवधि बढ़ाना अनियमित होगा। इस प्रकार इस नये संशोधन से मनमाने तरीके से पुष्टीकरण नहीं रोका जा सकेगा।

## 7 पुष्टीकरण के विशेष नियम एवं प्रावधान—

पुष्टीकरण की समस्या से निपटने के लिये सरकार ने निम्नांकित विशेष नियम एवं प्रावधान लागू किये हैं—

(क) राज्य सरकार ने 1-4-1964 से पूर्व के तथा 1-4-1968 तक के अस्थायी कमचारियों का तुरंत पुष्टीकरण करने के लिये—

“राजस्थान विहित सेवा अस्थायी कर्मचारियों की अधिष्ठायी नियुक्ति तथा वरिष्ठता निर्धारण) नियम 1972” बनाये थे, जो भागे परिशिष्ट (2) में दिये जा रहे हैं। कृपया यथास्थान देखिये।

(ख) अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियमावली में नियम 30 नियम 30 के अ पूर्व पुनर्गठित राजस्थान के कमचारियों के पुष्टीकरण के लिये तथा नियम 30 ख में दि 17-10-1970 को परिवीणाधीन व्यक्तियों का पुष्टीकरण करने के विशेष उपबंध किये गये हैं।

(ग) राजस्थान पचासत समिति त्रि प सेवा के सदस्यों के लिये दि 14 12 1976 का अधिनियम में संशोधन कर धारा 86 में नयी उपधारा (8-क) जोड़कर दि 14-12-76 को दो वर्ष की ‘यूनतम’ अस्थायी सेवा पूरी करने वाले कमचारियों का दि 14 12 76 से अधिष्ठायी नियुक्त (अनफुल) कर दिया गया है। यह प्रादेशात्मक संशोधन है।

## 8 विभागीय जांच एवं निरन्तरन के दौरान स्थायीकरण—

सरकार ने निर्देश जारी किया है कि—अनुशासनिक कायदाही के अधीन कमचारियों तथा निरन्तरनाधीन कमचारियों का स्थायीकरण उनके पुन स्थापन के बाद किया जाना चाहिये। यदि सी सी ए नियम 16 के अधीन असाधारण दण्ड दिया जावे, तो उसका स्थायीकरण नहीं किया जायेगा परंतु जिनके विरुद्ध नियम 17 के अधीन कायदाही चल रही है उनका स्थायीकरण नहीं रोका जाना चाहिये। परिवीणाधीन कमचारियों का स्थायीकरण आज्ञा दि 28 12 74 के अनुसार किया जाना चाहिये।

## 9 कुछ प्रश्न और उत्तर—(सुभाष)

प्रश्न (1) एक अस्थाई कनिष्ठ लिपिक दि 18 6 70 को नियुक्त हुआ। उसकी स्वेच्छा से उसका स्थानांतर दूसरे विभाग में हुआ और उसने दि 9 9 70 को कामभार सभाला। अब नये विभाग में उसकी वरिष्ठता 18 6 70 से होगी या 9 9 70 से।

उत्तर—अस्थायी सेवा में कोई पदाधिकार (लिपन) प्राप्त नहीं होता। केवल स्थायीकरण के बाद ही पदाधिकार प्राप्त होता है। अतः पदाधिकार के अभाव

मे पहले विभाग मे की गई अस्थायी सेवा का कोई लाभ नहीं मिल सकता। नये विभाग में सेवाकाल की गणना दि 9 9 70 से होगी और स्थायीकरण के बाद ही वरिष्ठता सूची में नाम अंकित हो सकेगा।

प्रश्न (2) एक कर्मचारी को दिनांक 14 9 72 की आज्ञा द्वारा दि 4 9 70 से स्थायी कर दिया गया, परंतु वरिष्ठता सूची बनाते समय दि 4 9 70 की बजाय आज्ञा की दिनांक 14 9 72 से वरिष्ठता दी गई, इससे उसका नाम 50 व्यक्तियों के नीचे आ गया।

उत्तर—इस मामले में नियमों में पहले “अधिविधायी नियुक्ति की आज्ञा के दिनांक से वरिष्ठता तय होने का उद्देश्य था, जिसे दि 15 11 76 से ‘अधिविधायी नियुक्ति का वध’ कर दिया गया है। यद्यपि उस समय लागू नियम की भाषा के अनुसार उद्देश्य वरिष्ठता सूची नियमित प्रतीत होती है, किंतु यह वरिष्ठता निवारण का मातृशब्द सही नहीं था [देखिये—ए सी पटवर्धन बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) 3 उन रि प 609=AIR 1977 SC 2051] अब ‘अधिविधायी नियुक्ति का वध’=दिनांक से वरिष्ठता तय करने का मातृशब्द मान लिया गया है। अब स्थायीकरण की आज्ञा के दिनांक का महत्व नहीं है, बल्कि अब से स्थायीकरण किया गया—अर्थात्—अधिविधायी नियुक्ति की गई उसी से वरिष्ठता मानी जावेगी। परिणामस्वरूप उपरोक्त मामले में वरिष्ठता दि 4 9 70 से मानी जावेगी। “अधिविधायी नियुक्ति” की परिभाषा अध्याय (1) में देखिये।

प्रश्न (3) देखने में आया है कि—कुछ स्थायीकरण की आज्ञाओं में नामों के सामने अ किन मूल नियुक्ति दिनांक से स्थायी किया जाता है, तो कुछ में कुछ भी नहीं लिखा जाता या तुरंत प्रभाव से’ (with immediate effect) लिखा होता है। इनमें से सही व नियमित कौन सी है ?

उत्तर—अधिकतर स्थायीकरण नियमित कामवाही के रूप में नहीं किये जाते, परंतु मनमाने ढंग से किये जाते रह चुके हैं और मनमाने तरीके से आज्ञायें निकाली जाती रही हैं। इस बात की उच्चतम न्यायालय ने भी भर्त्सना की है। अब नियमों में दिनांक 28 12 74 से इसे कुछ व्यवस्थित किया गया है। स्थायीकरण या पुष्टीकरण नियुक्ति का किया जाता है, अतः यह नियुक्ति की दिनांक से उस नियुक्ति की पुष्टि करता है। यह तभी किया जा सकता है, जबकि स्थायी पद रिक्त हो परंतु यह पुष्टि स्थायी पद रिक्त होने की दिनांक को या इसके बाद आज्ञा जारी कर किया जा सकता है और उस आज्ञा की दिनांक का कोई महत्व नहीं होना चाहिये, यह पूर्वकालिक प्रभाव से मूल नियुक्ति के दिनांक से किया जाना चाहिये। अब जिन आज्ञाओं में मूल नियुक्ति दिनांक से स्थायीकरण किया जाता है वे नियमित और वध हैं।<sup>1</sup>

1 एन एस मेहता बनाम भारतसच 1977 Lab IC 904, 1972 Lab IC 345 (SC) पर आधारित।

वर्ष बार रिक्त स्थान उपलब्ध होने की दिनांक से स्थायीकरण किया जाता है, इससे पहले की गई स्थानापन या प्रस्थायी सेवा को नहीं गिना जाता, जो एक प्रकार से अस्थायी है। फिर स्थायीकरण से वेतनादि पर तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं, केवल वरिष्ठता पर प्रभाव पड़ता है, अतः अव्यवस्थित व मनमाने दिनांक से स्थायीकरण नहीं किया जा सकता। यह पहले की गई नियुक्ति की पुष्टि मात्र है न कि कोई नयी नियुक्ति और इस पुष्टि की भाषा चाहे कभी दी जाय, यह उस मूल नियुक्ति की दिनांक से प्रभावी होती है। इससे वरिष्ठता सम्बन्धी बहुत से विषय समाप्त हो जायेंगे।

### 10 कुछ महत्वपूर्ण निर्णय—

(क) आठ वष बाद सरकार अपनी गलती को सही कर एक स्थायी नियमों के फील्डमैन नियुक्ति किया गया और प्राप्ति 19-3-1960 को कृषि विभाग कनिष्ठ लिपिक में परिवर्तित कर दिया गया, जो समान वेतनमान में था। प्राप्ति ने कनिष्ठ लिपिक का कार्यभार 14-1964 को सम्भाला और बाद में कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती की परीक्षा में सफल होने पर उसे 6 जनवरी, 1965 से स्थायी (कमलम) कर दिया गया। स्थायीकरण की भाषा दि-25-3-64 के अनुसार 11-62 के पहले की भर्ती की गई और 11468 को उस वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति दी गई और 30-12-72 की भाषा से निर्देशक कृषि विभाग ने उसे दि-1-4-70 से उस पद पर नियुक्त कनिष्ठ लिपिक की भाषा दि-25-3-64 के अनुसार 11-62 के पहले की भर्ती की गई और 11468 को नियुक्त हुआ, अतः वह इस परीक्षा में प्रवेश ले सकते थे, किन्तु प्राप्ति 14-1964 को स्थायीकरण की दिनांक को सशोधित कर 6-1-65 की बजाय 1-4-1970 कर दिया गया। इस आधार पर 30-12-72 की भाषा से कनिष्ठ लिपिक के पद पर उसकी स्थायीकरण की सूची में भी उसी के अनुसार सशोधन कर दिया। परिणामस्वरूप उसे 18-11-1972 से कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रतिवर्तित कर दिया गया।

उच्च यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि—दुमान लाल के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि—9 जुलाई, 1970 से पहले फील्डमैन का पद अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिक वर्ग में था और कनिष्ठ लिपिक के समान वेतनमान में था। अतः नियम 6 (2) की टिप्पणी के अनुसार फील्डमैन का पद कनिष्ठ लिपिक के समान पद का था। 8 वष बाद दिसम्बर 1972 में यह निर्णय देना कि—उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल दे दी गई, यह बात सगत नहीं है। अतः भाषा को अस्वीकार किया गया। प्राप्ति को 6-1-65 से कनिष्ठ लिपिक पद पर स्थायी माना गया।

वरिष्ठता के निर्धारण के लिये कनिष्ठ लिपिक के पद पर वास्तविक अधिष्ठायी नियुक्ति की दिनांक आधार होगी और प्राप्ति की स्थायीकरण की दिनांक 6-1-65 के अनुसार उसको वरिष्ठता सूची में स्थान दिया जायगा और उसे सब परिलाभ मिलेंगे।<sup>11</sup>

(ख) एक अस्थायी कमचारी और स्थायी पद—एक अस्थायी सरकारी सेवक के रूप में अस्थायी पद पर नियुक्ति की गई। बाद में उस पद को स्थायी बना दिया जाने पर उस अस्थायी सरकारी सेवक को कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं मिल जाता है और उसे स्वतः ही स्थायी सेवक की हैसियत प्राप्त नहीं हो जाती है।<sup>2</sup>

(ग) जब परीवीक्षा की अधिकतम अवधि (तीन वर्ष) की समाप्ति के बाद प्रार्थी को स्थायी समझा गया—“ स्थायीकरण की औपचारिक आज्ञा जारी नहीं होने पर भी उसे स्थायी समझा गया। उसे स्थायी करने से मना करना सेवानियमा के विपरीत होने से निष्प्रभावी है। यदि प्रार्थी का कार्य व आचरण सतोपजनक नहीं थे, तो उसकी सेवायें (उसी समय) समाप्त कर दी जानी चाहिये थी, परन्तु नियमों के अधीन यह अनुज्ञेय नहीं है कि उसे सदा एक अप्रुष्ट के रूप में सेवामें बनाये रखा जाय। अब तक प्रार्थी सेवा के चौबीस वर्ष पूरे कर चुका है और यह सरकार की ओर से बहुत पक्षपातपूर्ण (Unfair) है कि उसे परीवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर युक्तियुक्त अवधि के भीतर स्थायी (पुष्ट) नहीं किया गया।”<sup>3</sup>

(घ) स्थायीकरण स्थायी रिक्त पद होने पर ही सम्भव—नियम 7 (अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय नियमावली) द्वारा निर्धारित (विभागीय) परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर सभी अस्थाई लिपिकों को स्थायी बना देने की सरकार पर कोई बाध्यता नहीं है। केवल वही स्थायी किये जायेंगे, जो उपलब्ध स्थायी रिक्त स्थानों पर भरे जा सकते हैं। शेष को उनकी बारी आने तक प्रतीक्षा करनी होगी।<sup>4</sup>

(ङ) स्वतः स्थायीकरण कब हो सकता है? (i) परीवीक्षा की समाप्ति पर “स्वतः स्थायीकरण” नहीं होता, जबकि नियमों में ऐसा कोई उपबंध न हो। परीवीक्षाकाल में निःसम्बन्ध के बाद बिना किसी आरोप या जाच के बाद में सेवा समाप्ति कर देने से कोई कलक (दोष) नहीं माना गया।<sup>5</sup>

(ii) एक व्यक्ति परीक्षा पर नियुक्ति के बाद परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर भी सेवा में बना रखा गया। नियमों में जहाँ सेवा में बन रहना (Continuation) स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से मना हो, वहाँ इसे पुष्टीकरण मानना होगा, परन्तु जहाँ ऐसी रोक (मना) नहीं है वहाँ इसे पुष्टीकरण नहीं माना जायेगा।<sup>6</sup>

(iii) छ मास की परीवीक्षा की अवधि पूरी किये बिना पुष्टीकरण (स्थायी) नहीं किया जा सकता। पुष्टीकरण के पहले समुचित-चयन (due selection) होना आवश्यक है।<sup>7</sup>

2 निदेशक, पचायत राज बनाम बाबू सिंह [1972] 1 उप नि प नि सा 80 = AIR 1972 SC 420

3 मनाहरलाल बनाम पंजाब राज्य 1979 SLJ 150  
पंजाब राज्य बनाम धर्म सिंह 1968 SLR 247 (SC) पर आधारित।

4 राजस्थान राज्य बनाम फतेहचंद 1970 SLR 55 and 854 (SC)

5 कैलाशचंद्र सेठिया बनाम राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल 1973RLW544

6 मोतीलाल बनाम भारत सघ 1972 RSW 550

7 धोमप्रकाश गुप्ता बनाम राज्य (1978 RLT 76)

(घ) अप्रुटीकरण के पहले नोटिस देना आवश्यक—

एक बार किसी कर्मचारी को स्थायी (पनफर्म) कर दिया गया, तो उस नैसर्गिक 'बाय के सिद्धांत' का पालन किये बिना (अर्थात्-सूचना देकर सुनवाई का अवसर दिये बिना) अप्रुटीकरण (डिक्शनफर्म) नहीं किया जा सकता।<sup>8</sup>

(छ) प्रुटीकरण रोकना बन्ड नहीं—

पचायत समिति जिता परिषद सेवा नियम के नियम 25, 26 तथा 27 के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी एक परीचीक्षाधीन क बाय की सचीक्षा कर इस निष्पत्ति पर पहुँच सकता है कि—उसका बाय असतोप जनक है और वह प्रुटीकरण क स्थिति प्रयोज्य है। अतः नियमानुसार की गई बायवाही को दण्ड के रूप में नहीं माना जा सकता।<sup>9</sup>

(ज) राजस्थान सिविल सेवा (अस्थायी कर्मचारियों की अधिष्ठायी नियुक्ति एवं बरिष्ठता निर्धारण) नियम 1972 के अधीन, स्वतः प्रुटीकरण का अधिकार—

(i) अधीतार्थी को कनिष्ठ लिपिक पद से अधिष्ठेय (सरप्लस) घोषित कर कनिष्ठ लिपिक के रूप में आमेतित कर लिया गया, परन्तु बाद में उसे 'शेम्स सुपरवाइजर' के पद पर पदस्थापित कर दिया गया। परन्तु अब यह नहीं कहा जा सकता कि वह कनिष्ठ लिपिक नहीं था और केवल शेम्स सुपरवाइजर ही था। अतः उसे राजस्थान सिविल सेवा (अस्थायी कर्मचारियों की अधिष्ठायी नियुक्ति एवं बरिष्ठता निर्धारण) नियम 1972 के अधीन प्रुटीकरण (स्थायीकरण) का अधिकार है।<sup>10</sup>

(ii) राजस्थान सिविल सेवा (अस्थायी कर्मचारियों की अधिष्ठायी नियुक्ति तथा बरिष्ठता निर्धारण) नियम 1972 एक व्यक्ति को स्वतः प्रुटीकरण क बहुस्तोतरणीय अधिकार प्रदान करते हैं और इसके बाद उसकी बरिष्ठता स्थायी कर्मचारियों में तय करनी होगी।<sup>11</sup>

- 8 अपील स 159/78 गोवन्द नलाल दि 22-8-78
- 9 चम्पालाल बनाम राज्य 1974 WLN 910
- 10 अपील स 273/78 ओमप्रकाश सेनी दि 19-9-1978
- 11 अपील स 655/77 जगदीश प्रसाद विजय (1978 RLT147)

## वरिष्ठता सूची एवं वरिष्ठता के मापदण्ड (Seniority List & The Basis of Seniority)

### संयुक्त

- 1 वरिष्ठता का अर्थ व महत्व
- 2 वरिष्ठता का आधार कुछ निर्देशक सिद्धांत
- 3 वरिष्ठता का आधार एवं नियमावली
- 4 उच्चतम न्यायालय का प्रमुख निर्णय
- 5 "अधिष्ठायी नियुक्ति का बंध"
- 6 सरकारी निर्देश
- 7 अर्थ नियमों के उपबन्ध
- 8 स्थानान्तर और वरिष्ठता
- 9 पारम्परिक वरिष्ठता के मापदण्ड
- 10 वरिष्ठता सूची तैयार करना
- 11 कुछ महत्वपूर्ण निर्णय

1 वरिष्ठता या जेष्ठता (सिनिोरिटी) का अर्थ व महत्व—किसी सेवा या मकान में किसी कर्मचारी का जो स्थान होता है, उसे वरिष्ठता कहते हैं। जो व्यक्ति वरिष्ठतम होता है, उसे अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति मिलती है, यदि वह अयोग्य (fit) और पात्र (eligible) हो। अतः वरिष्ठता या जेष्ठता का सेवा में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। वरिष्ठता के क्रम से जो सूची बनाई जाती है, उस "वरिष्ठता सूची" कहा जाता है, जिसे देखकर प्रत्येक कर्मचारी को अपनी सेवा या मकान में अपने स्थान या क्रमांक का पता चलता है और उसे यह भी पता चलता है कि—उसने साधारण में से कौन उससे वरिष्ठ है और कौन उससे वरिष्ठ है? इस प्रकार अपनी पदोन्नति के अवसरों का एक कर्मचारी ध्यान रखकर समय पर अपने अधिकार का भाग कर सकता है। अतः 'वरिष्ठता सूची' एक कर्मचारी की भाग्य पथी की तरह है। हम यहां वरिष्ठता निर्धारित करने के सिद्धान्त व मापदण्डों व नियमों के आधार पर विवेचन करेंगे, ताकि सही वरिष्ठता का पता लगाया जा सके और उसका सही निर्धारण किया जा करवाया जा सके।

2 वरिष्ठता का आधार—कुछ निर्देशक सिद्धांत—वरिष्ठता के निर्धारण और पदोन्नति के प्रयोजन में वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिये किसी बाध्यकारी सिद्धान्त को आधार बनाना होता है। यह कार्य नियम बनाने वाले प्राधिकारी व विवेकाधिकार



का है।<sup>1</sup> किन्तु कोई आधारभूत सिद्धान्त बोधगम्य (intelligible) है या नहीं और उससे किसी वय के कमचारिया में भेदभाव किया गया है या नहीं?—इन प्रश्नों की सवीक्षा 'यायालय' कर सकता है। अतः नियमों में जो निर्देशक सिद्धान्त बताया गया है, उसी के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जावेगी। नियम विरुद्ध बनाई गई वरिष्ठता सूची अवैध होगी।<sup>2</sup> नियम जहाँ शान्त हो वहाँ प्रशासनिक निर्देशों के द्वारा वरिष्ठता के मापदण्ड निर्धारित किये जा सकते हैं जो बोधगम्य हों।<sup>3</sup> साधारणतया सेवा प्रवेश (joining) से वरिष्ठता गिनी जावेगी।<sup>4</sup>

3 वरिष्ठता का आधार एवं नियमावली विभिन्न नियमावलियों में वरिष्ठ के निर्धारण के लिये जो आधार बताये गये हैं, वे इस प्रकार हैं—

(i) अधीनस्थ कार्यालय नियमावली के नियम 27 में तथा

(ii) सचिवालय नियमावली के नियम 29 में—

(क) दि 15 11 76 तक—“अधिष्ठायी नियुक्ति की प्राप्ति के

दिनांक से”

(ख) दि 15 11-76 के बाद—“अधिष्ठायी नियुक्ति के वय से”

(iii) चतुर्थश्रेणी सेवा के लिये नियम 19 में—“अधिष्ठायी नियुक्ति के वय से”

(iv) अधीनस्थ 'यायालय नियमावली के नियम 21 के अनुसार—“अधिष्ठायी नियुक्ति के वय से”

(v) पचायत समिति जि० प० सेवा नियमावली के नियम 24 के अनुसार—“अधिष्ठायी नियुक्ति के वय से”

“अधिष्ठायी नियुक्ति (अधिष्ठायी) नियुक्ति की प्राप्ति के दिनांक से।

इस प्रकार वरिष्ठता को 'पुष्टीकरण' (वनफरमेशन) पर आधारित किया गया है, जिसके द्वारा नियुक्ति को अधिष्ठायी किया जाता है। 'अधिष्ठायी नियुक्ति' की परिभाषा का विवेचन अध्याय (1) में और 'पुष्टीकरण या स्थायीकरण' का विवेचन अध्याय (5) में किया गया है। स्थायीकरण की प्राप्ति की निर्धारित शर्तों का विवेचन हमने पीछे अध्याय (5) में किया है। पुष्टीकरण या अधिष्ठायी नियुक्ति की प्राप्ति के दिनांक से वरिष्ठता की गणना करना अवैध है। इसी लिये नियमों में दि 15-11-76 को संशोधन करना पड़ा, परन्तु तारांकित (क) नियमों

1 उच्च 'यायालय' बनाम 'अमलकुमार राय' AIR 1962 SC 1704

2 भारतसभ बनाम 'प्रभावतकर' AIR 1973 SC 2102 = 1973 SCC (L & S) 374

3 तेजंदर सिंह साधू बनाम 'पंजाब राज्य' 1975 Lab IC 203

4 एच पी मूद व 'पंजाब राज्य' 1970 SLR 483

म अभी तक यह सशोधन नहीं किया गया है अतः इन नियमों को उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित निर्णय के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।

4 उच्चतम न्यायालय का प्रमुख निर्णय—<sup>1</sup>पुष्टीकरण सरकारी सेवा की एक निम्नोच्च अनिवार्यता मात्र, जो वरिष्ठता का एकमात्र आधार नहीं हो सकती—

“ इस (नियम के) खण्ड में यह टुटि है कि—वह जेष्ठता के मूल्यवान अधिकार को केवल मात्र पुष्टीकरण की घटना पर ही निर्भर कर देता है। यह बात सविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधीन अनुपेक्ष्य है और इसलिए हमें नियम 8 (iii) को इस आधार पर अभिव्यक्ति करना होगा कि—वह प्रसवधानिक है। (पैरा 43, पृ 647)

हम यह आशा करते हैं कि—सरकार इस आधारभूत सिद्धान्त को ध्यान में रखेगी कि—

(1) यदि किसी कांडर (सबग) में स्थायी और अस्थायी दोनों कमचारी हैं तो पुष्टीकरण की घटना सीधी भर्ती किये गये और प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच जेष्ठता अवधारित करने के लिये बोधगम्य कसौटी नहीं हो सकती है।

(2) जब विभिन्न स्रोतों से भरती किये गये व्यक्ति एक ही कांडर के हो वे एक जैसे कार्य करते हो और उनके एक जैसे ही उत्तरदायित्व हो तब उनके बीच जेष्ठता के नियम अवधारित करते समय अन्य बातों के समान होने पर किसी अनाकस्मिक रीति में निरन्तर स्थानापन्न कार्य करने का सम्यक् रूप से मायना दी जानी चाहिए।<sup>2</sup> (पैरा 51, पृ 652)

5 “अधिष्ठायी (स्थायी) नियुक्ति या पुष्टीकरण का वय” — इस शब्दावली का अर्थ कुछ कठिन है। इस बारे में “अधिष्ठायी नियुक्ति कब से मानी जाय ?” — इस प्रश्न पर मतभेद है। पीछे अध्याय (5) में प्रश्न (3) के उत्तर में हमने इसका विवरण किया है।

जब नियुक्ति प्राधिकारी पुष्टीकरण की आशा जारी करता है, तो वह उसमें पुष्टीकरण के दिनांक और वय का उल्लेख करता है। उसी “वय” को आधार मानकर वरिष्ठता सूची तैयार की जावगी। पुष्टीकरण की पुरानी आशाओं को विलम्ब हो जाने के कारण अब चुनौती नहीं दी जा सकती और उनके आधार पर ही वरिष्ठता सूची बनी होगी। जहां वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, वहां वरिष्ठता और पुष्टीकरण दोनों को चुनौती दी जा सकती है। इसके लिये अपील-अधिकरण के द्वार खुले हैं।

<sup>1</sup> एस बी पटवदन बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) 3 उम नि प 609 = 1977 Lab IC 1367 (SC) = 1977 SLWR 254 = (1977)2 SLR 235 = (1977)3 SCC 399 = 1977 SCC(Lab) 391 1977 SLJ 457 = AIR 1977 SC 2051

6 वरिष्ठता निर्धारण के लिये सरकारी निर्देश—सामान्यतया किसी भी सेवा या सवग में वरिष्ठता “स्थायी नियुक्ति की दिनांक” से निर्धारित की जाती है, परन्तु जब विभिन्न अधिकारियाँ द्वारा नियुक्त सेवाओं को एकीकृत किया जाय, तो स्थायी नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता निर्धारण करने से कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिये ऐसी मामलों में स्थायी नियुक्ति की दिनांक का ध्यान रख बिना ‘निरन्तर स्थानापन्न (कार्यवाहक) नियुक्ति की दिनांक’ से निर्धारित का जा सकता है, परन्तु शत यह है कि इस प्रकार की स्थानापन्न नियुक्ति विशेष अवसर या तथ्य या अत्यावश्यक अस्थायी रूप में न हो और कमचारी की भार से ऐसी कमी न हो कि—नियुक्ति आशा देने पर भी उसने कार्यभार ग्रहण नहीं किया हो। उपराल मिटान्त के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता, जो सेवा या सक्ति या जिले के लिये निर्धारित की गई हो, अप्रभावित रहेगी।

7 वरिष्ठता निर्धारण के लिये अन्य नियमों के उपबन्ध—  
जिन नियमों पर भी ध्यान देना आवश्यक है—

(1) राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कामियों का आमेसन) नियम 1969 के अनुसार अधिशेष (सरप्लस) हुए कमचारियों को जब किसी दूसरे विभाग की सेवा में आमलित किया जाता है, तो उनकी वरिष्ठता का निर्धारण उपरोक्त नियमों के नियम 15 के अनुसार किया जावेगा और फिर उन्हें सम्बन्धित वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

(2) राजस्थान सिविल सेवा (अस्थायी कमचारियों की अधिष्ठायी नियुक्ति तथा वरिष्ठता निर्धारण नियम 1972 के अनुसार 14 1964 से पूर्व के तथा 14 1964 से 1-4-1968 तक के समस्त अस्थायी कमचारियों को दि 14 9 1972 से स्थायी कर दिया गया। उनकी वरिष्ठता का निर्धारण उपराल नियमों के नियम 5 के अनुसार किया जावेगा।

(देखिये—परिशिष्ट—1)

8 स्थानांतर और वरिष्ठता निर्धारण—(1) नियमों के प्रसंग—स्थानांतर द्वारा नियुक्ति के जो उपबन्ध नियमों में किये गये हैं उनका विवरण इस प्रकार है—

(देखिये—परिशिष्ट—2)

(क) सचिवालय नियमावली के नियम 5 के परतुक (8) के अनुसार आवश्यक शर्तों के अधीन सचिवालय के बाहर से किसी कमचारी को स्थानांतर द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। उसकी वरिष्ठता नियुक्ति आशा में वसित शर्तों से निश्चित की जावेगी।

वि स एफ 7 (7) वि वि/धे 2/स्टोर/72 दि 25 12 73,  
देखिये—‘संज्ञाविन—जनवरी 74—प० 240 तथा फरवरी 1979  
प० 125

(ग) अधीनस्थ कार्यालय नियमावली के नियम 6 के परतुक के अधीन एक जजशिप से दूसरी जजशिप में स्थानान्तर किया जा सकता है पर उसकी वरिष्ठता के बारे में ये नियम शान्त हैं।

(ग) अधीनस्थ कार्यालय नियमावली के नियम 7 के परतुक (1) व अधीन स्थानान्तर द्वारा भर्ती का प्रावधान है तथा आगे नियम 26 (2) में पदोन्नति प्रभावित होने वाले मामलों में स्थानान्तर द्वारा नियुक्ति करने पर रोक व शर्तें लगाई गई हैं। ऐसे मामलों में वरिष्ठता निर्धारण के लिये नियम 27 के परतुक (viii) व (ix) में तथा नियम 27-क में कुछ प्रावधान दिये गये हैं, जो परिपूर्ण नहीं हैं।

(घ) राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद सेवा नियम में—नियम 6 (ग) में स्थानान्तर (तबादला) द्वारा भर्ती करने का प्रावधान है और भाग (4) में नियम 22क, 22ख, 22 ग, 22 घ, 22ग में स्थानान्तर सम्बन्धी बातें दी गई हैं। वरिष्ठता निर्धारण के लिये नियम 24 के परतुक (iii) में 'अधिष्ठायी (मूल) सेवा की निरन्तर अवधि' को आधार बताया गया है।

(ङ) अतुल्य श्रेणी सेवा नियमावली में नियम 6 (ख) में स्थानान्तर द्वारा भर्ती का प्रावधान है, परतु उसकी वरिष्ठता निर्धारण के बारे में ये नियम शान्त हैं।

(॥) एक जिलाधीन कार्यालय से दूसरे में स्थानान्तर—वरिष्ठता निर्धारण के लिये निर्देश—(अब नियम 27-क देखिये)

1 स्थायी/अस्थायी वरिष्ठ या वरिष्ठ लिपिक का स्थानान्तर जनहित में या अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही एक जिलाधीन कार्यालय से दूसरे में किया जाना चाहिये। ऐसे स्थानान्तर के मामले में वह अपना पदाधिकार (लिपन) अपने मूल विभाग में ही धारण करेगा।

2 ऐसा स्थानान्तर तीन बय से अधिक की अवधि के लिये नहीं होगा।

3 ऐसे कर्मचारी का नाम मूल विभाग द्वारा प्रकाशित वरिष्ठता-सूची में ही रहेगा।

4 वह स्थायी करण पदोन्नति या पदावनति के लिये अपने मूल विभाग के सफर के अनुसार ही विचारार्थ लिया जायगा।

5 यदि वह अपने मूल विभाग में वापिस आना चाहता है, तो उसकी पिछले विभाग की सेवा में नये विभाग में मान्य नहीं होगी। उनको ऐसा विकल्प नये जिलाधीन कार्यालय में स्थानान्तरित होते ही या पदान्ति/स्थायीकरण के प्रश्न उठते ही देना चाहिये।

(iii) कुछ महत्वपूर्ण नियम—

जब एक वरिष्ठ लिपिक का स्थानान्तर एक जिलाधीन कार्यालय से दूसरे जिलाधीन कार्यालय में बिना उसकी सहमति या प्रायना के किया जाता है, तो

अभिनिर्धारित किया गया कि—इस प्रकार स्थानान्तरित वरिष्ठ लिपिक को अपनी वरिष्ठता तथा पदाधिकार (सियन) दोनों में से एक जिलाधीन कार्यालय में रखने का विकल्प देने का अधिकार है।

[अपील सं 22/76 रामस्वरूप शर्मा व राज्य 30-11-76]

स्थायी वरिष्ठ लिपिक वर्गीय सेवा के नियम 27 के परंतुक (ix)—  
जाने पर उसकी वरिष्ठता उस विभाग के स्थायी वरिष्ठ लिपिकों में तय की जा  
चाहिय थी। अन्तिम वरिष्ठता में परिवर्तन करने से पहले 'कारण-बताया-नादिस  
देना आवश्यक है।

[याल कृष्ण ठाका बनाम राज्य 1978 R L T 74]

(iv) स्थानान्तरण पर वरिष्ठता का निर्धारण—एक उदाहरण—

एक वरिष्ठ लिपिक की विभाग A में नियुक्ति दिनांक—7 9 65—है, उसने  
2-8 66 को अपनी इच्छा से विभाग B में स्थानान्तरण करा लिया। वहाँ स्थायीकरण  
के बाद उसका नाम वरिष्ठता सूची में क्र. सं 60 पर रखा गया। इसका बाद फिर  
उसने दिनांक 16 1-76 को अपनी इच्छा से स्थानान्तरण विभाग C में करा लिया।

ऐसी स्थिति में अब उसकी वरिष्ठता का निर्धारण एक समस्या बन गई।  
उसने विभाग A में लगभग 11 माह का सेवानुभव लोया। अब उसका विभाग C में  
स्थानान्तरण होने पर उसका पदाधिकार उसके मूल विभाग B में ही रहेगा। (रा. से  
नि. 16 (ख) के अधीन) तथा वरिष्ठता भी उसी विभाग B में रहेगी। नये विभाग  
C में उसकी वरिष्ठता के लिए उसे लिखित में विकल्प देना होगा। इसी प्रकार यदि  
स्थानान्तरण उसकी स्वयं की इच्छा और प्राप्ति पर (On own request) नहीं  
होकर प्रशासनिक कारणों से होता है तो भी उसका पदाधिकार विभाग B में रहेगा  
और उसे उस विभाग में वापस जाना पड़ेगा।

9 पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारण के मापदण्ड—जब दो या अधिक  
कर्मचारियों की अधिष्ठायी नियुक्ति का रूप एक हो या जब एक प्रवर्ग के कर्मचारियों  
का दूसरे प्रवर्ग में आमलन (absorption) या एकीकरण किया जाय तो उन के  
बीच आपस में जो तुलनात्मक वरिष्ठता निर्धारित की जाती है, उसे 'पारस्परिक  
वरिष्ठता' (Seniority inter se) कहते हैं। ऐसी स्थिति में 'पारस्परिक  
स्थान' देने के लिए कुछ मापदण्ड अपनाये जाते हैं जिनका विवरण आपको सम्बन्धित  
नियमों में मिलेगा जिन्हें प्रसंग नीचे दिये जा रहे हैं। कृपया सम्बन्धित नियमावली में  
देखिये—(i) अधीनस्थ कार्यालय नियमावली के नियम 27 के नीचे अलग अलग पदों  
पर स्थितियों का बरण करते हुए 'परंतुक' में वरिष्ठता निश्चित करने के  
मापदण्ड दिए गये हैं। (ii) सचिवालय नियमावली के नियम 29 के नीचे भी इसी  
कारण कुल 12 परंतुक हैं। (iii) अधीनस्थ 'यायालय नियमावली के नियम 21  
'पिछनी निम्न श्रेणी' के पारस्परिक स्थान को पारस्परिक वरिष्ठता का आधार

बनाया गया है। (iv) पचासत समिति नियमावली के नियम 24 के नीचे चार परतुक् इमीप्रवार दिय गये हैं और (v) चतुथ श्रेणी नियमावली के नियम 19 के नीचे पांच परतुक् हैं।

10 वरिष्ठता सूची तयार करना—सरकार का निर्देश है कि—“प्रत्येक विभाग में वरिष्ठता सूची किसी भी सेवा में सबग व निर्धारित होते ही तथा पदों पर नियमित चयन के पश्चात् बनाई जाकर प्रकाशित कर दी जानी चाहिये, ताकि सबग अपनी सही स्थिति या बोध हो। ऐसा ध्यान में रखा जाना है कि—वरिष्ठता-सूचियां वरिष्ठता निर्धारण का सिद्धान्त बताये बिना ही अनन्तिम रूप से प्रकाशित कर दी जाती हैं, जिससे कमचारी अपनी स्थिति के बारे में असमाधान करने में असमर्थ रहता है। इसीलिए ऐसे मामलों में “दूसरे पक्ष का सुनो” के सिद्धान्त का अनुसरण करना चाहिए।” इस निर्देश पर बार बार जार दिया गया है।

एक सुझाव—वरिष्ठता सूची बनाने के लिए एक फाम में आवश्यक व्यक्तिगत माँके स्वयं कमचारी से भरवाने चाहिए और उसकी कोई व्याख्या या समस्या हो, उसे भी प्रकट करा लेना चाहिए। इसके बाद कार्यालय रिकार्ड के आधार पर उस फाम की जाँच कर सही माँके तैयार कर लेने चाहिए। पहले अधिष्ठायी नियुक्ति के वष के आधार पर सूचियां बनाकर उनकी पारस्परिक वरिष्ठता का क्रम बना लेना चाहिए। अन्त में अस्थायी/तदर्थ/स्थानापन्न की वरिष्ठता सूची अलग से बनानी चाहिए। अस्थायी/तदर्थ/स्थानापन्न व्यक्तियों के नाम पिछली निम्न श्रेणी की अधिष्ठायी वरिष्ठता सूची में भी रहेंगे। इसके बाद वरिष्ठता निर्धारण करने के अनुरोध पर सिद्धान्तों व आधारों को स्पष्ट बताते हुए ‘अनन्तिम (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची’ निकालनी चाहिये और उस पर निश्चित अवधि में आये एतराजों की व्यक्तिगत सुनवाई के बाद ही “अन्तिम वरिष्ठता सूची” प्रकाशित करनी चाहिए।

### 11 कुछ महत्वपूर्ण नियम—

(क) वरिष्ठता निर्धारण के सिद्धान्त—सेवा में वरिष्ठता (जेष्ठता) सम्बन्धी नियम न होने पर सेवा में कार्यभार सम्भालने की तारीख से जेष्ठता अवधारित की जायेगी।<sup>1</sup>

एक समान श्रेणी (ग्रेड) या सबग (कैडर) से सम्बन्धित कमचारियों की एक समान वरिष्ठता सूची बनाई जा सकती है। यदि दो अलग श्रेणियों की एक समान सबग में आगे पदोन्नति के लिये भी एक सूची बनाई जाय, तो नीचे के सबग में की गई सेवा को एक नियम के रूप में उच्च सबग में की गई सेवा के रूप में उच्च सबग में की गई सेवा के समान नहीं माना जा सकता। अतः जब श्रेणी II के कमचारी श्रेणी I में पदोन्नति के लिये पात्र थे, तो उनकी श्रेणी II में की गई सेवा की सम्बन्धी अवधि को श्रेणी I व II की एक समान वरिष्ठता सूची बनाने के लिए

१ वि स एफ 1 (5) App'ts (A-II) 72 दिनांक 7 6 72

(देखिये लेखाविज्ञ 1979 पृ० 124-125)

1 डॉ० हरकिशनसिंह बनाम पंजाब राज्य (1971) 2 उम वि प 906

ध्यान में रखा जाना प्रवण होगा। वसने बनाय श्रेणी II से श्रेणी I में जाने के बाद श्रेणी I की वरिष्ठता को भ्रमणी पदोन्नति के समय देखा जाना चाहिये था तथा श्रेणी II की वरिष्ठता श्रेणी I के नीचे रहनी चाहिए थी।<sup>12</sup>

(ग) पूर्व पद या प्रवण की सेवा नहीं गिनी जावेगी—राजस्थान व स जिन प सेवा नियम क नियम 24 के अनुसार वनिष्ठ लिपिक तथा ग्राममवक अलग अलग प्रवण हैं। अतः वनिष्ठ लिपिक के रूप में की गई सेवा ग्रामसेवक के रूप में वरिष्ठता के लिये विचारणीय नहीं हो सकती।<sup>13</sup>

(घ) वरिष्ठता सूची तथा अधिष्ठायी नियुक्ति में सम्बंध—केवल वरिष्ठता सूची में नाम आ जाने से किसी अध्यापिका की नियुक्ति अधिष्ठायी नहीं हो जाती, जब तक कि यह वह प्रदक्षित न कर कि उसकी नियुक्ति राज पचायत समिति जिन प सेवा नियम के नियम 15 से 19 के अनुसार, प्रायोग द्वारा चयन के बाद की गई थी। सीपी प्रती से अधिष्ठायी नियुक्ति के लिये यह पट्टी आवश्यकता है।<sup>14</sup>

(ङ) विलम्ब (देरी) का दुष्प्रभाव—जब रिट ग्रहण नहीं की जाती—1952 में बनाये जेठना (सीनियोरिटी) व नियम के अनुसार की गई प्राप्तिथियों व विरुद्ध 1967 में रिट कराना विलम्ब के कारण वजित है। अब जिनकी सेवायें पुष्ट कर दी जा चुकी हैं उनकी सेवाओं में कोई हेरफेर करने के लिये मूल अधिकारों की मांग प्रति विलम्ब से किये जाने के कारण अभाव है।<sup>15</sup>

(च) वरिष्ठता के सिद्धान्त—वरिष्ठता का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि—जो व्यक्ति पूर्ववर्ती वर्गों में नियुक्त किये गये हैं, वे पश्चातवर्ती वर्गों में नियुक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे।<sup>16</sup>

सेवा मामलों में यह एक सुस्थापित सिद्धान्त है कि—अधिष्ठायी नियुक्ति वाला व्यक्ति उन सब लोगों से निश्चयपूर्वक वरिष्ठ होगा जो परीक्षा पर नियुक्त किये गये हैं।<sup>17</sup>

जब किसी एक पद पर पदोन्नति के लिये अलग अलग प्रवण के लोगों को अवसर दिया जाता है अर्थात् जब पदोन्नति का क्षेत्र कई प्रवर्गों में (चनल्स) से हो,

- 2 एम गुरुशास्त्रिणा बनाम निदेशक 1978 Lab I C 150
- 3 किशनपुरी बनाम राज्य 1977 WLN (UC) 100
- 4 सरजूदेवी बनाम विवास अधिकारी, 1974 WLN (UC) 144
- 5 रवीन्द्रनाथ बोस बनाम भारतसर्व (1970) 3 जम नि प 910= AIR 1970SC 470
- 6 अपील सा 598/77 सुरेश चन्द्र घटनागर दि 26 6 78
- 7 हरिहर श्याम बनाम राज्य (1978 RLT 10)





अध्याप

7

# पदोन्नति PROMOTION

—माप दण्ड, पाठ्यता एवं तरीकें

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1 स्वयं के भद्र       | अनुक्रम                     |
| 2 मापदण्ड (कसौटी) —   | 4 पाठ्यता द्वारा प्रमाणांतर |
| (क) निपटारा का विशेषण | 5 पदोन्नति का तरीका         |
| (ख) बरिष्ठता-मह-सोपना | 6 पदोन्नति के विशेष नियम    |
| 3 पाठ्यता की शर्तें   | 7 निमज्जन/विभागीय जीव में   |
|                       | 8 द्वारा महत्वपूर्ण नियम    |

## नियमावली-प्रस्ताव

	अधीनस्थ		अधीनस्थ	वर्षावत	कुल
	कायस्थ	सविद्यालय	न्यायालय	समिति	धरोती
	A	B	C	D	E
1 पदोन्नति में भारी	7(ग)	5(ग)	6(ग)	6(ग)	1
2 रित्तिया का विनिश्चय	9	8	X	X	
3 मापदण्ड (कसौटी)	26 घ (5)	26(5)	13(2)	20	17
4 पाठ्यता की शर्तें	15, 26 ग 26घ	24, 24घ 26(3)	13	20	17 176
5 पदोन्नति का तरीका—	26घ, 26घ, 26घ	25 26 26घ	X	—	17
6 अस्थाई पदोन्नति—	26(3)(4)	28, 28घ	X	23	18

1 पदोन्नति का स्वरूप व भेद—पदोन्नति सेवा में एक महत्वपूर्ण कार्य बाही है, जिसके लिये विचार किया जाना सविधान के अनुच्छेद 16 के अधीन एक मूल अधिकार माना गया है। पदोन्नति दो प्रकार की हो सकती है—(1) नियमित, जो विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन करने पर दी जाती है, और (2) अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के रूप में स्थापनापत्र पदोन्नति, जिसका विवेचन पीछे

अध्याय (4) में किया जा चुका है। हम यहाँ नियमित पदोन्नति का विवेचन करेंगे।

### ❧ (क) नियमों का विश्लेषण

2 मापदण्ड या कसौटी—(Criterion)—पदोन्नति के लिये मापदण्ड “वरिष्ठता सह योग्यता” (Seniority—cum—Merit) को माना गया है। अधीनस्थ कार्यालय नियमावली का नियम 26-घ तथा सचिवालय-नियमावली का नियम 26, जो विज्ञप्ति स एफ 7 (10) DOP (A-II) 77 G S R 93 दिनांक 7 मार्च 1978 द्वारा परिवर्तित किया गया, पुराने सभी मापदण्डों को निरस्त कर उपनियम (5) में अधीनस्थ सेवाओं तथा लिपिक वर्गीय सेवाओं के समस्त पदों के लिये “वरिष्ठता-सह योग्यता” को आधार बताता है। इससे पहले “मेरिट फॉर्मूला” लागू था, जो अब इन सेवाओं के लिए समाप्त कर दिया गया है। यह नया नियम विज्ञप्ति में दी गई अनुसूचियों के अनुसार 77+10=87 सेवाओं पर लागू कर दिया गया है। जो अध्यारोही (Overriding) प्रभाव से इसके पहले के सब मापदण्ड व तरीकों को, जो इस नियम के विपरीत हों, निरस्त करते हुये लागू किया गया है। अतः हमने आगे केवल उन्हीं बातों का विवेचन किया है, जो इस नियम के अनुसार नियमित हैं। [कृपया पूरा नियम पीछे पृष्ठ 61 से 66 पर पढ़िये तथा पुनर्गठन नियम भी पृष्ठ 67 से 71 पर देखिये]

अधीनस्थ कार्यालय नियमावली के नियम 13(2) में “वरिष्ठता के अनुसार दसता के अध्यधीन रहते हुए” पदोन्नति करने का उपबन्ध है। आगे टिप्पणी में इसका स्पष्टीकरण किया गया है, परन्तु पदोन्नति देने के तरीके का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। -

पञ्चायत समिति अि प सेवा नियमावली के नियम 20 में चयन के लिये कसौटी “सीनियोरिटी एव योग्यता” बतलाई गई है।

चतुर्थ श्रेणी सेवा नियमावली के नियम 17 में भी वरिष्ठता-सह-योग्यता से पदोन्नति करने की कसौटी निर्धारित की गई है।

इस प्रकार “वरिष्ठता-सह योग्यता” के मापदण्ड में वरिष्ठता को प्रधानता दी गई है, जिसके साथ योग्यता (मेरिट) होना आवश्यक है, जो पुराने अभिलेख पर आधारित उपयुक्तता है। यहाँ ‘मेरिट’ का प्रयोग तुलनात्मक न हो कर योगात्मक है।

### (ख) “वरिष्ठता-सह-योग्यता” का मापदण्ड—(महत्वपूर्ण निणय)

“वरिष्ठता सह उपयुक्तता” (Seniority—cum—fitness) के आधार पर वरिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नति मिलेगी, यदि वह अनुपयुक्त (unfit) नहीं है। इस

❧ ‘पदोन्नति’ पर विस्तृत कानूनी विवेचन के लिये पुस्तक “सेवा सम्बन्धी मामले एव अपील ट्रिब्यूनल कानून” का अध्याय (2) अवश्य पढ़िये।

प्रकार उपयुक्त होन पर वरिष्ठ को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता ।<sup>1</sup>

“वरिष्ठता-सह योग्यता” के आधार पर वरिष्ठ व्यक्ति जो योग्यता सहित हो, चयनित किया जावेगा, चाहे उससे वरिष्ठ व्यक्तियों की योग्यता उससे तुलना में अच्छी क्यों न हो ।<sup>2</sup> “योग्यता सह-वरिष्ठता” के आधार पर सबसे अधिक योग्यता वाला या सर्वश्रेष्ठ योग्यता वाला व्यक्ति ही चयनित किया जा सकेगा ।<sup>3</sup>

जब नियमों के अधीन ‘जेष्ठता एवं योग्यता’ के आधार पर ही उच्चतर पद के लिये पदोन्नति का उपबन्ध हो, तो जेष्ठ कर्मचारी को उच्चतर पद के लिये योग्यता होने या न होने का विचार किये बिना कनिष्ठ कर्मचारी की प्राप्ति कर देना उचित नहीं है ।<sup>3</sup>

पदोन्नति में प्रतिष्ठान कब हो सकता है ?—जब नियमानुसार एक कनिष्ठ लिपिक के पद से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर की जाती है, तो एक वरिष्ठ व्यक्ति को केवल तभी प्रतिष्ठित किया जा सकता है, जब वह ऐसी पदोन्नति के लिये कार्य और सेवाभिज्ञता के आधार पर अनुपयुक्त पाया गया हो ।<sup>4</sup>

### 3 पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें—

पदोन्नति के लिये पात्रता की निम्न शर्तें हैं—(1) अधिष्ठायी नियुक्ति—जिसे पदोन्नति देनी है, वह अपने पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त तथा स्थायी हो । परन्तु ऐसे स्थायी व्यक्ति के न मिलने पर “स्थानापन्न” व्यक्ति को स्थानापन्न आधार पर पदोन्नति का पान सम्भव जावेगा ।

[देखिये अधीनस्थ कार्यालय नियमों का नियम 26 ब का उपनियम (3), जो नियम 26 ख (3) के समान है । सचिवालय नियमावली का नियम 26 (3) तथा नियम 24 क । चतुर्थ श्रेणी सेवा का नियम 17 क]

2 “यूनतम योग्यता एवं अनुभव — यह पदोन्नति की पात्रता की दूसरी शर्त है, जिसका विवरण इस प्रकार है—

ॐ(क) अधीनस्थ कार्यालय नियमावली में—

(1) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों का 10% पदोन्नति के लिये आरक्षित किया गया है, (देखिये—नियम 7 का परतुक (3) पृष्ठ 18 पर)

- 1 हरिदत्त बनाम हिमाचल प्रदेश 1974 (1) SLR 208 (Para 13), मैसूर राज्य बनाम सैयद महमूद 1968 SLR 411
- 2 शादीलाल बनाम हि कमि 1974 (1) SLR 217 (P.H)
- 3 मैसूर राज्य बनाम सैयद महमूद (1968) 1 उम नि ५ 955 = AIR 1968 SC 1113
- 4 श्रीमती प्रवाशवती बनाम राज्य 1978 RLT 128

(2) आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी तथा कनिष्ठ लिपिक को छोड़कर अन्य सभी पद पट्टेनति या चयन द्वारा भरे जावेंगे (देखिये नियम 7 तथा 6 पृष्ठ 12-13 पर)

(3) पट्टेनति सम्बन्धी शर्तों के लिये नियम 15 में विभिन्न वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति की शर्तें दी गई हैं उनके नियम 7 के सम्बन्धित परन्तुको के साथ साथ पढ़ना चाहिये। इनकी प्रसंग तालिका इस प्रकार है—

(1) आशुलिपिक/निजीसहायक सवर्ग के लिये—

नियम 7(घ)—परन्तुक 7, 8 (पीछे पृष्ठ 19 से 22 तक)

नियम 15—उपनियम 7, 8 आशुलिपिक प्रथम श्रेणी (पृ 41 42)

उपनियम 11 निजी सहायक के लिये (पृ 43)

(ii) वरिष्ठ लिपिक के पद पर—नियम 7 (ग) 100% पट्टेनति द्वारा, सीमित प्रतियोगिता समाप्त कर दी गई। परन्तुक (2) का (ii) (पृष्ठ 16-17 पर)। नियम 1<sup>ए</sup> (1) (पृष्ठ 37 पर) देखिये

(iii) कार्यालय सहायक—नियम 15 (4-क) पृष्ठ 38 पर देखिये।

(iv) कार्यालय-अधीक्षक—द्वितीय श्रेणी के लिये नियम 15 (5) तथा 15 (5क) (पृष्ठ 39) पर देखिये। प्रथम श्रेणी के लिये नियम 15 (6) तथा 15 (6-क) पृष्ठ 40 41 पर देखिये।

[ कृपया अन्य वरिष्ठ पदों की शर्तों के लिये नियम 7 तथा नियम 15 पढ़िये ]

§(ख) सचिवालय नियमावली में—नियम 24 तथा अनुसूची I के स्तम्भ 6 में पट्टेनति के लिये महत्तामा एवं अनुभव का विवरण (देखिये पृष्ठ 141-145) दिया गया है।

(ग) अधीनस्थ न्यायालय निष्ठावली में—नियम 13 में कुछ शर्तें अनुभव के बारे में दी गई हैं किन्तु विस्तृत शर्तों का इन नियमों में अभाव है।

(घ) पचासत समिति सेवा नियमावली में—सलमन अनुसूची में पट्टेनति के लिये महत्तायें व अनुभव का विवरण दिया गया है। (देखिये पृष्ठ 189)

§(ङ) चतुर्थ श्रेणी सेवा नियमों की अनुसूची में भी इसी प्रकार महत्तायें व अनुभव दिया गया है। (देखिये पृ० 207)

उपरोक्त तारांकित (§§) नियमों में जहां अनुभव की अवधि स्पष्ट नहीं बताई गयी है वहां पांच वर्ष की अवधि नियम 26 घ (5) = 26 (5) के अनुसार पाछित होगी और 5 वर्ष के अनुभव की व्यक्तियों के न मिलने पर परन्तुक के आधार पर कम वर्षों के अनुभव वाले पात्र व्यक्तियों पर विचार किया जा सकेगा।

“सेवा या अनुभव” की मगणना के लिये इसकी परिभाषा के अनुसार विचार किया जायेगा।

[कृपया अध्याय (1) में पृष्ठ 219 पर देखिये]

(2) चक्रीय क्रम का निर्धारण—यदि नियमों के अनुसार या अनुसूची के अनुसार पदोन्नति में कोई कौटा (Quota) यानी निश्चित संख्या का प्रतिशत दिया हुआ है, तो उसका अनुसार चक्रीय—क्रम (Rotation) बनायेगा, ताकि पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की तालिका तैयार की जा सके। चयनित व्यक्तियों को इसी क्रम से पदोन्नत करना होगा।

(3) भारसूचक का रोटेशन—अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये निश्चित प्रतिशत के आधार पर रोटेशन रजिस्टर तैयार कर उनके भारसूचित पदों को पदोन्नति से भरने की कार्यवाही करेगा।

(4) पात्र व्यक्तियों का विचार क्षेत्र—यदि पदोन्नति के लिये 5 पद तक रिक्त हैं, तो चार गुनी संख्या में, 10 पद तक रिक्त हैं तो 3 गुनी संख्या में, (पर कम से कम 20), तथा 10 से अधिक पद भरने हों तो दो गुनी संख्या (पर कम से कम 30) में पात्र व्यक्तियों की सूची बनाई जावेगी, जिस पर विचार किया जा सकेगा।

(5) समिति का गठन—विभागीय-पदोन्नति—समिति का गठन अधीनस्थ कार्यालयों के लिये नियम 26 ग (2) के अनुसार तथा सचिवालय के लिये नियम 25 ब 26 के अनुसार किया जावेगा। जो क्रमशः नियम 26 ग = 25 के अनुसार पात्र व्यक्तियों की सूची पर विचार करेगी। वरिष्ठ लिपिकों के बार में क्रमशः नियम 26 ड = 26 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। किन्तु अधीनस्थ कार्यालय नियम 7 (ग) को—दिनांक 16-1-1978 से प्रतिस्थापित कर प्रतियोगी परीक्षा समाप्त कर देने से उपरोक्त नियम 26 ड निष्प्रभावी हो जाता है, जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है।

(6) समिति द्वारा चयन—उपनियम (11) के अनुसार समिति निम्न कार्य करेगी—

- (i) समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों पर, जो नियमानुसार पात्र एवं अर्हति हैं, समिति पदोन्नति के लिये विचार करेगी। वार्षिक गुप्त प्रतिवेदन तथा व्यक्तिगत पत्रिकाएँ देखी जावेंगी।
- (ii) रिक्तियों के लिये निश्चित संख्या में चयनित व्यक्तियों की एक 'चयन सूची' बनायेगी।
- (iii) उपरोक्त संख्या के 50% के बराबर संख्या की एक अलग चयन सूची भी बनायेगी, जिसको अस्थायी या स्थानापन्न रूप से भरने का काम में लिया जा सकेगा, जब तक कि समिति की अगली बैठक न हो जाय।
- (iv) ऐसी सूची को वरिष्ठता के क्रम में तैयार किया जावेगा और नियुक्ति-प्राधिकारी को भेजा जावेगा।

(7) आयोग से परामर्श—उपनियम (12) व (13) के अनुसार जहाँ आवश्यक हो, आयोग का परामर्श लिया जावेगा।

(8) नियुक्तियाँ—उपनियम (14) के अनुसार इस प्रकार बनी “अन्तिम चयन सूची” में से उसी क्रम में नियुक्ति—प्राधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की आजायें जारी करेगा, जब तक कि—वे सूचियाँ पूरी न हो जाय, या दुबारा समिति द्वारा पुनरावलोकित या संशोधित न कर दी जावे।

(9) निलम्बन एवं विभागीय जाच के अधीन कर्मचारियों के बारे में उपनियम (15) के अनुसार सरकार निर्देश जारी करेगी, जो आगे विवचना के खण्ड (7) में पृष्ठ 274 पर दिये जा रहे हैं।

(10) अध्यारोही प्रभाव—इस नियम के प्रावधान ही लागू होंगे और अन्य नियमों के प्रावधान जो इनके विपरीत हैं, लागू नहीं होंगे। यह इस नियम की विशेषता है।

उपरोक्त प्रक्रिया का वर्णन अधीनस्थ कार्यालय तथा सचिवालय की लिपिक वर्गीय सेवाओं के दृष्टिकोण से किया गया है, यद्यपि अन्य सेवाओं के लिये भी यह नियम समान है फिर भी सम्पूर्ण उपबन्ध यहाँ ऊपर नहीं बताये गये हैं। अतः मूल नियम (पृ० 61) पर पढ़ना उचित होगा।

पचायत समिति जि प सेवा नियमों में चयन की प्रक्रिया नियम 21 व 22 में स्पष्ट दी गई है। (कृपया पृष्ठ 175 पर देखिये)।

## 6 पूर्ववर्ती वर्षों के रिक्त पदों पर पदोन्नति के विशेष नियम

“राजस्थान सेवाओं (पूर्ववर्ती वर्षों की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति द्वारा भर्तों) नियम 1972—” (देखिये—परिशिष्ट-3)

1972 के इन नियमों का मुख्य उद्देश्य उस कठिनाई को दूर करना था, जो पदोन्नति के कोटा के रिक्त स्थानों की सीधी भर्तों के रिक्त स्थानों के विरुद्ध समय पर नहीं भरने से उत्पन्न हुई थी। अतः 1972 में पहले इनके प्रभावी (लागू) होने को किसी भी नियमन के सिद्धान्त द्वारा मना नहीं किया जा सकता। यदि 1972 से पूर्व के रिक्त स्थानों पर विचार नहीं किया जाता है, तो ये नियम बेकार हो जाते हैं।

अतः इनको पूर्वकालिक प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक है।<sup>1</sup>

जब प्रधानाध्यापकों के पदों पर तदर्थ नियुक्तियाँ की गईं और कोई अविष्टायी नियुक्तियाँ नहीं की गईं, न सीधी भर्तों ही की गईं। ऐसी स्थिति में प्रतिवय रिक्त स्थान तय नहीं करने से प्राप्ति का कोई हानि नहीं हुई, न वरिष्ठता में हानि हुई। तब नियम लागू नहीं होंगे।<sup>2</sup>

1 धपिलत स 29 & 30/78 सुखबीरसिंह 1978 R L T 59

2 माधुराम बनाम राज्य 1977 W L N (U C) 323

(2) चण्डीय क्रम का निर्धारण—यदि नियमों के अनुसार या अनुसूची के अनुसार पदोन्नति में कोई कौटा (Quota) यानी निश्चित सत्या का प्रतिशत दिया हुआ है, तो उसका अनुसार चण्डीय—क्रम (Rotation) उनायेगा, ताकि पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की तालिका तैयार की जा सके। चयनित व्यक्तियों को इसी क्रम से पदोन्नत करना होगा।

(3) आरक्षण का रोस्टर—अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये निश्चित प्रतिशत के आधार पर रोस्टर रजिस्टर तैयार कर उनके आरक्षित पदों को पदान्ति से भरने की कार्यवाही करेगा।

[देखिये पीछे अध्याय (3) तथा नियम 8 पृष्ठ 25 पर तथा नियम 6 पृष्ठ 116 पर] (4) पात्र व्यक्तियों का विचार क्षेत्र—यदि पदोन्नति के लिये 5 पद तक रिक्त हों, तो चार गुनी सत्या में 10 पद तक रिक्त हों तो 3 गुनी सत्या में, (पर कम से कम 20), तथा 10 से अधिक पद भरने हों तो दो गुनी सत्या (पर कम से कम 30) में पात्र व्यक्तियों की सूची बनाई जावेगी, जिस पर विचार किया जा सकेगा।

(5) समिति का गठन—विभागीय—पदोन्नति—समिति का गठन अधीनस्थ कार्यालयों के लिये नियम 26 ग (2) के अनुसार तथा सचिवालय के लिये नियम 25 व 26 के अनुसार किया जावेगा। जो क्रमशः नियम 26 ग = 25 के अनुसार पात्र व्यक्तियों की सूची पर विचार करेगी। वरिष्ठ लिपिकों के बार में क्रमशः नियम 26 ड = 26 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। किन्तु अधीनस्थ कार्यालय नियम 7 (ग) को दिनांक 16-1-1978 से प्रतिस्थापित कर प्रतियोगी परीक्षा समाप्त कर देने से उपरोक्त नियम 26 ड निष्प्रभावी हो जाता है, जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है।

(6) समिति द्वारा चयन—उपनियम (11) के अनुसार समिति निम्न कार्यवाही करेगी—

- (i) समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों पर, -जो नियमानुसार पात्र एवं अर्हति हैं समिति पदोन्नति के लिये विचार करेगी। वार्षिक गुप्त प्रतिवेदन तथा व्यक्तिगत पत्रिकाएँ देखी जावेंगी।
- (ii) रिक्तियाँ के लिये निश्चित सत्या में चयनित व्यक्तियों की एक चयन सूची बनायेगी।
- (iii) उपरोक्त सत्या के 50% के बराबर सत्या की एक अलग चयन सूची भी बनायेगी, जिसको अस्थायी या स्थानापन्न रूप से भरने का काम में लिया जा सकेगा जब तक कि समिति की अगली बैठक न हो जाय।
- (iv) ऐसी सूची को वरिष्ठता के क्रम में तैयार किया जावेगा और नियुक्ति-प्राधिकारी को भेजा जावेगा।

(7) आयोग से परामर्श—उपनियम (12) व (13) के अनुसार जहाँ आवश्यक हो, आयोग का परामर्श लिया जावेगा।

(8) नियुक्तियाँ—उपनियम (14) के अनुसार इस प्रकार बनी “अन्तिम चयन सूची” में से उसी क्रम में नियुक्ति—प्राधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जाना जारी करेगा, जब तक कि—वे सूचियाँ पूरी न हो जाय, या दुबारा समिति द्वारा पुनरावलोकित या संशोधित न कर दी जावे।

(9) निलम्बन एवं विभागीय जाँच के अधीन कर्मचारियों के बारे में उपनियम (15) के अनुसार सरकार निर्देश जारी करगी, जो आगे विधचना के खण्ड (7) में पृष्ठ 274 पर दिए जा रहे हैं।

(10) अध्यारोही प्रभाव—इस नियम के प्रावधान ही लागू होंगे और अन्य नियमों के प्रावधान जो इनके विपरीत हैं, लागू नहीं होंगे। यह इस नियम की विशेषता है।

उपरोक्त प्रक्रिया का बरताने अधीनस्थ कार्यालयों तथा सचिवालय की लिपिक वर्गीय सेवाओं के दृष्टिकोण से किया गया है, यद्यपि अन्य सेवाओं के लिये भी यह नियम समान है फिर भी सम्पूर्ण उपबन्ध यहाँ ऊपर नहीं बताये गये हैं। अतः मूल नियम (पृ० 61) पर पढ़ना उचित होगा।

पचायत समिति जिन्हीं सेवा नियमों में चयन की प्रक्रिया नियम 21 व 22 में स्पष्ट की गई है। (कृपया पृष्ठ 175 पर देखिये)।

## 6 पूर्ववर्ती वर्षों के रिक्त पदों पर पदोन्नति के विशेष नियम

“राजस्थान सेवाओं (पूर्ववर्ती वर्षों की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियम 1972—” (देखिये—परिशिष्ट-3)

1972 के इन नियमों का मुख्य उद्देश्य उस बठिनाई को दूर करना था, जो पदोन्नति के कोटा के रिक्त स्थानों की सीधी भर्ती के रिक्त स्थानों के विरुद्ध समय पर नहीं भरने से उत्पन्न हुई थी। अतः 1972 में पहले इनके प्रभावी (लागू) होने को किसी भी निवचन के सिद्धांत द्वारा मना नहीं किया जा सकता। यदि 1972 से पूर्व के रिक्त स्थानों पर विचार नहीं किया जाता है, तो ये नियम बेकार हो जाते हैं।

अतः इनको पूर्वकालिक प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक है।<sup>1</sup>

जब प्रधानाध्यापकों के पदों पर तदर्थ नियुक्तियाँ की गईं और कई अधिष्ठायी नियुक्तियाँ नहीं की गईं, न सीधी भर्ती ही की गई। ऐसी स्थिति में प्रतिवर्ष रिक्त स्थान तय नहीं करने से प्रार्थी को कोई हानि नहीं हुई, न वरिष्ठता में हानि हुई। ता ये नियम लागू नहीं होंगे।<sup>2</sup>

1 अपील नं० 29 & 30/78 सुखबीरसिंह 1978 R L T 59

2 मासुराम बनाम राज्य 1977 W L N (U C) 323



राज्य सरकार का भी निर्देश है कि—“पदोन्नति-समिति की बैठकें वित्तम स हान पर चलनित व्यक्तियों की प्रवर्तकों वरों की रिक्तियों के विपरीत नियुक्ति एवं परिष्कार दी जा सकती है। ऐसे मानने प्रवर्तकों वरों की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति नियम 1972 से शासित होंगे।”

7 नितम्बन/विभागीय जाच तथा पदोन्नति—राजस्थान सरकार ने इस विषय में निर्देश जारी किये हैं कि—“जो कनचारी नितम्बनाधीन न हो परन्तु उसके विरुद्ध सी सी ए नियम 16 के अधीन जाच चल रही हो, के मामल में ‘गुहा बन’ लिफाफा प्रणाली अपनायी चाहिये। किन्तु जहाँ यह समझा जाय कि धारण साधारण प्रकार के है, वहाँ प्रोविजनल पदोन्नति के लिये सिफारिश की जा सकती है। इसी प्रकार जिनके विरुद्ध सी सी ए नियम 17 में जाच चल रही हो, उनके लिये भी प्रोविजनल पदोन्नति की सिफारिश की जा सकती है। विभागीय-पदोन्नति-समिति जबित समझे, तो इसमें भी मुहरबन्द-लिफाफा प्रणाली अपनायी जा सकती है। नितम्बन से बहाल होने पर अनुभव के लिये विहित न्यूनतम सेवावधि में नितम्बन की अवधि को सम्मिलित कर लिया जावेगा।”

### 8 कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का सारांश—

समता का अधिकार (अनुच्छेद 14) पदोन्नति में लागू—सरकारी नौकरी में नियुक्ति के समय ध्यान में तथा बाद में सेवा के दोहरान भी समता का अधिकार प्राप्त है। चाहे सीपी भर्ती हो, या पदोन्नति द्वारा इसके लिये सरकार योग्य कर्मचारियों का समान मापदण्ड से विचार करेगी। सरकार को योग्यतायें निर्धारित करने का विगत विवेक प्राप्त है। भेदभाव करने वाली माय्यताया का न्यायालय निरस्त कर सकता है। अनुच्छेद 14 व 16 की मांग है कि—प्रत्येक योग्य व्यक्ति के मामले में समान सिद्धान्तों के आधार पर विचार किया जाय, इससे अधिक कुछ नहीं।<sup>3</sup>

पदोन्नति में मनमानी व अनुचित कार्यवाही सम्भव नहीं—पदोन्नति के लिए समान अवसर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 के अधीन प्रत्याभूत हुए अधिकार हैं, जिसे अबाधित तथा निरंकुश सरकारी कार्यवाही से हानि नहीं पहुँचानी जा सकती।

यह सुस्थापित है कि—प्रशासनिक कार्यवाहियों में भी सरकार प्रयुक्तित्व तरीके से या निरंकुश तरीके से कार्य नहीं कर सकती। विशेषतः जहाँ दूसरे कर्मचारियों के अधिकार भी प्रभावित होते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति को किसी कायुक्त के

- 3 वि स एफ/(7) नियु (क-2) 71 दि 7-1-72 (देखिये 'लेखाविज्ञ-मार्ग' 1972 पृष्ठ 12)
- 4 एफ 10 (1) कामिष (क-II) 75 दि 4 77], देखिये—लेखाविज्ञ-फरवरी 1977 पृष्ठ 44
- 5 हरपास सिंह बनाम केद्रासित चण्डीगढ़ 1978 Lab IC 121 (P&H) FB

अधीन विवेकाधिकार (डिसट्रिब्यूशन) सौंपा गया है, तो उसे अपने आपको कानून के अनुसार सही चलाना होगा। वह अयुक्तियुक्त या निरवश (मनमाने) तरीके से कार्य नहीं कर सकता।<sup>6</sup>

□ उच्च न्यायालय पदोन्नति के लिए स्पष्ट निर्देश दे सकता है—

न्यूनतम मत—सरकार द्वारा सविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन जारी किये गये कार्यकारी-निर्देश (executive instructions) सभी बंध होंगे, जब वे विधिक उपकरणों के अधीन होकर चलें, (न कि उनके विपरीत) (पैरा 22) ऐसे निर्देशों द्वारा उन बरिष्ठ लिपिकों के लिए एक विशेष-परख विहित करना, जिनको कनिष्ठ लिपिक नियुक्त करते समय 'न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं' से छूट दे दी गई थी, विभेदकारी है और सविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 का भंग करते हैं। (पैरा 24, 26)

जब पदोन्नति के लिए नियमों में विहित दोनों प्रकार के मापदण्ड यानी बरिष्ठता और उपयुक्तता मौजूद हैं, तो उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी को पदोन्नत करने के लिए स्पष्ट निर्देश (Positive direction) देना 'वायचित्त माना गया'।<sup>7</sup> (पैरा 30)

नियम 15 तथा 18 राज० अधीनस्थ० लिपिक० स्था० नियम-कार्यालय-अधीक्षक श्रेणी II के पद पर पदोन्नति के लिये पात्रता—

नियम 15 (5) के अनुसार दो प्रवर्गों के कर्मचारी इसके लिये पात्र हैं—(क) कार्यालय सहायक तथा (ख) आधुनिक श्रेणी III। इस पदोन्नति के लिये सूची (पनल) बनाने में सब पात्र व्यक्तियों को जो उपयुक्त पाये गये हों, सम्मिलित करना होगा।

जिलाधीश कार्यालय में कार्यालय-अधीक्षक श्रेणी II के लिये जिलाधीश नियुक्ति प्राधिकारी है, किंतु उसे राजस्व मण्डल द्वारा बनायी गयी सूची में से अभ्यर्थी का चयन करना होगा।<sup>8</sup>

विभागीय-पदोन्नति समिति द्वारा विचार करना—एक स्थापनापन बरिष्ठ लिपिक जो कि अधिष्ठायी कनिष्ठ लिपिक भी है, दूसरे कनिष्ठ लिपिकों के समान पदोन्नति के समय विचार करने योग्य है। उसका चयन इस कारण से अवधान नहीं हो जाता। जब पदोन्नति बरिष्ठता-सह-योग्यता पर आधारित हो, तो विभागीय-पदोन्नति समिति को मामले में उचित एवं निष्पक्ष तरीके से विचार करना चाहिये। ऐसे मामले में जहाँ यह पाया जाता है कि—समिति के सामने सम्पूर्ण तथा सही अभि-

6 अपील नं० 801/77 बैलाश चंद्र डी मायूर दि० 21-9-78

7 डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार पालघाट बनाम एम बी कोठ्याकुट्टी 1979 SLJ 278 (S C) = 1979 SCC (L&S) 126

8 चादमल जैन बनाम राज्य 1974 WLN 540 = 1974 RLW 393

लेख के धाकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये या समिति सही तथ्यों की वस्तुगन रूप से प्रशंसा नहीं कर सकी। इससे किया गया चयन दूषित हो गया और प्रभावित व्यक्ति पुनर्विचार के लिये पात्र हो गये। यदि वह उपयुक्त पाया जाता है, तो उसकी पदोन्नति हानी चाहिये।<sup>9</sup>

**पदोन्नति**—वरिष्ठ लिपिक के पद पर अपीलार्थी पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि वह दि. 21-2-75 की विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग द्वारा अनुपयुक्त पाया गया था। ऐवेल दो वर्ष पहले की वि. प. स. के विनिश्चय के आधार पर अपीलार्थी की पदोन्नति पर विचार नहीं करना उचित नहीं माना गया। 1978 RLT (iv) 33 का अनुसरण करते हुए अपीलार्थी की पदोन्नति के लिये विचार करने का निर्देश दिया गया।<sup>10</sup>

**गुटि (गलती) से की गई पदोन्नति**—प्राची की स्थानापन्न रूप से गुटि (गलती) से नियमों का भंग करने हुए पदोन्नति दे दी गई। बाद में अन्य व्यक्तियों के अभ्यावेदन पर तथा प्राची के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद उस आज्ञा को निरस्त कर दिया गया। अतिनिर्धारित कि—जब पदोन्नति की मूल आज्ञा ही अवैध थी, तो प्राची के प्रत्यावर्तन की वह कोई शिकायत नहीं कर सकता और सरकार को ऐसी गलती ठीक करने का अधिकार है। इस मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का हनन नहीं माना गया। ऐसे मामलों में सरकार न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक रूप में काम नहीं करती, परंतु उसे प्रशासनिक रूप में भी न्याय व निष्पक्षता से कार्य करना होगा, निरंकुशता व लापरवाही में नहीं।<sup>11</sup>

**पूर्वकालिक पदोन्नति और वेतन**—एक अधिकारी को पूर्वकालिक पदोन्नति देने के बाद सरकार उसे ऐसी पदोन्नति के लिये वेतन देने से इन्कार नहीं कर सकती जब कि इसके विपरीत किसी नियम का अभाव हो अर्थात्—(जब तक किसी नियम में स्पष्ट रूप से ऐसा वेतन नहीं देने का प्रावधान न हो, तो वेतन देना ही पड़गा) यह सुगतान करना पट्टक विभाग का कर्तव्य है।<sup>12</sup>

**पदोन्नति फव्वे से**—केवल माने की पदोन्नति ही पर्याप्त नहीं है, जब कि कमचारी का पदोन्नति का अधिकार उम्र दिनांक से है जिस दिन उसके कनिष्ठा की पदोन्नति किया गया, क्योंकि उसकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाने से उसके वेतनादि पर और उसकी सेवा पर बुरा प्रभाव पड़ता है।<sup>13</sup>

9 अपील नं. 6/78 केदार नाथ आदि दि. 30.8.78

10 मण्डल हाई बनाम राज्य (1978 RLT 44)

11 गुलाबचंद बनाम राजस्थान 1979 SCJ 163,

डॉ. पी. एस. गैलात बनाम राजस्थान 1977 WLN (UC) 384

12 राम चंद्र साखवा बनाम राज्य 1978 RLT 127

13 रमेश चंद्र बनाम राज्य (1978 RLT 86)

गुप्तप्रतिवेदन की प्रतिकूल प्रविष्टि की सूचना न देने का प्रभाव—

प्रतिकूल प्रविष्टि की सूचना न देने और उसे पदानति के समय में निराकरण के लिये विचार में लेने पर उस कर्मचारी के लिये 'याचपूरा तथा निष्पक्ष विचार नहीं किया गया। यह सविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। रिट याचिका स्वीकार कर प्रार्थी को वापस अपने पद पर लेने का आदेश दिया गया।<sup>14</sup>

अपीलार्थी को इसलिए पदानति नहीं दी गई कि—उसे विभागीय पदोनति समिति द्वारा उपयुक्त नहीं पाया गया, क्योंकि 1975-76 के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टियाँ थीं तथा उसे पदोनति के लिये अभी उपयुक्त (fit) नहीं माना गया था।

विभागीय पदोनति समिति ने केवल 1975-76 की रिपोर्ट को आधार बनाकर भूल की है, क्योंकि इसके पहले की रिपोर्टों में उसे पदोनति के लिये उपयुक्त बताया गया था। यदि वि.प.स. ने 1975-76 की रिपोर्ट को भी देख कर ध्यान दिया होता, तो स्पष्ट था कि—अपीलार्थी की दक्षता उसकी अस्वस्थता से क्षीण हुई थी न कि वह भ्रूत तथा आन्तरिक रूप से पदोनति के लिए उपयुक्त नहीं था। अतः वि.प.स. को कायवाही दूषित मानी गई और अपीलार्थी के मामले पर वि.प.स. द्वारा पुनः विचार करने का निर्देश दिया गया।<sup>15</sup>

ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टि को, जो एक कर्मचारी का समूचित नहीं की गई और उसे उसके विरुद्ध बचाव का कोई अवसर नहीं मिला, अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और विशेष रूप से तब जबकि उसका एक बार प्रयोग उसके प्रतिष्ठान के लिये किया जा चुका है और जब ऐसी प्रविष्टि स्थायी तथा निरूप्य प्रकार की न हो। इस सीमा तब अपीलार्थी पर निष्पक्ष विचार किया जाना चाहिये था। केवल विभागीय जांच विचारधीन है—यह अपीलार्थी की वरिष्ठता के बावजूद उसे अस्वीकार करने के लिये सुसंगत नहीं है।<sup>16</sup>

यह एक सुस्थापित कानून है कि—किसी को भी केवल सदेह के कारण दण्डित नहीं किया जायगा। जब प्रतिकूल प्रविष्टि केवल लगभग एक माह पहले समूचित की गई और उसके विरुद्ध अभ्यावेदन विचाराधीन था, तो प्राधिकारी को चाहिये था कि—या तो पहले उस अभ्यावेदन पर निराकरण देता, या उस पर निराकरण देन तक के लिये चयन को स्थगित कर देता।<sup>17</sup>

वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (CR) में दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टियाँ के विरुद्ध राज-यान सिविल सेवा अपील अधिकरण के समक्ष अपील की जा सकती है।<sup>18</sup>

14 नरेश्वर जोशी बनाम राजस्थान राज्य 1971 RLW 140, आनंद स्वरूप भटनागर बनाम राजस्थान राज्य 1965 RLW 272

15 केदार प्रसाद शर्मा बनाम राज्य 1978 RLT 170

16 अपील स. 562/77 भारतभूषण शर्मा दि. 15.9.1978

17 सतलाल अग्रवाल बनाम राज्य (1978 RLT 31)

18 एल.एन. अजमेरी बनाम वाणिज्यिक कर विभाग (1979 RLT 28)

जब वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में दी गई प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर अपीलार्थी का स्थायीकरण (क्वॉरमेंटेशन) रोक गया और उसे पदोन्नति नहीं दी गई, परंतु जब वे प्रतिकूल प्रविष्टियां बाद में हटा दी गईं, तो अपीलार्थी के स्थायीकरण तथा पदोन्नति पर पुन विचार करना होगा और उसे उसी दिनांक से लाभ मिलेगा, जब कि उसके कनिष्ठ को पदोन्नति दी गयी थी।<sup>19</sup>

वरिष्ठ लिपिबद्ध के पद पर पदोन्नति—वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन अनिश्चित और सदृश्य प्रकार की प्रविष्टियों का ऐसा बरा प्रभाव नहीं होता कि—अपीलार्थी को पदोन्नति में अतिष्ठित वर दिया जाय। केवल संदेह के कारण किसी को दण्डित नहीं किया जा सकता। केवल शिकायतें थी जो बिना साबित किये इक्षतरफा कथन थीं, उनको विचार में लेकर बिना उचित जांच किये अपीलार्थी को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। बाद में प्रतिकूल-प्रविष्टि को हलका कर दिया गया। सरकार के परिपत्र दि 10 9 73 के अनुसार अपीलार्थी का मामला उचित पाया गया।<sup>20</sup>

**सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र रोकना अवैध—**

यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि—नैसर्गिक याय के सिद्धान्तों के अनुसार, गोपनीय पत्रिका में दी गई प्रतिकूल रिपोर्ट पदोन्नति के अवसरों से मना करने के लिये जब तक उपयोग में नहीं लाई जा सकती, तब तक कि वह सम्बंधित व्यक्ति को समूचित न कर दी जाय ताकि वह अपना वाय व आचरण सुधार सके या उस बारे में परिस्थितियों को स्पष्ट कर सके। ऐसा अवसर कोई निरी अपेक्षाकारिता नहीं है, इसका प्राशिक उद्देश्य यह भी है कि उच्च प्राधिकारी को सम्बंधित व्यक्ति द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद यह विनिश्चित करना है कि—क्या वह प्रतिकूल रिपोर्ट 'यायोचित' है। दुर्भाग्य से, एक कारण या दूसरे कारण से, जो प्रार्थी के दोष के कारण उत्पन्न नहीं हुए पर सरकार उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार न कर सकी और न यह तय कर सकी कि क्या वह रिपोर्ट 'यायोचित' थी। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी को सत्य निष्ठा प्रमाणपत्र नहीं देने की वायवाही का समर्थन करना कठिन है।<sup>21</sup>

19 : जयन्त प्रकाश बनाम राज्य 1979 RLT 58

20 : सतलाल अग्रवाल बनाम राज्य (1978 RLT 31)

सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र रोकना अवैध—

21 : गुरदपाल सिंह पिज्जी बनाम पंजाब शासन 1979 SLJ 299 SC  
(Para 16)

अनुक्रम

- 1 दक्षताबरी पार करने की कसौटी
- 2 अधिशेष कमचारी घामेलन नियम  
बुद्ध महत्त्वपूर्ण नियम व निर्देश

1 दक्षताबरी (E B) पार करने की कसौटी—

सन् 1969 के पहले वेतनमान के बीच "दक्षताबरी" एक अडचन के रूप में लागू होती थी और दक्षताबरी को पार करने की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी तभी देता था, जब वह इस नियम में वर्णित शर्तें पूरी कर लेता था—अर्थात्—

(i) नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उसका कार्य सतोषप्रद हो, और

(ii) उस कमचारी की सत्य निष्ठा सदेह से परे हो।

इसके लिये उसका सेवाभिलेख व वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पर विचार कर नियुक्त होना होता है।

दक्षताबरी को 1969 के वेतनमान नियमों में हटा दिया गया है और 1976 के पुनरीक्षित नवीन वेतनमान में भी दक्षताबरी नहीं है। अतः कानून की दृष्टि से कोई दक्षताबरी अब नहीं है। राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 30 में भी दक्षताबरी का प्रावधान है। कृपया देखिये।

यह सक्षम प्राधिकारी का विवेकाधिकार है कि—वह दक्षताबरी पार करने के लिये किसी कमचारी को अनुमति दे या नहीं, किन्तु यह विवेकाधिकार मनमाने या निरंकुश तरीके से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। जहाँ वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनो में प्रतिकूल प्रविष्टियों को कमचारी को समुचित नहीं किया गया, जिससे अपीलार्थी के मामले में "यायसंगत" एवं सही विचार नहीं हो सका। अतः विवेकाधिकार का प्रयोग दूषित हो गया। फिर प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता प्राधिकारी ने प्रतिवेदनकर्त्ता प्राधिकारी की अभ्युक्तियों को अपास्त भी कर दिया तो अपीलार्थी को दक्षताबरी पार करने की अनुमति न देने की आशा भी दूषित मानी गई।<sup>1</sup>

अपीलार्थी को दि 23 12 1960 को दक्षताबरी पार नहीं करने दिया गया। इसके बाद उसका वेतन सशोधित वेतनमान नियमों में सशोधित कर दिया

गया। संशोधित दतनमान में कोई दक्षतावरी नहीं थी। फिर भी उसे वाणिज्य वेतन वृद्धि का तो ही गई क्योंकि वित्त विभाग ने एक परिपत्र के अनुसार उसे दक्षतावरी पार कर। दो अनुमति नहीं दी गई थी, जबकि सवा नियम तथा दतनमान नियमों काई दक्षतावरी नहीं थी। अग्निनियमित वि— वित्त विभाग का परिपत्र केवल स्पष्टीकरण मात्र है और वह विधिविनियमों के उपबन्धों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और वित्तविभाग के इस परिपत्र द्वारा अस्वाभाविक या वातपनिक रूप से दक्षतावरी नहीं लगाई जा सकती।<sup>2</sup>

## 2 अधिशेष (सरप्लस) कर्मचारी आमेसन नियम

### कुछ महत्वपूर्ण नियम—

राजस्थान सरकार ने 1969 में पदों की कटौती के मित-ययता के कारण अधिशेष घोषित किये गए कर्मचारियों को सरकारों सेवा में समायाहित करने के लिये एक नियमावली बनाई थी, जो आगे परिशिष्ट (1) में दी गई है। इस नियमावली में सम्प्रतिष्ठ कुछ महत्वपूर्ण नियमों का सारांश यहां दिया जा रहा है, जो उपयोगी होगा।

राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कर्मिकों का आमेसन) नियम 1969 (1) नियम 22 के अनुसार आमलित कर्मचारी को विभागीय परीक्षा तीन अवसरों में उत्तीर्ण करने पर ही स्थायीकरण करने का उपबन्ध है। उसके द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता पर वह अधिशेष कर्मचारी रह जाता है, जिसे पोटिस देकर हटाने का सरकार को अधिकार है। जब प्राप्ति को जो समय दिया गया उसमें 1970-1971 तथा 1972 में लगातार परीक्षाएँ हुईं और वह उनमें नहीं बठा। अब उसे पांच वर्ष बाद परीक्षा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है और उसकी सेवाएँ समाप्त करना या से नि 23—क के अनुसार उचित माना गया।<sup>3</sup>

(2) किसी अधिशेष कर्मचारी को किसी विभाग में समालीकृत पद या अथ पद पर आमेलित करने की अन्तिम शक्तियाँ 'आमेसन समिति' में निहित हैं। यदि एक कर्मचारी जो स्थायी पद के विरुद्ध अधिष्ठायी नियुक्ति धारण करता है और यदि आमेसनवर्ती विभाग में कोई अधिष्ठायी स्थायी पद रिक्त न हो तब आमलित कर्मचारी का पदाधिकार रखने के लिये एक अधिसूचक पद का भूजन करना होगा। प्राप्ति के मामले में इन नियमों का हनन हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि प्राप्ति का समान पद पर आमेलित नहीं किया गया, जबकि उसी विभाग में रिक्त स्थान उपलब्ध था।<sup>4</sup>

(3) नियम 2 तथा 15 (2) सांख्यिकी सेवा के एक अस्थायी कर्मचारी और एक अस्थायी अधिशेष कर्मचारी जिसे इस विभाग में आमेलित दिया गया— इन

2 अपील सं 229/78 हरिराम दि 31 8 1978

3 [विजये ड सिंह और बनाम राज्य 1977 W L N 610]

4 चन्दनमह बनाम राजस्थान राज्य 1977 W L N (UC) 331]

दोनों की पारस्परिक वरिष्ठता नियम 15 (2) आमेसन नियम से शासित होगी, न कि राजस्थान साख्यकी सेवा के नियम 31 के परतुक से।<sup>5</sup>

नियम 3 (क)—सरकार द्वारा सगणक के पद का विज्ञापन निकाला गया। प्रार्थीको चयन समिति में स्वयंनित किया तथा सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति अस्थायी आधार पर है, न कि तदर्थ आधार पर।<sup>6</sup>

नियम 11 तथा 111 दोनों भ्रमण के सुनिश्चित हैं। एक अधिशेष कमचारी को किसी विशिष्ट पद पर आमेलित किये जाने का कोई अधिकार नहीं है, किन्तु आमेलन-समिति का नियुक्त अन्तिम है।<sup>7</sup>

- 4 "तदर्थ" एवं "अस्थायी" नियुक्तियों में अन्तर के लिये देखिये—  
"जे एन कृष्णदत्त बनाम राज्य 1975 W, L N, 472"]

आमेसन तथा वेतन स्थिरीकरण—

जब किसी पद की समाप्ति पर एक कमचारी को दूसरी सेवा या रावग में आमेलित किया जाता है और जब आज्ञा स्पष्ट रूप से आमेलन का उल्लेख करती है, तो उस कमचारी को एक अधिशेष आमेलित कमचारी माना जावेगा। किन्हीं सेवा नियमों के अधीन एक रावग से दूसरे रावग में आमेलन आमतो पदोन्नति है और न विशेष चयन। अतः उसका वेतन राजस्थान सेवा नियम 26 (1) में स्थिर होना चाहिये।<sup>8</sup>

आमेसन नियमों का नियम 15 (2)-(1) बताता है कि—अग्रिष्ठायी अधिशेष कमचारियों की वरिष्ठता नये विभाग के अग्रिष्ठायी कमचारियों में नियत की जावेगी और ऐसे सब कमचारी उस विभाग के सब अस्थायी/स्थानापन्न कमचारियों से वरिष्ठ होंगे।<sup>9</sup>

जब एक बार कोई व्यक्ति अधिशेष हो जाता है, तो यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह उसे समुचित रूप से आमेलित करे। अपीलार्थी अग्रिष्ठायी होने से अधिशेष होने पर दूसरे विभाग में भी अग्रिष्ठायी हो पाये। (नियम 7 (1) (a))

- 5 हिरोबदलानी बनाम राजस्थान राज्य 1974 R L W 442  
1974 W L N 673 [1975] 1 S L R 748]

- 6 अपील सं 119/1976 राभावतार मुस्ता दि 7-10-1977

- 7 सक्षेमसिंह सोलंकी बनाम राज्य (1978 F L R 157) दि 17-11-78

- 8 अपील सं 200/78 श्यामलाल काकाणी दि 28-9-1978



## राजस्थान सरकार के निदेश

अधिशेष घोषित कमचारियों का भूतलसी प्रभाव से स्थायीकरण मूल विभाग द्वारा नये विभाग को सम्मति से किया जाना चाहिये। ऐसा स्थायीकरण बहुत ही समुचित मामलों में किया जाना चाहिये।

[वि. स एफ 4 (37) नियु (क-5) 72 दि 8-5-72]

अधिशेष (सरप्लस) कमचारियों का समायोजन निम्न पदों पर होने पर समान पदों पर किये जाने के लिये पुन विचार किया जा सकता है।

[वि स F 5 (6) DOP/A-II/78 दिनांक-13-8-78]

## दो अभूतपूर्व पुस्तकें—

वत्स

- ☐ अनुशासनिक कार्यवाही

[ भारत सरकार से पुरस्कृत ]

[हिन्दी में अनुशासन सम्बन्धी नियमों (CCA Rules) पर विस्तृत विवेचन]

1979 पूरा परिवादित संस्करण मूल्य 70/-

- ☐ सेवा सम्बन्धी मामले एवं अपील ट्रिब्यूनल कानून—

करिष्ठता • पदोन्नति • पुष्टीकरण • वेतनभत्ते • अनिवार्य

सेवा नियुक्ति • प्रत्यावेतन • वेतन आदि विषयों तथा

अपील अधिकरण कानून पर एकमात्र हिन्दी पुस्तक

मात्र ही खरोदिये।

मूल्य 25/-

[ इस पुस्तक के प्रकाशक के यहाँ मिलती है ]

राजस्थान लिपिकवर्गीय एवं  
चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम

वत्त श्री जैन

नियमावली--खण्ड

परिशिष्ट

[ तात्तिका पीछे देखिये ]

परिशिष्ट में—

[पृष्ठ संख्या 1 से पुन आरंभ होती है]

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कर्मियों का आभेसन) नियम  
Rajasthan Civil Services (Absorption of Surplus  
Employees) Rules, 1969 1-26
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (अस्थायी कर्मचारियों की अधिष्ठायी नियुक्ति  
तथा वरिष्ठता निर्धारण) नियम 1972  
(Rajasthan Civil Services (Substantive Appointment  
of Temporary Employees) Rules 1972) 26-31
- 3 राजस्थान सेवामें (पूववर्ती-वर्षों की रिक्तियों के विरुद्ध-यहोन्नति  
द्वारा भर्ती) नियम 1972  
(Rajasthan Services (Recruitment by Promotion  
against vacancies of Earlier years) Rules, 1972 32-34
- 4 राजस्थान सिविल सेवा (सरकार द्वारा अधिग्रहित निजी संस्थानों  
तथा अन्य स्थापनों के कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा  
की शर्तें) नियम 1977  
(Rajasthan Civil Services (Appointment and Other  
Service Conditions of Employees of Private Institu-  
tion and Other Establishment taken Over by the  
Government) Rules 1977 34-37
- 5 राजस्थान शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों (विश्लामों) का  
नियोजन नियम 1976  
(Rajasthan Employment of the Physically Handi-  
capped Rules 1976) 37-44
- 6 राजस्थान (सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर सरकारी कर्मचारियों  
के आश्रितों की भर्ती) नियम 1975  
(Rajasthan Recruitment of Dependants of Govt  
Servants dying while in Service Rules 1975 44-48
- 7 राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा के सदस्यों  
पर आश्रितों की भर्ती नियम 1978 49-53
- 8 राजस्थान सिविल सेवा (CCA) नियमों की अनुसूचियाँ—  
अनुसूची (3) लिपिक वर्गों/सेवामें 53  
अनुसूची (4) चतुर्थ श्रेणी सेवामें 55

# राजस्थान सिविल सेवा

(अधिशेष कार्मिकों का आभेलन)

नियम 1969 <sup>1</sup>

[RAJASTHAN CIVIL SERVICES (ABSORPTION  
OF SURPLUS PERSONNEL) RULES 1969]

## प्राधिकृत पाठ

भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल अधिशेष कार्मिकों की आभेलन द्वारा सिविल सेवाओं तथा राज्य के कायकलाप सम्बन्धी पदा पर भर्ती को और उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

## राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कार्मिकों का आभेलन) नियम 1969

1 सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ — (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कार्मिकों का आभेलन) नियम 1969 है

(2) ये 1 जनवरी, 1954 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2 व्याप्ति तथा लागू होना — विभिन्न सेवाओं में या राज्य के कायकलाप सम्बन्धी पदा पर व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त विही सेवा नियमों या आदेशों में किसी बात के होते हुए भी अधिशेष कार्मिक रिक्त पदा के उपलब्ध होने के अध्याधीन रहते हुए, इन नियमों के अनुसार आभेलन द्वारा ऐसी सेवा में या पदों पर भर्ती और नियुक्ति के पात्र होंगे —

- 1 वि स एफ 1 (18) नियुक्ति/क-2/67 दिनांक 27 नवम्बर 1969 द्वारा राजस्थान-राजपत्र, साधारण, भाग 4 (ग) दिनांक 11.12.1969 में प्रथम बार प्रकाशित।
- 2 जी एस आर 187 दिनांक 8 दिसम्बर 1976 द्वारा राजस्थान राजपत्र, 4 (ग) I दिनांक 8 दिसम्बर, 1976, पृष्ठ 569-591 पर प्राधिकृत हिन्दी पाठ प्रकाशित।

परतु —

- (1) इन नियमों की कोई भी बात, अखिल भारतीय सेवाओं, राजस्थान उच्चतर याचिक सेवा, राजस्थान याचिक सेवा, राजस्थान सचिवालय सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा राजस्थान लेखा सेवा तथा राजस्थान तहसीलदार सेवा में सर्वगति पक्षों पर लागू नहीं होगी
- (ii) इन नियमों की कोई भी बात उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी, जो डाइरेक्टोरेट ऑफ इकानोमिक्स एण्ड इण्डस्ट्रीयल सर्वे में उस विभाग के उत्पादन से पूर्व सार्विकों के पद धारण कर रहे थे तथा जिनको अधिशेष करार किये जाने के पश्चात् राजस्थान स्टेटिस्टिकल सर्विसेज क्लेम, 1971 के नियम 24 के अन्तर्गत सेवा में भर्ती के लिये उपयुक्त पाये जाने पर आर्थिक एवं सार्विकों निदेशालय से सार्विकों सहायका के रूप में आमंत्रित कर लिया गया था।

3 परिभाषाएँ —जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में —

- (क) 'तदर्थ नियुक्ति' से सुसंगत सेवा नियमों अथवा सरकार के किसी भी आदेशों के अधीन उपबधित भर्ती के किसी भी तरीके से, जहाँ कोई सेवा नियम विद्यमान न हो और यदि पद आयोग के क्षेत्र में आता है तो आयोग की सिफारिश से अन्यथा, चयन बिना की गई अभ्यर्थियों की अस्थायी नियुक्ति अभिप्रेत है,
- (ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से किसी पद विशेष पर लागू राज्य के सेवा नियम द्वारा यथा परिभाषित नियुक्ति प्राधिकारी तथा जहाँ इस प्रकार परिभाषित न किया गया हो, वहाँ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अधीन) नियम, 1958 द्वारा यथा परिभाषित या गठित नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है,
- (ग) "समिति" से इन नियमों के नियम 5 के अधीन सरकार द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है,
- (घ) "आयोग" से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है,
- (ङ) "विभागीय परीक्षा" से राजस्थान सिविल सेवाओं (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 के उपबधों के अधीन आयोजित विभागीय परीक्षा अभिप्रेत है,
- (च) 'समानित पद' से वह पद अभिप्रेत है जिसको समिति ने अधिशेष कार्मिक द्वारा उत्तमके अधिशेष घोषित किये जाने के तुरन्त पूर्व धारित पद से समानित घोषित किया हो,
- (छ) 'समतुल्य पद' से ऐसा पद अभिप्रेत है जिसका वर्तमान समरूप हो तथा जिसमें एक ही प्रकार के कर्तव्य और दायित्व अंतर्बलित हो
- (ज) "सरकार" तथा "राज्य" से क्रमशः राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य अभिप्रेत है,

- (भ) "नवीन पद" में ऐसा पद अभिप्रेत है जिस पर अधिशेष कमचारी इन नियमों के अधीन आमेसन द्वारा नियुक्त किया गया हो,
- (ज) "पूर्व पद" से वह पद अभिप्रेत है जिसे अधिशेष कमचारी उसको अधिशेष घोषित किये जाने की तारीख को स्थायी स्थानापन्न, अस्थायी या तदर्थ रूप से धारित किये हुए था,
- (झ) नियमित रूप से नियुक्त किया गया 'यकिन' से यदि पद आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं तो आयोग की सिफारिश पर नियुक्त किये गये व्यक्ति तथा किसी पद पर या सेवा में भर्ती के लिये अधिकृत प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये गये व्यक्ति, यथास्थिति अभिप्रेत हैं, कि तु 'समे' ऐसी कोई तदर्थ या प्रतिप्रावश्यक अस्थायी नियुक्ति या स्थानापन्न नियुक्ति, जो विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के अधीन हो सम्मिलित नहीं है,
- (ट) 'अनुसूची' से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है,
- (ठ) अधिशेष कार्मिक या 'अधिशेष कमचारी' से ऐसे सरकारी कमचारी अभिप्रेत हैं जिन पर राजस्थान सेवा नियम, 1951 लागू होते हैं तथा जो निम्नलिखित के उपाय या प्रशासनिक आचारों के कारण पदा में की गयी कमी या कार्यालयों की समाप्ति के फलस्वरूप सरकार के किसी विशेष विभाग की आवश्यकता की दृष्टि से अधिशेष कर दिया जान पर सरकार द्वारा या सरकार के निर्देश के अधीन नियुक्ति अधिकारी द्वारा अधिशेष घोषित कर दिये गये हों लेकिन जिनके मामलों में सरकार ने उनकी सेवाओं का समाप्त न कर उन्हें सेवा में अथवा पदा पर आमेसन द्वारा प्रतिधारित करने का विनिश्चय किया है
- 'परंतु याता भर्ती के सामान्य तरीकों के अपवाद के रूप में या सेवा के प्रारम्भिक गठन के रूप में स्त्रीनिग द्वारा उपयुक्तता विनिर्णित करने के लिये विभिन्न सेवा नियमों के अधीन नियुक्त की गयी समिति यदि कोई भी कमचारी, जो उस पद पर तीन वर्ष से अधिक सेवा कर चुका है जिसके लिये उसको स्वीकृत किया जाना है, उपयुक्त विनिर्णित नहीं किया जाता है और यदि तत्पश्चात् निचले पद पर नियुक्त किये जाने का अधिकारी भी नहीं है तो आमेसन समिति द्वारा उसे दिये जाने वाले निचले पद के लिये अनुग्रहपूर्वक सिफारिश कर सकेगी और इसके पश्चात् ऐसा कमचारी इन नियमों के उपबन्धों के अधीन अधिशेष कमचारी के रूप में समझा जायगा तथा ऐसा व्यक्ति समिति की सिफारिश पर उसके द्वारा अधिकृत शर्तों के अधीन रहते हुए निचले पद पर आमलित किया जा सकेगा।'
- (ड) "अस्थायी नियुक्ति" से तदर्थ नियुक्ति को छोड़कर अस्थायी अथवा स्थायी पद पर की गयी अस्थायी नियुक्ति अभिप्रेत है,
- (ढ) "रिक्त पद" से सरकार के अधीन ऐसा पद अभिप्रेत है जो किसी सरकारी कमचारी द्वारा अधिष्ठायी रूप से धारित नहीं हो।

4 निर्वाचन—जब तक सदस्य से श्रवण अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम स 8) इन नियमों के निवचन के लिए, उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निवचन के लिये लागू होता है।

5 समिति का गठन—अधिशेष कार्मिक के आमेलन हेतु सरकार एक आदेश द्वारा, कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक 5 सदस्यों की, जैसा भी ठीक समझे, एक आमेलन समिति का गठन करेगी।

परंतु सरकार, जैसा भी ठीक समझे, समय समय पर आदेश द्वारा, समिति का पुनर्गठन कर सकेगी या इसके समस्त श्रवण किन्हीं सदस्यों की बदल सकेगी।

6 समानित पदों की घोषणा—समिति यदि ठीक समझे, नियम 7 के प्रयोजनों के लिये किसी पद श्रवण पदों के वर्ग को, ऐसे पद या पदों के वर्ग से संबंधित कर्तव्यों का स्वरूप, ग्रहणार्थ तथा वेतनमानों को दृष्टि में रखते हुए, उस पद के समानित घोषित कर सकेगी जिसे अधिशेष कर्मचारी ने उसको अधिशेष घोषित किये जाने से ठीक पूर्व धारित कर रखा था।

7 आमेलन की प्रक्रिया—(1) समिति अधिशेष कार्मिकों को, उन विभागों श्रवण सेवाओं को आवंटित करेगी जहाँ समानित, समतुल्य श्रवण नीचे का एक या अधिक रिक्त पद नियुक्ति के लिये उपलब्ध हो तथा ऐसे रिक्त पद या पदों को भी विनिर्दिष्ट करेगी जिन पर अधिशेष कर्मचारी का आमेलित किया जाना है। समिति से अधिशेष कार्मिकों के आवंटन के आदेश प्राप्त होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, नियुक्ति के लिये आदेश जारी करेगा। उक्त पद श्रवण पदों पर ऐसी नियुक्ति अधिष्ठायी, स्थापना, प्रस्थापी या तदर्थ रूप में, जैसा कि नीचे बताया गया है, होगी—

क अधिशेष घोषित किये जाने के दिनांक को उसके द्वारा धारित पद का स्वरूप	अधिशेष घोषित किये जाने के दिनांक को उसके द्वारा धारित नियुक्ति का स्वरूप	आमेलन के पश्चात् दिये जाने वाली नियुक्ति का स्वरूप
--	--	--

1

2

3

4

(क) स्थायी

अधिष्ठायी

(क) स्थायी पद पर अधिष्ठायी पद स्पष्टतः रिक्त हो/यदि पद स्पष्टतः रिक्त नहीं है श्रवण यदि उस पर दूसरे व्यक्ति का धारणाधिकार है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव भेजने पर सरकार आमेलित कर्मचारी को उस पर धारणाधिकार उपलब्ध

1	2	3	4
			कराने के लिये अधिसरय पद का सृजन करेगी ।
(ख) निचला स्थायी पद अधिष्ठायी लेकिन उच्च- जो सतत विद्यमान तर पद पर जिससे वह है । अधिशेष घोषित किया गया है स्थानापन्न हो ।	(ख) नये पद पर स्थानापन्न, जबकि विभाग मे जिसमे से वह अधि- घोषित किया गया था, निचले स्थायी पद पर धारणाधिकार रखता हो ।		
(ग) निचला स्थाई निचले स्थायी पद पर पद जो उच्चतर अधिष्ठायी लेकिन पद के साथ- उच्चतर पद पर समाप्त हो चुका स्थानापन्न हो । है ।	(ग) नये पद पर स्थानापन्न, लेकिन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रस्ता वित करने पर सरकार निचले पद के समान एक अधिसरय पद का भूजन करेगी तथा ऐसे सजन के पश्चात ऐसे निचले पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति की जायगी ।		
(घ) अस्थायी	अस्थायी	(घ) अस्थायी	
(ङ) अस्थायी	तदथ	(ङ) तदथ	

(2) सरकार, आदेश द्वारा, जिलो के कलक्टरों को उनके अपने जिलो के भीतर सेवा कर रहे लिपिकवर्गीय तथा चतुथ श्रेणी कमचारियों के बारे में, समिति की शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

(3) 1 जनवरी, 1954 से इन नियमों के प्रकाशन के दिन तक की कालावधि के बारे में अनुसूची में वर्णित तथा अधिशेष कमचारियों को आमेसन द्वारा नियुक्ति के लिये उक्त कालावधि के दौरान लागू किये गये सरकार के नियुक्ति तथा सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न परिपत्र, अधिशेष कमचारियों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो वे इन नियमों के भाग हों तथा ऐसी नियुक्तियाँ अधिष्ठायी, स्थानापन्न, अस्थायी या तदथ होगी, जैसा कि इसके उप नियम (1) के नीचे दी गई सारणी में बताया गया है ।

8 आयु — राजस्थान सेवा नियम, 1951 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य सेवा नियम में किसी बात के होते हुए भी एक अधिशेष कमचारी यदि वह ऐसे पद पर, जिस पर वह प्रारम्भत भर्ती या नियुक्त किया गया था ऐसी भर्ती या नियुक्ति की तारीख को लागू होने वाले किसी नियम द्वारा विहित आयु सीमा के भीतर या ता उसके लिये यह भी समझा जायेगा कि वह ऐसे पद पर उसकी आमेसन द्वारा भर्ती या नियुक्ति की तारीख को, उस पद के बारे में जिस पर वह इन नियमों के अधीन



आमेलित किया जाता है तत्समय प्रवृत्त नियमा द्वारा विहित आयु सीमा के भीतर है।

9 आवृत्तन के पश्चात् भर्ती एवं पदोन्नति कोटा में कमो — जहाँ तत्समय प्रवृत्त सेवा का कोई नियम, रिक्त पदा की चयन और विशेष चयन सहित, सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा दोनों द्वारा भर्त जान का उपबन्ध करता है तो इस प्रकार से भरे जाने वाले उपलब्ध रिक्त पदों की कुल संख्या, समिति द्वारा किये गये आवृत्तन के परिणामस्वरूप इन नियमों के अधीन नियुक्ति द्वारा भर्त गये रिक्त पदों की संख्या घटा किये जाने के पश्चात् अवधारित की जायगी।

10 अहतायें — समिति द्वारा किये गये आवृत्तन के परिणाम स्वरूप इन नियमों के अधीन नियुक्त अधिशेष कामिकों के मामले में —

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी के क्षत्र में आने वाले पदों के लिये यह समझा जायगा कि तत्समय प्रवृत्त सुसंगत सेवा नियमा या सरकारी आदेशों के अधीन विहित शैक्षिक तकनीकी अथवा सेवा और अनुभव के अधिशेष अहतायों का शिथिल कर दिया गया है, और
- (2) आयोग की सिफारिशों पर भर्ती किये गये स्थायी तथा अस्थायी कमचारियों को छोड़कर, आयोग के क्षेत्र में आने वाले पदों के लिये, उन अधिशेष कमचारियों के मामले, जो 1 जनवरी, 1954 को या तत्पश्चात् लेबिन इन नियमों के प्रकाशन के पूर्व आमेलित किये गये थे तथा जो उसके लिये लिये विहित शैक्षिक, तकनीकी तथा अन्य अहतायें पूरी नहीं करत, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 6 माह के भीतर विहित अहतायों में शिथिलीकरण की सहमति प्राप्त करने के लिये आयोग को निर्देशित किये जायेंगे।

11 कतिपय मामलों में अधिशेष कमचारियों की उपयुक्तता विनिर्णित करने तथा अधिष्ठायी नियुक्ति करने के लिये प्रक्रिया —

- (1) 1 जनवरी, 1954 से इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के दौरान नियम 7 के उप नियम (3) के अधीन आमेलित अधिशेष कमचारियों के मामले में जहाँ वे पद पर वे आमेलित किये गये थे इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को आयोग के क्षेत्र में प्राप्त हैं तो अधिशेष कमचारियों की उपयुक्तता आयोग द्वारा निम्नलिखित तरीके से विनिर्णित की जायगी —

(क) वही पदा पर आयोग द्वारा उन पदों के लिये सम्यक चयन कर लिये जाने के पश्चात् नियुक्त किंतु उच्चतर पदा अथवा सेवा में निरंतर 3 वर्षों से अधिक समय से स्थानापन्न या अस्थायी या तदर्थ रूप के आधार पर कार्य कर रहे अधिशेष कमचारियों की उपयुक्तता आयोग द्वारा, उही उच्चतर पदों के लिये

विनिर्णित की जायगी जिनसे वे अधिशेष घोषित किये गये थे, तथा

(ख) उन अधिशेष कमचारियों की उपयुक्तता जिनकी नियुक्ति आयोग की माफन नहीं हुई थी आयोग द्वारा उस पद के लिये विनिर्णित की जायगी जो उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति के पद के समतुल्य है चाहे उनके अधिशेष घोषित किये जाने की तारीख को वे अग्र्य समानित या समतुल्य पदा या उच्चतर पद पर स्थानापन्न, तदर्थ अथवा अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हों, तथा ऐसी सेवावधि चाहे कितनी ही रही हो।

(2) उन नियम (1) के या नियम 7 के या नियम (3) के अधीन आमेलित अधिशेष कमचारियों के मामले में जहाँ वे पद जिन पर उन्हें आमेलित किया गया था, आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर हों तो ऐसे अधिशेष कमचारियों की उपयुक्तता स्त्रीनिर्णय समिति द्वारा जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी तथा समिति का सदस्य सचिव अथवा उसके द्वारा ऐसा मनोनीत व्यक्ति हो जो सहायक सचिव से नीचे के स्तर का न हो, निम्नलिखित तरीके से विनिर्णित की जायेगी —

(क) वही पद पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उन पदा के लिये सम्मूह चयन किये जाने के पश्चात् नियुक्त लेकिन उच्चतर पदों पर निरंतर 3 वर्ष से अधिक समय से स्थानापन्न या अस्थायी अथवा तत्प्रकार आधार पर कार्य कर रहे अधिशेष कमचारियों की उपयुक्तता, स्त्रीनिर्णय समिति द्वारा उही उच्चतर पदा के लिये विनिर्णित की जायगी, जिनसे अधिशेष घोषित किये गये थे तथा

(ख) उन अधिशेष कमचारियों की, उपयुक्तता जिनकी नियुक्ति नियमित तरीके से नहीं हुई थी स्त्रीनिर्णय समिति द्वारा उस पद के लिये विनिर्णित की जायगी जो कि उस पद के समतुल्य है जिस पर वे आरम्भित नियुक्त किये गये थे चाहे उनके अधिशेष घोषित किये जाने की तारीख को वे अग्र्य समानित या समतुल्य व उच्चतर पद पर स्थानापन्न तदर्थ अथवा अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हों तथा ऐसी सेवावधि चाहे कितनी ही रही हो

परन्तु उन नियम (1) तथा (2) के उद्देश्यों का उन अधिशेष कमचारियों पर लागू किया जाना आवश्यक नहीं है जो इन नियमों के प्रकाशन से पूर्व सेक्शन आमेलन के पश्चात् आयोग द्वारा चयन किये जाने पर ऐसे पदों पर भर्ती किये गये थे जिन पर वे आमेलित किये गये थे या जिनको सुसंगत सेवा नियमों के उपबन्धों के अधीन ऐसे पदों के लिये आयोग द्वारा

अथवा किसी समिति द्वारा अथवा रूप से उपयुक्त विनिर्णीत किया गया था।

- (3) नियम 7 के उप-नियम (3) के अधीन आमेलित कमचारियों के मामले में, जहां वे पद, जिन पर वे आमेलित किये गये थे इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को आयोग के क्षेत्र में आते हैं तथा उप नियम (1) या नियम 7 के उप नियम (3) के अधीन आमेलित अधिशेष कमचारियों के मामले में जहाँ पद, जिन पर वे आमेलित किये गये थे नियुक्ति प्राधिकारी के क्षेत्र में आते हैं, यदि अधिशेष घोषित किये जाने की तारीख को उस पद पर जिससे वे अधिशेष घोषित किये गये थे अथवा समतुल्य पदों पर तीन या तीन से अधिक वर्षों के लिये तदर्थ रूप से नियुक्त थे तो नये पदों पर नियुक्ति तदर्थ रूप में होगी जैसी कि नियम 7 के उप-नियम (1) में दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग (ड) में यथा उपबधित है और आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा उनकी उपयुक्तता ऐसे नये पदों के लिये विनिर्णीत की जायगी।
- (4) नियम 7 के उप नियम (1) के अधीन या उप नियम (3) के अधीन आमेलित अधिशेष कमचारियों के मामले में, जहां अधिशेष घोषित किये जाने की तारीख को उस पद पर जिस पर से वे अधिशेष घोषित किये गये थे या समतुल्य पदों पर तीन से कम वर्षों के लिये तदर्थ रूप से नियुक्त थे तो नये पदों पर नियुक्ति केवल तदर्थ रूप में होगी जैसा कि नियम 7 के उप नियम (1) में दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग (ड) में यथा-उपबधित है तथा वह प्रसामान्य अनुक्रम में तथा सुसंगत-सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुसार खूले बाजार से लिये जाने वाले अभ्यर्थियों के साथ नियमित सीधी प्रतियोगिता में भाग लेना होगा।
- (2) उन स्थायी या अस्थायी आमेलित अधिशेष कमचारियों की उपयुक्तता को विनिर्णीत करना आवश्यक नहीं होगा जो पहले के पदों पर आयोग की सिफारिश पर या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमित तरीके से प्रारम्भित नियुक्त किये गये थे और तत्पश्चात् नये पदों पर नियुक्त किये गये थे।
- (6) आमेलन द्वारा नये पदों पर नियुक्त अधिशेष कमचारी, जिनकी उपयुक्तता उप नियम (1) में (3) के अधीन विनिर्णीत की गयी है अथवा उप नियम (5) के अधीन जिसे विनिर्णीत करना आवश्यक नहीं है, आमेलन द्वारा उनकी नियुक्ति की तारीख से पदों पर नियमित रूप से नियुक्त किये हुए समझे जायेंगे।
- (7) विभाग में नये पदों पर आमेलन द्वारा नियुक्त अधिशेष कमचारी तथा उन कमचारियों के लिये जो इन नियमों में यथा उपबधित स्कीमिंग

के पश्चात् उपयुक्त विनिर्णीत नहीं किये गये हैं, विभाग में अगले नीचे के पद पर नियुक्ति के लिये उनकी उपयुक्तता विनिर्णीत करने पर विचार किया जायगा। ऐसे कमचारी को निचला पद ग्रहण करने या राजस्थान सेवा नियम के नियम 215 के अधीन यथा अनुज्ञेय प्रतिवर्ष उपदान/पेंशन पर सेवानिवृत्ति लेने का विकल्प भी दिया जा सकेगा।

**12 विभागीय परीक्षा तथा प्रशिक्षण** — नियम 11 से उप नियम (3) या उप नियम (5) के अन्तर्गत आने वाले एक तदर्थ अस्थायी अधिशेष कमचारी को नये पद पर नियुक्त किये जाने पर यदि ऐसे पदों को लागू होने वाले नियम के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करना या विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अपेक्षित हो तो नियम में विहित कालावधि के भीतर उसी रीति में जैसी सीधी भर्ती वाले के लिये उपबधित है, प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। यह कालावधि नये पद का कार्यभार लेने या इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, प्रारम्भ होगी।

परन्तु यदि आमेलन द्वारा उनकी नियुक्ति के पश्चात् लेकिन इन नियमों के प्रकाशन से पूर्व विभाग में कोई ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा आयोजित हुई हो तथा अधिशेष कमचारी होने के आधार पर अपात्रता के कारण ऐसे प्रशिक्षण में जाने या ऐसी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये उसे अनुज्ञात न किया गया हो तो उसके लिये ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना या ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा।

**13 भर्ती परीक्षा**—नियम 11 के उप नियम (4) के अन्तर्गत आने वाले अस्थायी कमचारियों को जो बरिष्ठ लिपिक के रूप में आमेलित किये गये हैं, विहित भर्ती परीक्षा में, यदि कोई हो, उत्तीर्ण होने के लिये सरकार द्वारा अधिकथित शर्तों एवं निबन्धनों पर दो अवसर दिये जायेंगे।

परन्तु उन कमचारियों से जिनके पूर्व पद बरिष्ठ लिपिक नहीं थे, बरिष्ठ लिपिकों के नये पदों का कार्यभार सभालने की तारीख से एक वर्ष पूरा होने तक प्रथम अवसर का उपयोग करने की अपेक्षा नहीं की जायगी।

(2) उनके, उप नियम (1) के अधीन दो अवसरों में भी परीक्षा में उत्तीर्ण न होने की दशा में उनकी सेवार्य एक माह का नोटिस देकर तुरन्त समाप्त किये जाने के दायित्वाधीन होंगी।

**14 वेतन, वेतनवृद्धि, छुट्टी आदि का विनियमन** — अधिशेष कमचारियों के अधिशेष बने रहने की कालावधि के दौरान तथा उनके आमेलन कर उनका वेतन, वेतनवृद्धि, भत्ता और छुट्टी आदि राजस्थान सेवा नियम तथा अन्य सुसंगत नियमों के उपबन्धों और समय-समय पर जारी किये गये आदेशों द्वारा विनियमित किये जायेंगे।

**15 बरिष्ठता** — (1) ऐसी सेवा या सवग के जिसमें अधिशेष कमचारी आमेलित किया गया है, स्थायी पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त अधिशेष कमचारी

को वरिष्ठता, संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे नयी सेवा या विभाग के उस कनिष्ठतम स्थायी कर्मचारी के नीचे रखते हुए भवधारित की जायेगी जिसने अधिशेष कर्मचारी की समतुल्य या उच्चतर पद की निरन्तर अधिष्ठायी सेवा की तुलना में उस पद पर दीयतर कालावधि तक निरन्तर अधिष्ठायी सेवा की है। अधिशेष कर्मचारी की वरिष्ठता, जो स्थानापन्न आधार पर उच्चतर पद पर शामिल किया गया है, केवल उसके स्थायी पद की दृष्टि से ही भवधारित की जायेगी।

परन्तु ऐसे अधिशेष कर्मचारी की वरिष्ठता, जिसकी अधिष्ठायी या स्थानापन्न रूप में या उक्त दोनों ही रूप में निरन्तर सेवाकाल ऐसे नये विभाग में की, जिसमें उक्त अधिशेष कर्मचारी को शामिल किया गया है, सेवा या सवग के कनिष्ठतम स्थायी कर्मचारी का अधिष्ठायी या स्थानापन्न रूप में या उक्त दोनों ही रूप में के निरन्तर सेवाकाल से कम है तो इस विभाग की सेवा या सवग में जिसमें कि अधिशेष कर्मचारी शामिल किया गया है, अधिशेष कर्मचारी की उक्त कनिष्ठतम स्थायी कर्मचारी के ठीक नीचे रखते हुए, भवधारित की जायेगी।

(2) नये पद पर अस्थायी या तदर्थ रूप में नियुक्त अधिशेष कर्मचारी की वरिष्ठता उसकी अधिष्ठायी आधार पर नियुक्ति होने तक निम्नलिखित तरीकों से भवधारित की जायेगी —

(क) नये पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त अधिशेष कर्मचारी के मामले में, सेवा या सवग में के, जिसमें वह शामिल किया गया है, उन्हीं पदों को धारण कर रहे अस्थायी कर्मचारियों के मध्य उसकी वरिष्ठता उसे नयी सेवा या सवग के उस अस्थायी कर्मचारी के ठीक नीचे रखते हुए भवधारित की जायेगी जिसने अधिशेष कर्मचारी को उस पद की या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर पद की निरन्तर अस्थायी सेवा की तुलना में दीयतर कालावधि तक निरन्तर अस्थायी सेवा की है।

(ख) नये पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त अधिशेष कर्मचारी के मामले में, सेवा या सवग में के जिसमें वह शामिल किया गया है, उन्हीं पदों को धारण कर रहे तदर्थ कर्मचारियों के मध्य उसकी वरिष्ठता, उसे नयी सेवा या सवग के उस तदर्थ कर्मचारी के ठीक नीचे रखते हुए भवधारित की जायेगी, जिसने अधिशेष कर्मचारी की उस पद की या के समतुल्य या उससे उच्चतर पद पर निरन्तर तदर्थ सेवा की तुलना में तदर्थ आधार पर कहीं अधिक लम्बी कालावधि तक निरन्तर सेवा की है।

परन्तु सवग या सेवा में शामिल अधिष्ठायी अधिशेष कर्मचारियों सहित उस के समस्त अधिष्ठायी कर्मचारी, उन नियमों के अधीन ऐसे सवग या सेवा में नियुक्त या शामिल अस्थायी कर्मचारियों से वरिष्ठ होंगे तथा समस्त ऐसे अस्थायी कर्मचारी इन नियमों के अधीन या अथवा रूप में नियुक्त या शामिल समस्त तदर्थ कर्मचारियों से वरिष्ठ होंगे।

15(2) (ख) परन्तु यह और कि सवग या सेवा में किसी पद पर के, उसमें आमेलित अधिशेष कमचारियों सहित, कमचारी की तथा जो 11 दिसम्बर, 1969 को या उससे पूर्व ऐसे पदों पर अधिष्ठायी थे, वरिष्ठता सुसंगत सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुसार अवधारित की जायगी।

(3) किसी सेवा या सवग में से अधिशेष घोषित कमचारियों की दूसरी सेवा या सवग में नये पदों पर नियुक्ति हो जाने के पश्चात् पारस्परिक वरिष्ठता बही होगी जो कि पहले वाली सेवा या सवग में विद्यमान थी।

16 परीक्षा, स्थायीकरण तथा सेवा की शर्तें —(1) इन नियमों में अन्यथा उपबोधित के सिवाय तथा उपनियम (2), (3) और (4) में के उपबन्धों के अधीन, नये पद पर आमेलन द्वारा नियुक्त होने पर अधिशेष कमचारी परीक्षा स्थायीकरण व सेवा की शर्तों से संबंधित समस्त मामलों में राजस्थान सेवा नियम, 1951 तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये गये और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत सेवा नियमों से शासित होगा।

(2) स्थायी अधिशेष कमचारी की नये पद पर आमेलन द्वारा नियुक्ति होने पर उसे परीक्षा पर रखने या उसको स्थायी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) नियम 11 के उपनियम (1), (2) तथा (3) के अन्तर्गत आने वाले अधिशेष कमचारी और उक्त नियम के उपनियम (5) के अन्तर्गत आने वाले अस्थायी अधिशेष कमचारी नये पदों पर उनकी उपयुक्तता विनिर्णीत किये जाने पर रिक्त पद उपलब्ध होने की तारीख से नियम 15 के अधीन यथा अवधारित वरिष्ठता क्रम में परीक्षा पर रखे बिना ही यदि उक्त उपनियमों द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, स्थायी किये जायेंगे।

(4) जहां कि-ही सेवा नियमों के अधीन, नये पद से उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिये किसी विनिर्दिष्ट कालावधि का अनुभव अपेक्षित हो लेकिन वह पद जिस पर अधिशेष कमचारी उसके आमेलन में पहले कार्य कर रहा था, ऐसे नये पद से भिन्न है तो उक्त अनुभव की गणना करते समय उस कालावधि की, जिसके दौरान अधिशेष कमचारी ने उसके आमेलन से पूर्व किसी समतुल्य या उच्चतर पद पर काम किया था, आधी कालावधि तक का श्रेय दिया जायगा।

17 शकाग्रों का निराकरण — यदि इन नियमों के लागू किये जाने, निवचन और व्याप्ति के बारे में कोई शका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के पास नियुक्ति विभाग को निर्दिष्ट किया जायगा और उस पर नियुक्ति विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।

18 फायदों की समाप्ति के लिए विलक्षण — किसी भी अधिशेष कमचारी को। किसी पद विशेष पर या किसी विभाग विशेष में या सवग विशेष में आमेलन द्वारा नियुक्ति का दावा करने का अधिकार नहीं होगा तथा इस बारे में समिति का विनिश्चय अंतिम होगा। अधिशेष कमचारी जो उस पद पर नियुक्त होना नहीं चाहता

जिस पर कि वह धामेहित किया गया है प्रामेलन के आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर राजस्थान सेवा नियम, 1951 के उपबन्धों के अनुसार अपनी सेवाओं समाप्त किए जाने के लिये सरकार को आवेदन कर सकेगा। यदि वह न तो ऐसा आवेदन करता है और न उस नये पद का कामभार सम्भालता है जिस पर कि वह धामेहित किया गया है, तो वह ड्यूटी से अनुपस्थिति माने जाने के दायित्वाधीन होगा तथा प्राप्ति से वह उस दिनांक से किसी प्रकार का वेतन और भत्ता पाने का हक्क नहीं होगा जिसे दिनांक से वह ड्यूटी से अनुपस्थित माना गया है।

### अनुसूची

#### [ नियम 7 (3) देखें ]

- 1 राजस्थान सरकार के सामान्य प्रशासन (क) विभाग द्वारा जारी किया गया परिपत्र संख्या एक 1 (6) जी ए/सी/60 दिनांक 23 मार्च, 1960।
- 2 राजस्थान सरकार के सामान्य प्रशासन (ग) विभाग द्वारा जारी किया गया परिपत्र संख्या एक 1 (13)/9/जी/ए/सी/61 दि 27 मार्च, 1961।
- 3 राजस्थान सरकार के सामान्य प्रशासन (ग) विभाग द्वारा जारी किया गया परिपत्र आदेश संख्या एक 1(13)/1/जी/ए/सी/62 दिनांक 15.6.1962।
- 4 राजस्थान सरकार के नियुक्ति (ग) विभाग द्वारा जारी किया गया परिपत्र आदेश संख्या एक 5 (2) ए/सी/56 दिनांक 4 फरवरी, 1966।
- 5 राजस्थान सरकार के सामान्य प्रशासन (ग) विभाग द्वारा जारी किया गया परिपत्र आदेश संख्या एक 1 (33) जी/ए/सी 66 दिनांक 23 जुलाई, 1960।

### आदेश

जयपुर, मार्च 23, 1960

संख्या एक 1 (6) जी ए/ए/ 60 —सरकारी आदेश संख्या एक 1 (6) जी/ए/60 दिनांक 1 मार्च, 1960 के अनुसार विभागाध्यक्षा के अधीन कुल लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत कटौती प्रवर्तित की गयी है। विभिन्न विभागों से प्राप्त उत्तरों से ऐसा ज्ञात हुआ है कि कुछ विभागों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है और इस भाषा से कि सरकार द्वारा कटौती से छूट दे दी जायगी उन्होंने अभी तक अनुदेशों का क्रियान्वयन नहीं किया है। अतः सभी संबंधित विभागों को पुनः लिखा जाता है कि 5 प्रतिशत कटौती किया जाना राज्य के सभी विभागों के लिये अनिवार्य है और यदि ऐसे किसी स्टाफ को रोक जाने के लिये कोई अपवाद आदि किया जाना प्रस्तावित हो तो संबंधित विभाग को पहले सरकारी आदेश का पालन करना चाहिये और इससे बाद ही अपने प्रशासनिक विभागों की भावना, इस प्रयोजन के लिये गठित समिति को लिखा जाना चाहिये। यह भी देखा गया है कि कुछ विभागों ने सरकारी आदेशों द्वारा सूचित निर्देशों का सही अनुसरण

नही किया है। कुछ विभागों द्वारा भेजी गयी अधिशेष कमचारियों की सूचियों से यह स्पष्ट है कि अधिशेष व्यक्तियों के नामों को डाटट समय उन्होंने वरिष्ठता के सिद्धान्त को पूर्णतः ध्यान में नहीं रखा है। अधिकांश मामलों में इस प्रकार अधिशेष घोषित व्यक्ति सम्पूर्ण विभाग के लिपिक वर्गीय स्टाफ के सत्रंग विशेष में कनिष्ठतम नहीं हैं, किन्तु अधिशेष स्टाफ की ऐसी घोषणा कार्यालयन की गयी है। इसी प्रकार कौनों को केवल निम्नतम सत्रंग तक सीमित किये जाने के आदेश दिये गये हैं किन्तु इनके प्रगत लिपिक वर्गीय स्टाफ के सम्पूर्ण सत्रंग को समान स्तर से सम्मिलित किया जाना है। अतः स्थिति को तथा इस विभाग के उपरिनिर्देशित आदेश को स्पष्ट करने के लिये निम्नलिखित अनुदेश और जारी किये जाते हैं—

1 कटौती केवल कनिष्ठ लिपिका, तक ही सीमित नहीं है अपितु वरिष्ठ लिपिक तथा लिपिक वर्गीय सेवा के अन्य सत्रंग भी इसके अन्तर्गत लिये जाते हैं। कटौती का वितरण लिपिक वर्गीय स्टाफ के सभी वर्गों में क्रमशः उनकी अपनी सराया के अनुपात के अनुसार किया जाना है लेकिन यह इस न्याय के अधीन होगा कि सत्रंग विशेष में एक भी पद की कटौती तब की जायगी जबकि पूरे राज्य में किसी विभाग को संपूर्ण लेते हुए उस सत्रंग में कमचारियों के पदों की सराया कम से कम बीस या बीस से अधिक हो।

- (i) इस प्रयोजन के लिये सम्पूर्ण सचिवालय एक इकाई समझा जायगा।
- (ii) कलक्टर कार्यालयों/कलक्टर के अधीनस्थ न्यायालयों तथा तहसीलों के लिपिक वर्गीय स्टाफ को एक इकाई माना जायगा।
- (iii) किसी विभाग विशेष के राज्यभर के सम्पूर्ण संगठन को एक इकाई माना जायगा।

2 केवल वे ही कमचारी जो लिपिक वर्गीय स्टाफ के सत्रंग में कनिष्ठतम हो अधिशेष घोषित किये जाने चाहिये। यदि एक या अधिक वरिष्ठ लिपिका के नामों को अधिशेष घोषित करना हो तो उन व्यक्तियों को अभी तक स्थानापन्न कर रहे हैं, ठीक नीचे के सत्रंग में प्रतिबन्धित किया जायगा। जब किसी इकाई विशेष में सभी व्यक्ति स्थायी हों तब उनमें से कनिष्ठतम को अधिशेष घोषित किया जायगा तथा उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग या ऐसे आमेनन आयोग के अधीन रखा जायगा।

3 समस्त अधिशेष स्टाफ को संबंधित विभाग द्वारा 15-12-1960 को उनके द्वारा लिये हुए अन्तिम वेतन आदि के बारे में दिये गये आदेशों के आधार पर उनकी पूरी परिलब्धियां उनके राज्य के किसी भी विभाग के अधीन वर्तमान स्थिति में उनके आमेलन की तारीख तक दी जानी चाहिए।

4 जिन व्यक्तियों को जयपुर में अधिशेष आयोग के अधीन रखने के लिये सचिव सामान्य प्रशासन (क) विभाग के समक्ष पदों की सूची, 1960 में सबधित द्वितीयक आयुक्त के समक्ष गिनाई गयी है, उन्हें के लिये निर्देश दिया जाय।



5 विभिन्न विभागों द्वारा अधिशेष घोषित कमचारियों की सर्वानुसार सूची सामान्य प्रशासन विभाग के साथ साथ संबंधित द्विवीजनल आयुक्त के कार्यालय में भी निम्नलिखित प्रपत्र में रखी जायगी तथा सूची रहे जाने के लिये आवश्यक विशिष्टियां विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेंगी ।

सबग —

1 कम सख्या

2 नाम

3 पद नाम

4 की गई कुल सेवा

5 विभाग, जिसमें आयोजन के लिए आवंटित किया गया

6 वरिष्ठता

7 वे विभाग, जिनमें आयोजन के लिए आवंटित किया गया

8 आवंटन की तारीख

9 अभ्युक्ति

6 रिक्तिओं की सर्वानुसार सूची भी निम्नलिखित प्रपत्र में रखी जाय ।

सबग —

1 कम सख्या

2 विभाग का नाम

3 पद का नाम

4 स्थाई या अस्थायी/यदि अस्थायी हो तो उसकी कालावधि

5 पद से संबंधित विशेष वेतन या भर्ती, यदि कोई हो

6 स्थान जहाँ पद विद्यमान है

7 पदस्थापित व्यक्ति का उसकी कम सख्या सहित नाम तथा अधिशेष सूची में की पृष्ठ सख्या

8 पदस्थापन की तारीख

9 अभ्युक्तियां

7 जैसे ही किसी विभाग द्वारा रिक्त की सूचना दी जाय, सामान्य प्रशासन विभाग या आयुक्त को इसे तुरंत भरना चाहिये ।

8 अधिशेष घोषित व्यक्ति की पूरा सेवा उसके अनुवर्ती आयोजन पर उस विभाग विशेष में की पारस्परिक वरिष्ठता के लिये धिनी जायगी ।

9 अधिशेष व्यक्ति घोषित व्यक्ति घोषित करते समय जिन विभागाध्यक्षों ने उपयुक्त अनुदेशों का ध्यान में नहीं रखा है उन्हें अब तुरंत पुनरीक्षित सूचियां भेजनी चाहिए । जिन व्यक्तियों को पहले अधिशेष घोषित कर दिया गया हो और जिनके नाम अब पुनरीक्षित सूचियों में नहीं हों, उन्हें पुन आयोजन हेतु संबंधित विभाग को वापस भेज

दिया जायगा। इसकी विवक्षा यह होगी कि उन कमचारियों को इस कालावधि तक सदाय जब तक वे सामान्य प्रशासन विभाग या आयुक्त के अधीन रहने हैं तदर्थ रहे गये अनुदान में से किया जायगा तथा उम तारीख से जब उनका पुन आमेलन उन विभागों में कर दिया जाता है सदाय संबंधित विभाग द्वारा किया जायगा।

10 विभागाध्यक्षों को अपने विभाग में विद्यमान और बाद में होने वाली सभी रिक्तिया, यथास्थिति उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग या आयुक्त को तुरत ससूचित की जानी चाहिये।

### परिपत्र

जयपुर, माच 27, 1961

सत्या एक 1 (13)/9जीए/सी/61—प्रशासन यय में मितव्ययिता करने की दृष्टि से सरकार ने निम्नलिखित विनिश्चय किये हैं—

1 कतिपय पद विनिर्दिष्टत 1 जून, 1961 से तोड दिये जायेंगे। तोडे जाने वाले पदों की सूचना सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को वित्त विभाग देगा, जो इसके पश्चात ऐसे पदों को तोडे जाने के औपचारिक आदेश जारी करेगा। वित्त विभाग पदों को तोडे जाने से सम्बन्धित अपनी सिफारिश की एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग (ग) को भी भेजेगा।

2 1 जून, 1961 से चरामियों (अर्थात् चतुथ श्रेणी के अधीन पद नामित तकनीकी कमचारियों को छोडकर अय चतुथ श्रेणी कमचारी) की सत्या 1 माच 1961 को विद्यमान कुल सङ्ख्या के 20 प्रतिशत तक कम करदी जायगी। वित्त विभाग कोषाधिकारियों को यह आदेश जारी करेगा कि 1 जुलाई, 1961 से विभिन्न विभागों के कमचारियों के वेतन के बिलों को तभी पास किया जाय जब कि आदान अधिकारी यह प्रमाण पत्र दे दे कि 1-3 61 को विद्यमान स्वीकृत सत्या में 1-6-61 से 20 प्रतिशत कटौती कर दी गई है तथा वेतन बिल तन्नुसार तैयार किये गये हैं। इस कमी को प्रवर्तित करने समय विभागाध्यक्ष यह विनिश्चय करेगा कि चरामियों की किस कोटि में कमी की जानी है और की गयी कमी की सूचना अपने प्रशासकीय विभागों तथा सामान्य प्रशासन विभाग (ग) को देगा।

3 चतुथ श्रेणी के कमचारियों को छोडकर छटनी किये जाने वाले पदों की सूची सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को तुरत भेजी जायगी। उसके पश्चात विभागाध्यक्ष निम्नलिखित 4 विवरण तैयार कर 7 अप्रैल 1961 तक सामान्य प्रशासन (ग) विभाग को भेजेगा। ये सभी विवरण निम्नलिखित प्रपत्र में होंगे—

- (i) छटनी किये गये पदों के पद नाम, यदि कोई हो
- (ii) ऐसे पदों की सत्या
- (iii) छटनी किये गये पदों के वेतनमान
- (iv) 1 4 61 या उससे पश्चात सृजित नये पदों को छोडते हुए समतुल्य सर्वगों में विद्यमान रिक्त पदों के पद नाम

(v) विद्यमान रिक्त पदों की संख्या

(vi) विद्यमान रिक्त पदों के वेतनमान

(vii) तत्समान सबर्गों में 1-4-61 के पश्चात् सृजित किये जाने वाले पदों के पद नाम

(viii) ऐसे पदों की संख्या

(ix) ऐसे पदों के वेतनमान

4 विवरण "ब" राजपत्रित पदों के लिये उपयुक्त प्रपत्र में होगा।

5 विवरण "ख" अधीनस्थ पदों के लिये उपयुक्त प्रपत्र में होगा।

6 विवरण 'ग' लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिये उपयुक्त प्रपत्र में होगा।

7 विवरण "घ" चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये उपयुक्त प्रपत्र में होगा।

जयपुर शहर के मामलों को छोड़कर विवरण 'ग' व 'घ' की प्रतियां सम्बंधित क्लर्क/डिप्टी को भी भेजी जाएंगी। ये विवरण सभी विभागाध्यक्षों द्वारा भेजे जाएंगे। चाहे किसी विभाग विशेष में किसी पद की छूटनी की गई हो या नहीं। पश्चात् कथित मामले में विभागाध्यक्षों को विद्यमान रिक्त पदों की पूर्ण विशिष्टियां तथा लोटे जाने वाले पदों के सबर्गों के समान सबर्गों में सृजित किये जाने वाले पदों की विशिष्टियां देनी होंगी।

8 सम्बंधित विभागाध्यक्ष छूटनी किये जाने वाले पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की विशिष्टियां निम्नलिखित प्रपत्र भेजेंगे।

(i) क्रम संख्या

(ii) छूटनी किये गये या छूटनी किये जाने वाले पद का नाम

(iii) पद का वेतनमान

(iv) कर्मचारी का नाम पिता के नाम सहित

(v) 1-4-61 को कर्मचारी की आयु

(vi) शैक्षणिक ग्रहता

(vii) छूटनी किये गये पद पर नियुक्ति की तारीख

(viii) नियुक्ति का प्रकार अविच्छाद्यी या अस्थायी

(ix) क्या लोक सेवा आयोग की सहमति आवश्यक है ?

(ix) क्या लोक सेवा आयोग ने सहमति दे दी है या नहीं दी है ?

(xi) क्या किसी अन्य पद पर अविच्छाद्यी नियुक्ति धारण की है ?

(xii) ऐसे पद का नाम तथा वेतनमान

(xiii) छूटनी किये गये पद पर नियुक्ति से ठीक पहले की नियुक्ति की विशिष्टियां, यदि कोई हो।

राजपत्रित अधिकाऱिया अधीनस्थ अधिकाऱिया, लिपिक वर्गीय कमचारियो तथा चतुथ श्रेणी कमचारियो के सम्बन्ध मे अलग अलग विवरण भेजे जायेंगे । लिपिक वर्गीय कमचारियो तथा चतुथ श्रेणी कमचारियो के सम्बन्ध मे विवरण की प्रतिया जयपुर शहर के मामला को छोडकर सम्बन्धित कलक्टरो को भेजी जायेंगी ।

9 सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित तथा अन्य कमचारियो को, जिहोने 1 4 61 को छह माह से अधिक की सेवा की हो, आमेलन की गारण्टी दी जायगी । वे अधिशेष रहते हुए आमेलन तक अपना वेतन प्राप्त करने के हक्दार होंगे लेकिन ऐसे मामले मे जब कि वे अधिशेष रहे, तीन माह से अधिक का वेतन नहीं दिया जायगा । यदि फिर भी रिक्तिया बाकी रहें तो 6 माह से कम सेवा काल के अन्य अस्थाई कमचारियो के आमेलन के सम्बन्ध मे भी विचार किया जायेगा तथापि ऐसे अस्थाई कमचारी अधिशेष बन रहने की कलावधि के दौरान किसी प्रकार के वेतन पाने के हक्दार नहीं होंगे तथा उन्हें केवल नाटिस वेतन मिलेगा ।

10 जयपुर शहर के मामलो को छोडकर लिपिक वर्गीय तथा चतुथ श्रेणी कमचारियो के आमेलन के लिए सभी कलक्टर अपने अपने जिलो के लिए उत्तरदायी होंगे । जयपुर शहर के लिपिक वर्गीय तथा चतुथ श्रेणी कमचारियो का तथा अन्य सभी प्रवर्गों के कमचारियो का आमेलन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा ।

11 सामान्य प्रशासन विभाग (ग) में आमेलन एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसमे निम्नलिखित होंगे —

(1) वित्त मंत्री	अध्यक्ष
(2) विशिष्ट सचिव नियुक्ति	सदस्य
(3) निर्वाचन सचिव	सदस्य सचिव

12 इस समिति को तथा कलक्टरो को अपने अपने जिला मे अधिशेष कमचारी का किसी विभाग मे समानित या किसी अन्य पद पर आमेलन करने का पूरा अधिकार होगा । ऐसे आवंटन के प्राप्त होने पर, सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी शुरन्त आदेश जारी करेंगे और साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग (ग) को या जहा कलक्टर ने किसी व्यक्ति का आवंटन किया हो तो सम्बन्धित कलक्टर को, सूचित करेंगे ।

13 जब तक कि छुटनी किये गये व्यक्तियो का आमेलन नहीं कर लिया जाता, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परिणामस्वरूप भर्ती किय गये व्यक्तिया को छोडकर किसी भी विभाग मे नई भर्ती नहीं की जायगी । राजस्थान सरकार के वित्तविभाग न कोषाधिकारियो को पहले ही यह आदेश जारी कर दिए हैं कि 15 फरवरी, 1961 के पश्चात् नियुक्त व्यक्तियो के वित्त पास नहीं किए जायें । भर्त आदान अधिकारी सम्बन्धित विभाग के वेतन बिलो के साथ आशय का एक प्रमाण-पत्र सलग करेगा कि पूर्ववर्ती माह के दौरान किसी नए व्यक्ति की

नियुक्ति नहीं की गई। यह प्रमाण पत्र उन पदा के लिए आवश्यक नहीं होगा जिनके सम्बन्ध में तकनीकी कुशलता या तकनीकी अनुभव अनिवार्य रहता हो। इसी तरह गैर तकनीकी सबर्गों में कोई नई पदोन्नति तब तक नहीं की जायगी जब तक कि सामान्य प्रशासन विभाग से अनुसन्धना प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हो जाय।

14 कलक्टर सामान्य प्रशासन (ग) विभाग का अधिरोप कमचारिया के आमेलन में सम्बन्धित भासिक प्रगति प्रतिबदन 1-5 61 में लेकर जिले में आमेलन काय की समाप्ति तब भेजेंगे।

15 चूँकि काय की यथा सम्भव शीघ्रता से पूरा किया जाना है अतः सभी विभिन्न स्तरों के प्राधिकारिया से अनुरोध है कि वे विनिश्चया तथा निर्देशों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें तथा आवश्यक आदेश जारी करन व सूचनाएँ उपलब्ध कराने के लिये शीघ्र कार्यवाही करें।

## आवेश

जयपुर जून, 12, 1962

सत्या एक 1 (31) जीए/सी/62 — मितव्ययिता हेतु उपाय किय जाने के परिणाम स्वरूप चासू विस्तीर्ण वष के दौरान विभिन्न प्रवर्गों व सरकारी कमचारी अधिशेष हो जायेंगे या पहले ही अधिशेष हो गये हैं। सरकार ने लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कमचारियों के तथा उन कमचारियों के जिन्होंने 1-4 62 को छह माह से अधिक की सेवा पूरी करली हो, आमेलन का विनिश्चय किया है। उन कमचारियों के जिन्होंने 1-4-62 को छह माह से कम की सेवा की हो, आमेलन के लिए भी यदि कोई रिक्रिया अभी भी विद्यमान हो तो विचार किया जायगा लेकिन ऐसे व्यक्ति अधिशेष बने रहने की कालावधि के दौरान किसी प्रकार के वेतन पाने के हकदार नहीं होंगे तथा उन्हें कवल नोटिस वेतन दिया जायेगा।

2 अधिशेष कामिकों के आमेलन हेतु निम्नलिखित आमेलन प्राधिकारी होंगे —

(क) आमेलन समिति जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे राज्य भर के आमेलन काय की प्रभारी होंगी। समिति राज्य भर की राज्य सेवाओं या अधीनस्थ सेवाओं तथा जयपुर शहर के अधिशेष लिपिक वर्गीय व चतुर्थ श्रेणी कमचारियों का आमेलन करेगी।

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| (1) वित्त मंत्री                 | अध्यक्ष    |
| (2) विशिष्ट सचिव, नियुक्ति विभाग | सदस्य      |
| (3) सचिव निर्वाचन विभाग          | सदस्य-सचिव |

(ख) जयपुर शहर के मामलों का द्योडकर सभी कलक्टर अपने अपने जिलों के लिपिक वर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी कमचारियों के आमेलन के लिए उत्तरदायी होंगे।

3 आमेलन समिति तथा कलक्टर का किसी अधिशेष कमचारी वा किसी भी विभाग मे के किसी समानित पद पर या किसी अन्य पद पर आमेलन करने सम्बन्धी सम्पूर्ण तथा अन्तिम शक्तिया होगी चाह उक्त पदो पर भर्ती के लिए विहित महताए कुछ भी हा । सबधित नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे आमेलन आदेश प्राप्त होने पर तुरत नियुक्ति पत्र जारी करेंगे और आमेलन प्राधिकारिया का सूचित करेंगे । नियुक्ति प्राधिकारी तथा नियुक्ति विभाग, आमेलित व्यक्तियों को विभाग मे उनका उचित स्थान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कायवाही करेंगे ।

4 नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के पश्चात यदि आमेलित व्यक्तिया से विच्छिन्न व्यक्ति ठीक निम्नतर सब्ग मे उपलब्ध हा तो अस्थाई व्यक्तियों को प्रतिवर्तित किया जा सकता है तथापि स्थाई व्यक्तिया को प्रतिवर्तित नहीं किया जायगा तथा केवल वरिष्ठता का निर्धारण नियमा के अनुसार किया जायेगा ।

5, वे पद जिन पर नई भर्ती के सबध मे प्रतिबध लगाया गया है, विभाग मे कमचारिया के स्थानांतरण द्वारा या पदोन्नति से सिवाय जब कि पदान्तरित राज स्थान लोक सेवा आयोग के परामर्श से की गई हा, नहीं भरे जायगे ।

6 किसी विभाग मे के विभिन्न पदा को तोडे जाने के आदेश की एक प्रति प्रशासनिक विभाग द्वारा सचिव आमेलन समिति का तुरत भेजी जायेगी ।

7 पदो का तोडने के आदेश के आधार पर अधिशेष होने वाल व्यक्तियों के नाम, यथास्थिति आमेलन समिति या सबधित कलक्टर को तत्काल सूचित किये जायेंगे । किसी व्यक्ति को अधिशेष किये जाने के पूर्व आमेलन प्राधिकारी को पूरे एक माह का समय दिया जायगा । अधिशेष किये जाने वाले कमचारिया के सबध मे आमेलन प्राधिकारी को सूचना निम्नलिखित प्रपत्र मे भेजी जायेगी —

- (1) कम मक्या
- (2) छटनी किए गए पद का नाम
- (3) छटनी किए गए पद का वेतनमान
- (4) पदधारी कमचारी का तथा उसके पिता का नाम
- (5) 1 4 62 को कमचारी की आयु
- (6) शक्षणिक ग्रहता
- (7) छटनी किए गए पद पर नियुक्ति की तारीख
- (8) नियुक्ति का प्रकार/अधिष्ठायी या अस्थाई
- (9) क्या पद को भरे जाने के लिए लाक सेवा आयोग की सहमति आवश्यक है ?
- (10) लाक सेवा आयाग ने व्यक्ति की नियुक्ति के सबध मे सहमति दी या नहीं ?
- (11) क्या किसी अन्य पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति धारण की है ?
- (12) ऐसे पद का नाम और वेतनमान

(13) छूटनी किए गए पद पर नियुक्ति से पूर्व की नियुक्ति से संबंधित विशिष्टिया, यदि कोई हो ।

8 राजपत्रित अधिकारिया निम्न वर्गीय कमचारिया तथा चतुर्थ श्रेणी कमचारियो के संबंध में असंग असंग विवरण भेज जायेंगे ।

9 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कमचारियो या 1 4 62 की छह माह से अधिक की सेवा वाले कमचारिया को अधिशेष बने रहने की अवधि में वेतन निम्न प्रकार मिलेगा —

(क) आमेलन समिति द्वारा आमेलित लिए जाने वाले सभी कमचारिया को उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ख) विभाग के आदेश के अधीन ।

(ख) संबंधित बलवर्द्ध के आदेश के अधीन उन कमचारियो को जिनके आमेलन के लिए वे सक्षम हैं । लेकिन, प्रति मास उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (ख) को भेजे जायेंगे ।

(ग) व्यय बजट शीप 19-जी ए डी ई पर प्रभावित होगा ।

(क) जिला स्थापना अधिशेष कमचारिया के वेतन तथा भत्ते

10 बलवर्द्ध, आमेलन समिति को 1-7-1962 से लेकर जिले में आमेलन कार्य पूरा हो जाने तक अधिशेष कमचारिया के आमेलन से संबंधित मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजेंगे ।

11 चूंकि आमेलन कार्य यथासंभव शीघ्रता से पूरा किया जाता है अतः विभिन्न स्तरों के सभी प्राधिकारियों से निवेदन है कि वे उपयुक्त विनिश्चयों तथा अनुदेशों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें तथा आवश्यक आदेशों के जारी करने व अपेक्षित सूचना भेजने में शीघ्र कार्यवाही करें ।

12 इस विभाग के आदेश संख्या एफ 1(13)/9/जी ए(सी)/61, दिनांक 27-3 61 को, इसके द्वारा रद्द किया जाता है । तथापि, सभी सम्बन्धित मामलों की या इन आदेश के अनुसरण में उठने वाली सभी समस्याओं का निपटारा उपयुक्त आमेलन प्राधिकारियों द्वारा किया जायगा ।

13 यह आदेश वित्त विभाग द्वारा उनको आई डी संख्या 1983/पीए/एफ एस /62, दिनांक 1 6 1962 द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किया जाता है ।

**परिपत्र**

**जयपुर, फरवरी 4, 1956**

संख्या एफ 5 (2) नियुक्ति (ग)/56 — यह रिपोर्ट की गई है कि समस्त प्रयासों के बावजूद, कस्टम्स और मिविल सप्लाय्स डिपार्टमेंट के सभी अधिशेष कमचारियों का आमेलन किया जाना संभव नहीं हो सका है । इन विभागों के उन

कमचारियों के आमेलन का प्रश्न भी जिहे विभागों के परिसमापन सबधी काय को पूरा करने के लिये अस्थायी आधार पर रोक रखा गया था, सुलझाया नहीं जा सका है। निष्कात सम्पत्ति अभिरक्षक के अधीन कार्यालयों में कायस्थ कतिपय कमचारी निकट भविष्य में अधिशेष घोषित किय जा सकते हैं तथा उनमें से कुछ के द्वारा अय विभागों और कार्यालयों में अपने आमेलन के लिए दावे किये जा सकेंगे। जबकि काय के य सभी मद पूरे किये जाने हैं, सरकार अधिशेष लोगों को आमेलित किय जाने की चिन्ता के कारण एकीकरण कार्यों पर लगाए गए निबन्धनों को अनिश्चित काल तक जारी रखना वाछनीय नहीं समझनी। अत एकीकरण काय को शीघ्र पूरा करने के लिए इस विभाग के इसी सरया के एव इसी तारीख के परिपत्र के जरिये अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। तथापि, उन लोगों के हितों की रक्षा के लिए जो अधिशेष घोषित किये जा चुके हैं या किय जाने वाले हैं, कुछ रक्षात्मक उपबध रखे गए हैं। उनमें से एक उपबध ऐसे कमचारियों के लिए अराजपत्रित पदों के 10 प्रतिशत का आरक्षण है। यह आरक्षण 1 अप्रैल 1956 तक ही प्रवृत्त रहेगा और इसलिये यह आवश्यक है कि उन लोगों के मामले में, जो दो वर्ष की अवधि में अधिशेष घोषित किए गए हैं या होने वाले हैं विचार किया जाय तथा आमेलन के लिए उनकी प्रवृत्ता एव उनके दावों पर उचित रूप से ध्यान दिया जाकर उन्हें अय विभागों/कार्यालयों को आवण्टित कर दिया जाय। इस काय को अंतिम रूप देने के लिए सरकार निम्न-लिखित बक्तियों की एक समिति गठित करती है —

- (1) श्री के एन भार्गव, आई ए एण्ड ए एस, अपर सचिव, वित्त सयोजक
- (2) श्री रामसिंह, आई ए एस, उप शासन सचिव, वित्त विभाग सदस्य
- (3) श्री जी के भनोट, आई ए एस, उप शासन सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग सदस्य

समिति को उन पदों के बारे में, जो कि एकीकरण के अनुक्रमण में स्थायी के आधार पर नहीं भरे गए हैं आकड़े प्राप्त करने चाहिए तथा सिविल सप्लाइ डिपार्ट-मेंट के सभी कमचारियों को जो अधिशेष घोषित किय जा चुके हैं या किये जात हैं आवण्टित किया जाना चाहिये। वर्तमान में विद्यमान अस्थायी विभागों और कार्यालयों में से केवल निष्कात सम्पत्ति अभिरक्षक के अधीन कार्यालय दो वर्ष के भीतर ही समाप्त किय जाने को है अत आमेलन के लिये इन कार्यालयों के दावों पर भी विचार किया जाना चाहिये। समिति द्वारा किये गये आवण्टन-विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों पर आवण्टकर होंगे।

समिति को अधिक से अधिक 15 मार्च, 1956 तक अपना काय पूरा कर लेना चाहिये।

आदेश

जयपुर, जुलाई 23, 1966

विषय — अधिशेष कमचारियों का आमेलन तथा जो आमेलन के हक्दार नहीं हैं उनकी सेवाओं की समाप्ति।



संख्या एफ 1 (33) जो ए/सी/66—मितव्ययिता के परिणामस्वरूप चालू वित्त वर्ष से विभिन्न वर्गों के कर्मचारी अधिरोप हो जायेंगे। सरकार न राजस्वाने लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये गये कर्मचारियों का तथा उन कर्मचारियों का जिन्होंने 1-10 65 को एफ वष से अधिक की सेवा करली है, आमेलन करने का विनिश्चय किया है। उन कर्मचारियों की सेवामें जिन्होंने 1-10 65 को एक वष से कम की सेवा की है, नियमा के अधीन नोटिस देकर समाप्त करदी जायेंगी।

2 संथा समाप्त करने के नोटिस की कालावधि के दौरान या सेवा की वास्तविक समाप्ति के पश्चात्, 1-10 65 को एक वष से कम की सेवावधि वाले व्यक्ति को विद्यमान रिक्त पद पर या सेवा समाप्ति के पश्चात् होने वाले रिक्त पद पर आमेलन जाने का अधिकार नहीं होगा। तथापि उससे वारे म रिक्तियों के भर जाने के नियमों को विनियमित करने वाले नियमा के अनुसार विद्यमान रिक्ति या भावी रिक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसकी नियुक्ति का प्रस्ताव किया जा सकेगा, चाहे उक्त पद का घटनमान उससे पद के जिससे की उसे अधिरोप घोषित किया गया हो वेतनमान से भिन्न या कम हो। यदि नियुक्ति का उक्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो उसे उक्त पद पर नियुक्त कर दिया जायगा परंतु उस पद के जिस पद से उसे अधिरोप किया गया था, अनुपेय वेतन और वेतनमान का संरक्षण नहीं दिया जायगा।

3 आमेलन समितिया —अधिरोप कर्मचारियों का आमेलन करने के लिए निम्नलिखित आमेलन प्राधिकारी होंगे —

(क) निम्नलिखित व्यक्तियों की आमेलन समिति राज्य भर के आमेलन की प्रभारी होगी। यह समिति राज्य सेवाभा और अधीनस्थ सेवाभा में के राज्य भर के अधिरोप लोगों के तथा जयपुर नगर में अधिरोप हुए लिपिक वर्गीय एवं चतुथ श्रेणी कर्मचारियों के आमेलन का आदेश देगी।

(1) वित्तमंत्री	अध्यक्ष
(2) वित्त आयुक्त	सदस्य
(3) विशिष्ट सचिव (नियुक्ति)	सदस्य
(4) उप सचिव (मंत्रिमंडल)	सदस्य-सचिव

(ख) समस्त कलक्टर अपने अपने जिला में, जयपुर नगर को छोड़कर, लिपिक वर्गीय एवं चतुथ श्रेणी कर्मचारियों के आमेलन के लिए जिम्मेदार होंगे।

4 आमेलन समिति को किसी भी अधिरोप कर्मचारी का समानित या किसी अन्य पद पर किसी भी विभाग में आमेलन करने का आदेश देने की पूर्ण एवं अंतिम शक्तियां होंगी। आमेलन या तो सीधी भर्ती की या फिर पदोन्नति काटा में होने वाली रिक्तियों के प्रति किया जा सकता है और चयन वेतनमान पदों के प्रति भी

किया जा सकता है किन्तु सामान्यतया चयन वेतनमान पद आमेसन के लिए तभी काम में लिए जायेंगे जब कि अधिशेष कमचारी समान प्रकार के कर्तव्य से युक्त किसी समतुल्य पद से अथवा जिस पद पर आमेसन किया जाता है उससे उच्चतर पद से अधिशेष घोषित किया गया हो। सबधित नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे आमेसन आदेश प्राप्त होने पर शीघ्र ही नियुक्ति आदेश जारी करेगा और इसकी सूचना आमेसन प्राधिकारी को देगा। आमेसन आदेश प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी को ग्रहताभा के आधार पर न तो कोई आमेसन करना चाहिए और न आमेसित कमचारियों को ड्युटी पर लेने में विलंब करना चाहिए। यदि किसी मामले में आमेसन समिति ग्रहताभा को शिथिल करना आवश्यक समझती हो तो नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति (क) विभाग को चाहिये कि अधिशेष कमचारियों को उस विभाग में उचित स्थान देने के लिये सेवा नियमों में मंशोधन यदि आवश्यक हो, कराने के लिए भी माय साथ आवश्यक कार्यवाही करे। नियुक्ति प्राधिकारी को अतिरिक्त ग्रहता, जो नियमों में गूनात्म ग्रहता के रूप में विहित नहीं है (जैसे कि वनिष्ट लिपिक के लिए टकण का अनुभव) के आधार पर भी आमेसन नहीं करना चाहिए बल्कि कमचारी का विभाग में ही समायोजन कर लेना चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो आमेसित कमचारी से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह किसी परिसीमित कानून वधि के भीतर कोई विशिष्ट प्रशिक्षण अथवा विशिष्ट प्रवीणता अर्जित करले।

5 प्रतिवर्तन —यदि उस अधिशेष व्यक्ति के आमेसन पर जो कि उसके पुराने पद पर स्थानापन्न अथवा अस्थायी था, यह पाया जाय कि उसी/विभाग/कार्यलय में अगली नीचे की ग्रेड में ऐसे स्थायी व्यक्ति भी उपलब्ध है जो कि आमेसित व्यक्ति की अपेक्षा नहीं अधिक लम्बे समय से स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं तो आमेसित व्यक्तियों को अगले नीचे के पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। नये विभाग में आमेसित किये जाने पर सरकार अधिशेष कमचारियों को उनकी पिछली सेवा का लाभ देना चाहती है लेकिन जब तक कि इस बारे में विस्तृत अनुदेश तथा नियम जारी कर दिये जायें नये विभाग में किसी भी कमचारी को ऊपर वहे गये के सिवाय सेवा की अवधि कम पढ़न के आधार पर प्रतिवर्तित या सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। उनकी वरिष्ठता की परीक्षा उहे विभाग क उस वनिष्ठतम कमचारी के जिसकी उसी ग्रेड में सेवा की अवधि बराबर हो ठीक नीचे अस्थायी तौर पर रखते हुए की जानी चाहिए।

6 नयी नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध —समस्त तकनीकी या गैर तकनीकी रिक्त पद जिन पर नयी भर्ती किये जाने का प्रतिबन्ध है। 10 60 से पहले भेजी गयी अभ्यपक्षा के अनुसार राजस्थान लोकसेवा आयोग की सलाह पर किए गए स्थानांतरण/की गई पदोन्नति द्वारा उई नियुक्ति के सिवाय किसी कमचारी को अथ विभाग से स्थानांतरण कर या किसी कमचारी की विभाग के ही भीतर पदोन्नति कर नहीं भरे जायेंगे। लिपिक वर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी कमचारियों के सर्वगों के आमेसित अधिशेष कमचारी साधारणतया उस जिले से अथ जिले में स्थानांतरित नहीं किये जायेंगे जिनमें कि वे आमेसित किये गये थे या जो उनका गृह जिले हो।

7 समाप्त किय गये पदों और अधिशेष किय गये कार्मिकों से सबधित सूचना —जब कभी किसी विभाग में पदा की समाप्ति का आदेश जारी किया जाय,

प्रशासनिक विभाग द्वारा आमेलन समिति के सदस्य सचिव को तुरंत उसकी एक प्रति भेजी जायगी। राजपत्रित अधिकांश, अधीनस्थ सेवा अधिकारियां, लिपिक वर्ग के कमचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बारे में अलग अलग विवरण भेजे जाने चाहिए।

8 पदा को उत्साहित करने वाले आदेश के आधार पर अधिशेष दिय गये व्यक्तियों के नाम तुरंत आमेलन समिति/क्लकटर को, जैसी भी स्थिति हो, प्रशापित कर दिय जायेंगे। कमचारियों को, वरिष्ठता के ठीक विपरीत क्रम में अधिशेष घोषित किये जाने चाहिए अर्थात् कनिष्ठतम सर्वप्रथम अधिशेष घोषित किया जाय। किसी व्यक्ति को अधिशेष घोषित किए जाने से पहले आमेलन समिति को स्पष्ट एक माह की पूर्व सूचना दी जाएगी। आमेलन प्राधिकारी को प्रशापना, सलग्न प्ररूप में प्रमाण पत्र के सहित, प्ररूप (उपाध्यक्ष) में भेजी जायगी जिससे कि विभागाध्यक्ष द्वारा व्यक्तियों को अधिशेष घोषित किए जाते समय कोई अनियमितता न हो। यदा कदा अधिशेष कमचारियों की विशिष्टियां समय पर प्राप्त नहीं होती और इस तरह इस पर जोर दिया जाता है कि व्यक्तियों को वास्तविक रूप से अधिशेष घोषित करने तथा उन्हें उनके पद के कर्तव्यों से मुक्त करने से यथेष्ट समय पूर्व विशिष्टियां भेज दी जानी चाहिए। विभागाध्यक्षों के पास अधिशेष कमचारियों के सेवाभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में उन्हें स्वयं कर्मचारी द्वारा दी गई विशिष्टियों के आधार पर अनन्तिम रूप से तैयार कर लिया जाना चाहिए।

9 विभाग के भीतर आमेलन —समस्त विभागाध्यक्षों से निवेदन है कि सर्वप्रथम वे विभाग के भीतर ही आमेलन की सभावनाएं खोजें। ऐसा करते समय विभागाध्यक्षों को चाहिए कि अधिशेष कमचारियों को विभाग में ही उन समान पदों पर समायोजित करने का प्रयत्न करें जिसके लिए वे ग्रहण तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभाग में श्रम्य वैसे ही पद के कमचारियों को, जो सेवा में कनिष्ठ हैं प्रतिवर्तित या सेवानिवृत्त कर देना चाहिए। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभाग में कनिष्ठ या अनग्रह कमचारी असम्भव रूप से प्रतिधारित न कर लिए जायें, ऐसे विभागीय आमेलन की आमेलन प्राधिकारी से पुष्टि कराली जानी चाहिए।

10 अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के कमचारियों का प्रतिधारण — व्यक्तियों को अधिशेष घोषित करते समय विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कमचारी यदि उन्हें विभिन्न विभागों में उनके कोटा के लिए आरक्षित पदा पर ऐसे वर्गों से अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए गठित विशेष भर्ती बोर्ड की सिफारिश पर नियुक्त किया गया था, अधिशेष घोषित नहीं किया जाये।

11 अधिशेष कर्मिक को वेतन का सदाय —राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये गये या 1-10 65 को एक वर्ष से अधिक की सेवा वाले कर्मचारी उस बालावधि का वेतन जिसमें वे अधिशेष रहे, निम्न प्रकार से प्राप्त करेंगे —

(क) आमेलन समिति द्वारा आमेलित किये जाने वाले समस्त कर्मचारी, आमेलन समिति के सदस्य सचिव के आदेश के अधीन,

(ख) सबधलत कलकटरु के आदेश के अधीन उस स्टाफ का जिसके आमेसन के लिए वे सक्षरु हल । उह उड सचलव (सामांय प्रशासन वलभाग-ख) को प्रति माह इसके लेवे भेजने हागे,

(ग) यह ध्यय आंय व्ययक के शीघ

“19 -सामांय प्रशासन ड जलला (क) जलला स्थापना अंतरक कम चारुी वग का वेतन तथा भत्ते ’ म प्रमांय होगा ।

12 प्रगति प्रतिवेदन —कलकटरु आमेसन समिति को अधिशेष स्टाफ के आमेसन के सबध मे 1-4 66 स एव मासिक प्रगति प्रतिवेदन जललो म आमेसन पूरा होने तक भेजते रहगे ।

13 कू कि आमेसन यथासक्य शीघ्र पूरा किया जाना है अत वलभिन्न स्तरा के अधिकारलया सो अनुरोध किया जाता है कि उघर दलये गये वलनलषच्या और नलदेशो पर दैयक्तलक रूप स ध्यान द तथा मावश्यक आदेश जारी करने और मावश्यक सूचना देने के लिए तुरत कायवाही करें ।

14 यह आदेश वलक्त (नलयरु) वलभाग तथा नलयुक्त(क) वलभाग की सरया 4661/पी ए /एफ सी /6० ग्लनाक 25-4 66 एव 12513/पीए/एसएसए/65 दलनाक 27-12-1965 द्वारा दी गई उनकी सहमति सो जारी किया जाता है ।

अधिशेष कमचारलयो की वलशलष्टलया प्रस्तुत करने क लिए प्ररूप

- 1 क्रम सरया
- 2 जिस पद की छटनी की गई उसका नाम
- 3 जिस पद की छटना की गई उसका वेतनमान
- 4 पद धारण करने वाले कमचारुी का नाम उसके पिता का नाम सहित
- 5 1-10 65 को कमचारुी की आंयु
- 6 शैलिक अहतायें
- 7 जिस पद की छटनी की गई उस पर नलयुक्ति की तारलख
- 8 नलयुक्ति किस प्रकार की है ? आंया अधलष्ठांयी अथवा अस्थायी
- 9 कया पद भरने के लिए लाक सेवा आंयोग की सहमति - आवश्यक है ?
- 10 कया व्यक्तल की नलयुक्ति के वारे मे लोक सेवा आंयोग ने सहमति द दी है अथवा नही ?
- 11 कया नलयुक्ति सेवा नलयरुो के अनुसार की गई है ?
- 12 कया कलसी अंय पद पर अधलष्ठांयी रूप से नलयुक्ति हो चुकी है ?
- 13 ऐसे पद का नाम और उसका वेतनमान ।
- 14 छटनी कलये गये पद पर की गयी नलयुक्ति से पूव की नलयुक्तलयो की, यदल कोई हो, वलशलष्टलया ।

वलभागाल्यक्ष के हस्ताक्षर

किसी कर्मचारियों को विभाग की आवश्यकता से

अधिशेष घोषित किये जाने का प्ररूप

राजस्थान सरकार के विभाग के पत्र स  
दिनांक के अनुसार पदों की समाप्ति के फलस्वरूप श्री  
निम्नलिखित कर्मचारी/कर्मचारियों को

दिनांक से इस विभाग से अधिशेष घोषित किया जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिशेष घोषित कर्मचारी सबग में कनिष्ठतम है/हैं तथा अनु ज जाति का नहीं है। के नहीं हैं। यह और प्रमाणित किया जाता है कि विभागीय तौर पर उसे/उहे आमेलित किये जाने के सारे प्रयत्न किये जा चुके हैं लेकिन उसके/उनके आमेलन के लिये कोई उपयुक्त पद उपलब्ध नहीं था/थे।

यदि वह/वे ऐसे पद/पदों तथा ऐसी शर्तों पर आमेलित किये जाने का इच्छुक हैं/के इच्छुक हैं, जैसा आमेलन समिति द्वारा विनिश्चित किया जाय तो उसे/उहें इसके लिये सामान्य प्रशासन (ग) विभाग में उपस्थित होना चाहिये, ऐसा न करने पर यह उपाधारित किया जायगा कि वह/वे आमेलित किये जाने में रुचि नहीं रखता/रखते और तब वह सेवा समाप्ति के नोटिस के रूप में माना जायगा।

उसके/उनके आमेलन के बारे में यात्रा के लिये वास्तविक यात्रा की कालावधि के भलावा और कोई कायग्रहण काल अनुज्ञात नहीं किया जायगा।

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट—[ 2 ]

## राजस्थान सिविल सेवा

\*[अस्थायी कर्मचारियों की अधिष्ठायी नियुक्ति तथा  
वरिष्ठता निर्धारण] नियम 1972

[Rajasthan Civil Services (Substantive Appointment &  
Determination of Seniority of Temporary Employees) Rules, 1972]

६ नियुक्ति (क-II) विभाग की विनियम सं० एफ 1 (9) नियुक्ति (क-II)  
71 दिनांक 14 9 1972 जो राजस्थान राजपत्र भाग IV (ग) दि  
14 9 1972 को पृष्ठ 284-287 पर प्रकाशित हुए व इसी दिनांक से  
प्रवृत्त (लागू) हुये। [अप्राधिकृत हिंदी अनुवाद]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल अस्थायी कमचारियों की अधिष्ठायी नियुक्ति तथा बरिष्ठता का निर्धारण करने के लिए उपबंध करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं—अर्थात् —

1 सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) ये नियम 'राजस्थान सिविल सेवायें (अस्थायी कमचारियों की अधिष्ठायी नियुक्ति तथा बरिष्ठता निर्धारण) नियम 1972" कहलायेंगे।

(2) ये तुरत प्रभाव से प्रवृत्त (लागू) होंगे।

2 परिभाषायें—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में—

(1) (क) अस्थायी कमचारी 'से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अनुसूची (क) में वर्णित अस्थायी या स्थायी पद पर, केन्द्रीय प्रवर्तित परियोजना (Centrally sponsored scheme) के अधीन सृजित पद धारण करने वाले व्यक्ति को छोड़कर, तदर्थ (एडहाक) या अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था,

(ख) अनुसूची से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयोग में लिये गये तथा परिभाषित नहीं किये गये अन्य समस्त शब्दों और पदों का अर्थ वही होगा जो उनको राजस्थान सेवा नियम 195, राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 तथा अनुसूची (ख) में वर्णित सम्बन्धित सेवा नियमों में क्रमशः दिया गया है।

3 निवचन (अर्थात् चयन)—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं 8) इन नियमों के निवचन के लिये उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निवचन के लिए लागू होता है।

4 अस्थायी कमचारियों का पुष्टीकरण (कनफर्मेशन)—(1) अनुसूची (ख) में वर्णित सेवानियमों में से किसी में या अनुसूची (क) में वर्णित पदों में किसी की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य नियम या आणामों में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित श्रेणियों के समस्त अस्थायी कमचारियों को जो 14 1964 को या इससे बाद किंतु 14 1968 के पहले नियुक्त किये गये थे इनमें ऐसे भी सम्मिलित हैं जो बाद में सेवा या सवग के भीतर या सेवा या सवग से बाहर उक्त अवधि के भीतर उच्चतर पदों पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये हैं और ऐसे पदों को मग उच्चतर पदों के इन नियमों के प्रवृत्त होने के दिनांक तक लगातार धारण किये हुये हैं, (वे समस्त कमचारी) इन नियमों के प्रवृत्त होने के दिनांक से उन पदों पर जिन पर उनको प्रारम्भ में नियुक्त किया गया था स्वतः, पुष्टीकृत (स्थायी) हो जायेंगे—

(क) सप्तस्त तृतीय श्रेणी के अध्यापक, जो सेवे-डरी, मेडिकुलेशन या हायर सेके-डरी मय एस टी सी की न्यूनतम ग्रहता रखते हों, सरकार द्वारा समय समय पर (i) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1961 तथा (ii) राजस्थान सिविल सेवा (नवीन वेतनमान) नियम 1968 के अधीन अधिसूचित किये गये अनुभव तथा विशेष विषयो व शिथिलीकरण के अधीन रहते हुए,

(ख) समस्त कनिष्ठ लिपिक, जो सेवे-डरी, मेडिकुलेशन या हायर सेके-डरी की न्यूनतम ग्रहता रखते हों,

(ग) अनुसूची (क) में वर्णित अन्य पदों के धारक, परन्तु शत यह है कि वे अनुसूची (ख) में वर्णित सेवा नियमों या उस समय प्रवृत्त अन्य किसी नियमों या आज्ञाओं में उपबोधित उस समय आरम्भिक नियुक्ति के लिये ऐसे पदों के लिए विहित शैक्षणिक, व्यावसायिक और अन्य ग्रहतायें और अनुभव रखते हों तथा आगे शत यह भी है कि—यदि ऐसे नियमों या आज्ञाओं में नियुक्ति से पहले भर्ती की ग्रहता परीक्षा उत्तीर्ण करना या नियुक्ति के बाद विहित अग्रघ में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने का उपबोध हो, तो वे ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे ।

(ii) अनुसूची (ख) में वर्णित सेवा नियमों में या अन्य नियमों या आज्ञाओं में विहित उच्चतम आयु सीमा उपनियम (1) के खण्ड (क) से (ग) में वर्णित व्यक्तियों के मामले में शिथिल कर दी गई समझी जावेगी ।

(iii) अनुसूची (ख) में वर्णित सेवा नियमों में से किसी में या अनुसूची (क) में वर्णित पदों में से किसी की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले तरसमय प्रवृत्त किसी अन्य नियम या आज्ञाओं में किसी बान के होते हुए भी, 14 964 से पहले के नियुक्त किये गये समस्त अस्थायी कर्मचारी और जो बाद में सेवा या सबग के भीतर या सेवा या सबग से बाहर उच्चतर पदों पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये हैं और जो ऐसे पदों को मय उच्चतर पदों के इन नियमों के प्रवृत्त होने के दिनांक तक लगातार धारण किये हुए हैं, (वे समस्त कर्मचारी) आयु सीमा, ग्रहतायें तथा अनुभव और सम्बन्धित सेवा नियमों में उपबोधित भर्ती के तरीके के शिथिलीकरण में इन नियमों के प्रवृत्त होने के दिनांक से उन पदों पर जिन पर उनको आरम्भ में नियुक्त किया गया था स्वतः स्थायी हो जायेंगे ।

(iv) उपनियम (1) तथा (iii) के अधीन ऐसे अस्थायी कर्मचारी के मामले में उस श्रेणी के स्थायी पद पर, जिस पर आरम्भिक नियुक्तियाँ की गई थी और जो अधिष्ठायी रूप से रिक्त हैं पुष्टीकरण किया गया माना जावेगा, परन्तु यह है कि— ।

(i) ऐसे स्थायी पदों के न होने पर, ऐसी श्रेणी के अस्थायी पद स्थायी पदों में परिवर्तित हो जायेंगे और उन पर पुष्टीकरण किया गया समझा जावेगा, और

(ii) अस्थायी प्रयोजन के लिये, जैसे परियोजना निर्माण, राहत कार्य आदि, सृजित पद परन्तु (i) के अधीन स्थायी पदों में परिवर्तित हो जायेंगे तथा एक

अस्थायी कमचारी जो ऐसे पदों पर प्रारम्भ में नियुक्त किया गया था अथवा अस्थायी पदों से स्थायी पदों में परिवर्तित पद था इस प्रयोजनाथ सृजित अधिसूचक पद पर स्थायी किया जावेगा ।

5 वरिष्ठता—नियम 4 के उपनियम (i) या (iii) के अधीन पुष्टीकृत (स्थायी) व्यक्तियों की वरिष्ठता निम्नांकित तरीके से विनियमित होगी—

(क) ऐसे व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता अस्थाई या तदर्थ रूप में उनकी लगातार सेवा की लम्बी अवधि के द्वारा तय की जावेगी

(ख) ऐसे व्यक्ति अनुसूची (ख) में वर्णित सेवा नियमों के अनुसार इन नियमों के प्रवृत्त होने से पहले भर्ती किये गये समस्त व्यक्तियों में वरिष्ठ होंगे ।

6 सूची की अधिवर्धना—नियम 4 के उपनियम (1) या (iii) के अधीन स्थायी (पुष्टीकृत) किये गये व्यक्तियों की सूची और उपनियम (iv) के अधीन स्थायी किये गये पदों की सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक विभाग के सम्बन्ध में तैयार की जावेगी और सूचना पट (नोटिस बोर्ड) पर अधिसूचित की जावेगी और उनकी प्रतिया प्रशासनिक विभाग के शासन-सचिव को तथा नियुक्ति (कल्याण) विभाग के शासन सचिव को संप्रेषित की जावेगी ।

7 शकाओं का निराकरण—यदि इन नियमों के लागू होने, इनका अर्थ करने और इनके विस्तार के बारे में कोई शका उत्पन्न हो, तो मामला सरकार के पास नियुक्ति विभाग में आदेशाथ भेजा जावेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

### अनुसूची "क" [देखिये—नियम 4]

राजस्थान लोक सेवा आयोग के परिक्षेत्र से बाहर के पद

(1) चपरासी और वेतनमान स 1, 2 तथा 2-क में तत्समान पद,

(2) कनिष्ठ लिपिक (L D C),

(3) टेलिफोन-प्रबालक वेतनमान स० 7 में

(4) सगणक वेतनमान स 9 में

(5) चालक (डाइवर) भय ट्रैक्टर तथा बस चालकों के वेतनमान स 7 में

(6) पटवारी,

❧ (6क) वन विभाग के अमीन

(7) आबकारी तथा वाणिज्यिक कर विभागों में सिपाही ।

❧ वि स एफ । (9) नियुक्ति (क-2) 71 जी एम आर 58 दिनांक 31 7-78 द्वारा निविष्ट तथा 14 सितम्बर 1972 में प्रभावी ।  
(1978 RLT 379)



(8) वेतनमान स 6 तथा इससे निम्न (वेतन मानों) में अधीनस्थ सेवाम्रा के समस्त पद, जो किसी विशेष विभाग के अधीन वर्णित न हो, परंतु जो सरकार की आज्ञाओं के अनुसार, सीधी भर्तों द्वारा सेवा नियमों के अनुसरण में भरे जा चुके हैं या भरे गये हैं, और पदोन्नति द्वारा नहीं तथा जो प्रायोग के परिक्षेत्र के बाहर हैं।

### अनुसूची (ख,—[देखिये-नियम 4]

- 1 राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय (मन्त्रालयिक) सेवा नियम 1970
- 2 राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय (मन्त्रालयिक) स्थापन नियम 1957
- 3 राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवामें (भर्तों तथा अन्य शर्तें) नियम 1962
- 4, राजस्थान साक्ष्यकी अधीनस्थ सेवा नियम 1971
- 5 राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा (श्रेणी I) नियम 1955
- 6 राजस्थान अधीनस्थ देवस्थान सेवा (श्रेणी II) नियम 1954
- 7 राजस्थान सरकारी मुद्रणालय अधीनस्थ सेवा नियम 1956
- 8 राजस्थान खान एवं भूगर्भ अधीनस्थ सेवा नियम 1960
- 9 राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1966
- 10 राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965
- 11 राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्तों एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम 1960

### परिपत्र

विषय दिनांक 14-9-1972 के बाद और अन्य विभागों/कार्यालयों में स्थानान्तरित कनिष्ठ लिपिकों का पुष्टीकरण

[स० एफ 1 (9) नियु (क-2) 71 दिनांक 18-1 1974]

इस विभाग के ध्यान में ऐसे उदाहरण आये हैं, जिनमें कुछ कनिष्ठ लिपिकों द्वारा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जो रा सि मे (स्थायी नियुक्ति एवं अस्थायी कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण) नियम 1972 के अधीन 14 9 1972 से पुष्टीकरण के हकदार थे किंतु उस दिनांक के बाद में उस विभाग/कार्यालय से जिसमें वे काम कर रहे थे, दूसरे विभाग/कार्यालय में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं। शक्यों उठाई गई कि—वह कर्मचारी किस विभाग/कार्यालय में स्थायी (कर्मस्थ) किया जावेगा तथा किस दिनांक से ?

वित्तविभाग से परामर्श से इस मामले की परीक्षा की गई और यह अभि-निर्धारित किया गया कि — सम्बन्धित लिपिक अधीनस्थ विभाग/कार्यालय में

॥ वर्षे मर्यादा मशोचित— वि स एफ 1 (9) नि (क 2) 71 दिनांक 3 1 73 द्वारा ।

जिसमें वह 14-9-72 को काय कर रहा था, स्थायी किये जाने का हकदार है और यह केवल उसका व्यक्तिगत हक होगा। उसके स्थानान्तर के बाद अन्य विभाग या कार्यालय में वह कनिष्ठ लिपिक अपना व्यक्तिगत स्थायी स्तर साथ ले जायेगा। नये विभाग या कार्यालय में वह स्थायी या अचिण्ठायी माना जावेगा और यदि आवश्यकता हो तो इस प्रयोजनाथ अस्थायी पदा में से एक को केवल ऐसे समय तक के लिये जब तक कि वह विशिष्ट कनिष्ठ लिपिक उन पदा पर अपना पदाधिकार धारण करे, स्थायी बनाया जा सकेगा। पहले विभाग/कार्यालय में जहाँ से वह सम्बन्धित लिपिक स्थानान्तरित किया गया था, उसके स्थान पर 14-9-72 से भर्ती किया गया कोई अन्य व्यक्ति इस आधार पर पुष्टीकरण का अधिकार प्राप्त नहीं करेगा कि— कनिष्ठ लिपिक जो 14-9-72 को इस पद को धारण करता था दूसरे विभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया है, जब तक कि अपना वह पुष्टीकरण के लिये उपरोक्त नियमों को ध्यान में लिये बिना पात्र न हो।

उपरोक्त नियम एक अधीनस्थ विभाग/कार्यालय से दूसरे अधीनस्थ विभाग/कार्यालय को स्थानान्तरित कनिष्ठ लिपिकों के लिये लागू होगा। सचिवालय के मामले में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्तियाँ किसी अधीनस्थ विभाग/कार्यालय से स्थानान्तर द्वारा वास्तव में नहीं की जाती हैं। येन केन एक व्यक्ति किसी अधीनस्थ कार्यालय में पहले से काय करते हुए दूसरे के साथ प्रतियोगिता में भाग ले सकता है और जो चयनित होते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है। अतः एक कनिष्ठ लिपिक को जो 14-9-1972 को किसी अधीनस्थ विभाग/कार्यालय में काय कर रहा था और जो बाद में कनिष्ठ लिपिक के रूप में सेवा में व्यवधान के बिना सचिवालय में नियुक्त किया जाता है, उसको उस विभाग/कार्यालय में जहाँ वह 14-9-72 को काय कर रहा था, स्थायी किया जायेगा और उसे सचिवालय में केवल तभी स्थायी किया जायेगा जब सामान्यतया उसके पुष्टीकरण की बारी आयेगी और जब तक वह सचिवालय में स्थायी नहीं किया जावेगा, उसका पदाधिकार उस पतुक विभाग/कार्यालय में रहेगा, जिसमें वह 14-9-72 को काय कर रहा था।

उपरोक्त नियमों के अधीन विचाराधीन पुष्टीकरण के समस्त मामले नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा इसी प्रकार से निपटाये जा सकेंगे।



चाहिये, ताबि यथोचित वय के सदम मे, ऐसे रिक्तस्थाना के विरुद्ध सरकारी उनकी नियुक्तिया कर सके ।

अत अव भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक के अधीन प्राप्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल प्रसन्न होकर निम्नलिखित नियम बनाते हैं —

1 सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) ये नियम “राजस्थान सेवायें (पूर्ववर्ती वर्षों की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियम 1972” कहलावेगे ।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे ।

2 जहाँ भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक के अधीन भर्ती एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करन के लिय बनाया गया कोई सेवा नियम भर्ती के लिय सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों द्वारा भर्ती का उपबन्ध करता है और जहा किसी पूर्ववर्ती वर्ष का पदोन्नति—कोटा उस नियम के अन्तगत नियुक्त विभागीय पदोन्नति-समिति की अभिशप्ता के अभाव मे नहीं भरा जा सका, तो नियुक्ति प्राधिकारी उस वर्ष का उल्लेख करते हुए जिसके रिक्तस्थानो को भरना है, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानो की सख्या निर्धारित करेगा ।

❧ [टिप्पणी— ‘राजस्थान प्रशासन सेवा के मामले मे शब्द ‘पदोन्नति’ मे सवाम ‘चयन द्वारा’ और ‘विशेष चयन द्वारा’ भर्ती भी सम्मिलित होंगी]

3 नियम 2 मे वर्णित सेवा नियमो के अधीन नियुक्त विभागीय पदोन्नति समिति सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिक्त स्थानो की सख्या का निर्धारण करन तथा पूर्ववर्ती वर्षों के रिक्त स्थानो के वर्षों का नियमाधीन उल्लेख करने की दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर अपनी अभिशप्ता करेगी । तत्पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशप्ताओ को उचित सम्मान देते हुए नियम 2 मे वर्णित सम्बद्ध वर्ष के पदोन्नति के कोटे के रिक्तस्थानो मे पदोन्नति द्वारा उनकी नियुक्तिया करेगा ।

4 जब नियुक्ति प्राधिकारी नियम 3 के अधीन पदोन्नति द्वारा नियुक्तिया करता है, तो वह उस वर्ष का उल्लेख करेगा, जिसमे ऐसी पदोन्नतिया की गई मानी जावेगी ।

5 जहाँ विभागीय-पदोन्नति समिति की अभिशप्ता पर पदोन्नति द्वारा की गई नियुक्ति के वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष मे पदोन्नति कोटा मे कोई रिक्त स्थान विद्यमान था तो नियुक्ति प्राधिकारी उस नियुक्ति आज्ञा को उस वर्ष का उल्लेख करते हुए जिसमे पदोन्नति की गई सम्झी जावेगी, संशोधित करेगा ।

6 जहा पदोन्नति द्वारा कोई नियुक्ति नियम 3 के अधीन की गई है या जहा नियुक्ति प्राधिकारी ने नियम 5 के अधीन पदोन्नति के वर्ष का उल्लेख किया है, ता

❧ वि स 1(7) Appts (A-II) 71 दिनांक 9 नवम्बर 1977 द्वारा जोड़ा गया तथा दि 7-1 1972 से प्रभावी ।

वह व्यक्ति जो इस प्रकार पदोन्नत किया गया है, उस किसी अवधि के लिये उसने उस पद के कर्तव्यों का वास्तव में परिपालन नहीं किया है जिस पद पदोन्नत किया गया है, किसी बकाया वेतन की मांग के लिये अधिकृत नहीं होगा।

\*[6-क—सम्बन्धित सेवा नियमों में किसी बात के होते हुए, वे व्यक्ति सम्बन्धित सेवा में इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किये गये हैं, सेवा में उनके अनुभव की सगणना के प्रयोजनार्थ, सम्बन्धित सेवा में उसी नियुक्त किया गया समझा जावेगा, जिस (व्य) से वह कोटा सम्बन्धित है।]

## परिशिष्ट [ 4 ]

### राजस्थान सिविल सेवायें

[सरकार द्वारा अधिग्रहीत निजी-संस्थानों तथा अन्य स्थापनाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति की शर्तें]

#### ×नियम 1977

[Rajasthan Civil Services (Appointment and Service Conditions of employees of Private Institutions & other establishments taken over by the Government Rules, 1977]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल सरकार द्वारा अधिग्रहीत निजी संस्थानों तथा अन्य स्थापनाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं —

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) ये नियम “राजस्थान सिविल सेवायें (सरकार द्वारा अधिग्रहीत निजी संस्थानों तथा अन्य स्थापनाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम 1977 कहलायेंगे।

\* वि स एफ 1 (7) नियुक्ति (क-II) 71 दिनांक 9 नवम्बर 1971 द्वारा जोड़ा गया तथा दि 7-1-1972 से प्रभावी।

× वि स एफ 5 (5) वार्षिक 1 (क-2) 76 दिनांक 28 दिसम्बर 1977, राजस्थान राजपत्र 'असाधारण भाग 4 (ग) 1 दिनांक 28 10 1977 पृष्ठ 279—(1977 R L T 545) पर प्रकाशित। अतः ये नियम 28 10 77 से प्रभावशील होंगे।

[अप्राधिकृत हिन्दी अनुवाद]

(ii) ये राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(iii) अधिग्रहीत निजी सस्थानों तथा अन्य स्थापनों के व्यक्तियों की इन के प्रवृत्त होने से पहले की गई नियुक्तियाँ इन नियमों के तत्सम्बन्धी प्रावधानों के अधीन की गई समझी जाएंगी।

(iv) ये नियम इन नियमों के प्रवृत्त होने के पहले सस्थानों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों पर भी लागू होंगे, सिवाय उस सेवा या पद के मामले में जिसके सेवा नियमों में इस प्रयोजन के लिये निश्चित उपबन्ध विद्यमान हैं, और जहाँ तक ये नियम किसी व्यक्ति को अलाभकर रूप से प्रभावित नहीं करते हों।

2 परिभाषाएँ—(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है और इसमें सेवा में किसी पद के सम्बन्ध में ऐसे अन्य अधिकारी या प्राधिकारी सम्मिलित हैं जो सरकार की स्वीकृति से नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों तथा कार्यों का प्रयोग करने के लिये विशेष रूप से सशक्त हैं।

(ख) ‘आयोग’ से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है,

(ग) “सरकार” तथा ‘राज्य’ संक्रमण राजस्थान-सरकार तथा राजस्थान-राज्य अभिप्रेत हैं,

(घ) “निजी सस्थान (प्राइवेट इस्टीब्लिशमेंट)” से एक शैक्षणिक सस्थान, अस्पताल या या अन्य कोई स्थापन जो किसी सहाय, सरकार या स्थानीय सस्था या पंचायत समिति या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य सहाय के अतिरिक्त, द्वारा संचालित या व्यवस्थापित है अभिप्रेत है।

3 इन नियमों का अध्यारोही प्रभाव—ये नियम तथा इनके अधीन जारी की गई आज्ञाएँ इन नियमों के आरम्भ होने के समय प्रवृत्त किसी नियम विनियम या आज्ञा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी लागू होंगे।

परन्तु यह है कि—इन नियमों के आरम्भ से पहले अधिग्रहीत निजी-सस्थानों के व्यक्तियों की विभिन्न नियमों के अधीन पदों की श्रेणियों पर की गई नियुक्तियाँ इन नियमों के नियम 5 के उपनियम (2) के अधीन की गई समझी जाएंगी।

4 निवचन (ध्याएया)—जब तक सदन से अथवा अपेक्षित न हो राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 8) इन नियमों के निवचन के लिये उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निवचन के लिये लागू होता है।

5 निजी सस्थानों का अधिग्रहण—

(1) किसी मामले में सरकार किसी निजी सस्थान को उसके स्थापन (स्टाफ) सहित जनहित में अधिग्रहीत करने का विनिश्चय करती है तो वह ऐसा सस्थान तथा सरकार के अधीन विद्यमान पदों के समीकरण का विनिश्चय करेगी और सरकारी सेवा में शामिल होने के इच्छुक ऐसे स्थापनों को जो उस सस्थान में सेवा

कर रहे हैं या पदाधिकार धारण करते हैं और सेवा में पदों तथा रिक्त स्थानों की उलब्धता के अधीन रहते हुए उनको समानोद्भूत या निम्नतर पद पर नियुक्त किया जा सकेगा, जैसा कि समिति द्वारा छानबीन करने के बाद निम्नांकित शर्तों के अधीन रहते हुए विनिश्चित किया जावे, यह (समिति) वही विभागीय पदोन्नति समिति होगी जो सम्बन्धित सेवा नियमों में सम्बन्धित पद के लिये गठित की गई हो या यदि ऐसी कोई समिति न हो, तो ऐसी समिति जो सरकार द्वारा नियुक्त की जायें—

( ) ऐसे सस्थान के कमचारी, जो सेवा में आगमन के लिये अभ्यर्थी हैं, उस पद के लिये जिनके लिये वे अभ्यर्थी हैं, नियमों/अनुसूची में वर्णित न्यूनतम अहताशों को धारण करता है या ऐसी अहताशें धारण करता है जो सरकार द्वारा सम्बन्धित पद के लिये विहित थी, जब कि वह ऐसे पदों पर प्रारम्भ में नियुक्त किया गया था।

(ii) निजी सस्थान को सरकार द्वारा अधिग्रहीत करने के दिनांक की अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम न हो और सरकार द्वारा विहित ऐसे पद के लिये अधिवापिकी की साधारण आयु से अधिक न हो।

(iii) कर्मचारी शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो और इन नियमों या सम्बन्धित पद के लिये तत्सम्बन्धी सेवा नियमों में वर्णित शर्तों के लिये अनहताशों में से किसी से ग्रस्त न हो।

परन्तु यह है कि—सरकार द्वारा अधिग्रहीत किये जाने के बाद, निजी सस्थान में सेवा कर रहे अभ्यर्थियों की सत्या, जो सेवा में प्रवेश के लिये इस प्रकार चयनित किये गये हैं, उस निजी सस्थान के लिये सभ्य प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पदों की सत्या से अधिक नहीं होगी, जब तक कि सरकार अथवा तय न करे।

(2) इस प्रकार चयनित व्यक्तियों की सरकारी सेवा में नये रिक्त समझा जावेगा और सम्बन्धित सेवा में भर्ती का कोटा, यदि कोई हो, ऐसे व्यक्तियों को आमेलित करने के बाद तय किया जावेगा और वे उसी समान स्तर (केपेसिटी) पर जैसा वे निजी सस्थान में थे—यथा—अस्थायी, स्थानापन्न, अधिष्ठायी, यथा स्थिति, नियुक्त किये जावेंगे और अधिष्ठायी या स्थायी कमचारियों के मामले में परीक्षा तथा पुष्टीकरण की शर्तें अहित्यजित कर दी गई समझी जावेंगी।

(3) निजी सस्थान के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप चयनित व्यक्तियों की वरिष्ठता ऐसी कमचारियों के अधिग्रहण के वर्ष के सदन में तय की जावेगी और वे सामूहिक रूप से (Enbloc) उन व्यक्तियों से वनिष्ठ होंगे जो उनकी नियुक्ति के वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा या पदानुति द्वारा, यदि वह पद सम्बन्धित श्रेणी में बेचल पदानुति से भरा जाना चाहिए, नियुक्त किये गये हैं। ऐसे व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, यन् वेन, ऐम प्रबन्ध/एजेसी के अधीन समान श्रेणी में जगतातर नियुक्ति के दिनांक के अनुसार स्थिर की जावगी, परन्तु यह है कि— कोई पूर्वनिश्चय वरिष्ठता की नहीं छेड़ा जायेगा। निजी सस्थान के कमचारियों द्वारा समानोद्भूत पद पर की गई सेवा पदोन्नति या सीधी भर्ती, यथास्थिति, के लिये वांछित अनुभव या सेवा के रूप में गणित किया जावेगा।

6 केन्द्रीय सरकार या स्थानीय सहाय या सरकार द्वारा नियंत्रित सहाय द्वारा संचालित या व्यवस्थित शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या अन्य किसी संस्थान का अधिग्रहण—ये नियम यथावश्यक परिवर्तन सहित उन संस्थानों या स्थापनों पर भी लागू होंगे, जो केन्द्रीय सरकार या स्थानीय सहाय या सरकार द्वारा नियंत्रित किसी सहाय द्वारा संचालित या व्यवस्थापित हैं सिवाय इसके कि—सरकार द्वारा अधिग्रहीत ऐसे संस्थान या स्थापन के कर्मचारियों की वरिष्ठता के बारे में उपबंध ऐसे होंगे जैसे सरकार द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श के बाद, जहाँ आवश्यक हो, विनिर्दिष्ट किये जायें।

7 कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति—राज्य सरकार भर्ती, परिवर्तन, पुष्टीकरण, पदोन्नति आदि से संबंधित अन्य मामलों के बारे में कोई कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से और इन नियमों के किसी उपबंध की परिपालना में जहाँ आवश्यक समझे या सही व्यवहार के हित में द्रुतगामी या जन हित में समझे, आयोग से परामर्श के बाद जहाँ आवश्यक हो, विशेष या सामान्य आज्ञा दे सकेगी।

## परिशिष्ट [ 5 ]

### 1 राजस्थान शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का नियोजन नियम 1976

[The Rajasthan Employment of the Physically Handicapped Rules 1976 ]

#### अधिकृत पाठ

जी एस आर 38 —भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य के वायकलाप संबंधी सेवाओं और पदों पर नियुक्त अक्षम व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों की विनियमित करने हेतु राजस्थान के राज्यपाल, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

- 1 वि.मं. 1 (17) DOP/A/II/72, GSR 92 दिनांक 25 सितम्बर 1976 द्वारा राज-पत्र, सप्ताहवार, भाग 4 (ग) 1 में दिनांक 25 9 1976 को प्रथम बार प्रकाशित।
- 2 अधिसूचना सं. 1 (1) विर/प्रशा/77 जी एस आर 38 दिनांक 30 मार्च 1978 द्वारा राज-पत्र दि. 22 जून 1978 में पृष्ठ 177-181 पर अधिकृत हिंदी पाठ प्रकाशित।



## राजस्थान शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का नियोजन नियम, 1976

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना —(1) इन नियमों का नाम “राजस्थान शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का नियोजन नियम, 1976” है।

(2) ये नियम राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे और अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रस्थापित किसी अन्य नियम या आदेश में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

(3) राज्य के कार्यकलाप सवधी विभिन्न सेवाओं या पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी सेवा नियम या आदेश में किसी बात के होते हुए भी शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति इन नियमों के अनुसरण में पृथक् रक्षित और आरक्षित पदों पर भर्ती और नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।

2 परिभाषाएँ —जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में—

- (i) “नियुक्ति प्राधिकारी” से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जो अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा प्रस्थापित सुसंगत सेवा नियमों के अधीन इस रूप में नियुक्त किया गया हो,
- (ii) “केन्द्रीय रजिस्ट्री” से वह प्रकोष्ठ अभिप्रेत है जो नियम 5 में के अभिज्ञान-पत्र जारी किये जाने के प्रयोजनार्थ शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण हेतु हो,
- (iii) “निदेशक” से राजस्थान के “[नियोजन के] निदेशक और ऐसा अन्य अधिकारी अभिप्रेत है जिसे इस मन्त्रालय में सरकार द्वारा शक्तियाँ प्रत्याभोजित की जाय,
- (iv) “सरकार” और “राज्य” से क्रमशः राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य अभिप्रेत है, और
- (v) “शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति” से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित है शारीरिक रूप से अक्षम निम्नलिखित प्रवर्गों के व्यक्ति —  
(क) अंधा —अंधे व हैं जो निम्नलिखित में से किसी एक से पीड़ित हैं —

(क) दृष्टि का पूर्णतः अभाव।

(ख) दृष्टि क्षमता 6/60 से या समुचित लेन्सों सहित मन्दी आँख से 20/200 (uncellan) में घटित।

\* “समाजकल्याण विभाग” के स्थान पर प्रतिस्थापित—वि स एफ। (17) DOP/A-2/72, GSZ-52 दिनांक 24 जुलाई 1978 द्वारा, राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग) 1 दि 27 7 78 पृ 218 पर प्रकाशित।

(ग) दृष्टि क्षेत्र 20 डिग्री के कोण तक सीमित या उससे बराबर ।

(क) बधिर — बधिर वे हैं जिनकी श्रवणशक्ति जीवन क सामान्य प्रयोजना हेतु क्रियाशील नहीं है । सामान्यतः 70 डेसीबिल पर या उससे ऊपर 500, 000 या 000 आवृत्तियों पर श्रवण शक्ति की हानि के कारण अवशिष्ट श्रवणशक्ति क्रियाशील नहीं रहेगी और इनमें भूक बधिर सम्मिलित होंगे ।

(ग) विकलांग — वे हैं जिनमें शारीरिक नुबश या अंग विकार हैं जिनके कारण अस्थियो, पेशिया और जोड़ों के सामान्य रूप से कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है ।

(घ) दृष्टिपूर्ण वाक्शक्ति — ऐसा व्यक्ति जो वाचाघात (वाक्शक्ति की पूर्ण हानि किन्तु श्रवणशक्ति सामान्य) से पीड़ित है या जिसकी वाक्शक्ति अस्पष्ट है तथा/या सामान्य नहीं है ।

3 पात्रता — शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति इन नियमों के नियम 4 के अधीन किसी सेवा या पृथक रक्षित पद पर नियुक्ति में पात्र होगा परन्तु यह तब जबकि वह सुसंगत सेवा नियमों में अधिकृत या जहाँ पद हेतु कोई सेवा नियम विरचित नहीं किये गये हो तो वित्त विभाग तथा कार्मिक विभाग से परामर्श के पश्चात् सरकार द्वारा अधिकृत ग्रहणाए पूरी करता हो और इन नियमों के अधीन पात्र हो और उनकी नि शक्तता होते हुए भी वह पद के कर्तव्यों का पालन करने योग्य हो ।

4 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण तथा पृथक रक्षण और शारीरिक तथा स्वास्थ्य मानक में छूट — (1) (1) प्रत्येक विभागाध्यक्ष या जहाँ विभागाध्यक्ष नहीं है वहाँ सरकार, अपने अधीन पद के प्रत्येक प्रवर्ग के स्वरूप और दृष्टिक अवेक्षा का सम्यक निर्धारण करके और नियम 2 के उपनियम (V) में उल्लिखित शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के प्रत्येक प्रवर्ग की दृष्टिक उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए निदेशक बिक्री तथा एव स्वास्थ्य सेवा, राजस्थान के परामर्श से और सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन से पदों के ऐसे प्रवर्ग में पदों के 2<sup>1/2</sup> स्थान समय समय पर पृथक रक्षित रखेगी जहाँ अंधे/बधिर/ विकलांग और दृष्टिपूर्ण वाक्शक्ति वाले व्यक्ति यथोचित रूप से नियोजित किये जा सकें और इस प्रकार पृथक रक्षित शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के नियोजन के लिए आरक्षित माने जाएंगे ।

(11) खण्ड (1) के अधीन पृथक रक्षित पदों के प्रवर्ग को और नियोजित किय जाने वाले अक्षम व्यक्तियों के प्रवर्ग की सूचना इन नियमों से सलग्न रूप प्ररूप 1 में सरकार के कार्मिक विभाग और निदेशक को दी जाएगी । प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को विद्यमान आरक्षण को और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के नियोजन की स्थिति से सम्बंधित सूचना भी प्ररूप 1 में उनको भेजी जाएगी ।

(11) किसी वय विशेष में उपयुक्त खण्ड (1) के अधीन शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षित रक्तिया के प्रति नियुक्ति हेतु उपयुक्त अभ्यासों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रक्तिया को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भर लिया जाएगा और उनके वगवग सस्था में अतिरिक्त रक्तिया आगामी वय में आरक्षित रखी जाएगी। इस प्रकार भरी न गयी रक्तिया को कुल मिलाकर भर्ती के तीन आगामी वर्षों तक भ्रारे ले जाया जाएगा और उसके पश्चात् ऐसा आरक्षण समाप्त हो जाएगा।

(2) ऐसी सेवाओं और पदों के सवध में जिनमें उप नियम (1) के अधीन कोई पद आरक्षित या पृथक् रक्षित नहीं रखा गया है, सेवा के या पदों के प्रवग के स्वरूप और हृदियक अपक्षा का सम्यक ध्यान रखते हुए लोक सेवा आयोग के या उच्च यायालय के परामश से, जहा ऐसा परामश करना आवश्यक हो, तथा निष्पक्ष चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के परामश से सरकार शारीरिक और स्वास्थ्य परीक्षा की शिथिलीकृत शर्तें अधिनयित कर सकेगी।

5 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्री—सवयक, समाज कल्याण निरीक्षक, सहायक परिवीक्षा अधिकारी आदि जस अधिकरणा की माफत निदेशक, समाज कल्याण विभाग इन नियमों के नियम 2 (V) के क्षेत्र के अधीन भ्राने वाले शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए नियोजन के अवसर उपलब्ध कराने हेतु रजिस्ट्रीकरण की उचित व्यवस्था करेगा। जिलों में उपयुक्त अधिकरणा की माफत एकत्रित सूचना <sup>1</sup>[अक्षम-व्यक्तियों की सूची निदेशक, नियोजन राजस्थान, जयपुर को भेजी जावेगी, जहा एक विनैप कक्ष एक उप निदेशक के अधीन रजिस्ट्रीकरण तथा परिचय पत्र जारी करने के लिये काप कटगा] विकल्पत शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति भी अपन रजिस्ट्रीकरण हेतु सीधे ही या तो निदेशक को या जहा वह अक्षम व्यक्ति निवास करता है उस क्षेत्र में काम करने वाले अधिनयियों में से किसी भी अधिनारी की माफत भी आवेदन कर सकेगा।

6 केन्द्रीय रजिस्ट्री के अधीन रजिस्ट्रीकरण तथा अभिज्ञान पत्र जारी किये जाने हेतु प्रक्रिया—(1) सरकार नियम 5 के अधीन यथा अपेक्षित शारीरिक रूप में अक्षम व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयाजनाथ <sup>2</sup>[नियोजन निदेशालय] में एक प्रकोष्ठ सृजित कर सकेगी।

1 जि स एफ। (17) DOP/A-2/72 GSR-52 दि 24 जुलाई 1972 द्वारा प्रतिस्थापित, जिसमें निम्न पक्तियाँ बदली गईं—

“जिला समाज कल्याण अधिनारी या जिला परिवीक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी। अक्षम व्यक्तियों की सूची प्राप्त होने पर जिला परिवीक्षा अधिकारी या समाज कल्याण अधिकारी उसे निदेशक समाज कल्याण विभाग को भेजेगा।”

2 उपरोक्त विनयि दि 24 7 78 द्वारा ‘समाज कल्याण विभाग’ के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) यह प्रकोष्ठ शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को, सरकार द्वारा समय समय पर विहित प्ररूप में और विहित रीति से प्रवर्गानुसार, रजिस्टर करेगा, और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को अभिज्ञान पत्र जारी करेगा बशर्ते कि आवेदक नियमा में अधिकृत और समय समय पर सरकार द्वारा विहित शर्तें पूरी करता हो।

(3) रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित या समय समय पर सरकार द्वारा विहित अन्य प्रमाणपत्र सलग्न किये जाएंगे—

(क) शैक्षिक दक्षताओं और प्रशिक्षण आदि के संबंधित प्रमाणपत्र, यदि कोई हो।

(ख) आयु का प्रमाण पत्र।

7 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की नि शक्तता की सीमा और करिष्य क्षमता अभिनिश्चित करना और सरकारी सेवा में नियुक्ति होने पर स्वास्थ्य परीक्षा में छूट देना—(1) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति की नि शक्तता की सीमा तथा पद के कतव्यों के पालन हेतु उसका सामर्थ्य बिना उसकी शारीरिक अक्षमता को ध्यान में रखते हुए अभिनिश्चित करने हेतु निदेशक, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अलग अलग चिकित्सा विशेषज्ञ मनोनीत करेगा और निदेशक से इस प्रकार प्राप्त प्रमाण पत्र नियुक्ति हेतु आवेदन के साथ सलग्न किया जाएगा।

(2) शारीरिक रूप से अक्षम ऐसे व्यक्तियों को जो किसी सरकारी विभाग में किसी भारक्षित या पृथक्करक्षित पद पर नियुक्त किये जाते हैं सरकारी सेवा में प्रथम प्रवेश के समय अलग अलग सेवा नियमों में उपबधित सामान्य स्वास्थ्य परीक्षा नहीं की जाएगी और सुमंगल सेवा नियमा को इस सीमा तक सशोषित समझा जाएगा।

■ आयु में छूट—विभिन्न पदों/सेवाओं में नियुक्ति हेतु विहित अधिकतम आयु सीमा में प्र धो और बधिर के मामलों में 0 वर्ष की और विकलांग तथा त्रुटिपूर्ण वाक्शक्ति वाले व्यक्तियों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जा सकेगी और विभिन्न सेवा नियम इस सीमा तक सशोषित होंगे। कष्टकारी विशेष मामलों में सरकार इस सीमा में और छूट दे सकेगी।

9 रियायतें (सुविधाय)—अ धे और बधिर व्यक्ति को नियम 4 में वर्णित नियोजन हेतु पात्र बनाने के लिए उसे निम्नलिखित रियायतें अनुपात की जाएगी—

(i) जहां किसी परीक्षा में अ को का न्यूनतम प्रतिशत विहित है वहां अ को का 5 प्रतिशत,

(ii) बधिरों हेतु अभिप्रेत भाष्यता प्राप्त सत्यान द्वारा जारी किय गये प्रमाण पत्र में दी गई शैक्षिक अहताएं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य सत्यानों के समान मानी जाएगी,

(11) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को अस्थायी नियुक्ति हेतु प्रशिक्षण/जाच/अनुभव की शन या वाछनीयता जहा वही विहित हो लागू नहीं होगी। जहा किसी पद पर नियुक्ति हेतु कोई विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यक हो तो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति से उसकी नियुक्ति से दो बष के भीतर ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जा सकेगी।

10 विकलांगों का पुनर्वास, —जहा नियुक्ति प्राधिकारी के विचार मे शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के लिये विवनाम को फिर से ठीक करने हेतु प्रशिक्षण आवश्यक हो तो इस प्रकार नियोजित व्यक्ति को तत्प्रयोजनाय मायता प्राप्त सस्यान मे उपयुक्त प्रशिक्षण हेतु जाना पड़ेगा।

11 यात्रा व्यय —नियोजन हेतु चयन के सम्बन्ध मे साक्षात्कार, जाच या परीक्षा हेतु बुलाय गये शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को आने जाने की यात्रा हेतु यथास्थिति, द्वितीय श्रेणी का रेल भाडा या वास्तविक साधारण बस भाडा, सदत किया जाएगा।

12 सरकारी वास सुविधा मे पूर्विक्ता —इस प्रकार नियोजित अथे और अधिकर व्यक्ति को जहा वही सभव हो सरकारी वास सुविधा के आवडन में पूर्विक्ता (प्राथमिकता) दी जायेगी।

13 अथ रियायते —अभिज्ञान पत्र धारण करने वाला शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति, सरकार द्वारा समय समय पर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों पर लागू की गई समस्त रियायतों और आरक्षण के फायदे का हकदार होगा और उससे उसकी शारीरिक नि शक्नता अभिनिश्चित करने के सम्बन्ध मे कोई और दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

14 नियोजित व्यक्ति यदि बाद मे शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए —पहले न ही सरकारी सेवा मे नियोजित व्यक्ति यदि इन नियमों में मथा परिभाषित शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए तो वे भी आरक्षण हेतु इन नियमों के नियम 4 मे उपबन्धित शारीरिक तथा स्वास्थ्य परीक्षा मे छूट के हकदार ह। और सरकार के अनुमोदन न किमा अथ वैकल्पिक पद पर आमलित या समायोजित किये जा के हक दार ह। जिस पर इन नियमों के अधीन कोई शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति हकदार हाता है।

15 स्वास्थ्य परीक्षा हेतु फीस —इन नियमों व अधीन किसी भी स्वास्थ्य परीक्षा व लिए या प्रमाण पत्र दिये जान के लिए सरकारी सेवा मे नियोजित किसी चिकित्साधिकारी या विशेषण को कोई फीस सदय नहीं होगी।

16 निरचन —जब तक सदम से अथथा अर्पित न हो, राजस्थान साधारण गण अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सन्ध्या (VIII) इन नियमों के निरचन के लिय लागू होगा।

17 शकाशों का निराकरण — यदि इन नियमों के लागू होने निर्बंधन और विस्तार के विषय में कोई शका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग में भेजा जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

### प्रारूप 1

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के नियोजन के लिए उपयुक्त रक्षित पदों की सूचना (राजस्थान शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का नियोजन नियम, 1976 के नियम

### 4 के अधीन)

- 1 वर्ष
  - 2 विभाग का नाम
  - 3 विभाग में पदों की कुल संख्या
- प्रमाणानुसार —

क्रमांक	पदों का प्रवर्ग	पदों की संख्या
(1)		
(2)		

4 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के नियोजन हेतु उपयुक्त पदों के प्रवर्ग —

क्रमांक	पदों का प्रवर्ग	पदों की कुल संख्या	नियोजन हेतु उपयुक्त शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का प्रवर्ग	2% के आधार पर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या
(1)				
(2)				

5 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के प्रवर्ग के लिए आरक्षित पदों के वर्तमान का स्वरूप —

क्रमांक	पद का प्रवर्ग	वर्तमान प्रसार
(1)		
(2)		

## 6 पहले से नियोजित शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की सख्या—

क्रमांक	पदों का प्रवर्ग	शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों का प्रवर्ग	नियोजित किये गये शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की सख्या
---------	-----------------	--	--

(1)

(2)

## 7 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की सख्या—

क्रमांक	पदों का प्रवर्ग	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का प्रवर्ग, जिन्हें नियोजित किया जा सकता है	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की सख्या
---------	-----------------	--	--

(1)

(2)

प्रमाणित किया जाता है कि मद्र 4 में वर्णित पद, राजस्थान शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का नियोजन नियम, 1976 के नियम 4 के अनुसार निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के परामर्श से तथा प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन से, प्रारक्षित किये गये हैं।

## परिशिष्ट [6]

## विशेष नियम

सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर सरकारी कर्मचारियों के  
आश्रितों की भर्तों के विशेष नियम

§(क) राजस्थान (सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्तों) नियम 1975

§ वि. ॥ एच (36) कार्मिक (क-2) 75 दिनांक 29 सितम्बर 1975, द्वारा, जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ग) 1 दिनांक 2 अक्टूबर 1975 को प्रथम बार प्रकाशित। मूल अंग्रेजी पाठ। हिंदी पाठ के लिये आगे 'पचायन समिति/जि.प. नियम' यथावश्यक परिवर्तन सहित पृष्ठ 49 पर दलिय।

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following special rules regulating the recruitment of the dependant of Government servants dying while in service, namely —

**The Rajasthan Recruitment of Dependants of Government  
Servants Dying while in Service Rules, 1975**

**Short title and commencement —**(1) These Rules may be called 'the Rajasthan Recruitment of Dependants of Government Servants Dying while in Service Rules, 1975'

(2) These Rules shall come into force from the date of their publication in the Rajasthan Rajpatra

**2 Definitions —**In these Rules unless the context otherwise requires —

- (a) "Government" and "State" means respectively the Government of Rajasthan and the State of Rajasthan,
- (b) "Appointing Authority" means the Government of Rajasthan and includes any other Officer to whom powers have been delegated by the Government through a special or general order to exercise the powers and functions of the Appointing Authority under the relevant Service Rules, if any,
- (c) "Head of Department/Office" means the Head of the Department/Office in which the deceased Government Servant was serving prior to his death
- (d) "Government servant" means person employed in connection with the affairs of the State and who—
  - (i) was permanent in such employment, or
  - (ii) though temporary had been regularly appointed in such employment, or
  - (iii) though not regularly appointed, had put in one year continuous service in a regular vacancy in such employment and
  - (iv) shall also include the person sent temporarily on deputation



**Explanation**—"Regularly appointed" means appointed in accordance with the procedure laid down for recruitment to the post or service as the case may be

- (e) "deceased Government servant" means a Government servant who dies while in service,
- (f) "family" means the family of the deceased Government servant and shall include wife or husband, sons and unmarried or widow daughters, who were dependant on the deceased Government servant,

**3 Application of the rules**—These Rules shall apply to recruitment of the dependants of the deceased Government servants to public service and posts in connection with the affairs of State, except service and posts which are within the purview of the Pajasthan Public Service Commission

**4 Overriding effect of these Rules** These rules and any orders issued thereunder shall have effect notwithstanding any thing to the contrary contained in any rule, regulation or orders in force at the commencement of these Rules

**5 Recruitment of a member of the family of the deceased**—In cases of Government servants, who die while in service on or after the commencement of these rules one member of his family who is not already employed under the Central/State Government or Statutory Board/Organisations/Corporations, owned or controlled by the Central/State Government, shall, on making an application for the purpose, be given a suitable employment in Government service without delay only against an existing vacancy, which is not within the purview of the State Public Service Commission in relaxation of the normal recruitment rules provided such member fulfils the educational qualifications prescribed for the post and is also otherwise qualified for Government service. In the event of non-availability of a vacancy or any of the member of the family, being unqualified or minor is not found suitable or eligible for immediate employment then such cases should be considered immediately on the availability of the post or any one of them becomes qualified or eligible for such employment under these Rules

**6 Contents of application for employment**—An application for appointment under these Rules shall be addressed to

the Appointing Authority in respect of the post for which appointment is sought, but it shall be sent to the concerned department or to the Head of the Department/Office where the deceased Government servant was serving prior to his death. The application shall, *inter alia*, contain the following information —

- (1) The name & designation of the deceased Government servant,
- (2) Department/Office in which he was working prior to his death,
- (3) The date & place of the death of the deceased Government servant
- (4) Last Pay drawn & the Pay Scale
- (5) Names ages and other details pertaining to all the members of the family of the deceased particularly about their marriage employment and income
- (6) Details of the financial condition of the family, and
- (7) Name, Date of birth education and other qualifications, if any, of the applicant & his/her relation with the deceased Government servant

**7 Procedure when more than one member of the family seeks employment** — If more than one member of the family of the deceased Government servant seeks employment under these Rules, the Head of Department/Office shall decide about the suitability of the person for giving employment. The decision will be taken keeping in view also the over all interest of the welfare of the entire family particularly the widow and the minor members thereof

**8 Relaxation for age and other requirement** — (1) The candidates seeking appointment under these rules must not be less than 16 years at the time of appointment. In the cases in which the wife of the deceased Government servant being the only candidate found qualified and eligible for such employment there shall be no maximum upper age limit

(2) The procedural requirement for selection, such as written test, typing test or interview by a Selection Committee or

any other Authority, shall be dispensed with, but it shall be open to the Appointing Authority to interview the candidate in order to satisfy that the candidate will be able to maintain the minimum standards of work and efficiency expected on the post or to prescribe any condition, if considered necessary, for acquiring any training or proficiency e.g. typing speed or any other qualifications etc., within a reasonable period, after such employment under these Rules

**9 Satisfaction of Appointing authority as regards general qualification**—Before a candidate is appointed the Appointing Authority shall satisfy that

- (a) The character of the candidate is such as to render him suitable in all respects for employment in Government service,

**Explanation**—Persons dismissed by the Union Government or by any State Government or by a Local Authority or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall be deemed to be ineligible for appointment to the service

- (b) He is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his/her duties, for which the candidate shall be required to appear before the appropriate medical authority and to produce a certificate of fitness in accordance with the rules applicable to the case, and
- (c) In the case of a male candidate, he has not more than one wife living, and in the case of female candidate, she has not married a person already having a wife living

**10 Power to remove difficulties**—The State Government may, for the purpose of removing any difficulty (of the existence of which it shall be the sole judge) in the implementation of any provision of these Rules, make any general or special order as it may consider necessary or expedient in the interest of fair dealing or in the public interest

---

# राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा के सदस्यों के आश्रितों की भर्ती नियम, 1978

× जी एस आर 163 — राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1959 की धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाले समस्त उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कमचारियों की सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर, उनके आश्रितों की भर्ती का उपबन्ध करने और उसे विनियमित करने के लिये निम्नलिखित विशेष नियम बनाती है, अर्थात् —

1 सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ — (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा के सदस्यों के आश्रितों की भर्ती नियम, 1978 है।

(2) ये राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाएँ — जब तक सदस्य से अथवा अप्रतिष्ठित न हो, इन नियमों में —

(क) “राज्य” से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है।

(ख) पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा के सबन्ध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से सेवा के उस वर्ग प्रथम अथवा ग्रेड में जिसमें ऐसा सदस्य तत्समय सम्मिलित है पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम की धारा 31 के अधीन नियुक्ति करने के लिये सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(ग) “पंचायत समिति” तथा “जिला परिषद” से राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम के अधीन गठित पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अभिप्रेत हैं।

(घ) “सेवा” से राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा अभिप्रेत है।

(ङ) “सेवा का सदस्य” से राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा में के किसी पद पर नियुक्त कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो—

(1) ऐसे नियोजन में स्थाई था, या

× जी एस आर 163 वि स एफ 4/एल जे /पी एस /ए आर/19/78 416 दि 24 अक्तूबर 1978 द्वारा, जो राजस्थान राजपत्र, प्रकाशित, भाग 4(ग)/दिनांक 24 अक्तूबर 1978 को अग्रणी में प्रकाशित व उसी दिन से प्रभावशील। उपरोक्त प्राधिकृत हिंदी पाठ राजपत्र में दि 25 जनवरी 1979 को प 431 पर प्रकाशित।

- (11) यद्यपि अस्थाई होने पर भी ऐसे नियोजन में नियमित रूप से नियुक्त किया था, या
- (12) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त न किये जाते पर भी ऐसे नियोजन में किसी नियमित रिक्ति में एक वर्ष की निरंतर सेवा कर चुका था,
- (13) और इसमें अस्थाई रूप से प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया व्यक्ति भी, यदि कोई हो, सम्मिलित होगा।

**स्पष्टीकरण —**“नियमित रूप से नियुक्त” से यथास्थिति पद पर या सेवा में भर्ती के लिए अग्रिमस्थित प्रक्रिया के अनुसार की गई नियुक्ति अभिप्रेत है।

- (क) “पंचायत समिति तथा जिला परिषद का मत कमचारी” से राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जिसकी सेवा काल में मृत्यु हो जाती है।
- (ख) “परिवार” से पंचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा के मत सदस्य का परिवार अभिप्रेत है और इसमें पत्नी या पति, पुत्र तथा अविवाहित या ऐसी विधवा लड़कियाँ सम्मिलित हैं जो पंचायत या जिला परिषद सेवा के मत सदस्य पर उसकी मृत्यु के समय आश्रित थी।

**3 नियमों का लागू होना —**ये नियम पंचायत समिति जिला परिषद के मत कमचारियों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होंगे।

**4 इन नियमों का अद्यारोही प्रभाव —**इन नियमों के प्रारम्भ के समय प्रवर्त किन्हीं नियमों, विनियमों अथवा आदेशों में अतविष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ये नियम तथा इनके अधीन जारी किये गये कोई भी आदेश प्रभावी रहेंगे।

**5 मतक के परिवार के सदस्य की भर्ती —**पंचायत समिति तथा जिला परिषद के किसी ऐसे कमचारी के मामले में, जिसकी मृत्यु इन नियमों के प्रारम्भ होने पर या उसके पश्चात् सेवा काल में हो जाती है, उसके परिवार के एक ऐसे सदस्य जो पंचायत समिति जिला परिषद/केन्द्रीय/राज्य सरकार के या केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन कानूनी बोर्ड/संगठन/नियमों के अधीन पहले से ही नियोजित नहीं है, इस प्रयोजनाय आवदन करने पर सामान्य भर्ती नियमों की शिथिल करते हुए पंचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा में किसी विद्यमान रिक्ति पर यथाशीघ्र उपयुक्त नियोजन दिया जायगा वस्तुतः ऐसा सदस्य पद के लिये विहित शैक्षणिक अहताएँ पूरी करता हो और वह राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा के लिये अग्रया अर्हित भी हो। किसी रिक्ति के उपलब्ध न होने पर या अनर्हित या अवस्यक होने के कारण परिवार के सदस्यों में से कोई भी सदस्य तुरन्त नियोजन के लिये उपयुक्त या पात्र नहीं पाये जाने पर, ऐसे मामले में,

पद के उपबन्ध हो जाने पर या इन नियमों के अधीन ऐसे नियोजन के लिये उनमें से किसी भी एक सदस्य के अहित या पात्र हो जाने पर तुरन्त विचार किया जायेगा।

6 नियोजन के लिये आवेदन पत्र की विषय वस्तु — इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र ऐसे पद के बारे में जिसके लिए नियुक्ति चाही गई है, नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, परन्तु वह उस संबंधित पचायत समिति या जिला परिषद को भेजा जायगा जहाँ पचायत समिति या जिला परिषद का मृत कमचारी अपनी मृत्यु से पूर्व सेवा कर रहा था।

आवेदन-पत्र में, अग्र बातों के साथ साथ निम्नलिखित सूचना होगी —

- (1) पचायत समिति जिला परिषद के मृत कमचारी का नाम तथा पदनाम।
- (2) उस पचायत समिति जिला परिषद का नाम जिसमें वह अपनी मृत्यु की तारीख को कार्य कर रहा था।
- (3) पचायत समिति जिला परिषद के मृत कमचारी की मृत्यु की तारीख तथा स्थान।
- (4) लिया गया अंतिम वेतन तथा वेतनमान।
- (5) मृतक के परिवार के समस्त सदस्यों के नाम, आयु तथा उनसे सम्बंधित अग्र विवरण, विशिष्ट उनके विवाह नियोजन तथा अग्र के बारे में।
- (6) परिवार की वित्तीय स्थिति का विवरण।
- (7) आवेदक का नाम, जन्म शैक्षणिक तथा अग्र ग्रहण, यदि कोई हो, तथा पचायत समिति जिला परिषद के मृत कमचारी से उसका संबंध।

7 परिवार के एक से अधिक सदस्य द्वारा नियोजन चाहने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया — यदि पचायत समिति/जिला परिषद के मृत कमचारी के परिवार के एक से अधिक सदस्य इन नियमों के अधीन नियोजन चाहते हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी, नियोजन देने हेतु व्यक्ति की उपयुक्तता के बारे में विनिश्चय करेगा। ऐसा विनिश्चय समस्त परिवारके, विशिष्ट उसकी विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के पूर्ण हित को ध्यान में रखकर किया जायगा।

8 आयु तथा अग्र अपेक्षाओं के लिए शिथिलीकरण—, (1) इन नियमों के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु उसकी नियुक्ति के समय 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामले में जिसमें पचायत समिति/जिला परिषद सेवा के मृत कमचारी की पत्नी ही अभ्यर्थी हो और वह नियोजन के लिये अहित तथा पात्र पाया जाये तो वहाँ अधिकतम उच्च आयु की सीमा नहीं होगी।

(2) चयन की प्रक्रिया से सम्बंधित आवश्यकताओं, जैसे कि लिखित परीक्षा, टंकण परीक्षा या किसी चयन समिति या किसी अग्र प्राधिकारी द्वारा साक्षात्कार स

अभिमुक्ति प्रदान की जायेगी परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, इस बात से अपना समाधान करने के लिये कि अभ्यर्थी काय के 'यूनतम स्तर' की तथा पद पर अपेक्षित दक्षता को बनाये रखने में समर्थ होगा, अभ्यर्थी का माक्षाद्वारा लेन अथवा यदि आवश्यकता हो तो इन नियमों के अधीन नियोजन के पश्चात् युक्तियुक्त बालावधि के भीतर कोई प्रशिक्षण या प्रवीणता, जैसे टक्का गति या अन्य ग्रहताएँ अर्जित करने हेतु कोई शर्त विहित करने के लिये स्वतन्त्र होगा।

9 साहाय्य ग्रहणार्थों के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान — किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति करने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना समाधान इस बात से करेगा कि —

- (क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा हो जो उसे समावाता में पचायत समिति/जिला परिषद् की सेवा के लिए उपयुक्त बनाता हो,

स्पष्टीकरण —सद्य सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या राजस्वान पचायत समिति तथा परिषद् सेवा या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्ववादी या नियन्त्रणाधीन किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये अपात्र समझे जायेंगे।

- (ख) वह भौतिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तथा उसमें कोई ऐसा शारीरिक नुबस न हो जिससे उसके उन कर्तव्यों के लिये अभ्यर्थी से समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होना की तथा मामले में लागू नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र पेश करने की अपेक्षा की जायेगी, दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधक होने की सम्भावना हो, तथा

- (ग) किसी पुरख अभ्यर्थी के मामले में उसके एक से अधिक जीवित पत्नी न हो तथा महिला अभ्यर्थी के मामले में उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो, जिसके पहले ही जीवित पत्नी हो।

10 कठिनाइयाँ का निराकरण करने के शक्ति —राज्य सरकार, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध के कार्यान्वयन में अनुभव की जान वाली किसी कठिनाई का (जिसकी विद्यमानता के सबब में वही एक मात्र निर्णायक होगी) निराकरण करने के प्रयोजनाय कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश कर सकेगी, जैसा वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक अथवा समीचीन समझे।

(ग) नगरपालिकाओं के तथा सावजनिक निर्माण के कार्य-प्रभारित कम कमचारिया पर लागू किये गये—राजस्थान (सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर पर सरकारी कमचारियों के आश्रितों की भर्ती) नियम 1975 यथा परिवर्तन के साथ—

(i) नगरपालिका सेवा के अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

[ जी एस आर 175 वि स प 2 (36) स्वा शा/58/भाग 4 दिनांक 19 सितम्बर 1978, जो राजस्थान राजपत्र, भाग 4 (ग) I दिनांक 15 फरवरी 1979 में प्रकाशित ]

(ii) सावजनिक निर्माण विभाग, बागान, सिंचाई, जलप्रदाय तथा आयुर्वेदिक विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों के आश्रितों को कार्य प्रभारित (वक चाज) कमचारी के रूप में उनकी नियुक्ति के लिये ये नियम लागू होंगे।

[आशा स एफ 3 (6) कार्मिक (क-II) 75 GSR 231 दिनांक 22 फरवरी 1977, जो राजपत्र भाग 4 (ग) I दि 10 3 1977 में पृष्ठ 718 पर प्रकाशित—1977 RLT-II Page 101, Note 104]

## परिशिष्ट [7]

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958

### अनुसूची (3) लिपिकवर्गीय सेवाये

समस्त विभागों में निम्नलिखित प्रवर्गों के पदधारक जैसे —

1 जिला राजस्व लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार 2 ग्रहलमद, बरिष्ठ कनिष्ठ या सहायक ग्रहलमद 3 लेखालिपिक और कनिष्ठ लेखा लिपिक 4 लेखा सकलनकर्ता 5 सहायक जिसमें राजस्व सहायक 'यायिक सहायक', स्थापना सहायक, विविध सहायक एवं आयोजना सहायक सम्मिलित हैं 6 अकेला, चिट्ठियात लिपिक 7 अकेला लिपिक 8 सभागीय अवेक्षक को सम्मिलित करते हुए अवेक्षक 9 बिल लिपिक 10 बिल्टी लिपिक 11 जिरदसाज 12 खजांची और सहायक खजांची 13 लिपिक जिसमें दौवानो लिपिक फौजदारी लिपिक, अपील लिपिक, पुनरीक्षण लिपिक, अग्रेजी लिपिक सम्मिलित हैं 14 गणना यम चानक 15 शिविर लिपिक 16 सूचीकार 17 सकलनकर्ता जिसमें निदेशक जिला गजेटियस के मुख्य सकलनकर्ता भी सम्मिलित हैं 18 अतरंग लिपिक 19 नकलनदीस 20 कोर लोर्गिंग लिपिक 21 पटल लिपिक 22 डाक लिपिक 23 प्रेषक लिपिक 24 टायरी



लिपिक 25 सहाय लिपिक 26 म्यापना लिपिक 27 आबकारी लिपिक 29, प्रदेष्ट लिपिक 29 विलोपित 30 क्षेत्र सहायक 31 सैन्य लिपिक 32 पर्नीचर लिपिक 33 गजपूर 34 राज-गर्भ 35, मुख्य लिपिक 36 जनगणना विभाग के निरीक्षक 37 रुपिया निरीक्षक, खुशी एवं आबकारी विभाग के उप निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक 38 उपकरण लिपिक 39 कनिष्ठ लिपिक 40 छाता जमाबंदी लिपिक 41 अभिलेख लिपिक 42 सदान एवं प्रेषण लिपिक 43 कार्यालय के पुस्तकाध्यक्षों या पुस्तकालय लिपिक 44 अनुसूची (1) या (2) में वर्णित पुस्तकालयों के प्रति रिक्त पुस्तकालयों के पुस्तकाध्यक्ष, सहायक पुस्तकाध्यक्ष, छाता पुस्तकाध्यक्ष, सदस्य पुस्तकाध्यक्ष 45 छुट्टी आरक्षित लिपिक 46 सदर मुसरिम को सम्मिलित करत हुए मुसरिम 47 मुशी तथा मुख्य मुशी 48 मोहरिर 49 मुकद्दम 50 नाकेदार 51 नाजिर 52 नागज विशेषज्ञ, सहायकारी विभाग 53 पासल लिपिक 54 पटवारी 55 वेतन लिपिक 56 पेंशन लिपिक 57 विभागाध्यक्षों या कार्यालयाध्यक्षों के निजी सहायक जो विभाग के सबब से संबंधित नहीं है।

नोट — पद 57 के पद धारकों के सबब में कार्यालयाध्यक्ष समुक्त विभागाध्यक्ष होगा।

58 पेशकार और कनिष्ठ सहायक पेशकार 59 याचिका लिपिक 60 प्रूप शोधक 61 जनसम्पर्क निदेशालय में निम्नलिखित पद — पूछताछ अधिकारी सम्पादन सहायक, पेशकार, सवीक्षक, प्रोडक्शन अधिकारी, व्याख्याता 62 पेशकार और मुख्य पेशकार 63, प्राप्त लिपिक 64 अभिलेखपाल, सहायक अभिलेखपाल तथा अभिलेख लिपिक 65 प्रत्यक्ष लिपिक 66 रोजनामचा लिपिक 68 अनुभाग प्रधारी और अनुभाग लिपिक 69 कनिष्ठ लिपिक जिसमें जिसमें जागीर विभाग के निरीक्षक सम्मिलित हैं 70 लेखन सामग्री लिपिक 71 सार्वजनिक लिपिक 72 आधुनिक लिपिक 73 माल पट्टालिया 74 भण्डारी तथा सहायक भण्डारी 75 उपसभाग लिपिक 76 अधीक्षक, महा अधीक्षक, अनुभाग अधीक्षक, जिसमें कार्यालय अधीक्षक एवं पजीयक मगनीराम बागड इन्जीनियरिंग महाविद्यालय, जोधपुर सम्मिलित हैं। 77 पयवेक्षक 78 सारणीकार 79 समयपाल और सहायक समयपाल 80 कार्यालयों के अनुवादक 81 यात्राध्यक्ष लिपिक 82 कार्यालयों के कोषाध्यक्ष, सहायक कोषाध्यक्ष तथा कनिष्ठ कोषाध्यक्ष 83 टक्क 84 भाषा लिपिक 85 लेखक 86 ग्राम सेवक 87 मुहाफिजान 88 उप पजीयक, विभागीय परीक्षाएँ लिपित 89 टिकिट बाबू एवं कण्डकठर, राजकीय परिवहन सेवा, सिरौही 90 देवस्थान विभाग के मैनेजर, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी 91 दारोगा, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी 92 मोहदेदार, प्रथम

91 से 96 देवस्थान विभाग के पद हैं।

तथा द्वितीय श्रेणी 94 महत्त, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी 94 मुखिया, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी 95 पुजारी प्रथम द्वितीय श्रेणी 96 गोस्वामी, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी 97 उपसपादक 98 सवाददाता 99 वरिष्ठ प्रूफशेक्क 100 निदेशक, कृषि विभाग के निजी सहायक 101 भण्डार पयवेक्षक 102 खेल-कूद एवं सहायक 103 पयवेक्षिका 104 महिला दर्जी 105 निरीक्षक, भण्डार एवं लेखा 106 अमीन 107, टेलीफोन चालक 108 चकबंदी विभाग के सर्वेक्षक 109 मागदशक 110 बनिष्ठ स्वागतकर्ता 111 कारिदा 112 सजिवालय और राजस्थान लोक सेवा प्रायोग कार्यालया के अनुभाग अधिकारी 113 लेखा निरीक्षक 114, अभिलेख सहायक 115 अवेपक 116 रिकाड अटेंडेंट 117 छटाई कर्ता 118 परिरक्षण सहायक 119 प्रयोगशाला सहायक 120 मुख्य अनुवादक सजिवालय 121 लोफ निर्माण (भवन एवं सड़क) विभाग में प्रशासन सहायक 122 भेड ऊन कार्यालय में मास्टर क्लक 123 प्रशासनिक सहायक 124 मुख्य अनुवादक 125 सहायक मुख्य अनुवादक 126 साक्षर अटेंडेंट 127 देखभालकर्ता (केयरटेकर)\* ।

## अनुसूची (4) चतुर्थ श्रेणी सेवायें

समस्त विभागों में निम्नलिखित प्रयोगों के पदधारक, जैसे—

1 शिल्पकार (लोहार, बडई भलाईगर, खरादी, रंगसाज आदि) 2 अटेंडेंट जिसमें गैलरी अटेंडेंट, बाड अटेंडेंट रिपिटर अटेंडेंट, सब स्टेशन अटेंडेंट सम्मिलित हैं 3 नाई 4 बरक-दाज 5 भिस्ती 6 जिल्दसाज तथा सहायक जिल्दसाज 7 बोहारिया 8 बाय जिसमें लाइब्रेरी बाय, टेलीफोन बाय, पैट्रोल बाय सम्मिलित हैं । 9 बम्तावरदार 10 बनिशर 11 गाडीवान 12 गाडी चालक 13 चवालिया 14 चौकीदार 15 जरीबी 16 सिनेमा कमचारी 17 क्लीनर 18 रसोइया 19 कुली 20 दफेत्तार 21 दफतरी 22 दाई या मिड बाइफ 23 डाक से जानेवाला 24 ड्रेसर 25 फर्निश 26 फिल्टर चालक 27 माली(हाली, माली चौधरी आदि) 28 गैंगमेट और गंगमैन 29 गेट पास चैकर 30 द्वारपाल और सार्जेंट 31 रणक जिसमें थोप रक्षक, बन रक्षक आखेट रक्षक तथा रिजव रक्षक सम्मिलित हैं । 32 हरकारा 33 मददगार 34 होशनाक 35 जमादार 36 कावडिया 37 खलासी 38 थ्रमिक जिमम स्वाधी थ्रमिक तथा कुशल थ्रमिक सम्मिलित हैं । 39 लिफ्टमैन 40 लाइन बेलदार 41 मेट और हैटमेड 42 लोपित 43 मोचिया 44 निगरा और निगरानदार जिममें महायक

\* [दि 16 10, 78 को जोड़ा गया]

निगरा तथा निगरानेदार सम्मिलित हैं। 45 घदली 46 वेस्टक 47 पैदल 48 प्रहरी 49 चपरासी 50 बस्तावरदार 51 रोड जमादार 52 गैहमा 53 शिवारी 54 सवार जैसे साईकिल सवार, ऊँट सवार, मुतर सवार, घुड़ सवार, हाथ सवार 55 महतर 56 सईस 57 दर्जी 58 टर्नकी एव सहायक टर्नकी 59 प्रहरी 60 बाइमैट 61 घोबी 62 जलघारी 63 किसान 64 चरवाहा 65 डील 66 मूर्त 67 भण्डारी 68 बेटर 69 मशालची 70 कोठारी 71 स्टीवड या सानसामा 72 आधदार 73 शकरची 74 बेकर 75 बेरा 76 बेसदार 77 बायलर अटेंडेंट 78 लोपित 79 सान रक्षक 80 पापोशा 81 लोपित 82 पहरायती 83 सरवण 84 टिनमैन 85 लोपित 86 कोठार सेवक 87 गद्दी बनाने वाला 88 मोधी 89 लोपित 90 लखर 91 सफाई पर्यवेक्षक 92 सिनेमा चालक 93 नादर ह्योदी 94 नादर लिडकी 95 दरबान 96 हजारो 97 नेवगन 98 भण्डार कमचारी 99 गार्ड निर्माता 100 सांघागार 101 बस्वेनाइजर 102 बसइसाज 103 बटरीम 104 मोची 105 रगसाज ॥ 106 कोठयारी 107 भण्डारी 108 रोकटिय 109 तोपसानी 110 अभियेकी 111 बालभोगी 112 शुभचिन्तक 113 रसोइय 114 टहलवा 115 भापटिया 116 कीतनिया 117 घोवदार 118 हरकारा 119 पोशाक 120 जलघडिया 121 मवपाता 122 कर समाहता 123 सहायक कोठा 124 यत्रपाल 125 प्रक्षेत्र सेवक 126 मुख्य हलवाला 127 हलवाला 128 मसुम 129 ईडनेट (देवासा) 130 घोबी 131 आदेशिका बाहक 132 लोपित 133 लोपित 134 सपायक युनाई मास्टर, परिसज्जक, सूत युनाई सहायक, बायलरम 135 चमडेवाला 136 तुलारा 137 प्रोजेक्ट चालक 138 गैज रीडर 139 प्रयोगशाला सवाहक (शिक्षा विभाग 140 प्रयोगशाला सेवक (शिक्षा विभाग 141 लोहार 142 लोपित 143 खरादी ॥ 144 बाजावाला 145 सारगि 146 पखावजिया 147 बाहदार 148 मुखिया 149 पुजारी 150 भीतरि 151 भापटिया 152 देश का पोशवान 153 नगारची 154 प्रचारक 155 गार्ड नायची 156 वृषपाल 157 ग्वाला तथा हलवाला 158 सहायक गसमैन 159 मेनुअल सहायक 160 मानचित्र पाल 161 फोरमैन 162 डिजल बॉय 163 मॅड (मरम्मत करने वाला) 167 नोकापाल 168 एलममैन 169 की मैन 170 ब कीपर 171 बाइलर मैन X 172 पुस्तकरक्षक (बुक लिपटर) ।

॥ 106 से 120 तथा 144 से 155 देवस्थान विभाग के पद हैं ।

X दि० 26 10 78 को जोड़ा गया ।





